

राजस्थान

शिक्षा कानून संग्रह

लेखक:—

पी. के. चौरडिया
बी.ए., एलएल.बी. (फाइनल)

प्रकाशक:—

करेन्ट लॉ पब्लिशर्स

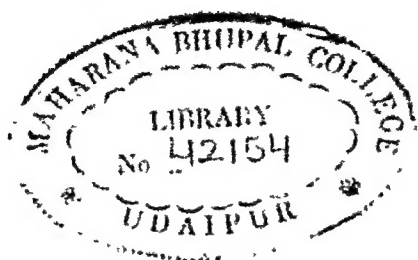
चौड़ा रास्ता—जयपुर ।

[स्विकरण १९६८]

मूल्य २०)

प्रकाशकः—

करेन्ट लॉ पब्लिशर्स
चौड़ा रास्ता—जयपुर ।



(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

(अप्रामाणिक प्रनुवाद)

मुद्रक :
कीर्ति प्रिन्टर्स
जयपुर ।

अपनी बात

अध्यापक जीवन से सम्बन्धित रहने के कारण उनके हित साधन की दृष्टि से कुछ करने की सर्वदा से अभिलाषा रही है। शिक्षा जगत के कार्य को सुचारु रूप से संचालन के लिए राज्य सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व यह शिक्षा नियम संहिता लागू की थी, किन्तु अंग्रेजी भाषा में होने से उसका लाभ यथेष्ट नहीं हो पाता था। स्वतन्त्र भारत में ऐसे नियमों का हिन्दी अनुवाद होना, न केवल एक प्रशासकीय संकल्प को ही पूरा करता है, अपितु इन नियमों की जानकारी को सर्व साधारण के लिये सुलभ बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अनुवाद में यथा संभव शुद्ध हिन्दी शब्दावली का ही प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु यदि कहीं अन्य प्रकार का प्रयोग भी प्रतीत हो, तो पाठकगण क्षमा करेंगे।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर इन शिक्षा नियमों के अलावा कुछ अन्य नियम भी लागू होते हैं, अतः उनमें से कुछ का समावेश भी इस पुस्तक में किया गया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स आवरण नियम, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये विशेष तौर पर लाभकारी रहेंगे क्योंकि विभागीय अनुशासन के नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार राजस्थान अमेनिक सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं पुनर्विचार) नियम के महत्वपूर्ण अंश भी इस पुस्तक में दिये गये हैं। कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की क्या विधि है, इसकी जानकारी सबको होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने जो नई वेतन शृंखलाएँ घोषित की हैं वे भी इस पुस्तक में दी गई हैं तथा पुराने वेतन से नये वेतन में परिवर्तन करने के लिये आवश्यक तालिकाएँ भी दी गई हैं। इनसे अध्यापक गण स्वयं जान सकते हैं कि नई वेतन शृंखलाओं में उनको कितना वेतन मिल सकेगा। वेतन शृंखलाओं के प्रकाशन में यद्यपि पूरी सावधानी रखी गई है फिर भी यदि कहीं अशुद्धियाँ रह गई हों, तो कृपया उनका पाठ शुद्ध करके ही पढ़ें। राज्य सरकार तथा शिक्षा संचालक द्वारा प्रसारित परिपत्रों को भी पुस्तक में यथेष्ट स्थान दिया गया है जिससे पुस्तक की न केवल उपयोगिता बढ़ गई है अपितु उसके प्रावधान आदिनांक तक संशोधित हो गये हैं। शिक्षा विभाग में वर्ष भर में कितने अवकाश होंगे, इससे सम्बन्धित कलेंडर, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम, १९६३ तथा राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६४ को भी इस पुस्तक में समाविष्ट किया गया है जो पंचायत समितियों एवं उनके अधिनस्थ शालाओं के लिये अत्यन्त उपयोगी है। तात्पर्य यह है कि पुस्तक को सभी प्रकार से लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया गया है।

अगर यह प्रयास कुछ भी उपयोगी सिद्ध हो सका, तो परिश्रम सार्थक हो उठेगा। इस अनुवाद को सम्भव बनाने में सौ० विजय लक्ष्मी चौरड़िया ने अत्यधिक सहयोग दिया है, अतः हृदय से उनका आभार प्रदर्शित करते हैं।

सहायक उपनिरीक्षक	१३	१७
शाखाओं के प्रभार	१४	१८

अध्याय ४

(निरीक्षण)

निरीक्षण में निये लायनेवाले नियम	१	१८
निरीक्षण प्रतिवेदन	४	२१
निरीक्षण का समय	५	२२
निरीक्षणों का यात्रा कार्यक्रम	६	२२
निरीक्षण की नैतिक रिपोर्ट	१२	२३

अध्याय ५

(स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय)

छात्राओं के अधिकार	४	२४
छात्रावास की व्यवस्था	४	२४
स्टाफ कोमिंग	७	२४
प्रोविडेंट फंडेशन पर प्रतिबन्ध	१५	२५
नैतिक शिक्षा	१७	२५
कार्यक्रमिक शिक्षा	२०	२५
सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ	२१	२५

अध्याय ६

(संस्थाओं का आन्तरिक प्रशासन)

शिक्षण की व्यवस्था	१	२६
कार्यस्थान छोड़ने की स्वीकृति	४	२६
कार्यक्रमिक शिक्षण	५	२६
नैतिक शिक्षा	६	२७
धार्मिक निर्देश	१०	२७
अनुशासनात्मक नियम	११	२७
शालाओं का समय	१३	२८
अध्यापकों के विरक्त अन्तर	१६	२८

विषय	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
संस्थाओं के लिये आवश्यक स्थान	१६	२६
स्थानीय स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध	२७	३०
अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ	३४	३०
छात्र रजिस्टर	४८	३२
विभागीय, आदेशों का पालन	६०	३४

अध्याय ७

(शुल्क एवं निधि)

विभिन्न प्रकार के शुल्क	२	३५
छात्र संघों की स्थापना	३६
संघ के पदाधिकारी	४	३७
निधियों के हिसाब हेतु नियम	५	३८

अध्याय ८

परीक्षाएँ एवं प्रमोशन के नियम

परीक्षाओं का काल	२	३९
प्रमोशन के नियम	६	३९
उत्तीर्ण करने के लिये प्रावधान	४१

अध्याय ९

प्रशिक्षण संस्थाएँ

वर्गीकरण	१	४३
प्रत्याशियों का चयन	४	४३
प्रशिक्षण काल में अनुबन्ध	१३	४४
प्रशिक्षणावधि में अवकाश	२०	४५
प्रशिक्षण समाप्ति पर यात्रा भत्ता	२४	४६
विद्यालयों द्वारा सहयोग	२६	४६

अध्याय १०

छात्रावास

निवास की रातें	४	४८
अधीक्षक की नियुक्ति	६	४८
अधीक्षक के कार्य	८	४८
— छात्ररण नियम	१३	४९
निजी सेवकों का प्रयोग	१६	५०

अध्याय ११

पुस्तकालय

वर्गीकरण	१	५०
समय	१७	५२
सार्वजनिक पुस्तकालय	२१	५३
सहायता प्राप्त पुस्तकालय	२७	५३
पुस्तकालय समिति	...	५४
समिति के कार्य	५५
पुस्तकालय नियम	५६

अध्याय १२

सेवा में नियुक्ति की शर्तें

नियुक्ति	१	६२
आयु	४	६३
पदोन्नति के सिद्धांत	७	६३
वरिष्ठता की सूची	८	६४
स्थानान्तरण	२१	६५
अवकाश	३०	६६

अध्याय १३

शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना

संस्थाओं का वर्गीकरण	१	६८
मान्यता की शर्तें	३	६८
प्रबन्धक समिति का गठन	६९
मान्यता देने वाले अधिकारी	१०	७२
निजी संस्थाओं के लिये सक्षम अधिकारी	१३	७२

अध्याय १४

विभागीय परीक्षाएँ

विभागीय परीक्षाओं के प्रकार	२	७३
केन्द्रों का वितरण	७	७४
एस. टी. सी. परीक्षार्थी	११	७४
पाठ्यक्रम आदि	१४	७४

अध्याय १५

संस्कृत एवं आयुर्वेदिक शिक्षा

वर्गीकरण	१	७५
नियंत्रण	२	७६
पाठ्यक्रम	७	७६
आयुर्वेदिक शिक्षा	८	७६

अध्याय १६

अन्य सहशैक्षणिक प्रवृत्तियाँ

खेलकूद	१	७७
शारीरिक शिक्षा	२	७७
प्रतियोगितायें	३	७८
गणवेश	५	७८
क्रोडांगण	६	७८
स्काउट आन्दोलन	६	७८

अध्याय १७

सहायता अनुदान के लिए नियम

संस्थाओं का वर्गीकरण	२	७९
सहायता अनुदान के लिए शर्तें	३	७९
अनुदान के लिए स्वीकृत व्यय	६	८१
अनुदान के लिये समिति	१३	८३

अध्याय १८

भवन एवं फर्नीचर

शाला के लिये भवन का चुनाव	८	८५
निर्माण की योजना	१०	८५
फर्नीचर की माप	११	८७
छात्रावास भवन	१२	८८
स्वास्थ्य सुविधायें	१७	८९

अध्याय १९

व्यक्तिगत द्यू शून्स तथा अन्य वृत्तियां

द्यू शून् पर प्रतिबन्ध	१	६०
स्वीकृत द्यू शून्स	३	६१
अनुमति के लिये सक्षम अधिकारी	६	६१

अध्याय २०

परीक्षाओं में बैठने की अनुमति

एल. एल. बी. परीक्षा	२	६२
अध्यापकों का प्रतिशत	३	६२
आवश्यक सेवाकाल	६	६२
स्वीकृत-कर्ता अधिकारी	१३	६३

अध्याय २१

रजिस्टर तथा अभिलेख

महा विद्यालय एवं उच्च विद्यालय	१	६४
छात्रावास	४	६६
प्रगति पुस्तिका	५	६६
आगन्तुक पुस्तिका	६	१००
आदेश पुस्तक	५	१००
स्टाक रजिस्टर	११	१००
छात्र रजिस्टर	१७	१०२
उपस्थिति रजिस्टर	१८	१०३

अध्याय २२

पत्र व्यवहार का क्रम

१०४

अध्याय २३

प्रशस्ति प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय २४

[संस्था प्रधानों आदि के लिये निर्देश]

संस्था प्रधान	१	१०९
शैक्षणिक कर्मचारी	२४	१११
कक्षाध्यापक	४३	११३

अध्याय २५

सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिये नियम	११४
--	------	-----

परिशिष्ट

१. विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले सामयिक विवरण पत्र	११७
२. सामयिक निरीक्षण	११८
३. सामयिक प्रत्यावृत्त एवं विवरण	११९
४. निरीक्षण टिप्पणियां	१२१
५. [अ] निरीक्षण पत्र	१३१
५. [ब] निरीक्षण पत्र	१३६
६. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन	१४०
७. सर्वेक्षण प्रतिवेदन	१४६
८. विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने सम्बन्ध में योजना एवं विषय	१४८
९. शुल्क सूची	१५२
१०. सार्वजनिक परीक्षा के लिये स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र	१५६
११. परीक्षा के लिये आवेदन कर्ताओं का सामूहिक विवरण पत्र	१५७
१२. प्रशिक्षण के लिये नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला बन्ध पत्र	१५८
१३. व्यक्तिगत शिक्षण संस्था मान्यता प्रार्थना पत्र	१६०
१४. शिक्षण संस्था सहायता प्रार्थना पत्र	१६४
१५. सहायता देने के सम्बन्ध में अधिकारियों का अभिमत	१७१
१६. प्राइवेट ट्यूशन के लिये आवेदन पत्र	१७१
१७. प्रशिक्षण के लिये आवेदन पत्र	१७२
१८. प्रशिक्षण के लिये आवेदन पत्र	१७३

विषय	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
१६. छात्र रजिस्टर	१७४
२०. प्रवेश पंजिका	१७६
२१. पाठशाला प्रवेश प्रार्थना पत्र	१७७
२२. प्रगति पत्र	१७८
२३. अनुबन्ध पत्र	१८०
२४. शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शक्तियों का हस्तान्तरण	१८२
२७. अनुसूचित जातियों की सूची	१८४
सारिणी सम्बन्धित हिदायतें तथा सारिणी विवरण	१८८

राजस्थान अर्सेनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम १६६१

नवीन वेतन शृंखलाओं की सूची	२०५
विकल्प प्रपत्र	२०७
पदानुसार वेतन शृंखलायें	२०८
अध्यापकों को नवीन शृंखलानुसार वेतन देने के लिये विशेष नियम	२२६
वर्तमान से नवीन वेतन शृंखलाओं की परिवर्तन तालिका	२२६

राजस्थान अर्सेनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनर्विचार) नियम १६६०

इन नियमों की प्रयुक्ति	२४३
सेवाओं का वर्गीकरण	२४३
निलम्बन	२४५
अनुशासन	२४६
बड़ी सजायें देने का तरीका	२४७
अपीलें	२४८
निलम्बन आदेश	२५०
अभियोग पत्र	२५२
अभियोग विवरण पत्र	२५३

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम १६६०

परिभाषायें	धारा	
सेवा की संख्या	४	२५४
सेवाओं का प्रारम्भिक गठन	६	२५४
नियुक्ति के साधन	७	२५५
	८	२५५

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं अनुभव	१३	२५६
चरित्र	१४	२५७
सीधी नियुक्ति का तरीका	१७	२५७
पदोन्नति का तरीका	२३	२५८
वरीयता	२८	२६०
परीक्षाकाल	२६	२६०
वेतन	३२	२६१
अनुसूची	२६२

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें अथवा विभागीय आदेश

कर्तव्य की व्याख्या	२६२
अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता में शिक्षण	२६३
अध्ययन अवकाश	२६४
राजनैतिक पीड़ितों को शिक्षा सुविधा	२६८
सहायता अनुदान	२७०
गैर सरकारी निधियों का संचालन	२७३
केन्द्रीय समुद्रापरोय छात्रवृत्ति योजना	२७५
प्रशिक्षणकाल में त्यागपत्र	२७५
विभागीय अधिकारियों का दोरे का समय	२७६
विभागीय परीक्षाओं को प्रारम्भ करना	२७६
अध्यापकों आदि के प्रार्थनापत्रों को अग्रसारित करने के सिद्धांत	२७६
उत्तम परिणामों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना	२८०
प्रशिक्षण का उद्देश्य	२८१
अग्रिम अध्ययन जारी रखने की छूट	२८२
शिक्षा संचालकों में कार्यविभाजन	१८४
अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति	२८६
शिक्षा सेवा नियम में संशोधन	२८७
ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान	२८८
अध्ययन जारी रखने के लिए छूट	२८९
शिक्षाविभाग का कलेण्डर	२८९
निःशुल्क शिक्षा	२८९
पाठ्यपुस्तकें	२९८
शक्तियों का हस्तांतरण	२९९

	विषय	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
१९.	छात्र रजिस्टर	१७४
२०.	प्रवेश पंजिका	१७६
२१.	पाठशाला प्रवेश प्रार्थना पत्र	१७७
२२.	प्रगति पत्र	१७८
२३.	अनुबन्ध पत्र	१८०
२४.	शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शक्तियों का हस्तान्तरण	१८२
२७.	अनुसूचित जातियों की सूची	१८४
	सारिणी सम्बन्धित हिदायतें तथा सारिणी विवरण	१८८

राजस्थान असेैनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम १९६१

नवीन वेतन शृंखलाओं की सूची	२०५
विकल्प प्रपत्र	२०७
पदानुसार वेतन शृंखलायें	२०८
अध्यापकों को नवीन शृंखलानुसार वेतन देने के लिये विशेष नियम	२२६
वर्तमान से नवीन वेतन शृंखलाओं की परिवर्तन तालिका	२२६

राजस्थान असेैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनर्विचार) नियम १९६०

इन नियमों की प्रयुक्ति	२४३
सेवाओं का वर्गीकरण	२४३
निलम्बन	२४५
अनुशासन	२४६
बड़ी सजायें देने का तरीका	२४७
अपीलें	२४६
निलम्बन आदेश	२५०
अभियोग पत्र	२५२
अभियोग विवरण पत्र	२५३

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम १९६०

	धारा	
परिभाषायें	४	२५४
सेवा की संख्या	६	२५४
सेवाओं का प्रारम्भिक गठन	७	२५५
निर्मुक्ति के माध्यम	८	२५५

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं अनुभव	१३	२५६
चरित्र	१४	२५७
सीधी नियुक्ति का तरीका	१७	२५७
पदोन्नति का तरीका	२३	२५८
वरीयता	२८	२६०
परीक्षाकाल	२६	२६०
वेतन	३२	२६१
अनुसूची	२६२

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें अथवा विभागीय आदेश

कर्तव्य की व्याख्या	२६२
अल्पसंख्यक वर्ग को मातृभाषा में शिक्षण	२६३
अध्ययन अवकाश	...	२६४
राजनैतिक पीड़ितों को शिक्षा सुविधा	२६८
सहायता अनुदान	२७०
गैर सरकारी निधियों का संचालन	२७३
केन्द्रीय समुद्रापरीय छात्रवृत्ति योजना	२७५
प्रशिक्षणकाल में त्यागपत्र	२७५
विभागीय अधिकारियों का दोरे का समय	२७६
विभागीय परीक्षाओं को प्रारम्भ करना	२७६
अध्यापकों आदि के प्रार्थनापत्रों को अग्रसारित करने के सिद्धांत	२७६
उत्तम परिणामों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना	२८०
प्रशिक्षण का उद्देश्य	२८१
अग्रिम अध्ययन जारी रखने की छूट	२८२
शिक्षा संचालकों में कार्यविभाजन	१८४
अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति	२८६
शिक्षा सेवा नियम में संशोधन	२८७
प्रीप्तावकाश के वेतन का भुगतान	२८८
अध्ययन जारी रखने के लिए छूट	२८९
शिक्षाविभाग का कलेण्डर	२८९
निःशुल्क शिक्षा	२८६
पाठ्यपुस्तकें	२९८
शक्तियों का हस्तांतरण	२९९

छात्रों से शुल्क की वसूली	३०३
खेलकूद के लिए छात्रवृत्ति	३०४
नये विषय खोलना व छात्रों का प्रवेश	३०७
नया पाठ्यक्रम चालू करना	३०९
अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता	३११
निःशुल्क शिक्षा की सुविधा	३१३
विद्यालयों को स्तर वृद्धि के सिद्धांत	३१४
प्राइवेट पार्टियों को स्कूल भवन देना	११७
परिपत्र व फाइलें ठीक तरह रखना	११७
अध्यापिकाओं को क्वार्टर	३२०
२ वर्ष से कम समय तक रहने वालों का स्थानान्तरण	३२१

राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स आचरण नियम

	नियम	पृष्ठ
उपहार आदि देना	२	३२३
अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य	२अ	३२४
रुपया उधार देना	८	३२५
सम्पत्ति का क्रय विक्रय	९	३२६
व्यक्तिगत व्यापार अथवा नियोजन	१४	३२८
शिक्षा संस्था में प्रवेश	४ब	३२८
कर्जदारी	१५	३२९
सरकारी सूचना देना	१६	३३०
समाचार पत्रों से संबंध	१७	३३०
सरकारी अलोचना	१९	३३१
राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना	२१	३३२
प्रदर्शन तथा हड़ताल	२२ अ	३३३
संघों की सदस्यता	२३	३३३
अवकाश प्राप्त कर्मचारी	२३	३३३
राजस्थान सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों) को छत्र-वृत्ति देने सम्बन्धी नियम, १९६२	३३४

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये राजस्थान

सहायता अनुदान नियम सन् १९६३

संक्षिप्त नाम तथा परिभाषाएँ

१

३४५

विषय	पेरा संख्या	पृष्ठ संख्या
संस्थाओं का वर्गीकरण	२	३४६
अनुदान के लिये शर्तें	३	३४७
कर्मचारियों की सेवा शर्तें	४	३५०
वार्षिक पुनरावृत्त अनुदान का निर्धारण	५	३५१
स्वीकृत खर्च	६	३५४
अनुदान में कमी, वापसी, रोकना आदि	१०	३५८
प्रबन्ध मण्डलों का निर्माण	३६१
शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन के नियम	..	३६२
एकरार नामों का प्रपत्र	३६३
परिशिष्ट ४	३६६
परिशिष्ट ५	३६८
परिशिष्ट ६	३७३
परिशिष्ट ७		३७७

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १९६४

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	१	३७९
परिभाषाएँ	२	३७९
प्राथमिक शिक्षा के लिये योजना	३	३८०
निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य होना	४	३८१
सहायताार्थ अनुदान	५	३८१
बालकों की सूची तैयार करने का शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य	६	३८२
उपस्थिति प्राधिकारी	७	३८२
माता पिता का उत्तरदायित्व	८	३८२
अनुपस्थिति के लिये युक्ति आधार	१०	३८२
प्राथमिक या मानसिक रूप से हीन बालकों के लिये विशेष शाला	११	३८३
उपस्थिति आदेश	१२	३८३
प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क होना	१५	३८४
न्यायालयों की प्रक्रिया	२१	३८५
नियम बनाने की शक्ति	२७	३८६
निरसन	२८	३८८

राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

अध्याय १

१. राजस्थान में स्थित शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम सरकार के आदेश संख्या एफ० २१(३४) वो० दिनांक १३-३-१९५७ में प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार जारी किये गये हैं। इन नियमों को सामूहिक रूप से “राजस्थान एज्युकेशन कोड” के नाम से पुकारा जायेगा।

२. इस कोड के परिशिष्ट (Appendices) इस कोड के ही भाग समझे जावेंगे तथा वे कोड की ही भांति प्रभावशील होंगे।

टिप्पणी:—इस कोड के साथ में दिये गये परिशिष्ट में जो भी आदेश या व्यवस्थायें दी गई हैं, उनका भी शिक्षा संस्थाओं को उसी प्रकार पालन करना पड़ेगा जैसे कि इस कोड के नियमों का होना चाहिये।

३. सरकार की स्वीकृति से “शिक्षा-संचालक” किसी क्षेत्र विशेष में स्थित संस्थाओं या संस्था के लिये किसी भी नियम को लागू करने से निवृत्त कर सकेंगे।

टिप्पणी:—यद्यपि ये नियम सब शिक्षण संस्थाओं पर समान रूप से लागू होंगे किन्तु यदि शिक्षा संचालक चाहे तो किसी संस्था विशेष को इन नियमों के पालन करने से मुक्त रख सकेंगे किन्तु ऐसा आदेश देने से पूर्व शिक्षा संचालक को राज्य सरकार की स्वीकृति अवश्य लेनी पड़ेगी।

४. सरकार की स्वीकृति से शिक्षा संचालक “स्टैंडिंग आर्डर्स” के रूप में इस कोड से सम्बन्धित कोई भी निर्णय (Ruling) अथवा अर्थ निरूपण (Interpretation) जो कि उन्हें आवश्यक प्रतीत हो, जारी कर सकेंगे तथा वे स्टैंडिंग आर्डर्स भी कोड की ही भांति प्रभावशील होंगे।

नोट:—आवश्यकतानुसार, संचालक, आदेश या गश्तीपत्र (Circulars) जारी कर सकेंगे जो कि इस कोड की भांति मान्य होंगे।

टिप्पणी:—इस कोड से सम्बन्ध रखने वाली समस्त आज्ञायें, गश्तीपत्र, स्टैंडिंग आर्डर्स जो कि संचालक आवश्यकतानुसार समय समय पर जारी करेंगे, का भी शिक्षण संस्थाओं को वैसा ही पालन करना पड़ेगा, जैसा कि इस कोड का।

५. राजस्थान राज्य में सम्मिलित होने वाली समस्त देशी रियासतों द्वारा लागू किये गये तत्सम्बन्धित समस्त कोड तथा अन्य नियम, आज्ञायें, सूचनायें जो कि इस कोड के अन्तर्गत आने वाले विषयों में सम्बन्धित हों, इस कोड द्वारा रद्द समझी जावेंगी।

टिप्पणी:—इस धारा का अर्थ यह है कि शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित देशी रियासतों (Covenanted States) के सब कोड, नियम आदि तथा १३-३-१९५७ तक इन विषयों पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई समस्त आज्ञायें, इस कोड के प्रभाव में आने के साथ रद्द समझी जायेंगी तथा उन सबके स्थान पर एक मात्र यह “राजस्थान शिक्षा कोड” जारी समझा जावेगा।

(१) यह कोड दिनांक १३-३-१९५७ में प्रभावशाली होगा ।

(२) जब तक प्रमंग से दूसरा अभिप्राय नहीं निकले, इन कोड के नियमः—

(अ) सार्वजनिक प्रवन्ध के अन्तर्गत सभी शिक्षा संस्थाओं तथा ।

(ब) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्रदत्त (Recognised & Aided) निजी क्षेत्र की समस्त शिक्षण संस्थाओं, पर लागू होंगे ।

नोटः—इस कोड के नियम सभी शिक्षण संस्थाओं, चाहे वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्रदत्त हों और सार्वजनिक प्रवन्ध या निजी क्षेत्र में कहीं भी हों, पर समान रूप में लागू होंगे ।

टिप्पणीः—इस धारा का अभिप्राय यह है कि यह कोड सभी शिक्षण संस्थाओं पर समान रूप में लागू होगा और जो संस्थाएँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या जिनको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, वे भी इन कोड के नियमों का पालन करना पड़ेगा । अर्थात् निजी क्षेत्र की संस्थाएँ यदि इन कोड के परिपालन के उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहें तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगी । जहाँ तक इस कोड में उल्लिखित नियमों के लागू होने का प्रश्न है, सरकारी तथा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ शिक्षा विभाग की दृष्टि में एक समान होंगी ।

परिभाषायें

जब तक कि प्रमंग से किसी अन्य अर्थ का आशय न हो, इन कोड में निम्नलिखित परिभाषायें लागू होंगीः—

(१) सहायक संचालिका में अभिप्राय है राज्य के बालिका विद्यालयों (Girls Schools) की कोई भी सहायक संचालिका ।

(२) विभाग (Department) में तात्पर्य राजस्थान शिक्षा-विभाग, जो कि शिक्षा संचालक के अधीन है और जिसमें राजस्थान के शिक्षा सचिव द्वारा प्रबन्धित स्नातक तथा स्नातकोत्तर (Degree and post graduate) कालेज भी शामिल हैं, में है ।

(३) स्नातक महाविद्यालय (Degree College) में उस संस्था का अभिप्राय है जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और जो कि उसकी किसी भी स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था करती हो ।

(४) संचालक में अभिप्राय राजस्थान के शिक्षा संचालक से है और उप संचालक का तात्पर्य भी राज्य के शिक्षा-विभाग के किसी भी उप-संचालक से है ।

(५) सरकार से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है ।

(६) अनिर्भावक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिन्ने कि अपने संरक्षित छात्र के नवाचरण तथा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले ली हो ।

(७) हाईस्कूल में उच्चतर माध्यमिक शालाएँ तथा बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शालाएँ भी सम्मिलित हैं ।

(८) छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent) से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कि किसी छात्रावास की व्यवस्था देखता हो, फिर चाहे वह किसी भी पद से क्यों नहीं पुकारा जाता हो ।

(६) (घ) शिक्षण संस्थायें विशेषतया दो वर्गों में विभाजित हैं—

(i) मान्यता प्राप्त (Recognised) तथा

(ii) Un recognised अर्थात् जिन्हें मान्यता नहीं मिली हैं

मान्यता प्राप्त संस्थायें वे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विभाग से इस सम्बन्ध में बनाये हुये नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त करली हो और जो कि इस नियमों का अब भी पालन कर रही हो तथा जो दक्षता (Efficiency) के आवश्यक स्तर को बनाये रखती हो, जिनका कभी भी निरीक्षण हो सकता है और जहां के छात्र माधारणतया विश्वविद्यालयों अथवा विभाग द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अध्ययन करते हैं, होगी । अन्य सभी संस्थायें अमान्य (Un recognised) होगी ।

(व) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें भी पुनः दो भागों में विभक्त हैं:—

(i) एक तो वे हैं जो कि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) के प्रबन्ध में हो और जो कि सार्वजनिक प्रबन्ध की संस्थाओं के नाम से जानी जाती है ।

(ii) दूसरी वे हैं जो कि निजी प्रबन्ध में होती हैं ।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें, जो कि निजी प्रबन्ध में हैं, के पुनः विभाग किये जा सकते हैं, जैसे कि सहायता प्राप्त अथवा जिन्हें सरकार से सहायता नहीं मिल रही हो ।

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें भी उनमें होने वाले शिक्षण के स्तर के अनुसार पुनः निम्नानुसार विभक्त हैं:—

(i) कालेज शिक्षा—स्नातक तथा स्नातकोत्तर इन्टरमीडियेट, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के कालेज ।

(ii) प्राच्य शिक्षा (Oriental Education)—संस्कृत कालेज, पाठशालाएँ, प्राथमिक तथा शिशु शालाएँ ।

(iii) व्यवसायिक स्कूल तथा विशेष प्रकार के स्कूल और संस्थायें ।

(द) सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएँ उनमें दिये जाने वाले शिक्षण के स्तर के अनुसार मानी जायेंगी ।

(अ) स्नातकोत्तर कक्षाएँ जहां कि एम० ए०, एम० एस० सी०, एम० काम तथा विश्व-विद्यालय की अन्य स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये शिक्षा दी जाती हो ।

(ब) स्नातक स्तरीय कक्षाएँ—वे कक्षाएँ जो बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम, बी० एस० सी० (कृषि) तथा विश्वविद्यालय की अन्य उपाधियों के लिये शिक्षण देती हो ।

(स) व्यवसायिक कक्षाएँ (Professional Classes)

(द) इन्टरमीडियेट कक्षाएँ—कक्षा ११ तथा १२ ।

(य) मिडिल कक्षाएँ—कक्षा ६ से ८ तक ।

(र) प्राथमिक कक्षाएँ—कक्षा १ से ५ तक ।

(ल) शिशु कक्षाएँ—इनमें नर्सरी, किंडरगार्टन तथा मान्टेसरी कक्षाएँ शामिल हैं ।

(१०) निरीक्षक:—से अभिप्राय राज्य के किसी भी शाला-निरीक्षक से है ।

(११) व्यवस्थापक (Manager) से उस व्यक्ति से अभिप्राय है जो कि किसी संस्था का आर्थिक तथा सर्वसाधारण प्रबन्ध अपने हाथ में रखता हो ।

(१२) माडल स्कूल से उम स्कूल से तात्पर्य है जो कि शिक्षा के व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रदर्शन के लिये बनाई गई हो तथा जो कि अभ्यापिकाय/प्रशिक्षण केन्द्र (Teacher's Training School) में संलग्न हो।

(१३) प्राच्य विद्या के कालेज, स्कूल, संस्थाएँ जैसे कि संस्कृत कालेज, जिन में पढ़ने वाले छात्र प्राच्य विद्या (Oriental learning) की विभिन्न पाठ्याशुओं की परीक्षाओं जो कि विश्व-विद्यालय अथवा विभाग द्वारा स्वीकृत, निर्दिष्ट या मान्यता प्राप्त हो, के लिए शिक्षित किये जाते हैं।

(१४) प्राथमिक शालाओं में वे जानाएँ शामिल हैं जहाँ पर कि विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा १ से ५ तक का पूरा काम चलाया जाता हो, तथा इसमें कक्षा १ व २ या अधिक की शिशु शालाएँ भी सम्मिलित होंगी।

(१५) स्नातकोत्तर कालेज में अभिप्राय उस संस्था में है जो कि विश्वविद्यालय में सम्बद्ध हो और जो कि स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिये शिक्षा देती हो तथा जहाँ अनुसंधान कार्य के लिये सुविधायें हो।

(१६) पब्लिक स्कूल्स ऐसे स्कूल हैं जो कि "इन्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस" के सदस्य हैं।

(१७) प्रस्तोता (Registrar) से अभिप्राय प्रस्तोता, विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान से है।

(१८) छात्रवृत्ति से अभिप्राय धनराशि के उस सामयिक भुगतान से है जो कि निश्चित शर्तों पर एक निश्चित अवधि के लिये, किसी छात्र को अध्ययन जारी रखने के लिये, किया जाता हो।

(१९) "स्कूल मीटिंग" से अभिप्राय शिक्षा देने की उस लगातार अवधि से है जिसके कि प्रारम्भ में स्कूल में छात्रों की उपस्थिति साधारणतया ली जाती हो। माध्यमिक शालाओं में प्रतिदिन आमतौर पर दो "मीटिंग" होंगी।

(२०) माध्यमिक शालाओं से उन संस्थाओं का तात्पर्य है जिनका कि मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कक्षा से आगे इन्टरमीडियेट स्तर तक शिक्षा देना है। इनमें ऐसी संस्थाएँ भी शामिल हैं जो कि इस दृष्टि में मान्यता प्राप्त हों।

(२१) तब से अभिप्राय कुल १२ माह के भीतर भीतर की उस अवधि से है जिसमें कि नई कक्षाएँ बनने के बाद वह संस्था शिक्षण कार्य के लिये खुली रहती हो।

(२२) विशिष्ट शालाएँ (Special Schools) वे हैं जो कि किसी विशेष विधि द्वारा शिक्षा देती हों अथवा जो विश्वविद्यालय या विभाग द्वारा निर्धारित या स्वीकृत किसी व्यावसायिक या तकनीकी कोर्स में प्रशिक्षण या शिक्षण देती हो।

(२३) स्टैपेंड (Stipend) उस पारिश्रमिक को कहते हैं जो कि किसी अध्यापक या छात्र को कोई विशेष अध्ययन करने के लिये प्रेरित करने हेतु किन्हीं शर्तों पर दिया जावे।

(२४) (Term) से अभिप्राय लगातार कार्य करने की उस अवधि से है जिसमें एक शैक्षणिक वर्ष विभाजित किया जावे।

(२५) विश्वविद्यालय से अभिप्राय राजस्थान विश्वविद्यालय से है।

(२६) व्यावसायिक संस्थाएँ वे कालेज या कालेज के विभाग अथवा स्कूल या संस्थायें हैं जहाँ पर कि छात्र, विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, प्रदत्त अथवा स्वीकृत, कानून, चिकित्सा, शिक्षण, इन्जिनियरिंग, कृषि अथवा तकनीकी प्रशिक्षण को कोई विशेष शाखा की उपाधियों, प्रमाणपत्रों या डिप्लोमाओं के लिये अध्ययन करते हों ।

अध्याय २

विभागीय व्यवस्था

१. शिक्षा विभाग जिसको कि आगे 'विभाग' शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, राज्य में सभी शिक्षात्मक क्रियाओं की व्यवस्था एवं प्रवन्ध करने के लिये राजस्थान सरकार की शाखा (Agency) है ।

२. राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्थायें जिनके द्वारा विभाग का शैक्षणिक कार्य चल रहा है निम्न प्रकार है :—

- (अ) राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकार में सभी स्नातकोत्तरीय तथा स्नातकीय महा-विद्यालय ।
- (ब) विभाग या विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक परीक्षाओं हेतु तैयारी करने वाले संस्कृत विद्यालय ।
- (स) व्यावसायिक विद्यालय ।
- (द) विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय ।
- (य) विश्वविद्यालय के अधिकार के इन्टरमीडियेट (Intermediate Colleges) विद्यालय ।
- (फ) भारतीय सार्वजनिक स्कूल संघ की सदस्यता प्राप्त सार्वजनिक स्कूल जो कि विभाग या विश्वविद्यालय या उनके द्वारा स्वीकृत किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिये छात्रों को अध्ययन कराता हो ।
- (व) अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल जो छात्रों को विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र, बेसिक एस. टी. सी. की परीक्षाओं हेतु छात्रों को तैयार करता हो ।
- (र) हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक तथा बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें जो विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वीकृत हों ।
- (त) विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यमिक तथा प्राथमिक पाठशालायें ।
- (ह) संस्कृत पाठशालायें जो कि विभाग द्वारा स्वीकृत संस्कृत परीक्षाओं में बैठने के लिये छात्रों को तैयार करती है ।
- (ग) ब्याधिग्रस्त (handicapped) प्राप्त बच्चों के लिये पाठशालायें ।
- (न) फाइन आर्ट, संगीत एवं हस्तकला के लिये पाठशालायें ।
- (त) केन्द्रीय, खण्डीय (Divisional) तथा जिला स्तरीय पुस्तकालय ।
- (थ) अन्य पुस्तकालय तथा वाचनालय ।
- (ज) समाज शिक्षा केन्द्र !

(म) विभिन्न स्वीकृत हिन्दी परीक्षाओं के लिये छात्रों को तैयारी कराने वाली संस्थाएँ ।

३. संचालक शिक्षा जिसको आगे संचालक ही कहा जायेगा केवल ऐसी शिक्षा को छोड़कर, जो शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में रहे तथा जो इसकी विशिष्टात्मक नीति को प्रभावशील करने के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी रहे, वह विभागाध्यक्ष रहेगा । अतिरिक्त, उप तथा सहायक संचालकों द्वारा उसे सहायता मिलेगी तथा अन्य ऐसे अधिकारियों द्वारा भी उसे सहायता मिलेगी जो कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ।

टिप्पणी:—ऐसी शिक्षण संस्थाएँ जो कि सीधी सरकार के अधीन हों, उनको छोड़कर बाकी सबके लिये शिक्षा संचालक की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है । सरकार की शिक्षा नीति को वह कार्यान्वित करेगा तथा उसे इस कार्य में अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तथा सहायक संचालक से भी सहयोग मिलेगा । इनके अलावा सरकार यदि उसकी सहायता के लिये किन्हीं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहे तो वे भी की जा सकेंगी ।

४. शैक्षणिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य को कई शैक्षणिक वृत्तों (Circles) में विभाजित किया गया है । इनमें से प्रत्येक वृत्त, निरीक्षक शिक्षा विभाग के आधीन है तथा उसे उप-निरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षकों से सहयोग मिलता है । कुछ छोटे जिले उप निरीक्षक के अधीन रहेंगे जो कि जिले का इन्चार्ज रहेगा तथा जिसके कि सहयोग के लिये सहायक उप निरीक्षक रहेंगे । ये वृत्त पुनः श्रेणियों (Ranges) में संगठित होंगे जो कि उप शिक्षा संचालक के अधीन होंगे ।

टिप्पणी:—शिक्षा की दृष्टि से समूचा राजस्थान राज्य कई श्रेणियों (Ranges) में विभाजित है जो कि उप शिक्षा संचालक के अधीन है । ये (Ranges) पुनः कई वृत्तों (Circles) में विभाजित है । ये वृत्त जिन्हें कि शिक्षा-प्रशासन की दृष्टि से जिलों के नाम से भी सम्बन्धित किया जाता है साधारण तथा एक निरीक्षक के अधीन होते हैं किन्तु यदि ये जिले छोटे हैं तो वहाँ उप-निरीक्षक ही उनके इन्चार्ज होंगे । निरीक्षक के सहायतार्थ उप-निरीक्षक तथा सहायक उप-निरीक्षक भी होंगे ।

५. संचालक, राज्य में स्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अलावा उन सब संस्थाओं के जो कि सीधे शिक्षा सचिव के नियंत्रण में हैं, पर साधारणतया नियंत्रण रखेगा और उसका सरकार द्वारा निविष्ट संस्थाओं पर सीधा नियन्त्रण रहेगा ।

६. उपशिक्षा संचालक साधारणतया प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चविद्यालयों पर नियंत्रण रखेगा और अपने क्षेत्र के इन्टर कालेजों तथा उप-निरीक्षकों द्वारा नियंत्रित जिलों में स्थित उच्च-माध्यमिक शालाओं का विशिष्ट अधिकार भी रखेगा ।

टिप्पणी:—जहाँ पर जिला निरीक्षक के स्थान पर केवल उप निरीक्षक ही जिले के इन्चार्ज होंगे वहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शालाएँ (Higher Secondary Schools) सीधी उप शिक्षा संचालक के अधीन होगी । इन्टर कालेज तो अनिवार्य रूप से उनके सीधे अधीन रहेंगे ।

७. उच्चविद्यालय (High School) के स्तर तक की सभी शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य वृत्त में स्थित पुरुषों के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों के नियन्त्रण तथा निगरानी का कार्य निरीक्षक के अधीन रहेगा जो कि इस कार्य में उप तथा सहायक उप-निरीक्षकों से सहयोग लेंगे ।

८. वालिकाओं की समस्त शिक्षण संस्थाओं तथा महिलाओं के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों का नियंत्रण सहायक संचालिका के हाथ में रहेगा जिसे कि निरीक्षिकाओं से भी सहायता मिलती रहेगी ।

९. संस्कृत पाठशालायें सीधी संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के अधीन रहेगी जिसकी कि सहायता के लिये उप निरीक्षक होंगे ।

१०. समाज शिक्षा का समस्त कार्य तथा पुस्तकालय समाज शिक्षा के उप संचालक के सीधे अधीन होंगे । इस कार्य में उसे जिले के समाज शिक्षा अधिकारी तथा सामुदायिक योजना और एन० ई० एस० ब्लाक के समाज शिक्षा संगठन से सहयोग मिलेगा ।

११. विभागाधीन सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन विभागीय परीक्षाओं के प्रस्तोता (Registrar) करेंगे । उप प्रस्तोता उनकी सहायता करेंगे ।

१२. ऊपर वर्णित विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्य व शक्तियां तृतीय अध्याय में दिये गये हैं ।

अध्याय ३

अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

१. विभाग के विभिन्न अधिकारी ऐसी शक्तियों का पालन करेंगे जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत शक्तियों की सूची (Schedule of Powers) के अनुसार उनको प्रदान की गई हो । (ये सब Appendix के रूप में दी गई है ।) विभाग के प्रशासन एवं संगठन के सम्बन्ध में वे कुछ विशेष शक्तियों एवं दायित्वों का पालन करेंगे जो कि यहां पर आगे उल्लिखित हैं ।

२. शिक्षा के उस भाग जो कि शिक्षा सचिव के द्वारा सीधा नियंत्रित है, को छोड़कर, समस्त शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन के लिये विभाग के प्रमुख होने के नाते संचालक उत्तरदायी है । वह निरीक्षण करने वाले स्टाफ पर नियंत्रण रखेगा और उसे:—

- (अ) आम प्रशासनिक सिद्धान्तों को बतलाते हुए आदेश, सूचनार्थ तथा गश्तीपत्र जारी करने या ऐसे आदेश जारी करने, जो कि सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत शिक्षा नीति के विषयों में सम्बन्धित हैं;
- (ब) राज्य में उसके प्रशासनिक नियन्त्रण में रहने वाली किसी भी शिक्षण संस्था को निरीक्षण करने;
- (स) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एम० एड० के प्रशिक्षण के लिये अध्यापकों का चुनाव करने तथा उन्हें (Stipend) स्वीकृत करने ।
- (द) सरकार की स्वीकृति से निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक संचालक, सहायक संचालिका, उप निरीक्षिकायें तथा इनके समान स्तर के अन्य अधिकारियों के प्रधान कार्यालय (Headquarter) निश्चित करने और अपनी स्वयं की इच्छानुसार सहायक उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षिकाओं, समाज शिक्षा के गाईड्स एवं आर्गेनाइजर तथा समान पदों पर आसीन अन्य अधिकारियों के प्रधान कार्यालय (Headquarter) निश्चित करने;

- (ग) विभागीय बजट में स्वीकृत धन राशि की (Contingent) आकस्मिक तथा अन्य खर्च के लिये अपने अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थाओं में उनकी आवश्यकतानुसार वितरित करने;
- (फ) सरकार के आदेशानुसार नई संस्थाएँ (प्राथमिक, शिशु, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक, अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र तथा इंटरमीजियेट कालेज) खोलने तथा बजट में किये गये प्रावधान में से स्वीकृत भाग के अनुसार उन पर किये गये खर्च को वहन करने, (इंटरमीजियेट कालेज तथा हाईस्कूल के सम्बन्ध में इन संस्थाओं को प्रारम्भ करने से पहले बोर्ड या विश्वविद्यालय से आवश्यक मान्यता या सम्प्रदत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी) ।
- (ह) सरकार की स्वीकृति से माध्यमिक स्तर की किसी भी संस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने और यदि आवश्यक होवे तो ऐसी संस्था को बन्द करने, (प्राथमिक शालाओं का खोलना, बन्द करना अथवा उनका स्थान बदलना संचालक की रुचि के अनुसार होगा ।)
- (व) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता दी जाने वाली संस्थाओं को सहायता की राशि स्वीकार करने;
- (ज) (Shedule of Powers) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नये भवनों के निर्माण अथवा वर्तमान भवनों की मरम्मत या उनमें वृद्धि करने की स्वीकृति देने;
- (क) सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने;
- (ल) शिक्षण संस्थाओं को गर्मो व सर्दों की दृष्टियों तथा संक्रामक रोगों के आक्रमण या किसी प्रकृति-प्रकोप की स्थिति में आवश्यक अवधि के लिये बन्द करने तथा उस अवधि में इन संस्थाओं के अध्यापकों को अन्यत्र विशेष कार्य पर लगाने;
- (म) शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक कारणों जो कि वह अपने विचार से उचित समझें, में वर्ष में विशेष अवकाश जो कि दस दिन से अधिक नहीं होगा, प्रदान करने, (उच्चाधि-कारियों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदार्पण को ऐसी छुट्टी देने का अवसर नहीं बनाना चाहिये;)
- (न) अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ग्रीष्मावकाश में रोकने तथा उसे अन्य कार्य के लिये नियुक्त करने;
- (प) निरीक्षण करने वाले समस्त अधिकारियों के यात्रा करने के दिनों की संख्या निर्धारित करने तथा उनके यात्रा कार्यक्रमों, यात्रा व्ययों तथा उप-संचालकों के निरीक्षक प्रतिवेदन को मंगाने व उन्हें स्वीकार करने;
- (र) पुस्तकालयों व वाचनालयों को स्थापित करने व आधारण तथा विशेष रुचि के समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं को शुल्क भेजने;
- का अधिकार होगा ।

नोट :—सरकार के आदेश तथा मार्ग दर्शन की सीमा के अन्तर्गत संचालक, विभागाध्यक्ष होने के नाते निर्देशक, प्रशासन, संगठन, निरीक्षण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

टिप्पणी:—इस कोड के बनने के पश्चात शिक्षा विभाग के संचालक का कार्य दो भागों में बांट दिया गया है । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग संचालक बना दिया गया है तथा कालेज शिक्षा (Director of Primary & Secondary Education)

का कार्यालय दीकानेर में है, जबकि संचालक कालेज शिक्षा का कार्यालय जयपुर में ही है।

दोनों संचालकों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है जिसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के अन्त में दिये गये सरकारी आदेशों में दी गई है।

(३) संचालक अपनी यात्राओं के कार्यक्रमों तथा प्रतिवेदनों को नियमित रूप से सरकार के शिक्षा विभाग के पास भेजेगा।

४. संचालक उसके अधीन विविध संस्थाओं का वर्ष में एक बार अवश्य दौरा करेगा। वह अपने कार्य क्षेत्र की अन्य प्रकार की संस्थाओं में से यथेष्ट संख्या में उन संस्थाओं का प्रतिवर्ष दौरा करेगा तथा उप-संचालकों के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेगा। प्रतिवर्ष लगभग एक तिहाई निरीक्षणालयों का भी वह निरीक्षण करेगा। ताकि शिक्षा की प्रगति एवं दक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तथा अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्य की निगरानी कर सके।

शिक्षा-उपसंचालक

५. प्रादेशिक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि या तो उन्हें सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई हो, अथवा उन्हें सौंपी गई हो। वे निम्न कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(अ) ऐसी संस्थाएँ, जो कि विशेष तौर पर सरकार द्वारा उनके अधीन रखी गई हो तथा निरीक्षकों, जिलों के इन्चार्ज उप-निरीक्षकों के कार्यालयों का एक वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के अलावा, वे अपने क्षेत्र की अन्य सब प्रकार की संस्थाओं का भी निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे ताकि वे शिक्षा की प्रगति एवं अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्य के बारे में जानकारी रख सकें।

(ब) वे माह में दस दिन दौरे पर रहेंगे।

(स) वे प्रत्येक Term के लिये अपने दौरे का कार्यक्रम पहले से ही बना लेंगे तथा उसे शिक्षासंचालक के पास स्वीकृति के लिये भेजेंगे।

(द) वे अपने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक डायरीज संचालक को उचित कार्यवाही के लिये भेजेंगे।

(य) वे निर्धारित प्रपत्र पर प्रति वर्ष जून के माह में अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन संचालक को भेजेंगे।

(फ) वे निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष जनवरी माह में अपने अधीन कार्य करने वाले राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में एक वार्षिक गुप्त (Confidential) प्रतिवेदन संचालक को प्रेषित करेंगे।

(ह) वे शाला-निरीक्षकों की डायरीज तथा उनके दौरे के कार्यक्रम मंगावेंगे तथा उन्हें स्वीकार करेंगे।

(व) सरकारी आदेशों के अनुसार वे अपने क्षेत्र में नये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोलने का व्यवस्था करेंगे और इस निमित्त स्वीकृत बजट प्रावधान में से उनपर होने वाले व्यय का प्रबंध करेंगे।

- (ग) विभागीय बजट में स्वीकृत धन राशि को (Contingent) आकस्मिक तथा अन्य खर्च के लिये अपने अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थाओं में उनकी आवश्यकतानुसार वितरित करने;
- (फ) सरकार के आदेशानुसार नई संस्थाएँ (प्राथमिक, मिश्र, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक, अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र तथा इन्टरमीडियेट कालेज) खोलने तथा बजट में किये गये प्रावधान में से स्वीकृत माप के अनुसार उन पर किये गये खर्च को वहन करने, (इन्टरमीडियेट कालेज तथा हाईस्कूल के सम्बन्ध में इन संस्थाओं को प्रारम्भ करने से पहले बोर्ड या विश्वविद्यालय से आवश्यक मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त करनी पड़ेगी) ।
- (द) सरकार की स्वीकृति से माध्यमिक स्तर की किसी भी संस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने और यदि आवश्यक होवे तो ऐसी संस्था को बन्द करने, (प्राथमिक शालाओं का खोलना, बन्द करना अथवा उनका स्थान बदलना संचालक की रक्ति के अनुसार होगा ।)
- (व) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता दी जाने वाली संस्थाओं को सहायता की राशि स्वीकार करने;
- (ज) (Shedule of Powers) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नये भवनों के निर्माण अथवा वर्तमान भवनों की मरम्मत या उनमें वृद्धि करने की स्वीकृति देने;
- (क) सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने;
- (ल) शिक्षण संस्थाओं को गर्मी व सर्दी की छुट्टियों तथा संक्रामक रोगों के आक्रमण या किसी प्रकृति-प्रकोप की स्थिति में आवश्यक अवधि के लिये बन्द करने तथा उस अवधि में इन संस्थाओं के अध्यापकों को अन्यत्र विशेष कार्य पर लगाने;
- (म) शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक कारणों जो कि वह अपने विचार से उचित समझें, में वर्ष में विशेष अवकाश जो कि दस दिन में अधिक नहीं होगा, प्रदान करने, (उच्चाधि-कारियों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पदार्पण की ऐसी छुट्टी देने का अवसर नहीं बनाना चाहिये;)
- (न) अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ग्रीष्मावकाश में रोकने तथा उसे अन्य कार्य के लिये नियुक्त करने;
- (प) निरीक्षण करने वाले समस्त अधिकारियों के यात्रा करने के दिनों की सख्या निर्धारित करने तथा उनके यात्रा कार्यक्रमों, यात्रा डायरियों तथा उप-संचालकों के निरीक्षक प्रतिवेदन की मंगाने व उन्हें स्वीकार करने;
- (र) पुस्तकालयों व वाचनालयों को स्थापित करने व साधारण तथा विशेष रक्ति के समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं को शुल्क भेजने;

का अधिकार होगा ।

नोट :—सरकार के आदेश तथा मार्ग दर्शन की सीमा के अन्तर्गत संचालक, विभागाध्यक्ष होने के नाते निर्देशक, प्रशासन, संगठन, निरीक्षण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

टिप्पणी:—इस कोड के बनने के पश्चात् शिक्षा विभाग के संचालक का कार्य दो भागों में बांट दिया गया है । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग संचालक बना दिया गया है तथा कालेज शिक्षा (Director of Primary & Secondary Education)

का कार्यालय धीकानैर में है, जबकि संचालक कालेज शिक्षा का कार्यालय जयपुर में ही है।

दोनों संचालकों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है जिसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के अन्त में दिये गये सरकारी आदेशों में दी गई है।

(३) संचालक अपनी यात्राओं के कार्यक्रमों तथा प्रतिवेदनों को नियमित रूप से सरकार के शिक्षा विभाग के पास भेजेगा।

४. संचालक उसके अधीन विभिन्न संस्थाओं का वर्ष में एक बार अवश्य दौरा करेगा। वह अपने कार्य क्षेत्र की अन्य प्रकार की संस्थाओं में से यथेष्ट संख्या में उन संस्थाओं का प्रतिवर्ष दौरा करेगा तथा उप-संचालकों के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेगा। प्रतिवर्ष लगभग एक तिहाई निरीक्षणालयों का भी वह निरीक्षण करेगा। ताकि शिक्षा की प्रगति एवं दक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तथा अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्य की निगरानी कर सके।

शिक्षा-उपसंचालक

५. प्रादेशिक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि या तो उन्हें सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई हो, अथवा उन्हें सौंपी गई हो। वे निम्न कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(अ) ऐसी संस्थायें, जो कि विशेष तौर पर सरकार द्वारा उनके अधीन रखी गई हो तथा निरीक्षकों, जिलों के इन्चार्ज उप-निरीक्षकों के कार्यालयों का एक वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के अलावा, वे अपने क्षेत्र की अन्य सब प्रकार की संस्थाओं का भी निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे ताकि वे शिक्षा की प्रगति एवं अन्य निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्य के बारे में जानकारी रख सकें।

(ब) वे माह में दस दिन दौरे पर रहेंगे।

(स) वे प्रत्येक Term के लिये अपने दौरे का कार्यक्रम पहले से ही बना लेंगे तथा उसे शिक्षासंचालक के पास स्वीकृति के लिये भेजेंगे।

(द) वे अपने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक डायरीज संचालक को उचित कार्यवाही के लिये भेजेंगे।

(य) वे निर्धारित प्रपत्र पर प्रति वर्ष जून के माह में अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन संचालक को भेजेंगे।

(फ) वे निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष जनवरी माह में अपने अधीन कार्य करने वाले राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में एक वार्षिक युक्त (Confidential) प्रतिवेदन संचालक को प्रेषित करेंगे।

(ह) वे शाला-निरीक्षकों की डायरीज तथा उनके दौरे के कार्यक्रम मंगावेंगे तथा उन्हें स्वीकार करेंगे।

(व) सरकारी आदेशों के अनुसार वे अपने क्षेत्र में नये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे और इस निमित्त स्वीकृत बजट प्रावधान में से उनपर होने वाले व्यय का प्रबंध करेंगे।

- (क) सरकार द्वारा स्वीकृत शक्तियों के अनुसार उनके स्वयं के अधिकार के अन्तर्गत अपने वाले वर्तमान भवनों की मरम्मत, उनमें ख़दोवदल अथवा वृद्धि करने तथा नये भवनों का निर्माण करने की स्वीकृति देंगे ।
- (ल) वे तत्संबंधित नियमों के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण के लिये प्रत्याशियों का चयन करेंगे तथा नियमानुसार उन्हें पारिधर्मिक (Stipend) दिये जाने की स्वीकृति देंगे ।
- (य) सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वे माध्यमिक (Middle) शालाओं को मान्यता प्रदान करेंगे ।
- (न) उन्हें संक्रमण रोग अथवा प्रकृति प्रकोप के कारण एक मौखणिक वर्ष में अपने अधीनस्थ संस्थाओं को ५ दिन का विशेष अवकाश घोषित करने का अधिकार होगा, वशत कि इस प्रकार की छुट्टियों की कुल अवधि जिसमें कि संचालक द्वारा प्रदत्त अवकाश भी सम्मिलित है, एक शिक्षण वर्ष में दस दिन से अधिक नहीं होगी ।
- (प) वे अपने स्वयं के कार्यालयों तथा अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों के कार्यालयों का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करेंगे ।

टिप्पणी:—उप शिक्षा संचालक माह में दस दिन दौरा करेंगे । अपने अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थाओं का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे । अपने निरीक्षण का प्रतिवेदन संचालक को भेजेंगे । अपने अधीनस्थ अधिकारियों के दोरे के कार्यक्रम स्वीकार करेंगे, एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिये प्रत्याशियों का वे चयन करेंगे । माध्यमिक शालाओं को वे मान्यता प्रदान करेंगे । वे आकस्मिक कारणों से एक वर्ष में ५ दिन का विशेष अवकाश अपनी अधीनस्थ शालाओं को प्रदान कर सकेंगे । अपने अधिकारों के अनुसार भवनों की मरम्मत, वृद्धि, निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे ।

निरीक्षकों, उप निरीक्षकों व इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट्स

१. निरीक्षक के मुख्य अधिकार व कर्तव्य निम्न हैं :—

- (अ) अपने क्षेत्र में छात्रों के लिये प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय शिक्षा के निरीक्षण के लिये सामान्यतया उत्तरदायी रहना ।
- (ब) अपने अधीन उप निरीक्षक तथा सहायक उपनिरीक्षक के कार्य का निरीक्षण करना तथा उस पर नियन्त्रण रखना ।
- (स) अपने अधीनस्थ क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं के निरीक्षण में, यदि आवश्यकता हो तो संचालक एवं उप-संचालक की सहायता करना ।
- (द) प्रतिवर्ष कम से कम १०% प्राथमिक शालाओं तथा २०% माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण करना जिससे कि अपने सहायक निरीक्षण अधिकारियों के कार्य की जांच की जा सके तथा उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन दिया जा सके ।
- (य) साल में कम से कम १२० दिवस दौरा करना तथा हर माह १० दिवस से कम दोरे पर न होना ।
- (फ) प्रत्येक बार अपना अग्रिम यात्रा कार्यक्रम काफी समय पूर्व तैयार करना तथा उसे उप संचालक के पास स्वीकृति हेतु भेजना । वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तथा मासिक यात्रा विवरण की प्रतिलिपियां उप-संचालक के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजेंगे ।

- (व) नियमों तथा विभागीय आदेशानुसार अपने अधीनस्थ अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति स्थानान्तरण, वेतन वृद्धि, अवकाश, निलम्बन, हटाना आदि के विषय में उप संचालक को सिफारिश करना ।
- (ह) उप निरीक्षकों तथा सहायक उप निरीक्षकों के यात्रा कार्यक्रमों तथा उनके यात्रा विवरणों की जांच करना तथा स्वीकार करना ।
- (क) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों को खोलने व बन्द करने के बारे में उप संचालक को अपनी सम्मति भेजना ।
- (ल) अपने अधीनस्थ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच करना तथा उन पर अपनी टिप्पणी लिखना ।
- (म) शैक्षणिक वर्ष में अपने अधीनस्थ संस्थाओं में व्यापक रोग अथवा अन्य कारणों से ३ दिवस तक का विशिष्ट अवकाश स्वीकृत करना । ऐसी छुट्टियां उन सब छुट्टियों को मिलाकर जो सभी निरीक्षण तथा निर्देशन करने वाले अधिकारियों ने दी हैं; उस शैक्षणिक सम्बन्धी वर्ष में १० से अधिक नहीं होंगी । निरीक्षक भी फिर किसी भी विशिष्ट पुरुष के निरीक्षण के कारण कोई विशेष अवकाश प्रदान नहीं कर सकेगा ।
- (न) अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रदूषित दोनों संस्थाओं के कार्य का विवरण तैयार करना तथा उसे उप संचालक को प्रस्तुत करना ।
- (प) व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार की प्रदूषित संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की तथा उन संस्थाओं की अन्तिम समय तक की सूची तैयार करना ।
- (र) प्रतिवर्ष जनवरी मास में नियमानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में गोपनीय प्रतिवेदन बनाना ।
- (ट) प्रतिवर्ष जून मास में निर्धारित प्रपत्र में भर कर अपनी तथा अपने अधीनस्थ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई यात्रा एवं निरीक्षण कार्य का वार्षिक विवरण पत्र तैयार कर उप संचालक को प्रेषित करना ।
- (त) नव-भवन निर्माण योजना की जांच करना तथा उन समस्त मामलों में जिनमें की नये भवनों की योजना या वर्तमान भवनों का वित्तार या मरम्मत करने पर विचार किया जाना हो, अपनी सम्मति प्रकट करना ।
- (थ) कैम्प, रेली तथा टूर्नामेन्ट्स का आयोजन करना तथा छात्र एवं अध्यापकों से सम्पर्क बढ़ाना ।
- (द) छात्रों के माता पिताओं व संरक्षकों के साथ तथा दूसरे विभाग के अधिकारियों एवं सर्वमान्य जनता के साथ सहयोग व प्रभावशील सम्बन्ध स्थापनार्थ प्रयत्न करना जिससे कि उनके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं के कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके ।
- (ध) वर्ष में कम से कम एक बार अपने कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण करना ।

टिप्पणी:—शिक्षा संस्थाओं की स्थिति, प्रगति आदि की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का कार्य निरीक्षकों द्वारा ही सम्भव होता है । अपने क्षेत्र में शिक्षा योजना को उन्हें ही कार्यान्वित करना पड़ता है तथा उसकी सुचारु व्यवस्था के लिये वे उत्तरदायी भी हैं । अपने क्षेत्र में दौरा करना, शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना, अपने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित करना उनके प्रमुख कार्य हैं । वे ३ दिन तक का विशेष अवकाश भी दे सकते हैं ।

सामान्य जनता, छात्रों आदि से सम्पर्क बढ़ाकर जिन क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करना भी उनका एक प्रमुख कर्त्तव्य होगा। वे समय समय पर कैम्प ट्रनिमेन्ट्स आदि का भी आयोजन करेंगे।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक

७. (१) राज्य में "आचार्य" स्तर से नीचे की समस्त संस्कृत पाठशालाओं के सम्बन्ध में पाठशालाओं के निरीक्षक को वही अधिकार, कर्त्तव्य तथा दायित्व प्राप्त होंगे जो कि "शाला निरीक्षकों" को होते हैं।

(२) वह संचालक के सीधा अधीन रहकर कार्य करेगा।

टिप्पणी:—संस्कृत पाठशालाओं के "निरीक्षक" के पद का नाम बदलकर अब संचालक, संस्कृत शिक्षा कर दिया गया है। इन संचालक महोदय में संस्कृत शिक्षा के कार्य की देख बाल के लिये दो उप निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

शिक्षा सहायक संचालिका

८. (१) शिक्षा सहायक संचालिका को अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित बालिका एवं महिला संस्थाओं के सम्बन्ध में उन्हीं कर्त्तव्यों दायित्वों, तथा शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिनका कि निरीक्षक शिक्षणालय को अपने अधीनस्थ छात्र एवं पुरुष संस्थाओं के सम्बन्ध में करना पड़ता है।

(२) वह सीधा संचालक के नियन्त्रण में कार्य करेगी। केवल स्टोर सम्बन्धी माल खरीदों में उप संचालक के अधीन कार्य करेगी।

टिप्पणी:—राज्य में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिये शिक्षा सहायक संचालिका उत्तरदायी है। उसे निरीक्षकों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं तथा उनके समान ही कर्त्तव्यों का पालन करता पड़ता है।

रजिस्ट्रार, विभागीय शिक्षा

९. (१) प्रस्तोता (Registrar) :—

- (i) सीधा संचालक के अधीन रहेगा तथा सम्पूर्ण विभागीय परिक्षाओं को लेने एवं उनकी व्यवस्था करने में वह स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
- (ii) वह उचित हिसाब रखने के लिये जिम्मेदार होगा तथा परीक्षकों, अधीक्षक परीक्षा केन्द्रों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त उनके पारिश्रमिक तथा अन्य फुटकर खर्चों से सम्बन्धित बिलों को पास करेगा तथा चेक प्राप्त करेगा।
- (iii) संचालक की अनुमति से विभागीय परीक्षा लेने हेतु नियम बनायेगा तथा उनमें सुधार करेगा।
- (iv) प्रश्न पत्र रचयिता (Paper Setter), परीक्षक आदि के लिये योग्य व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करेगा। संचालक द्वारा गठित तीन अस्थापकों या अधिकारीयों की एक समिति की सहायता से संचालक ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा।

- (v) संचालक द्वारा उचित रूप से बनाई गई समितियों द्वारा सभी प्रश्नपत्रों की जांच कराने एवं सरल कराने का प्रबन्ध करेगा ।
 - (vi) प्रश्न पत्रों के छपवाने का आवश्यक प्रबन्ध तथा उनके पैकिंग, सील लगाने व उन्हें विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर भेजने का प्रबन्ध करेगा ।
 - (vii) संचालक की स्वीकृति में परीक्षा केन्द्र निश्चित करेगा तथा ऐसे स्थानों पर आवश्यक प्रशासनात्मक प्रबन्ध करेगा ।
 - (viii) सभी परीक्षाओं हेतु आवश्यक स्टेशनरी खरीद कर वितरित करेगा ।
 - (ix) परीक्षा काल में परीक्षा केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र का जिसे वह आवश्यक समझे निरीक्षण कर सकेगा या संचालक की स्वीकृति द्वारा विभाग के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा करने हेतु कह सकेगा । ऐसे निरीक्षण हेतु बुलाये गये अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तोता (Registrar) को प्रेषित करनी पड़ेगी ।
 - (x) सभी परीक्षा परिणामों को संकलित (Compile) कर उसे संचालक की स्वीकृति से घोषित करेगा ।
- (२) परिणाम घोषणा के पश्चात् प्रस्तोता:—
- (i) परिणाम को राजस्थान राजपत्र तथा सर्वाधिक बिक्री वाले स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगा ।
 - (ii) सभी विभागीय परीक्षाओं में सफल छात्रों के लिये प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर उन्हें वितरित करेगा ।
 - (iii) संचालक के लिये इन सभी परीक्षाओं का एक संक्षिप्त (Consolidated) विवरण पत्र बनाकर भेजेगा । जिससे कि इसे विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
 - (iv) विभिन्न मुख्य परीक्षकों की रिपोर्ट का एक संक्षिप्त लेख तैयार करेगा जिसे संचालक की स्वीकृति प्राप्त करने पर छपवाया जायेगा तथा जिसे सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों के पास भेज दिया जायेगा ।
 - (v) परीक्षा सम्बन्धी भगड़ों एवं शिकायतों के विषय में प्रार्थनापत्रों पर विचार करेगा तथा उचित जांच के पश्चात् संचालक को आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करेगा ।
 - (vi) सभी बिलों के भुगतान हेतु परिस्थिति अनुसार या तो प्रबन्ध करेगा या सिफारिश करेगा ।
 - (vii) विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित अनुमानित बजट तैयार करेगा तथा स्वीकृति हेतु संचालक के पास प्रेषित करेगा ।

टिप्पणी.— शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के आयोजन के लिये प्रस्तोता उत्तरदायी है । उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है । परीक्षाओं के आयोजन से सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवस्था की देखभाल उसे करनी पड़ती है । प्रश्नपत्र बनवाना,

परिभाषियों में आवेदन पत्र आमन्त्रित करना, केन्द्र स्थापित करना, परीक्षा लेना उत्तर पुस्तिकों की जाँच का प्रबन्ध करना, परीक्षा फल सफलित करना, उसे घोषित करना परीक्षा में प्राप्त अंक एवं उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र सम्बन्धित प्रत्याशियों को भिजवाना आदि सभी कार्य उसके द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे।

उप संचालक योजना

१०. योजना उप संचालक मुख्य कार्यालय में रहेगा। वह निम्न कर्तव्यों का पालन करेगा —

(१) संचालक के निर्देशानुसार शिक्षा के सुधार तथा विस्तार करी की सभी योजनायें तैयार करना।

(२) ऐसे योजना कार्यों का एक अभिलेख तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों से आवश्यक सामयिक विवरण पत्र एवं सूचना भेजवाना तथा उन्हें संचालक को प्रेषित करना।

(३) योजनाओं के परिपालन पर निगाह रखना तथा संचालक की स्वीकृति द्वारा उनको ठीक कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

(४) योजनाओं में सम्बन्धित आधारभूत शिक्षणात्मक आंकड़े तथा अन्य सूचनायें तैयार करना।

टिप्पणी:—देश की प्रगति के लिये बनाई जाने वाली योजनाओं में शिक्षा का भी एक प्रमुख स्थान है। अतः योजनास्तर्गत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कार्य के लिये उपसंचालक योजना की व्यवस्था की गई है। शिक्षा-क्षेत्र में की गई प्रगति से मंदरित आवश्यक आंकड़े भी यही अधिकारी तैयार करते हैं।

उप-संचालक समाज शिक्षा

११. उप संचालक, समाज शिक्षा मंचालकालय (directorates) में सम्बन्धित रहेगा तथा समाज शिक्षा सम्बन्धी विषयों में वह संचालक के अधीन कार्य करेगा। उसके लिये आवश्यक होगा :—

(क) कि वह वर्ष में कम से कम १२० दिवस दोरे पर रहे तथा किसी भी मास में १० दिवस से कम दौरा नहीं करे।

(ख) कि वह प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा कार्य के सम्बन्ध में नियुक्त समाज शिक्षा व्यवस्थापकों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्यों पर नियन्त्रण एवं निरीक्षण करे तथा सरकारी नियमों तथा विभागीय आदेशानुसार उनकी वेतन वृद्धि, अवकाश, निरीक्षण, हटाना इत्यादि पर अपनी सिफारिश करे।

(ग) कि वह प्रतिवर्ष जून मास में राज्य में हुई समाज शिक्षा की प्रगति एवं विकास के सम्बन्ध में इसके विकास प्रस्तावों के साथ संचालक के पास एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करे।

(घ) कि वह प्रतिवर्ष जून मास में निर्धारित प्रपत्र में भरकर संचालक के पास जिला समाज शिक्षा अधिकारियों की उनके कार्य एवं चरित्र के बारे में, वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन प्रेषित करे।

- (इ) कि वह प्रत्येक बार अपना यात्रा कार्यक्रम संचालक के पास स्वीकृत हेतु भेजे तथा प्रत्येक माह अपने निरीक्षण प्रतिवेदन एवं यात्रा विवरण की प्रतिलिपिया उसके पास उसकी टिप्पणी तथा विशेष विवरण लिखने हेतु भेजे ।
- (व) कि वह निर्धारित प्रपत्र में जिला समाज शिक्षा अधिकारियों से उनका यात्रा कार्यक्रम व यात्रा विवरण मंगवा कर उन्हें स्वीकार करे ।
- (छ) कि वह समाज शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कैम्प, सम्मेलन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करे तथा उन्हें पूर्ण करे ।
- (ज) कि वह अपने अधीनस्थ पुस्तकालयों तथा ग्रन्थालय कक्षों का प्रबन्ध, निरीक्षण एवं नियन्त्रण रखे ।
- (झ) कि वह सामाजिक सम्पर्क स्थापित करे ताकि समाज शिक्षा सर्वप्रिय तथा व्यापक बन सके ।
- (ञ) कि वह समाज शिक्षा पर उचित साहित्य तैयार कर प्रकाशित कराये ।

टिप्पणी:—राज्य की शिक्षा प्रसार योजना केवल विद्यालयों, पाठशालाओं तक ही सीमित नहीं है अपितु अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है । निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र रात्री पाठशालायें आदि राज्य की ओर से खोली हुई हैं । शिक्षा के प्रसार के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय खुले हुये हैं । उन सबकी व्यवस्था समाज शिक्षा उपसंचालक के अधीन है । समाज शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य तैयार कराना व उसे प्रकाशित कराना उसका दायित्व होगा । समाज शिक्षा के प्रसार के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, कैम्प, सम्मेलन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी वही करेगा ।

उपनिरीक्षक शिक्षणालय

१२. इन अधिकारियों के विशेष अधिकार में छात्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक शालायें रहेगी, उनको निम्न कर्तव्य संभलाये गये हैं :—

(१) मुख्यतः वह जिले में प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा के कुशलता पूर्वक संचालन के लिये उत्तरदायी रहेगा । शालाओं से सम्बन्धित सभी मामलों का निर्णय उसके द्वारा होगा तथा अर्थ सम्बन्धी विषय एवं नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी मामले उसके द्वारा निरीक्षक के पास निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेंगे ।

(२) प्रतिवर्ष अपने जिले की प्रत्येक माध्यमिक शाला का निरीक्षण एक बार अवश्य करेगा । वह कुछ प्राथमिक शालाओं का भी निरीक्षण करेगा (इनकी संख्या निरीक्षक द्वारा निश्चित की जावेगी) । उसका निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक के अवलोकनार्थ तथा मार्गदर्शनार्थ भेज दिया जायेगा । साधारणतया वह निरीक्षण कार्य में एक मास में कम से कम १२ दिवस दौरे पर रहेगा । उसका यात्रा कार्यक्रम निरीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जावेगा ।

(३) वह माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों का आक्समिक अवकाश स्वीकृत करेगा ।

(४) वह प्राथमिक केन्द्रों तथा अन्य माध्यमिक पाठशालाओं के लिये स्टोर, माल तथा प्रपत्रों का वितरण करेगा ।

(५) वह निरीक्षक के कार्यालय की लेखा गांथा का प्रधान (Incharge) होगा और जब तक वह मुख्य स्थान (Headquarters) पर रहेगा इन कक्ष के सम्पूर्ण कामजात उसी के द्वारा भेजे जायेंगे । निरीक्षक के मुख्य स्थान से बाहर रहने पर वह उनके कार्यों की भी देखभाल करेगा ।

(६) स्थापन रजिस्टर को सही प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी उसका होगा । वह यह भी निश्चित करेगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों की सविस्तृत एवं व्यक्तिगत फाइलें अन्तिम समय तक पूर्ण रूप से भर रखी हैं तथा वर्ष के अन्त में आवश्यक प्रमाण पत्र भी इन बुको में दे दिये गये ।

(७) (सहायक उप-निरीक्षक की सलाह के पश्चात्) वह निरीक्षक के पास प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं को स्वीकृत धनराशि के उपयोग के विषय में प्रस्ताव प्रेषित करेगा ।

(८) सम्पूर्ण जिले के उच्च विद्यालयों एवं अन्य विशिष्ट शालाओं को मिलाकर वार्षिक सांख्यिक विवरण की तैयारी का निरीक्षण करेगा । वह माध्यमिक शालाओं तक के कर्मचारियों के वार्षिक स्थापना विवरण (Annual Establishment Returns) को संचित करेगा ।

(९) वह सम्पूर्ण सहायक उप-निरीक्षकों के यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकार करेगा तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा । वह उनका द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदनों की छटनी कर उन पर आगे आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(१०) निरीक्षण के समय विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं की छोटी कक्षाओं में पाये जाने वाले निष्प्रयोजन एवं स्थिरता की ओर विशेष ध्यान देना ।

(११) यह देखना कि माध्यमिक तथा प्राथमिक शालाओं के कर्मचारियों को ठीक समय पर तथा नियमित वेतन वितरित होता है या नहीं ।

(१२) प्रतिवर्ष जनवरी मास में ऐसे अध्यापकों की सूची तैयार करना जिन्हें अग्रिम सत्र में एस० टी० सी० में प्रशिक्षणार्थ भेजा जा सके तथा उसे निरीक्षक को प्रेषित करना ।

(१३) निरीक्षक द्वारा उसे भेजे गये मामलों की जांच करना ।

पाठशालाओं की उपनिरीक्षकायें

१२. ये अधिकारी लड़कियों की प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के लिये विशेष दायित्व रखेंगे । उन्हें निम्न कर्तव्य पालन करने होंगे:—

(क) एक वर्ष में कम से कम १२० दिन तथा एक माह में १० दिन दौरे पर रहना । वर्ष में एक बार उनके नियन्त्रण की समस्त माध्यमिक पाठशालाओं का तथा प्राथमिक शालाओं में से ३० प्रतिशत का निरीक्षण करना ।

(ख) निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक अवधि के लिये दौरे का कार्यक्रम बनाकर सहायक संचालिका को प्रेषित करना ।

(ग) अपने नियन्त्रण की समस्त संस्थाओं तथा उनके कर्मचारियों की आदिनांक (Upto-date) सूची रखना ।

(घ) प्रतिवर्ष जून में सहायक संचालिका को अपने तथा अपने अधीनस्थ सहायक उप-निरीक्षकाओं के दौरे तथा निरीक्षण कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भेजना ।

- (च) उन गांवों के नाम व अन्य जानकारी, जहाँ पर उनकी राय में नये विद्यालय खुलने चाहिये, निर्धारित प्रपत्र में अंकित करना तथा सहायक संचालिका को प्रतिवेदन भेजना ।
- (छ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की निम्न कक्षाओं में निरीक्षण के समय विशेष तौर पर निष्प्रयोजन (Wastage) तथा स्थिरता (Stagnation) का ध्यान रखना ।
- (ज) प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों को नियमित रूप से नियत समय पर वेतन बंटवाना ।
- (झ) अगले वर्ष एस० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले अध्यापकों की प्रतिवर्ष जनवरी में सूची तैयार करना तथा उसे सहायक संचालिका को प्रेषित करना ।
- (ट) सहायक संचालिका द्वारा भेजे गये मामलो में पूछताछ करना ।

सहायक उपनिरीक्षक

१३. इन अधिकारियों को विशेष तौर पर प्राथमिक शालाओं के निरीक्षण कार्य का दायित्व दिया गया है । उन्हें निम्न कार्य करने पड़ते हैं :—

- (अ) वर्ष में २०० दिन व महिने में १५ दिन कम से कम दौरा करना तथा अपने अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं का वर्ष में कम से कम दो बार इस प्रकार निरीक्षण करना कि पहले तथा दूसरे निरीक्षण में कम से कम तीन माह से अधिक का अन्तर नहीं रहे ।
- (ब) अपने अधीनस्थ समस्त पाठशालाओं तथा उनके कर्मचारियों की एक सूची रखना ।
- (द) नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के योग्य गांवों के नाम निर्धारित प्रपत्र में अंकित करना तथा अपने उच्चाधिकारियों को सूचना देना ।
- (स) अपने अधीनस्थ प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष जून में एक प्रतिवेदन निरीक्षक को देना तथा उसमें साधारण कठिनाईयों तथा सुधार के लिये सुझाव भी देना ।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेज बीकानेर तथा इन्टरमीजियेट कालेज के प्रधान

१४. इन्टरमीजियेट कालेज के प्रधान (Heads) को निम्न अधिकार होंगे :—

- (अ) शैक्षणिक कार्यों के लिए आधे दिन का अवकाश देना जो कि एक वर्ष में १० दिन से अधिक नहीं होगा ।
- (ब) अपने छात्रों के कल्याण तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाना ।
- (स) अपने अधीनस्थ अध्यापकों तथा छात्रावास-अधीक्षकों को अपनी ऐसी शक्तियाँ सौंपना, जो कि वे उचित समझें ।
- (द) कालेज की प्रवृत्तियों में अभिभावकों तथा नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके साथ सम्पर्क बनाने के लिये अभिभावक-अध्यापक संघ बनाना ।

- (य) अपने कॉलेज में बालचर, अमदान, समाज सेवा, वादविवाद, नाटक-प्रदर्शन व उत्सवों का आयोजन आदि सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना ।

उच्चविद्यालय तथा अध्यापक प्रशिक्षण शालाओं के प्रधान

१५. उच्चविद्यालय तथा अध्यापक प्रशिक्षण शालाओं के प्रधानों (Heads) को निम्न अधिकार होंगे :—

- (अ) शैक्षणिक कार्यों के लिये आधे दिन का अवकाश देना जो कि एक वर्ष में ६ दिन से अधिक नहीं होगा ।
- (ब) अपने छात्रों के कल्याण तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाना ।
- (स) अपने अधीनस्थ अध्यापकों तथा छात्रावास-अधीक्षकों को अपनी ऐसी शक्तियाँ सौंपना, जो कि वे उचित समझे ।
- (द) विद्यालय की प्रवृत्तियों में अभिभावकों तथा नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके साथ सम्पर्क बनाने के लिये अभिभावक-अध्यापक संघ बनाना ।
- (य) अपनी पाठशालाओं में बालचर, अमदान, समाज सेवा, वादविवाद, नाटक-प्रदर्शन व उत्सवों के आयोजन आदि सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना ।

माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के प्रधान

१६. माध्यमिक तथा प्राथमिक शालाओं के प्रधान (Heads) को निम्न अधिकार होंगे :—

- (अ) शैक्षणिक कार्यों के लिये आधे दिन का अवकाश देना जो कि एक वर्ष में चार दिन से अधिक नहीं होगा ।
- (ब) अपने छात्रों के कल्याण तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाना ।
- (स) अपने अधीनस्थ अध्यापकों तथा छात्रावास-अधीक्षकों को अपनी ऐसी शक्तियाँ सौंपना, जो कि वे उचित समझे ।
- (द) विद्यालय की प्रवृत्तियों में अभिभावकों तथा नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके साथ सम्पर्क बनाने के लिये अभिभावक अध्यापक संघ बनाना ।
- (य) अपनी पाठशालाओं में बालचर, अमदान, समाज सेवा, वादविवाद, नाटक प्रदर्शन व उत्सवों के आयोजन आदि सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना ।

नोट :—ऊपर संचालक, उप-संचालक, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, उच्चविद्यालय, माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों आदि के कर्तव्य एवं अधिकार दिये गये हैं, जिन्हें कि इस संहिता के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन अथवा अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये ।

अध्याय ४

निरीक्षण

१. विभाग के निरीक्षक अधिकारी संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, निरीक्षक,

उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षिका तथा सहायक उप निरीक्षक एवं अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सक्षम अधिकारी ने निरीक्षण का भार सौंप दिया है या जो सौंप सकता है।

२. निम्न नियम, जो समस्त शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते हैं; निरीक्षण अधिकारियों के पथ प्रदर्शन हेतु दिये जाते हैं :—

(अ) निरीक्षण अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य है कि वे शिक्षण संस्था के कार्य एवं दक्षता का निरीक्षण करें एवं उसको निश्चित करें। उन्हें यह कार्य चतुराई तथा सहानुभूति पूर्वक करना चाहिये तथा अपने गृहन अनुभव के आधार पर सलाह देनी चाहिये। उन्हें प्रशंसा तथा आलोचना से मुक्त रहना चाहिये लेकिन उनकी आलोचना रचनात्मक होनी चाहिये तथा उससे उन्हें उत्साह प्राप्त होना चाहिये न कि वह डराने वाली होनी चाहिये।

(ब) एक संस्था के कार्य एवं कार्यक्षमता को उचित जांच मुख्यतः दो भागों से सम्बन्ध रखती है अर्थात् निरीक्षण एवं परीक्षा। इनमें प्रथम का प्राशय किसी संस्था का उसके सामान्य कार्य के समय निरीक्षण करना है उदाहरणार्थ स्थान की सुविधा फर्नीचर, पढ़ाई के यन्त्र, कक्षाओं का प्रबन्ध एवं व्यवस्था, लेखा, रिकार्ड तथा रजिस्ट्रारों को रखने की विधि, शारीरिक शिक्षा के साधन, पुस्तकालय की दशा, सरों का व अनुशासन, अध्यापक व छात्रों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा अध्ययन आदि के तरीकों से है। दूसरे का प्राशय छात्रों की परीक्षा लेने के तरीके से है जिससे विदित हो सके कि वे अपने अध्यापकों के अध्यापन से कहां तक लाभान्वित हुये हैं व अध्यापकों की अध्यापन विधि में उन कमियों को ढूँढने से है जिनके कारण कक्षा कम योग्य रहती है। संस्था की दशा का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए निरीक्षण एवं परीक्षा दोनों ही अनिवार्य हैं। निरीक्षण या उनका कुछ भाग पहले पूरा करना चाहिये तथा छात्र परीक्षा बाद में। लेखा रिकार्ड तथा रजिस्ट्रार आदि की जांच, संस्था निरीक्षण तथा छात्र परीक्षा के उपरान्त की जानी चाहिये।

(स) निरीक्षण हमेशा निरीक्षण अधिकारी या उससे पूर्ववर्ती के पूर्व निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों तथा अनुक्तियों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये। निरीक्षण अधिकारी को पहिले यह निश्चित कर लेना चाहिये कि किन बातों पर उसके निरीक्षण एवं परीक्षाये विशेष रूप से निर्देश दिया जाना है तथा यह इन दृष्टिकोणों से किया जाना है कि पूर्व निर्देशों का पालन किया गया है अथवा नहीं। तब उसे संस्था का निरीक्षण करना चाहिये तथा इसके उपरान्त कक्षाओं की परीक्षा लेनी चाहिये। यही रचनात्मक निरीक्षण का सार है, तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिये कि निरीक्षण अधिकारी अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचा है पूर्ववर्ती या अपने अधिकारी के निर्णयों के आधार पर धारणा बना रहा है।

(द) क्योंकि संस्थाएँ छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, इसलिए एक निरीक्षण अधिकारी का मुख्य सम्बन्ध प्रत्येक संस्था जिनमें छात्र पढ़ते हैं, उनके भर्ती होने के कारण को ढूँढने से है। उन्हें यह मालूम करना चाहिये कि वे क्या करते हैं, वे क्या सीख रहे हैं, उनकी भावों कैसी बनती जा रही है, क्या उनकी शैक्षिक,

भावनाओं के प्रति इतने विचारशील होंगे कि मानों वे उनकी चेतना के प्रति जागरूक हों एवं क्रोध, अधैर्य एवं असन्तोष प्रकट न करेंगे। निरीक्षण के बीच में वे किसी भी परिस्थिति में न तो पान ही चबायेंगे और न धूँअपान ही करेंगे।

(उ) व्यक्तिगत प्रबन्धाधीन संस्थाओं के कल्याण हेतु प्रबन्धकों एवं निरीक्षकों में सहयोग होना आवश्यक है। ऐसी संस्थाओं में प्रबन्धकों एवं अध्यापकों को आदेश देने में ताना-शाही प्रवृत्ति को दूर रखने के लिए सावधानी बर्तनी चाहिये। ऐसी संस्थाओं में निरीक्षण अधिकारियों को कुछ भी ऐसी बात कहना, करना व लिखना नहीं चाहिये जिसमें कि अध्यापकों की इज्जत उनके प्रबन्धकों के सम्मुख समाप्त हो जाये तथा प्रबन्धकों का अधिकार, अध्यापकों पर समाप्त हो जाये। फिर भी यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि सुझावों एवं दोषों को दूर करना संस्था की मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त करने के लिये अत्यन्त अनिवार्य है। उनको शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयासों को सामान्यतः प्रोत्साहन देना चाहिये तथा लाभदायक दिशा में उसको मोड़ देने के लिये उन्हें अपने सम्पूर्ण अधिकारों के अन्तर्गत अपनी योग्य सलाह एवं सामयिक सूचना के द्वारा जो कुछ हो सके करना चाहिए।

(ह) इस बात का पता लगाने के लिये कि वह संस्था स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तथा माता-पिता एवं सामान्य जनता की अभिरुचि व प्रशंसा की पात्र है अथवा नहीं, निरीक्षण अधिकारी को उन क्षेत्रों से भी परिचित होना चाहिये जिनकी कि कोई मान्यता प्राप्त संस्था सेवा करती है।

(ई) निरीक्षक अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य यह है कि वे लोगों के सम्पर्क में रहें। यदि व्यवहारिक रूप से संभव हो तो यह उचित होगा कि संस्थाओं का प्रबन्ध व्यक्तिगत होने की दशा में उसे प्रबन्धक के साथ तथा संस्थाओं का प्रबन्ध सार्वजनिक होने की दशा में स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के साथ, इन संस्थाओं के सुधार हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए भीड़िंग करनी चाहिए। जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, वहाँ तक उसे छात्रों के माता-पिताओं तथा संरक्षकों से मिलना चाहिए। इस तरह वह उन कमियों को बतला सकता है जिनका उसे अनुभव हुआ हो, नियमित तथा समय पर उपस्थिति के बारे में समझा सकता है और लोगों को सामान्य रूप से शिक्षा में क्रियात्मक रुचि लेने के लिये प्रेरणा दे सकता है।

३. सामान्य रूप से महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक शालाएँ, प्रशिक्षण तथा विशिष्ट शालाओं की निरीक्षण तिथि का उचित नोटिस इस सूचना के साथ भेज दिया जायेगा कि वे निरीक्षण के समय तक अपने कार्य को सामान्य कार्यक्रमानुसार पूर्ण करें। संस्थाओं के प्रधान निर्धारित पत्रों में सामान्य विवरण पत्र तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा वांछित अन्य सूचनाओं को उनके आने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण अधिकारी सभी स्तरीय संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कर सकते हैं। ऐसे आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य प्रथम तो रजिस्ट्रारों को ठीक प्रकार से रखने के ढंग को देखना होगा तथा द्वितीय, संस्था प्रधानों एवं उनके सहायक नामान्यतः किस प्रकार से संस्थाओं का कार्य चला रहे हैं, देखना होगा।

४. (अ) प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम को निरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा (दिलिये परिशिष्ट ५ (अ) तथा ५ (ब) जो कि निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित निरीक्षण

अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा ।

(व) महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक, प्रशिक्षण तथा विशिष्ट शालाओं के निरीक्षण के सम्बन्ध में निरीक्षण की समाप्ति से एक माह के भीतर २ एक टंकणत 'Typed' प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए । इसकी एक प्रति सम्बन्धित संस्था के अध्यक्ष को तथा दूसरी प्रबन्धक को (यदि संस्था व्यक्तिगत प्रबन्धक के अधीन हो) तथा तीसरी अपने उच्च अधिकारी को भेजी जानी चाहिए; एक प्रति रिकार्ड में रखी जानी चाहिये ।

(त) 'ब' में निर्दिष्ट संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में निर्धारित मुद्रित प्रपत्रों में प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए तथा उनकी प्रतियां उपरोक्त सभी को भेजी जानी चाहिए ।

नोट:—यात्रा व्यय दियो को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि उपरोक्त निरीक्षण की प्रतियां नहीं भेज दी जाती हैं ।

५. विभिन्न प्रकार एवं स्तर की संस्थाओं के निरीक्षण में लगाये जाने वाला समय निम्न प्रकार से होगा:—

(अ) महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्रशिक्षण तथा विशिष्ट शालाओं के लिए २ दिन ।

(ब) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, संस्कृत पाठशालाओं, पुस्तकालय एवं समाजशिक्षा केन्द्रों के लिए १ दिन ।

६. (अ) निरीक्षण अधिकारियों को अपने यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार बनाने चाहिए कि वे कम से कम यात्रा में अधिक से अधिक शालाओं का निरीक्षण कर सकें । विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा कई मामलों में यह व्यावहारिक है कि यात्रा कार्यक्रम एक दिशा में बनाया जावे जिससे कि अधिक से अधिक शालाओं का निरीक्षण किया जा सके ।

(ब) लम्बी दैनिक यात्रायें उस समय तक नहीं की जानी चाहिये जब तक कि वे विवरण पत्रिका में अभिलेखित नहीं किए गए हों तथा विशेष एवं उचित कारणों द्वारा भवे-लित न हों ।

(स) जब शाला निरीक्षण में केवल एक ही दिन लगाना हो तो निरीक्षण अधिकारी को अपना विश्राम स्थल ऐसे समय पर छोड़ना चाहिये कि वह दूसरी निरीक्षण की जाने वाली शाला में उसके खुलने के पूर्व पहुँच जाये । उसे निरीक्षण उसी दिन पूर्ण कर लेना चाहिये तथा रात्रि में वही विश्राम करना चाहिये यदि जाँच इत्यादि का विशेष अवसर उसे वहाँ रुकने के लिए वाध्य न करें । इसके बाद दूसरे दिन प्रातः ही दूसरी शाला के निरीक्षणार्थ रवाना होना चाहिये । संक्षेप में एक यात्रा तथा एक निरीक्षण एक दिन में होने चाहिये लेकिन दो यात्रायें तथा एक निरीक्षण नहीं ।

(द) निरीक्षण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने स्वीकृत यात्रा कार्यक्रम को पूर्ण करने में दृढ़ रहेंगे । इस कार्यक्रम को उन्हें दिना. उस अधिकारी की स्वीकृति के नहीं बदलना चाहिये जिन्होंने कि उनका यात्रा कार्यक्रम स्वीकार किया है । फिर भी उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं यदि इस परिवर्तन से

सामान्य परिणाम में कोई अन्तर न हो तथा यात्रा व्यय में अन्य अतिरिक्त खर्च न हो । केवल अधिकारियों के अक्समात अस्वस्थ हो जाने तथा अन्य कोई अनौपचारिक अनुविधा उत्पन्न होनेके अतिरिक्त किसी भी कारणसे कार्यक्रमों में, प्राकस्मिक या ऐच्छिक परिवर्तन तथा द्रुत यात्रायें जिनका कोई उद्देश्य या प्रभाव न हो, स्वीकृत नहीं की जावेंगी ।

नोट:—निरीक्षणधिकारी का यात्रा भत्ता विल भुगतान के लिए उस समय तक स्वीकार नहीं होगा जब तक कि यात्रा सार्वजनिक हित में न हो ।

नोट:—किसी भी निरीक्षणधिकारी को उसके द्वारा सम्पन्न ऐसी किसी भी यात्रा जो कि गैर सरकारी या व्यक्तिगत कार्य के लिये अथवा किसी ऐसे कार्य के लिये जो कि सार्वजनिक हित में नहीं हो, के लिये कोई मार्ग व्यय नहीं मिलेगा ।

(घ) प्रत्येक निरीक्षणधिकारी निर्धारित प्रपत्र में एक मासिक विवरण पत्र तैयार करेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के पास इसकी एक प्रतिलिपि उस मास के यात्रा विलो साथ भेजेगा । विवरण के विशेष खण्ड में स्वीकृत कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन को स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

७. निधि एवं वित्त से संबंधित अन्य रिकार्ड, शुल्क एवं निधि की जांच की ओर निरीक्षणधिकारी अपना विशेष ध्यान देगा तथा स्थान पर ही रोकड़ को सुरक्षित रखने के प्रबन्ध की जांच करेगा ।

८. विशेष ध्यान इस बात की ओर रहना चाहिये कि निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में छात्रों द्वारा काम में नहीं लाई जा रही है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करा दिया जाता है ।

९. जब कि सरकार की नीति सामूहिक योजनाओं को प्रोत्साहन देना रही है तो ये संस्थाएँ सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की सूची की मौलिक अनिवार्यताओं को पूर्ण करने की शर्त पर अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम को भी विभाग की स्वीकृति द्वारा अपना सकती है ।

१०. निरीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ किन्हीं विषयों पर सुझाव सम्बन्धी निरीक्षण टिप्पणियाँ, जो निरीक्षण के समय बताई जानी चाहियें, परिशिष्ट ४ में दी गई हैं ।

११. निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपने सामान्य दौरों के समय ऐसे स्वागतों या जलपानों में सम्मिलित होना वर्जित है जहाँ भोजन वितरित किया जाता है ।

१२. निम्न सूचनायें देते हुये प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी एक औपचारिक रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों के पास प्रति वर्ष १५ जनवरी, १५ अप्रैल, १५ जुलाई तथा १५ अक्टूबर को भेजेगा ।

(अ) चालू वर्ष में निरीक्षण किये जाने वाले कार्यालयों तथा संस्थाओं की संख्या ।

(ब) पूर्व तीन मास में किये गये निरीक्षणों की संख्या ।

(स) चालू वर्षारम्भ से लेकर गत तीन मास की अवधि में किये गये निरीक्षणों सहित कुल किये गये निरीक्षणों की संख्या ।

(द) अवशिष्ट निरीक्षण ।

(ध) विशेष विवरण ।

टिप्पणी:—निरीक्षणधिकारी प्रत्येक वर्ष में ४ बार अपने निरीक्षण कार्य की एक शीमासिक रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों के पास भेजेगा जिसमें वह चालू वर्ष में किये गये निरीक्षणों की संख्या, अवशिष्ट निरीक्षण यादि समस्त विवरण देगा।

अध्याय ५

स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय

नोट:—इस अध्याय में उल्लिखित नियम समस्त राजकीय महाविद्यालयों पर लागू होते हैं तथा वे राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के पूरक हैं।

१. राजस्थान में स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Colleges) राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, से सम्बन्धित हैं।

२. महाविद्यालय राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव के अधीन हैं तथा वे सीधे उन्हीं से पत्र व्यवहार रखते हैं।

३. महाविद्यालय शुल्क वसूल करेंगे तथा सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार छात्रों को पूरी अथवा आधी शुल्क की छूट देगे।

४. सरकार द्वारा स्वीकृत Schedule of Powers के अनुसार जो अधिकार इन महाविद्यालयों के आचार्यों को दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त, उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार छात्रों के प्रवेश, श्रेणी में उन्नति (Promotions), स्थानान्तरण, हटाना, निवास, संस्था से निकाल देना अथवा सीमित अवधि के लिये अध्ययन से निलम्बित करना तथा कक्षाओं का विभाजन व अध्ययन के विषयों का निर्धारण आदि सभी अधिकार होंगे।

५. छात्रों के निवास की स्थिति संतोषजनक होनी चाहिये तथा जो छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं, उन्हें या तो अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ रहना चाहिये अथवा आचार्य (Principal) द्वारा स्वीकृत स्थान पर रहना चाहिये। इन महा विद्यालयों के साथ लगे हुये छात्रावास आचार्य की देख रेख में एक स्थानीय अधीक्षक द्वारा व्यवस्थित होंगे।

६. इन महाविद्यालयों के भवन (Premises) शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिये तब तक प्रयुक्त नहीं किये जावेंगे जब तक कि उपर्युक्त प्राधिकारी (authority) की स्वीकृति न मिल जावे।

७. प्रत्येक महाविद्यालय में वहाँ के समस्त प्राध्यापकों की एक "स्टाफ कौंसिल" होगी।

८. इस स्टाफ कौंसिल के अध्यक्ष आचार्य होंगे जो कि महाविद्यालय में सामाजिक जीवन, अनुशासन तथा अध्ययन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस कौंसिल की राय लेगा।

९. ऐसे महाविद्यालयों में जहाँ कि प्राध्यापकों की संख्या २० से अधिक नहीं होगी, यह कौंसिल एक निम्न के रूप में एक माह में कम से कम एक बार अवश्य एकत्र होगी तथा यदि आचार्य आवश्यक समझे तो अधिक बार भी इसी बैठक हो सकती है।

१०. (अ) ऐसे महाविद्यालयों, जहाँ कि प्राध्यापकों की संख्या २० से अधिक हो, स्टाफ कौंसिल की बैठक एक अवधि (Term) में कम से कम एक बार होगी। उसमें महाविद्यालय के सामाजिक एवं शैक्षणिक जीवन से संबंधित नीति पर विचार होगा।

(ब) ऐसे महाविद्यालयों में, शीघ्र निपटारा किये जाने वाले मामलों के संबंध में स्टाफ कौंसिल का कार्य, एक ऐसी स्टाफ "परामर्श दायी समिति" के द्वारा सम्पादित किया जा सकता है जो कि आचार्य (जो कि अध्यक्ष होंगे), विभागाध्यक्षों तथा स्टाफ कौंसिल द्वारा निर्वाचित अध्यापक वर्ग के पांच प्रतिनियोगों से मिलकर बनी हुई होगी। इस परामर्श दायी समिति की बैठक कम से कम माह में एक बार अवश्य होगी।

११. आचार्य एवं स्टाफ कौंसिल अथवा स्टाफ परामर्श दायी समिति के मध्य मतभेद हो जाने पर आचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

१२. महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के कर्तव्य केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास करने वाली सभी प्रवृत्तियों में वे आचार्य के साथ सहयोग करेंगे।

१३. विषयविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत छुट्टियाँ तथा अवकाश सभी महाविद्यालय मनायेंगे।

१४. यह आचार्य का दायित्व होगा कि महाविद्यालय में उचित अनुशासन बनाये रखें। वह समय समय पर इस संबंध में नियम बनायेगा तथा महाविद्यालय के भीतर या बाहर छात्रों के आचरण को नियंत्रित रखेगा।

१५. स्टाफ के द्वारा की जाने वाली प्राइवेट ट्यूशन को अनुत्ताहित किया जाना चाहिये और किसी एक प्राध्यापक द्वारा ली जाने वाली प्राइवेट ट्यूशन की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा उसके लिये भी आचार्य से पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये। वह ऐसी प्राइवेट ट्यूशन के बारे में आवश्यक जानकारी सहित, एक रजिस्टर रखेगा।

१६. किसी अन्य धंधे को करने की स्वीकृति आचार्य से लेनी चाहिये और सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी स्वीकृति, सरकार द्वारा स्वीकृत सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत ही दी जा सकेगी।

१७. आचार्य एवं अध्यापकगण को शैक्षणिक अवकाश भी, जो कि एक वर्ष में राजस्थान के लिये १५ दिन से अधिक तथा बाहर के लिये ६ दिन से अधिक का नहीं होगा, उनको आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने वाले उचित अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।

१८. यह शैक्षणिक अवकाश विषयविद्यालय के कार्य, जिसमें विश्वविद्यालय समितियों की बैठक, निरीक्षण, परीक्षाएँ, तथा शैक्षणिक सम्मेलन, बैठकें व सेमिनार सम्मिलित होंगे, के लिये दिया जावेगा।

१९. अपना कार्य-स्थल छोड़ने से पूर्व आचार्य समुचित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

२०. महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, जिसमें ड्रिल, जिम्नास्टिक, खेल-कूद सम्मिलित होंगे, तथा एम०सी०सी० के लिये भी उचित प्रावधान होना चाहिये। खेल-कूद, जहाँ तक हो सके, अनिवार्य किये जाने चाहिये तथा उसमें सभी छात्रों को भाग लेना चाहिये।

२१. महाविद्यालय में सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन देने तथा प्रजातन्त्रीय नागरिकता के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये आचार्य छात्रों का, अपने द्वारा निमित्त अथवा स्वीकृत

नियमों के अनुसार महाविद्यालय में सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल-कूद संबंधी प्रवृत्तियों को बढ़ाने हेतु समितियाँ निर्माण करने के लिये, मार्ग दर्शन करेगा।

अध्याय ६

संस्थाओं का आन्तरिक प्रशासन

टिप्पणी:—इस अध्याय के नियम (स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को छोड़ कर) सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते हैं जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय एवं इंटरमीजियेट कालेज भी सम्मिलित हैं जो कि विभाग द्वारा मंचालित तथा मान्यता प्राप्त है। वे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के पूरक है।

१. शिक्षण की अवस्था—शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएँ निम्न कक्षाओं तथा खण्डों से सम्बन्धित हैं:—

इंटरमीजियेट	कक्षा ११ एवं १२	इंटरमीजियेट खण्ड
उच्चविद्यालय अवस्था	कक्षा ९ एवं १०	उच्च विद्यालय खण्ड
उच्चतर माध्यमिक अवस्था	कक्षा ९, १० एवं ११	उच्चतर माध्यमिक खण्ड
माध्यमिक अवस्था	६ से ८ तक	माध्यमिक खण्ड
प्राथमिक अवस्था	कक्षा १ से ५ तक	प्राथमिक खण्ड

२. उच्च विद्यालय तथा इंटरमीजियेट कक्षाओं का अध्ययन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

३. विश्वविद्यालय, मण्डल या विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का, मान्यता देने वाले अधिकारियों द्वारा केवल विशेष रियायत स्वीकृत किये जाने के अतिरिक्त, सामान्यतया पालन किया जाना चाहिये। पाठ्य पुस्तकों का अधिकृत या निर्धारित पुस्तकों में से चयन होना चाहिये तथा संस्थाओं के अध्यक्ष इसके लिये उत्तरदायी होंगे कि कोई छात्र अनधिकृत पुस्तकों का तो प्रयोग नहीं कर रहा है।

४. कार्य स्थान छोड़ने की स्वीकृति:—संस्थाओं के अध्यक्ष, यदि वह संस्था राजकीय है तो बिना समक्ष अधिकारों की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किये अपने मुख्य स्थान नहीं छोड़ सकते तथा यदि वह संस्था व्यक्तिगत प्रबन्ध में है तो उन्हें प्रबन्धक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। प्रध्यापक-गण संस्था के अध्यक्ष की बिना पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं।

५. शारीरिक प्रशिक्षण:—प्रत्येक संस्था में छात्रों के स्वास्थ्य शारीरिक एवं नैतिक विकास के हित में ड्रिल, जिमनास्टिक, खेलकूद एवं कसरत आदि का उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण देने हेतु उचित प्रावधान रखा जाना चाहिये। मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, बास्केट, बाल, वालीबाल, बैक टेनिस तथा भारतीय खेलों की व्यवस्था करनी चाहिये। फिर भी यदि ऐसे खेलों के लिये पर्याप्त भूमि प्राप्य न हो तो ऐसे खेल जिनमें कम भूमि की आवश्यकता हो, प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

६. अध्यापकों से अपेक्षा है कि वे अपने छात्रों के शारीरिक प्रशिक्षण में क्रियात्मक रुचि रखें। क्रमानुसार उनको शाला के समय के बाद खेलों के निरीक्षण एवं व्यवस्था में सहायता देने हेतु कार्य दिया जाना चाहिये। यदि उम्र के कारण वे अयोग्य न हों तो उन्हें खेलों में भाग लेना चाहिये।

७. खेलों एवं कसरतों के अतिरिक्त, सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक प्रशिक्षण अवश्य होगा।

८. प्रत्येक स्तर की संस्थाओं में एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित करने व उसे बनाये रखने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। प्रकृति या कला की, वैज्ञानिक, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व की सुन्दर वस्तुयें, मान चित्र, नमूने, (Botanical and Zoological specimen) कृषि सम्बन्धी संग्रह तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के विशिष्ट हस्तकार्य आदि इस संग्रहालय की प्रमुख विशेषतायें होनी चाहिये। छात्रों को केवल ऐसे नमूने ही एकत्र करने के लिये उत्साहित नहीं करना चाहिये जिनसे कि संग्रहालय की उपयोगिता बढ़े वरन् उन्हें एकत्रित वस्तुओं का वर्गीकरण एवं प्रबन्ध में व्यावहारिक रुचि लेने हेतु भी उत्साहित करना चाहिये।

९. नैतिक शिक्षा:—सभी शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में नैतिक वातावरण तैयार करके शाला के सभा भवनों में भावनात्मक गीतों, व्याख्यानों एवं नाटकदि के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

१०. धार्मिक निर्देश:—मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत प्रबन्धाधीन शिक्षण संस्था में निम्न प्रतिबन्ध सहित धार्मिक निर्देशन दिया जा सकता है:—

(क) किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देशन या पालन करने हेतु उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि वह (यदि वह नाबालिग है) या उसका संरक्षक उस धार्मिक निर्देशन में सम्मिलित होने के लिये अपनी सहमति प्रकट नहीं करता है।

(ख) धार्मिक निर्देशन शाला या महाविद्यालय के कार्य के प्रारम्भ या अन्त में ही दिया जावे।

११. अनुशासनात्मक नियम:—निम्न आचरण सर्वथा वर्जित हैं:—

(क) शाला या महाविद्यालय भवन में या उसके पास थूँकना।

(ख) कक्षाओं में या उनके पास धूम्रपान करना।

(ग) औषधियों या नशीली वस्तुओं का प्रयोग।

(घ) किसी भी प्रकार का जुआ खेलना।

(ङ) शाला के फर्नीचर या भवन को असुन्दर बनाना या अन्य प्रकार से तुकसान पहुँचाना।

(च) शाला या विद्यालय प्रांगण में शोर गुल युक्त व्यवहार।

१२. छात्रों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता रखने हेतु तथा उनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतें डालने हेतु यथेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिये। संस्था के अध्यक्ष तथा उसके सहायक अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय की पात्रन्दी, नम्रता, स्वच्छता तथा सफाई की महत्ता पर जोर देने में हर प्रकार की उचित सावधानी बरतें। उन्हें छात्रों को प्रसन्नतापूर्वक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता के विषय में तथा दूसरों के प्रति आदर व श्रद्धा एवं क्रिया में ईमानदारी तथा सच्चाई आदि की महत्ता से प्रभावित करना चाहिये।

१३. (१) सभी राजकीय शिक्षण संस्थायें विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार ही संस्थाओं की खोलेगी तथा बन्द करेगी। विश्राम हेतु दिये जाने वाले समय के अतिरिक्त शिक्षा का समय सदियों में कम से कम ५ घन्टा तथा गमियों में ४ घन्टे से कम नहीं होना चाहिये।

(२) जहाँ किसी भवन में दो पाली चलती हो वहाँ शाला के मामले में शिक्षा का समय सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा निश्चित किया जायेगा तथा इन्टरमीडियेट कालेज होने पर उप संचालक द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(३) जिन संस्थाओं में एक ही पाली चलती है उनका खुलने एवं बन्द होने का समय सामान्यतया वर्ष भर से निम्न प्रकार में रहेगा:—

१ अप्रैल से १५ अगस्त

७ से ११-३० प्रातः

प्राथमिक शाला

७ से ११ ०० प्रातः

१६ अगस्त से ३१ अक्टूबर

११ से ५-०० दिन

१ नवम्बर से ३१ जनवरी

१०-३० से ४-३० दिन

१ फरवरी से ३१ मार्च

११ से ५-०० दिन

अल्प परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो शाला के मामले में निरीक्षक द्वारा तथा इन्टरमीडियेट कालेजों के मामले में उप संचालक की सहायता द्वारा किया जा सकता है।

(४) प्राथमिक शाला या माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं की दशा में उपरोक्त कार्य के समय खेल का समय भी सम्मिलित है जबकि अन्य शालाओं में खेल इस समय के अतिरिक्त समय में खेले जायेंगे।

१४. संस्थाओं के अध्यक्षों के मुख्य कर्तव्यों में से एक यह भी है कि वे इस बात के निरीक्षण में अपना उत्तर दायित्व समझें कि सम्पूर्ण संस्था में छात्रों को जिस प्रकार का गृह पठन पाठन कार्य दिया जाता है वह उनकी कार्य क्षमता के अनुकूल है तथा उनको इतना समय मिल सकता है कि वे इस कार्य को कर सकते हैं तथा वह कार्य विभिन्न विषयों में उचित प्रकार के विभाजन में दिया गया है। उसे करने दिये गये निर्देशों को लिख लेना चाहिये ताकि वह यह निरीक्षण कर सके कि उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

१५. संस्थाओं के प्रधानों को यह भी देखना आवश्यक है कि उनके सहायक अध्यापक निरीक्षण अधिकारी को उन पाठों जिसे उनको उस दिन पढ़ाना है कि टिप्पणी को पूर्व पाठों की टिप्पणी के माध्यम दिखाने हेतु पूर्ण रूप से प्रस्तुत हैं।

१६. प्रत्येक कक्षा में अध्यापकों एवं छात्रों के मार्ग दर्शन हेतु प्रति दिन के अध्ययन कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए उस कक्षा का समय विभाग चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान में लगा दिया जायेगा। जहाँ तक संभव हो उच्च विद्यालयों के अध्यापकों के लिये प्रति सप्ताह ६ अन्तर (Periods) तथा अन्य के ६ अन्तर (Periods) रिक्त रहने चाहिये।

१७. शाला के आकार तथा प्रकार के अनुसार संस्था का प्रधान प्रति दिवस दो या तीन अन्तर (Periods) पढ़ायेगा तथा समय विभाग चक्र इस प्रकार बनायेगा कि वह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्यालय का कार्य करने तथा तापियों के कार्य के प्रत्येक कार्य पर्याप्त समय निकाल सके।

१८. माध्यमिक शालाओं में स्टाफ का प्रावधान प्रधानाध्यापक एवं ऐच्छिक तथा व्यवहारिक

विषयों के अध्यापकों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा खण्ड के लिये एक अध्यापक से किया जाना चाहिये । प्राथमिक शालाओं में प्रत्येक ३० छात्रों पर एक अध्यापक सामान्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिये ।

१९. संस्थाओं के प्रधान कक्षाओं के कमरों के आकार तथा शिक्षण क्षमता का उचित ध्यान रखते हुए किसी भी कक्षा या खण्ड में छात्रों की प्रवेश संख्या निश्चित करेगे । सामान्यतया प्रत्येक छात्र के लिए १० फीट जमीन से कम जमीन नहीं होना चाहिये । कक्षा प्रथम से अष्टम तक छात्रों की संख्या सामान्यतः ४० से अधिक नहीं होनी चाहिये लेकिन माध्यमिक कक्षाओं के मामले में निरीक्षक की आज्ञा से छात्र संख्या को ४५ तक भी बढ़ाया जा सकता है । अष्टम कक्षा से आगे विश्व विद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा ।

२०. सामान्य रूप से छात्रों का प्रवेश सत्रारम्भ में ही किया जावेगा तथा जहाँ तक सम्भव होगा छात्रों के संरक्षकों द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रपत्र उचित एवं सही रीति से भर कर छात्रों को प्रवेश के लिए प्रेषित किया जावेगा ।

२१. प्रत्येक प्रवेश प्रपत्र को निर्णय दिये जाने के पश्चात् प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरों से शाला के अभिलेख (Record) में रखने हेतु फाइल में लगा दिया जावेगा ।

२२. एक छात्र का नाम कक्षा के रजिस्टर में उस समय तक प्रविष्ट नहीं किया जावेगा जब तक कि उसे प्रवेश न मिला हो तथा उसका नाम प्रवेश रजिस्टर में न दर्ज कर लिया गया हो । सामान्यतः एक छात्र को, जब तक उसका प्रवेश विचाराधीन है, कक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा ।

२३. एक विद्यार्थी जिसने पहिले कभी शाला में प्रवेश नहीं लिया हो उसे उस कक्षा में प्रविष्ट कर लिया जावेगा जिसके लिये प्रधानाध्यापक उचित परीक्षा लेने के बाद उसे योग्य समझता हो (कक्षा छः से ऊपर की कक्षा में नहीं) । प्रधानाध्यापक का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

२४. एक छात्र जो सम्पूर्ण वर्ष तक या वर्ष के अधिक समय तक शाला में उपस्थित नहीं रहा हो तथा उचित परीक्षा लेने के पश्चात् संस्था प्रधान यदि सन्तुष्ट हो जाये तो उसे सत्रारम्भ में पूर्व कक्षा में जिसमें वह पढ़ रहा था उससे एक उच्च कक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है, ऐसे मामलों का पूरा अभिलेख छात्र रजिस्टर (Scholars Register) में किया जाना चाहिये । इसी प्रकार यदि कोई छात्र दो वर्ष तक या दो वर्ष के अधिक भाग में शाला में अनुपस्थित रहा है तो उसे भी सत्रारम्भ में दो कक्षाएँ ऊपरवाली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन किसी भी दशा में कोई भी छात्र उस कक्षा से उच्च कक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जावेगा जिसका अभिलेख छात्र रजिस्टर में किया हुआ है तथा संस्था प्रधान को यह भी शक्ति प्रदान की जाती है कि वह किसी भी छात्र को परीक्षोपरान्त यदि वह उसको निम्न श्रेणी के योग्य समझे तो उसमें प्रविष्ट कर सकता है ।

२५. एक ही सत्र में एक छात्र को उस समय तक दूसरी शाला में उस कक्षा से उच्च कक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा जिसमें कि वह पूर्व शाला में पढ़ रहा था, जब तक कि उसे शाला के मुक्ति प्रमाण पत्र में यह घोषित न कर दिया जाये कि उसने उस कक्षा में उत्तीर्ण किये जाने वाली परीक्षा पास कर ली है ।

२६. कोई भी छात्र जिस शाला में पढ़ रहा है उसे छोड़ कर अन्य शाला में उस समय तक प्रविष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने प्रवेश पत्र के साथ अपनी पूर्व शाला का मुक्तिपत्र संलग्न न करे या संस्थाप्रधान से निर्धारित अवधि में उसे पेश करने की स्वीकृति न मिले । दूसरे

राज्य से स्थानान्तरण (Migration) की दशा में उसे प्रमाण पत्रों पर उस राज्य के सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये होने चाहिये ।

२७. सत्र के मध्य में एक शाला में स्थानान्तरणों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को अधिकार है कि वे ऐसे छात्रों को प्रविष्ट करने से इन्कार कर सकते हैं यदि वे ऐसे स्थानान्तरणों को उचित न समझे । सत्र के मध्य में किसी भी छात्र को एक ही वस्ती (Locality) में एक शाला से दूसरी शाला में बिना संस्था प्रधान की लिखित विशेष स्वीकृति के प्रविष्ट नहीं किया जायेगा । संस्था प्रधान ऐसी स्वीकृति प्रदान करने का कारण भी लिखेगा ।

२८. किसी भी को छात्र अमुक वर्ग, जाति या धर्म का अनुयायी होने के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश के लिए इन्कार नहीं किया जायेगा ।

२९. संस्था का प्रधान इस बात का निरीक्षण करेगा कि छात्रों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें शाला भुक्ति प्रमाण पत्र कम से कम समय में प्रदान किये जाते हैं । उन्हें वितरित करने से पूर्व उनकी सावधानी पूर्वक जांच एवं परीक्षा की जानी चाहिये ।

३०. छात्रायें, छात्रों की सभी प्रकार की संस्थाओं में अपना प्रवेश प्राप्त कर सकेंगी । नीति के अनुसार छात्रों के लिये प्राथमिक शालाओं में विशेष रूप से छात्राओं को प्रविष्ट किया जाना चाहिये ।

३१. यदि कोई छात्र किसी प्रकार के छल से प्रवेश प्राप्त किया हुआ पाया गया तो संस्था-प्रधान द्वारा उसका नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा दिया जावेगा तथा इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुझाव देकर उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देदी जावेगी ।

३२. एक छात्र को एक शिक्षण संस्था में पढ़ते रहने के लिए, नियमों का पालन तथा सद-व्यवहार एक आवश्यक शर्त है । ऐसे नियमों को भंग करने तथा अन्य अभद्र व्यवहार करने पर संस्था प्रधान को यह अधिकार है कि वह उस छात्र का नाम शाला के छात्र उपस्थिति रजिस्टर से अलग कर दे ।

३३. निम्न कारणों पर भी किसी छात्र का नाम छात्र उपस्थिति रजिस्टर से अलग कर दिया जावेगा:—

- (१) भुगतान की अन्तिम तिथि के पश्चात् एक माह तक शुल्क एवं अन्य ऋण उसके द्वारा जमा न कराने पर, या
- (२) इन्टरमीडियेट तथा उच्च विद्यालयों में बिना प्रार्थनापत्र भेजे हुये १० दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने पर तथा माध्यमिक शालाओं में १५ दिवस तक एवं प्राथमिक शालाओं में २० दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने पर ।

फिर भी शुल्को के भुगतान के सम्बन्ध में संस्था प्रधान विद्यार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर मामले के औचित्य को ध्यान में रखते हुये कुछ दिवस की अवधि बढ़ा सकता है ।

३४. निम्न लिखित कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के स्तरीय रूप हैं जिनको शिक्षण संस्थाओं में अपनाया जा सकता है:—

- (१) आरोपण (मानसिक या भौतिक प्रकृति के अन्य आरोपण जो कि कक्षा या संस्था के कार्य से सम्बन्धित हों)
- (२) आर्थिक दण्ड
- (३) शारीरिक दण्ड
- (४) बहिष्कार (Restiction)
- (५) निष्कासन (Expulsion)
- (६) निलम्बन (Suspension)

३५. इनमें से प्रथम दो प्रकार के दण्ड प्रधानाध्यापक द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों के अनुसार कक्षा के अध्यापकों द्वारा छोटे अपराधों के करने पर दिये जा सकते हैं ।

३६. काम न करने पर दण्ड दिया जा सकता है ।

३७. छुर्माता सामान्यतया निम्न बातों के होने पर दिया जा सकता है:—

- (१) जहाँ पर छात्रों के संरक्षकों को आंशिक रूप से दोषी ठहराया जाये । उदाहरण के तौर पर जैसे एक छात्र देरी से उपस्थित होता है तो उसके संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को ठीक समय पर घर से भेज दे ।
- (२) जब एक अध्यापक छात्र के किसी विशिष्ट अपराध के विषयों में उसके संरक्षक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो;
- (३) जब छात्र द्वारा स्कूल सम्पत्ति का कोई नुकसान कर दिया हो;
- (४) जब एक छात्र छुट्टियों के बाद देर से उपस्थित होता है; तथा
- (५) जब छात्र द्वारा शुल्क (फीस) एवं अन्य वसूला जमा करने में देर की जा रही हो ।

३८. प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा ।

३९. जब शारीरिक दण्ड दिया जावे तो इस बात उस समय ध्यान रखा जावे कि यह उग्र-कारी, कठोर एवं बहुत ज्यादा न हो । यह केवल प्रधानाध्यापक द्वारा ही दिया जाना चाहिए ।

४०. बहिष्कार (Restiction) तथा निष्कासन (Expulsion) का दण्ड केवल महान् अपराधों के किये जाने पर ही उस समय देना चाहिए जब कि लड़के को सुधारने के लिए अन्य कोई उचित साधन न हों या जब उसका शाला में रहना शाला की नैतिकता एवं अनुशासन को खतरे में डालने वाला हो ।

४१. निष्कासन (Expulsion) का तात्पर्य यह है कि उस छात्र को उस शाला में जिससे वह निकाला गया है, फिर भर्ती नहीं किया जावेगा । लेकिन इससे उसे सक्षम अधिकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करके दूसरी संस्था में भर्ती किये जाने से रोका नहीं जा सकेगा । बहिष्कार का तात्पर्य यह है कि जितने समय के लिए छात्र बहिष्कार (Restiction) किया गया है, उतने समय तक उसको किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

४२. प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट पर छात्र के बहिष्कार या निष्कासन के आदेश केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही निकाले जा सकते हैं (देखिये आगे नियम ४३) तथा ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि शिक्षातिथीय छात्र के संरक्षक या माता पिता के पास भेजनी चाहिये ।

४३. वहिष्कार या निष्कासन के आदेश जारी करने में निम्न अधिकारी सक्षम होंगे ।

संस्थाएँ
इंटरमीजियेट कालेजों की
११वीं एवं १२वीं कक्षाएँ
हाई स्कूल
मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल

सक्षम अधिकारी—
सम्बन्धित आचार्य
सम्बन्धित प्रधानाध्यापक
निरीक्षक शिक्षणालय, या
सहायक निरीक्षक शिक्षणालय
इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट ।

४४. वहिष्कार के आदेशों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा ।

४५. नियम के रूप में किसी भी अध्यापक को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूरा प्रारम्भ में उनका मन ही मन सख्त विरोध करना चाहिये तथा विवेक के आधार पर अपनी असहमति प्रकट करना चाहिये जिससे कि मामला स्वयं ही निपट जाये । बहुत से मामलों में चेतावनी देना ही पर्याप्त पाया गया है विशेषकर जब कि उसकी प्रगति पत्रिका में उसकी प्रविष्ट कर दिया जाता है ।

४६. पुरस्कार:—स्वीकृत वजत में से छात्रों को अध्ययन, कुशलता, व्यायामों एवं साप्ताहिक क्रियाओं के लिये पुरस्कार दिये जा सकते हैं ।

४७. पंजिकायें (रजिस्टर):—प्रत्येक शिक्षण संस्था में सरकार द्वारा निर्धारित सभी रजिस्टर एवं अन्य रिकार्ड रखा जायेगा तथा संस्था का प्रधान उनमें उचित प्रविष्टियों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा ।

४८. छात्र रजिस्टर:—छात्र रजिस्टर तैयार करने के लिए निम्न नियमों को उपयोग में लाना होगा—

(क) किसी भी स्तर की मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश पाने पर प्रत्येक छात्र के लिये एक छात्र रजिस्टर तैयार किया जायेगा । किसी विशेष सत्र के लिए छात्र रजिस्टर दूसरे सत्र के प्रारम्भ तक पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए । यह रजिस्टर या तो स्वयं संस्था के प्रधान द्वारा या उसकी देखरेख में तैयार किया जावेगा लेकिन 'चरित्र एवं कार्य सम्बन्धी' स्तम्भ हमेशा स्वयं उसके द्वारा भरा जाना चाहिए ।

(ख) छात्रों को प्रविष्ट करके समय उनके प्रवेश की संख्या उन्हें दे देनी चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उस संख्या को अपने उस संस्था में रहने के समय तक रखना चाहिए । कुछ समय तक अनुपस्थित रहने के बाद यदि वह छात्र फिर उस संस्था में वापिस आता है तो उसे अपने पूर्व प्रवेश संख्या पर ही दर्ज किया जायेगा ।

(ग) छात्र रजिस्टर सुविधाजनक आकार में तैयार किए जायेगे तथा प्रत्येक छात्र रजिस्टर १०० प्रपत्रों का होगा जिनको कि छात्रों के प्रवेश के क्रम के अनुसार लगाया जायेगा । रजिस्टर में वर्णमाला के क्रम के अनुसार सूची पत्र पहिले लगाया जायेगा, एक पृष्ठ या प्रत्येक अक्षर के लिए आवश्यक जगह छोड़ी जानी चाहिए तथा हासियाँ (मार्जिन) अक्षर के आवश्यक संदर्भ को लिखने के लिए सामान्य रूप से छोड़ा जाना चाहिए । रजिस्टर में इस वर्णमाला क्रम से बनाई गई सूची में प्रत्येक नाम के आगे छात्र की

प्रवेश संस्था को लिखना चाहिए । रजिस्टर हमेशा नियमित रूप से तैयार किया जाना चाहिये ।

- (घ) प्रत्येक संस्था का प्रधान छात्रों द्वारा किसी कक्षा में प्रवेश पाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों के साथ पूर्व संस्थाओं से लाये गये छात्र रजिस्टर की प्रतिलिपियों को भी आवश्यक संदर्भ के लिए सुरक्षित रखेगा तथा प्रत्येक छात्र के लिए स्कूल छोड़ते समय उसकी एक प्रतिलिपि दी जायेगी । पोर्ट फोलियो (Port Folio) पर एक सूची पत्र लगाना चाहिए जिसमें कि इन छात्रों का नाम लिखा जाये जिनके कि रजिस्टर इस प्रकार प्राप्त हुए हैं तथा इसमें इस रजिस्टर के प्राप्त करने की तारीख तथा वह तारीख जिसको कि इसकी प्रतिलिपि छात्र को या उसके संरक्षक को दी गई है, आदि भी दर्ज होना चाहिए ।

५९. एक छात्र को अनुपस्थित रहने की छुट्टी, छात्र द्वारा अपने संरक्षक या माता पिता के हस्ताक्षर की हुई दरखास्त पेश करने पर केवल संस्था के प्रधान द्वारा ही स्वीकृत की जा सकती है या यदि वह अपनी यह शक्ति कक्षाओं के अध्यापकों को प्रदान कर देता है तो वे भी ऐसे अवकाशों को स्वीकृत कर सकते हैं । मिडिल एवं हाई स्कूलों में बिना प्रार्थना पत्र भेजे अनुपस्थित रहने पर तीन पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना दिया जा सकता है ।

५०. अनुपस्थिति का कारण संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय केवल संस्था के प्रधान पर निर्भर रहेगा । सामान्य रूप से पिछली जियियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

५१. व्यक्तिगत प्रबन्ध के अधीन सभी संस्थाएँ विभाग द्वारा निर्धारित छुट्टियों की सूची एवं अवकाशों को प्रदान करेगी तथा संचालक की विशेष स्वीकृति के बिना उनमें से कोई भी अवकाश या छुट्टी कभी বেশी नहीं की जायेगी ।

टिप्पणी:—ऐसी छुट्टियों की सूची के लिए पुस्तक के अन्त में देखिये ।

५२. पूर्वोक्त सूची में निर्धारित छुट्टियों के अलावा कोई विशेष छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी । फिर भी शिक्षण संस्थाओं को चिकित्सको की सलाह के अनुसार व्यापक रोग के फैलने के कारण कुछ ऐसे समय के लिए बन्द रखा जा सकता है जिसके लिए नियन्त्रण अधिकारी आवश्यक समझें ।

५३. केवल विश्वविद्यालय से संलग्न संस्थाओं के प्रधानों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के प्रधानों को विशेषतया यह देखना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण संस्था का कार्य काल कम से कम साल में २०० दिन होना चाहिये तथा वे छुट्टियों एवं अवकाशों को कम करने का प्रस्ताव रख सकते हैं यदि वे यह समझें कि संस्था का कार्यकाल इस कम से कम अवधि से भी कम रहने वाला है ।

५४. 'परीक्षा एवं उन्नति' नामक अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों का टैस्ट एवं परीक्षा ली जायेगी तथा उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ाया जायेगा । फिर भी राज्य सरकार टैस्ट एवं परीक्षाओं के विषय में उत्साहात्मक प्रयोग करने के या छात्रों की प्रगति के मूल्य निर्धारण के अन्य तरीकों के अपनाने के पक्ष में है तथा संस्थाएँ विभाग की स्वीकृति प्राप्त करके विभिन्न योजनाओं को अपना सकती हैं ।

५५. सार्वजनिक प्रबन्ध के अधीन सभी शिक्षण संस्थाएँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल करेगी । सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधान माह की १५ तारीख से पूर्व मासिक शुल्क एकत्रित करने

के एवं उसे कोप में उस माह की २२ तारीख तक जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर इकट्ठा किया जाने वाला शुल्क, शुल्क के इकट्ठे किए जाने की निर्धारित तिथि से पहिले संग्रहित किया जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी यदि निर्धारित की गई अन्तिम तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराता है तो उसका नाम उपस्थित रजिस्टर में से काट दिया जायेगा। ऐसे भुगतानों की निश्चित तिथि के बाद शुल्क एवं अन्य वकाया जमा न कराने पर छः पैसे प्रति दिवस दण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा।

५६. वास्तव में योग्य छात्रों को शुल्क मुक्त करने एवं अर्धशुल्क मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संस्थाओं के प्रधानों को है। वे स्टाफ परिषद् की सलाह द्वारा इस उद्देश्य के लिए कुछ नियम बनायेंगे जिसमें वे यह सुनिश्चित कर सकें कि यह रियायत केवल गरीब एवं योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त हो।

५७. राजकीय नियमों के अनुसार केवल गरीब व्यक्तियों को ही शुल्क मुक्त किया जावे। संस्था का प्रधान कुछ पूर्ण शुल्क मुक्तियों को छात्रों के हित में अर्ध शुल्क मुक्तियों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। व्यक्तिगत प्रबन्ध के अधीन राज्यकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में यह पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं अर्ध शुल्क मुक्ति उतने ही प्रतिशत छात्रों को दी जायेगी जितनी कि राज्यकीय संस्थाओं में दी जाती है। यदि इन रियायतों में कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उसके लिए विभाग की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

५८. व्यक्तिगत प्रबन्ध के अधीन संस्थाओं में शुल्क दर का निर्णय संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा लेकिन उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक या उसी वस्ती में सहायता प्राप्त संस्थाओं से अपना शुल्क कम तय नहीं करने दिया जायेगा। इन्टर कालेजों की दशा में संचालक तथा अन्य शेष संस्थाओं की दशा में उप संचालक यह देखेंगे कि इन संस्थाओं में शुल्क की दर न तो अनुचित रूप से कम है न ज्यादा है तथा यदि ये दरें अनुचित रूप से कम या ज्यादा है तो वे अधिकारी इन संस्थाओं को उन्हें उचित रूप से बदलने के लिए निर्देशन देंगे तथा सम्बन्धित संस्थायें तब तक इन निर्देशों का पालन करेंगी जब तक कि वे उच्च अधिकारी द्वारा अपील करने पर संतोषित न कर दी गई हो।

५९. उन सभी विषयों पर जो उपरोक्त नियमों के अधीन नहीं आते उन विषयों में संस्थाओं के प्रधान अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेंगे तथा जब कभी आवश्यक होगा तो वे उच्च अधिकारियों से उस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करेंगे।

६०. सभी परिषदों, आदेशों एवं अधि सूचनाओं का, जो कि विभाग या सरकार से, संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्राप्त की जाती है, बढोस्ता के साथ पालन किया जाना चाहिए तथा संस्थाओं के प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने अधिकार के छात्रों एवं स्टाफ से उन नियमों का पालन करावें।

६१. अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं नियमितताओं के अलावा व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में, व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने की स्वीकृति एवं ऐसे अन्य मामलों में अपने अधीन अध्यापक एवं कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए विभाग अपने अलग नियम जारी करेगा।

टिप्पणी:—राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जो सेवा नियम आदि बनाये हुये हैं, उनके अलावा विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये और भी नियम बना सकेगा।

जैसे कि प्रॉइवेट ट्यूशन अथवा परीक्षा में बैठने के सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकते हैं ।

अध्याय ७

शुल्क एवं निधि

नोट:—यह अध्याय केवल राजकीय प्रबन्धाधीन संस्थाओं पर ही लागू होगा ।

१. राजकीय प्रबन्धाधीन संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों से शुल्क एवं निधि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार वसूल की जावेगी । शुल्क की वर्तमान दरें परिशिष्ट ६ में दी गई हैं ।

२.(१) ऐसी संस्थाओं में सम्पूर्ण निधि सम्बन्धी प्रशासन संस्था के प्रधान में निहित होगा जिसे कि एक समिति, जिसका नाम विद्यार्थी निविवित्त समिति होगा, सहायता एवं परामर्श देगी । संस्था प्रधान, जो कि समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, तथा छात्र समितियों जो कि विभिन्न कार्यकलापों पर अपना नियन्त्रण रखेगी जिनके लिये निधि जमा है के सचिव तथा संस्था के संघ की कार्यकारिणी यदि कोई हो तो, उसके सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे । संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों में से किसी एक सदस्य को उस समिति का सचिव बनाने के लिये नियुक्त किया जायेगा । यह समिति:—

- (i) प्रत्येक कक्षा में १०% की सीमा को ध्यान में रखते हुये इस निधि के इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई सीमा को ध्यान में रखते हुये इस निधि के शुल्क को माफ करने के आवेदन पत्रों पर ध्यान देगी ।
- (ii) विभिन्न कार्यकलापों को हाथ में लेकर समिति द्वारा तैयार किये गये बजट पर बहस करेगी तथा उसे स्वीकार करेगी ।
- (iii) संस्था के प्रधान की सहमति से विभिन्न समितियों द्वारा खर्च किये जाने वाले खर्चों की शक्तियों की व्याख्या करते हुये नियम बनायेगी ।
- (iv) विशेष आवश्यकता पर एक निधि को दूसरी निधि में परिवर्तित करेगी ।
- (v) निधि के उचित उपयोग सम्बन्धी अन्य सभी मामलों पर कार्यवाही करेगी ।
- (२) प्रत्येक निधि के लिये नियमित वार्षिक बजट तैयार किया जावेगा ।
- (३) निम्न विषयों पर निधि का उपयोग किया जायेगा:—

(अ) परीक्षा निधि:—

संस्था द्वारा आयोजित ग्रुह परीक्षा की व्यवस्था करना ।

(ब) वाचनालय कक्ष निधि:—

- (i) वाचनालय हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के लिये चन्दा देना ।
- (ii) छात्रों के लिये आवश्यक पुस्तकें क्रय करना ।
- (iii) पत्रिकाओं की जिल्द साजी पर खर्च ।
- (iv) वाचनालय के सम्बन्ध में अन्य फुटकर खर्च ।

(स) खेल निधि:—

- (i) मैचों एवं स्थानीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में टीम के प्रवेश शुल्क का भुगतान ।
- (ii) उपरोक्त वर्णित मैचों या प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में खिलाड़ियों या आमन्त्रित टीमों के लिये अल्पाहार ।
- (iii) ग्रन्थासार्व मैचों या प्रतियोगिताओं की व्यवस्था, जैसे निमन्त्रण पत्र तथा कार्यक्रमों के छपवाने आदि का प्रबंध ।
- (iv) खेलकूद में निपुणता प्रकट करने वालों के लिए विशेष पुरस्कार या पदक ।
- (v) वित्त समिति द्वारा स्वीकृत खेलकूदों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कार्य करने वाले सहायक कर्मचारियों को भत्ता या पुरस्कार ।
- (vi) खेलों के सामान की मरम्मत ।
- (vii) खेलकूद पर स्टेशनरी या अन्य फुटकर ऐसे खर्चें जो कि विभागीय वजह से नहीं किये जा सकेंगे ।

(ख) पत्रिका निधि:—

- (i) खेलों की प्रेस प्रतियों को तैयार करना ।
- (ii) प्लेक की कीमत आदि ।
- (iii) पत्रिका समिति के कार्यालय में फाम हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं अन्य फुटकर खर्चें ।
- (iv) पत्रिका का मुद्रण ।

(ग) सामाजिक संगठन निधि:—

- (i) सामाजिक एकत्रीकरण तथा उत्सवों के मनाये जाने पर खर्च एवं स्वस्थ सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अभिवृद्धि करने वाले अन्य कार्यक्रमों पर खर्च ।

(घ) संघ शुल्क निधि:—

- (i) संघ कार्यालय के लिये स्टेशनरी तथा अन्य फुटकर खर्चें ।
- (ii) संघ के उत्सव तथा सत्र (Sessions) पर खर्चा ।
- (iii) कोई ऐसा खर्च जो संघ एवं उसकी कार्य कारिणी द्वारा स्वीकार किया गया हो तथा प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के हित में उसे स्वीकार कर लिया गया हो ।

(च) महाविद्यालय छात्रावास सामान्य वक्ष शुल्क निधि:—

- (i) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ ।
- (ii) अन्तर्गत क्रीडायें (Indoor Games)
- (iii) प्रतियोगिता (छात्रालय व उसके अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम)।

(४) उपरोक्त निधियों के अतिरिक्त संस्था का प्रधान निम्न निधियाँ एवं संघ और स्थापित कर सकता है:—

- (i) छात्र सहायता निधि
- (ii) नाट्य संघ
- (iii) साहित्य समाज ।
- (iv) अन्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संघ

३. छात्र सहायक निधि, जिसका उपरोक्त अन्तिम नियम में उल्लेख किया गया है, की व्यवस्था एवं प्रशासन निम्न प्रकार से होगा:—

- (i) इस निधि को दान एकत्रित करके तथा स्वेच्छा के आधार पर विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों से चन्दा इकट्ठा कर बढ़ाया जावेगा ।
- (ii) इस निधि से केवल उपयुक्त परिस्थिति वाले छात्रों के अतिरिक्त किसी को किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जायेगा तथा न भुगतान ही किया जायेगा ।

नोट:—उपयुक्त विद्यार्थियों से तात्पर्य उस विद्यार्थी से है जिसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तथा जो अपनी गरीबी या योग्यता (Merit) के कारण ऐसी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी हो ।

- (iii) प्राप्त तथा उसमें से भुगतान की गई धन राशि का सही हिसाब संस्था के कार्यालय में रखा जावेगा ।
- (iv) संस्था के प्रधान द्वारा लिखित अधिकार के बिना कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जितना भी भुगतान किया जायेगा उन सब की रसीद ली जायेगी एवं सब प्राप्त धन की रसीद दी जायेगी । प्राप्त धन के लिये एक छपी हुई तथा क्रम संख्या लगी हुई रसीद पुस्तिका उपयोग में लेनी चाहिए ।
- (v) कालेजो में उपयुक्त छात्रों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में आवश्यक जांच एक वरिष्ठ अध्यापक द्वारा की जावेगी जिसे की छात्रों की सहायता देने हेतु संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किया जावेगा और जो विद्यार्थियों के द्वारा इस निधि की समिति का सचिव चुना जावेगा । शालाओं में ऐसी जांच में सहायतार्थ एक सदस्य स्टाफ का होगा जो संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किया जायेगा । जो संस्थायें बड़े शहरों अथवा कस्बों में हैं वहां इस मामले में सहायतार्थ बहुत से वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं ।
- (vi) विद्यार्थियों को सहायता सामान्यरूप से पुस्तकों के रूप में दी जायेगी । किन्हीं विशेष कारणों में ही नकद रकम की सहायता दी जायेगी ।

४. नियम दो के उपनियम ४ में क्रम संख्या (१) (२) में वर्णित संघों की व्यवस्था, प्रशासन एवं अर्थ व्यवस्था के संबंध में निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए :—

(१) यह निधि इन संघों के सदस्यों से मासिक या वार्षिक चन्दा इकट्ठा करके बढ़ानी चाहिए । तथा इन संघों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए, विविध दृश्य, नाटकों सिम्पोजियम आदि का आयोजन एवं प्रदर्शन के माध्यम को अपनाना चाहिए ।

(२) सामान्यरूप से इन संघों के कार्यकर्ता निम्न प्रकार से होंगे:—

- १ अध्यक्ष
- २ उपाध्यक्ष
- ३ सचिव
- ४ कोषाध्यक्ष
- ५ कार्यकारिणी समिति के ५ सदस्य

(३) संस्था का उपाध्यक्ष संघ की सब कार्यवाहियों का निरीक्षण करेगा तथा संघ द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जायेगा उन पर संस्था के प्रधान की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

५. निधियों के हिसाब रखने आदि के लिये निम्न लिखित नियम हैं:—

(i) खेल एवं स्पोर्ट्स या क्रीडास्पर्त पर अनुशासन का पालन न करने के कारण जो निधि वसूल की जायेगी वह खेल निधि में जमा की जायेगी।

(ii) सरकारी क्रम संस्था लगी हुई निर्धारित प्रपत्र में रसीद प्राप्त की गई उस सब धनराशि के लिए दी जायेगी जो इन निधियों में जमा की जायेगी।

(iii) इन रसीदों को उनसे सम्बन्धित निधियों जैसे व्यायाम निधि, अध्ययन कक्ष निधि एवं परीक्षा निधि आदि में जमा किया जायेगा।

(iv) (संघों की निधियों को छोड़कर) अन्य निधियों की सम्पत्ति:—

(१) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक अकाउन्ट में या

(२) संस्था द्वारा स्वीकृत किसी बैंक में जिसमें संस्था के नाम से खाता खोला जाना है; या

(३) संस्था के प्रधान के विशेष उत्तरदायित्व पर शाला या महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करादी जायेगी।

(४) सार्वजनिक हिसाब रखने के लिए राजकीय नियमों के अनुसार निधियों का हिसाब शाला या कालेज के कार्यालय में रखा जायेगा। उनका निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा या लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

टिप्पणी:—उपरोक्त हिसाब किताब रखने के लिये कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिये। अलग अलग फंड के लिये प्राप्त की गई रकम को अलग अलग फंड में जमा की जानी चाहिये। इन विभिन्न निधियों की रकम को फिर डाक घर में वचत खाता अथवा किसी स्वीकृत बैंक में जमा करादी जानी चाहिये। इन निधियों का हिसाब विभाग अथवा लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सकता है।

अध्याय ८

सन् १९५६ में आयोजित प्रशासनिक शिक्षाधिकारियों के सम्मेलन में प्रस्तावित तथा श्री अतिरिक्त शिक्षा संचालक जी द्वारा

स्वीकृत, परीक्षा व प्रमोशन्स के नियम

सभी कक्षाओं में परीक्षा तथा प्रमोशन्स के नियम निम्नलिखित होंगे।

जिन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का सम्बन्ध विभागीय एवं सार्वजनिक परीक्षाओं से है, उनमें परीक्षा के नियम तदनुसार पालित होंगे। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रमोशन के नियम किसी कक्षा के लिए वे ही होंगे जो उस वर्ष उस कक्षा के लिये पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं।

१. तृतीय कक्षा से ११ वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष नियमित अन्तर के साथ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के तीन परीक्षण टेस्ट होंगे और उनका कक्षागत व शालागत विवरण संस्था का प्रधानाध्यापक तैयार करेगा।

२. सत्र में दो परीक्षाएँ होंगी। एक किसी भी समय मास नवम्बर में तथा दूसरी १५ अप्रैल के पश्चात्। ये दोनों परीक्षाएँ क्रम से अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक परीक्षाएँ कहावेंगी। इन परीक्षाओं का परिणाम प्रोत्सावकाश में शालाओं के बन्द होने पूर्व घोषित कर दिया जावेगा।

३. परम्परागत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शालाओं में कक्षा ३ से ६ तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा १० तक तथा इन्टर कालेजों में ११ वी कक्षा तक कोई भी विद्यार्थी अपनी वार्षिक परीक्षा में उस समय तक सम्मिलित नहीं हो सकेगा जब तक उसकी उपस्थिति अपनी कक्षा में अपनी प्रवेश तिथि से परीक्षा प्रारम्भ होने तक अपनी रूग्णावस्था व अनिवार्य परिस्थितियों पर आधारित प्राप्त अवकाश सहित ६० प्रतिशत नहीं हो जावेगी, पर साथ ही उसकी वास्तविक उपस्थितियों का कुल योग भी परीक्षाकाल सहित शाला के कार्यकाल का ६० प्रतिशत होना अनिवार्य होगा। संस्था का प्रधान अपनी शाला की ६० प्रतिशत उपस्थिति के योग की १० प्रतिशत कमी को विशेष परिस्थिति में क्षमा कर सकता है पर ६० प्रतिशत उपस्थिति की कमी को पूरा करने का उसको कोई अधिकार नहीं होगा।

४. परीक्षार्थियों की संख्या १० से अधिक होने की दशा में प्रश्न पत्र मुद्रित अथवा साइकिलो-स्टाइल्ड तथा इससे कम संख्या होने पर प्रश्न पत्र साइकिलो स्टाइल्ड अथवा कारबन पेपर से निकाले हुए होंगे।

५. अ—तृतीय कक्षा से ११ वीं कक्षा तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के साथ केवल एक दिन का अवकाश दिया जावेगा।

(ब) वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सब कक्षाओं में रविवार तथा अन्य राजपत्रांकित अवकाश के अतिरिक्त दो दिन का अवकाश दिया जावेगा।

नोट—१० वीं, ११ वीं व १२ वीं कक्षाओं के लिए जिनका सम्बन्ध माध्यमिक शिक्षा परिपद से तैयारी के लिए अवकाश परिपद के नियमानुसार दिया जावेगा।

६. केवल उस संस्था को छोड़कर जिसको शिक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए विभाग द्वारा मूल्यांकन प्रणाली की वैकल्पिकता की स्वीकृति प्राप्त हो, अन्य सब कक्षाओं में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोशन देने के नियम निम्नलिखित होंगे।

६(अ) विद्यार्थियों को प्रमोशनस उनके सामयिक परीक्षा टेस्ट, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम को मिलाकर इस प्रकार दिये जावेंगे।

१. प्रत्येक विषय के लिए २०० अंक निर्धारित होंगे जिनमें से ३० अंक सामयिक परीक्षाओं टेस्टों के लिए ७० अंक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए तथा शेष १०० अंक वार्षिक परीक्षा के लिए नियत होंगे। परन्तु कक्षा ६ में तथा इससे आगे की कक्षाओं में अनिवार्य विषयों के लिए १०० तथा ऐच्छिक विषयों के लिए २०० अंक रखे जावेंगे।

२. यदि ८ वीं कक्षा तक का कार्य विद्यार्थी संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं में तथा संगीत, प्रकृति अध्ययन, उद्योग इन क्रियात्मक विषयों में अपने वांछनीय न्यूनतम अंक स्तर तक पहुंचने में असफल रहता है तो वह इस गणना में नहीं आवेगा। विद्यार्थियों का इन विषयों में नियमित रूप से भाग लेना ही पर्याप्त होगा।

३. किसी विद्यार्थी का उसकी परीक्षा में स्थान निर्णय उसके सामयिक परीक्षण (टेस्ट) अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा इन सब में प्राप्त अंकों के योग पर प्रमोशन के लिये निर्धारित अंकों के अनुरूप होगा।

(व) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम ३६ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा पर प्रत्येक विद्यार्थी को 'सिवाय उम दशा के कि उसको अपनी रुग्णावस्था के कारण उस परीक्षा में सम्मिलित होने में मुक्त कर दिया गया है' अपनी वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में २० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(स) १. किसी भी विषय में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी विशेष योग्यता के अधिकारी समझे जावेंगे।

२. प्राप्त अंकों के कुल योग के ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे।

३. प्राप्त अंकों के कुल योग के ५० प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे।

४. प्राप्त अंकों के कुल योग के ३६ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपनी परीक्षा में तृतीय श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे।

(द) १. यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको ८ प्रतिशत अंक तक का ग्रेस उस दशा में दिया जा सकता है जबकि उसने अपने कुल विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णों के योग से उतने ही अंक अधिक प्राप्त किए हों। कुल प्राप्त अंकों के योग में नियम संख्या ६ अ २ में अंकित विषयों के अंक नहीं जोड़े जावेंगे। यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसको उस दशा में जब कि उसने उससे पूर्व कक्षा में उस विषय में कम से कम २५ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों ३ प्रतिशत अंक ग्रेस के और दिए जावेंगे।

२. यदि कोई विद्यार्थी किन्हीं दो विषयों में अपने न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसको १०० व २०० अंकों वाले विषयों में कम से कम ५ व १० अंक तक ग्रेस के और दिये जा सकेंगे। ग्रेस के अंकों का आवश्यकतानुसार वितरण दोनों विषयों पर हो सकेगा।

(य) यदि कोई विद्यार्थी अपनी गम्भीर रुग्णावस्था के कारण अपने किसी सामयिक परीक्षण (टेस्ट) या अर्द्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो उसको केवल उन्ही परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर जिनमें सम्मिलित हुआ है प्रमोशन दिया जा सकेगा। इसके साथ नियम संख्या ६ का व खण्ड अवलोकनीय है। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से अपने एक सामयिक परीक्षण (टेस्ट) और दो परीक्षाओं में अथवा दो परीक्षण (टेस्ट) और किसी एक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका है तो उसके प्रमोशन का मामला इस नियम के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होगा।

(फ) किसी विद्यार्थी का अपने सामयिक परीक्षा अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की असमर्थता के लिये प्रार्थना पत्र सम्बन्धित परीक्षा के एक सप्ताह की अवधि में आजाना चाहिए ।

(ज) उन विद्यार्थियों को जो अपने किसी भी सामयिक परीक्षाएँ (टैस्ट) अथवा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, को ग्रेस नहीं दिया जायेगा ।

७ (अ) परीक्षा फल घोषित होते ही परीक्षा फल की एक प्रति तुरन्त अपने से निकटतम अधिकारी के पास प्रेषित की जावेगी । वह अधिकारी सम्बन्धित संस्था के प्रधानाध्यापक के पास उस संस्था के परीक्षा फल के सम्बन्ध में सामान्य निर्देशन व सुझाव भिजवायेगा ।

(ब) परीक्षा फल घोषित हो जाने के पश्चात् एक सप्ताह की अवधि में परीक्षार्थी के पास उसकी अंकसूची पहुंच जानी चाहिए ।

(स) परीक्षा फल की जांच पड़ताल के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात् १५ दिन के अवधिकाल में सम्बन्धित संस्था के पास पहुंच जाना चाहिए ।

(द) परीक्षाफल की जांच पड़ताल तथा नियम संख्या ७ स के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पूर्ण निर्याद दिनांक १५ जुलाई तक हो जाना चाहिए । यदि परीक्षा फल की जांच के परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन उपर्युक्त नियमों के बाहर अपेक्षित हो तो इसके लिए प्रार्थना पत्र एक सप्ताह के भीतर दूसरे उच्चतर अधिकारी के पास भिजवाया जायेगा ।

विज्ञप्ति—संख्या ई डी बी । ए सी ए । बी—२।१४२०६।२।६४ दिनांक २६-२-६५ अतिरिक्त अध्यक्ष-प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा समस्त सम्बन्धितों को प्रसारित ।

विषय - परीक्षा तथा प्रमोशन के नियम

निम्नलिखित वर्तमान बढ़ोतरी एवं परिवर्तन परीक्षा एवं उन्नति के नियमों में शीघ्र कार्य-वाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ।

१-निम्नांकित शब्द नियम संख्या ६(डी) (1) ग्रेस नम्बर के सम्बन्ध में से हटाये जाते हैं ।

वर्शते कि वह पिछली परीक्षाओं में कम से कम उत्तीर्ण होने वाले नम्बरों में अधिक से अधिक नम्बर प्राप्त करें ।

२-दो विषयों में ग्रेस नम्बर के सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्तमान नियम संख्या (डी) (11) में निम्नांकित बढ़ोतरी की जाती है:—

यदि दो विषयों में कुल योग २०० हो तो ८ नम्बर का ग्रेस दोनों विषयों में बांटा जा सकता है ।

नोट:—१-दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को ग्रेस नम्बर किसी भी दशा में फेल होने वाले विषय में प्राप्त नम्बर के समान या अधिक नहीं होने चाहिए । चाहे वह एक ही विषय में फेल हो ।

२-ग्रेस नम्बर प्रत्येक विषय में दिया जा सकता है चाहे उत्तीर्ण होने की प्रतिशत ३६% हो या २५% ।

३-परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी को ग्रेस नम्बर न दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम संख्या (६)(ए) लागू किया जावे ।

ग्रेस नम्बर उसी विद्यार्थी को देने चाहिए कि जिसे शालाप्रमुख ने अस्वस्थ होने के कारण क्षमा कर दिया हो अथवा किन ही उचित कारणों के आधार पर जिन शाला प्रमुखों में उच्च अधिकारियों द्वारा टेस्ट या परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थी को मना कर लिया है। इस स्थिति ने उसको विषय के अधिकतम नम्बर के अनुपात से जिस विषय में वह प्रविष्ट हुआ हुई है, ग्रेस नम्बर मिलने चाहिए। लेकिन अगर वह किसी ऐसे स्कूल अथवा दूसरे राज्य से आता है जहाँ पर कि मासिक टेस्ट या तिमाही परीक्षा नहीं होती है तो उसी तो उसे प्रमोशन वार्षिक परीक्षा से प्राप्त नम्बरों के आधार पर प्राप्त होगा और उसे ग्रेस परीक्षा में प्रविष्ट अधिकतम नम्बरों के अनुपात पर ही मिलेगा जिसमें वह प्रविष्ट हुआ है।

४-असत उपस्थिति के सम्बन्ध में विद्यमान नियम संख्या ३ पूर्व सत्र १९६५-६६ उन विद्यार्थियों के लिए जो अप्रैल ६६ व उसके पूर्व पश्चात में वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हों लागू किया जावे:—कोई भी विद्यार्थी जिसकी उपस्थिति स्कूल मीटिंग जुलाई से अप्रैल तक के सत्र तक ७५% से कम होने पर स्कूल की वार्षिक परीक्षामें प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए अथवा उसे जिस तिथि से कक्षा में प्रमोशन मिली हो (१ वर्ग की १५ अप्रैल) तक (उस स्थिति में जबकि उसे देर से देर से प्रमोशन मिली हो)।

शाला प्रमुख पूर्व सत्र में जुलाई १५ अप्रैल तक स्कूल खूलने की मीटिंगों में और ऐसे विद्यार्थी जिन्हें देर से प्रमोशन प्राप्त हुआ था उनको प्रमोशन तिथि से १५ अप्रैल तक १०% की कमी को क्षमा कर सकता है।

निम्नलिखित नियम १९६६ की वार्षिक परीक्षा से लागू होगा जिसे कि नियम ८ में सरक्यूलर संख्या ई डी वी। ए०सी०ए०/बी-२।१४२२१।एस०पी०/६० दि० २७।१।६० की संख्या दी जावेगी।

(अ) प्राइवेट छात्राएं एवं राज्य कर्मचारी

निम्नलिखित इन्स्पेक्टर और उप निरीक्षक शिक्षणालय से चर्ची व इसके नीचे की कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा में बैठने की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, वशत कि वह अपना प्रार्थनापत्र फीस सहित मार्च तक पूर्ण रूप से भेज दें या इसके बाद अधिकारीगण के सम्बन्ध के प्रबन्ध करने पर देर से भेज सकते हैं।

(१) छात्राओं को अपने संरक्षकों से राजस्थान के निवासी होने तथा पिछली ५ सालों से किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का लिखित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा जिसमें वह प्रमाणित किया हो कि छात्रा उसी कक्षा में पढ़ रही थी जिस परीक्षा में यह प्रविष्ट होना चाहती है तथा वह किसी कठिनाइयों के कारण स्कूल छोड़ना चाहती है।

२-राज्य कर्मचारी जिसे विभागाधिकारी व अपने कार्यालय से जहाँ वह कार्य कर रहा है आज्ञा प्राप्त होने पर पुनः यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये पहले ५ सालों से किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की है और यदि पढ़े हैं तो निरंतर शिक्षा प्राप्त कर उस कक्षा तक पहुँचे हैं।

(बी) उत्तीर्ण होने के लिए वार्षिक परीक्षा के पेपर पर अंकित अंकों में से ३६% अंकों की जरूरत होगी।

(सी) वे बराबर के ग्रेस नम्बर लेने के भी अधिकारी हैं।

डी:-)संस्कृत में उत्तीर्ण होने के लिए २५% अंकों की आवश्यकता होगी (न० ई डी बी ए जी ए. बी २-४२०६

ह०
अतिरिक्त शिक्षा संचालक,
राजस्थान बीकानेर,
दि० २२-४-६५

अध्याय ६

प्रशिक्षण-संस्थाएँ

१. वर्गीकरण:—राज्य में स्थित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ उनमें दी जाने शिक्षा के स्तर के अनुसार निम्नानुसार वर्गीकृत हैं:—

- (अ) एम० एड०
- (ब) स्नातकों के लिये, शिक्षा में उपाधि, बी० एड०
- (स) इन्टर तथा मैट्रिक पास के लिये बेसिक एस० टी० सी०, व शिक्षा में डिप्लोमा ।

२. प्रशिक्षण का कोर्स:—उपरिलिखित अध्यापकीय प्रशिक्षण के समस्त कोर्स एक शैक्षणिक सत्र के होंगे तथा उनकी समाप्ति पर छात्र द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त तथा व्यवहार में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने की स्थिति में उपाधि अथवा डिप्लोमा, जैसी भी अवस्था हो, दिये जायेंगे ।

३. एम० एड० तथा बी० एड० की उपाधियों के प्रशिक्षण के कोर्स विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियन्त्रण में होंगे जब कि बुनियादी प्रशिक्षण (एस० टी० सी०) के कोर्स विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

४. चयन (Selection):—विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिये प्रत्याशियों का चुनाव नियमों तथा आदेशों के अनुसार संचालक, उप-संचालक तथा निरीक्षक द्वारा किया जावेगा । साधारणतया २० वर्ष से कम तथा ३५ वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जायेगा । प्राथमिकता उनको दी जावेगी जो स्वीकृत शैक्षणिक अनुभव रखते हों तथा जो कि अन्य सब दृष्टि से योग्य हों । यदि विभाग सन्तुष्ट है कि कोई प्रत्याशी प्रशिक्षण से लाभान्वित होने वाला है तो एम० एड० के प्रशिक्षण के लिये विभाग ५ वर्ष की छूट दे सकता है ।

टिप्पणी:—प्रशिक्षण (Training) के लिये भेजे जाने वाले अध्यापकों की आयु २० तथा ३५ वर्ष के बीच की ही होनी चाहिये । केवल एम० एड० के लिये आयु सीमा में ५ वर्ष की छूट दी जा सकती है । अनुभवी व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भेजने के लिये प्राथमिकता दी जावेगी ।

५. प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या संचालक निर्धारित करेगा । वह प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च १९६२ से पूर्व विभिन्न श्रेणियों (Ranges) निरीक्षणालयों तथा व्यक्तिगत प्रबन्धाधीन संस्थाओं में से इन प्रशिक्षण संस्थाओं के भेजे जाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित करेगा ।

६. विभाग की सरकारी वरिष्ठता सूची के आधारे पर ही वरिष्ठता मानी जावेगी। बी० एड० के प्रशिक्षण के लिये ग्रेज्यूएट ग्रेड (स्थायी) में से अध्यापकों को नियमानुसार भेजा जावेगा। वेसिक एस० टी० सी० के लिये अध्यापकों की नियुक्ति संचालक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए गए आदेशों के अनुसार ही हो। यदि संचालक की राय है कि किसी व्यक्ति का विशेष कारणों से चयन किया जाना चाहिये, तो वह उस मामले को सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर देगा।

७. सरकारी संस्थाओं में से अध्यापकों का चुनाव किए जाने के अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त निजी प्रबन्ध की संस्थाओं के अध्यापकों व गैर सरकारी प्रत्याशियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया जावेगा। जुलाई से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिये, शालाओं के व्यवस्थापकों, जो कि अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये इच्छुक हों, अथवा गैर सरकारी प्रत्याशियों, को सम्बन्धित निरीक्षक को फरवरी मास में ही प्रार्थना पत्र दे देना चाहिये।

८. निजी प्रबन्ध की मान्यता प्राप्त संस्थाएँ, प्रशिक्षणार्थ भेजे गये अपने प्रत्याशियों को वेतन आदि की वही सुविधायें देगी जो कि सरकार द्वारा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अपने अध्यापकों को दी जाती है।

९. प्रशिक्षण के लिये चुने गये समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण केन्द्र पर सत्रारम्भ के दिन उपस्थित होना चाहिये। इसके बाद प्रवेश उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जब कि विलम्ब से उपस्थित होने के लिये स्वीकृति उचित अधिकारी से पहिले ही प्राप्त कर ली गई हो। सत्रारम्भ के एक माह बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

१०. जिन अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये चुन लिया गया है, उनको प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होना आवश्यक होगा। इससे मना करने वाले अध्यापक को या तो सेवा से पृथक् किया जा सकेगा अथवा ऐसी सजा दी जा सकेगी जो कि चयन करने वाला अधिकारी उपयुक्त समझे।

११. जिस वर्ष प्रशिक्षण के लिये किसी अध्यापक को भेजा जाना है उससे पूर्व के सत्र में ही प्रशिक्षण के लिये चुनाव समाप्त हो जायेंगे ताकि ग्रीष्मावकाश के लिये पाठशालाओं के बन्द होने से पूर्व ही प्रत्याशियों को ज्ञात हो जावे कि उन्हें अगले सत्र में प्रशिक्षण के लिये जाना है।

१२. सार्वजनिक संस्थाओं के उन सब अध्यापकों, जो कि अस्थाई नियुक्ति पर हैं, को उनके प्रशिक्षण के लिये चुने जाने की स्थिति में, प्रशिक्षण में प्रवेश देने से पूर्व, निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी एक चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (Medical Certificate) प्रेषित करना पड़ेगा।

१३. सार्वजनिक प्रबन्ध की संस्थाओं में से प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किए गए अध्यापक अपने प्रशिक्षण काल में साधारणतया अपने वेतन के समकक्ष पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे। ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी प्रवेश प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में, प्रतिभूतियों (Sureties) के साथ निम्न प्रावधानों सहित एक अनुबन्ध करेंगे:—

(अ) कि प्रशिक्षण काल में वह अपनी प्रशिक्षण संस्था के नियमों का पालन करेगा तथा निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये निश्चित पाठ्यक्रम को उत्साह, नियमितता व परिश्रम के साथ पूरा करेगा और व्यावसायिक प्रमाण-पत्र के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण के समय प्राप्त किये जाने वाले वेतन पर ही, उसको तीन वर्ष तक विभाग की सेवा करनी आवश्यक होगी।

(ब) कि प्रशिक्षण प्राप्त करते समय वह किसी अन्य परीक्षा के लिये तैयारी अथवा कोई

अन्य व्यय नहीं करेगा ।

(स) कि प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, तीन वर्ष की अवधि में बिना किसी वधाने के, चाहे किसी भी पद पर नियुक्त किया जावे, वह शिक्षा विभाग की सेवा करेगा ।

(द) वह प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर, अधिकार के रूप में उच्च पद की मांग नहीं करेगा ।

(य) कि प्रशिक्षण की अवधि में अथवा प्रशिक्षण समाप्ति और अनिवार्य सेवा के मध्य की अवधि पूरी होने से पूर्व, अपनी स्वयं की इच्छा से अथवा, किसी गलती के कारण यदि वह विभाग की सेवा से मुक्त होगा, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ पारिश्रमिक उसने सरकार से प्राप्त किया, वह पूरा अथवा तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा की अवधि के बाकी बचे हुए भाग के अनुपात से बचने वाली रकम, वापिस लौटा देगा ।

१४. दुर्व्यवहार अथवा बिना छुट्टी के लगातार अनुपस्थिति के कारण यदि किसी छात्राध्यापक को प्रशिक्षण संस्था को छोड़ने का आदेश दिया जावेगा, तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया समस्त पारिश्रमिक, उसे लौटाना होगा ।

१५. दुर्व्यवहार अथवा बिना छुट्टी के लगातार अनुपस्थिति के कारण किसी भी छात्राध्यापक का शाला से निष्कासन किया जा सकता है किन्तु सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में ऐसा करने से पूर्व उसका चुनाव करने वाले अधिकारी से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये । और यदि ऐसी प्रशिक्षण संस्थाये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों तो संस्थाओं के प्रधान केवल ऐसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्हें मिली हुई है ।

१६. अनुबन्ध में उल्लिखित सरकार को देय रकम, सरकारी बकाया की भांति ही वसूल की जावेगी ।

१७. समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में, छात्रावास में रहना अनिवार्य है तथा कुछ विशेष मामलों और उनमें भी कारणों को बतलाये जाने के बाद संस्था के प्रधान की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है, के अलावा बाहर रहने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी ।

१८. सार्वजनिक प्रबन्धाधीन प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग द्वारा नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा । प्राईवेट प्रत्याशियों अथवा उनको जो कि निजी प्रबन्ध की संस्थाओं में से आये हैं, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा । समस्त प्रत्याशियों, जिनमें कि सार्वजनिक प्रबन्ध की संस्थाओं के भी सम्मिलित हैं, को बशर्त कि वे संस्था के नियमों के अनुसार उनको देने के भार से मुक्त नहीं हैं, निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा ।

१९. निजी प्रबन्ध की प्रशिक्षण संस्थाओं में सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्याशियों का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जावेगा ।

२०. प्रशिक्षण की अवधि में छात्राध्यापकों को १५ दिन का आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा तथा बीमारी के कारणों से आधे वेतन पर भी अवकाश मिल सकेगा किन्तु आकस्मिक अवकाश सहित कुल अवकाश प्रशिक्षण अवधि में ३० दिनों से अधिक का नहीं हो सकेगा किन्तु बीमारी की विशेष अवस्था में १५ दिन का अवकाश और मिल सकेगा । इससे अधिक अवधि तक अनुपस्थिति रहने पर छात्राध्यापक को प्रशिक्षण संस्था से निकाला भी जा सकेगा ।

टिप्पणी:—प्रशिक्षण की अवधि में १५ दिन का सवेतन अवकाश, १५ दिन का आधे वेतन पर अवकाश तथा १५ दिन की विशेष बीमारी की छुट्टी मिल सकेगी। इससे अधिक छुट्टी किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकती।

२१. छात्राध्यापकों को सब प्रकार की छुट्टी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधान स्वीकृत करेंगे।

२२. यदि कोई छात्राध्यापक बिना छुट्टी के एक सप्ताह या अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम प्रशिक्षण संस्था से काट दिया जावेगा। ऐसे छात्र को पुनः प्रवेश तब तक नहीं दिया जावेगा जब तक कि उस अधिकारी से, जिसने उसका प्रशिक्षण के लिए चुनाव किया था, स्वीकृति नहीं ले ली जावे। किसी भी अवधि के लिए, बिना छुट्टी अनुपस्थित रहने पर उस अवधि का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।

२३. सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं में व्यतीत किया गया समय सेवा काल ही माना जावेगा तथा उनके प्रशिक्षण के समाप्ति के उपरान्त उनके वेतन में मिलने वाली वेतन वृद्धि के निर्णय करते समय उनको ध्यान में रखा जायेगा।

२४. सरकारी संस्थाओं से नियुक्त किए गए अध्यापकों को अपनी शाला से प्रशिक्षण केन्द्र तक की तथा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् उनकी नियुक्ति के स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता मिलेगा। यदि ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी नियुक्ति के विद्यालय के लिए, वे प्रशिक्षण केन्द्र से कार्यभार नहीं किए गए हों, तो चाहे वे सीधे प्रशिक्षण केन्द्र से सपने नियुक्ति स्थान पर नहीं गये हों, फिर भी वे प्रशिक्षण केन्द्र से अपनी नियुक्त की पाठशाला तक का यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

२५. अनुशासन भंग करने पर संस्था के प्रधान को छात्राध्यापक पर २) २० तक जुर्माना करने अधिकार होगा। यदि यह सजा अशिष्टता के लिए दी गई हो, तो यह बात उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) में लिखी जावेगी किन्तु यह धारा, विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के प्रधान को प्रदान की हुई शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकेगी।

२६. सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें वे सदृष्टियाँ करेंगी जो कि विभागाधीन अन्य संस्थाएँ करती हैं।

२७. छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क, जो कि निर्धारित होंगे, समस्त छात्राध्यापकों से लिए जावेंगे।

२८. ऐसे महिला प्रत्यागी जिनके छोटे बच्चे होंगे अथवा जो प्रशिक्षण काल में Maternity leave चाहती हों, प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजी जा सकेंगी।

२९. विद्यालयों का प्रशिक्षणशालाओं से सहयोग:—(अ)—प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण की विधि पर आधारित शैक्षणिक कार्य में आदर्श विद्यालय (Model School) सुधार रूप में कार्य करें, इसलिए तथा उनमें यथेष्ट सहयोग एवं आपसी प्रभाव डनाये रखने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि—

(१) आदर्श विद्यालयों पर शैक्षणिक नियंत्रण सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के प्रधान का रहेगा।

(२) प्रशिक्षण संस्था के प्रधान के सहयोग से आदर्श विद्यालय के प्रधान अपनी शाला का

काल विभाजन चक्र (Time Table) बनायेंगे, उसमें संशोधन कर सकेंगे, कार्य के घण्टे बदल सकेंगे तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों का आयोजन कर सकेंगे ।

- (३) वे प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानों तथा छात्राध्यापकों को अपने व्यावहारिक शिक्षण के लिए समस्त सुविधायें प्रदान करेंगे ।
- (४) सम्बन्धित आदर्श विद्यालय के प्रधान को आकस्मिक अवकाश प्रशिक्षण संस्था के प्रधान स्वीकृत करेंगे ।
- (५) प्रशिक्षण संस्था का स्टाफ (Staff) छात्राध्यापक तथा आदर्श विद्यालय का स्टाफ दोनों विद्यालयों की अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा ।

(व) संगठित जीवन यापन प्रशिक्षण संस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होने से, अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों के आयोजन तथा उनसे प्रत्येक छात्राध्यापक एवं अध्यापक वर्ग द्वारा भाग लिये जाने पर जोर दिया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये:—

- (१) छात्राध्यापकों की प्रगति आदि पर नियंत्रक अध्यापकों द्वारा दी गई सार्वधिक टिप्पणी (Periodical Remarks) के साथ साथ, प्रत्येक छात्राध्यापक द्वारा उपरोक्त सामाजिक प्रवृत्तियों में लिए गए भाग तथा किए गए कार्य का उचित आलेख रखना चाहिए ।
- (२) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में अध्यापकों के सहयोग एवं देखरेख में प्रत्येक छात्र अध्यापक के चरित्र, आदत, रुचि, स्वभाव, पसन्द तथा नापसन्द एवं साधारण चान-चलन का मूल्यांकन किया जावेगा । सत्र के दौरान में प्रत्येक छात्राध्यापक से इस संबंध में यदि कोई प्रगति अथवा परिवर्तन हुआ होवे, तो उनको आगे दृष्टिगत रखा जावेगा । सत्र समाप्ति पर उपरोक्त मूल्यांकन पर पुनर्विचार किया जावेगा तथा अन्तिम निरूपण लिखित किया जावेगा ।
- (३) यद्यपि समस्त सामाजिक प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये, फिर भी निम्न में छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखना चाहिए:—

- (अ) स्काउटिंग
- (ब) प्राथमिक उपचार व रेडक्रास
- (स) शारीरिक ड्रिल व जिमनास्टिक
- (द) समाज सेवा, ग्राम-सर्वेक्षण तथा सुधार कार्य ।

अध्याय १०

छात्रावास

नोट:— इस अध्याय का नियम १ व ३ केवल सार्वजनिक प्रबन्ध की संस्थाओं पर ही लागू होते हैं ।

१. छात्रावास की स्थापना:—उन छात्रों, जिनका कि शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर अपना मकान नहीं हो, को शिक्षा संबंधी सुविधायें देने के लिये, जब भी कभी ऐसी मांग होगी, तभी सार्व-

जनिक संस्थाओं के लिये छात्रावास स्थापित करने के लिये जहां कहीं संभव हो सके, विभाग आवश्यक प्रावधान करेगा ।

२. सामान्य नीति के अनुसार, छात्रावास साधारणतया निम्न संस्थाओं से संलग्न रहेंगे ।

(१) महाविद्यालय (Colleges)

(२) बहुउद्देशीय, उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय

(३) माध्यमिक विद्यालय

(४) प्रशिक्षण विद्यालय

(५) विशिष्ट विद्यालय (Special schools)

३. भवनः—जहां पर राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होवे, वहां पर छात्रावास किराये के मकान से स्थापित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में, सुविधायें, मोहल्ला तथा संस्था से दूरी को ध्यान में रखते हुए किसी योग्य मकान का चयन किया जाना चाहिये ।

४. निवास की शर्तेंः—संस्था के प्रधान द्वारा उनको मुक्त नहीं किये जाने की स्थिति में, नमस्त छात्रों की निम्न में से किसी एक परिस्थिति में अवश्य रहना पड़ेगा—

(अ) माता पिता के साथ

(ब) स्वीकृत अभिभावक के साथ

(ग) विभाग द्वारा स्वीकृत किसी छात्रावास में

जो छात्र उपरोक्त में से किसी भी शर्त के अनुसार नहीं रह रहे होंगे उन्हें संस्था से हटाया जा सकता है तथा यह तथ्य छात्र रजिस्टर (Scholars Register) में भी अंकित किया जावेगा ।

५. व्यवस्था तथा देखरेखः—छात्रावास अथवा छात्रावासों की व्यवस्था के लिए संस्था का प्रधान उत्तरदायी है तथा अधीक्षक अथवा अधीक्षकों की नियुक्ति करने से वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा ।

६. प्रत्येक छात्रावास, वही निवास करने वाले एक अधीक्षक के अधीन रहेगा जो कि सम्बन्धित संस्था के Staff का एक सदस्य होगा । यदि किसी एक ही छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों की संख्या ६० से अधिक हो जावे तो सहायक अध्यापकों में से सहायक अधीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

७. छात्रावास अधीक्षक संस्था के प्रधान द्वारा सामान्यतया दो वर्ष तथा विशिष्ट रूप से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा ।

८. संस्था के प्रधान के निर्देशन में छात्रावास-अधीक्षक का सामान्य कर्तव्य उसको सौंपे हुए छात्रों के अभिभावक का कार्य करना, उनके साथ रहना, उन पर नियंत्रण रखना, उनके कार्य तथा मनोरंजन की देखरेख करना, उनके निवास की व्यवस्था देखना तथा वह सब करना जो कि उनकी शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक उत्थान तथा उनकी प्रसन्नता के लिये वह कर सके, होगा । इस सामान्य कार्य के अलावा अधीक्षक को वियेन सौर पर निम्न कार्य भी करने पड़ेंगे—

(क) छात्रों में अनुशासन तथा नैतिकता को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होना ।

(ख) छात्रावास-नियमों का पालन कराना तथा ऐसी अनुशासनहीनता अथवा नैतिक स्तर

की गिरावट को संस्था के प्रधान के ध्यान में लाना, जिसके लिये वह स्वयं कुछ नहीं कर सके ।

(ग) विभाग द्वारा निर्धारित उचित रजिस्टर तथा अभिलेख रखना ।

(घ) छात्रावास से संबंधित समस्त वकाया रकम को वसूल करने के लिए उत्तरदायी होना तथा समस्त आय व व्यय का हिसाब रखना ।

(च) छात्रों में वकाया रकम की उन्हें प्रतिमास सूचना देना तथा उनसे वसूल की गई रकम के लिए रसीद देना ।

(छ) बीमारी व अस्वच्छता के सब मामलों की सूचना देना तथा छात्रावास के चिकित्सा अधिकारी और छात्रों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करना ।

(ज) छात्रों की भोजन व्यवस्था की देखरेख करना ।

(झ) छात्रावास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना तथा अपने संतोष के लिए यह देखना कि रसोई घर, भोजन कक्ष, निवास कक्ष, शौचालय आदि सब स्वास्थ्यकारक स्थिति में हैं ।

(ट) निर्धारित घंटों में छात्रों की अध्ययन व्यवस्था को देखना ।

(ठ) छात्रावास में खेलों में भाग लेना तथा खेल के मैदान में छात्रों के आचरण पर नियन्त्रण रखना ।

(ड) संस्था के प्रधान द्वारा बतलाये हुये अन्य समस्त कार्य करना ।

(ढ) छात्रों के सहयोग से सांस्कृतिक, खेलकूद तथा मनोरंजन सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ तथा प्रतियोगितायें, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन आदि की व्यवस्था करना ।

नोट:—जिस छात्रावास में सहायक अधीक्षक हों, वहाँ उपरोक्त कर्तव्यों के पालने में वह अधीक्षक से सहयोग करेगा ।

६. चिकित्सा-सेवा:—नियमित चिकित्सा-सेवा के लिये प्रावधान किया जावेगा । जहाँ सम्भव हो सके किसी अच्छी स्थिति के हवादार कमरे में रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया जावेगा ।

१०. यदि सम्भव होवे तो प्रत्येक छात्रावास में एक ऐसा कक्षा होगा जहाँ पर समाचार पत्र पत्रिकायें रखी रहेगी ।

११. प्रवेश:—छात्रावास में छात्रों को प्रवेश संस्था के प्रधान की स्वीकृति से ही मिल सकेगा अन्यथा नहीं । संस्था का प्रधान किसी भी प्रवेशार्थी को कारण बताये बिना प्रवेश से मना भी कर सकता है ।

१२. चेक का टीका लगाये बिना तथा मान्यता प्राप्त संस्था के छात्र हुये बिना किसी भी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि कोई छात्रावास किसी संस्था विशेष से सम्बद्ध है तो सम्बन्धित संस्था के छात्र के अलावा किसी अन्य को उस छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

१३. नियम:—छात्रावास में आचरण के लिए निम्न विषयों पर सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा विस्तृत नियम बनाये जा सकते हैं ।

(अ) भोजन की व्यवस्था

(व) स्थान की विभक्ति (Allotment of accommodation)

(स) सीमार्थ, जिनसे आगे छात्र स्वीकृति बिना नहीं जा सकते ।

(द) परिस्थितियाँ जिनमें छात्रों को सीमा से बाहर जाने की अथवा अवकाश लेने की या छात्रावास से पृथक् होने की स्वीकृति दी जा सके ।

(य) व्यक्तिगत अध्ययन, प्रातः उठना, रात्रि-शयन तथा आमोद-प्रमोद का समय ।

(क) सुबह व शाम को उपस्थिति लेने का समय

(ख) छात्रावास में आगन्तुकों का प्रवेश

(ग) बाहर खेले जाने वाले खेल तथा शारीरिक अभ्यास में छात्रों द्वारा भाग लिया जाना ।

(घ) छात्रावास की वकाया व जुर्माना की वसूली ।

(च) नियमों के उल्लंघन के लिए दिया जाने वाला दण्ड ।

(छ) अन्य कोई नियम जो कि संस्था का प्रधान नियम बनाने के लिए उपयुक्त समझे ।

ये नियम छात्रावास में किसी उपयुक्त स्थान पर लगा दिए जाएंगे तथा निरीक्षक अधिकारी को उसकी वार्षिक निरीक्षण यात्रा के समय बतलाये जायेंगे । अनुशासन के विशेष मामलों में संस्था के प्रधान का निर्णय अन्तिम माना जावेगा ।

१४. ऐसे निजी छात्रावास, जो कि किसी भी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बद्ध नहीं होंगे, में मान्य संस्थाओं के छात्रों द्वारा प्रवेश लेने से पूर्व उन्हें विभाग से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी । वे विभागीय अधिकारियों के लिए जांच के लिए खुले रहेंगे तथा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का उन्हें पालन करना पड़ेगा ।

१५. छात्रावासः—भवनों की आवश्यकता के बारे में आवश्यक विवरण, भवनों से सम्बन्धित अध्याय में दिया हुआ है ।

१६. छात्रावास के छात्रों की सेवा के लिए निजी सेवकों के प्रयोग की स्वीकृति नहीं दी जावेगी ।

१७. छात्रों के कमरों में मेहमानों के ठहरने की इजाजत नहीं दी जावेगी । यदि अतिथि—कर्म होने तो उसमें उन्हें ठहरने की स्वीकृति दी जा सकती है ।

१८. छात्रावास के छात्र छात्रावास के सेवकों से कपड़े नहीं धुलवायेंगे ।

अध्याय ११

पुस्तकालय

१. वर्गीकरणः—विभागाधीन पुस्तकालय मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हैः—

(अ) संस्थात्मक पुस्तकालय—वे पुस्तकालय जो संस्था का एक नियमित अंग हो ।

(ब) सार्वजनिक पुस्तकालय जो जनता के हितार्थ चालू किये गये हैं ।

अ— संस्थात्मक पुस्तकालय

अ—संस्थात्मक पुस्तकालय

३. संस्थाओं से संलग्न पुस्तकालयों का उद्देश्य यह है कि छात्रों में व स्टाफ के सदस्यों में पढ़ने के अभ्यास के प्रति उत्साह तथा ज्ञान बढ़ाये। पुस्तकालय में सहायक पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें तथा संस्थाओं के लिए अनिवार्य तकनीकी एवं व्यवसायात्मक साहित्य के अतिरिक्त सामान्य हित की अन्य पुस्तकें भी होंगी।

४. निधियां:—विभाग ऐसे पुस्तकालयों के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय की आय के अतिरिक्त उचित अनुदान भी स्वीकृत कर सकता है।

५. नियन्त्रण:—ऐसे पुस्तकालय पर संस्था प्रधान का पूर्ण नियन्त्रण होगा तथा वह उसकी कुशलता पूर्वक व्यवस्था एवं सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा।

६. जहां पूर्ण समय के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष प्राप्त न हो तो वहां अध्यापन स्टाफ का एक सदस्य पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा तथा वह पुस्तकालय के प्रबन्ध एवं पुस्तकों की सुरक्षा के लिए संस्था प्रधान के प्रति उत्तरदायी होगा। पुस्तकालय में लगाये गए समय अनुदान से उसका अध्यापन का समय कम कर दिया जावेगा।

७. एक पुस्तकालय को सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया जाएगा:—

(अ) अध्यापकों के लिए सामान्य एवं सहायक पुस्तकों का एक सामान्य एवं सहायक पुस्तक विभाग।

(ब) छात्रों को घर पर पढ़ने के लिये दी जाने वाली पुस्तकों का एक छात्र विभाग।

(स) पाठ्यपुस्तक विभाग।

८. वाचनालय:—जहां तक सम्भव हो एक वाचनालय का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे साहित्यिक एवं सामान्य रचि की सामयिक पत्रिकायें एवं समाचार पत्र रहने चाहिए जो छात्रों को लाभदायक शिक्षा प्रदान कर सकें तथा उनके चरित्र पर पूर्ण प्रभाव डाल सकें।

९. ये समाचार पत्र एवं सामयिक पत्रिकायें सरकार द्वारा स्वीकृत सूची से चुनी जायेंगी यदि किसी ऐसे समाचार पत्र एवं सामयिक पत्रिकाओं को मंगाना हो जो स्वीकृत सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे मामलों में इनके मंगाने से पहले इनका चन्दा देने हेतु नियन्त्रण अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

१०. प्रविष्ट करना:—जो कोई भी पुस्तक पुस्तकालय में लाई जायेगी चाहे वह खरीद के द्वारा या अन्य प्रकार से प्राप्त हो, पुस्तक सूची में उचित विभाग में मय प्राप्त होने की तिथि तथा उसकी क्रम संख्या आदि लगाकर दर्ज करली जायेगी। उस पुस्तक के भीतर एवं बाहर पुस्तक के गत्ते पर संस्था का नाम एवं उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक चिट्ठी चिपकाने के अलावा पुस्तकालयाध्यक्ष को इस पुस्तक को किसी को देने या प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ अन्तर से कई पृष्ठों पर संस्था की मुद्रा लगानी चाहिए।

११. जारी करना:—छात्रों एवं अध्यापकों को पुस्तकें उधार देने के लिए अलग २ रजिस्टर बनाये जायेंगे जिनमें दी गई पुस्तक का नाम, देने एवं प्राप्त करने की तिथि, पुस्तक लेने वाले के तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पुस्तक वापिस प्राप्त करने पर उसकी दशा का वर्णन करने के लिए विशेष विवरण आदि के स्तम्भ बनाये जायेंगे। छात्रों के अध्ययन के अभ्यास को उत्साह

प्रदान करने के लिए कम से कम उच्चविद्यालय एवं इन्टरमीडिएट विभागों में छात्रानुसार पुस्तक देने का एक रजिस्टर तैयार करना चाहिये ।

१२. नियमानुसार किमी भी स्टाफ के सदस्य को आवश्यक सहायक पुस्तकों एवं पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त ५ पुस्तकों से ज्यादा नहीं दी जायेगी तथा आठवीं कक्षा तक के छात्र के लिए एक पुस्तक से ज्यादा तथा उच्चविद्यालय और इन्टर-मीडिएट कक्षाओं के लिए दो से अधिक पुस्तकें नहीं दी जायेंगी । वगैरें कि यदि संस्था के प्रधान द्वारा संस्था की शिक्षात्मक कुशलता के हित में यह आवश्यक समझा जाय कि पुस्तकें अधिक दे दी जानी चाहिए तो पुस्तकें उपरोक्त निर्धारित सीमा से भी अधिक दी जा सकती हैं ।

१३. पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें जारी करने से १४ दिन के अन्दर २ वापस जमा करा देनी चाहिए । कोई भी नई पुस्तक उम समय तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पूर्व में ली गई पुस्तक लौटा न दी गई है ।

१४. पुस्तकालयाध्यक्ष को यदि १४ दिन के निर्धारित समय में वापस नहीं लौटाई जाती है या पुस्तक खो दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है तो इन सन्धियों से संस्था के प्रधान को शीघ्र सूचित करना चाहिए । इस पर संस्था का अध्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति को एक नोटिस देगा कि या तो वह खोई हुई या नष्ट की गई पुस्तक के बदले में वही दूसरी पुस्तक जमा करवा दें अन्यथा नोटिस के अनुसार १ माह के भीतर उसकी कीमत जमा करादे । इस आदेश का पालन न करने पर संस्था प्रधान उस व्यक्ति के वेतन में से यदि वह स्टाफ का सदस्य है तो पुस्तक की कीमत काट सकता है । विद्यार्थियों से भी जुगतान न करने पर अन्य शुल्क की तरह समान जुर्माना करके पुस्तक का मूल्य वसूल किया जा सकेगा ।

१५. साल के आरम्भ में पाठ्यपुस्तकें केवल अध्यापकों को ही दी जावेगी तथा ग्रीष्मावकाश से पहिले उन्हें पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटानी पड़ेगी ।

१६. स्टाफ के सदस्यों एवं छात्रों को पुस्तकें देने के सम्बन्ध में तथा ग्रीष्मावकाश में जहाँ सम्भव हो पुस्तकालय खुला रखने के लिए संस्था के प्रधानों को नियम बनाने चाहिए ।

१७. समयः—संस्था का प्रधान पुस्तकालय के उचित प्रबन्ध के लिए उचित नियम बनाएगा तथा ऐसा नियम निर्धारित करेगा जिसमें कि पुस्तकालयाध्यक्ष उपस्थित रहेगा तथा पुस्तकालय पुस्तकें देने, जमा कराने एवं पढ़ने के लिए खुला रहेगा ।

१८. रजिस्टर एवं अभिलेखः—संस्था के प्रधान के निरीक्षण के अधीन पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों की सूची तैयार करने का, स्टाफ एवं पुस्तकें देने के रजिस्टर एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य अभिलेख पूरा तैयार रखने का जिम्मेवार होगा ।

१९. संस्था के प्रधान इसे देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि पुस्तकालय में अनावश्यक प्रकृति की कोई समयिक पत्रिका एवं पुस्तकें तो नहीं हैं । विभाग द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार ही पुस्तकें खरीदनी चाहिए ।

२०. स्टाफ लेनाः—प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के समय संस्था के प्रधान द्वारा निर्धारित तिथि पर, एक समय सारी पुस्तकें जमा करवा ली जाएगी जिससे कि उनको सूची से मिलाया जा सके तथा खोई हुई पुस्तकों का पता लग सके और पुस्तकों की आवश्यक मरम्मत कराई जा सके । पुस्तकालय की जांच करने के बाद संस्था के प्रधान को पुस्तकें उधार देने के रजिस्टर में आखिरी

निविष्टि देखने के बाद तथा यह देखने के बाद कि कोई पुस्तक खोई गई है या निरर्थक है यह प्रमाणित करना चाहिए कि पुस्तकालय अच्छे ढंग से जमा हुआ है लेकिन जब कोई पुस्तक नहीं मिल रही है या निरर्थक है तो उसे इस तथ्य को जारी रजिस्टर में लिखना चाहिए तथा सक्षम अधिकारी को उचित आदेशार्थ सूचना भेज देनी चाहिए ।

व—सार्वजनिक पुस्तकालय

२१. सरकार द्वारा निम्न प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं ।

(अ) केन्द्रीय पुस्तकालय ।

(ब) चल पुस्तकालय सेवा के साथ प्रादेशिक पुस्तकालय ।

(स) जिला एवं तहसील स्तर के पुस्तकालय ।

(द) ग्राम पुस्तकालय

केन्द्रीय एवं प्रादेशिक पुस्तकालय

२२. ये पुस्तकालय अलग से जारी किये गये नियमों के अनुसार शासित होते हैं ।

जिला एवं तहसील पुस्तकालय

२३. शिक्षा संचालक के आर्थिक समाज शिक्षा अधिकारी के विरोध अधिकार में ये पुस्तकालय होंगे ।

२४. विभिन्न पुस्तकालयों के खुलने के समय, पुस्तकें देने, धन जमा करने, सदस्यता शुल्क आदि के सम्बन्ध में नियम समाज शिक्षा अधिकारी को सिफारिश पर संचालक द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे ।

अन्य पुस्तकालय एवं वाचनालय

२५. ग्राम पुस्तकालय का प्रबंध सीधा समाज शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेगा । इन पुस्तकालयों के नियम समाज शिक्षा अधिकारी की सिफारिश पर संचालक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे ।

२६. वाचनालयों का प्रबंध समाज शिक्षा आयोजकों के द्वारा समाज शिक्षा अधिकारी की ओर से किया जायेगा । इन अध्ययन कक्षों के सम्बन्ध में नियम समाज-शिक्षा आयोजकों की सिफारिश पर समाज शिक्षा अधिकारी स्वीकृत करेगा ।

सहायता प्राप्त पुस्तकालय

२७. निम्न शर्तें पूरी करने पर सरकार पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करती है—

(१) पुस्तकालय की उचित व्यवस्था है ।

(२) छोटे व्यक्तियों को पढ़ने की उचित सुविधा है ।

(३) अच्छी पुस्तकों का संग्रह है ।

(४) उचित हिसाब रखे जाते हैं तथा पुस्तकें जमा करवाई जाती हैं ।

(५) बिना किसी जाति या धर्म को ध्यान में रखते हुए सब के लिए खुला रहता है ।

राजस्थान में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों को सामान्य संविधान

१. राजस्थान में पुस्तकालय सेवा, संचालक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में है। राज्य में क्षेत्रीय, जिला एवं तहसील स्तरीय विभिन्न पुस्तकालयों की निम्न लिखित अनुसार क्रमशः ११, ७, ७ सदस्यों की सामान्य प्रबंधकारिणी समितियां होंगी।

(अ) क्षेत्रीय पुस्तकालय समितियां

(ब) जिला पुस्तकालय समितियां

(ग) तहसील पुस्तकालय समितियां

(अ) क्षेत्रीय पुस्तकालय समितियां

(१) क्षेत्रीय आयुक्त समिति का अध्यक्ष होगा।

(२) जिस जिले में क्षेत्रीय पुस्तकालय होगा, वहां का जिलाधीश समिति का उपाध्यक्ष होगा।

(३) तीन पदेन सदस्य ये होंगे (अ) उच्चतम शिक्षा अधिकारी (प्रशासनात्मक) जो पुस्तकालय के मुख्य स्थान पर नियुक्त हो। यह सामान्य रूप से उप संचालक शिक्षा विभाग होगा।

(ब) उच्चतम स्तर के स्थानीय राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य यदि वहां समान स्तर के दो महाविद्यालय हों तो कला महाविद्यालय (आर्ट्स कालेज) का प्राचार्य। (स) क्षेत्रीय समान शिक्षा आयोजक।

(४) पुस्तकालय के लिए चन्दा देने वालों में से कोई से तीन मनोनीत सदस्य।

(५) नगरपालिका परिषद् के दो मनोनीत प्रतिनिधि, जो कि स्वयं नगरपालिका परिषद् के सदस्य होने चाहिये।

(६) पुस्तकालयाध्यक्ष जो पदेन सचिव का कार्य करेगा।

(ब) जिला पुस्तकालय समिति

(१) जिले का जिलाधीश जो अध्यक्ष के रूप में रहेगा।

(२) उच्चतम शिक्षा अधिकारी (प्रशासनात्मक) जो पुस्तकालय के मुख्य स्थान पर नियुक्त किया गया हो, पुस्तकालय के मुख्य स्थान पर उच्चतम स्तर की स्थानीय राजकीय शिक्षा संस्था का प्राचार्य या प्रधानाध्यापक।

(३) स्थानीय नगरपालिका मंडल से एक मनोनीत प्रतिनिधि जो कि मंडल का एक सदस्य हो। जहां कोई नगरपालिका बोर्ड न हो वहां पंचायत का मनोनीत प्रतिनिधि।

(४) पुस्तकालय के लिये चन्दा देने वालों में कोई से दो मनोनीत सदस्य।

(५) जिला पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष जो समिति का पदेन सचिव होगा।

(ग) तहसील पुस्तकालय समिति

(१) तहसीलदार अध्यक्ष का कार्य करेगा (जहां खंड मंडलाधीश या खंड विकास अधिकारी तहसील के मुख्यालय पर होंगे वहां वह समिति का अध्यक्ष होगा)।

(२) तहसील के मुख्यालय पर उच्चतम स्तर की राजकीय शिक्षा संस्था का प्रधानाध्यापक।

(३) तहसील पंचायत बोर्ड का सरपंच।

(४) नगरपालिका मंडल द्वारा मनोनीत एक सदस्य, यदि कोई हो तो उनके सदस्यों में से।

स्य ही मनोनीत किया जायेगा अन्यथा जहाँ कोई नगरपालिका मंडल न हो वहाँ पंचायत मंडल एक मनोनीत सदस्य ।

(५) पुस्तकालय के लिये चन्दा देने वालों में से समिति द्वारा दो मनोनीत सदस्य ।

(६) पुस्तकालयाध्यक्ष जो पदेन सचिव का कार्य करेगा ।

२. इन समितियों के सदस्य दो वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते रहेंगे वशत कि वे अयोग्य हों । एक मनोनीत सदस्य कितनी ही बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है ।

३. समिति के सदस्य जो त्यागपत्र देना चाहें उन्हें त्यागपत्र देने के कारणों से अध्यक्ष को बगत कराना चाहिए जो कि निर्वाचन द्वारा या अन्य दिये गये नियमों के अनुसार रिक्त स्थान को ले के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

४. बिना मान्य कारणों के समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने से सदस्य को त्यागपत्र देने को बाध्य किया जायेगा ।

५. पुस्तकालय समिति का साधारणतया कार्य इस प्रकार से होगा:—

(१) संचालक, शिक्षा विभाग को पेश करने के लिये वार्षिक बजट पर विचार करना एवं उस पर अपनी सहमति प्रकट करना ।

(२) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, पत्रिकायें तथा समाचार पत्रों का चयन करना ।

(३) चन्दा देने वाले एवं आगन्तुकों के सुझावों और शिकायतों पर विचार करना ।

(४) पुस्तकालय में स्थायी या अस्थायी प्रयोग के लिए किताबों एवं अन्य वस्तुओं की मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत करना ।

(५) पुस्तकालय में सामान्य सुधार एवं विस्तार का प्रयत्न करना एवं उसके साधनों को सुझाना ।

(६) संचालक, शिक्षा विभाग को स्वीकृति से संस्था के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन भेजना ।

(७) पुस्तकालय के सम्पूर्ण कार्यों पर सामान्य रूप से निगरानी व देख रेख रखना ।

(८) अनुदान ग्रहण करना ।

(९) किसी विशेष कार्य के लिए यदि आवश्यकता हो तो उसके सदस्यों की एक उप समिति बनाना ।

पुस्तकालय के लाभार्थ संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों पर समिति पालन करेगी ।

६. त्रैमासिक रूप से समिति की एक बैठक हुआ करेगी जिसमें क्रमानुसार सचिव द्वारा समय समय पर अल्प महत्व के छोटे छोटे मामलों पर विचार किया जायेगा ।

७. साधारणतया समिति के सदस्यों को उनकी बैठक होने से एक सप्ताह पूर्व सूचित किया जायेगा ।

८. अध्यक्ष की स्वेच्छा से या समिति के कम से कम ५ सदस्यों से लिखित आवश्यकता प्राप्त हो जाने पर समिति की असाधारण सभा बुलाई जा सकती है । ये सदस्य अपने लिखित रूप में उस उद्देश्य का वर्णन करेंगे जिसके लिये वे बैठक करना चाहते हैं ।

९. पिछले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये समिति की बैठक अग्रे स. में होगी तथा अग्रिम वर्ष के लिए वषट प्रस्तावों पर विचार करने के लिए करीब प्रगस्त मा. अन्तिम सप्ताह में होगी। किसी अन्य विषय पर भी विचार किया जा सकता है।

१०. चार सदस्यों के उपस्थित होने पर समिति का गोरम पूरा हो जायगा। यदि समिति बैठक के निश्चित समय में १५ मिनट के भीतर गोरम पूरा नहीं होता है तो वह एक वि. तिथि तक स्वगित कर दी जायेगी तथा स्वगित बैठक में बिना गोरम के ही कार्य किया सकता है।

११. समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के ल. चुनेंगे।

१२. सभी प्रश्न बहुमत के आधार पर तय किये जायेंगे तथा जनमत बराबर हो तो का मत निर्णायक मत होगा।

१३. यदि कोई सदस्य किसी विषय को समिति के विचारार्थ रखना चाहता है तो वह लिये बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम दस रोज पूर्व सचिव को उसकी लिखित में सूचना देगा।

१४. बैठक की कार्यवाही को इस उद्देश्य में बनाई गई एक पुस्तक में दर्ज किया जायेगा दूसरी बैठक में उसे स्वीकृत किया जायेगा।

१५. जब कोई विशेष बैठक बुलाने का समय न हो तो आवश्यक मामलों का निपटारा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है तथा शीघ्रातिशीघ्र गुविमा के अनुसार मामला समिति के सम्मुख ला जायेगा।

१६. पुस्तकालय के सामान्य निरीक्षण का तथा समिति के प्रस्ताव पारित करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा। वह संचालक, निदाविभाग से पत्र व्यवहार करने में कड़ी का का करेगा।

१७. पुस्तकालयाध्यक्ष सचिव के रूप में समिति एवं उप समिति की बैठक बुलायेगा ठा समस्त कार्य स्वयं करेगा।

१८. कार्यकारिणी समिति पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के चयन में सलाह देने के लिये एक उप समिति गठित करेगी।

१९. उप समिति नयोजन एवं समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत सदस्यों से दैगी। पुस्तकालयाध्यक्ष उप समिति का पदेन सचिव रहेगा।

पुस्तकालय नियम

खुलने का समय

१. क्षेत्रीय पुस्तकालय (मय जिला पुस्तकालय कोठा के) रोजाना १२ घण्टे तक खुले रहे (गमियों में ८ बजे प्रातः से ८ बजे सायं, सदियों में ८-१० प्रातः से ७ बजे सायं)।

२. जिला पुस्तकालय रोजाना आठ घण्टे तक खुले रहेगे। (गमियों में प्रातः ७ बजे से ११ बजे तक सायं ५ बजे से ८ बजे तक, सदियों में प्रातः ८ बजे से दोपहर के १२ बजे तक एवं सायं ४ से ८ बजे तक)।

तहसील पुस्तकालय

८. जिला पुस्तकालयों के ही नियम लागू होंगे ।

चल पुस्तक जमा केन्द्र

९. सरपंच, पटवारी या राजकीय शाला के अध्यापक द्वारा सिफारिश किया गया कोई भी व्यक्ति बिना चन्दा दिये एवं नकद जमानत जमा कराये पुस्तकालय का सदस्य हो सकता है । सदस्य एक बार में एक ही पुस्तक निकलवा सकेगा ।

१०. किसी भी एक पुस्तकालय के (क्षेत्रीय, जिला एवं तहसील आदि) सदस्य के रूप में प्रविष्ट होने के लिए एक व्यक्ति को नामांकन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेगे । जो कि पुस्तकालय से एक आना लेकर प्राप्त किया जा सकेगा ।

११. सदस्य को अपना निवास स्थान परिवर्तन करने पर एक सप्ताह में सूचित कर देना चाहिए ।

स—विशेषाधिकार (Privileges)

१२. प्रत्येक सदस्य को, जैसी भी परिस्थिति हो, एक या दो उधार टिकिट दिये जायेंगे जिनके द्वारा वह एक बार में ही एक या दो पुस्तकें उधार ले सकेगा ।

१३. पाठक का टिकिट केवल १२ मास तक ही मान्य होगा तथा नामांकन प्रपत्र भरने पर एवं नई प्रतिभूति (Guarantee) देने पर नया दिया जा सकता है, वे व्यक्ति जिन्होंने पहले ही प्रतिभूति की धनराशि जमा करा दी है वे अपनी पहले वाली सदस्य संख्या छोड़ सकते हैं जिसके कि लिए जमानत पहले जमा कराई गई थी ।

१४. जमा वापिस प्राप्त करने के लिए एक माह की पूर्व सूचना दी जावेगी ।

१५. यदि कोई सदस्य १२ मास पश्चात अपनी सदस्यता का फिर से नवीनीकरण नहीं करा पाता है तथा इस सदस्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि तीन माह में अपनी जमानत वापिस निकलवाने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत की धनराशि पुस्तकालय में कालातीत (Lapse) हो जायेगी ।

१६. एक सदस्य को पुस्तक, टिकिट के बदले में ही, उधार दी जावेगी जो कि सदस्य को पुस्तक वापिस जमा कराते समय लौटा दिया जावेगा । जब वह पुस्तक उचित तिथि पर नहीं लौटाई जाती है तब वह टिकिट उसे उभी समय दिया जायेगा जब कि वह देर से लौटाने का दण्ड जमा करादे ।

१७. सदस्य की ओर से बकाया पुस्तकें तथा सभी बकाया रकमें एवं सदस्यता टिकिट जब तक जमा नहीं करा दिये जाते हैं तब तक उसे अपनी जमानत की धनराशि नहीं लौटाई जा सकती है ।

द—टिकिट का खो जाना

१८. टिकिट प्राप्तकर्ता उस पर अंकित पुस्तक के लिए उत्तरदायी होगा ।

१९. यदि किसी सदस्य का टिकिट खो जाता है तो वह उसकी लिखित सूचना पुस्तकालय को देगा तथा निर्धारित प्रपत्र में जमानत का वाढ़ भरेगा एवं प्रत्येक दुबारा चाहेंगे

टिकिट के लिए आठ आना जमा करायेगा ।

य—उधार की शर्तें

२०. पुस्तकालय (केवल प्रसंग वाली पुस्तकों के अतिरिक्त) खुली पद्धति अपनायेगा । कोई भी पाठक खुले हुए खण्डों में से किसी भी पुस्तक को पढ़ने हेतु निकाल सकता है या उसे निकालने हेतु उधार देने वाले काउन्टर (Counter) पर ले जा सकता है । पाठक खण्डों में पुस्तकों की बदला बदली नहीं करेंगे वरन् उन्हें काउन्टर लेखक (Counter Clerk) के पास ही छोड़ देंगे ।

२१. पुस्तकों उधार देने का काउन्टर पुस्तकालय बन्द करने से आधा घन्टा पूर्व ही बन्द कर दिया जावेगा ।

२२. प्रत्येक सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तकों लाने व ले जाने का प्रबन्ध स्वयं को करना चाहिए ।

२३. काउन्टर (Counter) को छोड़ने से पूर्व सदस्य उसको दी गई पुस्तक की अच्छी दशा से अपने आपको असन्तुष्ट करेगा, यदि वह अच्छी दशा में नहीं है तो इस तथ्य से शीघ्र ही पुस्तकालयाध्यक्ष को अवगत करायेगा, अन्यथा उसे एक नई पुस्तक द्वारा बदलने का उत्तरदायित्व उस पर हो सकता है ।

२४. यदि पुस्तक नष्ट हो गई या खो गई है तो सदस्य या तो दूसरी प्रति लौटाएगा या इसके बदले में पुस्तक की कीमत पुस्तकालय को लौटा देगा । ऐसी दशा में यदि वह पुस्तक या पुस्तकों जिन्हें बदला जाना है, उस समय अप्राप्य हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष अपने निर्णयानुसार सदस्य से ऐसी पुस्तकों के मूल्य से ५% अधिक मूल्य जमा कराने के लिए कह सकता है ।

२५. यदि एक शृंखला (Set) की एक पुस्तक नष्ट हो गई हो या खो गई हो तो सम्बन्धित सदस्य से पूर्ण सेट बदलवाया जा सकता है या उसका मूल्य वसूल किया जा सकता है ।

२६. खोई गई पुस्तक का मूल्य पुस्तकालय में शीघ्र जमा करा दिया जावेगा ।

२७. खोई हुई पुस्तक का मूल्य जो सदस्य से वसूल किया गया है उसे लौटाया जा सकता है यदि वह पुस्तक मूल्य राशि जमा कराने से ४५ दिन की अवधि के भीतर जमा करा दी जाती है तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को उसकी दशा से सन्तोष है ।

२८. सामयिक प्रकाशन शब्दकोष, निर्देशिकायें आदि रचनायें जिनकी कि पूर्ति किया जाना कठिन प्रतीत हो अन्य कोई रचना जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष प्रसंगवली पुस्तक कह सकता हो, उसे घर के लिए नहीं दिया जायेगा ।

२९. सदस्यों को पुस्तकालयों की पुस्तकों बीच ही में उधार देने या टिकिटों के प्रयोग के अधिकारों का स्थानान्तर करने की स्वीकृति नहीं है । दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को पुस्तकालय से पुस्तक उधार प्राप्त करने से मना कर दिया जायेगा ।

३०. पुस्तकालय की पुस्तक यदि विभाग के काम के लिए जाही गई हो तो वह विभाग के उत्तरदायी कार्यालय द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त करने पर दी जा सकेगी । जिसमें यह स्पष्ट किया जायगा कि वह उस सम्बन्धित विभाग के कार्य के लिए हो जाही गई है । ऐसी पुस्तकों शीघ्रातिशीघ्र वापिस सीटा देनी चाहिए इस प्रकार दी गई पुस्तक यदि खो गई या ग़ुम हो गई हो तो पुस्तक लेने

वाले विभाग द्वारा उसकी कीमत दी जायेगी या पुस्तक मंगाकर जमा करानी होगी।

३१. सभी पुस्तकों जो उधार दी गई हैं, उधार देने की तारीख को हटाकर या जमा कराने की तारीख के छुट्टी वाले दिन को हटाकर, उधार देने के दिन से १४ दिन की अवधि के भीतर जमा करवा दी जायेगी।

३२. यदि बकाया पुस्तक निर्धारित समय के कुछ अन्तर से तीन बार स्मरण कराये जाने पर भी जमा नहीं कराई जाती है तो दांपी पाठक को पुस्तकें उधार लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा तथा ऐसी किसी सूचना के जारी न करने का कोई लाभ उठाने का वह दावा नहीं कर सकता है।

३३. उधार दी गई पुस्तकों को वापिस मंगवाया जा सकता है तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्णय से उसका देना किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यदि पुस्तक निर्धारित समय पर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर प्रति पुस्तक प्रति दिन चार आना दण्ड किया जा सकता है।

३४. यदि पुस्तक उचित समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो प्रति पुस्तक प्रति दिन एक आना के हिसाब से दण्ड शुल्क प्रथम सप्ताह में वसूल किया जायेगा तथा इसके पश्चात् के दिनों का दो आना प्रतिदिन प्रति पुस्तक वसूल किया जायेगा।

३५. पुस्तकालयाध्यक्ष को उचित मामलों में पुस्तक देर से लौटाने पर दण्ड भाग करने का अधिकार होगा। यह दण्ड बहुत कम तथा विशेष मामलों में प्रयोग में लाई जायेगी।

३७. पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के आधार पर उसी पुस्तक को पुनः उधार दिया जा सकता है:—

(अ) यदि उधार की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस पुस्तक को फिर से निकलवाने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष से प्रार्थना की गई हो।

(ब) इतने समय में अन्य पाठक ने उस पुस्तक के लिए प्रतिवेदन नहीं किया हो।

(स) उसी पुस्तक को दो बार से अधिक उधार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बार पुस्तक निकलवाते समय उसको पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखानी चाहिये।

३८. एक सदस्य जिसकी तरफ कोई दण्ड शुल्क या रकम बकाया हो तो जब तक वह अपना बकाया धन जमा नहीं करायेगा उस समय तक न तो उसे कोई पुस्तक ही उधार दी जायेगी तथा न वह अपनी जमानत की धन राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

३९. यदि एक सदस्य किसी नुकसान या हानि को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है या निर्धारित समय में पुस्तक लौटाने में असमर्थ हो जाता है या अपने बकाया धन को जमा कराने में असफल रहता है और यदि नियमानुसार उसे सूचना दे दी गई है तो ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को अधिकार है कि वह ऐसे सब बकायों को पहले उसकी नकद जमा धन राशि से काट सकता है तथा यदि वह रकम बकाया धन वसूली के लिये अपर्याप्त है तो वह शेष श्रेणी को ऐसे मामलों के धन को वसूल करने में लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वसूल करवा सकेगा। किन्तु यदि यह है कि यदि अपराधी राज्य कर्मचारी है तो ऐसे धन को कागज के अन्तर्गत वसूल करने से सम्बन्धित विभाग द्वारा वसूल करने का प्रयास किया जायेगा।

४०. प्रस्तकालय में प्रवेश करते समय व्यक्ति सर्व प्रथम द्वार पंजिका में अपना नाम, पते

जाने योग्य अक्षरों में लिखेगा तथा इसके द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में प्रतिदिन प्रवेश करने वालों के आंकड़े एकत्रित करने में सहायता देगा ।

फ-पुस्तकालय में प्रवेश

४१. एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक न हो या अवांछनी हो उसे पुस्तकालय में प्रविष्ट नहीं होने दिया जायेगा ।

४२. लकड़ी, छाता, सन्दूक तथा अन्य ऐसी वस्तुयें तथा सामान जो द्वारपाल द्वारा निषिद्ध हो, दरवाजे पर ही छोड़ दी जावेंगी ।

४३. बाहर दरवाजे पर किसी सामान के नुकसान या परिवर्तन का उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार से पुस्तकालयाध्यक्ष का नहीं होगा ।

४४. कुत्ते या अन्य जानवरों का भीतर प्रवेश निषिद्ध है ।

४५. पुस्तकालय में शान्ति स्थापित रखी जावेगी ।

४६. धूम्रपान एवं धूम्रपान करना सख्त मना है ।

४७. शयन करना सख्त मना है ।

४८. पुस्तकालय में सम्बन्धित पुस्तक, नक्शा, हस्तलिखित ग्रन्थ आदि पर कोई भी व्यक्ति न तो कुछ लिखेगा, और न चिन्ह लगायेगा और न हानि ही पहुँचायेगा । पुस्तकालयाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई चिन्ह या यान्त्रिक अनुकृति (Mechanical Reproduction) नहीं की जावेगी ।

४९. पाठक स्वयं पुस्तकालय की किसी पुस्तक या अन्य सामग्री को हानि पहुँचाने आदि के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसे उस वस्तु को, जिसको उसने नष्ट किया है या हानि पहुँचाई है, बदलेगा या उसकी वीमत जमा करायेगा ।

५०. पुस्तकालय छोड़ने से पूर्व पाठकों को काउंटर सहायक (Counter Assistant) के पास जाकर कोई पुस्तक, ग्रन्थ, नक्शे जो विशेष रूप से पठनार्थ लिये गये हों, लौटा देने चाहिये ।

ह-सामान्य

५१. विशेष परिस्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को पुस्तकालय में प्रवेश करने से मना कर सकता है या किसी पुस्तक को प्रयोग में लेने से इन्कार कर सकता है । उसे उस व्यक्ति को रोके जाने के कारणों से संतुष्ट करना चाहिये ।

५२. विशेष परिस्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों के उधार लेने के अधिकार के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर सकता है । उसे उस व्यक्ति को मना किये जाने के कारणों से संतुष्ट करना चाहिये ।

५३. वार्षिक स्टॉक लेने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दिसम्बर के अन्त में पुस्तकालयाध्यक्ष १० दिन तक पुस्तकों देना रोक सकता है । अध्ययन कक्ष फिर भी इन दिनों में यथावत् खुला रहेगा ।

५४. वार्षिक स्टॉक की जांच उपसंचालक, समाज शिक्षा द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्ती अधिकारी के समक्ष होगी । इसका एक प्रतिवेदन पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा १५ जनवरी तक उस अधिकारी जिसके सम्मुख स्टॉक सम्माला गया है, के पृष्ठांकन द्वारा उपसंचालक समाज शिक्षा को भेज दिया जायेगा ।

५५. पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य द्वारा निर्मित नियमानुसार पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष की सहमति के बाद या निर्धारित शर्तों के आधार पर पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सामग्री को विशेष तौर पर उधार दे सकता है ।

५६. किसी भी प्रकार के नियम भंग पर प्रवेशाधिकार छीन लिया जायेगा एवं पुस्तकों पुस्तकालय से उधार देना बंद कर दिया जावेगा ।

५७. पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पुस्तकालय में डभी उद्देश्य के लिए रखे गये रजिस्टर के आधार पर आंकड़े तैयार करेंगे, जैसे पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, पुरानी पुस्तकों की संख्या में बढ़ी हुई नई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों उधार लेने वालों की संख्या, प्रतिदिन उधार दी गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालय में पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालय में प्रतिदिन दर्शन आदि की संख्या का विवरण रखेगा तथा मासिक, त्रै मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में भरकर अभिलेख के साथ को उप संचालक शिक्षा विभाग के कार्यालय में प्रेषित करेंगे ।

५८. सभी पुस्तकालयों में निम्नांकित तकनीकी पद्धति अपनाई जावेगी:—

(१) ड्यू दसिमल क्लासीफिकेशन (Dewey Decimal Classification)

(२) डिक्शनरी कार्ड कैटालोगिंग (Dictionary Card Cataloguing A.L.A. Cade)

(३) ब्राउन्स चार्जिंग व डिस्चार्जिंग सिस्टम (Brownes' Charging & Discharging System)

(४) खुली पहुँच (Open access)

५९. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय के कार्य एवं प्रगति के बारे में पुस्तकालयाध्यक्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन हर ३० अप्रैल तक उपसंचालक, समाज शिक्षा को प्रेषित करेगा ।

६०. पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों को क्रमानुसार एवं सुरक्षित रखने तथा फर्नीचर व पुस्तकालय भवन की सफाई के लिए उत्तरदायी होगा । वह पुस्तकों को रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा अन्य रजिस्टर एवं पुस्तक सूचियों को अन्तिम तिथि तक क्रमानुसार रखेगा । चन्दा देने वालों की सूची तैयार करेगा, सब हिसाब रखेगा एवं आवश्यक स्वीकृति के बाद पुस्तकों एवं सामयिक पत्रिकाएँ खरीदेगा तथा पुस्तक विक्रेताओं व चन्दा देने वालों से सम्बन्ध स्थापित करेगा और पुस्तकालय में सभी अन्य कार्य करेगा ।

६१. पुस्तकालय सम्बन्धी विषयों में सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय पुस्तकालय सलाहकार मण्डल होगा तथा क्षेत्रीय, जिला एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक पुस्तकालय की एक पुस्तकालय समिति होगी जो कि इस कार्य के लिए बनाये गये संविधान द्वारा स्वीकृत सभी शक्तियों का उपयोग करेंगी ।

अध्याय १२

सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम

नोट:—(प्र) ये नियम, सेवा से सम्बन्धित सरकारी नियमों तथा आदेशों, जिनमें कि निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, के पूरक हैं:—

(१) राजस्थान सेवा नियम

(२) राजस्थान असैनिक (Civil) सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण, पुनर्विचार) नियम १९५० ।

(३) अधिकारियों की शक्तियों की सूची

(४) इसी प्रकार के अन्य नियम व आदेश

(व) ये नियम केवल सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं पर लागू होंगे ।

१. नियुक्ति:—राजपत्रित पदों पर समस्त नियुक्तियां अथवा पदोन्नति सामान्यतया राज्य-लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा की जाती हैं ।

२. नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में मंचालक व उसके अधिनस्थ अधिकारी उन सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत Shedule of Powers के अन्तर्गत मिली है ।

३. नियुक्ति के लिए समस्त प्रार्थना पत्र नियुक्ति कर्ता अधिकारी को योग्यता, आयु तथा निवास से सम्बन्धित आवश्यक कागजात के साथ निर्धारित प्रपत्र में देने होंगे । जो पहले से ही सरकारी सेवा में हो, उन्हें अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों के मार्फत (Through proper Channel) भिजवाना चाहिये ।

४. १६ वर्ष से कम तथा २५ वर्ष का कोई भी व्यक्ति सामान्यतया विभाग में नौकरी करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जावेगा ।

५. अध्यापकों की भर्ती में, स्थानापन्न, पदों के अलावा प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापकों को यदि वे अन्य प्रकार से योग्य हो, प्राथमिकता दी जावेगी । खेल कूद तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लिया जाना अतिरिक्त योग्यता होगी । मैट्रिक्यूलेशन अथवा समकक्ष योग्यता में नीचे की योग्यता रखने वाले को अध्यापक नियुक्त नहीं किया जावेगा ।

६. बिना उचित आधार के नियुक्ति का नियन्त्रण ठुकराने वाले किसी भी प्रत्याशी को विभाग में नौकरी दिये जाने से उतने समय तक तथा उन परिस्थिति पर अलग रखा जा सकेगा जो कि नियुक्ति कर्ता अधिकारी उचित समझे ।

७. पदोन्नति देने के लिये निम्न निर्देशक सिद्धान्त ध्यान में रखे जावें ।

(१) पदोन्नति, नियम के रूप में, सम्बन्धित वेतन श्रृंखला में वरिष्ठता तथा कार्य कुशलता पर आधारित होगी ।

(२) किसी रिक्त स्थान पर पदोन्नति के लिए कोई भी तब तक अधिकारी नहीं होगा जब तक वह उस पर नियुक्ति के लिये योग्यता नहीं रखता हो, साथ में विद्यालय अथवा कार्यालय जहां पर वह स्थान रिक्त हो, की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा ।

(३) ऐसी पदोन्नति, जिसमें किसी अन्य विद्यालय में जाने की आवश्यकता पड़े, सामान्यतया सत्र के मध्य में नहीं दी जानी चाहिये ।

(४) अध्यापकों के किसी भी वर्ग में रिक्त स्थानों में स्थाई नियुक्तियां करने से पूर्व, ऐसी नियुक्ति करने के लिए सक्षम अधिकारी, निम्न वर्ग (Cadre) में कार्य कर रहे अध्यापकों के दावों- (Claims) पर सर्व प्रथम विचार करेगा । स्थाई पदों पर नई नियुक्ति तभी की जानी चाहिये जबकि यदि वर्ग में से पदोन्नति के लिये कोई योग्य अध्यापक नहीं मिले

८. (१) नियुक्ति के लिये प्रत्याशियों का चुनाव उनकी निम्न बातों पर विचार करने के बाद किया जावेगा:—

- (अ) शैक्षणिक योग्यता
- (ब) शारीरिक सक्षमता
- (स) चरित्र
- (द) आयु
- (य) व्यक्तित्व
- (फ) शैक्षणिक अनुभव
- (ग) खिलाड़ीपन (Sportsmanship)

(२) किसी भी स्टाई पद के लिए चयन किये गये प्रत्याशी को सर्व प्रथम एक वर्ष के परीक्षाकाल (Probation) के लिये नियुक्त किया जावेगा।

९. (१) वरिष्ठता की सूची निम्नानुसार रखी जावेगी—

- (अ) जिलावार:—नानमेट्रिक, अन्ट्रेन्ड मेट्रिक तथा समान श्रेणियों के अध्यापक।
- (ब) श्रेणी (Range) वार:—अन्ट्रेन्ड ग्रेजुएट, अन्ट्रेन्ड इंटरमीजियेट, ट्रेन्ड मेट्रोक्लूनेट तथा समान श्रेणियों के अध्यापक।
- (स) राज्य व्यापी:—शेष सब श्रेणियों के अध्यापक।
- (द) राज्यव्यापी:—लेखक वर्ग (Ministerial Staff)।
- (य) सम्बन्धित संस्था वार:—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

(२) सम्बन्धित अधिकारी तदनुसार आदिनांक तक की सूची रखेंगे।

(३) एक वर्ष की वरिष्ठता सूची प्रत्येक निरीक्षणालय अथवा उप निरीक्षणालय में भी रखी जावेगी। उनकी सामान्य वरिष्ठता सूची उच्चाधिकारियों के कार्यालय में रखी जावेगी।

१०. प्रशासन:—प्रशासनिक पदों अथवा ऐसे पदों पर जिनके कर्तव्य में निरीक्षण भी शामिल है, नियुक्त अधिकारियों को हिन्दी अच्छा का ज्ञान होना चाहिये। यदि वे राजस्थानी से परिचित हैं अथवा जिन क्षेत्र में उन्हें काम करना है, वहां की स्थानीय बोली को समझ सकते हैं, तो यह उनके लिये बड़े उपयोग की बात होगी।

११. निरीक्षण करने वाले अधिकारी के रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जावेगी जिसने स्वीकृत प्रशिक्षण नहीं किया हो अथवा जिनके पास प्रशासन व अध्यापन का अनुभव नहीं होवे।

१२. व्यक्तिगत फाईलें:—अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाईलें संचालक रखेंगा तथा उसके अधीन अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत फाईलें रखेंगे।

१३. संस्था का प्रधान अपने अधीन कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईलें रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यही बात कार्यालय के प्रधान पर अपने अधीन कर्मचारियों के लिये लागू होगी।

१४. निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिये यह उपयोगी होगा कि वे यात्रा के दौरान

एक रफ गोपनीय नोट बुक रखें जिसमें कि संकेत ले लेवें तथा जो कि बाद में अधिनस्थ कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलों में लगा दिये जावें ।

१५. इन फाइलों में प्रवृत्तियां (entries) काफी सावधानी तथा सोच विचार करके की जानी चाहिये क्योंकि वह एक स्थाई रेकार्ड रहेगा जो कि सम्बन्धित अधिकारी के पूरे सेवा काल को प्रभावित करेगा । प्रविष्टियां, नैतिक चरित्र, अधिकारी को सोपे हुये काम को करने के बारे में योग्यता उसका चातुर्य व स्वभाव, आयोजनात्मक व प्रशासनात्मक क्षमता, सामान्य व व्यावसायिक ज्ञान, भाषा सम्बन्धि उपलब्धियां और दौरा करने वाले अधिकारी की बाहर काम करने की योग्यता तथा शारीरिक सहिष्णुता, आदि के बारे में सामान्यतया होनी चाहिये ।

१६. गोपनीय प्रतिवेदनः—संचालक के अधिनस्थ अधिकारी प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च तक अपने अधीन उन समस्त कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति पदोन्नति, व सजा आदि सरकार अथवा संचालक के हाथ में है, के कार्य व व्यक्तिगत आचरण पर एक संक्षिप्त गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

१७. प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट ७) में दिया जाना चाहिये तथा समस्त प्रविष्टियां प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी के द्वारा अपने स्वयं के हाथ से लिखी जानी चाहिये यह प्रतिवेदन रजिस्टर्ड डाक से संचालक को उसके नाम से भेजा जाना चाहिये । निरीक्षण करने वाले अधिकारी के बारे में उसकी निरीक्षण की संख्या व उत्तमता पर सम्मति प्रकट की जानी चाहिये ।

१८. इन प्रतिवेदनों में दी गई सम्मतियां, सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइलों में की गई समय समय की प्रविष्टियों पर आधारित होनी चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवेदन करने वाले अधिकारी को अपनी बात की पुष्टि में प्रमाण देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

१९. प्रतिवेदन करने वाले अधिकारी को अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से दूर रहना चाहिये तथा पक्ष में अथवा विपक्ष में दी गई सम्मति का विवरण देना चाहिये । बहुत ही गम्भीर एवं विरुद्ध प्रतिवेदन होने की स्थिति में, यह आवश्यक है कि विपरीत सम्मति दिये गये कार्यों तथा प्रवृत्तियों का संक्षेप उदाहरण भी दिया जावे ।

२०. ईपानदारी परिश्रम तथा परिपूर्णता आदि सहित विभाग में उच्च कार्य किये जाने की योग्यता ही वे सिद्धान्त हैं जिन पर ही किसी अधिकारी को विशेष पदोन्नति दिये जाने की सिफारिश की जा सकती है ।

२१. स्थानान्तरण—विभागीय कार्य के लिये ही स्थानान्तरण किए जायेंगे ।

२२. कार्य में गड़बड़ी होने तथा शैक्षणिक संस्थाओं की कार्य कुशलता में शिथिलता आजाने जिससे की छात्रों के अध्ययन की हानि हो जाती है, को रोकने के लिए स्थानान्तरण सामान्यतया सत्र के प्रारम्भ में ही किये जायेंगे । वर्ष के मध्य में किये गये समस्त स्थानान्तरणों के आदेश निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर में लिखे जायेंगे जो कि उप शिक्षा संचालकों शाला-निरीक्षकों जिलों के इन्चार्ज उप-निरीक्षकों, सहायक शिक्षा संचालिका अजमेर तथा जोधपुर डिवीजन के कार्यालयों में रहेंगे तथा ऐसे स्थानान्तरणों का आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा वे हस्ताक्षरित होंगे ।

२३. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, विशेष मामलों को छोड़ कर स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । और यदि स्थानान्तरण करना भी हो तो विशेष कारणों के होने पर कर सकेंगे ।

२४. किसी विशेष निर्देश के नही होने की स्थिति में, स्थानान्तरित अधिकारी को उससे वरिष्ठ अधिकारों द्वारा स्थानान्तरण की सूचना मिलने से एक सप्ताह की अवधि में भार मुक्त कर

दिया जावेगा। यदि उपरोक्त अवधि को किसी कारण से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो, तो तत्सम्बन्धी एक प्रतिवेदन नियन्त्रणकर्ता अधिकारी को भार मुक्त किया जा सकता हो, का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

२५. स्थानान्तरण के समय कार्य भार सम्भालने वाले अधिकारी को रजिस्टर व अभिलेख का निरीक्षण कर लेना चाहिए तथा यह पता लगा लेना चाहिए कि वे परिपूर्ण तथा अंतिम तिथि तक तैयार हैं। उसे संस्था में रखी जाने वाली सूची से सम्भाले हुए फर्नीचर, पुस्तकें, रजिस्टर, यन्त्र, (Appliances) आदि का मिलान कर लेना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि नकद रकम कैश बुक में की हुई प्रविष्टि, से मिलती है अथवा नहीं। यदि उस संस्था में स्थायी तौर पर कोई हवालगी रकम (Advance) रहती हो तो उसका भी भार संभाल लेवे। अगर उसको कोई चीज नहीं मिले तो उसे इन तथ्य का कार्य-भार सम्भालने के प्रतिवेदन में उल्लेख करना चाहिए। यह प्रतिवेदन भार-मुक्त होने वाले व भार प्राप्त करने वाले दोनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

२६. कार्य-भार संभालने में अनावश्यक रूप से देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि जाने वाला व आने वाला, दोनों अधिकारी एक ही पद पर साथ साथ काम पर नहीं माने जा सकते।

२७. स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी हो जाने पर भार-मुक्ति का प्रतिवेदन सीधे भेज देना चाहिए।

२८. यदि किसी स्कूल अथवा कार्यालय के किसी कर्मचारी का किसी अन्य स्थान पर स्थित स्कूल अथवा कार्यालय में स्थानान्तरण हो जावे तो उस स्कूल अथवा कार्यालय का प्रधान निर्धारित प्रपत्र में उस कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन चुकारा प्रमाण पत्र (Last pay Certificate) तैयार करेगा तथा आवश्यक जाच के बाद उसे बिना किसी विलम्ब के उस स्कूल अथवा कार्यालय के प्रधान को भेज देगा जहां पर कि स्थानान्तरित कर्मचारी जाने वाला हो। उसे अधिकारी की सेवा पुस्तिका (Service Book) भी भरी जानी चाहिए तथा उसे उसकी नई जगह के उच्चाधिकारी को भेज दी जानी चाहिए।

२९. यदि किसी पदाधिकारी का सामानान्तरण उसकी स्वयं की प्रार्थना पर अथवा उसे मिले हुए दण्ड के परिणाम स्वरूप हुआ हो तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग व्यय नहीं मिलेगा।

३०. अवकाश—सरकारी कर्मचारियों को आकास्मिक अवकाश के अलावा अन्य सब प्रकार के अवकाश के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रार्थना पत्र अवकाश पर जाने की तिथि से लगभग ६ सप्ताह पूर्व अपने नियन्त्रण अधिकारी को दे देना चाहिए।

३१. यदि वह अधिकारी जिसे कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, अवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं होवे तो वह उस प्रार्थना पत्र को बिना अनावश्यक विलम्ब के अपने से उच्च अधिकारियों को भेज देगा।

३२. बीमारी के लिए ली जाने वाली छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ उचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी भेजना चाहिए।

३३. आकस्मिक अवकाश अथवा स्वीकृत छुट्टियों या लम्बे अवकाश के दिनों में अपना हैड क्वार्टर छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र सामान्यतया लगभग एक सप्ताह अग्रिम ही दे देना चाहिए उस

में वापिस लौटने की तिथि का भी उल्लेख होना चाहिए। ग्रीष्मावकाश अथवा लम्बे अवकाश के दिनों का उस कर्मचारी का पता भी सम्बन्धित अधिकारी को लिखा हुआ रखना चाहिये।

३४. कोई भी पदाधिकारी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र से बाहर बिना उचित स्वीकृति के व्यतीत किये गये समय के लिए, कोई भी पदाधिकारी वेतन अथवा भत्ते को पाने का अधिकारी नहीं होगा।

३५. उन समस्त मामलों में, जहाँ पर कि अवकाश (leave) की अवधि एक सप्ताह से अधिक होवे, प्रार्थी को उस अवधि में अपने तात्कालिक उच्चाधिकारी के घर पर जाकर मिलना चाहिये।

३६. (१) आकस्मिक अवकाश, अवकाश सम्बन्धी नियमों द्वारा प्रशासित नहीं होता है।

(२) अवकाश लेने वाला तथा अवकाश स्वीकृत करने वाला, दोनों पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे यदि आकस्मिक अवकाश पर गये हुए किसी पदाधिकारी की अनुपस्थिति से नागरिक सेवा के किसी कार्य का हर्जाना होता हो।

३७. (अ) संस्था के किसी प्रधान अथवा अध्यापक को लम्बे अवकाश (Vacation) में अपने सामान्य कर्तव्यों के अन्तर्गत किये गये किसी कार्य के एवज में कोई अतिरिक्त अवकाश पाने का अधिकार नहीं मिल सकेगा, जब तक कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अथवा उसके विशेष आदेशों के अधीन उसे छुट्टी मनाने से रोक नहीं लिया गया हो।

(ब) उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, भविष्य में निम्न नियमों का पालन करना चाहिये :—

(१) अत्यावश्यक कार्य के लिए एक विद्यालय में केवल एक ही अध्यापक को ऐसे अवकाश में रोकना चाहिये तथा (Vacation) प्रारम्भ होने के लगभग दो माह पूर्व उस अध्यापक का नाम सक्षम अधिकारी को भेज दिया जाना चाहिये ताकि उसे उसके बदले में प्रीविलेज छुट्टी दी जा सके।

(२) यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य प्रशासनिक कार्य के लिए प्रधानाध्यापक को स्वयं को ही (Vacation) में रकना चाहिए किन्तु किन्हीं विशेष कारण से सम्बन्धित प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति आवश्यक समझता हो तो उसे कारणों का वर्णन करना चाहिए तथा (Vacation) प्रारम्भ होने से दो माह पूर्व ही उसे उस अवधि में कार्य करने की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(३) यदि प्रधानाध्यापक को इस अवकाश में रोका जावे तो फिर किसी अन्य अध्यापक को रोकना आवश्यक नहीं है।

(४) विद्यालय का लेखक वर्ग (Clerks), लम्बे अवकाश पाने का अधिकारी नहीं होने से (Vacations) में भी अपना कार्य जारी रखेगा।

३८. संस्था तथा कार्यालयों के प्रधानों को अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ (Service Books) रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

३९. स्थायी नियुक्ति पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उसकी नियुक्ति अथवा उसके स्थायीकरण की तिथि से तीन माह के भीतर भीतर तैयार कर ली जानी चाहिए।

४०. प्रत्येक पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका उसके तात्कालिक उच्चाधिकारी के नियंत्रण में रहेगी जो कि उसको ठीक प्रकार से रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

अध्याय १३

शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना

१. राज्य में स्थित समस्त शिक्षा संस्थाएँ उनमें दिये जाने वाले शिक्षण के स्तर एवं स्वरूप के अनुसार निम्नानुसार वर्गीकृत की जावेगी ।

(१) (अ) स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ।

(ब) इन्टरमीडियेट महाविद्यालय ।

(स) बहुउद्देशीय, उच्चतर माध्यमिक व उच्च विद्यालय ।

(द) माध्यमिक विद्यालय ।

(य) प्राथमिक शालाएँ ।

(फ) शिशु शालाएँ ।

(२) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ ।

(अ) वे संस्थाएँ जो कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण देती हों यथा एम० एड० व बी० एड० ।

(ब) शिक्षण में डिप्लोमा देने वाली :—

[१] इन्टरमीडियेट के लिये सी० टी०

[२] मैट्रिक्यूलेंट के लिए वेसिक एस० टी० सी०

(३) प्राच्य विद्या संस्थाएँ ।

(४) तकनीकी व व्यावसायिक संस्थाएँ ।

(५) विशिष्ट संस्थाएँ ।

२. उच्च विद्यालय, इन्टरमीडियेट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय और एम० एड०, बी० एड० व सी० टी० के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, अतः एतदर्थ प्रार्थना पत्र तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय को ही दिया जाना चाहिए । उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं को मान्यता उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदान करता है ।

टिप्पणी :—गत कुछ वर्षों से हाईस्कूल परीक्षा की व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंप दी है अतः उच्च विद्यालयों को मान्यता भी अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल ही प्रदान करता है । इस मंडल का कार्यालय अजमेर में स्थित है ।

३. पूर्ववर्ती नियम संख्या २ में उल्लिखित संस्थाओं तथा उन संस्थाओं जिनको कि मान्यता सीधी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, को छोड़कर बाकी समस्त संस्थाओं को मान्यता विभाग

प्रदान करता है तथा वह मान्यता विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती नियमों के अनुसार निम्न-लिखित शर्तों पर प्रदान की जावेगी :—

(१) कि वह संस्था एक उपयोगी शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति करती है तथा विभाग द्वारा निर्धारित अथवा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण देती है।

(२) कि छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम की विविधता, जो कि विद्यालय बढ़ाना चाहे, तथा दक्षता की सामान्य आवश्यकताओं को देखते हुए वह संस्था अपने छात्रों के मानसिक, नैतिक, व शारीरिक विकास के लिए उचित, न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने के लिए यथेष्ट धन स्रोत रखती है।

(३) कि धर्म, जाति, नस्ल व वंश पर आधारित भेदभाव के बिना सब के लिए जिसमें प्रवेश खुला है।

(४) कि व्यवस्थापक महमत है कि वे संस्था की काय कुशलता को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जारी किये गए नियम एवं निर्देशों, जो कि समय समय पर जारी किए गये हों, का पालन करेंगे।

(५) कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की संस्था, चाहे वह एक अथवा अधिक व्यक्ति या किसी न्य'स (ट्रस्ट) द्वारा संचालित हो, एक निर्धारित प्रबन्ध समिति के नियंत्रण में कार्य करेगी ऐसी प्रबन्ध समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। उसके बाद ही मान्यता प्रदान की जावेगी अथवा जारी रखी जावेगी।

प्रबन्ध समिति में १५ से अधिक सदस्य नहीं होंगे तथा आधे से अधिक सदस्य किसी विशिष्ट जाति अथवा वर्ग के नहीं होंगे। उस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

१. सदस्यों में से एक तिहाई दाताओं तथा नियमित रूप से चन्दा देने वालों में से होंगे।

२. सदस्यों की $\frac{1}{2}$ संख्या, जिला शिक्षा निरीक्षक व प्रधानाध्यापक दोनों की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामजद की जावेगी। यदि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष तथा शिक्षा-संचालक अलग अलग व्यक्ति हो तो इन मनोनीत सदस्यों में से एक की नामजदगी शिक्षा संचालक करेंगे तथा दो की माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। जो संस्थायें मण्डल के अधिकार-क्षेत्र में नहीं हैं, उनमें ये मनी-नयन शिक्षा संचालक करेंगे।

३. कुल संख्या के $\frac{1}{2}$ सदस्य छात्रों के अभिभावकों में से होने चाहिए।

४. दो अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा एक जिला शिक्षा प्रशासन का प्रतिनिधि होगा।

५. प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य-सचिव होगा।

प्रबन्ध-समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

१. अध्यक्ष

१. दो उपाध्यक्ष (इनमें से एक व्यवस्थापक का कार्य करेगा)

३. कोषाध्यक्ष

४. सचिव (प्रधानाध्यापक)

नोट:—सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी दाताओं में से होंगे।

(६) कि उस संस्था की प्रबन्ध समिति का गठन संचालक द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा उसमें बाद में उसकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि संचालक की राय में स्वीकृति रोक दी जानी चाहिए तो वह आदेश प्राप्त करने के लिए उस मामले को सरकार के पास भेजेगा। सरकार उस मामले पर, यदि सम्बन्धित संस्था चाहे तो उसके प्रतिनिधि की बात सुनकर अपना आदेश देगी।

(७) कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों में किया गया प्रत्येक परिवर्तन विभाग को सूचित किया जावेगा।

(८) कि भवन के अन्दर व बाहर किये जाने वाले कार्यों के लिए उचित भवन व क्रीडांगण बने हुए हैं और उनका प्रयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य तक ही सीमित है। वे किसी भी हालत में सांप्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त नहीं होंगे।

(९) कि विभाग द्वारा निदिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें, फर्नीचर, तथा दूसरा सामान संस्था में मौजूद है।

(१०) कि छात्रों की शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रावधान किया जाता है।

(११) व्यवस्थापकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे सेवा के निर्धारित नियम, जिनमें वेतन, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि आदि के बारे में शर्तें निश्चित ही, बनायेंगे। प्रत्येक व्यवस्थापक को नियुक्ति के समय इन सब नियमों की एक प्रति मिलनी चाहिये तथा उसे विद्यालय में सेवा करने के लिये एक अनुबंध करना पड़ेगा। अनुबंध में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान भी होना चाहिये कि किसी कर्मचारी को पदच्युत करने पर, नौकरी से हटाने पर अथवा उसका वेतन कम करने पर वह निम्नानुसार पुनर्विचार (appeal) की प्रार्थना कर सकेगा।

अपील कर्ता

सक्षम प्राधिकारी

(अ) १०० तक मूल वेतन
पाने वाला कर्मचारी

संबंधित उप शिक्षा संचालक

(ब) १०० से अधिक
मूल वेतन पाने वाले
कर्मचारी (उच्च विद्यालयों
के प्रधानाध्यापक तथा महा विद्यालयों
के आचार्य के अतिरिक्त)

संचालक

(स) उच्च विद्यालयों के
प्रधानाध्यापक तथा
महा विद्यालयों के आचार्य

सरकार का शिक्षा
सचिव

निजी क्षेत्र की संस्था के कर्मचारियों का एक नक्शा निर्धारित प्रपत्र पर उनके नाम, योग्यता आदि का उल्लेख कर प्रति वर्ष संस्था के प्रधान द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जावेगा।

(१२) संस्था अपने कर्मचारियों के लिए वे ही वेतन शृंखलाएँ निर्धारित करेगी जो कि उसी योग्यता वाले कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत है। सक्षम अधिकारी द्वारा उनमें छोड़ी

बहुत हेर फेर करने की अनुमति दी जा सकती है ।

(१३) संस्था के समस्त कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान किये जाने का प्रावधान भी किया जावेगा । संबंधित कर्मचारी अपने मासिक वेतन की ६ $\frac{१}{४}$ % धनराशि संस्था में जमा करावेगे जिसके कि बराबर का अंश संस्था द्वारा भी जमा किया जावेगा । यह रकम सरकारी सिक्यूरिटीज अथवा अन्य प्रकार के कार्य (जिसमें कि बैंक में जमा कराना भी सम्मिलित है) जो कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, में लगाई जावेगी । प्रत्येक कर्मचारी की भविष्य निधि का विवरण प्रतिवर्ष निर्धारित प्रपत्र पर भरकर सक्षम प्राधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को प्रेषित किया जाना चाहिये ।

(१४) कि शिक्षक वर्ग में किया गया प्रत्येक परिवर्तन, कारणों सहित सरकार को सूचित किया जावेगा ।

(१५) कि किसी जाति विशेष के लिए दी जाने वाली शिक्षा में छात्रों अथवा अध्यापकों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ।

(१६) संस्था में दी जाने वाली सामूहिक प्राधनार्थ जाति गत अथवा विषादाग्रस्त नहीं होगी ।

(१७) विभाग की पूर्व स्वीकृति बिना कोई नई कक्षा अथवा सेक्सन नहीं खोला जावेगा ।

(१८) प्रत्येक कक्षा अथवा सेक्सन में छात्रों की अधिकतम संख्या विभाग द्वारा निर्धारित अंक से अधिक नहीं होगी ।

(१९) विभाग द्वारा चाही गई सूचनायें तुरन्त तथा नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

(२०) संस्था एवं उसका समस्त अभिलेख (Record), हिसाब आदि निरीक्षण किये जाने तथा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आडिट किये जाने के लिए प्रस्तुत हैं ।

(२१) अध्यापकों व छात्रों के एक संस्था से दूसरी संस्था में आवागमन के लिए विभाग द्वारा बनाये हुए नियम अथवा विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंधों के संचालन हेतु बनाये गये नियमों का संस्था पालन करती है ।

(२२) संस्था का सामान्य वातावरण बच्चों की शिक्षा के लिये सहायक है ।

४. संचालक चाहे तो मान्यता चाहने वाली किसी संस्था को उपरोक्त शर्तों में से एक अथवा अधिक का पालन करने से सकारण मुक्त कर सकता है ।

५. संस्था को प्रदान की गई मान्यता यदि उसको प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर भीतर उसका उपयोग नहीं किया गया, तो रद्द समझी जावेगी ।

६. यदि शिक्षा संचालक संतुष्ट हों कि वह संस्था शिक्षा के लिए उचित परिस्थितियों में मुविधा प्रदान नहीं कर रही है तो वे उस संस्था की मान्यता अस्थायी तौर निलम्बित या स्थाई तौर पर वापस कर सकते हैं ।

७. जिस संस्था की मान्यता वापस ले ली गई हो, उसे वह मुविधा तब तक पुनः नहीं लौटाई जावेगी जब तक कि संचालक को संतोष नहीं हो जावे कि वे सब कमियाँ, जिनके कि कारण से मान्यता छीन ली गई थी, दूर कर दी गई हैं तथा अन्य सब प्रकार से संस्था निर्धारित शर्तों को पूरा करती है ।

८. यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्था अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, या किसी अन्य

स्थान पर स्थानान्तरित हो जाते हैं अथवा नई प्रबंधक समिति का गठन हो जाता है, तो उस संस्था की मान्यता रद्द हो जावेगी तथा भविष्य के लिए मान्यता के प्रश्न के लिये उसे नई संस्था माना जायेगा यदि परिवर्तन संचालक की स्वीकृति के बिना हुआ होवे ।

६. मान्यता एक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही दी जावेगी अर्थात् १ जुलाई से उसके लिये प्रार्थना पत्र ३१ अक्टूबर से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट १३) मान्यता प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारों को दे देना चाहिए ।

१०. विभागीय अधिकारी निम्नानुसार मान्यता प्रदान करने के लिये अधिकृत हैं

प्रशिक्षण संस्थायें)	
विशिष्ट संस्थायें)	
तकनीकी संस्थायें)	शिक्षा संचालक
महाविद्यालय के स्तर की प्राच्य-)	
विद्या संस्थायें)	
माध्यमिक विद्यालय		—श्रेणी का उप शिक्षा संचालक
प्राथमिक पाठशाला		—जिला निरीक्षण
संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय से)	निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला
निम्नास्तर की प्राच्यविद्या संस्थायें)	

११. प्रार्थना पत्र देने पर तथा प्रत्येक मामले में अलग अलग शर्तें निर्धारित कर सरकार यदि चाहे तो ऐसी संस्थाओं को कि गिला को अपनी योजना तथा स्वतंत्र पाठ्यक्रम का अनुकरण करती हो, को सीधी ही मान्यता प्रदान कर सकती है ।

१२. उन समस्त संस्थाओं, जिनको कि इन नियमों के प्रचलन से पूर्व ही राजस्थान शिक्षा विभाग अथवा देशी रियासतों के शिक्षा विभागों द्वारा मान्यता मिल चुकी हो, को उनके वर्तमान स्तर तक इन नियमों के अन्तर्गत भी मान्यता प्राप्त समझा जावेगा । यदि उनका स्तर बढ़ाया गया हो, अथवा नई कक्षाएँ खोली गई हों तो उन्हे इन नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी ।

१३. जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था नहीं दी गई हो, मान्यता, प्रबन्ध, फीम, छुट्टियाँ, लम्बे अवकाश, पाठ्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के लिए सक्षम अधिकारी निम्न होंगे:—

संस्थायें	सक्षम अधिकारी
(१) स्नातक व स्नातकोत्तर)
महाविद्यालय) सरकार के शिक्षा सचिव
(२) इंटरमीजियेट महाविद्यालय)
(३) प्रशिक्षण संस्थायें, विशिष्ट)
संस्थायें, महाविद्यालय स्तर) शिक्षा संचालक
की प्राच्य विद्या संस्थायें)

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| (४) उच्च विद्यालय | —उप शिक्षा संचालक |
| (५) माध्यमिक विद्यालय | —जिला शिक्षा निरीक्षक |
| (६) संस्कृत पाठशालायें | —संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक |

जब तक कि विशेष आदेश नहीं हो, अमान्य संस्थाओं के छात्र वे सब सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे, जो कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को मिलती है ।

अध्याय १४

विभागीय परीक्षायें

१. विभागीय परीक्षाएँ, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षा के नियन्त्रण में हैं जिसकी सहायतायें उन रजिस्ट्रार तथा अन्य आवश्यक लिपिक वर्ग एवं कर्मचारी कार्य करते हैं । वह संचालक, शिक्षा विभाग के निरीक्षणधीन इन परीक्षाओं को लेने के प्रति उत्तरदायी हैं ।

२. वर्तमान में निम्न विभागीय परीक्षाएँ ली जाती हैं:—

(१) अध्यापक प्रमाणपत्र परीक्षा ।

(अ) सीनियर बेसिक टीचर सर्टिफिकेट परीक्षा ।

(२) संस्कृत परीक्षाएँ:—

(अ) प्रवेशिका परीक्षा ।

(ब) उपाध्यक्ष परीक्षा ।

(स) शास्त्री परीक्षा ।

(द) आचार्य परीक्षा ।

(३) आयुर्वेद परीक्षाएँ:—

(अ) भिषग्वर ।

(ब) आयुर्वेदिक शास्त्री ।

(स) भिषगाचार्य ।

(द) आयुर्वेदाचार्य ।

(४) व्यापारी वर्ग परीक्षाएँ (इंग्लिश शार्ट हैंड तथा टाइप राइटिंग) ।

३. विभिन्न परीक्षाओं के शुल्को की सूची परिशिष्ट ६ में दी गई है ।

४. संस्कृत, आयुर्वेदिक तथा व्यापारी वर्ग परीक्षाओं की कोई पूरक परीक्षा न होगी ।

५. (अ) परीक्षा शुल्क किसी भी आधार पर वापिस नहीं किया जावेगा ।

(ब) कोई विद्यार्थी यदि विशेष बीमारी के कारण उस परीक्षा में नहीं बैठ सकता हो जिसके लिये वह प्रविष्ट किया गया है या की गई है, तो आगामी वर्ष में केवल परीक्षा शुल्क का चौथाई शुल्क जमा कराकर उस परीक्षा में वह बैठ सकेगा, बशर्ते कि

(i) वह परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से १५ दिन के भीतर प्रस्तोता के पास अपना शुल्क आगामी वर्ष की परीक्षा में बैठने हेतु सुरक्षित रखने हेतु आवेदन पत्र देवें ।

(ii) इस आवेदन के साथ राजकीय चिकित्सा अधिकारी का रोग प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे जिसमें उसकी बीमारी का वर्णन हो ।

६. प्रश्न पत्र बनाने वाले, परीक्षक, परीणाम की सूची तैयार करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति संचालक के द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति में संचालक की सिफारिश द्वारा की जावेगी।

७. (१) केन्द्रों का वितरण जहाँ छात्र उम्मीदवार १०० होंगे या छात्रायें उम्मीदवार ५० होंगी वहाँ एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र की जगह का चुनाव करते समय यातायात के साधन तथा आवास, कर्मचारीगण, फर्नीचर आदि की सुविधा को ध्यान में रखा जावेगा।

(२) उन जालाओं के प्रधानाध्यापक, जहाँ परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, परीक्षा केन्द्र के परीक्षक अधीक्षा (Superintendent) होंगे।

(३) केन्द्र अधीक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार संचालक, शिक्षा विभाग की अनुमति से, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षा द्वारा प्रसारित एक विवरण पत्र में दिये हूये होंगे।

८. विभिन्न विभागीय परीक्षाएँ लेने की तिथि प्रस्तोता द्वारा निश्चित तथा प्रकाशित कर दी जावेगी। सामान्यतः परीक्षाएँ निम्न प्रकार से ली जावेगी :—

एस० टी० सी० परीक्षाएँ

(i) व्यावहारिक—लगभग मार्च माह में।

(ii) सैद्धांतिक—मई के प्रथम सप्ताह में या अप्रैल के सप्ताह में।

संस्कृत एवं आयुर्वेदिक परीक्षाएँ

अप्रैल के तीसरे सप्ताह में।

व्यापारिक वर्ग परीक्षाएँ

अप्रैल के दूसरे सप्ताह में।

९. विभिन्न परीक्षाओं का पाठ्यक्रम (Syllabus) व अध्ययन क्रम (Course) समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

१०. विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में उम्मीदवारों को उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य नियम निम्न प्रकार होंगे किन्तु जब कभी आवश्यकता हो तो संचालक अपने निर्णयानुसार इन नियमों को संशोधित या कुछ बंधन मुक्त कर सकता है।

११. एस० टी० सी० परीक्षाएँ :—

एस० टी० सी० (बैसिक) की व्यावहारिक परीक्षा में अध्यापकों के अनुत्तीर्ण हो जाने पर उन्हें दूसरे वर्ष प्रशिक्षणार्थ पुनः भेजा पड़ेगा। यदि पुनः भी वे इस व्यावहारिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे इस परीक्षा में पुनः बैठने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि एक उम्मीदवार जो राजकीय सेवा में है एक बार इस व्यावहारिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह दूसरी बार यह व्यावहारिक प्रशिक्षण अपने खर्च से लेगा तथा यदि वह दुबारा इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा तो वह राज्य सेवा से मुक्त कर दिया जायगा।

१२. संस्कृत एवं आयुर्वेदिक परीक्षाएँ :—

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम :— जो पाने हेतु योग्यता, उत्तीर्ण करने के लिए नियम आदि अलग में जारी किये गये पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार होंगे।

१३. सभी परीक्षाओं के एक प्रश्नपत्र के स्थान, समय, दिनांक आदि का पूर्ण कार्यक्रम प्रस्तोता द्वारा राजस्थान राजपत्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व घोषित कर दिया जावेगा।

१४. सभी परीक्षाओं के लिए अध्ययनक्रम व पाठ्यक्रम (Syllabus) प्रत्येक विषय के

प्रश्नपत्रों की संख्या तथा प्रत्येक विषय या प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित अंक तथा विशेष नियम एवं निर्देश जिनका उल्लेख इस कोड के प्रावधानों में नहीं किया गया है, वे सब संचालक द्वारा जारी किये जायेंगे, यदि वे पहले इस रूप में प्रकाशित नहीं किये गये हों जैसा कि वह चाहता है।

१५. (१) आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिए गये प्रश्न-पत्रों का उत्तर सम्बन्धित भाषाओं में ही दिया जावेगा। केवल किसी विशेष प्रश्न या प्रश्न के अंश में या जब तक परीक्षक द्वारा अन्य भाषा का प्रयोग नहीं चाहा गया हो तो वहां उस भाषा का प्रयोग किया जावेगा।

(२) विदेशी भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर सम्बन्धित भाषा में दिया जावेगा। यदि परीक्षक द्वारा अन्य भाषा में उत्तर वांछित हो तो वह उस भाषा में ही दिया जावेगा।

(३) वाकी विषयों के प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जावेगा।

१६. जो अध्यापक या उम्मीदवार राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र के रूप में प्रविष्ट होंगे वे अध्यापक प्रशिक्षण में प्रविष्ट किये जावेंगे यदि उन्होंने परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है तथा उन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार निर्धारित व्यावहारिक कार्य पूर्ण कर लिया है।

१७. संस्कृत, आयुर्वेदिक परीक्षाओं के छात्रों का प्रवेश इन परीक्षाओं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार किया जावेगा।

१८. व्यापारी वर्गीय परीक्षाओं के लिए प्रवेश समय समय पर जारी किये गये इस कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार होगा।

१९. मुख्य परीक्षक, प्रश्नपत्र बनाने वाले, परीक्षक, टेब्लेटर्स, चैकर्स तथा परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों का पारिश्रमिक संचालक द्वारा निश्चित किया जावेगा।

२०. परीक्षायें लेते समय उसकी उचित गोपनीयता, दक्षता आदि की ओर रजिस्ट्रार को विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। प्रश्न पत्र बनाने वाले, परीक्षक, टेब्लेटर्स आदि के नामों की अत्यन्त गोपनीयता रखनी पड़ेगी तथा प्रश्नपत्र रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेजे जाने चाहियें। प्रस्तोता या एक उप प्रस्तोता प्रैस में प्रूफरीडिंग (Proofreading) हेतु रहेगा जिससे कि उसकी गोपनीयता रह सके। सभी परीक्षा पत्र प्रस्तोता के पास सुरक्षित रहेंगे। जब तक कि वे सम्बन्धित केन्द्रों पर बीमायुक्त डाक पार्सल द्वारा नहीं भेज दिये जाते हैं। प्रस्तोता के लिए ऐसे प्रश्न पत्रों को छपाने के लिए टैंडर आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं होगा बशर्तकि प्रश्नपत्रों का छपना पूर्ण रूपेण प्रस्तोता के जिम्मे रहेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए वह पूर्ण स्वतन्त्र है।

विभागीय परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य विषय में जिसका ऊपर वर्णन नहीं किया गया हो, रजिस्ट्रार को संचालक से मार्ग प्रदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त करना चाहिए तथा उसे उन सभी आदेशों का पालन करना चाहिये जो संचालक द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों।

अध्याय १५

संस्कृत एवं आयुर्वेदिक शिक्षा

१. वर्गीकरण—राजस्थान में वर्तमान संस्कृत संस्थाओं को सामान्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(अ) प्रवेशिका तथा उपाध्याय स्तर तक के पाठ्यक्रम की शालायें ।

(व) शास्त्री एवं आचार्य परीक्षाओं के लिये उम्मीदवारों को अध्ययन कराने वाले संस्कृत महा विद्यालय ।

२. नियन्त्रण—केवल संस्कृत विद्यालय, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर के अतिरिक्त सभी शिक्षण संस्थायें विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं तथा संस्कृत पाठशाला के निरीक्षक द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता है निरीक्षक को उपनिरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है ।

३. संस्कृत महा विद्यालय जयपुर, उदयपुर एवं अलवर सीधे सरकार के अधीन कार्य करते हैं तथा सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान से उनका सीधा पत्र व्यवहार रहता है ।

४. किसी भी संस्कृत संस्था में कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाता है तथा गरीब एवं योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति सहायता के रूप में दी जाती है ।

५. अन्य शिक्षण संस्थाओं का जो समय, अवकाश एवं छुट्टियां रहती हैं वे सभी इन संस्कृत संस्थाओं में रहेंगी । समक्ष अधिकारी द्वारा जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

२. प्रस्तोता निम्न परीक्षायें लेता है:—

प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आचार्य । प्रवेशिका के अध्ययन का पाठ्यक्रम दस वर्ष का होता है । एक व्यक्ति के प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसे उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु दो वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा तथा इस प्रकार जो शास्त्री परीक्षा में प्रविष्ट होगा उसे उपाध्याय उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा । एक शास्त्री को आचार्य परीक्षा में प्रवेश होने से पूर्व ३ वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा इस प्रकार आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कम से कम १७ वर्ष का पूर्ण समय होना अनिवार्य है ।

७. सभी संस्कृत संस्थाओं एवं सभी संस्कृत परीक्षाओं हेतु एक सामूहिक पाठ्यक्रम (Syllabus) एवं अध्ययनक्रम तैयार किया गया है । प्रवेशिका उत्तीर्ण करने में अंग्रेजी को आवश्यक तथा उपाध्याय एवं शास्त्री परीक्षा में ऐच्छिक विषय रहा है । शास्त्री स्तर तक हिन्दी आवश्यक विषय है ।

८. राजस्थान में आयुर्वेदिक कालेज, आयुर्वेदिक अध्ययन, अधीक्षक के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।

९. प्रस्तोता निम्न आयुर्वेदिक परीक्षायें लेता है:—

(१) निपगवर (आयुर्वेद शास्त्री)

(२) निपगचार्य (आयुर्वेदाचार्य)

१० उपरोक्त परीक्षाओं के अध्ययन का संग्रहीत पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है तथा निपगवर तथा निपगचार्य की परीक्षाओं में बैठने के लिये कम से कम समय क्रमशः ४ और २ वर्ष हैं ।

११ निपगवर परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये निम्न परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:—

(१) संस्कृत कालेज बनारस से मध्यमा परीक्षा ।

(२) इनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मध्यमा ।

- (३) पंजाब से विशारद ।
- (४) बंगाल की तीर्थ परीक्षा ।
- (५) जयपुर की उपाध्याय ।
- (६) मैट्रिक जिसमें ऐच्छिक विषय संस्कृत रहा हो ।

१२. किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जाता है तथा गरीब एवं योग्य व्यक्तियों की सहायतार्थ छात्रवृत्ति दी जाती है ।

१३. आयुर्वेदिक कालेज के साथ अस्पताल, प्रदर्शन तथा अम्याम आदि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति हेतु संलग्न है तथा परीक्षाये व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों रूपों में ली जाती है ।

अध्याय १६

स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य सह-शैक्षणिक प्रवृत्तियां

१. (१) खेलकूद (Games & Sports) शिक्षा का एक अभिन्न अंग है अतः शरीर एवं मस्तिष्क के उचित विकास के लिए, जो कि सही प्रकार के नागरिकों का निर्माण करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, उस पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(२) प्रत्येक संस्था का प्रधान खेलकूद के आयोजन के लिये मुख्यतया उत्तरदायी है और उसे यह देखना चाहिये कि छात्रों तथा अध्यापकों द्वारा उनमें यथेष्ट रुचि ली जाती है । जहां तक संभव हो प्रत्येक छात्र को खेलकूद में नियमित रूप से भाग लेने के लिए कहना चाहिए ।

(३) जहां तक कि खेलकूद की विविधता का प्रश्न है, यह पाठशाला के स्तर तथा छात्रों की संख्या और प्राप्त धनराशि पर निर्भर करेगा । माध्यमिक शालाओं के लिए हांकी, फुटबाल, वालीबाल तथा वास्केट बाल उचित है जबकि प्राथमिक शालाओं में बिना खर्चे के खेल तथा "खो खो" को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

(४) इन प्रवृत्तियों के धन की व्यवस्था हेतु, इस कार्य के लिए सरकार से मिले अनुदान (Grant) की कमी पूरी करने के लिए समस्त शिक्षण संस्थाएँ क्रीड़ा शुल्क (Games fee) लेती हैं । संस्था-प्रधान का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त अनुदान का छात्रों की अधिकतम संख्या के लाभार्थ उचित रीति से उपयोग होता है ।

(५) इन लाभदायक प्रवृत्तियों को गति व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, अध्यापकों को इन्हें अपने कर्तव्य का एक भाग समझना चाहिए और इनके आयोजन में सक्रिय सहयोग देना चाहिए तथा स्वयं को उनमें भाग लेना चाहिए ।

२. शारीरिक शिक्षा:—(१) माध्यमिक विद्यालयों में जबकि साधारणतया पूरे समय कार्य करने वाले शारीरिक प्रशिक्षण होते हैं, अन्य संस्थाओं में अध्यापकों में से ही एक इन प्रवृत्तियों को देखता है । अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें कि अपने विद्यालयों में इन प्रवृत्तियों के आयोजन व प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षित अध्यापक मिल सकें ।

(२) निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को अपने निरीक्षण के समय देखना चाहिए कि शिक्षा के इन महत्वपूर्ण अंग पर आवश्यक ध्यान दिया जाता है । अपने निरीक्षण कार्य के भाग के

रूप में शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेलकूद का प्रदर्शन देखना चाहिए ।

(३) शारीरिक शिक्षा के कुशल प्रावधान के लिए शारीरिक प्रशिक्षकों का शिक्षण आवश्यक है । अतएव राजस्थान में शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय की स्थापना होने तक राज्य से बाहर स्वीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए योग्य अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिये ।

(४) दीर्घकालीन अवकाश तथा छुट्टियों में अल्पकालीन प्रशिक्षण अध्ययन क्रम (Courses) और शारीरिक शिक्षा कम्पस का आयोजन किया जाना चाहिये । अपने ज्ञान तथा व्यवहार को आदिनांक (Upto Date) रखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए नवीनीकरण अध्ययन क्रम (Refresher Courses) आवश्यक है ।

(५) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में रखा गया है । छात्रों के शारीरिक विकास के लिये स्वीकृत शारीरिक परीक्षा (Physical tests) का भी आयोजन किया जाना चाहिये ।

३. स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतियोगितायें:—खेलकूद के टूर्नामेंट्स एक स्वस्थ प्रतियोगिता का अवसर देते हैं, अतः वे विभिन्न स्तर की संस्थाओं द्वारा स्थानीय प्रादेशिक अथवा राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिये । त्रिदं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था में जन सहयोग स्वच्छन्दता से लिया जाना चाहिये और उनकी व्यवस्था के लिए गठित समितियों में गैर सरकारी लोगों को भी लिया जाना चाहिए । इनका खर्च पूरा करने व लोगों में अभिरुचि जागृत करने के लिये सार्वजनिक चन्द्रा व दान राशि भी एकत्रित की जानी चाहिये ।

४. शारीरिक योग्यता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, स्कूलों द्वारा अलग अलग अथवा किसी क्षेत्र में बहुत से विद्यालयों द्वारा सामूहिक रूप से शारीरिक सांस्कृतिक सप्ताहों का आयोजन किया जाना चाहिए जैसा कि प्रचार की दृष्टि से इन सप्ताहों का आयोजन एक अच्छा साधन है ।

गणतन्त्र दिवस व स्वतन्त्रता दिवस जैसे उत्सवों के अवसर पर विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए तथा छात्रों में राष्ट्रीय व सामूहिक चेतना जागृत करने के लिये सामूहिक शारीरिक शिक्षण व संचलन (March past) के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करनी चाहिए ।

५. गणवेश (Uniform):—जहां तक सम्भव हो सके खेलों व शारीरिक शिक्षा के लिये विशेष गणवेश निर्धारित की जानी चाहिए । गणवेश सस्ती होनी चाहिए ताकि छात्र उसे खरीदने की स्थिति में हो सकें । योग्य तथा इच्छुक छात्रों को खेल कूद के अनुदान व क्रीड़ा शुल्क निधि में से सहायता दी जा सकती है ।

क्रीड़ांगण (Play Ground):—खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के उचित विकास के लिए क्रीड़ांगण के लिए प्रावधान होना अत्यावश्यक है । जहां पर (क्रीड़ांगण) विद्यमान नहीं हो, वहां पर उद्देश्य के लिए भूमि का एक उपयुक्त टुकड़ा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । इन सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति प्रमुखतया सम्बन्धित संस्था के प्रयत्नों व मूत्रपात (Initiative) पर निर्भर करेगी ।

७. चिकित्सा निरूपण (Medical Examination) (१) छात्र के स्वास्थ्य की

उचित जांच रखने तथा जहां आवश्यक हो, संरक्षकों को आवश्यक सम्मति व मार्ग दर्शन देने के लिये, उचित चिकित्सा निरूपण के लिये सभी संस्थाओं में प्रावधान किया जाना चाहिये ।

(२) संस्था प्रधान को यह देखने के लिये कि छात्रों के स्वास्थ्य व सफाई की उचित तौर पर देखभाल होती है अथवा नहीं स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रगाढ़ सम्पर्क रखना चाहिये । कभी अथवा दोष पाये जाने पर शीघ्र व उचित इलाज की आवश्यकता के लिये छात्रों व उनके अभिभावकों पर बल दिया जाना चाहिये तथा उनके क्रियान्वयन का लेखा रखना चाहिये ।

८. रेडक्रास:—जूनियर रेडक्रास आन्दोलन, जिसका कि उद्देश्य स्वास्थ्य में अभि वृद्धि तथा बीमारों की सेवा करना और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता बढ़ाना है, को हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा यह वांछनीय है कि सगस्त मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक एवं माध्यमिक, शालाओं व इन्टरमीजियेट महाविद्यालयों में जूनियर रेडक्रास समूहों (Groups) की स्थापना की जानी चाहिये ।

९. स्काउट व गाइड आन्दोलन:—(१) बालचर आन्दोलन की महान् शैक्षणिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा संचालक को शिक्षा संस्थाओं में रोवर क्रूज (Rover Crews) स्काउट व गाइड ट्रूप्स (Scout & Guide Troops) तथा कब्ज व बुलबुल पैक्स (Cubs & Bul-Bul Packs) की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

(२) अध्यापकों के प्रशिक्षण को समृद्धि बनाने तथा स्काउट्स यथेष्ट संख्या में प्राप्त करने के लिये एस० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों में स्काउटिंग व कबिंग के प्रशिक्षण को अनिवार्य बना देना चाहिये । प्रशिक्षण विद्यालयों के बजट अनुदान में ऐसे प्रशिक्षण केम्पो के लिये उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए ।

अध्याय १७

सहायता-अनुदान के लिये नियम

१. राजस्थान में राज्य के शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास के लिये कार्य करने वाली समस्त संस्थाएँ इन नियमों के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए ग्राह्य (Eligible) होगी ।

२. ये संस्थाएँ दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जावेंगी ।

(अ) शैक्षणिक संस्थाएँ:—इस श्रेणी में वे सब संस्थाएँ सम्मिलित होंगी जो कि नियमित रूप से शिक्षा देती हैं तथा जो या तो विभाग अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हैं या अपनी विशेष शिक्षा योजना तथा स्वतन्त्र पाठ्यक्रम के अनुसार चलती हैं ।

(ब) अन्य संस्थाएँ:—इस श्रेणी में शिक्षा के अन्य अंगों से सम्बन्धित संस्थाएँ सम्मिलित हैं यथा प्राचीन साहित्य के प्रकाशन के लिये शोध संस्थान (Research Institutes), प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक स्तकालय, शिशु शालाएँ, व्यावसायिक व शिशु मार्ग दर्शक संस्थाएँ, खेलकूद क्लब, शारीरिक संस्कृति रुच, हार्डिङ्ग व कैम्पिंग (Hiking & Camping club) स्काउट तथा गाइड संघ, संगीत तथा ललितकला संस्थाएँ व इनके समान अन्य संस्थाएँ ।

३. उपरोक्त श्रेणी संस्था २ (अ) की कोई भी संस्था सहायता अनुदान के लिये तभी ग्राह्य

(Eligible) होंगी जबकि वे सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत एक सार्वजनिक संस्था (Public Society) के रूप में पंजीकृत (Registered) होंगी तथा विभाग अथवा विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त होंगी और निम्न शर्तों को पूरा करेंगी:—

(१) उसके अभिलेख (Records) तथा हिसाब आदि विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण व आडिट के लिये प्रस्तुत रहेंगे।

(२) विभाग द्वारा वांछित समस्त जानकारी समय पर भेज देंगे।

(३) बिना जातिगत या अन्य किसी भेदभाव के उसके द्वारा दी गई सुविधायें नागरिकों के सभी वर्गों के लिये खुली हैं।

(४) संस्था के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति के लाभ के लिये नहीं चलाई जाति हो तथा उसकी व्यवस्थापक समिति पर इस बात के लिये विश्वास किया जा सके कि संस्था की पूंजी केवल उस संस्था के उद्देश्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई जाती है।

टिप्पणी:—सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की आवश्यक जानकारी इस तक के अन्त में दी गई है। शिक्षण संस्थायें यदि महायता अनुदान चाहती हैं तो उन्हें पहले अपने आपको पंजीकृत करवाना पड़ेगा। पंजीकरण के लिये आवश्यक बातें आगे दी गई हैं।

४. उपयुक्त श्रेणी २ (ब) को कोई भी संस्था सहायता अनुदान के लिये तभी ग्राह्य होगी जबकि वह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत एक सार्वजनिक संस्था के रूप में पंजीकृत हो तथा निम्न शर्तों को पूरा करती हो:—

(१) कि वह किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तथा उसके द्वारा दी गई सुविधायें सब लोगों को बिना किसी जातिगत या वर्णगत भेद के प्राप्त होती हो।

(२) कि वह संस्था केवल शैक्षणिक कार्य तक ही सीमित है।

(३) कि संस्था की प्रशासनिक समिति का गठन संचालक द्वारा स्वीकृत है तथा उसकी स्वीकृति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अन्य बातों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि प्रशासनिक समिति असांख्यिक हो और उसके सदस्यों के दो तिहाई से अधिक सदस्य किसी जाति, वर्ग या समाज विशेष के नहीं होंगे।

(४) कि प्रशासनिक समिति द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन शीघ्रतया विभाग को सूचित किया जाता है।

(५) कि वह संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के लाभार्थ नहीं चल रही है और उसकी प्रशासनिक समिति पर उस संस्था की पूंजी का उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किये जाने के लिए विश्वास किया जा सके।

(६) कि शिक्षा का स्तर व अन्य प्रवृत्तियां स्वीकृत स्तर के अनुसार हैं।

(७) कि उसके वित्तीय स्रोत, जब महायता अनुदान मिलकर उन्हें पूरा कर देवे उसे अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिये अथवा उचित पारिश्रमिक देने के लिये, और जहां पर नरकार या अन्य अक्षम अधिकारी द्वारा वेतन श्रृंखलाओं निर्धारित कर दी गई हों, वहां पर उनके अनुसार अपने पूरे समय के लिये रखे गये कर्मचारियों को नियमित रूप से पारिश्रमिक देने के लिये यत्न करना सभ्य होगा।

(८) कि छात्रों की संख्या, औसत उपस्थिति व उस संस्था से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उस स्तर अथवा संस्था से नीचे नहीं रहती है जो कि सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से निर्धारित की गई हो ।

(९) कि विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण व आडिट के लिये उसके अभिलेख व हिसाब आदि प्रस्तुत होंगे ।

(१०) कि विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचना समय पर भेज दी जाती है ।

(११) कि संस्था के कुशल संचालन के लिये विभाग द्वारा जारी किये सब निर्देशों का शीघ्रतया पालन किया जाता है ।

५. उपरोक्त प्रकार की संस्थाओं को प्रतिवर्ष मिलने वाला अनुदान गत वर्ष के स्वीकृत व्यय का ५०% अथवा गत वर्ष के वास्तविक स्वीकृत व्यय का ७५% से सामान्यतया अधिक नहीं होगा । यदि कुल स्वीकृत व्यय के ५०% के अनुसार आने वाली रकम वास्तविक स्वीकृत व्यय के आधार पर गणना की गई धनराशि से अधिक हो, तो दोनों में जो राशि अधिक होगी, वही अनुदान के रूप में मिलेगी । ऐसी संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग अथवा अनुसंधान कर रही हों, विशेषकर बुनियादी या स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिये, अथवा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में यथा दीपयुक्त बच्चों की शिक्षा आदि, उन्हें यह अनुदान स्वीकृत व्यय का ६०% तथा वास्तविक स्वीकृत व्यय का ६०% तक भी दिया जा सकेगा ।

किन्तु इस राज्य से मिलने वाले अनुदान की कुल राशि, संस्था के कुल स्वीकृत व्यय तथा शुल्क व अन्य नियमित स्रोतों, जिनमें अन्य राज्य सरकारों से मिलने वाला अनुदान भी सम्मिलित है, से होने वाली आय के अन्तर से अधिक होगी ।

उस संस्था को उसके बार बार होने वाले व्यय (Recurring Expenditure) के लिये केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों से एक मुस्त (Lump Sum) मिला हुआ अनुदान भी इस प्रावधान के लिये बार बार मिलने वाला अनुदान ही समझा जावेगा ।

नोट:—(१) वास्तविक स्वीकृत व्यय से तात्पर्य होगा उस व्यय से जो कि कुल स्वीकृत व्यय में शुल्क तथा अन्य नियमित स्रोतों (जैसे कि क्लबों की सदस्यता शुल्क) किन्तु जिसमें केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों से मिलने वाले अनुदान तथा दान-राशि (Donation) सम्मिलित नहीं होगी, से प्राप्त आय को घटाने पर आता हो ।

(२) गत वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष जिसमें अनुदान का भुगतान किया गया हो, के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से है । उदाहरण के लिये अप्रैल ५५ से मार्च १९५६ तक के वर्ष का अनुदान अप्रैल १९५४ से मार्च १९५५ वाले वर्ष के व्यय के आधार पर निश्चित किया जावेगा ।

६. नियम ५ में वर्णित स्वीकृत व्यय केवल निम्न पदों से ही सम्बन्धित हो सकेगा:—

(क) वेतन तथा भविष्य निधि का अंशदान (Contribution) जो कि अध्यापक वर्ग के सम्बन्ध में ६.३% से अधिक नहीं होगा ।

(ख) लेखक वर्ग व सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि का अंशदान जो कि ६.३% से अधिक नहीं होगा, तथा उनका वेतन ।

(ग) मंहगाई भत्ता

(घ) स्टेशनैरी तथा छपाई खर्च

(च) जल व विद्युत खर्च

(छ) ग्रीष्म तथा शरद ऋतु के लिए विशेष व्यय

(ज) प्रयोग-यन्त्रों तथा अन्य साधनों की खरीद के लिए बार बार होने वाला व्यय :

(झ) भवनों (यदि वे संस्था के हों) तथा फर्नीचर की साधारण मरम्मत

(ट) मकान किराया (यदि भवन किराये पर हों)

(ठ) सनिवास संस्था (Residential Institutions) या शैक्षणिक समितियों जो कि एक से अधिक संस्थाओं का संचालन करती हैं, के मामले में प्रबंध पर आने वाला ऐसा खर्च, जो कि उम संस्था या समिति के लिए आवश्यक हो।

(ड) पुस्तको, पुस्तकालय, व वाचनालय पर बार बार होने वाला खर्च।

(ढ) खेलकूद, शारीरिक शिक्षा व अन्य शैक्षणिक प्रवृत्तियों यथा वेम्पस, वार्षिक उत्सव, नाटक, शैक्षणिक यात्राएँ, आनन्द-प्रमोद, समाज सेवा, कार्यक्रम आदि आदि पर बार बार होने वाला खर्च।

(त) शिल्प (Craft) जिनमे कृषि, डेयरी, गृह विज्ञान आदि सम्मिलित हैं, से होनेवाली आय को निकाल कर उस पर आने वाला खर्च।

(व) सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाने वाले अध्यापकों का यात्रा व्यय। संचालक द्वारा सरकार की स्वीकृति से इस सम्बन्ध में निर्धारित दरों के अनुसार ही मार्ग व्यय दिया जावेगा।

७. यद्यपि वार्षिक-सहायता-अनुदान विगत वित्तीय वर्षों के स्वीकृत व्यय के आधार पर ही सामान्य तथा निर्धारित किया जावेगा, फिर भी चालू वर्ष के किसी विशिष्ट स्वीकृत व्यय के आधार पर यदि स्वीकृति कर्त्ता-अधिकारी चाहे तो कोई अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा सकता है।

८. कोई भी नई संस्था सहायता-अनुदान के लिए तब तक उपयुक्त नहीं मानी जावेगी जब तक कि उसने सफलतापूर्वक एक वर्ष तक कार्य न कर लिया हो। बहुत ही विशेष मामलों में सरकार द्वारा यह शर्त हटाई जा सकती है।

९. छात्रावास पर होने वाले व्यय किसी संस्था के स्वीकृत व्यय में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। गत वर्ष के स्वीकृत व्यय के ६०% तक का प्रति वर्ष दिया जाने वाला अनुदान, निम्न खर्चों पर स्वीकार किया जा सकता है:—

(१) छात्रावास अधीक्षक या मैट्रन, जो भी होवे, का वेतन या भत्ता।

(२) लेखक वर्ग अथवा चर्च श्रेणी कर्मचारी जो कि आवश्यक होवे।

(३) अन्य सामान कार्यालयीय आकस्मिक व्यय।

१०. प्रति वर्ष नहीं दिया जाने वाला अनुदान ऐसे खर्च के लिए दिया जा सकता है यथा फर्नीचर की खरीद, पुस्तक, पुस्तकालय व प्रयोगशाला के सामान की खरीद, निर्माण, भवन की मरम्मत व विस्तार (छात्रावास का भी) आदि आदि। विशेष अनुदानों की निश्चित धन राशि तो प्रत्येक मामले की उपयोगिता को दृष्टिगत रख कर ही निर्धारित की जावेगी किन्तु किसी भी स्थिति में वह रकम उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत व्यय के आधे से अधिक नहीं होंगी। कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़ कर ऐसे अनुदान स्वीकृत नहीं किये जायेंगे यदि अनुदान स्वीकृत होने और नकशे तथा अनुमा-

नित्य व्यय के संस्कारों द्वारा स्वीकृत होने से पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो, अथवा खेरीद कर ली गई हों ।

११. कोई भी संस्था सहायक अनुदान या किसी वित्तीय वर्ष के लिये विशेष अनुदान चाहने हेतु संचालक को अथवा सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को, जैसी भी स्थिति हो प्रार्थना पत्र देगी । प्रति वर्ष दिये जाने वाले तथा एक ही बार दिये जाने वाले अनुदानों के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर पृथक पृथक प्रार्थना पत्र दिये जावेगे । समस्त प्रार्थना पत्र, जिस वित्तीय वर्ष के लिए सहायक अनुदान चाहा गया हो उसके प्रारम्भ होने से पूर्व आने वाले अगस्त मास के अन्त तक दे दिये जाने चाहिये; उनके साथ निम्न विवरण—पत्र भी आने चाहिये:—

(१) विगत ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का जांच शुदा लेखा (Audited Accounts)

(२) उस वित्तीय वर्ष, जिसमें प्रार्थनापत्र दिया जाता है, के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई) का वास्तविक खर्च और बाद के आठ माह (अगस्त से मार्च) का अनुमानित व्यय बतलाने वाला विवरण पत्र । विवरण पत्र में बार बार होने वाले तथा एक ही बार होने वाले खर्च अलग अलग बताये जायेगे ।

सहायता अनुदान अथवा विशेष अनुदान, जो कि किसी संस्था को उसके आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया जावेगा, कि अस्थाई तौर पर उपर्युक्त नं० २ के विवरण पत्र के आधार पर ही, गणना की जावेगी । जब नं० २ का जांच शुदा लेखा अगले वर्ष प्रेषित किया जावेगा, और उपर्युक्त नं० २ में वर्णित अनुमानित व्यय व जांच शुदा लेख में यदि कोई अन्त होगा तो आवश्यक समायोजन (Adjustment) कर लिया जावेगा ।

१२. यदि कोई संस्था समाप्त हो जाती है अथवा उपरोक्त नियम ३० व ४ में वर्णित शर्तें पूरी करना बंद कर देती है, तो स्वीकृत कर्ता अधिकारी के निर्देशन अनुदान रोक, कम किया अथवा बन्द किया जा सकता है लेकिन इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व उस संस्था के व्यवस्थापकों को, वे सब कारण लिख कर दिये जाने चाहिए, जिनके कि आधार पर कार्यवाही किये जाने का विचार किया जा रहा है । उनको उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उत्तर देने का अवसर देना चाहिये व्यवस्थापक यदि चाहे तो अनुदान को रोकने, कम करने अथवा बन्द किए जाने के आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकेंगे ।

१३. प्रति वर्ष दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि हेतु, नई संस्थाओं को प्रति वर्ष दिये जाने वाले अनुदान के लिए दिए गए समस्त प्रार्थनापत्रों पर विचार एवं अनुशंसा (Recommendation) निम्नानुसार गठित एक समिति के द्वारा किया जावेगा:—

१. शिक्षा संचालक

२. सम्बन्धित श्रेणी का उप शिक्षा संचालक

३. सरकार द्वारा मनोनीत, या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक आचार्य (Principal)

४. गैर सरकारी तीन प्रमुख शिक्षा शास्त्री

५. वित्त विभाग का एक मनोनीत प्रतिनिधि

१४. जो संस्थाएँ वर्तमान में सहायता अनुदान पा रही हैं, उनकी इन नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष दिये जाने वाले सहायता अनुदान स्वीकृत करने तथा उनके खर्च को अनुमोदन करने का

अधिकार, स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सम्बन्ध में सरकार तथा अन्य संस्थाओं के लिये संचालक के पार हैं। नई संस्थाओं को वार्षिक अथवा थोक में दिये जाने वाले अनुदानों को वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता है।

अध्याय १८

भवन एवं फर्नीचर

नोट:—नियम १ से ६ तक एवं ९ से १५ तक केवल राजकीय प्रबन्ध के सामान्य अधीन संस्थाओं पर ही लागू होंगे।

१. जहाँ तक सम्भव हो सभी भवन विभागीय पद्धति योजना के अनुसार बनाने चाहिए। ये योजनाएँ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा विशेष शालाओं, महा विद्यालयों छात्रालय आदि की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तैयार की जायेंगी। जहाँ तक सम्भव हो इन योजनाओं के क्षेत्र में आचार्य या प्रधानाध्यापक तथा अन्य स्टाफ के निवास भवन भी सम्मिलित करना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सलाह से ऐसी योजनाओं का संचालक अपने नियन्त्रण में लेगा।

२. राजकीय भवनों का निर्माण एवं सुरक्षा का भार सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) को सौंपा गया है।

३. शिक्षण संस्थाओं के भवन के निर्माण के लिये, जो कि राज्य द्वारा बनाये जा रहे हैं, आवश्यक निधि निम्न वितरणों (Allotment) द्वारा दी जाती है:—

(अ) शिक्षात्मक भवनों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के नियन्त्रण के अधीन वितरण।

(ब) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियन्त्रित वार्षिक सुरक्षा भार के लिये वितरण।

(स) विभागीय वजट में किये गये लघु निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का विवरण।

४. प्राथमिक माध्यमिक तथा प्रशिक्षण एवं उच्च विद्यालयों के वर्तमान भवनों की मरम्मत के लिए एवं उनके लिये नये भवन बनाने की मांग सम्बन्धित शिक्षा विभाग के द्वारा तथा कालेज भवनों के बारे में संस्थाओं के अध्यक्षों के द्वारा संचालक के पास ऐसे समय पर प्रस्तुत की जायेंगी जो कि आगामी वर्ष के वित्तीय वजट में खर्च के नये मद प्रस्तुत करने के तिथि चक्र के अनुसार हो।

५. संचालक ठीक समय में इन्हें वजट में शामिल करने पर निर्णय करेगा कि कौन से नये भवनों का निर्माण करना है तथा किन २ वर्तमान भवनों की मरम्मत एवं विस्तार करना है तथा ऐसे नये निर्माण कार्यों एवं विस्तार कार्यों की एक सूची वह मुख्य अभियन्ता (चीफ इन्जिनियर) के पास भेजेगा जो कि योजनाएँ तैयार करेगा एवं संचालक की सहमति से अनुमानित व्यय निर्धारित करेगा एवं उसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजेगा।

६. प्रस्तावित भवनों एवं चाहे गये सामान्य स्थानों की शिक्षात्मक, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता सम्बन्धी आवश्यकताओं के विषय में संचालक, मुख्य अभियन्ता को सूचना देगा।

७. (अ) निर्माण स्थल को चुनने में काफी समय लगता है इस वास्तव्य उचित स्थानों को फिर भी ध्यान में रखना चाहिये चाहे निकट भविष्य में उस में कोई भवन नहीं बनाना हो।

(ब) प्राथमिक शालाओं का निर्माण स्थान निरीक्षक शिक्षणायय द्वारा चुना जायेगा। उच्च-तर शालाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं और इंटर कालेजों के भवनों के निर्माण स्थानों के लिए संचालक की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है तथा स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के भवनों के लिए सचिव, शिक्षाविभाग, राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

८. शालाओं के भवनों के स्थान चुनते समय माता पिताओं के भवनों की समीपता, सुविधा कम खर्च आदि को दृष्टिगत रखने की अपेक्षा निम्न बातों पर बल दिया जाना चाहिये:—

(अ) शाला भवन के लिए ऐसी जमीन नहीं चुननी चाहिए जो प्रकृति से ही नीचे खड्डे में हो या बड़े पेड़ों एवं मकानों के पास में हो क्योंकि वहां मकान बनाने पर स्वच्छ हवा न मिल सकेगी तथा शाला में खूब सूर्य का प्रकाश न पहुंच सकेगा।

(आ) जहां तक सम्भव हो आर्द्रता पूर्ण भूमि में भवन निर्माण नहीं करना चाहिए।

(इ) बस्ती स्वस्थ हो तथा पड़ोस माननीय हो।

(ई) पर्याप्त स्थान का होना आवश्यक है। उसमें खेल के मैदान की जगह होनी चाहिए एवं सम्भावित विस्तार के साथ शाला में एक बगीचे की भी जगह होनी चाहिए। कक्षा कक्षों की बनावट का उचित ध्यान रखना चाहिए।

(उ) नियमानुसार भवन जगह के बीचोबीच नहीं बनाना चाहिए।

(ऊ) नाले एवं तालाब पड़ोस में नहीं होने चाहिए।

(ए) तालाबी वनस्पति का उपस्थित होना आपत्तिजनक है।

(ऐ) धूलमय एवं शोरगुल वाली सड़कों तथा दुकानों या कारखानों के समीप भवनों का बनाना जहां तक सम्भव हो सके, टालना चाहिए।

(ओ) ग्राम शाला भवन, जहां कहीं सम्भव हो, गांव के बाहर बनाना चाहिए।

९. निर्माण कार्य के सभी नकशों में चारों ओर के पास पड़ोस की प्रकृति तथा पड़ोस के भवनों की ऊंचाई उत्तर दिशा तथा बहने वाली हवा की दिशा आदि सभी बातों को दिखाना चाहिए।

नोट:—शाला-भवनों के निर्माण में स्वास्थ्य सुविधायें, प्रकाश व हवा के साधनों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

टिप्पणी:—कहने का तात्पर्य यह है कि शाला भवन का स्थान ऐसा हो जो शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का वातावरण पैदा करे। खुली जगह, शोर गुल से दूर व सूरज की रोशनी शाला भवन के स्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

१०—योजना:—स्कूल भवन बनाने समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

दिशा (Orientation) (अ):—राज्य में विभिन्न स्थानों में शाला भवन बनाने की दिशायें विभिन्न हैं तथा प्रमुख रूप से हवा के आगमन को दृष्टि में रखते हुए उनका निर्माण किया जायेगा। इस आधार पर भवनों का नियमानुसार मुंह उत्तर या दक्षिण की ओर होना चाहिए तथा दक्षिण की ओर एक बरामदा होना चाहिए। ऐसे मामले में उत्तर की ओर बरामदे की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है लेकिन उत्तर शालाओं में पूर्व एवं पश्चिम की ओर बरामदों का होना वांछनीय है।

(घ) प्रकाशः—प्रकाश उत्तर की तरफ से आना चाहिए एवं जहाँ तक सम्भव हो उस तरफ कोई वरामद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रकाश पहुँचाने के लिए दरवाजे व खिड़कियाँ बनानी चाहिए जोकि कुल कमरे के घरातल क्षेत्र के १।५ क्षेत्र से कम न होने चाहिए। मुख्य प्रकाश छात्रों के बाईं तरफ से होकर आना चाहिए। छात्रों के विलकुल सामने या पीछे कोई बड़ी खिड़कियाँ नहीं होने चाहिए। कमरे का भीतरी भाग प्रांगण तक सफेदी किया हुआ होना चाहिए, तथा ३,४ फीट की ऊँचाई तक रंगा हुआ होना चाहिए। मुख्यतया यह रंग काला या गहरा भूरा होना चाहिए।

(स) रोशनदान—यदि सम्भव हो तो, कक्षा के कमरे को एक पंक्ति में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ होना चाहिए। यदि कमरे की ऊँचाई तक की खिड़कियाँ न हो तथा वे खोली न जाने वाली हो तो दीवार की चोटी के पास रोशनदानों का होना आवश्यक है। ये रोशनदान भी खिड़कियों के समान ढंग से नियमित रूप में बंटे हुए होने चाहिए। शुद्ध हवा के अशोधित रूप से प्रवेश करने के लिये रोशनदानों का कम से कम क्षेत्रफल प्रत्येक छात्र के लिए ४८ वर्ग इंच के हिसाब से कम न होना चाहिए किन्तु इसमें दरवाजे एवं खिड़कियों का क्षेत्रफल शामिल न किया जाये।

(द) खिड़कियाँ—खिड़कियाँ दो कार्य करती हैं, प्रकाश आने देती है तथा हवा भी आने देती हैं। ये नियमित फासले पर होनी चाहिये जिससे प्रकाश अच्छे ढंग से आ सके। खिड़कियों का दासा उन कमरों में जमीन से ४ फीट से ऊँचा न होना चाहिये जिनमें छात्र कुर्सियों पर बैठते हैं। जब छात्र जमीन पर बैठते हैं तो ये दासे जमीन से २।१ या ३ फीट के बीच में होने चाहिए।

(ध) कक्षा कक्ष—कक्षा के कमरों की शलाघें एक भाग से दूसरे भाग को जाने के लिए रास्ते के काम में नहीं लेना चाहिये। वे एक दूसरे कमरे में न खुलकर वरामदों या रास्ते में खुलने चाहिये। कमरों के दरवाजे अध्यापक के पास में से होने चाहिये।

(फ) प्राथमिक शालाओं में छात्रों के लिए कम से कम १० वर्ग फीट जगह होनी चाहिए तथा उच्चतर पाठशालाओं की दशा में कम से कम १२ वर्ग फीट होनी चाहिए। कमरों की ऊँचाई कम से कम १३ फीट होनी चाहिए। चित्रकला भूगोल तथा प्रयोगशाला के कमरे उनमें किये जाने वाले कार्य तथा बैठने वाले छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उचित रीति से सावन् सम्पन्न तथा सावधानी से बने हुए होने चाहिए।

(ग) साधारणतया कक्षाएँ लम्बे आकार में बनी हुई होनी चाहिये। कमरे के अन्त में अध्यापक के लिए मेज कुर्सी का स्थान ऊँचा होना चाहिये। कमरे का अवशिष्ट भाग जिसमें छात्र बैठते हैं वर्गाकार होना चाहिए क्योंकि यह माना जा चुका है कि अध्ययन कार्य के लिये वर्गाकार क्षेत्र ही श्रेष्ठ होता है।

(ह) अध्यापक के पास ही श्यामपट्ट के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिये। सीमेंट का श्यामपट्ट यदि हो तो अच्छा रहता है क्योंकि वह खूब समय तक चल सकता है। श्यामपट्ट का आकार ४।१×३ फीट होना चाहिये। टांड और आले दीवारों में बनाये जाने चाहिये नक्शों, तस्वीरों तथा चित्रों की दीवार के साज के नीचे लटकाने के लिये आले खुली टांड के साथ होना जरूरी है।

(ई) अन्य कक्षा—कक्षा के कमरों के अलावा उच्चतर एवं प्रशिक्षण शाला भवनो में एक बड़ा कक्ष होना चाहिये जिसमें सारे छात्र इकट्ठे हो सकें, तथा एक पुस्तकालय प्रधानाध्यापक का कक्षा, कार्यालय कक्ष एवं अध्यापकों के लिये एक कक्ष आदि होना चाहिये।

(ज) आंगन व छतें—आंगन ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो सरलता से धोया जा सके । जिन कमरों में ढलवां भेजें व सीटें बैठने के वास्ते हों वहां पत्थर का आंगन होना चाहिए । अगर बच्चों को फर्श पर बैठना पड़े तो वहां का आंगन पत्थर का होना आवश्यक नहीं, किन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उसके सम्बन्ध में ठंडक होने की आपत्ति चटाइयां बिछा कर दूर की जा सकती है । लेकिन चटाइयां पूर्ण साफ होनी चाहिये । जहां तक सम्भव हो छत गर्मों के लिये दूभेंच होनी चाहिये ।

(क) जलकक्ष—एक कमरा पानी के लिए अलग से होना चाहिये । इस कमरे का आंगन ईंट, पत्थर व कंकरीट से बना हुआ होना चाहिये ।

(ल) कुएं—जहां तक सम्भव हो प्रत्येक शाला में जहां १०० से अधिक छात्र हों वहां ईंट या पत्थर का एक कुआं होना चाहिये चाहे वे किसी श्रेणी की शाला हो । कुएं का व्यास ४ फीट होना चाहिए, उसका ऊपरी भाग बना हुआ होना चाहिये ।

(म) स्वास्थ्य सन्बन्धी सुविधायें—किसी भी शाला भवन से ४० फीट से कम नजदीक कोई पाखाना नहीं होना चाहिए । शालायें इस प्रकार बनानी चाहिये कि चलने वाली हवा वहां होकर कमरों में प्रवेश न करे । पाखाने छात्रों की संख्या के २ प्रतिशत व पेशाब घर ४ प्रतिशत के हिसाब से बनाना चाहिये । ग्रन्थापकों के लिए पाखाने व पेशाब घर अलग होने चाहिए । ग्रामशालाओं में साधारण पाखाने आवश्यक रूप से होने चाहिए ।

११—(घ) फर्नीचर इस तरह का बना हुआ होना चाहिए जिससे छात्रों के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े । सीटें ऐसी होनी चाहिए कि छात्र सीधे बैठकर लिख सकें तथा रीढ़ की हड्डी पर जोर न पड़े । पढते समय पीछे आगे झुक सके । उठते बैठते समय गलत ढंग नहीं अपनाना चाहिए । पुस्तकें एवं कागज उनकी आंखों के सामने सुविधाजनक फासले पर स्थित रहना चाहिए ।

(ङ) निम्नलिखित कक्षाओं के लिए निम्न फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(१) कक्षा १ से ५ तक के छात्र के लिए टाट पट्टियां एवं नीची भेजें होनी चाहिये ।

(२) कक्षा ६ से १० तक नीची भेजें एवं सीटें । प्राथमिक शालाओं में कोई फर्नीचर होना आवश्यक नहीं है तथा वैसे उस समय तक नहीं दी जानी चाहिये ।

जब तक उनके साथ डेस्क न हो । समाप्तान्तर पंक्तियों में लगाई जानी चाहिये तथा शेष दायें कोनों में होनी चाहिये ।

(स) डेस्क एवं सीटों की शाखाओं में लगाने के उपाय आदि के सम्बन्ध में निम्न नाप को अपनाना चाहिये—

नाप इंचों में	सीटें		
	छोटी	मध्यम	बड़ी
(१). जमीन से सीट के ऊपरी तल्ले की दूरी	१३	१५	१७
(२) सीट के तल्ले की चौड़ाई	१०	११	१३
(३) प्रत्येक छात्र के लिए सीट की कम से कम लम्बाई—	१८	१९	२०

(४) सीट के ऊपरी तख्ते से पिछली सीट के ऊपरी तख्ते तक की ऊपर से नीचे तक की दूरी	१०	११	१२
(५) पिछली सीट की ढलाई	१	१	१
(६) फर्श से डेस्क के सामने किनारे तक की दूरी	१२	२५	२८
(७) डेस्क के सामने किनारे एवं सीट के सामने किनारे के बीच की आड़ी तौर पर नापी गई दूरी	३	३½	४
(८) डेस्क की चौटी की चौड़ाई (टेढ़ा भाग)	१२	१३	१४
(९) उच्च डेस्क की चौड़ाई (समतल भाग)	३	३	३
(१०) सामने में पीछे की ओर ढलवां	१	१½	२
(११) प्रत्येक छात्र के लिए डेस्क की कम से कम लम्बाई	१८	१९	२०
(१२) पुस्तकों के खाने की गहराई	१०	१०	१०
(१३) पुस्तकों के खाने एवं डेस्क की चौटी का अन्तर	५		५

छात्रवास का भवन

वासस्थान (Accommodation)

१२. (अ) शालाओं के छात्रावासों में सभी लड़कों के लिए छोटे कक्षों की अपेक्षा बड़े कम बनाना चाहिए । बड़े कमरों के अभाव में छोटे कमरे, ३, ५ या ७ तक छात्रों को दिए जा सकते हैं, तथा किसी भी दशा में एक या दो छात्रों के लिए अलग कमरे नहीं दिए जाने चाहिये । समान उम्र वाले छात्र एक ही कमरे में रहें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

(ब) आंगन का हिस्सा निम्नानुसार प्रत्येक छात्र को दिया जाना चाहिए ।

(१) बड़े कमरों में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम ५० वर्ग फीट ।

(२) एक छात्र वाले कमरे में कम से कम ६६ वर्ग फीट ।

(३) ३ से ४ तक छात्रों वाले कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम ६५ वर्ग फीट ।

(४) ५ या ५ से अधिक छात्रों वाले कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम ६० वर्ग फीट ।

(स) प्रत्येक कमरे में जो भोजन करने के काम में लिया जावे या सोने के अतिरिक्त किसी अन्य तरह से रहने के कार्यों में लिया जावे, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए ८ सुपरफीशियल फीट या ८० घन फीट जगह होनी चाहिये ।

(द) प्रत्येक छात्रावास में उचित आकार का एक सामान्य कक्ष होना चाहिए जिसमें छात्र भोजन कर सकें—रोशनदान एवं खिड़कियाँ शाला भवन की तरह ही होनी चाहिए ।

(य) छात्रालय या उसके पास छात्रालय अधीक्षक का उचित निवास स्थान होना चाहिए ।

(फ) छात्रालय बस्ती ही में होना चाहिए तथा दर्शकों के आगमन तथा छात्रों के किसी भी समय बाहर जाने के लिए बन्द रहेगा ।

१३. फर्नीचर—हर एक छात्र के लिए एक खाट, मेज, कुर्सी, पुस्तकें रखने की आलमारी व कपड़े लटकाने की खूटियाँ आदि होनी चाहिये । उसको अपने स्वयं की मच्छरदानी रखनी होगी सम्भव हो तो एक अच्छे लैम्प की भी व्यवस्था होनी चाहिए चाहे एक-एक लैम्प हर छात्र को या बड़ा लैम्प पूरे कमरे के लिए । एक घड़ी या घंटाल छात्रों को बुलाने के लिए दिया जाना चाहिये ।

१४. अस्पताल—एक भली प्रकार से स्थित एवं रोशनीदार, खिड़कियों से युक्त कमरा बीमार कक्ष के रूप में प्रत्येक छात्रालय में सुरक्षित रहना चाहिए तथा इसी प्रकार का एक कमरा सजाया हुआ चिकित्सा अधिकारी के लिए सुरक्षित रहना चाहिए । यह सलाह देने योग्य है कि बीमार कक्ष वरामदे के अन्त में या भवनों की कतार में आखिरी होवे ।

जल वितरण—जब कभी सम्भव हो सभी कुश्रों पर, ढक्कन होने चाहिए जो केवल मरम्मत के समय ही हटाया जाय तथा उसमें एक मजबूत पम्प लगाना चाहिए जिससे जल ऊपर होज में झकड़ा किया जा सके तथा नल द्वारा रसोई व स्नान गृह में पहुँचाया जा सके । स्नान के स्थान पर जब कभी जल वितरण एवं नालियों के प्रबन्ध की व्यवस्था, इसके होने की व्यवस्था हो जाय, तो छात्रों के १० प्रतिशत के हिसाब से ढूँटियों वाला एक होज बनवाना चाहिए तथा प्रति छात्र के हिसाब से उसमें ४ गैलन पानी आना चाहिए ।

१६. छात्रालय की दशा को ठीक रखने के लिए स्नान गृह, रसोई, भोजनालय आदि से गन्दे खराब पानी को दूर ले जाने के लिए एक पक्की नाली होनी चाहिए—वे नगरपालिका द्वारा बनाई गई या बड़ी पक्की नालियों में मिलानी चाहिए या खण्डे से जिसका कि पैदा पक्का न बनाया गया हो और जो समय समय पर साफ किया जा सके ।

१७. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें—कम से कम ३ प्रतिशत के हिसाब से पेशाब गृह एवं ८ प्रतिशत के हिसाब से पाखाने बनाकर छात्रालयों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए । जहाँतक हो पाखानें रसोई व भोजनालयों से दूर सोना चाहिए । नल के लिए एक ढक्का हुआ बर्तन होना चाहिए । कूड़े का कट व झूँटन के लिए एक अलग बर्तन होना चाहिए । छात्रालय इस तरह का होना चाहिए कि रात्रि में ताला लगाने पर पाखाने उसी भवन में रहें ।

१८. जहाँ तक सम्भव हो स्कूल, छात्रालय तथा खेल के मैदान सब एक ही साथ होने चाहिए ।

१९. विभिन्न श्रेणियों की राजकीय संस्थाओं के नए निर्माण के लिए प्रयोग रूप में निम्न क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं ।

(१) प्राथमिक शाला	२ एकड़
(२) माध्यमिक शाला	५ एकड़
(३) उच्च विद्यालय	१० एकड़
(४) इंटर कालेज	१५ एकड़
(५) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय	२० एकड़

२०. दान—शिक्षण संस्थाओं के निर्माण के लिए व्यक्तियों, संघ तथा स्थानीय संस्थाओं से दान प्राप्त करने की रीति को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा ये दान विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकृत किये जायेंगे। नियमानुसार कोई भी संस्था जो सरकार की ओर से स्थापित की गई है किसी व्यक्तिगत या धार्मिक उपाधि के नाम से नहीं पुकारी जायेगी—लेकिन बहुत बिरले मामलों में सरकार द्वारा कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा भी किया जा सकता है।

२१. मरम्मत—राजकीय भवनों की सालाना मरम्मत साधारणतया सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। मरम्मत एवं सुरक्षा की आवश्यकता की मांग स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी से की जानी चाहिए।

२२. यदि कुछ पेड़ फसल उत्पन्न करने वाले हो तो कार्यालय या संस्था के प्रधान द्वारा उस फसल को इकट्ठी करने का ठेका किसी एक व्यक्ति को दे दिया जावे और धनराशि को खजाने में जमा करा देगा।

२३. छात्रों से श्रमदान के रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि 'विद्यार्थी निधि' में जमा होनी चाहिए तथा संस्था के प्रधान के निर्णयानुसार उनके लाभार्थ उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

२४. छात्रालयों के अधीक्षक जो राजकीय संस्थाओं के साथ संलग्न हैं, वे निशुल्क मकान या भूदा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

२५. निवास की सुविधा—शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी शिक्षण संस्था के किसी एक भाग में केवल सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके तथा प्रभावशील नियमों के अनुसार सामान्य किराया जमा कराके रह सकता है ऐसी स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जावेगी जब तक कि ऐसा चाहा गया हिस्सा संस्था एवं कार्यालय के कार्य में बिना बाधा उपस्थित किए खाली नहीं किया जा सके।

नोट:—छात्रावास के भवन निर्माण में भी उन्हीं मुख्य सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए जिनका कि विद्यालय के भवन निर्माण में किया जाता है।

अध्याय १६

व्यक्तिगत अध्ययन तथा अन्य वृत्तियाँ

अध्यापकों को व्यक्तिगत अध्ययन तथा अन्य वृत्तियों को करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं:—

१. साधारण तौर से छात्रों को व्यक्तिगत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए विभाग की नीति यह है कि व्यक्तिगत अध्ययन की प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। निरीक्षण अधिकारी तथा संस्था प्रधान दोनों को यथावृत्ति इस प्रथा को रोकना चाहिए।

२. शिक्षण संस्था में नियुक्त अध्यापक को कोई व्यक्तिगत अध्ययन या व्यक्तिगत अलग कार्य नहीं करना चाहिये जब तक कि सक्षम अधिकारी की वे लिखित स्वीकृति प्राप्त न कर लें। इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रवन्धाधीन या राजकीय संस्थाओं में लगे हुये अध्यापकों को भी ऐसा ही करना चाहिए।

नोट:—किसी भी छात्र की अध्ययन करते समय स्वीकृति प्राप्त करना अति अनिवार्य है चाहे विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी है या नहीं।

३. (अ) अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाये जाने वाले छात्र की प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति केवल विशेष कारणों के कारण ही दी जानी चाहिए, जिनको अभिलेखित भी किया जाना चाहिये।

(ब) ऐच्छिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपने द्वारा पढ़ाये जाने वाले छात्र की भी व्यक्तिगत ट्यूशन करने की स्वीकृति यदि इस विषय में अन्य अध्यापकों की उपलब्ध होना सम्भव न हो तो दी जा सकती है।

(स) महाविद्यालयों के आचार्य, उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं छात्रालयों के अधीक्षक (जो २० रु० या इससे अधिक छात्रालय भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हों) जो महाविद्यालय या विद्यालय से संलग्न हो तथा वे अध्यापक जिनको सार्वजनिक परीक्षा में प्रवेश होने की स्वीकृति दी गई हो (उस वर्ष के लिए जिस वर्ष वे परीक्षा में प्रविष्ट होंगे) उनको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत ट्यूशन करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(द) परिशिष्ट १६ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ट्यूशन करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए।

(य) महाविद्यालयों में एक तथा शालाओं में दो व्यक्तिगत ट्यूशन करने के अतिरिक्त अधिक ट्यूशन करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। ट्यूशन का कुल समय महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा ११ घंटा एवं शालाओं के अध्यापकों द्वारा २ घंटा से किसी भी हालत में अधिक नहीं दिया जायेगा।

(फ) महाविद्यालयों एवं उच्च विद्यालय के छात्रों की ट्यूशन संख्या २ से अधिक न होगी तथा माध्यमिक कक्षाओं में तीन एवं निम्न श्रेणी की कक्षाओं में ४ से अधिक न होगी।

४. उपरोक्त नियमानुसार व्यक्तिगत प्रवन्धाधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान, प्राप्राना-पत्रों पर स्वीकृति देने हेतु विचार करेंगे।

५. किसी भी अध्यापक को व्यक्तिगत ट्यूशन करने से या व्यक्तिगत व्यक्त्याय करने से मना किया जा सकता है यदि उसने ऐसा करने से शाला के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती ही या यहाँ तक कि घर पर पाठ तैयार करने पंजिकायें निरीक्षण करने एवं सामूहिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने में कोई बाधा उत्पन्न होती हो।

६. राजकीय प्रवन्धाधीन संस्थाओं में व्यक्तिगत ट्यूशन करने की अनुमति देने वाले अधिकारी निम्न प्रकार से होंगे:—

पद	स्वीकृति प्रदानकर्ता
(१) व्याख्याता एवं प्राध्यापक, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय	संस्थाप्रधान
(२) इन्टरमीडियेट विद्यालय के व्याख्याता व अध्यापक	संस्था प्रधान
(३) उच्च विद्यालय के अध्यापक	निरीक्षक, शिक्षणालय

नोट:—सरकार ट्यूशन प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में है क्योंकि इससे शिक्षण स्तर अवरोद्ध होता है।

अध्याय २०

सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति

अध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों तथा लेखक वर्ग को सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान करने के नियम—

विभाग के अध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों तथा लेखक वर्ग को सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित नियम हैं:—

१. सम्बन्धित संस्था प्रधान की अनुशंसा (Recommendation) पर अध्यापकी को सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की प्रतिवर्ष अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उस परीक्षा जिसमें बैठने के लिए अनुमति चाही जा रही है, में सफल हो जाने पर विभागीय कर्तव्यों के पालन करने में वह अधिक कुशल हो जाता हो।

२. किसी भी अध्यापक तथा निरीक्षण अधिकारी को एल० एल० बी० परीक्षा में बैठने की अथवा कानून की कोई अन्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

३. (अ) परीक्षाओं में किसी संस्था के कर्मचारियों में से २० प्रतिशत से अधिक को बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ब) जिस संस्था में अध्यापकों की संस्था २ से अधिक व पांच से कम हैं, वहां केवल एक अध्यापक को ही बैठने की अनुमति दी जावेगी।

(स) जहां तक एक अध्यापक वाली शालाओं का प्रश्न है, एक निरीक्षणालय के अन्तर्गत आने वाली समस्त शालाओं के कुल अध्यापकों के अधिकतम तौर पर २०% को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी।

४. उपरोक्त अनुमति ऐसे अध्यापक को ही दी जावे जिसका कि कार्य एवं आचरण पूर्णतया सन्तोषजनक रहे, और अनुमति देने में उनको प्राथमिकता दी जावेगी जिनको कि गत सत्र में अनुमति नहीं दी गई हो। इन्टरमीडियेट विद्यालय तथा उच्च विद्यालयों में, उन प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जावेगी जिनके ऐच्छिक विषय संस्था के लिए लाभकर हों। विश्वविद्यालयी उपाधियों तथा एम० ए०, एम० काम०, एम० एस० सी० आदि में जिनमें प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष होते हैं, किसी ऐसे प्रत्याशी को अनुमति अवश्य दी जावेगी जिसने गत वर्ष परीक्षा का पूर्वाधिकार लिया हो बशर्ते कि इस विषय पर अने अन्य नियमों एवं अन्य सब बातों से ऐसा सम्भव हो।

५. परीक्षा के सम्बन्ध में, परीक्षा की अवधि तथा यदि आवश्यक हुआ तो यात्रा दिनों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिल सकेगा यह अवकाश भी प्रायों द्वारा सम्बन्धित परीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाने के बाद, यदि वह छुट्टी पाने का अधिकारी हुआ तो मिलेगा।

६. अनुमति उन स्थायी अध्यापकों को दी जावेगी जिन्होंने २ वर्ष का स्वीकृत व निरन्तर सेवा काल पूरा कर लिया हो।

७. कार्यकारी (Officiating) अस्थाई तथा वे अध्यापक जो कि प्रयोगविधि (Probation) पर हो, को सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु अत्यन्त विशेष

मामलों में व्यक्तिगत तौर पर विचार करके संचालक अनुमति प्रदान कर सकता है, जो कि एक उदाहरण नहीं माना जावेगा।

८. जिन अध्यापकों की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है, वे न तो परीक्षा से पूर्व सत्र में कोई व्यक्तिगत व्यूशन ही करेंगे तथा न वे शैक्षणिक तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपनी रुचि कम करेंगे अथवा उदासीन होंगे।

९. निरीक्षण अधिकारियों तथा लेखक वर्ग को अनुमति संचालक अथवा उनके निकटतम अधिकारी की इच्छा पर ही दी जा सकेगी।

१०. यदि अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारी को संतोष हो जावे कि इन नियमों में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन हो गया है तो वह दी हुई अनुमति वापिस ले सकता है।

११. (१) सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट १०) में दिया जाता चाहिए तथा समुचित मार्ग (Proper channel) के द्वारा प्रतिवर्ष १५ अगस्त तक स्वीकृति देने वाले अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। जहां तक सम्भव होवे, ऐसी अनुमति के आदेश उसी वर्ष के ३१ अगस्त तक जारी हो जाना चाहिये।

(२) संस्था प्रधानों को अपनी संस्था से सम्बन्धित सभी प्रार्थना पत्रों को एक साथ प्रेषित करना चाहिए न कि अलग अलग, साथ में निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट ११) में एक एकत्रित विवरण भी भेजा जाना चाहिए। निरीक्षक शिक्षा विभाग को अपने क्षेत्र के विद्यालयों के ऐसे सब प्रार्थनापत्र जिन पर कि उनके उच्चाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी हो, को उचित प्रपत्र में एक एकत्रित विवरण के साथ प्रेषित करने चाहिये।

१२. संस्था प्रधानों को, अनुमति के लिए दिये गये ऐसे किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी अथवा उनके तात्कालिक अधिकारी के पास भेजते समय अपने आपकी संतुष्ट कर लेना चाहिये कि प्रार्थी इस कोड में दी हुई इस सम्बन्ध की सब शर्तों का पालन करने को तैयार है अथवा नहीं।

१३. परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की दृष्टि से, स्वीकृति: कर्ता अधिकारी निम्ननुसार होंगे:—

- | | |
|---|-----------------|
| (१) स्नातक तथा स्नातकोत्तर
महाविद्यालयों के व्याख्याता
तथा प्राध्यापक | संस्था प्रधान |
| (२) इंटरमीजियेट महाविद्यालय
के अध्यापक, व्याख्याता तथा
आचार्य (Principal) | शिक्षा संचालक |
| (३) प्रशिक्षण तथा उच्चविद्यालयों
के सहायक अध्यापक तथा
प्राध्यापक | उपशिक्षा संचालक |
| (४) निरीक्षण अधिकारी | शिक्षा संचालक |

- (५) माध्यमिक तथा प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक तथा उच्च निरीक्षक, शिक्षा विभाग माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के सहायक अध्यापक

अध्याय २१

राजस्थान द्वारा संचालित संस्थाओं में निम्नलिखित रजिस्टर तथा अभिलेख (Record) रखे जावेंगे:—

१. इन्टरमीजियेट महाविद्यालय और उच्च विद्यालय

(अ) सामान्य:—

- (१) आगन्तुक पुस्तिका (Visitor's Book)
- (२) अध्यापक डायरी
- (३) संस्था प्रधान का पर्यवेक्षण रजिस्टर
- (४) सेवा इतिहास (History of services), सेवा पुस्तिका तथा सर्विस रोल्स

(५) स्टॉक उपस्थिति रजिस्टर

- (६) कार्यालय निर्देश पुस्तिका
- (७) लॉग बुक

(ब) वित्तीय:—

- (१) केश बुक तथा लैजर
- (२) वेतन विलों की प्रतिलिपियां
- (३) कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा कराये गये शुल्क का विवरण रजिस्टर
- (४) सर्विस स्टेम्प के हिसाब की पुस्तक
- (५) शुल्क, वसूली पुस्तिका
- (६) शुल्क मुक्तियों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की फाईल
- (७) मासिक पर्यावर्त फाईल (Monthly Return Files)
- (८) अवकाश रजिस्टर
- (९) छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की फाईल
- (१०) स्टेशनरी रजिस्टर
- (११) छात्र बकाया पुस्तिका
- (१२) विचाराधीन फाईल रजिस्टर

(स) पत्र व्यवहार

- (१) पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण रजिस्टर
- (२) डाक पुस्तिका

- (३) सर्विस स्टेम्प रजिस्टर
- (४) आदेश पुस्तक
- (५) विभागीय गश्तीपत्रों तथा आदेशों की फाइल
- (६) सार्वजनिक परीक्षा फाइल
- (७) पोस्टल पार्सल पुस्तिका
- (८) रेलवे पार्सल पुस्तिका
- (९) निम्न फाइलें

- [१] अध्यापकों की व्यक्तिगत फाइलें
- [२] चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फाइलें
- [३] वेतन चुकारा प्रपत्र (Acquittance Rolls)
- [४] सर्विस स्टेम्प
- [५] वजट फाइलें (प्रत्येक पद के लिये अलग अलग)
- [६] विद्यालय निधि की फाइलें (प्रत्येक निधि के लिए अलग अलग)
- [७] प्रवेश प्रपत्र
- [८] वर्णक्रमानुसार, वापसी प्रार्थनापत्र
- [९] छात्रवृत्तियां
- [१०] भवन
- [११] विभागीय प्रत्यावर्त
- [१२] काल विभाग चक्र
- [१३] वार्षिक प्रतिवेदन
- [१४] वजट
- [१५] परीक्षायें (प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग भाग)
- [१६] पाठ्यक्रम
- [१७] खेल कूद
- [१८] छात्रावास
- [१९] विभागीय आदेश
- [२०] फर्नीचर
- [२१] सह शैक्षणिक प्रवृत्तियां (प्रत्येक प्रवृत्ति के लिये अलग २)
- [२२] छात्र प्रार्थनापत्र
- [२३] खाता विवरण तथा हिसाब प्रत्यावर्त
- [२४] निरीक्षण टिप्पणियां
- [२५] अन्य

(द) विज्ञान, चित्रकला कृषि और शारीरिक शिक्षा

(१) विज्ञान, चित्रकला आदि का स्टॉक तथा इन्वेंटरी रजिस्टर

- [१] नष्ट होने योग्य सामान का
- [२] ऐसा सामान जो नष्ट नहीं हो सकता

(य) (१) स्टॉक रजिस्टर

(फ) पुस्तकालय

- (१) पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर
- (२) नक़्क़े तथा चार्ट्स का रजिस्टर
- (३) उधार देने का रजिस्टर
- (अ) अध्यापकों के लिये
- (ब) छात्र के लिए
- (४) सुझाव पुस्तक
- (५) पुस्तकालय की पुस्तकों का रजिस्टर
- (६) विषयवार रजिस्टर

(व) स्पोर्ट्स:—

- (१) खेलकूद के सामान का जमा-खर्च रजिस्टर

(ह) कक्षावार रजिस्टर तथा समय विभाजक चक्र

- (१) प्रवेश रजिस्टर
- (२) छात्र उपस्थिति रजिस्टर
- (३) छात्र प्रगति पुस्तक (उच्च विद्यालय के लिये)
- (४) परीक्षा परिणाम रजिस्टर
- (५) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र रजिस्टर
- (६) सामान्य समय विभाजक चक्र
- (७) अध्यापकवार समय विभाजक चक्र
- (८) कक्षावार समय विभाजक चक्र
- (९) दण्ड रजिस्टर

२. माध्यमिक विद्यालय

(अ) सामान्य

- (१) आगन्तुक पुस्तिका
- (२) अध्यापक डायरी
- (३) प्रधानाध्यापक-पर्यवेक्षण रजिस्टर
- (४) सेवा-पुस्तिका तथा सविस रोल (उन विद्यालयों के लिये जो कि प्रधान-कार्यालय के सीधे नियंत्रण में हों) ।
- (५) निरीक्षण पुस्तक (लॉग बुक)
- (६) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर

(ब) वित्तीय

- (१) कैश बुक तथा लेंजर
- (२) वेतन-मुगतान प्रपत्र (Acquittance Rolls)
- (३) शुल्क रजिस्टर
- (४) कोषागार तथा उपकोषागार में जमा कराई हुई शुल्क का रजिस्टर

- (५) डाक बुक
- (६) सर्विस स्टैम्प रजिस्टर
- (७) शुल्क-वसूली रजिस्टर
- (८) शुल्क मुक्तियों के लिये प्रार्थनापत्रों का रजिस्टर
- (९) मासिक प्रव्यावर्त-फाईल
- (१०) अवकाश-रजिस्टर
- (११) छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थनापत्रों का रजिस्टर
- (१२) स्टेशनरी-रजिस्टर
- (१३) स्टेशनरी-विवरण रजिस्टर
- (१४) विचाराधीन फाईल रजिस्टर

(स) पत्र-व्यवहार

- (१) पत्र प्राप्ति तथा प्रेषण रजिस्टर
- (२) डाक बुक
- (३) आदेश पुस्तक
- (४) विभागीय आदेश तथा गपती पत्रों की फाईल
- (५) सार्वजनिक परीक्षा फाईल रजिस्टर
- (६) अन्य फाईलें वे सब फाईलें जो कि इन्टरमीजीएट महाविद्यालय तथा उच्च विद्यालय के लिये हैं)

(द) विज्ञान

- (१) वैज्ञानिक वस्तुओं का स्टॉक तथा विवरण रजिस्टर
 - (अ) नष्ट होने योग्य वस्तुयें
 - (ब) जो नष्ट नहीं होवें

(य) फर्नीचर:—

- (१) स्टॉक रजिस्टर

(फ) पुस्तकालय

- (१) पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर
- (२) अध्यापकों को उधार देने का रजिस्टर
- (३) छात्रों को उधार देने का रजिस्टर
- (४) वर्ष में खरीदी हुई पुस्तकों का रजिस्टर
- (५) विषयवार रजिस्टर

(ब) कक्षा-रजिस्टर तथा समय विभाजक चक्र

- (१) प्रवेश रजिस्टर
- (२) छात्र उपस्थिति रजिस्टर
- (३) छात्र प्रगति पुस्तिका
- (४) परीक्षा परिणाम रजिस्टर
- (५) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पुस्तक

- ### ३. प्राथमिकशाला

(१) आगन्तुक पुस्तिका

- (२) प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण रजिस्टर
(३) निरीक्षण (पुस्तक लॉग बुक)

(व) (१) सविन टिफ्टों की डाक बुक

- (३) प्रवक्ता रजिस्टर

(स) पत्र व्यवहार

- (१) पत्र प्राप्त तथा प्रेषण रजिस्टर
- (२) टाक पुस्तिका
- (३) विभागीय आदेश तथा गलती पत्रों की फाइल
- (४) अन्य फाइलें

(द) फर्नीचर

- (१) सामान्य रजिस्टर

(ग) पुस्तकालयः--

- (१) पुस्तकालय रजिस्टर (प्राप्ति पंजीक)
- (२) पुस्तकें उधार देने का रजिस्टर
- (३) विपणन रजिस्टर

(फ) पक्षा रजिटर तथा समय विभाजक चक्र

- (१) प्रवेश-रजिस्टर
- (२) पाठ उपस्थिति रजिस्टर
- (३) पाठ प्रगति पुस्तक
- (४) परीक्षा परिणाम रजिस्टर
- (५) अनुनातरण-प्रमाणपत्र सूचिका
- (६) सामान्य मन्त्र विभागक गृह
- (७) सामान्य कार मन्त्र विभागक गृह
- (८) कक्षागत मन्त्र विभागक गृह

નોંધ - (1) જો: (Accounts) ને વર્ગીકૃત કરવાની સલાહકારતા અને સમર્થન આપનાર સમિતી
વર્ગીકૃત કરવાની જગ્યાએ નોંધ: નો ઉપયોગ ન કરે.

[illegible]

४. छात्रावास

- (१) उपस्थिति रजिस्टर
- (२) प्रवेश रजिस्टर
- (३) केश बुक
- (४) खाता (Ledger)
- (५) स्टाल रजिस्टर
- (६) मेस अकाउन्ट्स बुक (Mess Accounts Book)
- (७) आदेश पुस्तक
- (८) लॉग बुक
- (९) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर
- (१०) स्वास्थ्य अभिलेख पुस्तक (Health Record Book)
- (११) पत्र प्राप्ति तथा प्रेषण रजिस्टर
- (१२) आगन्तुक-पुस्तक
- (१३) विचाराधीन फाईल पुस्तक
- (१४) गश्तीपत्र-पुस्तक
- (१५) अवकाश रजिस्टर
- (१६) निम्न फाईलें

[१] कर्मचारीगण

[२] चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

[३] वेतन भुगतान बिल

[४] लेखा

[५] अन्तर्वासियों (Boarders) का व्यक्तिगत अभिलेख

[६] फर्नोवर

[७] प्रत्यावर्त

[८] वार्षिक प्रतिवेदन

[९] बजट

[१०] स्वीकृतियां

[११] आदेश

[१२] अन्य

प्रगति-पुस्तिका

५. (अ) उच्च, माध्यमिक तथा प्राथमिकशालाओं (कक्षा ३ से ५) के प्रधान सामान्यतया परिशिष्ट २२ के आधार पर छात्रों की प्रगति पुस्तिकाएं रखेंगे।

(ब) समस्त प्रगति पुस्तिकाएं कक्षाध्यापक द्वारा भरी जावेंगी तथा कक्षा में ही रखी जावेंगी।

(स) ये प्रगति पुस्तिकाएं छात्रों के अभिभावकों के पास उनके सूचनार्थ तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु प्रति मास भेजी जावेंगी।

(द) छात्र अपने माता-पिता अथवा अभिभावक से हस्ताक्षर कराकर ये प्रगति पुस्तिकाएँ प्रत्येक मास की १० तारीख से पूर्व अपने कक्षाध्यापक को लौटा देंगे।

(य) प्रत्येक प्रगति पुस्तक पर कक्षाध्यापक तथा संस्था-प्रधान के हस्ताक्षर किये जावेंगे।

(५) जब छात्र अन्तिम रूप से स्कूल छोड़ देंगे तब स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के साथ प्रगति पुस्तिका भी छात्र को दी जावेगी।

रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख रखने के लिए निर्देश

६. आगन्तुक-पुस्तिका (Visitor's Book) इस पुस्तिका में केवल सम्मानित आगन्तुकों को ही अपनी सम्मतियाँ लिखने दी जावे।

७. लॉग बुक (Log Book) संस्था प्रधान को इस पुस्तिका में कक्षाप्रो के अपने निरीक्षण का परिणाम तथा संस्था एवं उसके अध्यापक से सम्बन्धित ऐसे तथ्य, यथा उनके कार्य का प्रारम्भ, सूचनाएँ बीमारी आदि जो कि आगे के लिए आवश्यक हों, अंकित करना चाहिए। इस पुस्तक में एक बार की गई प्रविष्टि हटाई नहीं जा सकेगी और न बदली जा सकेगी। किसी अन्य प्रविष्टि को पूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर प्रस्थापित करके ही उसे बदला जा सकेगा।

८. आदेश-पुस्तक-आदेश पुस्तक में प्रत्येक आदेश की संख्या तथा दिनांक अंकित की जानी चाहिये। संख्या का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाना चाहिए। आदेशों को घुमाना आवश्यक नहीं अपितु उनकी एक प्रति एक ही बार सूचना पट्ट पर लगा दी जानी चाहिए।

९. परिपत्र-पुस्तक-इस पुस्तक में विभाग अथवा विश्वविद्यालय से प्राप्त परिपत्र लगाये जाने चाहिये।

१०. कार्यालय-निर्देश-पुस्तिका—कार्यालय में काम करने वाले लेखक-वर्ग को समय समय पर दिये गये निर्देशों की एक प्रति इस पुस्तक में लगानी चाहिये।

११. सामान्य स्टॉक रजिस्टर—(अ) फर्नीचर की विभिन्न वस्तुओं यथा भेज, कुर्सी, डेस्क आदि को रजिस्टर में अंकित करना चाहिए चूँकि इस प्रकार के सामान की संख्या काफी होती है, अतः उनकी वर्तमान संख्या तथा अगले १० वर्षों में होने वाली वृद्धि के अनुमान के आधार पर रजिस्टर में काफी स्थान छोड़ दिया जाना चाहिये। दूसरी वस्तुएँ जो कि कम संख्या में हों, एक साथ विभिन्न मदों में अंकित कर ली जावे, यथा वागवानी के औजार, काले तरते, रेखागणित के उपकरण खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम का सामान जो कि स्याई तौर पर सुरक्षित रह सके, प्याऊ की आवश्यक वस्तुएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान, प्राथमिक उपचार के स्थायी रहने वाली स्टेशनरी। जो वस्तु ये किसी भी मद में नहीं आती, उनको "विविध" में वर्गीकृत किया जाया चाहिए। फर्नीचर मद तथा उस पृष्ठ संख्या, जिस पर वह सामान रजिस्टर में अंकित हो, की एक सूची, रजिस्टर के प्रारम्भ में दी जानी चाहिए।

(ब) फर्नीचर की प्रत्येक वस्तु उस विद्यालय के नाम के संक्षिप्त अक्षर तथा विशिष्ट संख्या इस प्रकार अंकित की जानी चाहिए कि उसके उपयोग से वे मिटे नहीं।

(स) स्टॉक रजिस्टर में वस्तु का नाम व पूरा विवरण वाले स्तम्भ में सामान का आकार तथा उसकी किस्म अंकित की जानी चाहिए।

प्रधान अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल

में पूरे स्टॉक की जांच की जानी चाहिए तथा ३० अप्रैल तक उसमें पाई जाने वाली कमी-वैशी का प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये ।

(य) जांच के बाद, काम में नहीं आने योग्य, खोये हुये अथवा बेचे जाने योग्य सामान की एक सूची संस्था के प्रधान द्वारा विभाग प्रदत्त प्रपत्र में तैयार की जायेगी तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष उसके अगले निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जायेगी । आवश्यक मरम्मत के बाद जो सामान काम में आने योग्य बन जाये, उसे इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये । काम में नहीं आने वाली वस्तुओं पर, सम्बन्धित सूची में अंकित उनकी संख्या, लिख देनी चाहिए तथा उनको तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि सक्षम अधिकारी से उनको खारिज करने के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते । सामान को बेचना अथवा उसके खो जाने से सम्बन्धित समस्त पत्रादि सूची के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(क) अवशिष्ट सामान को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार में काट देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रत्येक १० वर्ष या लगभग समय के बाद नया स्टॉक रजिस्ट्रार खोला जा सकता है ।

१२. गेम्स रजिस्ट्रार:—(अ) गोल-पोस्ट, पम्प आदि जैसे खेल के सामान जो कि अधिक समय तक चलते हैं, इनकी प्रविष्टि एक सामान्य स्टॉक रजिस्ट्रार में करना चाहिए । गेम्स रजिस्ट्रार में केवल सोल्यूशन, ट्यूब, लेमेज, चाक, बैट, बाल, ग्लेडर आदि सामान जिनको कि वितरण करना या बदलना पड़ता है, की प्रविष्टि की जानी चाहिये ।

(ब) गेम्स रजिस्ट्रार में एक जैसे ट्यूब, चाक जो कि सामान्यतः एक ही प्रकार के हैं आदि वर्णन एक ही पृष्ठ पर किया जाना चाहिये, किन्तु बैट, फुटबाल, कवर, हाकी स्टिक जैसे पदार्थ जिनकी विभिन्न किस्में हैं, की प्रविष्टि भिन्न भिन्न पृष्ठ पर की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, क्रिकेट के बल्ले का एक पृष्ठ पर, बैडमिन्टन के रैकेट का दूसरे पृष्ठ पर तथा हाकी स्टिक का तीसरे पृष्ठ पर, इसी प्रकार सब की भिन्न भिन्न पृष्ठों पर प्रविष्टि होनी चाहिये ।

(स) प्रति वर्ष सभी स्टॉक की एक नवीन सूची बनानी चाहिये । यदि उसी पृष्ठ में स्थान हो तो यह सूची उसी पर तैयार करनी चाहिए अन्यथा फिर दूसरे पृष्ठ पर तैयार की जानी चाहिए ।

(द) विषय के स्तम्भ (Column) में वस्तु का पूर्ण विवरण लिखना चाहिए जैसे क्रिकेट के बल्ले के शीर्षक के अन्तर्गत, “बैलेज, प्रविट्स, इम्पीरियल, खालसा” आदि हर किस्म का हर अलग पंक्ति में वर्णन होना चाहिये ।

(य) एक बार स्टॉक से दिया गया सामान पुनः नहीं जमा करना चाहिए तथा नये सामान में उसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए । यह गेम्स के अध्यक्ष के अधीन रहना चाहिए जब तक कि वह अनुपयोगी दशा में परिणत न हो जाये ।

१३. चित्रकला स्टॉक रजिस्ट्रार:—चित्रकला स्टॉक रजिस्ट्रार में पुस्तक स्लेट, कॉपियां, माडल, रंगाई का सामान, चित्रकला आदि अनिवार्य वस्तुओं का भिन्न २ स्तम्भों में कम से कम प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक किस्म के लिये एक पंक्ति सुरक्षित रखने हुये प्रविष्टि की जानी चाहिए । स्टॉक की जांच प्रतिवर्ष की जानी चाहिए तथा सामान्य स्टॉक की भांति ये अनुपयोगी पदार्थ भी समाप्त किये जाने चाहिये ।

१४. भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र स्टॉक रजिस्ट्रार:—भौतिक शास्त्र एवं रसायन

शास्त्र के स्टॉक रजिस्ट्रों में:—

(अ) स्टॉक बुक में वर्णमाला के क्रमानुसार प्रत्येक वर्ण के लिए एक या दो पृष्ठ सुरक्षित रखते हुए सभी भौतिक एवं रासायन शास्त्र के सामान की प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा सरलता से संदर्भ प्राप्त करने के लिए रजिस्टर में एक विषय सूची लगानी चाहिए।

(ब) समाप्त किये जाने वाले सामान की दशा में वर्ष के अप्रैल माह में आमद एवं खर्च के शेष सामान को खत्म किया जायेगा तथा बचा हुआ माल अग्रिम वर्ष के रजिस्टर में चढ़ा दिया जायेगा लेकिन उपयोग में आने वाले सामान के विषय में यह आवश्यक नहीं है।

(स) लापरवाही या उबासीनता के कारण किसी भी हट-फूट की कीमत वसूल की जानी चाहिए। यदि किसी चीज के टूटने की कीमत २) से अधिक हो जाती है तथा इसे पूर्णतः वसूल नहीं करना हो तो इसकी सूचना ३ दिन के भीतर प्रधान को दे देनी चाहिए।

१५. सभी खातों का सारांश—प्रत्येक माह की ५ तारीख तक यह देखने के लिए खातों की बकाया रोकड़ वही (Cash Book) की बकाया से माह की अन्तिम तारीख को मिलती है या नहीं स्वीकृत प्रपत्र में सभी खातों का एक सारांश तैयार करना चाहिए।

१६. छात्रों की बकाया रजिस्टर—इस रजिस्टर में से जब छात्र का नाम काटा जाये तो उसकी ओर बकाया सभी रकमों का उल्लेख होना चाहिए। ये नाम वर्णमाला के क्रमानुसार लिखे जाने चाहिए तथा पुस्तक के प्रारम्भ से ही प्रत्येक अक्षर के नामों के लिए पुस्तिका में एक या दो पृष्ठ जोड़ देने चाहिए।

१७. छात्र रजिस्टर—(अ) प्रत्येक छात्र, जो कि किसी भी श्रेणी की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश पाता है, के लिए परिशिष्ट न० १६ में निर्धारित प्रपत्र में एक छात्र रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा। छात्र रजिस्टर या तो स्वयं संस्था प्रधान के द्वारा भरा जाना चाहिए या उसके निरीक्षण में किसी अन्य अध्यापक द्वारा भरा जाना चाहिये लेकिन छात्र के चरित्र एवं कार्य के बारे में स्वयं उसको (प्रवास को) लिखना चाहिए।

(ब) छात्रों के प्रविष्टि होने पर उनका प्रवेशांक दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र अपने प्रवेशांक को संस्था में रहते तक की अवधि में अपने पास रखे। जो छात्र लम्बे अवकाश के बाद पुनः आ रहा हो, को उसका प्रवेशांक नया नहीं दिया जायेगा तथा उसके पुराने रजिस्टर को ही नवीन कर दिया जायेगा।

(स) छात्र रजिस्टर एक सुविधाजनक आकार के रूप में जित्त किया जायेगा। तथा प्रत्येक रजिस्टर में १०० पन्ने होंगे जो कि छात्रों के प्रवेश के क्रमादेश के अनुसार होंगे। इस रजिस्टर में वर्णमाला के क्रमानुसार सूची रखी जानी चाहिए तथा प्रत्येक अक्षर के लिए एक या दो पृष्ठों की जितनी जगह आवश्यक प्रतीत हो, छोड़ दी जानी चाहिए एवं इन पृष्ठों के पार्श्व (Margin) को आवश्यक संदर्भ के लिए काट दिया जाना चाहिए।

इस वर्णक्रम की सूची से प्रत्येक नाम के आगे उस संस्था का वर्णन किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत छात्र रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है। रजिस्टर नियमित रूप से तैयार किये जाने चाहिए।

(द) 'क' अभिलेख के प्रथम स्तम्भ (Column) का तात्पर्य प्रवेश एवं पुनः प्रवेश की तिथियों से है। महीनों का नाम जैसे जुलाई आदि पूरा लिखा जाना चाहिए। इसे '७' या 'सात' इस तरह में नहीं लिखा जाना चाहिए। नाम के सभी अंक लिखे जाने चाहिए न कि अन्त के केवल दो

अंक ही लिखे जाने चाहिए। तीसरे स्तम्भ में छात्र को हटाये जाने का कारण संक्षेप में लिखना चाहिए उदाहरणार्थ निरन्तर अनुपस्थिति, अपनी इच्छा से शाला छोड़ना, वकाया का भुगतान न करना, निष्कासन, स्थानान्तरण आदि।

(घ) 'ख' अभिलेख के स्तम्भ २ में जन्म तिथि पूर्ण लिखी जानी चाहिए, जैसे २० जुलाई १९२३ तथा छात्र के शाला एवं कालेज जीवन में शाला व कालेज के अभिलेख में छात्रों की आयु में बिना पर्याप्त कारण प्रस्तुत किये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

(फ) 'ग' अभिलेख में उन्नति की तिथि १ मई मानी जानी चाहिए जब तक कि उन्नति सत्र के मध्य में नहीं दी गई हो, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तिथि स्तम्भ २ में '२६ अप्रैल' इस प्रकार लिखी जानी चाहिए। असफल छात्रों के लिए '१ मई' स्तम्भ २ में एवं स्तम्भ ६ में 'अनुत्तीर्ण' लिखा जाना चाहिए।

(ह) 'घ' अभिलेख ये छात्र के चरित्र का वार्षिक विवरण लिखा जायेगा। शाला महा-विद्यालय के प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वर्ष को सूचित करने वाले बड़े अक्षरों को लिखा जाना चाहिए इसके नीचे किसी गम्भीर दुर्व्यवहार की घटना की विशेष बातों का तथा दिये गए दण्ड का एवं कोई पुरस्कार एवं छात्र के अपनी टीम का मोनीटर या सहायक मोनीटर होने का संक्षेप में वर्णन किया जायेगा। प्रत्येक प्रविष्टि में प्रथम से लेकर अन्त तक क्रम संख्या दी जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष के चाल चलन का अभिलेख यदि अनिवार्य हो तो अलग अतिरिक्त पृष्ठों पर लिखकर उसमें संलग्न किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रविष्टि जहां तक सम्भव हो, सूक्ष्म होनी चाहिए।

(व) छात्र जो शारदकालीन अवकाश के पश्चात् पुनः शाला में उपस्थित नहीं होता है उसके हटाये जाने की तिथि ३१ दिसम्बर होगी तथा इसी प्रकार यदि कोई छात्र ग्रीष्मावकाश के बाद पुनः नहीं लौटता है तो उसके हटाये जाने की तिथि ३० जून होगी।

(ल) शाला मुक्ति के प्रमाणपत्र चाहने के प्रार्थनापत्र के आने पर संस्था प्रधान उस प्रपत्र में अंकित विभिन्न अभिलेखों को अन्तिम तिथि तक भरेगा तथा छात्र रजिस्टर पर निम्न प्रमाणपत्र देते हुए हस्ताक्षर तथा तिथि दोनों का ही उल्लेख करेगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि विभागीयनियमानुसार छात्र की शाला मुक्ति की अन्तिम तिथि तक का पूर्ण विवरण उपरोक्त छात्र रजिस्टर में कर दिया गया है।”

(म) संस्था प्रधान, छात्र द्वारा पहली संस्था से लाये गये छात्र रजिस्टर की प्रतिलिपियां अपने पास रखेगा तथा उन्हें सुगम रंजर्भ के लिए जमा करके रखेगा एवं प्रत्येक छात्र को उसके शाला छोड़ने पर उसकी एक प्रतिलिपि देदेगा। उन छात्रों का नाम दिखाते हुए प्रारम्भ में एक सूची लगा देनी चाहिए जिनको ऐसी प्रतियां प्राप्त हुई हैं तथा उनकी छात्रों को या उनके संरक्षकों को लौटाने की तिथि का तथा उनको देने की रसीद की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

१८. उपस्थिति रजिस्टर—उपस्थिति रजिस्टर भरने के नियम निम्न प्रकार से हैं:—

(i) प्रत्येक कक्षा या कक्षा के खण्डों का अलग अलग उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए। इसमें इतने ही पृष्ठ होने चाहिये जो एक वर्ष के लिए पर्याप्त हों, इसकी जित्द पक्की नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके कवर भूरे मोटे कागज के होने चाहिए। वर्ष के अन्त में समस्त कक्षाओं के उपस्थिति रजिस्टर अभिलेख के वार्य हेतु एक जित्द में सम्मिलित बांधे जाने चाहिए।

(ii) कक्षाध्यापक द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में दिन में दो बार छात्रों की उपस्थितियाँ हमेशा नियमित रूप से ली जानी चाहिए। यह उपस्थिति प्रथम, द्वितीय एवं बैठक (Meeting) के प्रथम पांच मिनट में ली जानी जाए।

(iii) प्रपत्र जिनमें राजकीय शालाएं एवं इन्टरमिजिएट महाविद्यालय के छात्रों की उपस्थिति ली जानी है, संचालक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

(iv) उपस्थिति 'P' द्वारा की जानी चाहिए तथा अनुपस्थिति 'A' द्वारा की जानी चाहिए। यदि किसी छात्र ने अनुपस्थिति रहने हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर रखा हो या बीमारी के कारण अवकाश पर हो तथा उसे संस्था प्रधान या कक्षाध्यापक द्वारा स्वीकृत कर लिया हो तो वहाँ 'A' के बाद 'L' लगा देना चाहिए।

(v) उपस्थिति स्याही से की जानी चाहिए, कभी भी पेंसिल से करके फिर स्याही द्वारा पुनः नहीं लिखना चाहिये। ये प्रविष्टियाँ हमेशा स्पष्ट एवं असन्देहास्पद होनी चाहिये।

(vi) उपस्थिति रजिस्टर बन्द करने के पश्चात् किसी भी छात्र की उपस्थिति नहीं लगाई जावे।

(vii) रजिस्टर मौलिक होना चाहिए तथा वह साथ रखने एवं अन्य कारणों के आधार पर किसी अन्य कागज से नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए।

(viii) कोई उद्धर्षण (Erasures) नहीं होना चाहिए, यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उस पर लाल रेखा खींच देनी चाहिए तथा लाल स्याही द्वारा प्रविष्टि कर देनी चाहिए तथा उस पर अपने लघु हस्ताक्षर कर देना चाहिए।

(ix) उपस्थिति स्तम्भ में कोई स्तम्भ खाली नहीं रखना चाहिये एवं केवल बिन्दु लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए।

(x) शालाएं व महाविद्यालय में दो बैठक (Meetings) होनी चाहिए। एक छात्र जो किसी भी बैठक के बीच में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उस बैठक में अनुपस्थिति लगाई जानी लगी जानी चाहिए तथा उसकी उपस्थिति को लाल स्याही से काट देना चाहिए तथा लघु हस्ताक्षर कर देना चाहिये।

(xi) जब पूर्ण या अर्ध अवकाश होता है तो स्तम्भों के मध्य में एक रेखा खींच देनी चाहिए जिसमें कि "रविवार" "दरत ५ चमी" जैसी भी परिस्थिति हो लिख देना चाहिए। अधिक अवकाश होने पर स्तम्भों को काटते हुए रेखा खींची जानी चाहिए।

(xii) जब किसी छात्र का नाम काट दिया जाता है तो उसके नाम पर उस मास के अन्त तक के स्तम्भों में एक लाल रेखा अंकित कर देनी चाहिए। यह रेखा उस दिन से अंकित की जानी चाहिए जिस दिन से वह उपस्थित रहना स्थगित करता है तथा इसके आगे के त्रिवरण स्तम्भ में "काटा गया" लिखा जाना चाहिए।

(xiii) उपस्थिति स्तम्भ में केवल 'P', 'A', 'A', 'L' तथा उपनियम ११ के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए।

(xiv) कुल उपस्थिति व छात्रों की संख्या नियुक्ति प्रविष्टि की जानी चाहिए।

(xv) रजिस्टर के नीचे उपस्थिति, अनुपस्थिति, अवकाश, शुरुक दण्डादि की प्रविष्टियाँ दूसरे

मास की १५ तारीख तक पूर्ण हो जानी चाहिए ।

(xvi) प्रत्येक माह के लिए छात्रों के नाम, क्रम संख्या व प्रवेश संख्या कक्षाध्यापक द्वारा विगत मास की अन्तिम तिथि तक अवश्य लिख लिए जायेंगे ।

१६. प्रवेश रजिस्टर—परिशिष्ट २० में दिये गये प्रपत्र के अनुसार प्रवेश पत्र रजिस्टर तैयार किये जायेंगे ।

अध्याय २२

पत्र व्यवहार का क्रम

सम्बन्धित अधिकारियों को किन्हीं विषयों तक स्वयं का निष्पत्ति लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन साधारणतया पत्रव्यवहार की परम्परा निम्न प्रकार होगी:—

१. संचालक, अन्य विभागों के खण्ड एवं जिला स्तर के अधिकारियों, उप संचालकों, संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक सहायक संचालिकाओं, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षाएँ तथा आचार्य, शादूल सार्वजनिक शाला के साथ सीधा पत्र व्यवहार करेगा एवं सरकार के साथ शिक्षा सचिव के द्वारा करेगा ।

२. उप संचालक, सहायक संचालक इन्टर कालेज के आचार्यों व निरीक्षकों के साथ पत्र व्यवहार करेगा । वे सम्पूर्ण जिले या जिले के किसी भी भाग को प्रभावित करने वाले सामान्य महत्व के विषयों में सीधे अन्य विभागों के खण्ड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करेंगे ।

३. निरीक्षक एवं महाविद्यालयों के आचार्य सम्बन्धित क्षेत्र के उप संचालकों के साथ पत्र व्यवहार करेंगे । वे अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी पत्र व्यवहार कर सकते हैं ।

४. उप संचालक योजना, उप संचालक समाज शिक्षा, सहायक संचालक या संचालिकाएँ, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षाएँ, संस्कृत पाठशाला के निरीक्षक आचार्य, शादूल सार्वजनिक शाला, संचालक के साथ सीधा पत्र व्यवहार करेंगे ।

५. उच्च विद्यालय वैसिक एस. टी. सी. पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक, जिला समाज शिक्षा अधिकारी, छात्रा उच्च विद्यालय व महिला प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रधानाध्यापिकाएँ, संचालक के साथ सीधा पत्र व्यवहार नहीं करेंगी । संचालक से सीधे प्राप्त किए गए पत्रों या अत्यावश्यक परिस्थिति के मामले में केवल अर्द्ध सरकारी पत्र लिख सकेंगे तथा ऐसा करने पर इसकी प्रतिलिपि अपने तात्कालिक सक्षम अधिकारी को आवश्यक रूप से भेजनी पड़ेगी । उपरोक्त अधिकारी केवल अपने सक्षम तात्कालिक अधिकारी तथा उनके सहायक अधिकारियों से ही पत्र व्यवहार करेंगे ।

६. माध्यमिक शालाएँ, प्राथमिक शालाएँ तथा उप सहायक निरीक्षिकाएँ केवल सम्बन्धित उप निरीक्षकों व उप निरीक्षिकाओं से ही पत्र व्यवहार करेंगी । वे सहायक संचालिकाओं या विभाग के उनसे ऊपर के अन्य अधिकारियों के नाम उनसे सीधे प्राप्त किये गये पत्र के उत्तर में पत्र व्यवहार कर सकती हैं । ऐसे मामलों में इस पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ अपने तात्कालिक उच्च सक्षम अधिकारी के पास आवश्यक रूप से भेज देनी चाहिए ।

७. इसी प्रकार अन्य सहायक केवल अपने तात्कालिक अधिकारियों के अतिरिक्त विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ उचित मार्ग द्वारा पत्र व्यवहार करेंगे।

८. उचित मार्ग द्वारा नहीं किये गये पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, लेकिन कोई भी अधिकारी कोई भी पत्र या प्रार्थना पत्र जो उच्चाधिकारी को भेजा जाना है, एक सप्ताह से अधिक नहीं रोक सकेगा तथा उसे सम्बन्धित पते पर निर्धारित तिथि की अवधि में आवश्यक रूप में अपनी टिप्पणियों सहित पहुंचा देगा।

अध्याय २३

प्रशासन प्रतिवेदन-सामान्य निर्देश

(अ) मुख्य एवं उप प्रतिवेदन लेखकों को प्रतिवेदन तैयार करते समय निम्न सिद्धान्तों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए:—

१. प्रतिवेदन में केवल उन्हीं तथ्यों का विवरण दिया जाना चाहिए जो वास्तविक रूप में उनके नियन्त्रण एवं निरीक्षणधीन विभाग के प्रशासनिक वर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हों इसके अतिरिक्त अन्य विषय ऐसे भी सम्मिलित करना चाहिए जो विशेषतः सार्वजनिक हित में हों।

२. प्रतिवेदन जितना छोटा हो उतना ही उत्तम है वशतः कि इसमें चार्हे गये तथ्यों एवं आंकड़ों को बुद्धिमत्ता पूर्वक सम्मिलित कर लिया गया हो तथा वर्ष पर्यन्त के कार्य की प्रमुख बातें उसमें सम्मिलित करली गई हों।

३. प्रतिवेदन का स्वरूप प्रायः पर्याप्त रूप से वर्णनात्मक होना चाहिए। वर्णन में तुलनात्मक आंकड़ों की सूची देना अवसर आने पर आवश्यक होगा लेकिन ऐसी तालिका संक्षिप्त एवं सरल होनी चाहिये तथा उनको संख्या निश्चित तौर पर सीमित होनी चाहिए।

४. प्रतिवेदन उनके अवतरणों में लिखि जायेगी तथा अवतरणों पर क्रम संख्या लगायी जायगी।

५. प्रतिवेदन में केवल उन्ही आंकड़ों को सम्मिलित करना चाहिए जो महत्व के हों। आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

६. आंकड़ों की सूची को अधिक संख्या में प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से (सामान्यतः परिशिष्ट में आंकड़ों का अस्पष्ट रूप में पुनः सम्मिलित करना) वह अपने स्वरूप तथा उद्देश्य को खो बैठता है। इसलिए आंकड़ों की विभिन्नता को जो व्याख्या हेतु इतने अनिवार्य या असाधारण न हो उन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का प्रयास तब तक न करना चाहिए जब तक कि प्रतिवेदन में कही गई बात के स्पष्टीकरण हेतु आंकड़ों की आवश्यकता न समझी जावे।

७. आंकड़ों सम्बन्धी सूची पर सम्बन्धित अवतरणों के पूर्ण प्रसंगों को अवतरण के पार्श्व के भाग में इंगित किया जाना चाहिए।

८. मुख्य कार्यालय से सीधे पत्रव्यवहार करने वाली शिक्षण संस्थाओं के प्रधान निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत सामान्यतः अपने अधीन संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रबन्ध करेंगे तथा उसे अपने तात्कालिक सहाय अधिकारी के पास १५ जुलाई तक प्रेषित कर देंगे ताकि वह संचालन शिक्षा विभाग के पास प्रतिवर्ष १५ अगस्त तक पहुंच जाया करे:—

- (१) कार्य-भार (Charge)
- (२) स्टाफ में परिवर्तन ।
 - (अ) स्थानान्तरण ।
 - (ब) वृद्धि ।
 - (स) पदोन्नति ।
- (३) छात्रों की कुल संख्या—
 - (अ) प्रत्येक कक्षा में ।
 - (ब) औसत उपस्थिति ।
- (४) परीक्षा परियाम ।
- (५) अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की प्रगति
- (६) छात्रवृत्ति प्राप्त कर्त्ता छात्र एवं उनकी प्रगति ।
- (७) पाठशाला निधि विवरण ।
- (८) व्यायाम गतिविधियां एवं विवरण ।
- (९) कार्यालय—
 - (अ) लेखा ।
 - (ब) पत्र व्यवहार ।
 - (स) पुस्तकालय ।
- (१०) भवन—
 - (अ) वृद्धि ।
 - (ब) मरम्मत ।
 - (स) कर्त्तव्य ।
- (११) विशेष घटनाएँ (यदि कोई हों) ।
- (१२) सुधार हेतु सुझाव ।
- (१३) सामान्य पर्यवेक्षण ।
- (१४) परिशिष्ट ।

६. अपने क्षेत्र के उच्च एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रशानावस्थापकों से निरीक्षक एक अलग प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे । प्रतिवेदन की सतर्कतापूर्ण जांच के बाद निरीक्षक उनका एक सम्मिलित प्रतिवेदन तैयार करेंगे तथा उसे उप संचालक के पास प्रतिवर्ष १० अगस्त तक भेज देंगे । निम्न शीर्षकों के अन्तर्गतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा:—

- (१) कार्य-भार (Charge)
- (२) क्षेत्र में प्रशासनात्मक परिवर्तन ।
- (३) यात्रा—
 - (अ) कार्यक्रम ।
 - (ब) कुल दिवस ,
 - (स) निरीक्षण की गई शालाओं की संख्या मय दिन एवं माह के ।

(द) पाठशाला में दिये गये विशेष विवरण ।

(i) शिक्षात्मक ।

(ii) प्रशामनात्मक ।

(iii) शैक्षणिक कर्मचारी ।

(iv) व्यायाम एवं अन्य क्रियायें ।

(य) यदि अनिवार्य हो तो संक्षिप्त सुझाव ।

(४) प्राथमिक तथा उच्चतर शिक्षा पर टिप्पणियाँ ।

(अ) वृद्धि, कमी या शालाओं एवं छात्रों का स्थानान्तरण ।

(ब) शालाओं के स्तर में वृद्धि ।

(५) सहायता प्राप्त शालायें:—

(अ) शालाओं एवं छात्रों की संख्या में वृद्धि या कमी ।

(ब) स्टॉक, लेख, रजिस्टर एवं अनुशासन के सम्वन्ध में विभागीय नियम का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन ।

(६) आत्मनिर्भर शालायें ।

(७) उच्चतर शालाओं पर टिप्पणियाँ ।

(८) रूपरेखा के रूप में विशेष विवरण ।

(अ) महिलाओं की ।

(ब) खेलकूद प्रवृत्तियाँ ।

(स) शारीरिक प्रशिक्षण ।

(द) कृषि प्रशिक्षण ।

(य) राजकीय परीक्षाओं के परिणाम ।

(फ) बालचर ।

(९) महत्वशील घटनायें ।

(१०) सामान्य पर्यवेक्षण एवं सुझाव ।

(११) परिशिष्ट ।

१०. उप संचालक इन प्रतिवेदनों को प्रतिवर्ष ३१ अगस्त से पूर्व संचालक के पास भेजेंगे। निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें महामयक संचालिकायें, प्रस्तोता, विभागीय परीक्षायें, उप संचालक योजना भी इसी प्रकार के प्रतिवेदन संचालक के पास प्रतिवर्ष १५ जुलाई से पूर्व ही भेजेंगे ।

अध्याय २४

संस्था प्रधानों तथा अध्यापन कर्मचारियों के लिये निर्देश

संस्था प्रधानों तथा अध्यापन कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिये सामान्य निर्देश

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन के स्तर एवं आन्तरिक कार्य करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधानों एवं अध्यापन कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु निम्न निर्देश

दिये गये हैं ।

१. संस्था प्रधानों के लिये निर्देश—संस्था प्रधानों को शिक्षा संहिता पूर्ण रूपेण पढ़ना चाहिये एवं वर्णित निर्देशों का उसी अर्थ तथा भावना से पालन करना चाहिये । संहिता के किसी भी खण्ड में की गई व्याख्या में संदेह उत्पन्न हो जाने पर उसे संचालक के पास उसकी व्यवस्था तथा तात्पर्य प्राप्त करने हेतु प्रेषित कर देनी चाहिये ।

२. संस्था प्रधानों को विशेष रूप से इस बात को देखना चाहिए कि संस्था का भवन एवं उसका क्षेत्र साफ एवं सुथरा रखा जाये तथा आरोग्यकारी एवं मरम्मत की दृष्टि से उचित रूप से रखा जाये । यह वांछनीय है कि शाला भवन पर प्रतिवर्ष सफेदी कराई जाये और फर्नीचर को अच्छी दशा में रखा जाये ।

३. संस्था प्रधानों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों के माता-पिता या संरक्षकों एवं अपने अधीन कर्मचारियों के साथ नम्रता का व्यवहार करें ।

४. प्रधान इसे भली प्रकार से याद रखेंगे कि अपने अधीनस्थ संस्था की शिक्षा सम्बन्धी उन्नति अध्यापन कर्मचारी वर्ग के साथ सहयोग स्थापित किये रखने एवं स्वयं द्वारा व्यक्तिगत रुचि रखने से ही हो सकती है ।

५. प्रधानों का सर्व प्रमुख कर्तव्य अध्यापन कार्य एवं पद्धति का निरन्तर निरीक्षण करना एवं अध्यापकों को जब भी आवश्यकता हो, उनका उचित मार्ग दर्शन करना है । उन्हें इस बात से स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि अध्यापक उनके द्वारा आयोजित शैक्षणिक प्रगति के कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं ।

६. पत्र प्रेषण में शीघ्रता, कठोर संवैधानिक प्रक्रिया एवं प्रबन्धात्मक कार्यवाही में शीघ्रता पर उनको ध्यान देना चाहिए ।

७. संस्था अध्यक्षों को, जिनको प्रशासनात्मक कार्य पूर्ण करना पड़ता है, जब वे अवकाश या लम्बी छुट्टियाँ या किसी अन्य कारण से अपने मुख्य स्थान छोड़ें, तो उन्हें अपना पता संस्था में लिखकर छोड़ जाना चाहिए । इससे किसी भी मामले में उनकी सलाह प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी ।

८. उन्हें अपनी अनुपस्थिति में संस्था के प्रशासनात्मक कार्य को पूर्ण करने हेतु उचित व्यवस्था करके जाना चाहिए । तथा ठीक समय पर इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

९. उन्हें अपने कार्यालय में आलोक पुस्तिकाओं (Note Books) की एक सूची रखनी चाहिए जो कि विभिन्न कक्षा के छात्रों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है । यह और ध्यान में रखना चाहिये कि अध्यापकों द्वारा छात्रों को यह कार्य नियमित रूप से दिया जाता है एवं ठीक किया जाता है ।

१०. प्रत्येक शिक्षण सत्र के आरम्भ में प्रत्येक संस्था प्रधान को शाला के अध्यापन कार्य हेतु, गम्भीर विचार एवं ठोस आधार को ध्यान में रखते हुए, एक समयसारणी तैयार करनी चाहिये ।

११. समय सारणी में प्रत्येक अध्यापक के अध्यापन के अन्तर (Periods) के शीर्षक एवं विषय के नीचे उसके कार्य की व्याख्या की जानी चाहिये । प्रत्येक विषय पर एक माह में दिये

जाने वाले अन्तर की संख्या भी दिखाई जानी चाहिए ।

१२. प्रत्येक कक्षा—कक्ष के प्रमुख स्थान पर यह समय-सारणी लगा दी जानी चाहिये ।

१३. संस्था प्रधानों से यह देखने की अपेक्षा की जाती है कि अध्यापक परीक्षाओं में व कक्षा पण्डिकाओं को सही करने एवं परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को जांचने में पूर्ण उत्साह एवं सावधानी दिखाते हैं ।

१४. जो अध्यापक छात्रों के स्वास्थ्य, नैतिक तथा मानसिक विकास में स्वेच्छापूर्वक शाला समय के उपरान्त भी रुचि लेते हों, उनकी सूचना संस्था प्रधानों द्वारा संचालक को दे देनी चाहिए । संस्था के वार्षिक प्रतिवेदनों में ऐसे प्रयासों का वर्णन किया जाना चाहिए ।

१५. संस्था प्रधानों से वादविवाद समितियाँ एवं साहित्यिक क्लब बनाने व उन्हें प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया जाता है । फिर भी समितियों या क्लब बनाने से पूर्व उचित सविधान एवं नियम बना लेने चाहिए ।

१६. संस्था प्रधानों से, विभिन्न प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने की ओर ध्यान देने की, अपेक्षा की जाती है । यह वांछित है कि छात्र शाम को किसी भी प्रकार का व्यायाम करें । छात्र जीवन के इस पक्ष की ओर प्रधानों को अधिक जोर देना चाहिये उन्हें देखना चाहिए कि उनकी राय कार्य रूप में परिणित हो जाये तथा खेल सम्बन्धी तमाम सामग्री की सुविधायें छात्रों को प्राप्त हो जाये ।

१७. प्रत्येक संस्था को, यदि सम्भव हो तो वार्षिकोत्सव या पारितोषिक वितरण के रूप में, प्रतिवर्ष एक उत्सव मनाना चाहिए । ऐसे अवसरों पर प्रख्यात नागरिक व छात्रों के माता पिताओं को इस दृष्टिकोण से अवगत कराने हेतु निमन्त्रण देने का प्रयास करना चाहिए कि वे संस्था के कार्य से परिचित हो तथा उसमें रुचि लें । इससे संरक्षकों की सहानुभूति एवं सहयोग प्राप्त होगा जो कि शिक्षा के विकास में अत्यन्त आवश्यक है ।

१८. अन्तर्कक्षीय एवं अन्तःशाला खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये व्यक्तिगत विशिष्टता प्राप्त करने की अपेक्षा शाला की प्रसिद्धि को प्राप्त करने के प्रयासों पर जोर देना चाहिए ।

१९. महाविद्यालय, उच्च विद्यालय एवं विशेष संस्थाओं में पत्रिकायें इस आशय से निकाली जानी चाहिए कि उनमें छात्रों में आत्म विश्लेषण कला के विकास में प्रोत्साहन मिले ।

२०. अनुसूच्य मध्यान्तर से प्रधानों को अध्यापकों द्वारा कक्षा में पढ़ाये जाने वाले पाठ के लिए तैयार की गई टिप्पणियों का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा अध्यापकों व छात्रों द्वारा कुंजियों, को प्रयोग में लाने से सख्त निषेध करना चाहिए ।

२१. एक नियमित आलोक पुस्तिका में अध्यापकों के निरीक्षण कार्य का एक अभिलेख संस्था प्रधानों को अपने पास रखना चाहिए ।

२२. यह संस्था प्रधान की इच्छा पर निर्भर है कि वह कार्यालय पर्यवेक्षण का अपना कार्य किसी अन्य सहयोगी के सुपुर्द कर सकता है परन्तु अपने कार्यालय के कार्यों का अन्तिम दायित्व स्वयं पर ही होगा ।

२३. दैर्घ्यिक यात्रायें भी छात्र जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । महाविद्यालय एवं

उच्च-विद्यालयों के प्रधानों को ऐसी यात्रायें अवकाशों या छुट्टियों में करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोष प्राप्य हो तो संचालक शिक्षा विभाग ऐसे यात्रा खर्चों के लिए उचित प्रस्तावों का स्वागत करेगा। उनकी अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र के साथ निम्न सूचनायें और प्रस्तुत करनी चाहिये:—

(अ) यात्रा के मध्य में देखे जाने वाले स्थानों का कार्यक्रम, जिनमें इन स्थानों का छात्रों के लिये ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक व औद्योगिक महत्त्व को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

(ब) छात्र, अध्यापक एवं नौकरी की संस्था के आधार पर यात्रा का कुल स्पष्टतया अनुमानित व्यय।

(स) यात्रा व्यय के लिए छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा दिया गया धन का अंशदान।

(द) वह अंशदान जो संस्था प्रधानों द्वारा दिया गया है।

(व) विभाग से अपेक्षित अंशदान।

नोट—सक्षम अधिकारी यात्रा करने की स्वीकृति दे सकता है परन्तु शर्त यह है कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाये कि इस यात्रा का परिणाम छात्रों के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा तथा यह यात्रा छुट्टियों में ही की जायेगी एवं इससे संस्था के नियमित कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी।

२४. शैक्षणिक वर्मचारियों के लिए निर्देश:—अध्यापकों को इस आदेशिका (Precept) को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी छात्रों के लिये उत्तम पुस्तक स्वयं अध्यापक ही है। उसके व्यवहार, व्यक्तिगत आकृति एवं स्वभाव सभी का प्रभाव छात्रों के विकसित मस्तिष्क पर होता है तथा ये बातें उनके विकास को प्रभावित करती हैं।

२५. उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि वे अपने छात्रों को लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में ढाल कर एक सक्रिय नागरिक के रूप में भाग लेने हेतु शिक्षित कर रहे हैं।

२६. उन्हें अपने छात्रों को पहिले से ही आंकड़ों के रूप में तैयार किये गये ज्ञान को देने की अपेक्षा उन्हें (छात्रों को) स्वयं, को व्यक्तिगत रूप से ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।

२७. जहां तक सम्भव हो प्रत्येक छात्र की आवश्यकतानुसार निर्देशन के तरीके को अपनाया जाना चाहिए ताकि मन्द बुद्धि, असतन एवं प्रगल्भ बुद्धि छात्र सभी अपनी समझ के अनुसार उन्नति करने का अवसर प्राप्त करें।

२८. उन्हें अपने छात्रों को समुदायों में काम करने का अवसर देना चाहिए तथा सामुदायिक योजनायें एवं कार्यक्रम चालू करने चाहिए जिससे कि उनमें सामूहिक जीवन एवं सहकारिता से कार्य करने के गुण अनिवार्य रूप से विकसित हों।

२९. सामान्य रूप से सम्पूर्ण वर्ष के लिये उन्हें अपने कार्य की योजना तैयार करनी चाहिये जिसमें वर्ष के चालू भाग के कार्य का विस्तृत वर्णन होना चाहिये। छात्रों को इससे अवगत कराने के लिए इसकी एक प्रतिलिपि कक्षा कक्ष में रखी जानी चाहिये।

३०. उन्हें कक्षा में पढ़ाये जाने वाले विषय की पूर्ण तैयारी करके जाना चाहिए और उदाहरण देने हेतु पर्याप्त समग्री अपने पास रखनी चाहिए।

३१. छात्रों में अपने देश तथा विश्व के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण रुख को जागृत करने तथा उन्हें उनमें विवेक पूर्ण तथा सक्रिय रुचि लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए अध्यापकों को वर्तमान घटनाओं तथा प्रवृत्तियों का पूर्णतया जानकारी होना चाहिए।

३२. उन्हें छात्रों को ज्ञान की मात्रा बढ़ाने के अतिरिक्त उनमें वाङ्मयीय मूल्यों, उचित प्रवृत्ति एवं कार्य की आदत का समावेश करने का प्रयास करना चाहिये।

३३. व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में कार्य के अभिहस्तांकन (Assignment) द्वारा कक्षा व शाला के पुस्तकालय के उपयोग का वे (अध्यापक) प्रचार करेंगे।

३४. प्रत्येक विषय में छात्रों द्वारा कक्षा में प्राप्य ज्ञान को क्रियात्मक रूप प्रदान करने की प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न प्रकार से 'अभिव्यक्ति कार्य' को अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मिलित करेंगे।

३५. उनको ऐसे विषयों एवं क्रियाओं में, जो उनके नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण में हों, छात्रों की प्रगति का एक अभिलेख तैयार करना चाहिये एवं प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता, रुचि व निपुणता के विषय में जानकारी देने हेतु उसे उपलब्ध कराना चाहिये। इस प्रकार खोजी गई व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कई कार्यों को उन्हें आयोजित करना चाहिये।

३६. सम्पूर्ण लिखित कार्य सावधानी से करवाना चाहिये तथा नियमित रूप से जाँचना चाहिये, सामान्य त्रुटियों को कक्षा में स्पष्ट किया जाना चाहिये तथा छात्रों को उन्हें पुनः शुद्ध लिखने हेतु करना चाहिये।

३७. सभी प्रयोगात्मक कार्यों में उन्हें यह देखना चाहिये कि सामान, यन्त्र, उपकरण आदि सभी अन्तर (Period) शुरू होने से पूर्व प्रयोग के लिये तैयार है।

३८. वे संस्था प्रधान को इस बात के देखने में सहायता देंगे कि श्रेणी क्रम स्वच्छ रखा जाता है तथा कक्षा का फर्नीचर छात्रों द्वारा जानबूझ कर नहीं तोड़ा गया है।

३९. छात्रों के संसर्ग में रहते समय उन्हें पहली, व्यंग या विद्वाने आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिये, "भय" वाली पद्धति को अपनाने के बजाय उन्हें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिये जिससे कि वच्चा अपने आपको सुरक्षित, स्वतन्त्र एवं प्रसन्न अनुभव करे।

४०. प्रत्येक अध्यापक को अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में विद्यार्थी की प्रवृत्ति ही बनाये रखनी चाहिये तथा शिक्षा में मंत्रन्वित एवं व्यावसायात्मक ज्ञान में अभिवृद्धि प्राप्त करने सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये अपने आपको अधिक सुसज्जित रखना चाहिये। उसको ऐसी सभी क्रियाओं में सक्रिय भाग लेना चाहिये जो उसे अपना जीवन सफल एवं सुखद बनाने हेतु नया अनुभव प्रदान करे।

४१. उन्हें पाठ्य पुस्तकों तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखना चाहिये बल्कि आज तक के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर उसे बढ़ाना चाहिये तथा उसका सम्बन्ध वर्तमान जीवन व छात्रों के जीवन एवं अनुभव में स्थापित करना चाहिये।

४२. उन्हें शालाओं के सामूहिक कार्यक्रमों में क्रियात्मक रूप से भाग लेना चाहिए जितना ही वे अपने छात्रों को समझेंगे तथा छात्रों की सर्वशुद्धी प्रगति में सहामता प्रदान करने से समर्थ सकेंगे।

कक्षाध्यापकों के लिए निर्देश

४३. पाठशाला में अध्यापन व्यवस्था आदि से सम्बन्धित चाहे कितनी ही निपुणता के साथ सुव्यवस्था क्यों न हो परन्तु किशोर छात्रों के सम्बोधनक विकास के लिए व्यक्तिगत ध्यान एवं संभाल अत्यावश्यक हैं। जिस प्रकार से यह आवश्यकता घर पर माता पिता पूर्ण करते हैं उसी प्रकार यह उत्तरदायीत्व शाला में कक्षाध्यापक के कंधों पर रहता है।

४४. कक्षाध्यापक को अपनी कक्षा के छात्रों की (शैक्षणिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक) सर्वमुखी उन्नति हेतु आवश्यक कदम उठाना एवं निगरानी रखना चाहिए तथा उनका अभिलेख तैयार करना चाहिए।

४५. उसे दक्ष एवं पिछड़े हुए छात्रों को ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी अधिकतम उन्नति हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा उनका अभिलेख तैयार करना चाहिए।

४६. उसे छात्रों को स्वयं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो स्वयं को उनकी निगरानी रखनी चाहिये तथा आवश्यकतानुसार पथ प्रदर्शन करना चाहिए।

४७. अपने छात्रों के हितार्थ उनके संरक्षकों से सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये विशेषतया उस समय जब कि उन छात्रों की सहायता करने में कुछ कठिनाई उपस्थित होती हो।

४८. उसे छात्रों के साथ औपचारिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर व वातावरण उत्पन्न करना चाहिए तथा अपनी सहानुभूति एवं सहायक प्रवृत्ति द्वारा छात्रों को उनकी कठिनाइयाँ अपने समक्ष लाने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए।

४९. विभिन्न अध्यापकों द्वारा छात्रों को दिये गये गृह कार्यों का उसे समन्वय करना चाहिये ताकि एक विषय में दिया गया कार्य कुल दिये गये कार्य के अनुपात में अधिक न होवे तथा कुल कार्य भी इतना अधिक नहीं होना चाहिये।

५०. जो छात्र अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं ऐसे छात्रों को कक्षा में रोकना चाहिये या अतिरिक्त समय का प्रबन्ध करना चाहिए।

५१. चरित्र भ्रष्टता या अनुशासन के भंग किये जाने की स्थिति में, जिसको कि निपटाने में वह अधिकृत एवं समर्थ नहीं है, प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देना चाहिए।

५२. उसे अपनी श्रेणी की उपस्थिति शीघ्रतापूर्वक एवं नियमित रूप से लेनी चाहिए एवं उपस्थिति रजिस्टर को साफ सुथरा व पूर्ण रूप से तैयार रखना चाहिए।

५३. उसे छात्रों की प्रगति पत्रिका में आवश्यक प्रविष्टि करनी चाहिए तथा उस पर उनके संरक्षकों के हस्ताक्षर समय पर करा लेना चाहिए।

५४. उसे शाला की वक़ाया रकम समय पर वसूल कर जमा करा देना चाहिये एवं उसका लेखा रखना चाहिए।

५५. उसे शुल्क मुक्त किए जाने वाले एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने योग्य मामलों को उनकी निपुणता एवं दरिद्रता या दोनों के आधार पर, प्रधानाध्यापक के पास अनुशंसित करना चाहिए।

५६. उसे छुट्टी आदि के मामलों में प्रधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग उचित न्याय के साथ करना चाहिए।

५७. उसे देखना चाहिए कि छात्रों के लिए उनके गम्भीर विश्राम काल में उनके मूल्य जलपान की व्यवस्था है तथा वे अपने स्वास्थ्य को खतरों में डाल कर कार्य नहीं कर रहे हैं। छात्र अपने नाव घर से कुछ (खाने हेतु) ला सकते हैं।

५८. उसे देखना चाहिये कि प्रकाश, रोगनयन, स्वच्छता, बैठने यादि का प्रबन्ध कक्षा में मन्तोपप्रद है।

५९. शारीरिक पीड़ा ने पीड़ित हो जाने पर या टूँकोमा, एडीनोइडस, दाँतों की खराबी, गले में गाँठें, दर्द आदि में छात्र के पीड़ित होने पर उसे पता लगाकर उसको उचित चिकित्सा कराने हेतु ज्ञात देना चाहिये।

६०. यदि चिकित्सक कोई विशेष कदम उठाने की राय दे तो उसे देखना चाहिए कि वह कार्य पूरा हो रहा है।

६१. उसे अपने छात्रोंको किसी विषय में विशेष रुचि रखने हेतु प्रेरित करना चाहिए शिक्षा आराम के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शिक्षा परिश्रम के लिए।

६२. उसे, व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति उचित आदत डालने की ओर प्रयास करना चाहिये तथा नैतिक एवं चरित्र को बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

६३. उसे, दलबली बानों पर जोर देकर छात्रों में आत्म विश्वास की विकसित करने के प्रयास करने चाहिये। छात्रों की दुर्बलताओं को पकड़ कर सन पर बार बार विवाद करना उनके स्वास्थ्य विकास के लिये अत्यन्त हानिकारक है।

अध्याय २५

शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियमों की प्रतिलिपी

राजस्थान सरकार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक संस्थाओं से सहायता स्वरूप उपहार प्राप्त करने एवं स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम बताती है :—

१. इन नियमों को राजस्थान सार्वजनिक शिक्षण संस्थाये (सहायता) नियम १९५१ कहा जायेगा।

२. इन नियमों के अन्तर्गत:—

(i) 'सहायता' का तात्पर्य नकद या किसी रूप में अथवा कुछ नकद व कुछ अन्य रूप में सहायता प्राप्त करने से है तथा इसमें भवन दान, खुला स्थान, या भूमि का भाग चाहे दीवार खींची छूआ हो या नहीं, सब सम्मिलित है।

(ii) 'निर्माण' के अन्तर्गत भवन वृद्धि, मरम्मत तथा वर्तमान भवन को अन्य प्रकार से निमित्त करना सम्मिलित है।

(iii) 'दानकर्ता' से तात्पर्य एक व्यक्ति या सामूहिक मनुष्यों की संख्या से है जो सहायता प्रदान करे हैं तथा इसमें ऐसी सहायता प्रदान करने वाली संस्था भी सम्मिलित है।

(iv) 'सामग्री' से तात्पर्य सार्वजनिक शिक्षण संस्था को आवश्यक रूप से प्रदत्त सामग्री से है, जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण, फर्नीचर, मानचित्र, पुस्तकें या इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ।

(v) 'सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(vi) 'सार्वजनिक संस्था' का तात्पर्य उस व्यक्ति समुदाय से है जो चाहे किसी भी नाम से प्रख्यात हो तथा, जो वर्तमान समय में प्रभावशील कुछ कानूनों के अन्तर्गत या अनुसरण में स्थापित की गई हो या पंजीकृत की गई हो।

(vii) 'सार्वजनिक शिक्षण संस्था' का तात्पर्य उस शिक्षण संस्था से है जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के खर्च से स्थापित की गई है अथवा स्थापित की जाने वाली है।

३. इन नियमों के अन्तर्गत सहायता:—

(अ) सार्वजनिक शिक्षण संस्था से सम्बन्धित, भवन निर्माणार्थ या भवन की सुरक्षा अथवा यन्त्रों हेतु, या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हो सकती है, तथा—

(ब) सरकार द्वारा स्वीकृति के आधार पर, चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित, कानूनी रूप से हस्तान्तरण के समझौते स्वरूप हो सकती है तथा अन्य ऐसी किसी सम्पत्ति के रूप में हो सकती है जो सहायता के अन्तर्गत आती हो।

४. इन नियमों के अन्तर्गत दी गई किसी भी प्रकार की सहायता के समय उसके देने के विशेष कारणों या उद्देश्यों का वर्णन करना पड़ेगा।

५. (१) इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था यदि सहायता देना चाहे तो वह इस प्रकार की सहायता देने हेतु सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित करेंगे जिसमें वह इस प्रकार की सहायता देने के कारणों एवं उद्देश्यों तथा शर्तों का जिसके आधार पर सहायता दी जाने वाली है, यदि कोई हो, वर्णन करेगा।

(२) ऐसे प्रार्थनापत्र या तो सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान या संचालक शिक्षा विभाग राजस्थान, के नाम से प्रस्तुत करने पड़ेंगे।

(३) इस नियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी, उसे राज्य सरकार के पास आदेशार्थ भेजने से पूर्व यदि कोई हुई तो, ऐसी जांच करेंगे जो वे उसके निपटारे में अनिवार्य समझें।

(४) ऐसे अधिकारी उप नियम ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यता में बिना पक्षपात किये विशेष मामलों में या तो स्वयं या अपने सहायक किसी अधिकारी द्वारा, नियम ७ में कहे अनुसार मामलों में विशेष रूप से पूर्ण निरीक्षण करायेंगे तथा प्रत्येक मामले में अपने द्वारा पाये गए तथ्यों का वर्णन करेंगे।

६. (१) नियम ६ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली किसी भी सहायता के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार कर सकती है।

(अ) यदि यह नियम ३ के अन्तर्गत वर्णित सब शर्तों को पूर्ण करता हो।

(ब) यदि वह ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा सार्वजनिक संस्था के द्वारा आती है जो उस प्रकार के समझौते करने में तथा प्रस्तावित सम्पत्ति या वस्तुएं देने में समर्थ हो।

(स) यदि वह शर्तों पर आधारित न हो या जहाँ पर शर्तें लागू की गई हों, वे शर्तें उचित हों।

(द) यदि सहायता की विषय सामग्री उसके दृष्टिकोण में वांछित उद्देश्यों एवं कार्यों को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त है, तथा

(य) यदि सहायता किसी भी क्षेत्र या वस्ती की वास्तविक शिक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली है।

(२) शर्तों के आधार पर प्राप्त होने वाली सहायता के विषय में राज्य सरकार या अधिकारी जिसे प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, उन प्रार्थना पत्रों में दी गई शर्तें या शर्तों में संशोधन करने का सुभाष दे सकता है तथा जब दान देने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा लिखित में इस प्रकार के संशोधित सुभाषों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस समय संशोधित शर्तें या शर्तें ही सहायता प्राप्त करने की शर्तें समझी जावेंगी।

७. (१) सार्वजनिक शिक्षण संस्था के भवन निर्माण हेतु जब इन नियमों के अन्तर्गत सहायता की राज्य सरकार स्वीकार करती है, तब यदि आवश्यक समझा जाये, तो इस कार्य हेतु राज्य सरकारी राय में जो भी सबसे उपयुक्त स्थान हो उसे बिना किसी धन-भार (Charge) के छात्रा भवन के निर्माण हेतु बतलाया जा सकता है। अन्यथा सार्वजनिक उपयोगिता की आवश्यकता को निम्न शर्तों के आधार पर ध्यान में रखा जा सकता है।

(अ) कि यह भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी।

(ब) कि विषयान्तर्गत भवन राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार निर्मित किया जायेगा एवं सम्पूर्ण प्रकार के फर्नीचर व सामान आदि बसाये जायेंगे तथा विभाग द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे, तथा

(स) कि ऐसा बनाया गया भवन तथा इसके सम्पूर्ण फर्नीचर एवं अजारा सभी राज्य सरकार के अधीन रहेंगे।

(२) उप नियम (१) में वर्णित शर्तों के आधार पर, राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों हेतु भूमि की अवाप्ति को प्रभावशील करने वाले कानूनों के अन्तर्गत, भूमि को अपनी कीमत पर या दान-दाता के मूल्य पर या आशिक रूप से दानदाता और आशिक रूप से अपनी स्वयं की कीमत पर कार्य हेतु वांछित भूमि प्राप्त कर सकती है।

(३) भवन निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(४) विशेष मामलों में राज्य सरकार विशेष कारणों द्वारा दानदाता को ऐसे भवन निर्माण करने या निर्माण कार्य चालू करने की आज्ञा दे सकती है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ तक सम्भव हो सके समय की अन्य अनिवार्यताओं को हटिगत रखकर निर्माण कार्य हेतु कन्ट्रोल रेट पर भवन सामग्री वितरण करने का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है।

८. राज्य सरकार उचित मामलों में या यदि ऐसा दानकर्ता द्वारा वांछित हो तो—

(अ) निर्मित भवन के किसी भाग में दानकर्ता की दानशीलता के परिणामस्वरूप दानकर्ता के नाम व उसके अन्य विशेष विवरण को वर्णनात्मक शिलालेख खुदवाने की आज्ञा प्रदान कर सकती है।

(ब) दानकर्ता के नाम पर उस सार्वजनिक शिक्षण संस्था का नाम रखने हेतु प्रस्तुत सकती है या दानकर्ता द्वारा प्रस्तावित अन्य व्यक्ति का नाम रखने हेतु राजी हो सकती है ।

६. इन नियमों के अन्तर्गत सहायता स्वरूप सभी प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी तथा उचित विचार किया जायेगा ।

१०. जब इन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता लेना स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्वीकृति के तथ्य मय उसकी सम्पूर्ण सूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

सहायक सचिव
शिक्षा (स) विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

Sd/एस. के. जिवू
सचिव, शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ट १

१. उप संचालकों एवं निरीक्षकों द्वारा क्रमशः संचालक शिक्षा विभाग एवं उप संचालक, शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने वाले सामयिक विवरण पत्रः—

	उप संचालक शिक्षा विभाग को	संचालक शिक्षा विभाग को
१. रिक्त स्थानों की मासिक सूची	अगले माह की ५ तारीख	अगले माह की ५ तारीख
२. मासिक उपस्थिति प्रत्यावृत्त का अर्ध मासिक विवरण	द्वितीय तिमाही की १५ तारीख
३. अगले वर्ष अतिरिक्त अव्यापक एवं नयी शालायें खोलने की आवश्यकता की सूची के साथ बजट अनुमान	प्रत्येक वर्ष की १५ अगस्त	प्रत्येक वर्ष की ३१ अगस्त
४. कृषि क्षेत्रों (Agricultural forums) से सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन	प्रत्येक वर्ष की १ अगस्त	प्रत्येक वर्ष की १६ अगस्त
५. सहायना अनुदान के लिए अनुशंसायें (Recommendations)	प्रत्येक वर्ष की १५ जुलाई	प्रत्येक वर्ष की ३१ जुलाई
६. आय व्यय का मासिक विवरण	अगले माह की १० तारीख	अगले माह की १० तारीख

७. निवृत्ति वेतन एवं निवृत्ति
पारितोषिक (Pension &
Gratuity) का मासिक
विवरण

अगले माह की
१५ तारीख

८. विश्राम वृत्ति प्राप्त अधि-
कारियों का त्रैमासिक प्रत्यावृत्त

अगले माह की १५ तारीख,
अर्थात् १५ अप्रैल, १५ जुलाई
१५ अक्टूबर एवं १५ जनवरी

९. स्थापन प्रत्यावृत्त

प्रत्येक वर्ष की ३१ मई
(महालेखापाल को भेजना है)

नोट:—निरीक्षक शिक्षणालय ऐसे विवरण पत्रों को अपने उच्चाधिकारियों के पास भेजने से
कम से कम १० दिवस पूर्व तथा इसी प्रकार के अन्य समान विवरण पत्र अपने
अधीनस्थ अधिकारियों से भंगावेगे।

परिशिष्ट २

सामयिक निरीक्षण

अधिकारी या संस्था का नाम	निरीक्षण अधिकारी का पद	निरीक्षणों के बीच का अन्तर
१. शिक्षा संचालक का कार्यालय	कक्ष अधिकारी	१ वर्ष
२. प्रस्तोता विभागीय परीक्षा का कार्यालय	प्रस्तोता विभागीय परीक्षा	१ वर्ष
३. उप संचालकों के कार्यालय	सम्बन्धित उपशिक्षा संचालक	त्रै मासिक
४. उप संचालकों के कार्यालय	लेखाधिकारी के साथ संचालक शिक्षा विभाग	वर्ष में एक बार
५. स्कूल निरीक्षकों के कार्यालय	सम्बन्धित स्कूल निरीक्षक	वर्ष में एक बार
६. स्कूल निरीक्षकों के कार्यालय	उप संचालक एवं शिक्षा संचालक	वर्ष में एक बार
७. मुख्य कार्यालय से सीधा पत्र न्यवहार करने वाली संस्थाओं के कार्यालय	संचालक शिक्षा विभाग	वर्ष में एक बार
८. मुख्य कार्यालय से सीधा पत्र न्यवहार करने वाली संस्थाओं के कार्यालय	संस्थाओं के प्रधान	६ माह में एक बार

९. इन्टर मीजिएट कालेज	संचालक शिक्षा विभाग	वर्ष में एक बार
१०. महाविद्यालय	आचार्य	६ माह में एक बार
११. उच्च विद्यालय	शिक्षा संचालक	जैसी सुविधा हो
१२. उच्च विद्यालय	उप संचालक शिक्षा विभाग	तीन वर्ष में एक बार
१३. उच्च विद्यालय	शाला निरीक्षक	वर्ष में एक बार
१४. उच्च विद्यालय	प्रधानाध्यापक	६ माह में एक बार
१५. माध्यमिक शाला	निरीक्षक	तीन वर्ष में एक बार
१६. माध्यमिक शाला	उप निरीक्षक	वर्ष में एक बार
१७. माध्यमिक शाला	प्रधानाध्यापक	६ माह में एक बार
१८. प्राथमिक शाला	उप निरीक्षक	३ वर्ष में एक बार
१९. प्राथमिक शाला	महायक उप निरीक्षक	वर्ष में दो बार किन्तु निरीक्षण में ४ माह से कम का अन्तर न हो।
२०. प्राथमिक शाला	मुख्य अध्यापक	त्रै मासिक
२१. सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूल	मुख्य अध्यापक	त्रै मासिक
२२. विशेष शाला	उप संचालक अथवा निरीक्षक	वर्ष में एक बार
२३. विशेष शाला	प्रधानाध्यापक	त्रै मासिक
२४. स्वतन्त्र संस्थापें	उप संचालक, शिक्षा	वर्ष में एक बार

परिशिष्ट ३

सामयिक प्रत्यावृत्त एवं विवरण

(ये अपने तात्कालिक अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने हैं)

प्रत्यावृत्त या विवरण का नाम	किसके द्वारा पेश किए जाने हैं	पेश करने की तारीख
१. सहायक उपनिरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों द्वारा शालाओं के निरीक्षण के सम्बन्ध में विवरण पत्र	निरीक्षक	२० जुलाई वार्षिक

२. वेतन शृङ्खला सूची-	शालानिरीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणाधीन संस्थाओं के प्रधान एवं निरीक्षक	२० जुलाई वार्षिक
३. वार्षिक लेखा	निरीक्षक	१० अगस्त
४. कृषि क्षेत्र की प्रसूचना के साथ वार्षिक प्रशासन प्रसूचना	शाला निरीक्षक के प्रत्यक्ष निरीक्षण में संस्थाओं के प्रधान व निरीक्षक	१५ अगस्त
५. राजकीय सम्पत्ति विवरण	शाला निरीक्षक के प्रत्यक्ष निरीक्षण में संस्थाओं के प्रधान व निरीक्षक	२० अगस्त
६. आय-व्ययक प्रस्ताव	शाला निरीक्षण के प्रत्यक्ष निरीक्षक में संस्थाओं के प्रधान व निरीक्षण	२० नवम्बर
७. सहायता अनुदान की स्वी-कृत्यर्थ अनुशंसा	निरीक्षक	१ जनवरी व १० जून (छठे माह)
८. मासिक लेखा	निरीक्षक	दूसरे माह की १० तारीख
९. नियुक्तिस्थानान्तरण व नि-म्दन का त्रैमासिक विवरण	निरीक्षक	१५ जुलाई, १५ प्रवहवर
१०. सहायक उप निरीक्षकों की निरीक्षण दैनिक पंजिकाओं (टायरियों) का त्रैमासिक विवरण	निरीक्षक	दूसरे माह की १५ तारीख
११. छात्र उपस्थिति का मासिक विवरण पत्र	निरीक्षक संस्थाओं के प्रधान	दूसरे माह की १० ता० दूसरे माह की ५ ता०
१२. छात्र उपस्थिति की मासिक विवरण तालिका	संस्थाओं के प्रधानाध्यापक	दूसरे माह की ५ ता०
१३. शिक्षण शुल्क के विवरण सहित वेतन चिट्ठा	संस्थाओं के प्रधानाध्यापक	प्रत्येक माह की १० तारीख
१४. प्रमाणकों (वाजवरों की) प्रतिनिपियां	संस्थाओं के प्रधानाध्यापक	प्रत्येक माह की १० तारीख
१५. विचारार्थित एवं निर्णय ली गई फाटलों का विवरण	निरीक्षक	अर्द्धवार्षिक १५ जनवरी एवं १६ जुलाई
१६. बी. एड. प्राध्यापक के लिए प्राध्यापकों के प्राधानपत्र	संस्थाओं के प्रधानाध्यापक एवं निरीक्षक	७ फरवरी से पूर्व

परिशिष्ट ४

(अध्याय ४, नियम १०)

निरीक्षण टिप्पणियां

निरीक्षण अधिकारी का किसी शैक्षणिक संस्था से सम्बन्धित प्रतिवेदन निम्न बातों पर प्रकाश डालने वाला होना चाहिए:—

१. कर्मचारी वर्ग

(क) क्या अध्यापकों की संख्या यथेष्ट है तथा क्या वे कार्य कुशलता का एक उचित स्तर बनाये रखते हैं ?

(ख) गत निरीक्षण के बाद से अब तक क्या कोई परिवर्तन कर्मचारी वर्ग में हुआ है ? यदि हुआ है तो क्या और क्यों ?

(ग) क्या कर्मचारियों की योग्यता संतोषप्रद है ? क्या उनमें कोई अयोग्य अथवा कम योग्यता वाले अध्यापक हैं ?

(घ) प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों का क्या अनुपात है तथा किन अध्यापकों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए ?

(च) क्या किसी अध्यापक पर बाह्य उत्तरदायित्व अथवा रुचि है जो कि उसके शाला के कर्तव्य को भली प्रकार निभाने में हस्तक्षेप करता है ?

(छ) सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों में अध्यापक कहां तक भाग लेते हैं ?

(ज) जो विषय पढ़ाते हैं उनमें क्या अध्यापक अपने को पूर्ण जानकार रखते हैं तथा अपनी वक्षाओं के लिए क्या वे प्रतिदिन सावधानी से पाठ तैयार करते हैं, अपने द्वारा पढ़ाए गये पाठों की अध्यापक क्या टिप्पणियां रखते हैं ?

(झ) क्या वे अध्यापन-कला, विद्यालय तथा वक्षाप्रबन्ध, अनुशासन पर पुरतर्क पढ़ते हैं ?

(ट) क्या इस दिशा में संस्था प्रधान अध्यापकों पर अपना प्रभाव डालते हैं अथवा उनको अपने ढंग से काम करने देने से ही वह संतुष्ट है ।

(ठ) संस्था में होने वाले कार्य के सावधिक निरीक्षण की क्या वह टिप्पणियां रखता है और क्या वह अध्यापकों के अध्यापन कार्य की उस समय स्वयं जांच करता है जब कि वे छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हों ?

(ड) क्या कर्मचारी वर्ग की बैठक होती है ? यदि हां तो इस सत्र में कितनी बैठक हुई ? किस प्रकार के प्रश्नों पर उनमें विचार किया गया ? क्या शैक्षणिक समस्याओं तथा विधि पर विचार किया गया ?

(ड) शिक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों, जिनमें संस्था को मान्यता प्राप्त है, को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है ।

(त) अध्यापन एवं रिक्त अन्तरों (Periods) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा विभाग के नियमों का क्या पालन किया जाता है ? प्राइवेट ट्यूशन तथा अन्य कार्य करने के सम्बन्ध में विभागीय निर्देशों का क्या पालन किया जाता है ?

(घ) क्या वेतन नियमित रूप से दिया जाता है ?

(ङ) संस्था प्रधान एक सप्ताह में कितने अन्तर पढ़ाता है ? क्या उसके पास पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त समय है ?

(च) क्या छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है तथा उसका अभिलेख रखा जाता है ? विषयों में दिया गया गृह कार्य क्या भली प्रकार से सम्पन्न, आनुपातिक एवं स्तर वाला होता है ?

२ स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण

(क) क्या शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य है ?

(ख) कौन कौन से खेल होते हैं ? क्या उनको सावधानीपूर्वक आयोजित किया जाता है ? क्या वे अनिवार्य हैं तथा कोई नियमित योजना बना रखी है ? शारीरिक प्रशिक्षण में क्या छात्रों को उचित रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है ?

(ग) खेलों के पर्यवेक्षण के लिए क्या व्यवस्था है ?

(घ) शारीरिक प्रशिक्षक अथवा ड्रिल मास्टर क्या प्रशिक्षित व्यक्ति है ? यदि हां तो उसका प्रशिक्षण कहाँ हुआ ? शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कितने योग्य अध्यापक करते हैं ?

(च) क्या समय-सारणी में निम्नतम कक्षा के लिये खेलों के लिए तथा उच्च कक्षाओं में खेलों तथा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कोई प्रावधान है ?

(छ) क्या संस्था ने स्काउट तथा गर्ल गाइड की प्रवृत्ति प्रारम्भ कर दी है ? उसमें कितने प्रशिक्षित स्काउट मास्टर, कब मास्टर, गाइड्स तथा रोवर लीडर हैं ? कितने ट्रूप्स, पैक्स तथा क्यूज प्रारम्भ कर दिये गये हैं ?

(ज) संस्था में सम्बन्ध क्या कोई क्लब अथवा संघ है ? यदि हां तो उनका क्या उद्देश्य है ? क्या उन पर उचित नियन्त्रण रखा जा रहा है तथा उनके लेखा की अच्छी प्रकार देखभाल की जाती है ?

(झ) क्या संस्था में स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का अध्यापन तथा पालन सन्तोषजनक है ।

(ट) क्या छात्रों की चिकित्सा जांच की कोई व्यवस्था है ? रोगों से कितने प्रतिशत छात्र मुक्त है ? क्या उनकी देखभाल सन्तोषजनक तौर पर होती है क्या तोलने की मशीन है ? क्या विद्यालय में कोई जूनियर रेडक्रॉस ग्रुप है ?

(ठ) क्या संस्था का कोई क्रीडांगण अथवा व्यायाम शाला है ? क्या बड़े व छोटे छात्रों के खेलने के लिए पर्याप्त क्रीडांगण है ? क्या वे संस्था से संलग्न हैं ?

(ड) खेलरूढ़ व स्कार्पटिंग के लिये क्या वित्तीय प्रावधान है ?

(ढ) क्या छात्रों की स्वास्थ्य प्रगति पत्रिकाएँ उनके अभिभावकों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ?

(ण) क्या छात्रों के चेचक का टीका लगा दिया गया है ? यदि हां तो, कितने छात्रों के, तथा और किसनों की उसकी आवश्यकता है ?

(प) क्या छात्रों के खाने की व्यवस्था सन्तोषजनक है ?

३. पुस्तकालय

(क) पुस्तकालय के खुले रहने का क्या समय है ?

(ख) पुस्तकालय-अनुदान की रकम तथा पुस्तकालय और वाचनालय शुल्क, यदि कोई हो, से आय कितनी है ?

(ग) पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या तथा विषयवार उनकी संख्या कितनी है ? गत सत्र में कुल कितनी पुस्तकें, किस किस विषय की कितनी तथा कितने कीमत की पुस्तकालय में आई ? क्या कक्षा पुस्तकालय भी है ? यदि हां, तो उनका गठन एवं शक्ति कितनी है ?

(घ) क्या पुस्तकालय के लिये कोई उपयुक्त पुस्तक सूची है ? क्या छात्रों तथा अध्यापकों को पुस्तकें उधार देने के लिये अलग अलग रजिस्टर है ? क्या पुस्तक सूची तथा ये रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते हैं ?

(च) क्या पुस्तकालय की पुस्तकों का अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा उचित उपयोग किया जाता है ? गत पूरे सत्र तथा प्रत्येक माह में अध्यापकों तथा छात्रों को कुल कितनी पुस्तकें दी गई ।

(छ) क्या पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग बाहर के लोगों द्वारा भी किया जाता है ?

(ज) पुस्तकालय को व्यवस्थित रखने के लिये कौन भार-वहन करता है ?

(झ) पुस्तकों की दशा कैसी है ? क्या पुस्तकालय की स्थिति ठीक है ?

(ट) अध्यापकों द्वारा ली जाने वाली पुस्तकें क्या उनके विद्यालय के कार्य से सम्बन्ध रखती हैं ।

(ठ) क्या पुस्तकालय में कोई अनुचित पुस्तकें भी है ?

(ड) क्या विद्यालय में एक वाचनालय है ? वहां कौन कौन से पत्र आदि मंगवाये जाते हैं ? क्या वे छात्रों तथा अध्यापकों के लिये उचित हैं ?

४. भवन व स्वास्थ्य

(क) विभिन्न विषयों के कार्यों के लिए क्या समुचित स्थान है ? क्या उसे मरम्मत की आवश्यकता है ?

(ख) क्या विद्यालय भवन की स्थिति तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकतायें सन्तोषजनक हैं ?

(ग) क्या विद्यालय के निकट कोई खुली हुई नालियां हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या उचित देखभाल होती है ?

(घ) विद्यालय के अहाते में या आसपास क्या कोई कूड़े के ढेर हैं ?

(च) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था क्या यथेष्ट है तथा ठीक तरह रखी जाती है ? क्या मूचालय तथा शौचालय बने हुये हैं ? यदि हां तो कितने ?

(छ) क्या पीने के पानी का प्रबन्ध सन्तोषजनक है ? क्या वर्तन व जगह नियमित रूप से साफ की जाती है ?

(ज) क्या प्रकाश व हवा काफी आती है ? क्या प्रकाश छात्रों के बाईं ओर से आता है ?

(क) क्या कक्षा में, प्रत्येक छात्र को १० वर्ग फीट जगह के अनुपात पर स्थान दिया गया है ?

(ट) क्या छात्रों के लिये कोई सभा कक्ष है ?

(ठ) क्या संस्था प्रधान के लिये कोई अलग कार्यालय कक्ष है ? क्या स्टाफ के लिये कोई अलग कक्ष है ?

५. छात्रावास

(क) संस्था से कौन कौन से छात्रावास सम्बद्ध हैं तथा उनमें प्रत्येक में कितने छात्र रहते हैं ? क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई अधीक्षक रहता है और वह अपना कर्तव्य पालन कैसे करता है ?

(ख) प्रत्येक छात्र को दी गई जगह की माप क्या है ? क्या बड़े कमरे में प्रत्येक छात्र को कम से कम ५० वर्गफीट जगह दी गई है ?

(ग) छात्रावास के किसी कमरे में क्या कोई केवल २ छात्र रहते हैं ?

(घ) क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई केन्द्रीय कक्ष है ?

(च) किस आधार पर शौचालय व सूत्रालय बनाये गये हैं ? क्या वे क्रमशः ८ तथा ३ प्रतिशत के अनुपात पर बने हुये हैं ?

(छ) क्या संस्था प्रधान छात्रावास पर कोई पर्यवेक्षण रखता है ?

(ज) क्या छात्रावास के प्रबन्ध के लिये कोई नियम बने हुये हैं ? क्या ये नियम सक्षम अधिकाारी द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं ?

(झ) क्या अध्ययन कक्षाओं व निवास कक्षाओं में रात को प्रकाश की व्यवस्था संतोषजनक है ?

(ट) क्या जल वितरण की व्यवस्था यथेष्ट तथा सफाई व्यवस्था संतोषजनक है ?

(ठ) क्या रसोई घर की व्यवस्था अच्छी व संतोषजनक है ?

(ड) क्या यह नियम लागू है कि यदि छात्र अपने माता पिता या स्वीकृत अभिभावक के साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें संस्था से सम्बद्ध छात्रावास में रहना अनिवार्य है ?

(ढ) क्या छात्रों को व्यस्त रहने के लिये Indoor खेलों तथा मनोरंजन के अन्य साधनों का समुचित प्रावधान है ?

६. अध्ययन-क्रम

(क) क्या विश्वविद्यालय अथवा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है ? यदि नहीं, तो उनकी कौन सी बात का पालन नहीं किया जा रहा है ?

७. उपकरण तथा फर्नीचर

(क) विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण (Apparatus) तथा शाला का फर्नीचर समुचित, उपयुक्त तथा अच्छी दशा में है ?

(ख) क्या फर्नीचर, काले तस्ते, मानचित्र तथा अन्य उपकरण कक्षा-कक्षाओं में उचित रूप से रने हुये हैं तथा वे उनका उचित उपयोग होता है ?

(ग) क्या छात्रों के पास आवश्यक पाठ्य पुस्तकें, मानचित्रावली, रेखागणित के उपकरण आदि हैं ?

(घ) क्या अध्यापक, छात्रों को चार्ट, मानचित्र तथा शिक्षा में सहायक अन्य चीजों को तैयार करने के लिये, मार्ग दर्शन एवं व्यक्तिगत उदाहरण से प्रोत्साहित करते हैं ?

८. उपस्थिति

(क) क्या उपस्थिति का प्रतिशत सन्तोषजनक है ?

(ख) उपस्थिति कब ली जाती है ? क्या वह नियमित रूप से व ठीक समय पर ली जाती है ?

(ग) क्या अनुपस्थिति के लिये जुर्माना किया जाता है ? क्या अनियमित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है ?

(घ) क्या निर्धारित छुट्टियां तथा ग्रीष्मावकाश दिये जाते हैं ? अनाधिकृत छुट्टियां अथवा अतिरिक्त अवकाश देने की क्या कोई प्रवृत्ति है ?

(च) गत सत्र में बैठकों (Meetings) की संख्या कितनी थी ?

(छ) क्या एक ही समय में एक ही कक्षा या उसके खण्ड में पढ़ाये जाने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित से अधिक है:—

कक्षा ११ व १२—५०

कक्षा ६ से १०—४५

प्राथमिक कक्षाएँ—४०

९. अनुशासन

(क) क्या निर्धारित प्रपत्र में प्रगति पुस्तिकाएँ नियमित रूप से जारी की जाती हैं ?

(ख) क्या संस्था व छात्रावास में अनुशासन सन्तोषजनक रूप में बनाये रखा जाता है ?

(ग) छात्रों के व्यवहार, उनकी प्रतिभा, उनकी स्वच्छता आदि से संस्था की सामान्य स्थिति का क्या पता चलता है ?

(घ) दिये जाने वाले दण्डों के सामान्यतः कौन कौन से प्रकार हैं ?

(च) क्या जुर्मानों में अधिकांशतया छूट दे दी जाती है ?

१०. कक्षा का कार्य

(क) संस्था में शैक्षणिक सहायता की क्या कोई प्रथा है ?

(ख) सत्र में कक्षा में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों तथा किये जाने वाले कार्य का क्या उचित रीति से विभाजन कर दिया गया है ?

(ग) क्या अध्यापक, डायरी रखते हैं ? यदि हाँ तो, क्या वे निर्धारित प्रपत्र में है तथा उनको ठीक प्रकार से रखा जाता है ? क्या संस्था प्रधान उनकी नियमित रूप से जाँच करते हैं तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिये सुझाव देते हैं ?

(घ) होशियार व कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देते हुए क्या अध्यापक समस्त कक्षा पर

अपना ध्यान भली प्रकार विभाजित करता है ।

(च) क्या संस्था में लिखित अभ्यासों पर पूरा जोर दिया जाता है ? क्या अभ्यास पुस्तिकायें साफ तथा उचित श्रेणी की हैं ? क्या उनमें एकरूपता है ? क्या उनकी सावधानी से जांच की जाती है ? क्या संस्था प्रधान द्वारा इन अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच नियमित रूप से की जाती है ?

(छ) क्या प्रत्येक कक्षा के लिये समय सारिणी है ? यदि है तो उसमें कोई दोष है क्या ?

(ज) कुंजियों के उपयोग पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, क्या उसका सख्ती से पालन किया जाता है ?

(झ) अध्यापन-विधि में मुख्य दोष क्या है ?

(ट) क्या लिखित या मौखिक प्रबन्ध कार्य पर उचित रीति से ध्यान दिया जाता है ?

(ठ) क्या स्वच्छ एवं अच्छे हस्ताधारों तथा संक्षिप्त अभिव्यक्ति पर पूरा ध्यान दिया जाता है ? क्या छात्रों को चित्रकला के लिए खूब प्रोत्साहन दिया जाता है ?

(ड) विचारों की मौखिकता तथा सृजनात्मक विचारों के लिए क्या छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है ?

(त) विद्यालय में किस प्रकार की हस्तकला सिखाई जाती है ? यदि कोई नहीं पढ़ाई जाती है, तो अध्यापकों को क्या सुझाव दिये गये हैं ?

(थ) क्या विद्यालय में कोई उद्यान है ? यदि है तो, किस उद्देश्य से बनाया गया है ?

११. कार्यालय

(क) विगत निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को क्या कार्यान्वित कर दिया गया है ?

(ख) क्या प्राप्त पत्रों पर समुचित ध्यान दिया जाता है ?

(ग) क्या पत्र व्यवहार का विधि मन्तोपजनक है ?

(घ) क्या सब रजिस्टर व फाइलें उचित रीति में व्यवस्थित हैं ?

(च) संस्था में प्रवेश लेने वाले छात्रों में क्या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं तथा छोड़ने वालों को क्या वे दिये जाते हैं ? संस्था में प्रवेश लेने वाले छात्रों से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों को क्या उचित रीति में फाइल किया जाता है ? ऐसे छात्रों, जो कि अन्य राज्यों की शिक्षा संस्थाओं से आते हैं, के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित राज्य के सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित है ?

(छ) छात्रों की वास्तविक आयु मापन करने के प्रति क्या सावधानी रखी जाती है ? प्रवेश प्रार्थना पत्र क्या छात्रों के माता पिताओं, प्रगवा संस्थाओं द्वारा भली प्रकार भरे जाते हैं तथा क्या उन्हें भली प्रकार रखा जाता है ?

(ज) क्या छात्र विवरण मन्तोपजनक रूप में रक्ते जाते हैं तथा उनमें क्या प्रादिनांक अर्थात्प्रा की जाती है ?

(झ) क्या अध्यापकों का व्यवस्थित रजिस्टर है ? क्या अध्यापक अपने संस्था-प्रधान के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाने के लिये क्या वे मरने जाते तथा मरने का वास्तविक समय

भंजित करते हैं ? क्या अध्यापक समय के पाबन्द है ?

(ट) क्या छुट्टियों में नियमों का पालन किया जाता है ?

(ठ) छात्रों के प्रवेश तथा स्थानान्तरण के नियमों का क्या पालन किया जाता है ?

१२. वित्त

(क) क्या लेखा प्रया सन्तोषजनक हैं ? क्या वे लेखक द्वारा तैयार किए जाते हैं, संस्था प्रभाग द्वारा जांचे जाते हैं तथा नियमित रूप से आडिट किये जाते हैं ? सहायता प्राप्त संस्था होने पर, क्या उसके लेखा एक स्वीकृत आडिटर द्वारा नियमित रूप से आडिट किये जाते हैं ?

(ख) विगत वित्तीय वर्ष की आय तथा व्यय क्या निर्धारित मदों के अन्तर्गत प्रविष्ट कर लिए गये हैं ?

(ग) क्या भुगतान सीधे से किया जाता है ? क्या अध्यापकों तथा छात्रवृत्ति पाने वालों की प्रादिनांक तक भुगतान कर दिया गया है ?

(घ) क्या अध्यापकों के वेतन-अदायगी बिल भली प्रकार रखे जाते हैं ? क्या वेतन, वेतन-शुल्कलाभों में निबद्ध हैं ? यदि हाँ, तो क्या वार्षिक वेतन वृद्धियाँ नियमित रूप से दी जाती हैं ?

(च) क्या खेलकूद, परीक्षा, पुस्तकालय तथा वाचनालय की निधियों के अलग लेखा रखे जाते हैं ?

(छ) विद्यालय की विभिन्न निधियों का आय व्ययान्तर (balance) क्या स्वीकृत बैंक में जमा कराया जाता है ?

(ज) संस्था की आय के कौन कौन से साधन हैं तथा संस्था को हानि हो रही है, प्रयत्न लाभ ? शेष धनराशि, यदि कोई होवे, तो उससे क्या किया जाता है ?

(झ) क्या चन्दा देने वालों की, यदि कोई हो, सूचियाँ रखी जाती हैं ? क्या उनके प्राप्त होने की तारीख दिखाई जाती है ?

(ट) क्या संस्था की कोई पूंजी (Capital) है ?

(ठ) क्या कोई रकम, वर्तमान आय में से स्वाई कार्यों या भवन बनाये तथा फर्नीचर के लिए निकालकर अलग रखी गई है ?

(ड) प्रत्येक कक्षा की शुल्क की क्या दर है ? क्या शुल्क निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाता है ? यदि नहीं, तो उनमें परिवर्तन के क्या कारण हैं ? क्या वे प्रति माह और पूरी वसूल की जाती हैं ?

(ढ) निःशुल्क तथा अर्धशुल्क तथा छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी हैं ? क्या यह संख्या नियमों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है ? क्या निःशुल्क तथा अर्धशुल्क वाले छात्रों की प्रगति सन्तोषजनक है ?

(ण) क्या कोई संचित निधि बनाई गई है ? उसमें कितनी धनराशि है । उसको कहाँ लगाया जाता है ?

१३. परीक्षा

(अ) संस्था निम्नलिखित में कैसी रही:—

(१) हाल ही की सार्वजनिक परीक्षा में

(२) विगत निरीक्षण के बाद से त्रैमासिक परीक्षाओं में

(ब) क्या संस्था ने सार्वजनिक परीक्षा में कोई छात्रवृत्ति पाई ? यदि हां तो उसकी संख्या नाम तथा रकम

(स) क्या छात्रों को उन्नतियां विभागीय नियमों के अनुसार दी गई है ?

१४. प्रबन्ध (निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए)

(क) प्रबन्ध समिति का संविधान यदि कोई होवे तो, कैसा है, तथा उसके सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है ?

(ख) क्या समिति नियमित रूप से गठित है तथा उसने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करली है ?

(ग) प्रबन्ध समिति के गठन में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं ? समिति के सदस्यों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, क्या उन सब पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ?

(घ) क्या उसके कार्य संचालन के नियम संतोषजनक हैं ?

(च) क्या उसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं ?

(छ) क्या कोई ऐसा संकेत है कि समिति पर किसी का प्रभुत्व होवे ?

(ज) क्या अध्यापकों के सेवा की शर्तें ऐसी हैं कि वे कार्य जारी रखने में सुरक्षित महसूस करें ? यदि नहीं तो, उनमें अत्यधिक परिवर्तन के क्या कारण हैं ? स्टाफ में हुये समस्त परिवर्तनों, चाहे वे नियुक्ति, बर्खास्तगी, निलम्बन से हुए हों, को क्या सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत कर दिया है ? क्या अध्यापकों की नियुक्ति किसी स्वीकृत समझौते के अनुसार होती है ?

१५. अन्य टिप्पणियां

१. (क) अन्य कोई विवरण जो कि निरीक्षण अधिकारी आवश्यक समझे ।

(ख) निरीक्षण अधिकारी का शिक्षण संस्था पर प्रतिवेदन निम्न बातों पर भी प्रकाश डालें:—

१. क्या भवन राजकीय है अथवा किराये का ?

२. क्या वह यथेष्ट तथा उपयुक्त है ?

३. यदि किराये का है तो, सरकारी भवन बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

२. फर्तीचर:—

(अ) उसकी दशा तथा यथेष्टता

(ब) क्या स्टाफ बुक आदिनांक तक पूरी है तथा क्या वितरण उसमें की गई प्रविष्टियों से मेल खाता है ?

(स) क्या बेकार सामान को नियमित रूप से पारिज कर दैते हैं ताकि वह अनावश्यक जगह नहीं घेरे ?

(द) क्या उचित प्रपत्र में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं ?

३. मानचित्र तथा संदर्भ पुस्तकें, जो कि निर्धारित हैं, क्या ठीक प्रकार से रखी जाती हैं तथा क्या उन्हें स्टाफ बुक में प्रविष्ट किया जाता है ?

४. पुस्तकालय

(अ) पुस्तकालय की यथेष्टता तथा उपयुक्तता

(ब) क्या पुस्तकालय की पुस्तकों को कार्यालय, रजिस्टर में अंकित किया जाता है तथा उन्हें वर्गीकृत किया जाता है ?

५. लेखक वर्ग—

(अ) नाम, योग्यता, सेवा तथा वर्तमान वेतन ।

(ब) क्या उनमें कार्य का वितरण उचित है ?

(स) क्या कैशियर ने अपनी जमानत दे रखी है तथा क्या उसे प्रतिवर्ष नवीन किया जाता है ? यदि उसने जमानत नहीं दे रखी है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

६. कैश बुक—

(अ) क्या कैशबुक की प्रतिदिन जांच की जाती है तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ?

(ब) क्या कोषागार से निकाला हुआ खपया अविलम्ब वितरित किया जाता है ?

(स) क्या आयव्यान्तर को विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाता है ?

७. क्या निर्धारित रजिस्टर रखे जाते हैं तथा उनमें प्रविष्टियां आदिनांक तक की जाती हैं ?

८. कोष-तिजोरी की दशा:—

(अ) क्या वह सुरक्षित है तथा उसकी चाबियां उचित नियन्त्रण में रखी जाती हैं ?

(ब) क्या आयव्यान्तर की एकम कैशबुक से मेल खाती है ?

(ग) क्या कभी आय व्ययान्तर (Cash balance) केशियर की जमातत की रकम से अधिक हो जाती है, यदि हां तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है ?

(द) क्या रकम की जांच प्रतिमाह की जाती है तथा संस्था प्रधान द्वारा भी कभी क्या आकस्मिक जांच की जाती है ? क्या कभी प्रविष्टियों को प्रमाणक (Voucher) से मिलाया जाता है तथा केश बुक में इस तथ्य का कोई प्रमाणपत्र दिया जाता है ?

६. क्या स्थायी तौर पर दी गई अग्रिम धनराशि (Permanent Advance) सही है तथा समय समय पर खर्चों की रकम को उसमें पूरा किया जाता है ।

१०. क्या यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत हैं ?

११. क्या निरीक्षण डायरी में प्रविष्टियां रोजाना की जाती हैं ?

१२. क्या कार्यालय कलेण्डर रखा जाता है ?

१३. क्या आवश्यक आंकड़े आदिनांक तक रखे जाते हैं ?

१४. क्या अधिकारी के नियन्त्रण में रहने वाली सेवा पुस्तकियों विभागीय आदेशों तथा सरकारी परिपत्रों के अनुसार समय समय पर भरी जाती हैं ?

१५. क्या निरीक्षण प्रतिवेदनों को उचित रीति से फाइल किया जाता है ?

१६. नियतकालिक प्रतिवेदन व प्रत्यावर्त (Periodical Reports & Returns)

(अ) क्या उस कार्यालय से भेजे जाने वाले समस्त नियतकालिक प्रतिवेदनों तथा प्रत्यवर्तों की एक सूची रखी जाती है ?

(ब) क्या उनको ठीक समय पर प्रेषित किया जाता है ?

(स) क्या उनकी कार्यालय प्रतिलिपियां ठीक ठीक पर फाइल की जाती हैं ?

१७. नई स्वीकृतियों का रजिस्टर क्या रखा जाता है तथा उसमें समय समय पर क्या प्रविष्टियां की जाती हैं ?

१८. प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों को समय समय पर लिख लेने के लिए क्या कोई फाइल रखी जाती है ?

१९. अभिलेखों की समाप्ति—क्या समस्त अनुपयोगी अभिलेख समय समय पर प्राप्त सरकारी नियमों के अनुसार समाप्त कर दिये जाते हैं ?

२०. सामान्य अभ्युक्ति (General Remarks)

परिशिष्ट ५. [अ]

(देखिये अध्याय ४ नियम ४)

शिक्षा विभाग

निरीक्षण-पत्र

नाम शाला प्राथमिक/उच्च/उच्चतर जिला

मरकरी या मान्यता प्राप्त तहसील

पाठशाला के प्रधान का नाम निरीक्षक का नाम पद

..... इस शाला में कब से है ।

..... निरीक्षण समय

दिनांक निरीक्षण { गत वर्तमान

१. छात्र विवरण

क्रम क्रमांक संहिता	निरीक्षण के समय					निरीक्षण के समय			
	छात्र संख्या					छात्र विवरण			
	रजिस्टर में अंकित					उपस्थिति			
	समस्त	पुष्कल	जाति	अनुसूचित जाति	पुर्णगोत्रित जाति	योग	पूर्ण शैक्षणिक शुल्क मुक्त छात्र संख्या	अर्द्ध शैक्षणिक शुल्क मुक्त छात्र संख्या	छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र संख्या
viii									
vii									
vi									
v									
iv									
iii									
ii									
i									

छात्रों की संख्यानुसार उपयुक्त स्थान, कर्नावर इत्यादि पर विशेष टिप्पणी ।

२. ग्रन्थ्यापक अनुचर आदि का विवरण

क्र.सं.	नाम सिद्धांत अनुचर आदि	पद	योग्यता मम विषय के	जन्म दिनांक	मासिक वेतन रु. में	काल		निवास स्थान	प्रत्येक सप्ताह में विश्रान्ति कालान्तर संख्या	चाहू क्रियात्मक प्रवृत्तियों में कार्य का विवरण
						इस साला में	इस विभाग में			
१										
२										
३										
४										
५										
६										
७										
८										
९										
१०										

स्टाफ छात्रा के योग्य हैं या नहीं—३. (प्र) व्यवस्था का विवरण (मान्यता प्राप्त शालाओं के लिए) :—

४. अध्यापक वार समय सारणी

(ब) शाला की आर्थिक दशा:—

[illegible]

५. शिक्षण स्थिति (कक्षावार ध्यौरा) :—

viii
vii
vi
v
iv
iii
ii
i

६. शाला कार्यालय विवरण

रजिस्टर आदि	विवरण	अभ्युक्ति
१	२	३
—		

७. ग्रन्थ प्रभिलेख :—

८. शाला व पुस्तकालय

विषय	पुस्तकों की संख्या	दी गई		सामयिक पत्रिकाएँ जो दी गई	विशेष विवरण
		छात्रों को	अध्यापकों को		
१	२	३	४	५	६

६. छात्रावास :—

१०. शाला का अनुशासन और व्यवस्था—

११. शाला का सामान और पढ़ाई की पुस्तकें आदि—

१२. पाठशाला भवन तथा स्वच्छता—

१३. व्यायाम खेल और स्वास्थ्यः—

१४. स्कार्टिंग और काविय गाइडिंग-बुल बुलः—

१५. अन्य प्रवृत्तियां—

१६. गत परीक्षा और उनका परिणामः—

सन् १९..... ई०

viii
vii
vi
v
iv
iii
ii
i

१७. विशेष वृत्तान्त और सुझावः—

तारीख .. सन् १९६..... ई०

निरीक्षण अधिकारी

क्रम संख्या ..

दिनांक ..

प्रतिनिधि सूचनार्थ प्रेषित ..

.....

निरीक्षण अधिकारी

परिशिष्ट ५ (ब)

(देखिये अध्याय ४, नियम ४)

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग

निरीक्षण—पत्र

प्राथमिक पाठशाला सहसील योयता
 समय कब से है

सारीख निरीक्षण/इससे पहले
 वर्तमान

१. छात्र संख्या

नाम कक्षा	रजिस्टर में उपस्थिति निरीक्षण के समय				रजिस्टर में उपस्थिति	निरीक्षण के दिन उपस्थिति गत निरीक्षण
	वर्तमान निरीक्षण					
	पिछड़ी जाति	जाति	अनुसूचित जाति	अन्य		
१						
२						
३						
४						
५						
६						
७						
८						
९						
१०						

- (व) शुल्क स्थानान्तरण-पत्र
 (स) अनुपस्थिति दण्ड
 (द) अन्य
- (२) छात्र कोष निधि
 (अ) क्रीड़ा निधि
 (ब) परीक्षा निधि
 (स) वाचनालय निधि
 (द) अन्य

अन्य रजिस्ट्रों की दशा और वृत्तान्त—

६. शाला का सामान और पढ़ाई की पुस्तकें आदि—

७. शाला का मकान व स्थान बगीचा आदि।

७. शाला का पुस्तकालय—

पुस्तकों की संख्या	काल के प्रारम्भ में पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या		नाम छात्र इत्यादि जो शाला में आते हैं
	अध्यापक	छात्र	

८. व्यायाम खेल व स्वास्थ्य:—

पेक रजिस्टर्ड है या नहीं कब मास्टर का नाम

कब्स की संख्या.

रेकूट	टेन्डर पैड	फर्स्ट स्टार	सैकंड स्टार	मीजान	योग्यता के वैज	

विशेष वृत्तान्तः—

११. यूनिवर रेडक्रासः—

१२. व्यवस्थापिका समिति

१३. शाला की माली हालतः—

१४. विशेष वृत्तान्त (लिखाई व पढ़ाई):—

१५. उद्योगः—

१६. भोजन व स्वास्थ्यः—

१७. व्यक्तिगत स्वास्थ्यः—

१८. ग्राम सुधारः—

१९. शाला का शासनः—

२०. सामान्य अभ्युत्थियां

तारीख ... १९६

निरीक्षण अधिकारी

नोटः—नम्बर १३ व १४ के छाने केवल सहायता प्राप्त व स्वतन्त्र पानागों के निरीक्षण के समय भरे जावें ।

परिशिष्ट ६

(देखिये अध्याय १२ नियम ११)

प्रपत्र 'अ'

(देखिये नियम संख्या १)

राजस्थान सरकार

राज पत्रित एवं अराजपत्रांकित अधिशासी अधिकारियों के वर्ष..... के लिये
वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ।

भाग १ (विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु)

१. अधिकारी का नाम

जन्म तिथि

२. वर्ष जिसमें नियुक्ति की गई (मय तारीख) तथा वेतन एवं वेतन शृंखला

३. सम्बन्धित पद के लिए अभियोद्यता जिसमें कोई विशेष तकनीकी एवं व्यवसायात्मक
प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं

४. वर्ष में अधिकारी ने किस प्रकार से अपना कार्य किया अर्थात् क्या सन्तोषजनक या
अन्यथा (सन्तोषप्रद कार्य के विशिष्ट उदाहरण) यदि विपरीत लिखा जावे तो इस सम्बन्ध में प्रसारित
किये गये आदेश की संख्या एवं दिनांक

५. क्या अधिकारी में ये बातें पाई जाती हैं ? :—

(अ) धैर्य

(ब) तरीका

(स) शिष्टाचार

(द) जनता के साथ तथा सहायक एवं उच्च स्टाफ के साथ जिनके वह सम्पर्क में आता
है, उनके साथ व्यवहार में निष्पक्षता ।

६. क्या अधिकारी में निम्न बातें पाई जाती हैं :—

(अ) सच्चरित्रता ?

(ब) सुगठित शरीर ?

७. क्या अधिकारी :—

(अ) शारीरिक रूप से उत्साहात्मक है ?

(ब) मोतसिक रूप से सचेष्ट है ?

८. क्या अधिकारी में :—

(अ) प्रेरणा देने एवं अपनी बात मनवाने की सामर्थ्य है ?

(ब) नियन्त्रण करने की शक्ति है ?

(स) प्रयुक्ति की शक्ति है ?

६. क्या अधिकारी कोई विशेषता रखता है तथा या ऐसी कोई विशेष योग्यता या गुण रखता है जो उसकी उन्नति और सेवा में उच्च नियुक्ति के लिए किए गए उसके विशिष्ट चयन को न्यायोचित ठहरा सके ।

१०. (अ) क्या प्रतिवेदित अधिकारी (Officer under report) पर्याप्त मात्रा में यात्रा करता है ?

(व) क्या वह अपने सहायक अधिकारियों के साथ घण्टे सम्पर्क बनाये रखता है तथा उन पर नियन्त्रण रखता है ? तथा क्या वह कार्य को अपूर्ण उनके हाथों में छोड़ देता है ?

(स) क्या वह अधीनस्थ क्षेत्र की सामान्य जनता के सम्पर्क में रहता है ?

नोट:—सरकार के लिए दौरो का बहुत महत्व है इसलिए प्रतिवेदन में इस मद के अधीन दिये गए शीर्षकों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करना चाहिए ।

११. विशेष विवरण:—

प्रतिवेदन में सामान्यतया उन तरीकों पर टिप्पणी लिखी जानी चाहिए जिनमें अधिकारी नौ वर्ष में विभिन्न कार्यों को पूरा किया है तथा उसे उसके व्यक्तित्वो चरित्र एवं योग्यता तथा अपने साथी अधिकारी एवं सार्वजनिक जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने आदि के बारे में एक-सम्मति दी जानी चाहिए । किसी-विषय पर इसमें अपने द्वारा टिप्पणी लिखी जानी चाहिए । विशेषकर उन विषयों पर जिनकी किसी भी समय ऐसी आवश्यकता पड़े यथा कार्यकुशलता दक्षता बरी (Efficiency Bar) को पार करने की योग्यता और तकनीकी विभागों के सम्बन्ध में व्यवसायात्मक योग्यता और योग्यता आदि के बारे में (जब अधिकारी स्वयं के बारे में प्रतिवेदन नहीं कर रहा हो) प्रतिवेदित अधिकारी की कार्यकुशलता एवं चरित्र पर विभागाध्यक्षों की सम्मति ।

विभागाध्यक्ष

भाग २—स्वच्छतापूर्ण भरा जाना चाहिये एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

१. नाम

२. पिता का नाम

३. स्वयं का जिला

४. जन्म तिथि

५. पद

६. शिक्षा या योग्यता

६. किसी अधिकारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की अवल सम्पत्ति में परिवर्तन

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ १ से ७ तक में दी गई सूचना अभिलेख से मिलाती गई है तथा सही है।

कार्यालयीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म 'ब'

देखिये नियम १

.....विभाग

१९५.....वर्ष के लिए कर्मचारी अधिकारियों पर गोपनीय वार्षिक प्रतिवेदन।

नाम

पद शाखा

(अ) जन्म तिथि

(व) राजकीय सेवा में प्रविष्टि की तिथि.....

वर्तमान वेतन शृंखला.....प्रतिवेदन के फार्म 'ब' को भरने के लिए परिशिष्ट

‘प्र’ देखिये ।

खण्ड १-वर्तमान वेतन शृंखला में कर्तव्यों का पालन करना ।

- | | | |
|---|--------------|-------------|
| १. ज्ञान | दिये गये अंक | विशेष विवरण |
| (अ) शाखा का | | |
| (ब) विभाग का | | |
| २. चरित्र का प्रभाव एवं व्यक्तित्व | | |
| ३. निर्णय | | |
| ४. उत्तरदायित्व वहन करने की शक्ति | | |
| ५. सूत्रपात (Initiative) | | |
| ६. परिशुद्धता | | |
| ७. भाषण एवं वाचुर्य | | |
| ८. पर्यवेक्षण कर्मचारियों की शक्ति | | |
| ९. सत्साह एवं परिश्रम | | |
| १०. स्वास्थ्य | | |
| ११. उपस्थिति (नोट २ देखिये) | | |
| १२. कार्यालय सम्बन्धी आचरण (अनुशासन) (नोट २ देखिये) | | |
| १३. (अ) टिप्पणियाँ लिखने की योग्यता | | |
| (ब) प्रारूप बनाने की योग्यता | | |

सामान्य विवरण (विग्वस्नीयता एवं प्रमाणिकता) (Integrity) के विवरण को सम्मिलित करते हुये तथा ऐसी कोई विशेष योग्यता का वर्णन जिसको उपरोक्त में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

खण्ड २-उन्नति हेतु योग्यता की मात्रा ।

निम्न में से एक को छोड़कर सबको विमुक्त कर दो-

असाधारण योग्य/उच्च योग्यता प्राप्त/योग्यता प्राप्त/अभी तक योग्यता प्राप्त न करने वाला ।

विशेष विवरण—

मैं एवद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय के अनुसार अधिकारी का आचरण कार्य कुशलता का स्तर तथा योग्यता स्तर की मात्रा वैसी है जैसी इसमें लिखी गई है ।

दिनांक

हस्ताक्षर (प्रमाणित करने वाला अधिकारी)

प्रति हस्ताक्षर कर्ता अधिकारी की टिप्पणियाँ:—

हस्ताक्षर (विभागाध्यक्ष)

दिनांक.....

परिशिष्ट 'अ'

नोट:—प्रतिवेदन फार्म 'ब' पूरा करने पर ।

भाग १

नोट:—निम्नलिखित नियुक्तियों में से प्रत्येक के सामने इस कालम में क ख ग घ या ङ को प्रस्थापित करो

(क) सबसे अच्छा

(ख) बहुत अच्छा

(ग) सन्तोषजनक

(घ) तटस्थ

(ङ) बहुत कम

नोट:—(२) इन मर्कों के लिये 'क' 'ख' चिन्हित करना ठीक नहीं है ।

नोट:—(३) इस प्रतिवेदन को गुप्त प्रतिवेदन समझना चाहिए तथा किसी मद के आगे ङ चिन्ह लगाने पर उसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा केवल निम्न परिस्थितियों के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों को दो प्रति में तैयार कर सूचित कर देना चाहिए ।

(१) जब कि कार्यालयाध्यक्ष की राय में इस सूचना के अधिकारी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होवे ।

(२) जब कि चिन्ह उसकी एक साल से कम सेवा होने के कारण अनुभव न रखने पर लगाया गया हो (केवल असन्तोषजनक आचरण एवं आलस्य आदि के कारणों के अलावा) ।

(३) जब कि कमजोरी से पहले ही ज्ञात करा दिया गया हो तथा स्पष्ट हो कि बार बार सूचना देने से कोई लाभ नहीं हो सकता है ऐसी परिस्थिति में अधिकारी को इस सम्बन्ध में बार बार अग्रिम सूचना देने को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना उसे पहले ही दी जा चुकी है । कोई बुरा या विपरीत प्रभाव जो पहले से ज्यादा पड़ा हो उससे अधिकारी को सूचित कर देना चाहिए ।

अधिकारी को 'ङ' चिन्हित की सूचना की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर स्थापनशाखा को वापस लौटाना चाहिए क्योंकि इस बात से यह प्रमाणित हो सके कि उसे इसमें अवगत करा दिया गया है ।

भाग २

नोट:—(४) पक्षोन्नति करने की योग्यता का अनुमान उपरोक्त वेतन शृंखला के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों की लक्ष्यता से सम्बन्धित होना चाहिए । उसे यदि असाधारण, अच्छा योग्य या अभी तक अयोग्य निश्चित किया जाये, तो इस प्रकार के चिन्ह लगाये जाने के कारण लिखे जाने चाहिये तथा सामान्यतया प्रतिवेदन करने वाले अधिकारी को विवरण लिखने के लिये दिये गए स्थान का पूर्ण उपयोग उठाना चाहिये ।

नोट:—(५) जिस समय प्रतिवेदन भरा जाता है उस समय अधिकारी की योग्यताओं के अनुमान आदि को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्रतिवेदन अधिकारी को किसी भी परि-

स्थिति में उसी अधिकारी की अन्य प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा भरी गई सूचना पर निर्भर न रहना चाहिये ।

फार्म (स)

राजस्थान सरकार

.....विभाग

अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों का शुद्ध वार्षिक प्रतिवेदन
वर्षके लिए

नाम

वर्तमान पद

कहां पर नियुक्त है तथा किस कार्य पर लगा रखा है

व्यक्तित्व एवं व्यवहार

स्वास्थ्य, शारीरिक योग्यता तथा उसे बनाए रखने के उपाय

परिश्रम, कार्य का गुण

निर्याय

नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं व्यवस्था करने की शक्ति

व्यवसायात्मक ज्ञान या विभागीय अनुभव

ऋण प्रवृत्ति (यदि ऋण प्रवृत्ति है, तो ऋण का दायित्व अपने ऊपर लेने की व्यक्तिगत

सीमा)

प्रतिवेदन अवधि के लिए दण्ड, निन्दा या विशेष अनुशंसायें

विगत प्रतिवेदन के पश्चात् अधिकारी को किसी विपरीत चिन्ह अंकित किये जाने की सूचना देने की तिथि ।

पदोन्नति या स्थाई किये जाने की योग्यता ।

सामान्य विवरण

तत्कालीन वरिष्ठ या प्रतिवेदन अधिकारी के विवरण

स्टेशन

दिनांक

हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)

अधिकारी का पद

परिशिष्ट ७

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

सर्वेक्षण प्रतिवेदन

.....स्कूल

इस प्रपत्र को भरने में पूर्व आगे की ओर दी गई सूचनाओं को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़िए ।

वस्तु का नाम	मात्रा	तरीक़े की तारीख	वास्तविक मूल्य	दया	टूटने आदि के कारण	निरीक्षण अधिकारी का मत	स्वीकृति कर्ता अधिकारी के आदेश
योग							

संख्या

दिनांक

संख्या

दिनांक

उपरोक्त सभी वस्तुएं अनुपयोगी है तथा निरीक्षक/निरीक्षिका/सहायक उप निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जब उसने इस शाला का निरीक्षण किया, दिखावा दी गई है।

मैंने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त सभी वस्तुओं की जांच की है तथा उनको वास्तव में अनुपयोगी तथा ख़त्म किये किये जाने योग्य पाया है। ये वस्तुएं असावधानी के कारण नहीं अस्तित्व केवल प्रयोग में लाने के कारण ही अनुपयोगी हुई हैं।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

निरीक्षण अधिकारी

.....विद्यालय.....

स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी

निर्देश

१. यह प्रपत्र केवल अनुपयोगी वस्तुओं के निस्तार के बारे में ही काम में लाया जाना चाहिए।

२. कोई भी अनुपयोगी वस्तु उस समय तक ख़त्म नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उनकी निरीक्षण प्रतिवेदन न भेज दिया जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उचित स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है।

३. शिक्षण वर्ष में निरीक्षण प्रतिवेदन केवल एक ही बार या तो अप्रैल में या नवम्बर माह में भेजना चाहिए।

४. निरीक्षण प्रतिवेदन उचित मार्ग के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए।

५. निरीक्षण प्रतिवेदन की हमेशा तीन कॉपियां भेजी जानी चाहिए।

६. निरीक्षण अधिकारी को इस प्रपत्र से किसी भी वस्तु या इसके भाग को काट देना चाहिए (मात्रा के स्तर में जिसमें कि उस वस्तु को ख़त्म करने या नीलाम करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है जहां ऐसे संगोपन किये गये हों वहां अपने गंभीर हस्ताक्षर करने चाहिए।

मरम्मत किये जा सकने वाली वस्तुओं को भी इसमें से काट देना चाहिए।

संख्या /३६—४०/

दिनांक १९६

मूल प्रति लौटाकर लेख है कि जिन वस्तुओं को खत्म किये जाने के आदेश दिये गए हैं उन्हें पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए, जिनको जलाने का आदेश दिया है उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए तथा जिनको नीलाम करने का आदेश दिया है, उन्हें सार्वजनिक नीलाम द्वारा नीलाम करना चाहिए तथा इस प्रकार जो रकम प्राप्त हो उसे राजकीय कोष में सदैव की भांति जमा करा देना चाहिए तथा इसके बाद शाला के स्थक रजिस्टर में से उन वस्तुओं को उनके आगे इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक लिखकर खत्म कर देना चाहिए तथा प्रधानाध्यापक के उन पर पूर्ण हस्ताक्षर हो जाने चाहिए।

कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष

परिशिष्ट =

विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में योजना एवं नियम

संख्या १७४ (२) शिक्षा/५४ विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना एवं नियमों के सम्बन्ध में दिनांक ६—११—५१ के राजस्थान राजपत्र में पृष्ठ संख्या ६ पर प्रकाशित इस कार्यालय संख्या एक १५ (३०) गिद्या ११—५१ दिनांक ३—११—५१ के अतिरिक्त में राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने और तत्सम्बन्धित निम्नलिखित संशोधित योजना पर स्वीकृति प्रदान करती है।

१. योग्यता एवं आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्तियाँ —

योग्यता एवं आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्ति जो दो शिक्षण वर्षों तक देय होगी वह निम्नलिखित सीमा तक प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित कक्षा में से ऐसे विद्यार्थियों को दी जायेगी जो कि उस शिक्षा के द्वारा, जिसके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, बहुत उच्च लाभ उठाने का वादा करते हैं लेकिन जिनके पास ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के साधन बहुत कम हैं ऐसी छात्रवृत्तियों के धन को वापस लौटाने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(क) राजस्थान की मान्यता प्राप्त शालाओं एवं इन्टरमीडिएट महाविद्यालयों के उच्च विद्यालय कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रति शिक्षण वर्ष १०० रु० की २५० छात्रवृत्तियाँ।

(ख) राजस्थान की मान्यता प्राप्त शाला एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में इन्टरमीडिएट कक्षाओं के विद्यार्थियों को १५० रु० प्रति शिक्षण वर्ष की दर से १५० छात्रवृत्तियाँ।

(ग) राजस्थान के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति शिक्षण वर्ष २०० रु० की दर से ७५ छात्रवृत्तियाँ।

(घ) राजस्थान के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में केवल कानून के विद्यार्थियों को छोड़कर स्नातकोत्तरीय विद्यार्थियों को २५० प्रति वर्ष शिक्षण वर्ष की दर से २५ छात्रवृत्तियाँ।

(ङ) ज्यादा से ज्यादा २५० रु० प्रति शिक्षण वर्ष दर से १० ऐसी छात्रवृत्तियाँ जो राजस्थान के विद्यार्थी हों तथा राजस्थान के बाहर किन्हीं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विशिष्ट पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों।

(घ) अधिक से अधिक २५०) २० प्रति शिक्षण वर्ष के हिसाब से १० छात्रवृत्तियाँ ऐसे विद्यार्थियों को जो राजस्थान के हो तथा उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य न हो लेकिन जो शारीरिक अशक्तता अधिक गरीबी या अन्य ऐसे कारण जिनको कि समिति ठीक समझे, के कारण से सहायता प्राप्त करने के योग्य हों ।

नोट: - इस खण्ड के अधीन छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नहीं दी जायेगी उनके लिए निम्नलिखित दूसरा खण्ड लागू होगा ।

२. राजस्थान के विद्यार्थी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में यदि तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हों तो उपर्युक्त मामलों में उन्हें इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई धनराशि से ज्यादा नहीं दिया जा सकेगा :—

ऐसी सहायता हर वर्ष अध्ययन काल तक ही दी जायेगी तथा प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षा में उसकी योग्यता के आधार पर उसका नवीनीकरण किया जायेगा ।

(क) सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग, ऐरोनोटिकल इंजीनियरिंग १५००) २०

(ख) चिकित्सकीय प्रशिक्षण १५००) २०

(ग) आयुर्वेदिक प्रशिक्षण ८००) २०

(घ) कृषि एवं पशु चिकित्सा १०००) २०

(च) अनुसंधान करने वाले छात्र:— अध्यापक प्रशिक्षण
सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण
तथा अन्य जो उपरोक्त नियमों के अधीन नहीं
आते किन्तु सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए हों । १५००) २०

(३) मृत राज्य कर्मचारियों के वच्चों की आर्थिक सहायता

१. उपरोक्त योग्यता एवं आवश्यक प्राप्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त ५० छात्रवृत्तियाँ ऐसे राज्य कर्मचारियों के लड़कों एवं लड़कियों को दी जायेगी जो कि राज्य सेवा काल में ही देवगति को प्राप्त हो गए हैं तथा जिनके वच्चों के पास अपनी शिक्षा को जारी रखने के साधनों की कमी है ।

२. इसी छात्रवृत्तियाँ देते समय यह ध्यान नहीं रखा जाएगा कि छात्र किस कक्षा में पढ़ रहा है । यह छात्रवृत्ति उस समय तक देय होगी जब तक कि छात्र संतोषजनक प्रगति कर रहा है तथा उसने कला विज्ञान या वाणिज्य में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न करली हो ।

३. इन छात्रवृत्तियों के पुनर्भुगतान के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा ।

४. प्रत्येक छात्र को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि १०) २० से ३०) २० प्रतिमास तक होगी किन्तु किसी एक परिवार को दो गई ऐसी घन राशी का योग ६०) २० से अधिक नहीं होगा ।

(४) छात्रवृत्तियों एवं अध्ययनार्थ ऋण का भुगतान, वापिस लेना, निलम्बित करना, फिर से चालू करना, स्थापित करना या स्थानान्तरण करना आदि निम्न नियमों द्वारा शासित होंगे:—

(क) जैसे ही उन्हें धनराशि स्वीकृत की जायेगी, छात्रवृत्ति या ऋण का उसी समय भुगतान कर दिया जायेगा। निम्न प्रमाण पत्रों के साथ स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के पास प्रार्थनापत्र देना चाहिए:—

१. उस संस्था के अध्यक्ष का प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिनमें वह छात्र अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति या ऋण प्राप्ति की अवधि तक पढ़ना चाहता है।

२. उस संस्था के अध्यक्ष ने निर्धारित प्रपत्र में उसकी आर्थिक स्थिति एवं साधनों के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र जिससे छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या अपने निवास स्थान से कम से कम प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पद के मजिस्ट्रेट ने एक प्रमाण पत्र।

३. जहाँ से छात्र ने परीक्षा पास की है, वहाँ की संस्था के अध्यक्ष का छात्र की शिक्षात्मक प्रगति के बारे में प्रमाण पत्र।

(ख) स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा इन छात्रवृत्तियों या ऋणों में से कोई भी छात्रवृत्ति या ऋण निलम्बित या वापिस किया जा सकता है यदि विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित रहता नहीं पाया जाता हो, उसकी शिक्षात्मक प्रगति संतोषप्रद नहीं हो रही हो, चरित्र अच्छा नहीं रहा हो या शाला अथवा महा विद्यालय के अनुशासन को भंग कर रहा हो। किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार से निलम्बित की गई छात्रवृत्ति या ऋण तत्कालीन समय से या पूर्व समय से पुनः स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह इसे सन्तुष्ट हो जाये कि यह निलम्बन अब और जरूरी नहीं है।

(ग) सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण प्रायः उस समय तक चलते रहेंगे जितने समय तक वे स्वीकृत किये गये हैं किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी समय समय पर अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट करता रहेगा कि छात्र नियमित रूप से उपस्थित तो रह रहा है, शिक्षात्मक उन्नति कर रहा है, उसका सामान्य चाल चलन अच्छा है तथा शाला व महाविद्यालय के अनुशासन का पालन कर रहा है। स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि छात्र उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन करने में असमर्थ हो रहा है तो वह उसकी छात्रवृत्ति या ऋण को स्थाई व अस्थायी रूप से जितने समय के लिए आवश्यक समझें बन्द कर सकता है।

(घ) उपरोक्त नियमों के अधीन रोकੀ गई छात्रवृत्ति या ऋण, स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी अपने निर्णय के आधार पर बाकी बचे हुए समय के लिए अन्य योग्य छात्रों को प्रदान कर सकता है।

(ङ) कोई भी छात्रवृत्ति या ऋण प्राप्तकर्ता छात्र व छात्रा, अपनी छात्रवृत्ति या ऋण को उसकी देयता के समय तक किसी भी अन्य मांग्यता प्राप्त संस्था में परिवर्तित कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि वह उसे परिवर्तित करने से पहिले स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करले।

(च) एक समय में एक छात्र एक से अधिक राजकीय निधि में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

(छ) छात्रवृत्ति या ऋण उस काल तक ही स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें कि वह पढ़ रहा है न कि भूतपूर्व समय के लिए।

(ज) वह विद्यार्थी जिसे ऋण स्वीकृत किया गया है, को ऋण के भुगतान करने के पूर्व स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जायेगा कि जैसे ही वह १५० रु. माहवार या अधिक कमाना शुरू कर देगा वैसे ही उस ऋण को निम्न न्यूनतम किश्तों में चुकाना शुरू कर देगा:—

आय की धनराशि	मासिक किस्त
१४६) रु० प्रति माह से कम	कुछ नहीं
१५०) रु० से १६६ रु० प्रति माह	१५) रु. प्रति माह
२००) रु० से २६६ रु. प्रति माह	२५) रु. प्रति माह
३००) रु. से ४६६ रु. प्रति माह	३०) रु. प्रति माह
५००) रु. या इससे अधिक	५०) रु. प्रति माह

(अ) योजनानुसार स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियां एवं ऋण शिक्षण सत्र के प्रारम्भ से ही अर्थात् जुलाई से देय होंगी ।

(ब) राजस्थान के विभिन्न भागों में अब तक प्रचलित छात्रवृत्तियां एवं ऋणों के सभी नियम इन नियमों के द्वारा अतिक्रमिit किए हुए समझे जायेंगे तथा उनके स्थान पर इन नियमों को लागू किया जायेगा । केवल ऐसी छात्रवृत्तियां एवं अध्ययन ऋण जो इन नियमों के बनने से पहिले स्वीकृत किए गए थे वे उन सम्बन्धित नियमों के अधीन जिनके द्वारा कि वे स्वीकृत किए गए थे, चलते रहेंगे ।

५. छात्रवृत्तियों एवं ऋणों का प्रशासन

(क) इन नियमों में दी गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर, छात्रवृत्तियां एवं ऋण निम्नलिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित एक समिति द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

१. शिक्षा मन्त्री	अध्यक्ष
२. शिक्षा सचिव	सदस्य सचिव
३. शिक्षा संचालक	सदस्य
४. स्नातकीय या स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय का प्राचार्य (शिक्षा सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जायेगा)	"
५. सवाई भानसिंह मेडिकल कालेज का प्रिन्सिपल	"
६. एम. बी. एम इंजिनियरिंग कालेज जोधपुर का प्रिन्सिपल	"
७. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि	"
८. कृषि कालेज जोधपुर का प्रिन्सिपल	"

समिति को इस योजना के प्रशासन के लिए ऐसे अतिरिक्त नियम बनाने का अधिकार रहेगा जो कि किसी भी रूप में इस योजना के प्रावधानों को बदलने या विपरीत बनाने वाले न हों ।

(ख) इन छात्रवृत्तियों एवं ऋणों के प्रशासन के लिए आवश्यक निधि सरकार द्वारा प्रति वर्ष समिति को सूचित कर दी जायेगी ।

(ग) समिति योजना के अनुसार एवं छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के लिए अपनी सिफारिश करेगी ।

(घ) स्वीकृत ऋणों की सम्पूर्ण धन राशि शिक्षा विभाग द्वारा वसूल की जायेगी ।

(ङ) पिछड़ी हुई जाति का छात्र या महिला छात्र होने पर समिति, यदि उचित समझे तो छात्रवृत्ति या ऋण प्रदान करने के लिए उन्मीदवारों के चयन में, तुलनात्मक रूप से कम स्तर वाले छात्रों को भी चुन सकती है ।

(च) अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत किए जाने वाले छात्रवृत्तियों एवं ऋणों की न्यूनतम संख्या के सम्बन्ध में समिति समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशनों का पालन करते हुए निश्चय करेगी ।

(छ) सरकार अपने निर्णयानुसार निर्दिष्ट कर सकती है कि समिति के निर्णय पर रद्दी गई निधि में से कुछ विशिष्ट धन राशि को राज्यकीय कर्मचारियों के उन लड़कों व लड़कियों में ऋण स्वीकृत करते हुए बांट दिया जाये, जो सेवाकाल में दैवगति को प्राप्त हो गए थे ।

(ज) नियम १ के अधीन सभी छात्रवृत्ति समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी किन्तु नियम २ व ३ के अधीन छात्रवृत्तियों एवं ऋणों के सभी मामले सरकार द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे ।

(झ) भारत में बाहर तकनीकी शिक्षा अथवा शोधकार्य हेतु कर्ज के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है ।

टिप्पणी— समय समय पर सरकार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में योजनाओं एवं नियमों को स्वीकृत करती रहती है, तथा बदलती रहती है इसलिए अन्तिम स्वीकृत एवं नियमों योजनाओं को, यदि कोई हो तो, लागू समझना चाहिए ।

परिशिष्ट ६

शुल्क सूची

(देखिए अध्याय ८ एवं अध्याय ११ नियम ३)

भाग १ राज्यकीय संस्थाओं में शुल्क

प्रति माह

१. महाविद्यालयों के लिए

(१२ माह के लिए)

	र०	न०	पै०
(१) इन्टरमीडिएट कला	३		००
(२) इन्टर मीडिएट विज्ञान एवं वाणिज्य	३		५०
(३) बी. ए., बी. काम	४		००
(४) बी. एस. सी.	४		५०
(५) एम. ए. एम. काम., एम. एस. सी.,	८		००

(६) एल. एल. बी	१०	००
(७) शोधकर्ता (रिसर्च स्कालर)	१०	००
(८) विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क (शोध विद्यार्थियो से)	५	००
(९) पोस्ट ग्रेज्यूएट विद्यार्थियो से विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	२	००
(१०) बी. ए., बी. काम, सार्यंकल की कक्षाये (स्त्री छात्राग्री से शिक्षण शुल्क नही लिया जावेगा लेकिन प्रयोगशाला शुल्कलिया जायेगी)	८	००
२. प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष एवं पंचम वर्ष कक्षाग्री एवं पूर्व कक्षाग्री मे प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियो से तथा अन्य महाविद्यालयों को द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम वर्ष तथा कानून अन्तिम वर्ष में स्थानान्तरण करा कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थिग्री से प्रवेश शुल्क ।	२	००
३. पुनः प्रवेश शुल्क (संस्कृत एवं ग्रायु-वेदिक महाविद्यालयो में वसूल नहीं किया जायेगा)	२	००
४. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र का शुल्क	२	००
५. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने प्रमाण पत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने का शुल्क ।	२	००
६. प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा मे बैठने के लिए विश्वविद्यालय प्रार्थना पत्र भेजने का शुल्क ।	५	००
७. ऐसे भूतपूर्व विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हों, और प्राइवेट छात्र जो विज्ञान में प्रयोग कार्य की ग्रथवा टाइपरार्डिंग की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हो, यदि सम्बन्धित ग्राचार्य व्यवहारिक समझे तो, इनको अधिक से अधिक तीन माह तक ये सुविधायें प्रदान कर सकता है तथा इसके लिए उससे पूरी ट्यूनशन फीस एवं प्रयोग-		

शाला फीस, यदि वह भी प्रयोग में ली जा रही हो तो कम से कम तीन माह तक वसूल करेगा ।

८. ऐसा भूतपूर्व विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय की प्रारंभिक परीक्षा देने की तैयारी कर रहा हो तथा विज्ञान प्रयोगशाला एवं टाइप राइटिंग की व्यावहारिक सुविधा प्राप्त करना चाहता हो, प्रिन्सिपल यदि व्यावहारिक पाये, तो वह ज्यादा से ज्यादा एक माह के लिए उसे इन सुविधाओं को प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इसके लिए कम से कम एक माह की उससे पूरी शिक्षण शुल्क, तथा प्रयोग शाला शुल्क यदि उसके द्वारा उपयोग में लाई जा रही हो तो, वसूल की जायेगी ।

	रुपये	प्रतिवर्ष
६. खेलकूद शुल्क	६)	"
१०. सामान्य कक्ष या वाचनालय कक्ष	२)	"
११. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	२)	"
१२. महाविद्यालय परीक्षा शुल्क	२)	प्रति परीक्षा
१३. छात्र संघ शुल्क	२)	प्रति वर्ष
१४. सुरक्षित धन	१०)	"

इसमें पुस्तकालय सुरक्षित धन एवं प्रयोगशाला सुरक्षित धन भी शामिल होता चाहिये तथा स्थानान्तरण या संस्था छोड़ने का प्रमाणपत्र देते समय यह वापिस नौटाने योग्य है ।

छात्रालयों (छात्रावास) के लिए

	रुपये	
१५. छात्रालय प्रवेश शुल्क	२)	
१६. छात्रालय में पुनः प्रवेश शुल्क	२)	
१७. छात्रालय के कमरों का किराया	२)	
(१) एक विद्यार्थी के लिये १ सीट वाला प्रथम श्रेणी का कमरा	मासिक ७)	१० माह के लिए
(२) एक विद्यार्थी के लिए १ सीट वाला द्वितीय श्रेणी का कमरा	" ६)	"
(३) दो सीट वाला प्रथम श्रेणी का कमरा प्रति विद्यार्थी	" ५)	"
(४) दो सीट वाला कमरा द्वितीय श्रेणी का प्रति छात्र प्रति माह	" ४)	१० माह तक
(५) दो से अधिक सीट वाला कमरा, प्रथम श्रेणी का, प्रति छात्र प्रति माह	" ३)	"
(६) दो से अधिक सीट वाला कमरा, द्वितीय श्रेणी का प्रति छात्र प्रति माह	" २)	"

छात्रालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में कमरों का विभाजन सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा ।

उपरोक्त स्वीकृत किराये में विद्युत व पानी का व्यय तथा साधारण सेवा (रसोईघर से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त) का व्यय भी शामिल है

१८. छात्रालय सामान्य कक्ष शुल्क	२	००	प्रति वर्ष
१९. छात्रालय सुरक्षित धन	५	००	"
२०. वर्तन शुल्क	२	००	"

छात्रों से कोई मैस सुरक्षित धन अलग से वसूल नहीं किया जावेगा ।

टिप्पणी:—संख्या १ से ८ तथा १५, १६ एवं १७ से होने वाली आय सरकार के पास जमा करा दी जायेगी ।

उच्च विद्यालय

१. शिक्षण शुल्क	(१) ९वीं एवं १० वीं कक्षाये	१-५० न. पै. प्रति माह १२ माह के लिए केवल उन संस्थाओं के अतिरिक्त जहां कोई ऐसा शुल्क वसूल नहीं किया जाता है।	
	कक्षा ३ से ५	६ से ८	९वीं से १०वीं
२. प्रवेश शुल्क	—	—	१.००
३. पुनः प्रवेश शुल्क	०.२५	०.५०	१.००
४. स्थानान्तरण या त्याग नै का प्रमाण पत्र शुल्क या इसकी दूसरी प्रतिलिपि)	—	०.५०	१.००
५. खेलकूद शुल्क	१.००	२.००	४.०० वार्षिक
६. छात्र संघ शुल्क	—	—	१.०० "
७. वाचनालय शुल्क	—	१.००	२.०० "
८. सोशल गेदरिंग शुल्क	—	—	१.०० "
९. प्रत्येक परीक्षा की फीस	०.५०	१.५०	२.०० प्रति परीक्षा
१०. सुरक्षित धन (केवल विज्ञान के विद्यार्थियों से)	—	—	५.०० जो शाला छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे

संख्या १, २, ३ एवं ४ से होने वाली आय सरकार के पास जमा करायी जायेगी ।

बुनीयादी एस. टी. सौ. प्रशिक्षण शाला राजकीय मनोनीत विद्यार्थियों के लिए

६०

१. प्रवेश शुल्क	१)
२. छात्र संघ शुल्क	२) प्रति वर्ष
३. सुरक्षित धन	५) विद्यार्थी द्वारा शाला छोड़ने पर लौटा दिया जायेगा ।

प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए

४. प्रवेश शुल्क	१)	
५. छात्रालय प्रवेश शुल्क	१)	
६. शिक्षण शुल्क	३) प्रति माह	
७. छात्रालय किराया	३) प्रतिमाह	
८. सुरक्षित धन (शाला)	५) प्रति वर्ष	सत्र की समाप्ति पर लौटा दिया जायेगा।

क्रमांक १, ४, ५, ६ एवं ७ से होने वाली आय सरकार के पास जमा करा दी जायेगी।

विभागीय परीक्षाओं का शुल्क

भिन्न भिन्न परीक्षाओं के नाम

१. एस. टी. सी. परीक्षा	१५)
२. संस्कृत परीक्षा—	
(१) आचार्य (नियमित)	१४)
आचार्य (प्राइवेट)	१६)
(२) शास्त्री (नियमित)	१२)
शास्त्री (प्राइवेट)	१४)
(३) उपाध्याय (नियमित)	८)
उपाध्याय (प्राइवेट)	१२)
(४) प्रवेशिका (नियमित)	२)
प्रवेशिका (प्राइवेट)	४)
३. आयुर्वेदिक परीक्षा—	
(१) भिषगाचार्य (नियमित)	१०)
" (प्राइवेट)	१०)
(२) भिषग्वर (नियमित)	६)
" (प्राइवेट)	६)

परिशिष्ट १०

[द्वितीय अध्याय २२ नियम ११ (१)]

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

सार्वजनिक परीक्षा में बैठने हेतु विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन पत्र।

(प्रतिदिन केवल १५ जुलाई एवं १० अगस्त तक की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।)

१. प्रार्थी का नाम

२. स्टाफ संख्या

३. पद

४. योग्यता

(क) विभाग में कार्यारम्भ करते समय

(ख) वर्तमान

५. नियुक्ति की तिथि

६. वेतन एवं श्रेणी

७. परीक्षा

(क) गत समय किस विभागीय परीक्षा में बैठने की कय स्वीकृति प्रदान की गई ।

(ख) गत परीक्षा का परिणाम जिसमें बैठे

(ग) परीक्षा का नाम मय विषयों के नाम के जिसमें आप बैठना चाहते हैं, नाम तथा वर्ष

(घ) कय और कहां परीक्षा ली जायेगी

(ङ) विश्वविद्यालय या मण्डल का नाम

८. इस परीक्षा को देने का कारण

९. प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित ।

१०. केवल परीक्षा के दिनों में अवकाश चाही जाने वाले दिनों की संख्या

दिनांक १९६६

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संख्या.....

दिनांक..... १९५६

११. को प्रस्तुत है । इस विषय पर सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की जाती है और यदि स्वीकृति दी गई कार्य में बाधा उपस्थित होगी ।

कृपया इन दोनों में से कोई सा काट दोजिएशाला का नाम

१२. स्वीकृत प्रदान करने वाले अधिकारी का आदेश

स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पद

परिशिष्ट ११

[देखिये अध्याय २२ नियम ११ (२)]

१९५५ से १९५५...वाले सत्र में सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्त्ताओं का सामूहिक विवरण पत्र

१. क्रम संख्या

२. संस्था का नाम

३. संस्था में अध्यापकों की संख्या
४. क्रम संख्या
५. प्रार्थी का नाम
६. योग्यता मय वर्ष के जिसमें प्राप्त की
७. वह वर्ष जिसमें परीक्षा में बैठने के लिये गत स्वीकृति दी गई थी परीक्षा का नाम सहित ।
८. परीक्षा का नाम जिसमें प्रार्थी बैठना चाहता है ।
९. आगे भेजने वाले अधिकारी की सिफारिश

प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

१०. स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के आदेश

स्वीकृति देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पद

परिशिष्ट १२

अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला बन्ध पत्र ।

यह बन्ध पत्र दिनांक माह

वर्ष को श्री

आत्मज निवासी

द्वारा (जो आगे प्रशिक्षार्थी कहलायेगा) प्रथम भाग के लिए

तथा श्री आत्मज

निवासी द्वारा

(जो आगे प्रतिभूति कहलायेगा) राजस्थान राज्य के राज्यपाल के साथ (जो आगे सरकार कहलायेगी) भरा गया है ।

जब कि प्रशिक्षार्थी, तथा शिक्षा विभाग का राजकीय कर्मचारी एस. टी. सी./बी एड./एम. एड. क्राफ्ट पाठ्यक्रम के लिए राज्य सरकार के खर्च पर प्रशिक्षण के लिए साला में जाने हेतु चुन लिया गया है ।

तथा जब कि सरकार के नियमों के अधीन प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति को निम्न शर्तों पर सरकार के साथ यह बंध पत्र निस्त है । और जब कि उपरोक्त बंधपत्र को निखा जाना प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति ने स्वीकार कर लिया है ।

इसलिए यह बंध पत्र माफी के तौर पर है । प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति दोनों सामूहिक रूप से बंधपत्र के निम्न पक्षों के राज्य सरकार के साथ अनुबंध करते हैं:—

(१) राज्य सरकार के विचार में प्रशिक्षार्थी को उपरोक्त शाला में उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये बिना किसी शुल्क के तथा उसके उस वेतन में से किसी प्रकार की बिना कटौती काटे, जो कि वह प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा था, तथा उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, प्रशिक्षार्थी एवं जमानत देने वाले दोनों एतद्द्वारा निम्न शर्तों स्वीकार करते हैं:—

(अ) प्रशिक्षार्थी उपरोक्त शाला में अपना अध्ययन अच्छी तरह एवं विरवासपूर्वक करेगा तथा अपने श्रापको प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त करने के लिए योग्य करेगा ।

(ब) प्रशिक्षार्थी उपरोक्त शाला में अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कम से कम ३ साल की अवधि तक सेवा करेगा तथा उपरोक्त ३ वर्ष की अवधि में मेहनत एवं कौशल के साथ सभी ऐसे कार्य करेगा तथा कर्तव्यों को निभायेगा जो उससे राज्य सरकार के कर्मचारी होने के नाते करवाये जा सकते हैं ।

(२) उपरोक्त शाला में प्रशिक्षण काल में यदि प्रशिक्षार्थी सुस्ती उदासीनता तथा सहायक रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण न करने के कारण दोषी पाया गया तो उपरोक्त शाला के प्राचार्य को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण देने से रोक दे तथा शाला से हटा दें ।

(३) यदि इस उपखण्ड २ के अधीन प्रशिक्षार्थी को उपरोक्त शाला से निकाला जाता है या प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी ड्यूटी पर पुनः उपस्थित नहीं होता है या इस प्रकार ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद यदि तीन साल तक सेवा न करने से पहले बीच ही में सक्षम अधिकारी द्वारा बरखास्त कर दिया गया है, या नौकरी से त्यागपत्र दे देता है तो प्रशिक्षार्थी को इस बन्ध पत्र की शर्तों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार समाप्त समझे जायेंगे यदि सरकार के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा करने पर जोर दिया गया तो वह उस शाला में दिया गया प्रशिक्षणकाल के कुछ खर्च को या उसके श्रांशिक भाग को (उसके प्रशिक्षण काल में उसे दिये गए वेतन सहित) जो राज्य सरकार द्वारा संचर्च किया गया था, तथा जितना सक्षम अधिकारी निश्चित करे उतना वापिस कर देंगे ।

(४) प्रतिभूति यह स्वीकार करता है कि:—

(अ) वह राज्य सरकार को कुल धनराशि का भुगतान करने योग्य होगा जब कि प्रशिक्षार्थी राज्य सरकार को वह भुगतान करने में समर्थ न हो ।

(ब) प्रशिक्षार्थी के द्वारा की गई भूल गतती उदासीनता या अपराधों के किये जाने पर उसकी ओर से किसी प्रकार की क्षमा या सहनशीलता की याचना राज्य सरकार से करने पर प्रतिभूति को इस बन्ध पत्र के अधीन किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त या कम नहीं किया जायेगा ।

(५) प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति का इस बंधपत्र के अन्तर्गत उत्तरदायित्व रूपरेखा की सीमा तक ही होगा । (यहां पर उतनी धनराशि लिखिए जितनी के लिए प्रशिक्षार्थी एवं प्रतिभूति दोनों को किया जाता है ।) इससे (स्टैम्प ड्यूटी से) स्टैम्प की ₹५-१७ धाराओं के अधीन स्टैम्प सुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी ।

उपरोक्त लिखे हुए दिन व वर्ष को साक्षी रूप में प्रशिक्षणार्थी एवं प्रतिभूति द्वारा बन्धपत्र किया गया ।

१) श्री..... (साक्षी) की उपस्थिति में नै हस्ताक्षर किए ।

(२) श्री..... (साक्षी) की उपस्थिति में प्रशिक्षार्थी ने हस्ताक्षर किए ।

(१) श्री..... (साक्षी) की उपस्थिति में प्रतिभूति ने हस्ताक्षर किये ।

(२) श्री..... (साक्षी) की उपस्थिति में प्रतिभूति ने हस्ताक्षर किये ।

परिशिष्ट १३

राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग

व्यक्तिगत शिक्षा संस्था मान्यता प्रार्थना पत्र

१. संस्था सम्बन्धी विवरण

नाम	प्रकार	स्तर	संस्था कब से चल रही है (तिथि)	संस्था के व्यवस्थापक का नाम पता प्रबन्धक समिति का विधान और यदि हो तो सदस्यों के नाम

२. संस्थाद्वारा शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धी विवरण

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षण का अभिमत

विवरण (अ) संस्था का विशेष उद्देश्य

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षण का अभिमत

विवरण (आ)

सम्बन्धित स्थान पर संस्था की आवश्यकता एवं उपयोगिता और यदि संस्था नए मिर्रे मे खोली जा रही है तो उसका वर्तमान संस्थाओं पर सम्भावित प्रभाव

व्यवस्थापक का वक्तव्य

निरीक्षक का अभिमत

(२) अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय जिनके सम्बन्ध मे मान्यता स्वीकृति की प्रार्थना अपित की जा रही है ।

व्यवस्थापक का प्रस्ताव

निरीक्षक का अभिमत

३. कक्षानुसार छात्र संख्या

कक्षा (वर्ग सहित)

छात्र संख्या

औसत उपस्थिति

व्यवस्थापक का
वक्तव्य

निरीक्षक का
अभिमत

४. संस्था का भवन एवं छात्रावास-भवन विवरण

व्यवस्था का उल्लेख

निरीक्षक का अभिमत

१. कमरों की संख्या लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई
२. पुस्तकालय एवं वाचनालय का कमरा ।
३. गोदाम ।
४. सम्मेलन गृह ।
५. छात्रावास के कमरों और विद्याभित्तों की संख्या ।
६. पेशाबघर ।
७. पाठान्तरण एवं स्थानीय ।
८. उपयुक्तता ।
९. अन्य विवरण ।

नृचना—इस विवरण के साथ संस्था का उक्त विवरण प्रदर्शक मानचित्र सम्मिलित होना चाहिए—

५. उपस्कर (फर्नोचर) एवं शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं ।

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत
६ छात्रों की शारीरिक व्यायाम, डाक्टरी परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन आदि	
व्यवस्थापक का विवरण	निरीक्षक का अभिमत

७. अध्यापक सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	अध्यापको के पूरे नाम योग्यता सहित	पद	वेतन तथा ग्रेड	महंगाई आदि	निरीक्षक का अभिमत

८. यदि शुल्क लिया जाता हो तो मासिक या एक बार देय तथा असहाय छात्रों के शुल्क रहित प्रवेश सम्बन्धी विवरण—

व्यवस्थापक का उल्लेख			निरीक्षक का अभिमत	
कक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	अन्य शुल्क	
अन्य विवरण				

८. संस्था की आर्थिक परिस्थिति

यदि शुल्क ली जाती हो तो उनकी मासिक आय	संस्था कोप एवं अन्य आय	कुल मासिक आय	कुल मासिक व्यय	निरीक्षक का अभिमत

१०. अन्य ज्ञातक विषयक प्रश्न

प्रश्न	व्यवस्थापक द्वारा उत्तर	निरीक्षक का अभिमत
१. क्या संस्था शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुगमन करती है ?		
२. क्या संस्था में, समस्त जाति तथा धर्मों वाले छात्रों को शुल्क-सुविधा आदि के तथा किसी भी मतभेद के बिना प्रवेश खुला है ?		
३. संस्था के स्टाफ की योग्यता, वेतन शृंखला, उप वेतन पूर्वोपायी कोष अवकाश नियम आदि शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं एवं नियमों के अनुसार है ।		
४. शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित नियम पत्र (Agreement) के अनुसार संस्था के प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति की गई है ?		
५. क्या शैक्षणिक वातावरण में अव्यवस्था पैदा करने वाली किसी सार्वजनिक वादविवाद एवं प्रवृत्ति में संस्था के अध्यापकादि भाग लेते हैं ?		
६. क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में छात्रों और अध्यापकों का सम्मिलित होना अनिवार्य है ?		

प्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणिकरण एवं प्रतिज्ञा:—

१. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण सही है ।

२. मैंने मान्यता-प्रदान सम्बन्धी नियम ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं ।

३. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि उक्त संस्था को मान्यता प्राप्त करदी जावेगी तो मैं मान्यता प्रदान सम्बन्धी शर्तों से और तत्सम्बन्धि समस्त वर्तमान और तथा समय परिवर्तन एवं परिवर्द्धित नियमोपनियमों से आवद्ध रहूँगा और समय २ पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निर्देशों का अनुगमन करता रहूँगा ।

तिथि.....

हस्ताक्षर

व्यवस्थापक

निरीक्षक का आवेदन:—

(आवेदन करते समय निरीक्षक को नियमों का संदर्भ अङ्कित करना चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि उक्त संस्था को उसके अभिमतानुसार किस स्तर की एवं किन किन विषयों की मान्यता प्रदान करना किन शर्तों पर उचित है ।)

तिथि

हस्ताक्षर

निरीक्षक का पद

केन्द्र

परिशिष्ट १४

शिक्षा विभाग राजस्थान

शिक्षण संस्था सहायता प्रार्थना-पत्र

प्रेषक

श्रीमान शिक्षाविभागाध्यक्ष,

राजस्थान, जयपुर ।

मान्यवर महोदय,

३१ मार्च सन् १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (संस्था का नाम)
 संस्था की सहायता स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सेवा में प्रेषित करता हूँ ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

१. संलग्न सूचना पूर्णतया सत्य है ।

२. किसी उल्लेखनीय बात को जानबूझकर छिपाया नहीं गया है ।

३. यह संस्था मान्यता की आवश्यकताओं एवं सहायता के नियमों का पालन करती रही है और करती रहेगी ।

४. संस्था के कक्षावार एवं ग्रन्थापकवार समय चक्र विभाग की प्रतियाँ आपके अवलोकनार्थ साथ में संलग्न है ।

५. मैं अनुबन्ध करता हूँ कि ऊपर खण्ड ३ में उल्लिखित नियमों में से किसी की अवहेलना होने की दशा में राजस्थान सरकार, सहायता बन्द कर सकती है ।

दिनांक

भण्डीय

हस्ताक्षर.....

पद.....

सूचना:—यह प्रार्थना पत्र शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास जिस वर्ष के लिए सहायता चाही गई है उस वर्ष के पहले वाले अक्टूम्बर मास के अन्त तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए । परन्तु सन् १९६६—६७ की सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास ३१ जुलाई १९६६ तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए ।

साधारण सूचना

संस्था का नाम.....

संस्था का स्तर.....

संस्था की स्थापना की तिथि
 मान्यता की तिथि
 इसके वर्तमान स्तर की तिथि
 संस्था को सहायता कब से मिल रही है
 संस्था को गत वर्ष कितनी सहायता मिली,
 संस्था की कार्यकारिणी नियमानुसार सरकार से रजिस्टर्ड है अथवा नहीं । यदि है तो

रजिस्ट्रेशन नम्बर

संस्था का अन्य कोई विरोधवृत्तान्त (यदि कोई हो तो) ...

प्रबन्ध कारिणी समिति

क्रम संख्या	नाम सदस्य	निर्वाचन की तिथि
१		
२		
३		
४		
५		
६		
७		
८		
९		
१०		
११		
१२		
१३		
१४		
१५		

सूचना—प्रबन्ध कारिणी समिति के नये विधान तथा नियमों की प्रति साथ में संलग्न हो ।

लेखक वर्ग

१

२

३

४

योग

लेखक वर्ग पर मासिक व्यय

श्रुत्य वर्ग

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

योग—

श्रुत्य वर्ग पर मासिक व्यय

घृह्य योग्य : मासिक व्यय—

संस्था के गत ३१ मार्च तक के वित्तनिक कार्यकर्ताओं का विवरण
अध्यापक

क्रमांक	नाम अध्यापक	योग्यता व अवस्था	सेवा काल	पाठन कार्य का अनुभव	वेतन तथा ग्रेड	प्रोविडेंट फण्ड	मंहगाई	अन्य कोई भत्ता	विशेष	वृत्तान्त
१										
२										
३										
४										
५										
६										
७										
८										
९										
१०										
११										
१२										
१३										
१४										
१५										
१६										
१७										
१८										
१९										
२०										
२१										
२२										
२३										
२४										
२५										
२६										
२७										
२८										

योग

अध्यापक वर्ग पर कुल मासिक व्यय

कुल कार्य विवरण

गत सत्र की संख्या एवं कक्षावार उपस्थिति का विवरण

कक्षा	कार्य दिवस	ग्रीसत दैनिक छात्र संख्या	पिछली ३१ मार्च को रजिस्टर में अंकित छात्र संख्या
-------	------------	---------------------------	--

नोट—दैनिक ग्रीसत उपस्थिति के लिए सत्र के कुल कार्य दिवसों का कुल उपस्थिति की संख्या में भाग देना चाहिए।

गत तीन वर्षों के कक्षावार परीक्षाफल

कक्षा वर्ष १९			कक्षा वर्ष १९			कक्षा वर्ष १९		
छात्र संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्र संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्र संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								
१०								
११								
१२								
१३								
१४								

आय व्यय का विवरण

आय

संस्था का स्थाई कोष जो गत ३१ मार्च को था

इस स्थाई कोष का धन किस प्रकार लगा

रखा है उसका संक्षिप्त विवरण

आय के मद	गत वर्ष की की आय	चालू वर्ष की अनुमानित आय	आगामी वर्ष की अनुमानित आय
१. पाठन शुल्क			
२. दण्ड			
३. प्रवेश शुल्क			
४. छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क			
५. मासिक चन्दा प्रथवा स्थाई चन्दा			
६. स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त धन			
७. सरकारी सहायता			
८. स्थायी कोष के व्याज प्रादि से प्राप्त धन			
९. अन्य किसी प्रकार से प्राप्त धन			

योग

वृद्ध योग

तिथि.....

प्रबन्धक अथवा मन्त्री के हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

व्यय

आय की मदें	गत वर्ष की ठीक आय	चालू वर्ष का अनुमानित व्यय	आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय
१. अव्यापक वर्ग का वेतन, प्रोविडेंट फण्ड के लिए देने योग्य धन २. लेखक वर्ग को वेतन एवं प्रोविडेंट फण्ड के लिए देने योग्य धन ३. मंहगाई ४. स्टेशनरी व छपाई का व्यय ५. पानी तथा प्रकाश का व्यय ६. पाठन सामग्री को ठीक रखने के लिए व्यय ७. संस्था के भवन तथा फर्नीचर की साधारण मरम्मत का व्यय ८. मकान किराया, यदि संस्था किराये के मकान में हो ९. पुस्तकालय, पुस्तकों तथा वाचनालय का मरम्मत व्यय १०. जो शिक्षणालय एक से अधिक संस्था चला रहा है वहाँ पर उस संस्था का संचालन सम्बन्धी आवश्यक्रीय व्यय ११. अन्य व्यय			

योग

वृहद् योग

तिथि

हस्ताक्षर मन्त्री तथा प्रबन्धक

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

परिशिष्ट १५

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

संस्था की सहायता लेने के सम्बन्ध में अधिकारी वग का अभिमत ।

संस्था की सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्तता

(सहायता सम्बन्धी नियमों में से चौथा नियम)

२. प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हुई सूचना की सत्यता ।

३. अन्य कोई विशेष वृत्तान्त ।

४. सिफारिश (अभिर्शसा)

सन् १९६६ तक के लिए

अभिर्शसक के हस्ताक्षर तथा पद

सं० सहायता के लिये
.....

संस्था को स्वीकृत किये गये

स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं पद

परिशिष्ट १६

(देखिए अध्याय २१ नियम ३)

(प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र)

महाविद्यालयों के आचार्य, शालाओं के प्रधानाध्यापक तथा छात्रालयों के अधीक्षक (जो छात्रालय अधीक्षक का २० रु. प्रतिमाह या इससे अधिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं) जो महाविद्यालय व शालाओं के साथ संलग्न है, को स्वतन्त्र शिक्षण करने की इजाजत नहीं है ।

१. प्रार्थी का नाम

२. पद

३. शाला या महाविद्यालय का नाम जिसमें वह नियुक्त किया गया है ।

४. छात्र का नाम तथा कक्षा

५. क्या छात्र प्रार्थी द्वारा पढ़ाई जानै वाला कक्षा में पढ रहा है ?

६. विषय जिसमें ट्यूशन करने की स्वीकृति चाही जा रही है ।

७. यदि प्रार्थी द्वारा कोई अन्य ट्यूशन पहले से ही की जा रही हो तो उसका विवरण ।

८. मैं घोषणा करता हूँ कि इस ट्यूशन के लिए मुझे घण्टे प्रति दिन या प्रति सप्ताह से अधिक नहीं देना पड़ेगा ।

८. मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि इस प्राइवेट श्रूशन करने से मेरी छात्रा के वर्तमान के पालन में मय घर पर पाठ तैयार करने, पाठों को जांचने तथा सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेने में किसी प्रकार की बाधा न होगी।

१०. मैं प्राइवेट श्रूशन के सम्बन्ध में प्रभावशील शिक्षा विभाग के सामान्य विभाग के सामान्य नियमों का पालन करूँगा।

दिनांक

दिनांक

प्राथी के हस्ताक्षर

स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पद

परिशिष्ट १७

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

(राजकीय कर्मचारी)

१. नाम
 २. पिता का नाम
 ३. जन्म तिथि
 ४. नौकरी में आने की तिथि
 ५. स्थानों होने की तारीख
 ६. दिए गए विषयों की वनाति हुए योग्यता
- (विश्वविद्यालय के प्रभार पत्र या विभागीय अभिलेख के अनुसार)

परी १ का नाम	पास करने का वर्ष	लिये गए विषय	अंश
१. माध्यमिक			
२. उच्च विद्यालय			
३. इन्टरमीडिएट			
४. बी. ए., बी. एन. ना. या बी. कॉम			
५. एम. ए. (प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित)			
६. वर्तमान वेतन एवं वेतन शृंगला तथा वर्तमान वेतन पर वसूल दिये जाने की तारीख			
७. प्रशिक्षण संस्था का नाम जिसकी प्राप्ति पत्र भेजा गया है (अनुसार के अनुसार)			
८. संस्था जिसमें सेवा कर रहे हैं			
९. गैरईका			

प्राथी के हस्ताक्षर

प्रेषित करने वाले अधिकारी का विशेष विवरण एवं सिफारिश

भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं

पद

परिशिष्ट १८

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

(स्वतन्त्र व्यक्तियों के लिए)

१. नाम

२. पिता/पति का नाम भय पते

३. जन्म तिथि

(विश्वविद्यालय या बोर्ड के प्रमाणपत्र के अनुसार)

४. निम्न कक्षाओं में विषय सहित योग्यता प्राप्त करने का विवरण:—

नाम परीक्षा	पास करने का वर्ष	लिए गये विषय	पद
-------------	------------------	--------------	----

(१) माध्यमिक

(२) उच्च विद्यालय

(३) इन्टर मीडिएट

५. सेवा के बारे में विवरण, यदि कोई हो :

(१) शाला व शालाओं के नाम

(२) सेवा काल का समय

६. प्रशिक्षण संस्था का नाम (जिसमें वह प्रशिक्षण लेना चाहता है)

७. स्थायी पता

८)

आर्थी के हस्ताक्षर

.....शाला.....

छात्र रजिस्टर
लेख प्रमाण (क)

रजिस्टर संख्या.....

राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

प्रवेश दिनांक			छोड़ने का दिनांक			छोड़ने का कारण			
छात्र का नाम व धर्म	जन्म तारीख	इस शाला में प्रथम प्रवेश के दिनांक	पिता का नाम व्यवसाय और पता	संरक्षक का नाम व्यवसाय और पता	छात्र का निवास स्थान	प्रथम प्रवेश के दिन छात्र का राजस्थान में निवास का समय	उस शाला का नाम जिसमें छात्र इस शाला में प्रवेश होने से पहले पढ़ा हो	पिछले शाला की छोड़ते समय छात्र कौनसी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ था किस कक्षा में बढ़ाए जाने योग्य था	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

बर्तमान

परिशिष्ट २०

(देखिये अध्याय २३ नियम १६)
प्रवेश पंजिका (रजिस्टर)

राजस्थान शिक्षा

प्रारम्भिक पाठशालाओं का

..... तहसील

क्रम संख्या	नाम विद्यार्थी	जन्म तिथि	उम्र		पिता का नाम	निवास स्थान तहसील सहित	पिता या संरक्षक का धंधा	पाठशाला जहाँ पहले शिक्षा प्राप्त की	कक्षा में प्रवेश या उल्लंघन की तिथि
			वर्ष	माह					

सरकार

विभाग

प्रवेश रजिस्टर

जिला ...

डिविजन ...

हस्ताक्षर

पाठशाला छोड़ते समय अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण	पुरानी क्रम संख्या यदि छात्र ने पुनः प्रवेश किया हो	यदि पुनः प्रवेश तो पुनः प्रवेश शुल्क	यदि पुनः प्रवेश किया है	पाठशाला छोड़ने की तारीख तथा कारण		यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसकी क्रम संख्या दी जाय	स्थानांतरण प्रमाण शुल्क		हस्ताक्षर
				रुपया	पैसा		रुपया	पैसा	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

विशेष विवरण १२

जमान संख्या जिसके द्वारा स्थानांतरण प्रमाण शुल्क या पुनः प्रवेश शुल्क कोष में जमा कराया गया

११

परिशिष्ट २१

राजस्थान शिक्षा विभाग

पाठशाला प्रवेश प्रार्थना पत्र

(अ) प्रवेशार्थी-प्रवेशार्थिनी के पिता या संरक्षक द्वारा पूर्ति निमित्त पाठशाला का नाम स्थान

१. प्रवेश प्रार्थना-पत्र अर्पित करने की तिथि
२. छात्र-छात्रा का पूरा नाम
३. धर्म
४. जन्म तिथि ईस्वी सन्. में
५. प्रवेश के समय आयु
६. छात्र-छात्रा का पूरा नाम, आजीविका एवं स्थाई पता
७. संरक्षक का पूरा नाम, आजीविका एवं स्थाई पता
८. छात्र-छात्रा और संरक्षक का सम्बन्ध
९. छात्र-छात्रा और संरक्षक का सम्बन्ध ग्राम
तहसील जिला
१०. राजस्थान में निवास की अवधि
११. प्रवेश से पूर्व जिस पाठशाला में अध्ययन किया हो उसका नाम, स्थान प्रमाण पत्र
१२. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है या चाहती है
१३. अभीष्ट ऐच्छिक विषय
१४. यदि छात्र पुनः इसी पाठशाला में प्रविष्ट हो रहा हो तो कक्षा का नाम जिसमें पढ़ना छोड़ा और कब छोड़ा

हस्ताक्षर पिता या संरक्षक

(आ) पिता अथवा संरक्षक द्वारा प्रमाणीकरण और प्रतिज्ञा

१. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण ठीक हैं।
२. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र-छात्रा का नाम

(क) छात्र/छात्रा ने इस पाठशाला में प्रवेश पूर्व किसी राज्य द्वारा प्रमाणित पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई है।

(ख) इस प्रार्थना पत्र में अंकित छात्र की जन्म तिथि सही है।

३. मैं प्रमाणित करता हूँ कि:—

(क) जब तक उक्त छात्र-छात्रा इस संस्था में शिक्षा प्राप्त करता रहेगा, मैं संस्था के नियमों, उप नियमों से आबद्ध रहूँगा।

(ख) छात्र-छात्रा की उल्लिखित जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध नहीं किया जावेगा।

(ग) पाठशाला का नियमित शुल्क दूँगा।

पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर

(घ) पाठशालाधिकारियों के निर्मित:—

..... कक्षा में प्रविष्ट करने के लिए छात्र-छात्रा की परीक्षा ली जावे।

तिथि

प्रधानाध्यापक — प्रधानाध्यापिका

१.	विषय में योग्य, अयोग्य पाया गया, सम्बन्धित अध्यापक के हस्ताक्षर
(२)	" " " "
(३) ...	" " " "
(४)	" " " "
(५)	" " " "
(६)	" " " "
(७)	" " " "
(८)	" " " "
(९)	" " " "
.....	कक्षा में शुल्क प्राप्त करके प्रविष्ट किया जावे ।

तिथि.....

प्रधानाध्यापक—प्रधानाध्यापिका

यह प्रमाण तब करने की आवश्यकता है जब नम्बर १३, १४ की पूर्ति की गई हो.....
प्रवेशांक पर आवश्यक शुल्क प्राप्त करके प्रविष्ट किया गया हो शुल्क का विवरण.....

तिथि पाठशाला कर्मचारी.....

अवलोकित.....

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

परिशिष्ट २२

(देखिये अध्याय २३ नियम ५)

(केवल सुभावात्मक)

नाम.....सत्र.....जन्म तिथि कक्षा.....
खण्ड.....पिता का नाम.....
संरक्षक का नाम व पता.....
शाला में नियमित छात्र अथवा छात्रावास में अन्तेवासी—
परिवार के सदस्य जिनके साथ वह रहता है
संरक्षक की औसत आय
नगर, कस्बे या गांव में निवास स्थान

(क) शिक्षात्मक उन्नति

विषय	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	-------	--------

अध्यापक के हस्ताक्षर

संरक्षक के हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

(ख) विविध

जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
-------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	-------	--------

शाला की बैठकों की संख्या

छात्रों की उपस्थिति

दूसरे माह में जमा कराया जाने वाला शुल्क

दूसरे माह में जमा कराया जाने वाला दण्ड

..... कक्षा के अध्यापक के हस्ताक्षर

..... प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

..... संरक्षक के हस्ताक्षर

(ग) सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति

प्रवृत्ति	प्रथम अवधि	द्वितीय अवधि	तृतीय अवधि

..... अध्यापक के हस्ताक्षर

..... प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

..... संरक्षक के हस्ताक्षर

(घ) शारीरिक उन्नति

अवधि	ऊँचाई	वजन	छाती फुलाना	दाँत मालिश गला	कोई बीमारी	हस्ताक्षर
------	-------	-----	-------------	-------------------	------------	-----------

प्रथम अवधि

अध्यापक
प्रधानाध्यापक
संरक्षक

द्वितीय अवधि

अध्यापक
प्रधानाध्यापक
संरक्षक

तृतीय अवधि

अध्यापक
प्रधानाध्यापक
संरक्षक

(ङ) नैतिक उन्नति

विशेषता	प्रथम अवधि	द्वितीय अवधि	तृतीय अवधि
---------	------------	--------------	------------

अनुशासन

व्यवहार

स्वभार

नामाङ्कितता

उत्तरदायित्व की भावना

नेतृत्व शक्ति

(च) नामान्य

प्रथम	द्वितीय
प्रथम प्रथम	प्रथम प्रथम
द्वितीय प्रथम	द्वितीय प्रथम
तृतीय प्रथम	तृतीय प्रथम

परिशिष्ट २३

अनुबन्ध पत्र (बॉन्ड)

(पाठशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में)

ग्राम..... तहसील.....
 जिला.....

स्टाम्प

जो कि हम..... ग्राम के निवासी उक्त ग्राम में पाठशाला की स्थापना इस दस्तावेज़ पर स्वीकार
 की है कि हम नियमानुसार अनुबन्धन पत्र लिखें। अतः हम निम्नलिखित व्यक्ति—

१. श्री..... का पुत्र श्री.....
 निवासी..... मुख्य प्रतिनिधि
२. श्री..... का पुत्र श्री.....
 निवासी..... मुख्य प्रतिनिधि
३. श्री..... का पुत्र श्री.....
 निवासी..... मुख्य प्रतिनिधि
४. श्री..... का पुत्र श्री.....
 निवासी..... मुख्य प्रतिनिधि
५. श्री..... का पुत्र श्री.....
 निवासी..... मुख्य प्रतिनिधि

पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुबन्ध करते हैं कि:—

१. इस पाठशाला में सर्वदा छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति ठीक ठीक रहेगी ।

२. इस ग्राम में पाठशाला स्थापित होने से पहले उसके लिए उपयुक्त मकान का प्रबन्ध करके मकान को शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर देंगे या मकान किराये पर लेकर दे देंगे । यह प्रबन्ध हम पाठशाला खुलने के दस वर्ष पर्यन्त कर देंगे । इसी नमूने के अनुसार शाला भवन निर्माण करा देंगे अथवा शाला निर्माण के लिए द्रव्य संग्रह करके शिक्षा विभाग के उक्त कार्य निमित्त जमा करा देंगे ।

३. पाठशाला खुलने से पहले हम अध्यापक के निवास गृह का सुप्रबन्ध कर देंगे ।

४. शाला भवन की लिपाई, पुताई, मरम्मत आदि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रति वर्ष हम कराते रहेंगे ।

५. (क) यदि बिना किसी कारण के जिसमें हम विवश हों बालक-बालिकाओं की ग्रासत उपस्थिति निरन्तर ६ मास तक प्रति मास ३० से कम रही तो पाठशाला को शिक्षा विभाग द्वारा हटाने में कोई आपेक्ष नहीं करेंगे ।

(ख) यदि किसी मास में मध्यमोपस्थिति ३० से कम हो गई तो उस मास के समाप्त होते ही रजिस्ट्री से तत्काल सम्बन्धित निरीक्षक महोदय के द्वारा उपस्थिति की कमी का कारण लिखित रूप में तहसील से समर्थित कराके शिक्षा विभाग में अर्पण करा देंगे । यदि शिक्षा विभाग स्वीकृत योग्य नहीं समझेगा तो सम्बन्धी मासों का भी पाठशाला का अर्ध व्यय हम देंगे ।

अतः यह प्रतिज्ञा पत्र हम सबने स्वेच्छा एवं प्रसन्नतापूर्वक सावधानी के साथ लिख दिया है जिससे कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे ।

तारीख

मास

सन्

प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

- (१) का पुत्र
- (२) का पुत्र
- (३) का पुत्र
- (४) का पुत्र
- (५) का पुत्र

प्रमाणीकरण तहसीलदार अथवा अन्य राज पत्रांकित अधिकारी द्वारा

तारीख

माह

सन्

प्रतिनिधियों के प्रतिज्ञापत्र को अक्षरः सुनकर अपना लिखा हुआ स्वीकार किया ।

तारीख

हस्ताक्षर और मुहर

जयपुर, दिनांक १८-१०-५५

विषय:—शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शक्तियों का हस्तान्तरण

संख्या एक १८ (१३)-एक ११ (आर) ५५-राज्य प्रमुख संलग्न सूची के अनुसार, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए वित्तीय शक्तियां एवं सेवा नियमों के अधीन शक्तियां प्रदान करने के लिए प्रस्ताव हो गये हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वित्तीय शक्ति एवं सेवा नियमों के अधीन शक्तियां प्रदान करना।

राजस्थान शिक्षा नियम १९५५

क्रमा संख्या	शक्तियों की विवरण	शिक्षा संचालक	उप शिक्षा संचालक	निरीक्षक एवं उप निरीक्षक शाला प्रभारी (In-charge) तथा इस श्रेणी के अन्य अधिकारी	इन्टर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यक्ष	उच्च विद्यालय एवं प्रशिक्षण शालाओं के अध्यक्ष	पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अध्ययन एवं अस-मर्थता के अतिरिक्त अन्य अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति	संशोधित अनुसूचि के अनुसार	नियुक्ति की शक्ति तक तथा अप्रशिक्षित जेज्यू-एटो मे सहायक अध्यापकों तक	नियुक्त करने की सीमा तक तथा इन्टर अप्रशिक्षित अध्यापकों तक	नियुक्ति की शक्ति तक	नियुक्ति की शक्ति तक	नियुक्ति करने की शक्ति तक
२	मकान मरम्मत कराने जिसकी सुरक्षा का भार विभाग पर है	पूर्ण शक्ति	२०००० रु० तक	५०० रु० तक

३	भवन आदि का किराया	इस शर्त के आधार पर कि अधिकाधिक सीमा जिस तक कि साधारण कार्यालय की इमारत किराये पर ली जाती है, १००) ६० माह से अधिक नहीं होना चाहिये जैसा कि संशोधित अनुसूची में परिशिष्ट आठ के संलग्न 'क' के २२ वें मद में दिया हुआ है।	५००) ६०	१००) ६० तक	१००) ६० तक
४	स्टाक एवं स्टोर की खरीद	दी गई शक्तियों के अनुसार	५००) ६० तक	१०) ६० तक प्रत्येक मामले में पर साल में कुल १००) ६० तक पिछले कालम की शर्तों के आधार पर	१००) ६० तक प्रत्येक मामले में लेकिन साल में कुल १००) ६० से अधिक नहीं
५	नुकसान एवं जाय-दाद को खत्म करना	२५०) ६० तक प्रत्येक विषय में जिसकी सीमा कुल साल में ५०००) ६० तक की होगी वसतें कि ऐसा नुकसान, गवन या चोरी न गया हो।	१००) ६० तक प्रत्येक मामले में पर साल में कुल १०००) ६० तक वसतें कि यह चोरी या गवन किये जाने के कारण नहीं हुआ हो।	१०) ६० तक प्रत्येक मामले में १००) ६० तक पर साल में कुल १००) ६० तक पिछले कालम में दी गई शर्तों के आधार पर	१०) ६० तक प्रत्येक मामले में १०) ६० तक तथा साल में कुल १००) ६० तक
६	अनुपयोगी वस्तुओं को नीलाम करना एवं उनकी कीमत को खत्म करना	प्रत्येक मामले में २५०) ६० तक पर साल में कुल ५०००) ६० तक किन्तु शर्त यह है कि यह चोरा नहीं गया हो या गवन न किया गया हो	१००) ६० तक प्रत्येक मामले में १००) ६० तक पर साल में कुल १०००) ६० तक वसतें कि यह चोरी नहीं गया हो या गवन न किया गया हो	१०) ६० तक प्रत्येक मामले में १००) ६० तक पिछले कालम में दी गई शर्तों के आधार पर	१०) ६० तक प्रत्येक मामले में १०) ६० तक तथा साल में कुल १००) ६० तक
७	राजस्व का पुनः लौटाना	एक बार में १००) ६० तक

परिशिष्ट २७

मभी विद्यार्थी जो अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति तथा पिछड़े हुये वर्ग से सम्बन्धित है (इस निशुल्कता के लिए वर्गों की सूची नीचे दी हुई है) वे राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की शिक्षण शुल्क की भुगतान से मुक्त कर दिये जायेंगे ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े हुए वर्ग के लोगों की सूची

१—अनुसूचित जन जाति—

भोल

२—अनुसूचित जाति—

१. आधी धरमी	२. ददगर	३. भांड
४. चूरा	५. डोम	६. जाटिया
७. खाटके	८. भदारी (बाजीगर)	९. मोची
१०. खेदासिस	११. सांसी	१२. अहेरी
१३. वांसफोड़	१३. भंगी	१५. दवगर
१६. गंडिया	१७. कालवेलिया	१८. कूचवान
१९. भधावी	२०. वुट	२१. रावल
२२. थोरी	२३. बाड़ी	२४. वारंगी
२५. विडाकिया	२६. धानकिया	२७. गरेच्छा महतर
२८. कपाडिया सांसी	२९. कोरिया	३०. मेहर
३१. पासी	३२. सरसंगी	३३. तिरगर
३४. वागरी	३५. वसारिया	३६. चमार
३७. डेढ	३८. गोधी	३९. खंगरि
४०. कंजर	४१. मेहतर	४२. रेगर
४३. मिगीवाला	४४. वाल्मीकि	

३—पिछड़ी हुई जातियां—

१. बागरी	२. बोला	३. चेस्ता
४. डोली	५. धनछा	६. गडेरिया
७. जुलाहा	८. कहार	९. छुहार
१०. साटिया (सिन्धी)	११. खांट	१२. वेरिया
१३. वेअरी	१४. चमतार	१५. धान्धी
१६. गवारिया	१७. हलार	१८. कलाल

१६. खटीक	२०. बांवी	२१. भेर
२२. माय	२३. भेगवाल	२४. पटवा (फादल)
२५. राय	२६. सिकलीगर	२७. बलाई
२८. बढेरा	२९. शन्धावल	३०. धानका
३१. गरासिया	३२. जोगी	३३. कन्जर
३४. कोन्नी	३५. कोजी	३६. मेरठ
२७. मीराम	३८. मेंक	३९. पिन्जारा
४०. साद (सांढिया)	४१. सिल्कीवाला	४२. बन्जारा
४३. बगेरिया	४४. धोषी	४५. गम्हानी
४६. गडिक लोहार	४७. जाटव (यादव)	४८. कुम्हार
४९. खारोल	५०. लखारा	५१. मोना
५२. महा ब्राह्मण	५३. नैरिया	५४. सोंसी (सेहर)
५५. ठठेरा	५६. रावत	

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

(वर्ष)

सामान्य शिक्षा के स्कूलों के आंकड़े इकट्ठे करने का फार्म

पत्र संख्या.....
स्थान.....
दिनांक.....

वास्ते

.....
.....
.....

महोदय,

मैं ३१ मार्च, को समाप्त होने वाले वर्षके अपने स्कूल से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े फार्म को भरकर भेज रहा हूँ ।

भवदीय

नाम.....
पद.....

दिनांक.....
.....

महोदय,

मुझे ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्षके आंकड़े भरने के लिये फार्म प्राप्त हो गया है, उसकी प्राप्ति की रसीद भेज रहा हूँ ।

भवदीय,

नाम.....
पद.....

दिनांक.....

यह फार्म अच्छी तरह भर कर सम्बन्धित शिवा निरीक्षक/उप-शिवा निरीक्षक/सहायक उप-शिवा निरीक्षक को १५ अप्रैल..... या स्कूल बन्द होने से पहले प्रवर्ग्य भिजवा देना चाहिये ।

प्रत्येक सारिणी से सम्बन्धित हिदायतों उसके पहले पृष्ठ पर दी हुई हैं । फार्म भरते समय इन हिदायतों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिये ।

(१) अनुसूचित जातियों की सूची

(i) अजमेर जिला, आधूरोड़ तालुका, व सुनेलटप्पा क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त राजस्थान में अनुसूचित जातियों की सूची इस प्रकार है—

१. आदि धर्मी	२. अहेरी	३. बाडी
४. बागरी	५. बैरवा या बैरवा	६. बाजगर
७. बलाई	७. बासफोर	८. बाखी, बाखी या बिरगी
१०. बाबरिया	११. केड़िया या बैरिया	१२. भांड
१३. भंगी	१४. बिदाकिया	१५. बोला
१६. चमार, भाम्नी, जाटव, जटिया, मोवी, रावदास, रामवासिया, कारायगर		
१७. चण्डाल	१८. चूरा	१९. दावगर
२०. धानकिया	२१. डेडा	२२. डोम
२३. गाडिया	२४. गराचा, मेहतर या शान्चा	२५. गारो, गरुडा या गुरडा
२६. गवारिया	२७. गोधी	२८. जीतगर
२९. कालबेलिया	३०. कामड या कामडिया	३१. कन्जर
३२. कपाडिया सांसी	३३. खानगर	३४. खटीक
३५. कोली या कोरी	३६. कुचवन्ध	३७. कोरिया
३८. कन्जर	३९. मदारी या बाजीगर	४०. मजहवी
४१. मेघ या मेघवाल	४२. मेहर	४३. मेहतर
४४. नट	४५. पासी	४६. रावल
४७. सालवी	४८. सांसी	४९. सान्धिया
५०. सरभंगी	५१. सरगरा	५२. सीगीवाल
५३. थोरी या नायक	५४. तीरगर	५५. वाल्मिकी

(ii) अजमेर जिले में अनुसूचित जातियों की सूची

१. अहेरी	२. बागरी	३. बलाई
४. भाम्नी	५. बान्सकांडे	६. बाओरी
७. बागरी	८. बाजीगर	९. भंगी
१०. बिदाकिया	११. चमार, जाटव, नटिया, मोची-चौर रेगर	
१२. दावगर	१३. धानक	१४. डेड
१५. धोवी	१६. डोली	१७. डोम
१८. गरोडा	१९. गांचा	२०. कबीरपन्थी
२१. खदर	२२. खटीक	२३. कोली

(ii) अजमेर जिले में—

१. भील
२. भील मीना

(iii) सिरोही जिले के आघूरोड़ तालुका में—

१. वरडा
२. बावचा या वामचा
३. भील, भील गरासिया, ठोली भील, झूंगरी भील, झूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, टडवी भील, भागानिया, भीलाला, पावरा, वासवा और वासदी
४. चौवरा
५. धानका टडवी; टेटारियां और बलवी
६. घोडिया
७. डूबला, तालविम्रा या हल्यदि
८. गीमित या गामता या गाविता—भावगी, माडवी, वासवा, वासावी और बालगा
९. गोंड या राजगोड
१०. कवोडी या कटकारी—डोर कजोड़िया या डोर कटकारी और सोन काघोडी या सोन कटकारी ।
११. कोकनी, कोकना, कुकना ।
१२. कोली डोर, टोकरे कोली, कीलचा या कोलंघा ।
१३. नायकडा या नायका चोलीवाला नायका, कपाड़िया नायका, कोटा नायक और नाना नायक ।
१४. पारधी, अश्विचिचेर और फासे पारधी
१५. पातिलिया ।
१६. पोमला ।
१६. राथावा ।
१८. वारलो ।
१९. बिटोलिया, कोटवालिया या बारोड़िया ।

(iv) भालावाड़ जिले के सुनिलटप्पा क्षेत्र में—

१. गोद ।
२. कोरकु ।
३. सेहरिया ।

सारिणी नं० (१) सम्बन्धित हिदायतें

१. यह फार्म उन समस्त स्कूलों द्वारा भरा जावेगा जो राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ।

२. लड़कों के स्कूल—यह स्कूल जहाँ केवल लड़के पढ़ते हैं उसको तो लड़कों के स्कूल में गिना ही जावेगा साथ में सह शिक्षा के स्कूलों को भी लड़कों के स्कूलों में दिसलाना चाहिये ।

३. स्कूल स्तर—प्रत्येक स्कूलको उसके उच्चतम स्तर से माना जावेगा । जैसे किसी स्कूल में यदि पहली से दसवी कक्षा एक ही हैटमास्टर के अन्तर्गत चल रही है तो उसे हाईस्कूल गिना जायेगा । परन्तु यदि पहली से पांचवी कक्षा छठी से दसवी कक्षाओं अलग अलग चल रही हो व उनके

हैडमास्टर भी अलग अलग हों, चाहे वह एक ही भवन में हो तो उसको दो स्कूलों में गिना जावेगा। पहला प्राइमरी स्कूल १ से ५ वीं कक्षा तक। दूसरी हाई स्कूल छठी से दसवीं कक्षा तक। यह मालूम करने के लिये कि मिडिल स्कूल में कितनी प्राइमरी कक्षाएँ चल रही है और हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में कितनी प्राइमरी अथवा मिडिल कक्षाएँ चल रही हैं कालम नं० ४ में यह सूचना भरनी चाहिये कि उस स्कूल में कितनी सेक्सन्स चल रही है। जैसे एक हाई स्कूल पहली से दसवी कक्षा तक चल रही है तो १४ वे कालम में यह भरना है कि उस स्कूल में १ सेक्सन पहली से पांचवी कक्षा तक चल रही है। एक छठी से आठवी तक और एक नवी से दसवी तक चल रही है।

सारिणी नम्बर (१) सामान्य विवरण

(१) पाठशाला का नाम तथा पूरा पता

(२) लड़कों/लड़कियों के लिये। (३) पाठशाला की स्थिति गांव या कस्बे में। (४) स्कूल के स्थापना का वर्ष। (५) स्कूल का स्तर—नर्सरी पाठशाला/प्राइमरी पाठशाला/जूनियर बेसिक/मिडिल सीनियर बेसिक/हाई स्कूल/मल्टीपरपज हाई स्कूल/जूनियर हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी/मल्टीपरपज हायर सेकेण्डरी/पोस्ट बेसिक स्कूल।

(६) स्कूल का प्रबन्ध—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पंचायत समिति/नगरपालिका/प्राइवेट सहायता प्राप्त/प्राइवेट सहायता रहित।

(७) स्कूल भवन—(अ) कच्चा/पक्का (ब) राजकीय/निजी/किराये पर/बिना किराये पर। धर्मशाला में/चौपाल में या मन्दिर में।

(८) ३१ मार्च को नाम दर्ज विद्यार्थियों की संख्या—	बालक	बालिका	योग
(अ) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	_____	_____	_____
(ब) अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी	_____	_____	_____
(स) अन्य विद्यार्थी	_____	_____	_____
(द) योग (अ+ब+स)	_____	_____	_____

(९) पाठशाला से संलग्न छात्रावासों की संख्या	लड़कों के लिये	लड़कियों के लिये	योग
(अ) केवल अनुसूचित जाति के लिये	_____	_____	_____
(ब) केवल अनुसूचित जन जाति के लिये	_____	_____	_____
(स) अन्य विद्यार्थियों के लिये	_____	_____	_____
(द) योग (अ+ब+स)	_____	_____	_____

(१०) पाठशाला से संलग्न छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या (३१-३ को)

	बालक	बालिकाएँ	योग
(अ) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	_____	_____	_____
(ब) अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी	_____	_____	_____
(स) अन्य विद्यार्थी	_____	_____	_____
(द) योग (अ+ब+स)	_____	_____	_____

	पुरुष	स्त्री	योग
(११) ग्रन्थापकों की संख्या (३१-३- को)	_____	_____	_____
(१२) (अ) क्या पाठशाला में शिक्षा मुफ्त दी जाती है ?—			हां या नहीं
(ब) अगर हां तो किस कक्षा तक			_____
(१२) स्कूल में कौन कौन सी सेवशन चल रही हैं—			
(१) नर्सरी			_____
(२) प्राइमरी (१-५)			_____
(३) मिडिल (६-८)			_____
(४) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल (९-१०-११)			_____
(१४) ऐच्छिक विषय जो स्कूल में पढ़ाये जाते हैं			_____

सारिणी नं० २ (अ) से सम्बन्धित हिदायतें

१. इस सारिणी में ३१ मार्च, को स्कूल में उपस्थित कुल का विद्यार्थियों का व्यौरा देना है। इसमें विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों का उनकी उम्रानुसार व्यौरा दिया जावेगा। इस सारिणी को भरते समय यह विशेष ध्यान रहे कि समस्त विद्यार्थियों की उम्र का व्यौरा स्कूल में उपलब्ध रिकार्ड से भरा जावे। क्लर्क टीचर को अन्दाज से यह व्यौरा नहीं देना चाहिए।

२. इस सारिणी के अन्त में प्रत्येक कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति व जन जाति के विद्यार्थियों की संख्या देनी है। इसके उम्रवार व्यौरे की आवश्यकता नहीं। अनुसूचित जाति व जन जाति की सूची संलग्न है। विद्यार्थियों की संख्या भरते समय इन सूची को ध्यान में रखा जावे।

३. सारिणी नम्बर १ के आर्टिकल नं० ८ के अन्तर्गत दी गई विद्यार्थियों और इस सारिणी में दी गई कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग परस्पर मिलना चाहिए।

४. इस सारिणी में यह भी बताना है कि प्रत्येक कक्षा में ऐसे कितने लड़के हैं जिनके पास सामान्य विज्ञान ऐच्छिक विज्ञान व हिन्दी विषय है। प्रत्येक विषय के बारे में अलग अलग सूचना देनी है।

सारिणी नम्बर २ (ब) से सम्बन्धित हिदायते

१. इसमें विभिन्न शिक्षा स्तर पर हो रहे अवरोध का व्यौरा देना है। यदि किसी प्राइमरी स्कूल में तीन ही कक्षाएँ चल रही हैं तो उसे प्रथम तीन कक्षाओं का व्यौरा देना है। इसी तरह किसी हाई/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में जहाँ पहली से दसवी, ग्यारहवी कक्षा में चल रही है, इस सारिणी में पहली से दसवी/ग्यारहवी कक्षा तक का व्यौरा देना है।

२. कॉलम नम्बर ३ में ३१ मार्च, को उपस्थित कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या देनी है जो सारिणी नम्बर २ (अ) में दी हुई है।

३. कॉलम नम्बर ५ से ८ में उन विद्यार्थियों के बारे में विवरण देना है जो एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे जैसे कोई लड़का पहली कक्षा में दो साल तक फँस हो जाता है और तीसरी बार फिर उसी कक्षा में पढ़ रहा है तो उसे कॉलम नम्बर ७ में दर्ज करना है।

४. इसमें लड़के व लड़कियों का अलग अलग विवरण देना है।

सारिणी नम्बर २ (ब) १ से ११ कक्षा के विद्यार्थियों में अवरोध

कक्षा	बालक बालिकाएँ	३१ मार्च को विद्या- र्थियों की संख्या	इन विद्यार्थियों में से जो उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं					
			१ साल से	२ साल से	३ साल से	४ साल से	५ साल से	६ साल से
१	२	३	४	५	६	७	८	९
पहली	बालक बालिकाएँ							
दूसरी	बालक बालिकाएँ							
तीसरी	बालक बालिकाएँ							
चौथी	बालक बालिकाएँ							
पाँचवीं	बालक बालिकाएँ							
छठी	बालक बालिकाएँ							

१	२	३	४	५	६	७	८	९
सातवीं	बालक बालिकाएं							
आठवीं	बालक बालिकाएं							
नवीं	बालक बालिकाएं							
दसवीं	बालक बालिकाएं							
ग्यारहवीं	बालक बालिकाएं							
योग	बालक बालिकाएं							

सारिणी नं० ३ (अ) व ३ (ब) से सम्बन्धित हिदायतें

१. इस सारिणी में वार्षिक परीक्षा व पूरक परीक्षा फल का व्योरा देना है।

२. सारिणी नं० ३ (अ) में पांचवी, आठवीं, दसवी व ग्यारहवीं कक्षाओं के वार्षिक परीक्षाफल का व्योरा देना है, यह ध्यान रखना चाहिये कि पहली से पांचवी, पहली से आठवीं, छठी से दसवीं व छठी से ग्यारहवीं में पढ़ रहे समस्त विद्यार्थियों के परीक्षा फल का व्योरा इसमें न दें। यदि किसी मिडिल स्कूल में पहली से आठवीं कक्षाएँ चल रही हैं तो उसे केवल पांचवी व आठवी कक्षा का परीक्षा फल ही इस सारिणी में देना चाहिये यदि किसी प्राइमरी स्कूल में पहली से तीसरी कक्षाएँ ही चल रही हैं तो उसे इस सारिणी को खाली छोड़ना चाहिये।

३. इस सारिणी में दिये गये परीक्षार्थियों की संख्या का मिलान सारिणी नं० २ (ब) में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या से कर लेना चाहिये। माना कि दसवी कक्षा में किसी हाई स्कूल में ३१ मार्च को ३० लड़के पढ़ रहे हैं तो सामान्यतः यह उम्मीद की जाती है कि वहाँ ३० लड़के वार्षिक परीक्षा में भी बैठें हों, यदि कुछ लड़कों की हाजरी में कमी होने को वजह से रोक दिया हो तो इसमें कुछ अन्तर आ सकता है या कुछ प्राइवेट लड़के बैठें हों।

४. सारिणी ३ (ब) में पूरक परीक्षा में बैठे लड़कों की सूचना देनी है।

५. यदि वार्षिक परीक्षाफल व पूरक परीक्षा फल सारिणी भेजने की अन्तिम तिथि तक उपलब्ध नहीं हो तो इस फार्म के अन्त में दी हुई सारिणी को फाड़ लेना चाहिये और फार्म को बिना परीक्षा फल की सारिणी को भर भेज देना चाहिये। परीक्षाफल को फाड़ी हुई सारिणी को बाद में भर कर भिजवा देना चाहिये।

६. प्राइवेट व रेगुलर लड़कों का व्योरा अलग २ देना चाहिये।

सारिणी नं० ४ से सम्बन्धित हिदायतें

१. इसमें स्कूल में कार्य कर रहे अध्यापकों के बारे में सूचना भरनी है ।

२. प्रत्येक अध्यापक का यह विभाजन करना होगा कि वह कितने मैक्सिमम को पढ़ा रहा है । जैसे किसी हाई स्कूल में पहली में दस कक्षाएँ चल रहीं हैं और उसमें ३० अध्यापक कार्य कर रहे हैं तो उनका यह विभाजन करना होगा कि कितने अध्यापक प्राथमिक स्तर (१-५) की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं कितने माध्यमिक स्तर (६-८) की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं व कितने उच्च माध्यमिक स्तर (९-११) की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं । एक अध्यापक को केवल एक बार ही गिना जावेगा इस विभाजन को करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा—

(क) विषय व कक्षाओं के अनुसार अध्यापकों का विभाजन किया जा सकता है जैसे जो अध्यापक विशेषतः हाई/हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में चल रहे विषयों के लिये नियुक्त किये गये हैं व उन्हीं कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, उनको हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर पर बताया जावे या जो मिडिल कक्षाओं के लिये नियुक्त किये गये हैं व उन्हीं कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें मिडिल स्तर पर बताया जावे, व जिन अध्यापकों को प्राइमरी कक्षाएँ पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया है और जो उन्हीं कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर बताया जावे ।

(ख) अध्यापकों का उनके द्वारा कार्यभार के अनुसार भी विभाजित किया जा सकता है जैसे एक अध्यापक ८, १०, ११ कक्षाएँ पढ़ा रहा है और उसके सप्ताह में कुल ३६ पीरियड होते हैं । यदि वह १०, ११ कक्षाओं के २० पीरियड लेता है तो उसे उच्च माध्यमिक स्तर पर बताया जावे क्योंकि उसका अधिक समय १०, ११ कक्षाओं को पढ़ाने में बीतता है और यदि वह ६ व ८ कक्षाओं के २० पीरियड लेता है तो उसे माध्यमिक स्तर पर बताया जा सकता है क्योंकि उसका अधिक समय मिडिल कक्षाओं के पढ़ाने में व्यतीत होता है ।

३. प्रशिक्षित अध्यापकों में उन समस्त अध्यापकों को लेना है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रशिक्षित हैं, या सरकार ने जिन्हें अध्यापन कार्य अवधि के आधार पर प्रशिक्षित मान कर प्रशिक्षित ग्रेड दे दिया है ।

४. सारिणी के अन्त में अनुसूचित जाति व जन जाति के अध्यापकों का विवरण देना है ।

सारिणी नं० ५ (अ) व ५ (ब) से सम्बन्धित हिदायतें

१. इस सारिणी में स्कूल द्वारा साल भर में खर्च की रकम का व्यौरा देना है। ऐसे देखा गया है कि स्कूल में खर्च के समस्त व्यौरे नहीं रखे नहीं जाते और इस सारिणी को सही रूप से नहीं भरा जाता इसलिये प्रत्येक स्कूलों को चाहिये कि यह खर्च का पूर्ण व्यौरा अपने रिकार्ड में रखें और इस सारिणी में भर कर भिजवावें।

२. सारिणी नं० ५ (ब) को ५ (अ) से पहले भरना चाहिये। सारिणी नं० ५ (ब) को दो भागों में बाटा हुआ है प्रत्यक्ष व्यय व परीक्षा व्यय। प्रत्यक्ष व्यय में केवल वह आवर्तक व्यय जो सीधे रूप से खर्च होता है, लिया जावेगा बाकी व्यय परीक्षा व्यय के अन्तर्गत लिया जावेगा। इस सारिणी को भरते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जावे—

- (१) मकान किराया भत्ता के आगे स्कूल के मकान किराये का व्यौरा नहीं देना चाहिये बल्कि अध्यापकों को कुछ मुख्य मुख्य शहरो जगहों पर सरकार से मिल रहे मकान किराये भत्ते की रकम देनी चाहिये।
- (२) विद्यार्थी शुल्क के अन्तर्गत खेल कूद परीक्षण आदि पर खर्च की गई राशि का व्यौरा कालम नं० १ में देना चाहिये न कि कालम नं० स (ख) (२) व (७) में। इन कालमों में यदि सरकार या अन्य स्रोत से कोई रकम प्राप्त हुई हो और यह खर्च की गई हो तो लिखनी चाहिये अन्यथा नहीं।
- (३) फरतीचर, इमारत व साज सज्जा की मरम्मत पर खर्चा आवर्तक व्यय है और इनके खरीद पर खर्चा अनावर्तक व्यय है इस बात का खर्च की सूचना भरते समय विशेष ध्यान रखना चाहिये।

३. सारिणी नं० ५ (ब) को भरने के बाद ५ (अ) को भरना चाहिये। इस सारिणी में यह व्यौरा देना है कि स्कूल पर समस्त व्यय की रकम किन किन स्रोतों से प्राप्त की गई। ये स्रोत हैं, सरकार, स्वायत्त संस्थाएँ जैसे नगरपालिकायें, पंचायत समितियाँ, विद्यार्थी शुल्क, चन्दा व अन्य स्रोत इत्यादि।

सारिणी नं० ५ (अ) व ५ (ब) सम्बन्धित हिदायते चालू

४. खर्च का व्यौरा ५ (अ) में इस तरह भरा जावेगा—

- (१) राज्यकीय संस्था—एक स्कूल में कुल प्रत्यक्ष व्यय ५०,०००) हुआ है और उसकी आमदनी राज्य सरकार निधि से ४३,०००), द्यूशन फीस से ५,०००), अन्य विद्यार्थी शुल्क से २,०००) अन्य स्रोतों से ५,०००) है विद्यार्थी शुल्क से प्राप्त पूरा २,०००) खर्च हुआ है। ५ (अ) को भरते समय पहले ५,०००) द्यूशन फीस में, २,०००) विद्यार्थी शुल्क में बता देंगे फिर ५,०००) अन्य स्रोतों से बता देंगे। बाकी ३८,०००) (५०,०००-१२,०००) सरकारी निधि के अन्तर्गत बताया जावेगा। हालांकि ४३,०००) रुपये सरकारी निधि से प्राप्त हुआ था परन्तु ५,०००) द्यूशन फीस का उस स्कूल द्वारा सरकार की वापिस ट्रेजरी में जमा कर देना पड़ता है व वास्तविक रूप में उसे केवल ३८,०००) रुपये ही सरकार से मिलता है।
- (२) मान्यता प्राप्त निजी संस्था—माना कि एक स्कूल का कुल प्रत्यक्ष व्यय ५०,०००) हुआ है और उसकी आमदनी राज्य सरकार से ६०,०००), द्यूशन फीस से ५,०००) विद्यार्थी शुल्क से ४,०००), चन्दे व अन्य स्रोतों द्वारा १६,०००) है तो ५ (अ) में

सारिणी नं० ५ (ब) वित्तीय वर्ष का व्यय विवरण

व्यय विवरण	रकम	व्यय विवरण	रकम
भाग १ प्रत्यक्ष व्यय		(५) अन्य खर्च	
(अ) वेतन व भत्ते		[६] योग (क)	
(क) अध्यापकों के		(ख) अन्य खर्च	
[१] वेतन व महंगाई भत्ता		[१] मकान किराया	
[२] यात्रा भत्ता		[२] खेल-कूद इत्यादि पर व्यय	
[३] मकान किराया भत्ता		[३] इनाम	
[४] अन्य भत्ते		[४] स्वीकृत शुल्क	
[५] योग (क)		[५] कृषि खर्च	
(ख) अन्य कर्मचारी के		[६] कैम्प व प्रदर्शनी खर्च	
[१] वेतन व महंगाई भत्ता		[७] परीक्षा व्यय	
[२] यात्रा भत्ता		[८] स्कूल के बच्चों के द्वार	
[३] मकान किराया भत्ता		[९] अन्य छोटे खर्च	
[४] अन्य भत्ते		योग (ख)	
[५] योग (ख)		(ग) विद्यार्थी शुल्क में से खर्च	
योग (अ) (क+ख)		[१] परीक्षा पर	
(व) उपकरण एवं साज सज्जा (आवर्तक)		[२] खेल-कूद पर	
[१] फरनीचर की मरम्मत		[३] अन्य	
[२] विज्ञान उपकरण की मरम्मत		योग (ग)	
[३] टाइपराइटर व डुप्लीकेटर की मरम्मत		योग (क+ख+ग)	
[४] पंखा, साइकिल इत्यादि की मरम्मत		योग (१) (अ+ब+स)	
[५] लाइब्रेरी ग्रान्ट (आवर्तक)		भाग (२) परोक्ष व्यय	
[६] वस्त्र की मरम्मत		(क) अनावर्तक	
[७] इमारत की मरम्मत		[१] इमारत पर (नवनिर्माण)	
[८] सीने का सामान (आवर्तक)		[२] उपकरण एवं साज सज्जा (खरीद)	
[९] अन्य कच्चा माल (आवर्तक)		[३] किताबें (खरीद)	
[१०] अन्य खर्च		[४] अन्य अनावर्तक खर्च	
योग (व)		योग (क)	
(स) अन्य खर्च		(ख) आवर्तक	
(क) ऑफिस का खर्चा		[१] वजीफे, स्ट्राइफंड. एवं अन्य आर्थिक	
[१] डाक भ्रादि पर व्यय		रियायतों पर खर्च	
[२] टेलीफोन पर व्यय		[२] छात्रावास पर खर्च, (भोजन खर्च	
[३] पानी विजली का खर्चा		निकाल कर)	
[४] बर्तों		योग (ख)	
		योग (२) (क+ख)	
		कुल योग (१+२)	

सारिणी नं० ६ सम्बन्धित हिदायतें

१. इस सारिणी में इन्हीं वजीफों और वृत्तियों के आंकड़े दिये जावेगे जो वास्तव में विद्यार्थियों को साल भर में मिले हैं और न कि जितने संस्था में दिये जा सकते हैं। कॉलम नं० २०, २१ में दी गई रकम का योग केवल नं० ५ व में वजीफो व वृत्तियों पर दिये खर्च, से मिलाना चाहिये।

२ रिहैविलिटेशन डिपार्टमेंट (पुनर्वास विभाग) सोशियल वेलफेयर (समाजकल्याण विभाग) डेवलपमेंट विभाग (विकास विभाग) इत्यादि से दिये वजीफे, वृत्तियां राजस्थान सरकार के ही अन्तर्गत दिखलाई जायेगी क्योंकि ये विभाग राजस्थान सरकार के ही हैं।

३ अन्य आर्थिक रियायतें साल में दी गई हो (जैसे वच्चों को कपड़े, वस्त्रियां, छात्रावास में मुफ्त खाने का प्रबंध कुछ ही छात्रागो के लिये, इत्यादि) उनको सारिणी नं० ५ में वजीफे और वृत्तियों के सामने दिखाये गये खर्च में शामिल करना चाहिये।

४. फीस के आंकड़े देते समय आधी अथवा आंशिक फीस माफियों की पूर्ण फीस माफी में बदल कर लिखा जायगा।

५. उन विद्यार्थियों की संख्या जो स्कूल को उन कक्षाओं, जिनमें ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है वह कक्षाएँ स्कूल के साथ संलग्न हों, में अध्ययन करते हो, दिखाई जावेगी (उदाहरणार्थ हाई या हायर सेकेन्डरी स्कूल में कक्षा ८ तक ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है और ९वीं १०वीं तथा ११वीं में फीस ली जाती है तो कक्षा ८वीं तक पढ़ने वाले लड़के दिखाये जायेंगे। नम्बर (द) के सामने रकम दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

सारिणी नं० ७ से सम्बन्धित हिदायतें

१. इसमें स्कूल में कार्य कर रहे समस्त अध्यापकों के नाम व अन्य विवरण देना है।

२. उम्र के कॉलम में ३१ मार्च को जितनी अध्यापक की उम्र हो वह दर्ज करना है।

३. वेतन के अन्तर्गत मार्च का वेतन, भत्ते, इत्यादि शामिल होंगे। इसमें जो बीमा, प्रोविडेंट फण्ड, इन्कम टैक्स इत्यादि की रकम को काट कर नहीं दिखाना चाहिये।

४. कॉलम नं० ८ में यह दिखाना है कि अध्यापक किस सेक्सन को पढ़ाता है जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई/हायर सेकेन्डरी। इसके लिये सारिणी नं० ४ में आवश्यक हिदायतें दी हुई हैं। उनका ध्यान रख कर इस कॉलम को भरना चाहिये।

५. कॉलम नं० ९ में यदि अध्यापक अनुसूचित जाति या जन जाति का है तो उसका ध्यास देना है।

सारणी नं० ६

११-३-१६६ को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के वजीफों, वृत्तियां, फीस माफियां और विद्यार्थियों को दी हुई दूसरी आर्थिक रियाजतों +

शिक्षण के विधायियों को	शिक्षण के विधायियों को		शिक्षण के विधायियों को		शिक्षण के विधायियों को		कुल जोड़
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	
(म) वजीके और वृत्तियां देने वाले सीत सरकार द्वारा नगरपालिकाओं पंचायत समिति स्वयं स्कूल के सीत से	२	४	६	८	१०	१२	१६
अन्य साधन	३	५	७	९	११	१३	१५
सब वजीकों और वृत्तियों के कुल जोड़							
(न) अन्य वार्डिक (भाषिक) रियायतें							
[i] केन्द्रीय न राज्य सरकार							
[ii] अन्य राज्य सरकार							
[iii] नगरपालिका पंचायत समिति							
[iv] अन्य साधन							
(स) पूरी फीस माफ़ी							
(द) विधायियों की संख्या जहां पर शिक्षा मुफ्त हो जाती है।							

...३१ मार्च.....को कार्य करने वाले स्कूल छात्रापकों की सूची

प्रायः०=प्राथमिक, मा०=माध्यमिक

सारिणी नम्बर ३ (अ) वार्षिक परीक्षाफल

[illegible]

सारिणी नम्बर ३ (ब) पूरक परीक्षाफल

हार्द स्कूल	प्राइवेट	रेगुलर
कक्षा १०वीं		
हायर सेकेंडरी		
कक्षा ११वीं	प्राइवेट	रेगुलर

राजस्थान असाैनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम १९६१ द्वारा
निर्धारित नवीन वेतन शृङ्खलायें

(शिक्षा विभाग से सम्बन्धित वेतन दरें ही यहां पर दी जा रही हैं)

वेतन शृङ्खला संख्या	वेतन शृङ्खला
१.	४५-१-७०
२.	५०-१-७०-२-७६ दक्षतावरी-२-८०
३.	६५-१-७०-२-९०
६.	७५-३-९०-४-११०-५-१३० दक्षतावरी-५-१६०
८.	७५-४-९५-५-१०५ दक्षतावरी ५-१३० दक्षतावरी-५-१६०
९.	९०-४-१०२ दक्षतावरी-४-११०-५-१५०
१०.	९०-४-११० दक्षतावरी ५-१५५-७११-१७०
११.	१०५-५-२००
१२.	१०५-५-१५०-८-१९०-१०-२४०
१३.	११५-५-१५५-१०-१६५ दक्षतावरी १०-२३५-२५०
१४.	१३०-५-१५५-१०-२३५-२५०
१६.	११५-५-१५५-१०-२५५-दक्षतावरी १०-२९५-१२११-३२०-३३५
१७.	१७०-१०-३१०-१२११-३३५
१८.	१७०-१०-३१०-१२११-३८५
१९.	२००-१०-३१०-१२११-४३५
२०.	१५५-१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५

२१. २२५-१०-२७५ दक्षतावरी १०-२८५-१५-४३५-२५-४८५
२२. २८५-२०-३८५-२५-५१०-५४०
२३. २२५-१५-२७०-२०-३६०-२५-६४०
२४. २७५-२०-३३५-२५-५६०-३०-६५०
२६. २८५-२५-५१० दक्षतावरी २५-५६०-३०-८००
२७. ३६०-२५-५६०-३०-५६० दक्षतावरी ३०-८६०-६००
२८. ५५०-३०-८२० दक्षतावरी ३०-८५०-५०-६५०
२९. ५५०-३०-८२० दक्षतावरी ३०-८५०-५०-११००
३०. ६५०-५०-१२५०
३१. ६५०-५०-१४००
३२. १०५०-५०-१५००
३५. १६५०-५५-१८८०-१००-२०००

(संशोधित वेतन) नियम १९६१ के अन्तर्गत वेतन क्रम के चयन के लिए
विकल्प-प्रपत्र (Form of option)

[नियम ६ (२) के अनुसार]

(१) मैं एतद् द्वारा १ सितम्बर सन् १९६१ से संशोधित वेतन क्रम का चयन करता हूँ ।

(२) मैं मेरे निम्नलिखित स्थायी/अस्थायी पद का वर्तमान वेतन शृंखला को जब तक जारी रखने को चयन करता हूँ ।

मैं जब तक कि मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि न आजावे ।

मैं मेरे वेतन में अभिवृद्धि कर उसे रुपये तक पहुंचाने वाली वेतन वृद्धि की तिथि न आजावे ।

मैं अपनी वर्तमान वेतन शृंखला को छोड़ न हूँ अथवा उसमें वेतन लेना बंद न कर हूँ ।

वर्तमान वेतन शृंखला.....

दिनांक

हस्ताक्षर.....

स्थान

नाम " "

पद

कार्यालय

मैं जो काम के नहीं हों, उन्हें काट दिया जावे ।

राजस्थान शिक्षा सेवा (सामान्य शाखा)

१ नाम पद	२ नवीनीकरण वेतन श्रृंखला	३ संशोधित वेतन श्रृंखला	४ वेतन श्रृंखला	५ विवरण
वरिष्ठ श्रृंखला का पद, अर्थात्:— उप शिक्षा संचालक। उप संचालक, बोर्डोफिस ड्यूरी। आचार्य, मध्यमक प्रशिक्षण महाविद्यालय। आचार्य, कालेज का फिजीकल एज्यूकेशन। आचार्य, शाहूल पब्लिक स्कूल।	५००-३०-८००-५०-६००, 	५५०-३०-८२०-२० दक्षतावरी	—	—
प्रथम साधारण श्रेणी पद, अर्थात्:— निरीक्षण विद्यालय। सहायक संचालक। उप-आचार्य, कालेज आफ फिजीकल एज्यूकेशन। प्रस्तोता (Registrar) विभागीय परीक्षा।	३००-२५-५५०-३०-७०० 	३०-८५०-५०-६५० 	३६०-२५-५६०-३०-५६० दक्षतावरी ३०-८६०-६०० (न्यूनतम वेतन रु. ४३५/००)	(२७)

द्वितीय साधारण श्रेणी पद, अर्थात्:—

ग्रन्थापक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं का मिश्रित कलेवर ।

२५०-२५-५५०-३०-७००
२५-७५०,

२८५-२५-५१० दसताबरी
२५-५६०-३०-८०० (२६)

तृतीय साधारण श्रेणी पद, अर्थात्:—

प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकायें बहुउद्देशीय तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

३००-२५-६००,

२७५-२०-३३५-२५-५६०
३०-६५० (न्यूनतम वेतन रु.
३३५ प्रतिमाह) (२४)

चतुर्थ साधारण श्रेणी पद, अर्थात्:—

परिष्ठ व्याख्याता, कालेज आफ फिजि-
कल एज्युकेशन ।

२५०-१५-४००-२५-६००,

२२५-१५-२७०-२०-३६०
२५-६४० (न्यूनतम वेतन
रु. २७० प्रतिमाह) (२३)

पंचम साधारण श्रेणी पद, अर्थात्:—

प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकायें, उच्चविद्यालय, वैसिक एस. टी. सी. विद्यार्थन स्कूल ।

उप निरीक्षक शिक्षणालय ।

२५०-१५-४००-२०-५००

२८५-२०-३८५-२५-५१० (२२)
५४०,

मन्त्रापक प्रचार्य, टी. टी. सी. प्रजमेर

राजस्थान शिक्षा सेवा (महानिद्यालय शाखा)

र श्रेणी (Selection grade) पदः—

प्राचार्य, एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कालेज ।	१६५०-७५-१८००-१०००-१०००	१६५०-७५-१८००-१०००-१००० (३५)
संचालक ।	१०००-५०-१५००	१०५०-५०-१५०० (३२)
प्राध्यापक, असैनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल और मार्टीनिंग इन्जीनियरिंग ।	६००-५०-१४००	६५०-५०-१४०० (३१)
प्रभुतकार (Reader), असैनिक इलेक्ट्रीकल, मैकेनिकल तथा मार्टीनिंग इन्जीनियरिंग प्राचार्य, स्नातकोत्तर महानिद्यालय ।	६००-३०-६००-५०-११०० ७००-५०-१२००	६५०-५०-१२५० (३०) ६५०-५०-१२५० (न्यूनतम वेतन रु. ७५०/००० प्रतिमाह) (३०)
वरिष्ठ मृदाला पद, अर्थात्— प्राचार्य, स्नातक महानिद्यालय । नियम विभागध्यक्ष जहाँ स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती हो ।	५००-३०-८००-५०-६००,	५००-३०-८००-५०-६०० (२८) ८५०-५०-६५०
प्रथम साधारण श्रेणी पद अर्थात्— सहायता प्राध्यापक इन्जीनियरिंग कालेज ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी ।	३५०-२५-७००-३०-८५०,	३६०-२५-७५०-२०-५६० (२७) दक्षतावरी ३०-८६०-६०० (न्यूनतम वेतन रु. ३८५/०० प्रति माह)

द्वितीय साधारण श्रेणी पदः—

स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के व्याख्याता और विभागाध्यक्ष जहाँ स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है (इसमें इन्जीनियरिंग कालेज के व्याख्याता तथा प्राध्यापक जिनका सम्बन्ध नान इन्जीनियरिंग विषयों से है, सामान्य शाखा के अतिरिक्त अध्यापक ।

प्रविशण विद्यालय के व्याख्याता, और कुपि महाविद्यालय के व्याख्याता जिनका सम्बन्ध कुपि भिन्न विषयों से है, समाविष्ट हैं, लेकिन अप्रावैधिक विषय और पशु चिकित्सा विषय पशु चिकित्सा और पोलो टैक्नीक महाविद्यालयों के व्याख्याताओं का समावेश नहीं है ।

संचालक, संस्कृत शिक्षा—

प्राध्यापक, राजस्थान महाविद्यालय जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर स्थायी आचार्य स्तर के संस्कृत महाविद्यालयों के आचार्य ।

(२६) सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक, ग्रह विज्ञान के पद की राजस्थान शिक्षा सेवा की महाविद्यालय शाखा के कलेक्टर से सम्बन्धित किया गया है तथा इसी शृंखला में रखा गया है ।

२५०-२५-५५०-३०-७००-
२५-७५०

२८५-२५-५१० दक्षतावरी
२५-५६०-३०-८००

५००-३०-८००-५०-६००

विशेष वेतन रु. १५०/८००

५००-३०-८००-५०-१०००

५००-२५-६५०-३०-८००

(जयपुर) २५०-१५-४००-

२५-६०० (उदयपुर) ११०-५-

१३५-१०-२२५ (जोधपुर)

(२६)

(२८)

जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर स्थित प्राचार्य स्तर के संस्कृत महाविद्यालयों के प्राध्यापक

राजस्थान महाविद्यालय ध्यास्याता-

कॉमलर, वोकेशनल माइडेंस न्यूरो

जिला समाज शिक्षा अधिकारी आठियों विस्तृत अधिकारी

(समाज शिक्षा) सहायक संचालक संस्कृत शिक्षा

अलवर, सीकर, नाथद्वारा स्थित शास्त्री स्तर के संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य

अमरसर, मोहनपुरा, महापुरा व काला-देरा स्थित उपाध्याय स्तर के संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य

ग्राम्य शोध संस्थान

उप संचालक

२८५-२५-५१० दक्षतावरी २५- (२६)

५६०-३०-८००

२५०-१५-४००-२५-६०० जयपुर, उदयपुर, जोधपुर-गौ-

२८५-२५-५१० दक्षतावरी २५- (२६)

५६०-३०-८००

२५०-२५-५०० दक्षतावरी २५-

७५०

२२५-१५-२७०-२०-३६०-२५- (२३)

६४० (न्यूनतम नैतन २७% होगा)

२८५-२०-३६५-२५-१०-५४० (२२)

२५०-१५-४००-२०-५००

२५०-१५-४००-२५-६०० (अलवर)

२००-१०-२८०-१५-४०० (नाथद्वारा)

११०-५-१-३५-१०-२२५ (सीकर)

२८५-२०-३६५-२५-१०-५४० (२२)

२००-१०-२८०-१५-४००

२८५-२५-५१० दक्षतावरी २५- (२६)

५६०-३०-८०० (न्यूनतम वेतन

३३५/-होगा)

तकनीकी शिक्षा

उप संचालक

पोलीटेक्निकों के प्राचार्य

पोलीटेक्निकों में सिविल इंजिनियरिंग

व मैकेनिकल इंजीनियरिंगों के विभा-

गाध्यक्ष

पोलीटेक्निक में इन्जिनियरिंग विषयों

के व्याख्याता

पोलीटेक्निक में वर्कशॉप

सुपरिन्टेन्डेंट

तकनीकी शिक्षण केन्द्र के प्राचार्य

२५०-१५-४००-२५-६००

२२५-१५-२७०-२०-३६०-
२५-६४० (न्यूनतम वेतन
२७०/- होगा)

७००-३०-१०००-५०-१२००
७००-३०-१०००-५०-१२००
७००-३०-१०००

६५०-५०-१२५० (न्यूनतम
७५० रु. होगा) (३०)
५५०-३०-८२० दक्षतावरी
३०-८५०-५०-११०० (न्यून-
तम वेतन ७६० रु.) (२६)

३५०-२५-७००-३०-८५०

३६०-२५-५६०-३०-५६०- (२६)

दक्षतावरी ३०-८६०-६००-
(न्यूनतम वेतक ३८५ रु.)

३००-२५-७००

२८५-२५-५१०-दक्षतावरी-
२५-५६०-३०-८०० (न्यूनतम
३३५ रु.)

विभिन्न विभागों में समान पाये जाने वाले पद

२००-१०-२५०-१५-४००

२५-४५०

१५०-१०-२५०-१२३-३००

१५५-१०-२२५-१५-४३५ (२०)

२५-४८५ (न्यूनतम वेतन
१७५ रु.)

ये दोनों प्रकार के पद मिलकर
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का
गठन करेंगे।

१७५-१०-२७५-१२३-३५०

१५०-१०-२५०-१२३-३००

८०-५-१२०-८-१६०-१०

२००

२००-१०-३१०-१२३-४३५ (१६)

१७०-१०-३१०-१२३-३३५ (१७)

१०५-५-१५०-८-१६०-१० (१२)

२४०

जूनियर प्रकाउन्ट्स सर्विस के पद

प्रकाउन्टेन्ट्स

उच्च विभागाध्यक्ष के कार्यालय-

अधीक्षक

अधीनस्थ कार्यालयों के अधीक्षक

वरिष्ठ लेवल (U. D. C.) विभा-

गाध्यक्ष कार्यालयों के लिये)

निम्न लिखित विभागाध्यक्षों के कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी इस श्रेणी में टाईपिस्ट स्टोर क्लर्क, प्रसिस्टेड स्टोरकीपर भी सम्मिलित हैं।

सुवर्ण श्रेणी कर्मचारी
जमादार, दफ्तरी, लायन्सरी बाय

अलवर, सीकर नाथद्वारा स्थित शास्त्रास्तर के महा विद्यालयों में व्याख्याता

जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर स्थित संस्कृत, महा विद्यालय में प्राधुनिक विषयों के व्याख्याता

अलवर, सीकर तथा नाथद्वारा स्थित संस्कृत महा विद्यालयों में प्राधुनिक विषयों के व्याख्याता

डिमोन्ट्टेर
स्नातकोत्तर महा विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष, राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष शिबीजल

पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड १,
उच्चतर एवं बहुउद्देशीय विद्यालयों में किसी विषय का इन्चार्ज

६०-४-८०-४-१०० दशतावरी

५-१३०

२५-१-४०

३०-१-४५ साथ में ५ रुपया विशेष वेतन

१५०-१०-२५०-१२३-३०० (अलवर) सीकर व नाथद्वारा में—कोई नहीं

१५०-१०-२५०-१२३-३००

१५०-१०-२५०-१२३-३०० अलवर, सीकर व नाथद्वारा में कोई नहीं

२००-१०-२८०-१५-४००

६०-४-१०२ दशतावरी ४- (६)

११०-५-१५०

४५-१-७० (१)

५०-१-७०-२-७६ दशतावरी (२)

२-८०

२२५-१०-२७५ दशतावरी- (२१)

१०-२८५-१५-४३५-२५-

४८५

२२५-१०-२७५ दशतावरी- (२१) इस श्रृंखला में अध्यापक ग्रेड कहलायेंगे।

१०-२८५-१५-४३५-२५-

२८५

वरिष्ठ अध्यापक, वाणिज्य महा-
विद्यालयों में सक्षिप्त लिपि निर्देशक,
स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्या-
लयों में शारीरिक प्रशिक्षण

सकुल पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक	२००-१०-२५०-१५-४००-२५- ४५०	२००-१०-२१०-१२॥-४३५ (१६)
एज्यूकेशन करेवान के सुपरवाइजर डिवीजनल लायन्स रिजन ग्रेड २ एन्फोर्स मेन्ट आफिसर	१७५-१०-२७५-१२॥-३५०	
विभागीय परीक्षाओं का उपप्रसूता	१७५-१०-२७५-१२॥-४००	

दुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में संगीत
अध्यापक
अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में कला
अध्यापक
अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में क्राप
मास्टर
वीकानेर अनाथालय का अधीक्षक
दुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में इन्स्ट्रक्टर
(अध्यापक)
दुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में शारीरिक
प्रशिक्षक

२५०-१०-२५०-१२॥-३००	१७०-१०-३१०-१२॥-३५५ (१८)
--------------------	-------------------------

शारीरिक प्रशिक्षक पद पर भविष्य में उन्हीं की नियुक्ति की जावेगी।
जिनहोंने ११५-५-१५५-१०-२२५
दक्षतावरी १०-२६५-१२॥-३२०-
३३५ की वेतन गृहला से तीन
वर्ष तक कार्य किया हो या समान
अनुभव व योग्यता होवे।

१७०-१०-३१०-१२३-३३५ (१७)

१५०-१०-२५०-१२३-३००

कला व विज्ञान महा विद्यालयों में
शारीरिक प्रशिक्षक (उनके प्रलावा
जो वेतन गृहला २२५-१०-२६५-
१५-४३५-२५-४६५ से है)

अधीक्षक, मंत्रालय, जयपुर
बोर्डिंगल गार्डेन्स थूरो मे जनरल
असिस्टेंट
शारीरिक शिक्षा महा विद्यालय मे
जूनियर लेक्चरर

१७०-१०-३१०-१२३-३३५ (१७)

१५०-१०-२५०-१२३-३००

उच्च विद्यालयो मे कला क्लपट व
संगीत के अध्यापक, जो कि स्नातक
होवे तथा विभाग द्वारा निर्धारित
प्रशिक्षण प्राप्त होवे।

११५-५-१५५-१०-२५५- (१६)

दक्षता वरी १०-२६५-१२-
३२०-३२५

६०-५-१५०

विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के
प्रश्न पत्र सहित स्नातक शारीरिक
प्रशिक्षक

शारीरिक प्रशिक्षक में स्वीकृत
डिप्लोमा प्राप्त स्नातक शारीरिक प्रशि-
षक, महा विद्यालयों में संगीत अध्या-
पक (व्याख्याता नहीं)

११०-५-१३५-१०-२२५

कला विद्यालयों में सितार, वायलिन
य चित्रकारी के अध्यापक

तीस हजार अथवा अधिक जनसंख्या वाले शहर में स्थित पुस्तकालयों के प्रो. ड० के जिला पुस्तकालयाध्यक्ष

026-4-03-2-06

संस्कृत शिक्षा संघालनालय में सहायक
उपनलरलषक

वोकिशनल गाइडेंस ब्यूरो में समाज-सेवक उच्चतर विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष डिप्लोमा पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष स्नातक महा विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष निर्दिष्ट उच्च विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष

220-2-234-20-334

50-X-220-5-250-20
200

उच्च विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों में अभ्यर्थित स्नातक अध्यापक संस्कृत महा विद्यालयों के प्रवेशिका एवं पूर्व प्रवेशिका छात्रों तथा संस्कृत पाठ-शालाओं में शास्त्री अध्यापक

20-1-28

90-70-4-200

इस वेतन शृंखला में उन्होंने को
वेतन मिल सकेगा जिनकी कि
नियुक्ति विशेष रूप से कार्यकार
या स्थायी तौर पर हुई हों अन्यथा
वेतन शृंखला संख्या १० में वेतन
पाने के वे प्राधिकारी होंगे ।

2304.244-03-KK2.K022 (22)

इस वंश में शृंगला के अध्यापक अध्यापक ग्रेड २ कहलायेंगे

(3)

११५-५-११५-१०-१६५-
दक्षतावरी १०-२३५-२५०

उक्त एवं उत्पत्तर विद्यालयों में प्रामाणिक, स्नातक अध्यापक, एग्जोसिटेंट असिस्टेंट, बाल संस्तर में स्नातक सहायक अध्यापिका

११०-५-१३५-१०-२२५

११५-५-१५५-१०-१६५-
दस्तावेज १०-२३५-२५०

(१३)

उत्पत्तर साध्यमिक विद्यालयों में फील्डमेन, पुस्तकालयों में कैटेलागर-क्लासीफायर

१०-५-६०-५-१३०

(१०) जो पुस्तकालयाध्यक्ष विभाग द्वारा स्वीकृत प्रविक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त किये हुये होंगे उसे मूल वेतन १०२ रु. मिलेगा ।

तीस हजार से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर स्थित डिस्ट्रिक्ट लाय-ब्रैरिंगन ग्रेड २ (१३०-५-१५५-१०-२३५-२५० की वेतन शृंखला के अतिरिक्त),

७०-५-६०-५-१४०

तहसील व ब्लॉक लायब्रैरियन डिप्टी-जनरल पुस्तकालयों के कैटेलागर व क्लासीफायर,

६०-५-१२०-६-१६०-१०-२०० की वेतन शृंखला के अतिरिक्त उच्च विद्यालयों के अन्य पुस्तकालयाध्यक्ष

६०-५-११० दस्तावेज ५-
१५५-७११-१७०

यह वेतन शृंखला उन्हीं तहसील व ब्लॉक लायब्रैरियनों पर लागू होगी जहाँ पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ३००० या उससे अधिक हो ।

साधारण अध्यापक

५०-४-७०-५-५०-५०-

(भ) जो योग्यता प्राप्त नहीं हो

२-६०-३-७५-४०-१-५०

(क) जो मिडिल पास हो किन्तु अप्रति-
क्षित हो ।

(स) बर्नार्ड्स स्कुल फार्मिन पास हो
तथा प्रशिक्षित भी हो

(क) मिडिल स्कुल पास एवं प्रशिक्षित

हो
(ग) मैट्रिक्युलेट लेकिन अप्रशिक्षित

साधारण अध्यापक, जो इण्टरमीडियेट
पास हो किन्तु

७०-४-६०-५-१००

अप्रशिक्षित हो

साधारण अध्यापक जो

६०-४-५०-५-१३०

(अ) मैट्रिक व प्रशिक्षित हो

७०-४-६०-५-१४०

(क) इण्टर पास व प्रशिक्षित हो

संस्कृत पाठशालाओं एवं संस्कृत महा-
विद्यालयों के पाठशाला लण्डों के संस्कृत
अध्यापक जो कि

(भ) प्रशिक्षिका पास हो

४०-१-५०

(क) उपाध्याय हो

५०-४-७०-५-५०

५०-२-६०-३-७५

७०-४-६०-५-१००

७५-४-६५-५-१०५ दशतामरी (न) इस शुंखला के अध्यापक, ये ३३
५-१३० दशतामरी ५-१६० के कहलायेंगे

विद्यालयों तथा सामान्य विद्या- लयों में कला, क्राफ्ट, संगीत एवं तबला अध्यापक	५०-२-६०-३-७५ ५०-४-७०-५-८० ६०-३-६० ६०-४-८०-५-१३० ७०-४-८०-५-१४०	७५-४-८५-५-१०५ दशता- वरी ५-१३० दशतावरी ५-१६०	(८)
कार्यरिक्त प्रविशक जो कि (म) योग्यता रहित हो, (य) मैट्रिक्यूलेंट, प्रविशक प्रमाण पत्र सहित कहरे, यूरो विद्यालय में सहायक अध्यापक	५०-२-६०-३-७५ ५०-४-८०-५-१३० ६०-४-८०-५-१३०	७५-३-६०-४-१०-५-१३० (६) दशतावरी ५-१६०	
कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में— गैसमैन गैस बोयलर गैस मिस्त्री मैकेनिक राजस्थान कालेज आयवर में पंप ड्राईवर टुक लिफ्टर लायन्स रो वाय महाविद्यालयों में सेवोरेटो बोयलर वर्कशाप में हेल्पर गवर्नमेंट कालेज सिरोही में लायन्स रो वाय	५०-३-६५-१०० — — ६०-४-१००-५-१२० ५०-२-६० ३०-१-४५ — — — ३०-१-४५-२-५५	६५-१-७०-२-६० (२) ५०-१-७०-२-७६ दशतावरी २-८० (२)	

एन० सी० सी० में लस्कर	४०-१-५०	५०-१-७०-२-७६ दक्षावरी (२)
एयर स्क्वेड्रन, नैवल विंग एण्ड	—	२-८०
आर्बालिरीविंग	—	
जसवंत कालेज जोधपुर में एनीमल	२५-१-४०	
कैचर		
एयरोनोटिकल इंस्ट्रक्टर		
स्टोरकीपर	१००-५-१५०	४५-१-७० (१)
महाराजा भूपाल महोविद्यालय		१०५-५-२०० (११)
उदयपुर में स्टोर पीयान	३०-१-४५-२-५५	४५-१-७० (१)
मैस मैनजर (साहुल पब्लिकस्कूल)	८०-५-१२०-८-१६०-१०-२००	१०५-५-१५०-८-१६०-१०-२४०
ग्रंथ अभिलेख—		
ग्रंथीक्षक	१७५-१०-२७५-१२॥-३५०	२००-१०-३१०-१२॥-४२५ (१६)
पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)	१५०-१०-२५०-१२॥-३००	१७०-१०-३१०-१२॥-३३५ (१७)
कस्टोडियन एण्ड कंजरेक्टर		
ग्रसिस्टेंट	११५-५-१३५-१०-२२५	१३०-५-१५५-१०-२३५-२५० (१४)
एस. बी. एस. इन्जिनियरिंग कालेज		
आचार्य के प्रशासकीय सहायक	२५०-२०-३५०-२५-५००	२८५-२०-३८५-२५-५१०-५४० (२२)
ग्रसिस्टेंट वर्कशाप सुपरिन्टेण्डेंट		२२५-१०-२७५ दक्षावरी
भारतीय प्रशिक्षक	२००-१०-२८०-१५-४००	१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५ (२३)
पुस्तकालयाध्यक्ष		
नाम टेक्नीकल डिपार्ट्मेंटर ग्रेड I	२००-१०-२५०-१५-४००-४५०	

बिमानस्ट्रुटर (टैक्नीकल)	१७५-१०-२७५-१२॥-३७५	२००-१०-३१०-१२॥-४३५ (१६)
वर्कशाप इन्सट्र	१५०-१०-२५०-१२॥-३५०	१७०-१०-३१०-१२॥-३६५ (१८)
नाग टैक्नीकल डिमानस्ट्रुटर जो कि स्नातक हो	१००-५-१५०-१०-३००	११५-५-१५५-१०-२२५ दक्षता-वरी १०-२६५-१२॥-३२०-३३५ (१६)
ब्रूस्टसमैन	८०-५-१००-८-१४०-१०-२००	१०५-५-१५०-८-१६०-१०-१४० (१२)
आयनर प्रापेटर	८०-५-१७५	१०५-५-२०० (११)
सेम्पलिंग प्रसिस्टेन्ट	६०-४-८०-५-१३०	६०-४-११० दक्षतावरी ५-१५५ (१०)
		७॥-१७०
प्रसिस्टेन्ट गैसमैन	३०-१-४५	५०-१-७०-२-७६ दक्षतावरी (२)
लायब्रेरी प्रटेन्डेन्ट		२-८०
हैड गार्डनर	४०-१-५०	५० १-७०-२-७६ दक्षतावरी २ ८० (२)
		(न्यूनतम वेतन ६५) क. होमा)
प्राकृत्य शोध संस्थान		
सर्वेयर कैंडेलाग प्रसिस्टेन्ट	१५०-१०-२५०-१२॥-३००	१७०-१०-३१०-१२॥-३३५ (१७)
जूनियर रिसर्च प्रसिस्टेन्ट		
सायन्सरी, प्रसिस्टेन्ट, कापीस्ट	६०-५-१३०	६०-४-११० दक्षतावरी ५- (१०)
मेन्टर	५०-३-८०-५-१००	१५५-७॥-१७०
मेम्बरिफिकान्ट प्रटेन्डेन्ट	३०-१-५५	७५-३-६०-४-१०-५-१३० (६)
		दक्षतावरी ५-१६०
		५०-१-७०-२-७६ दक्षतावरी (२)
		२-८०

महनी की शिक्षा

बोर्ड के सदस्यों में महात्मक वर्षगांठ

आसीक

से मानविकी काल

मेमबर (डिप्टी)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

मेमबर (कैड ?)

१००-१०-२००-१५-४००

२००-१०-२५०-१५-४००

२५-४५०

१७५-१०-२७५-१२॥-३५०

२००-१०-२००-१५-४००

१५०-१०-२५०-१२॥-३००

२००-१०-२५०-१०-२५०-१२॥-३००

१२॥-३००

२००-१०-२५०-१० २२५-१२॥-

३००

२२५-१०-२७५ दसतावरी (२१)

१००-२०५-१५-४३५-२५०-

४०५

२००-१०-३१०-१२॥-४३५ (१६)

२२५-१०-२७५ दसतावरी (२१)

१०-२०५-१५-४३५-२५०-४०५

१७०-१०-३१०-१२॥-३३५ (१७)

११५-१०-१५५-१०-२५५ (१६)

दसतावरी १०-२६५-१२॥-

३२०-३३५

११५-१०-१५५-१०-२२५ दसतावरी (१६)

तावरी १०-२६५-१२॥-३२०-

३३५ (ग्युनसम वेतल १३५

रुपया)

पोलिटेक्नीक में नान टेक्निकल डिप्लॉमेडर्स [जो स्नातक हों]	१००-५-१५०-१०-३००	१५५-५-१५५-१०-२५५ दशतावरी १०-२६५-१२११-३२०-३३५	(१६)
हैड ड्राफ्ट्समैन			
ड्राफ्ट्समैन	६०-५-१२०-८-१६०-१०-२००	१०५-५-१५०-८ १६०-१०- (१२)	
सहायक छात्रावास अधीक्षक	२००	२४०	
इन्स्ट्रुमेंट डिप्लॉमेड/टेक्नीशियन	८०-५-१७५	१०५-५-२०० (११)	
सेक्रेटरी प्रिन्सिपल	६०-५-८०-५-१३०	६०-५-१२० दशतावरी ५- (१०)	
नान टेक्निकल इन्स्ट्रक्टर जो कि स्नातक नहीं हों	८०-५-१२०-८-१६०-१०-२२०	१५५-७११-१७०	
ट्रेसर	५०-५-६०-५-१२०	७५-५-६५-५-६५-५ दशतावरी ५-१६०	(८)
टेक्नीशियन (मैकेनिक भी शामिल है)			
हैमरमैन	६०-५-८०-५-१३०	७५-३-६०-५-१०-५-१३० (६)	
इन्जिन ड्राईवर		दशतावरी ५-१६०	
ट्रेसर	३०-१-५५	५०-१-७०-३-७६ दशतावरी (२)	
वर्कशॉप प्रिन्सिपल		२-८०	
सर्वे खलासी, ट्रेसर (भाई० टी०)	३५-१-५०	४५-१-७०	(१)

विशेष वेतन, जिसे कि नई वेतन श्रृंखला में मूल वेतन में सम्मिलित करके समाप्त कर दिया

पद	वर्तमान वेतन श्रृंखला	विशेष वेतन	नई वेतन- श्रृंखला संख्या
संस्कृत शिक्षा-संचालक	} ५००-३०-८००-	१५०)	१२६)
संचालक, ग्रंथ अभिलेख विभाग		१००)	(२६)

विशेष वेतन जो कि पूर्णतया समाप्त कर दिया गया

वे कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ लेखक जो कि कैशियर, स्टोरकीपर, स्टोरक्लर्क आदि का कार्य करें और जिन्हें अपनी जमानत की रकम के आधार पर विशेष वेतन नहीं मिलता अपितु निर्धारित विशेष वेतन ही दिया जाता है।	—	१५) अथवा १२)	(६) तथा (१२)
---	---	--------------	--------------

विशेष वेतन जो कि कठिन कर्तव्यों तथा उच्च उत्तरदायित्वों के लिए जारी रहेगा

पद	विशेष वेतन की रकम	नई वेतन श्रृंखला संख्या	विशेष विवरण
माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक	२० से लेकर ३०) शाला के आकार के अनुसार	—	—
सहायक उप निरीक्षक	३०)	(१८)	
भूग, वहरों व अंधे बच्चों के विद्यालय में सहायक अध्यापक	२०)	(८)	
योग्यता प्राप्त अकाउन्टेन्ट (राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मंडल में)	२०)	(२०)	जमानत की धन राशि के कारण अन्य कोई विशेष वेतन नहीं मिलेगा

कैशियर स्टोरकीपर आदि सरकारी अधिसूचना जिसके पास रकम अथवा स्टोर का काम हो तथा जिन्हें जमानत देनी पड़ती हो। संख्या एक० १६ (२) एक० II/५३ दिनांक १-३-५४ में निर्धारित जमानत की रकम के अनुसार ३ से लेकर १०) तक

विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कनिष्ठ लेखक

५)

(६)

विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में वरिष्ठ लेखक	१०)	(१२)
योग्यता प्राप्त वरिष्ठ लेखक जो कि अकाउंट क्लर्क का काम करता हो	१०)	}
वरिष्ठ लेखक जो हैडक्लक का काम करता हो	२०)	
वरिष्ठ लेखक जो कि मैक्शन इन्चार्ज का काम करता हो	१५)	
वरिष्ठ लेखक जो कि स्टैनोग्राफर-क्लर्क का काम करता हो	२५)	
उन कार्यालयों में मार्टिक्लोस्टाईल मशीन के इन्चार्ज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जहाँ मशीनमैन का अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं हो।	५)	
स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उपाचार्य का कार्य करने वाले प्राध्यापक	७५)	(२८)

(चूंकि अध्यापक वर्ग से मुख्यतया निम्न तीन वेतन क्रम सम्बन्ध रखते हैं अतः उनका विस्तृत विवेचन यहां दिया गया है)

वेतन क्रम संख्या ८— ७५-४-६५-५-१०५-दशतावरी-५-१३०-दशतावरी-५-१६०

(१) स्तानक क्रम एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा यह वेतन शृंखला सब प्रकार के अध्यापकों पर लागू होगी। इस शृंखला के अध्यापक, ग्रेड ३ के अध्यापक कहलायेंगे। यह वेतन शृंखला अन्य विभागों के अध्यापक यथा समाज कल्याण, कारागृह, श्रम आदि विभागों में भी लागू होगी।

(२) सामान्यतया भर्ती प्रशिक्षित मैट्रिक्यूलेट की की जावेगी। सभी मामलों में प्रशिक्षण से अभिप्राय सरकारी संस्थाओं में दिये जाने वाले पाठ्यक्रम को पूरा करने से होगा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया प्रशिक्षण होगा किन्तु नान मैट्रिक्यूलेट अध्यापकों के मामले में सरकार का शिक्षा विभाग निर्धारित कर सकता है कि निश्चित वर्षों का अनुभव ही प्रशिक्षण के समान मान लिया जायेगा।

(३) एक सामान्य अथवा संस्कृत अध्यापक, जो कि मैट्रिक्यूलेट नहीं हो अथवा प्रशिक्षित भी नहीं हो और न जिसने प्रवेशिका भी पास की हो, को ७५) प्रतिमास का निर्धारित वेतन मिलेगा। संगीत, क्राफ्ट तथा आर्ट्स के अध्यापक अथवा शारीरिक प्रशिक्षण इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

(४) उच्च मूल वेतन एवं अग्रिम वेतन वृद्धियां निम्नानुसार दी जा सकेंगी।

नई नियुक्ति पर ६१) जो कि (१) प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक्यूलेट साधारण अध्यापक हो।

(२) गूंगे, वहरों व अंघों के विद्यालय में अध्यापक हो

और जो कि विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त हो ।

(३) तीन वर्षों के अध्यापन—अनुभव सहित उपाध्याय हो अथवा प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक्यूलेट हो ।

नई नियुक्ति पर १००) जो कि (१) आर्टस् क्राप्टस और संगीत में मैट्रिक्यूलेट अध्यापक हो और जिसके पास विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र हो ।

(२) मैट्रिक्यूलेट शारीरिक प्रशिक्षण हो और जिसके पास विभाग से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र हो ।

दो अग्रिम वेतन वृद्धियां, मंचयी प्रभाव सहित अथवा ६१) का मूल वेतन, इन दोनों में से जो अधिक हो—ऐसे व्यक्ति को जो सेवा में हो और जो कि

(१) नान मैट्रिक्यूलेट प्रशिक्षित सामान्य अध्यापक हो किन्तु जिसने मैट्रिक परीक्षा पास करली हो ।

(२) नान मैट्रिक्यूलेट, आर्टस् क्राप्टस तथा संगीत का अध्यापक अथवा शारीरिक प्रशिक्षक हो और जिसने मैट्रिक परीक्षा पास करली हो बशर्ते कि वह विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र रखता हो ।

संचयी प्रभाव सहित, दो वेतन वृद्धियां प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित मैट्रिक्यूलेट अध्यापक हो वृद्धियां अथवा १००) का मूल वेतन इन दोनों कि सरकार से मान्यता प्राप्त आर्टस्, वेतन—इन दोनों में से जो अधिक हो क्राप्टस संगीत एवं शारीरिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो—ऐसे व्यक्ति को जो कि प्राप्त कर लिया हो ।

(५) वर्तमान कर्मचारियों एवं नई नियुक्तियों पर निम्न दक्षतावारी लागू होगी:—

१०५) यह दक्षतावारी

(१) ऐसे नान मैट्रिक्यूलेट प्रशिक्षित सामान्य अध्यापक जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास नहीं की हो ।

(२) ऐसे मैट्रिक्यूलेट अप्रशिक्षित सामान्य अध्यापक जब तक कि वे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेवे ।

के द्वारा पार नहीं जावेगी ।

१३०)

यह दक्षतावारी एक नॉन मैट्रिक्यूलेट आर्टस क्राप्टस संगीत एवं शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा तब तक पार नहीं की जावेगी जब तक कि वह मैट्रिक पास नहीं कर लेवे और विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेवे ।

वेतन क्रम संख्या १३

११५-५-१५५-१०-१६५ दक्षतावारी १०-२३५-२५०

- (१) यह वेतन क्रम समस्त स्नातक अध्यापको तथा संस्कृत पाठशालाओं एवं संस्कृत महाविद्यालयों के पाठशाला खंडों के शास्त्री अध्यापकों पर लागू होगा—
- (२) सामान्यतया प्रशिक्षण स्नातकों की नियुक्ति की जावेगी । सामान्य अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण से अभिप्राय “शिक्षण में उपाधी” एवं शिशु शालाओं के सम्बन्ध में मान्देसरी ट्रेनिंग से होगा ।

उच्च मूल वेतन निम्नानुसार दिया जा सकेगा—

- १२५) का मूल वेतन— एक ऐसे व्यक्ति को जो कि
- (१) विज्ञान में स्नातक हो, अप्रशिक्षित हो, सामान्य अध्यापक के रूप में ३१ मार्च १९६४ तक जिसकी नियुक्ति हाल ही में की गई हो ।
- (२) सेवा में हो तथा संशोधित शृंखला में वेतन १२५) से कम हो और जो कि विज्ञान का स्नातक हो ।
- १४०) का मूल वेतन ऐसे व्यक्ति को जो कि
- (१) “शिक्षण” में स्नातक हो और जिसकी कि हाल ही में सामान्य अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई हो ।
- (२) मान्देसरी प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक हो और जिसकी कि शिशु शाला में सहायक अध्यापिका के रूप में नियुक्ति हुई हो ।
- (३) प्रवेशिका कक्षाओं को पढ़ाने का ७ वर्ष का अनुभव हो और जो कि शास्त्री तथा आचार्य हो ।
- (४) सेवा में हो तथा नये वेतन क्रम में १४०) से कम वेतन पाता हो और जो कि एक स्नातक अध्यापक, स्नातक सहायक अध्यापिका (शिशु शाला में), अथवा संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेशिका पढ़ाने का ७ वर्ष से कम अनुभव होने के साथ शास्त्री अध्यापक होते हुए क्रमशः “शिक्षण में उपाधि” अथवा मान्देसरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या आचार्य की उपाधि आदि प्राप्त करें ।

(३) वर्तमान कर्मचारियों एवं नई नियुक्तियों पर दसतावरी निम्नानुसार लागू होगी—

१६५) पर आने वाली दसतावरी

निम्न द्वारा पार नहीं की जावेगी ।

- (१) उच्च विद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक शाला में स्नातक अध्यापक जब तक कि वह शिक्षण में उपाधि प्राप्त नहीं कर लेवे ।
- (२) शिशु शाला में स्नातक सहायक अध्यापिका जब तक कि वह मान्देसरी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेवे ।
- (३) एक संस्कृत अध्यापक जब तक कि वह आचार्य अथवा प्रवेशिका कक्षाओं पढ़ाने का ७ वर्ष का अनुभव पाकर शास्त्री नहीं बन जावे ।

वेतन क्रम संख्या-२१

२२५-१०-२७५ दक्षतावरी १०-२८५-१५-४३५-२५-४८५

(१) यह वेतन क्रम केवल निम्न पदासीन व्यक्तियों पर ही लागू होगा वशतें कि वे निर्धारित योग्यता वाले हों—

पद

योग्यता

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष
इंजीनियरिंग एवं कृषि महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष
स्टेड लायन्स रियन एवं डिबीजनल लायन्स रियन ग्रेड-१
स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शारीरिक
प्रशिक्षक

स्नातक, पुस्तकालय विज्ञान में
डिप्लोमा एवं ३ वर्ष का अनुभव
स्नातक एवं शारीरिक प्रशिक्षण
में डिप्लोमा तथा ३ वर्ष का
अनुभव ।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में
वाणिज्य विषयों में डिप्लोमा स्टेड,
गैर तकनीकी विषयों में व्याख्याता, जो कि
राजस्थान शिक्षा सेवा नियम से सम्बद्ध नहीं हों,
स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में विज्ञान
विषयों में डिप्लोमा स्टेड

संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर
उपाधि ।

(२) २७५ की दक्षतावरी निम्न पदासीन कर्मचारियों (वर्तमान एवं नवनियुक्त) द्वारा तब तक पार
नहीं की जा सकेगी जब तक कि वे उनके लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर लेवे—

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक—

पैरा १ उपरोक्त में वर्णित
योग्यता

उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में

बी. एड.

विषयों के इन्चार्ज वरिष्ठ अध्यापक

—

ऐसे वर्तमान कर्मचारियों के लिए जिनका कि वेतन नये वेतन क्रम में २६५) या इससे ऊपर
निर्धारित किया गया हो, दक्षतावरी ३००) पर लागू होगा । जिनका वेतन ३००) या इससे अधिक
निश्चित किया गया हो, उनके लिए कोई दक्षतावरी नहीं होगी ।

वर्तमान वेतन के समकक्ष नवीन वेतन दरो में कितना वेतन होगा, इसके लिये निम्न तालि-
कार्यें दी जा रही हैं, अतः सम्बद्ध वर्तमान वेतन शृंखला देखें ।

वेतन शृंखला संख्या १

नवीन वेतन शृंखला

४५-१-७०

वर्तमान वेतन शृंखला

२५-१-४०

४०) निर्धारित

२५-१-४०+५) विशेष वेतन

३०-१-४०

३०-१-४५,

३०-१-४५-२-५५

वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	कुल वर्तमान पारिश्रमिक
४५	१०	५५	२५	३०	५५
४६	१०	५६	२६	३०	५६
४७	१०	५७	२७	३०	५७
४८	१०	५८	२८	२०	५८
४९	१०	५९	२९	३०	५९
५०	१०	६०	३०	३०	६०
५१	१०	६१	३१	३०	६१
५२	१०	६२	३२	३०	६२
५३	१०	६३	३३	३०	६३
५४	१०	६४	३४	३०	६४
५५	१०	६५	३५	३०	६५
५६	१०	६६	३६	३०	६६
५७	१०	६७	३७	३०	६७
५८	१०	६८	३८	३०	६८
५९	१०	६९	३९	३०	६९
६०	१०	७०			
६१	१०	७१			
६२	१०	७२			
६३	१०	७३			
६४	१०	७४			
६५	१०	७५	४०	३५	७५
६६	१०	७६	४१	३५	७६
६७	१०	७७	४२	३५	७७
६८	१०	७८	४३	३५	७८
६९	१०	७९	४४	३५	७९
७०	१०	८०	४५	३५	८०

(२)

नवीन वेतन शृंखला	वर्तमान शृंगलापे			
५०-१-७०-२-७६-	३०-१-४५	+५) का विशेष वेतन	३०-१-४५-२-५५	३०-२-५० ४०-२-६०
दक्षतावरी-२-८०	३०-१-५०			
	३०-१-५५			
	३५-१-४५			
	३५-१-५०			
	४०-१-५०			

वेतनदर महंगाई योग			वेतनदर महंगाई वर्तमान परिश्रमिक का योग			वेतनदर महंगाई वर्तमान परिश्रमिक का योग			वेतनदर महंगाई वर्तमान परिश्रमिक का योग		
५०	१०	६०	३०	३०	६०	३०	३०	६०	३०	३०	६०
५१	१०	६१	३१	३०	६१	३१	३०	६१			
५२	१०	६२	३२	३०	६२	३२	३०	६२	३२	३०	६२
५३	१०	६३	३३	३०	६३	३३	३०	६३			
५४	१०	६४	३४	३०	६४	३४	३०	६४	३४	३०	६४
५५	१०	६५	३५	३०	६५	३५	३०	६५			
५६	१०	६६	३६	३०	६६	३६	३०	६६	३६	३०	६६
५७	१०	६७	३७	३०	६७	३७	३०	६७			
५८	१०	६८	३८	३०	६८	३८	३०	६८	३८	३०	६८
५९	१०	६९	३९	३०	६९	३९	३०	६९			
६०	१०	७०									
६१	१०	७१									
६२	१०	७२									
६३	१०	७३									
६४	१०	७४									
६५	१०	७५	४०	३५	७५	४०	३५	७५	४०	३५	७५
६६	१०	७६	४१	३५	७६	४१	३५	७६			
६७	१०	७७	४२	३५	७७	४२	३५	७७	४२	३५	७७
६८	१०	७८	४३	३५	७८	४३	३५	७८			
६९	१०	७९	४४	३५	७९	४४	३५	७९	४४	३५	७९
७०	१०	८०	४५	३५	८०	४५	३५	८०			

७२	१०	८२	{ ४६ ३५ ८१ ४७ ३५ ८२	४७ ३५ ८२	४६ ३५ ८१
७४	१०	८४	{ ४८ ३५ ८३ ४९ ३५ ८४	४९ ३५ ८४	४८ ३५ ८३
७६	१०	८६	{ ५० ३५ ८५ ५१ ३५ ८६	५१ ३५ ८६	५० ३५ ८५
७८	१०	८८	{ ५२ ३५ ८७ ५३ ३५ ८८	५३ ३५ ८८	५२ ३५ ८७
८०	१०	९०	{ ५४ ३५ ८९ ५५ ३५ ९०	५५ ३५ ९०	५४ ३५ ८९

(८) — भाग — १

नवीन वेतन दर				
७१-४-९५-१०५	४०-१-५०	५०-२-६०-३-७५	५०-४-७० ५-८०	६०-३-९०
दक्षतावरी-५-१-१३०				
दक्षतावरी-५-१-१६०				

वेतनदर	महंगाई	योग	वेतनदर	महंगाई	योग	वेतनदर	महंगाई	योग	वेतनदर	महंगाई	योग	वेतनदर	महंगाई	योग
७५	१०	८५	४०	३५	७५	५०	३५	८५	५०	३५	८५			
			४१	३५	७६									
			४२	३५	७७									
			४३	३५	७८									
			४४	३५	७९									
			४५	३५	८०									
			४६	३५	८१									
			४७	३५	८२									
			४८	३५	८३									
			४९	३५	८४									
			५०	३५	८५									
७६	१०	८६				५२	३५	८७	५४	३५	८९			
						५४	३५	८९						
८३	१०	९३				५६	३५	९१	५८	३५	९३			
						५८	३५	९३						

८७	१०	६७										
८१	१०	१०१		६०	४०	१००				६०	४०	१००
८५	१०	१०५		६३	४०	१०३	६२	४०	१०२	६३	४०	१०३
१००	१०	११०		६६	४०	१०६	६६	४०	१०६	६६	४०	१०६
				६९	४०	१०९	७०	४०	११०	६९	४०	१०९
				७२	३८	११०				७२	३८	११०
				७५	३५	११०	७५	३५	११०	७५	३५	११०
१०५	१०	११५					८०	३५	११५	७८	३५	११३
११०	१०	१२०								८१	३५	११६
										८४	३५	११९
११५	१०	१२५								८७	३५	१२२
										९०	२५	११५
१२०	१०	१३०										
१२५	१०	१३५										
१३०	१०	१४०										
१३५	१०	१४५										
१४०	१०	१५०										
१४५	१०	१५५										
१५०	२०	१६०										
१५५	२०	१७५										
१६०	२०	१८०										

(न) भाग—२

नवीन वेतन दर			
७५-४-६५-१०५-	६०-४-८०-५-१३०	७०-४-९०-५-१००	८०-५-१२०-८-१६०-
दक्षतावरी-५-१३०		७०-४-९०-५-१४०	१०-२२०
दक्षतावरी-५-१६०			

वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग
७५	१०	८५									
७९	१०	८९									
८३	१०	९३									
८७	१०	९७									
९१	१०	१०१	६०	४०	१००						

६५	१०	१०५	६४	४०	१०४						
१००	१०	११०	६८	५०	१०८	७०	४०	११०			
			७२	३८	११०	७४	३६	११०			
१०५	१०	११५	७६	३५	१११	७८	३५	११३			
			८०	३५	११५		८०	३५	११५		
११०	१०	१२०	८५	३५	१२०	८२	३५	११७	८५	३५	१२०
११५	१०	१२५	९०	३५	१२५	८६	३५	१२१	९०	३५	१२५
						९०	३५	१२५			
१२०	१०	१३०	९५	३५	१३०	९५	३५	१३०	९५	३५	१३०
१२५	१०	१३५									
१३०	१०	१४०	१००	४०	१४०	१००	४०	१४०	१००	४०	१४०
१३५	१०	१४५	१०५	४०	१४५	१०५	४०	१४५	१०५	४०	१४५
१४०	१०	१५०	११०	४०	१५०	११०	४०	१५०	११०	४०	१५०
१४५	१०	१५५	११५	४०	१५५	११५	४०	१५५	११५	४०	१५५
१५०	२०	१७०	१२०	४०	१६०	१२०	४०	१६०	१२०	४०	१६०
			१२५	४०	१६५	१२५	४०	१६५			
			१३०	४०	१७०	१३०	४०	१७०	१२८	४०	१३८
१५५	२०	१७०				१३५	४०	१७५			
१६०	२०	१८०				१४०	४०	१८०	१३६	४०	१७६

(६)

नवीन वेतन शृंखला			वर्तमान वेतन दर		
६०-४-१२०-दक्षतावरी-४-११०-५-१५०			६०-४-८०-५-१३०		
वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग
६०	१०	१००	६०	४०	१००
६४	१०	१०४	६४	४०	१०४
६९	१०	१०८	६८	४०	१०८
१०२	१०	११२	७२	३८	११०
			७६	३५	१११
१०६	१०	११६	८०	३५	११५
११०	१०	१२०	८५	३५	१२०
११५	१०	१२५	९०	३५	१२५
१२०	१०	१३०	९५	३५	१३०

राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

[२३५]

१३०	१०	१४०	१००	४०	१४०
१२५	१०	१३५			
१३५	१०	१४५	१०५	४०	१४५
१४०	१०	१५०	११०	४०	१५०
१४५	१०	१५५	११५	४०	१५५
१५०	२०	१७०	१२०	४०	१६०
			१२५	४०	१६५
			१३०	४०	१७०

(१०)

नवीन वेतन दर			वर्तमान वेतन दर								
६०-४-११०-वक्षतावरी-											
५-१५५-७११-१७०			६०-४-८०-५-१३०			७०-४-९०-५-१४०			८०-५-१३०		
वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग
८०	१०	१००	६०	४०	१००						
८४	१०	१०४	६४	४०	१०४						
८८	१०	१०८	६८	४०	१०८						
१०२	१०	११२	७२	३८	११०	७०	४०	११०			
			७६	३५	१११	७४	३६	११०			
१०६	१०	११६	८०	३५	११५	७८	३५	११३			
११०	१०	१२०	८५	३५	१२०	८२	३५	११७			
११५	१०	१२५	९०	३५	१२५	८६	३५	१२१	८०	३५	१२५
						९०	३५	१२५			
१२०	१०	१३०	९५	३५	१३०	९५	३५	१३०	८५	३५	१३०
१२५	१०	१३५									
१३०	१०	१४०	१००	४०	१४०	१००	४०	१४०	१००	४०	१४०
१३५	१०	१४५	१०५	४०	१४५	१०५	४०	१४५	१०५	४०	१४५
१४०	१०	१५०	११०	४०	१५०	११०	४०	१५०	११०	४०	१५०
१४५	१०	१५५	११५	४०	१५५	११५	४०	१५५	११५	४०	१५५
१५०	२०	१७०	१२०	४०	१६०	१२०	४०	१६०	१२०	४०	१६०
			१२५	४०	१६५	१२५	४०	१६५	१२५	४०	१६५

१५५	२०	१७५	१३०	४०	१७०	१३०	४०	१७०
१६२॥	२०	१८२॥	१३५	४०	१७५	१४०	४०	१८०
१७०	२०	१९०						

(१२)

नवीन वेतन दर			वर्तमान दर			८०-५-१२०-८-१६०-१०-२००		
१०५-५-१५०-८-१९०-१०-२४०			८०-५-१००-८-१४०-१०-२००					
वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग
१०५	१०	११५	८०	३५	११५	८०	३५	११५
११०	१०	१२०	८५	३५	१२०	८५	३५	१२०
११५	१०	१२५	९०	३५	१२५	९०	३५	१२५
१२०	१०	१३०	९५	३५	१३०	९५	३५	१३०
१२५	१०	१३५						
१३०	१०	१४०	१००	४०	१४०	१००	४०	१४०
१३५	१०	१४५				१०५	४०	१४५
१४०	१०	१५०	१०८	४०	१४८	११०	४०	१५०
१४५	१०	१५५				११५	४०	१५५
१५०	२०	१७०	११६	४०	१५६	१२०	४०	१६०
			१२४	४०	१६४	१२८	४०	१६८
१५८	२०	१७८	१३२	४०	१७२	१३६	४०	१७६
१६६	२०	१८६	१४०	४०	१८०	१४४	४०	१८४
१७४	२०	१९४	१५०	४०	१९०	१५२	४०	१९२
१८२	२०	२०२	१६०	४०	२००	१६०	४०	२००
१९०	२०	२१०	१७०	४०	२१०	१७०	४०	२१०
२००	२०	२२०	१८०	४०	२२०	१८०	४०	२२०
२१०	२०	२३०	१९०	४०	२३०	१९०	४०	२३०
२२०	२०	२४०	२००	४५	२४५	२००	४५	२४५
२३०	२०	२५०						
२४०	२०	२६०						

(१३)

नवीन वेतन दर	वर्तमान दर	११०-५-१३५-	७०-४-२०-५-१००
११५-५-१५५-१०-१६५	६०-५-१४०	१०-२३५	
दसतावरी-१०-२३५-२५०			

वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग	वेतन दर	महंगाई	योग
११५	१०	१२५	६०	३५	१२५				७०	४०	११०
									७५	३५	११०
									७५	३५	११३
									८२	३५	११७
									८६	३५	१२१
									९०	३५	१२५
१२०	१०	१३०	८५	३५	१३०				९५	३५	१३०
१२५	१०	१३५							१००	४०	१४०
१३०	१०	१४०									
१३५	१०	१४५	१००	४०	१४०						
१४०	१०	१५०	१०५	४०	१४५						
१४५	१०	१५५	११०	४०	१५०	११०	४०	१५०			
१५०	१०	१६०	११५	४०	१५५	११५	४०	१५५			
१५०	२०	१७०	१२०	४०	१६०	१२०	४०	१६०			
						१२५	४०	१६५			
						१३०	४०	१७०			
१७५	२०	१९५				१३५	४०	१९५			
१८५	२०	२०५				१६५	४०	२०५			
१९५	२०	२१५				१७५	४०	२१५			
२०५	२०	२२५				१८५	४०	२२५			
२१५	२०	२३५				१९५	४०	२३५			
२२५	२०	२४५				२०५	४५	२५०			
२३५	२०	२५५				२१५	४५	२६०			
२५०	२०	२७०				२२५	४५	२७०			

(३३)

नवीन वेतन श्रृंखला				
१११-५-१५५-१०-	वर्तमान दरे	११०-५-१३५-	६०-५-१२५ १०-	१००-५-१५०-
२२५ दक्षतावरी-१०				
२६५-१२११-३२०-	६०-५-१४०	१०-२२५	२२५-१२११-३००	१०-३००
३३५				

[illegible]

३२० ० ३२०
३३५ ० ३३५

२८० ४० ३२०

{ २८७॥ ३५ ३२२॥ २८० ३५ ३२५
३०० ३५ ३३५ ३०० ३५ ३३५

(१७)

नवीन वेतन शृंखला	वर्तमान वेतन दरें		१७५-१०-२७५-	१५०-१०-२५०-
१७०-१०-३१०- १२॥-३३५	१५०-५-२००- १०-२५०	२००-१०-३००	१२॥-३००	१२॥-३००
वेतनदर महंगाई योग	वेतनदर महंगाई योग	वेतनदर महंगाई योग	वेतनदर महंगाई योग	वेतनदर महंगाई योग
१७० २० १९०	१५० ४० १९०			१५० ४० १९०
१८० २० २००	{ १५५ ४० १९५ १६० ४० २००			१६० ४० २००
१९० २० २१०	{ १६५ ४० २०५ १७० ४० २१०			१७० ४० २१०
२०० २० २२०	{ १७५ ४० २१५ १८० ४० २२०		१७५ ४० २१५	
२१० २० २३०	{ १८५ ४० २२५ १९० ४० २३०		१८५ ४० २२५	१८० ४० २२० १९० ४० २३०
२२० २० २४०	१९५ ४० २३५		१९५ ४० २३५	
२३० २० २५०	२०० ४५ २४५	२०० ४५ २४५	२०५ ४५ २५०	२०० ४५ २४५
२४० २० २६०	२१० ४५ २५५	२१० ४५ २५५	२१५ ४५ २६०	२१० ४५ २५५
२५० २० २७०	२२० ४५ २६५	२२० ४५ २६५	२२५ ४५ २७०	२२० ४५ २६५
२६० २० २८०	२३० ४५ २७५	२३० ४५ २७५	२३५ ४५ २८०	२३० ४५ २७५
२७० २० २९०	२४० ४५ २८५	२४० ४५ २८५	२४५ ४५ २९०	२४० ४५ २८५
२८० २० ३००	२५० ४५ २९५	२५० ४५ २९० २६० ४० ३००	२५५ ४० २९५	२५० ४५ २९५
२९० २० ३१०		२७० ४० ३१०	२६५ ४० ३०५	२६२॥ ४० ३०२॥
३०० २० ३२०				
३१० १० ३२०		२८० ४० ३२०	२७५ ४० ३१५	२७५ ४० ३१५
३२२॥ ० ३२२॥			२८७॥ ३५ ३२२॥	२८७॥ ३५ ३२२॥
३३५ ० ३३५		{ २९० ३५ ३२५ ३०० ३५ ३३५	३०० ३५ ३३५	३०० ३५ ३३५

[illegible]

Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1950

राजस्थान असेनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनर्विचार) नियम १९५०

इस शिक्षा नियम संहिता के अध्याय १२ में अध्यापको की सेवा की शर्तों का जहां उल्लेख किया गया है, वहां अध्याय के प्रारम्भ में नोट (घ) में इन नियमों का भी वर्णन किया गया है, अतः इन नियमों में से केवल आवश्यक नियम नीचे दिये जाते हैं।

सामान्य

१. (क) "नियुक्ति अधिकारी"—(Appointing Authority) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में इसका अर्थ होगा:—

(१) वह प्राधिकारी जो कि उस सेवा के लिए नियुक्ति करने के अधिकार रखता हो जिसका कि वह राज्य कर्मचारी उस समय (For the time being) सदस्य हो अथवा सेवा की उस श्रेणी (Grade) के लिये जिसमें कि वह राज्य कर्मचारी उस समय के नियम सम्मिलित हो, या

(२) वह प्राधिकारी जो कि उस पद (Post) के लिए नियुक्ति कर सकता हो जिसे कि वह राज्य कर्मचारी उस समय धारण किये हुये है, या

(३) वह प्राधिकारी जिसने कि उस राज्य कर्मचारी को उस सेवा, ग्रेड या पद पर, जैसी कि सूरत हो, नियुक्त किया था, या

(४) जहां कोई राज्य कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य रह चुकने या किसी अन्य सेवा में या किसी अन्य पद (Post) को स्थाई रूप से धारण कर चुकने पर राज्य की सेवा में लगातार रह रहा हो तो वह प्राधिकारी जिसने कि उसको उस सेवाओं या उस सेवा की किसी श्रेणी या पद पर नियुक्त किया,

जो भी प्राधिकारी सबसे ऊंचा हो।

द्वारा कि जब विभाग के अध्यक्ष ने अपने अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्याधिकृत (Delegate) किये हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष नियम २३ (२) (क) (ख) के प्रयोग के लिये नियुक्त प्राधिकारी होगा। (देखिये राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) दिनांक १४-५-६० पृष्ठ ६२)

(ग) "अनुशासन प्राधिकारी" (Disciplinary Authority) से अभिप्राय किसी राज कर्मचारी को दण्ड देने के सम्बन्ध में उस प्राधिकारी में है जो कि इन नियमों के अन्तर्गत उसको वह दण्ड दे सकता है।

(च) राज कर्मचारी (Government Servant) से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सेवा का सदस्य है या जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई असेनिक पद धारण किये हुये है और इसमें सम्मिलित होगा कोई भी वह व्यक्ति जो विदेश सेवा पर (On foreign service) है अथवा जिसकी सेवाएँ किसी स्थायी अथवा अन्य अधिकारी के यहाँ (Disposal) पर दे दी गई हो अथवा वह व्यक्ति जिसकी सेवाएँ अनुवच्य (Contract) पर हो अथवा वह व्यक्ति जो किसी दूसरे स्थान से सेवानिवृत्त हो चुका हो और राजस्थान सरकार द्वारा फिर सेवा में रख लिया गया हो परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो कि केन्द्रीय अथवा दूसरे राज्य की सेवा में हो और

राजस्थान में प्रति नियुक्ति (Deputation) पर सेवा कर रहा हो और जो कि उन्ही नियमों से शासित होता रहेगा जो कि उस पर लागू हो ।

(घ) 'विभागाध्यक्ष' (Head of Department) से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो कि सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन किसी विभाग के अध्यक्ष की तरह अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट (Specified) किया गया हो ।

(ज) 'कार्यालयाध्यक्ष' (Head of Office) से अभिप्राय उस अधिकारी से है जो सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक अधिकारी (Officer) के लिए कार्यालयाध्यक्ष अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट किया गया हो ।

३. प्रयुक्ति [Application]:—[१] ये नियम सत्र राज्य कर्मचारियों पर लागू होंगे सिवाय:—

- (क) उन व्यक्तियों के जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र [Union Territories] से प्रति नियुक्त [on Deputation] हों,
- (ख) उन व्यक्तियों के जो सरकार की ऐसी उद्योग संस्थाओं [Industrial Organisation] में नौकर हो जिन्हें समय पर विज्ञप्ति [Notified] किया जाय और जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम [Industrial Disputes Act] के अर्थ में मजदूर [Workmen] हो,
- (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के.
- (घ) उपरोक्त उच्च न्यायालय [High Court] के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जो कि संविधान के अनुच्छेद २२६ के भाग (२) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों (Regulation) से शासित होंगे, (दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय) कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियम १६५३ जो राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) दिनांक ३०-६-५६ में प्रकाशित हुए
- (ङ) राज्य जन सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो कि संविधान के अनुच्छेद ३१८ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों (Regulation) से शासित होंगे ।
- (छ) उन व्यक्तियों के जिनकी नियुक्तियों तथा इन नियमों के अन्तर्गत (Covered) अन्य मामलों के लिए किसी समय में लागू (for the time being in force) किसी कानून के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत ऐसे कानून में सम्मिलित किन्हीं मामलों के संबंध में, विशेष प्रावधान रखा गया हो ।
- (ज) आकस्मिक (Casual) नौकरी में रखे गए व्यक्तियों के—
- [ज] उन व्यक्तियों के जिन्हें एक माह से भी कम अवधि के नोटिस से हटाया [Discharged] जा सकता हो,
- (झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य ।

वर्गीकरण

६. (१) असेनिक सेवाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा ।

(१) राज्य सेवाएँ

(२) अधीनस्थ सेवायें

(३) लेखा (ministerial) सेवाये, और

चतुर्थ श्रेणी की सेवायें ।

(२) यदि एक सेवा में एक से अधिक वर्ग (Cadre) हो तो विभिन्न वर्ग विभिन्न श्रेणियों (Classes) में सम्मिलित की जा सकेंगी ।

७. राज्य सेवा (State Service) में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची १ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची १ में सम्मिलित पदों (Posts) को स्थाई रूप में (Substantively) धारण करते हों और जो पद (Post) किसी अन्य सेवा के वर्ग (Cadre) में नहीं हो ।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चुनाव से पूर्व एड हाक (Adhoc) आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गए हों जो कि वाक्यांश (Clause) (क) में उल्लिखित सेवाओं के वर्ग (Cadre) में सम्मिलित (Borne) हों या जो वाक्यांश (ख) में उल्लिखित हों ।

८. अधीनस्थ सेवा (Subordinate Service) में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची २ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची २ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के वर्ग (Cadre) में नहीं हो ।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चुनाव से पूर्व एड हाक (ad hoc) आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों जो कि वाक्यांश [क] में उल्लिखित सेवाओं के वर्ग (cadre) में सम्मिलित (borne) हों या जो वाक्यांश [ख] में उल्लिखित हों ।

९. लेखक सेवा (Ministrial services) में ये सम्मिलित होंगे:—

(क) अनुसूची ३ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची ३ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा के वर्ग में नहीं हो ।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चुनाव से पूर्व एड हाक आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों जो कि वाक्यांश (क) में उल्लिखित सेवाओं [Adhoc] के वर्ग (Cadre) में उल्लिखित हों या जो वाक्यांश [ख] में उल्लिखित हों ।

१०. चतुर्थ श्रेणी सेवा (Class iv service) में सम्मिलित होंगे ।

(क) अनुसूची ४ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ख) जो व्यक्ति अनुसूची ४ में सम्मिलित पदों को स्थाई रूप से धारण करते हों और जो पद किसी अन्य सेवा वर्ग में नहीं हो ।

(ग) जो व्यक्ति एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार अन्तिम चुनाव से पूर्व एड हाक आधार पर उन पदों पर नियुक्त किये गये हों जो कि वाक्यांश (क) में उल्लिखित सेवाओं के वर्ग (Cadre) में सम्मिलित हों अथवा जो वाक्यांश (ख) में सम्मिलित हों ।

११. (क) सरकार समय समय पर अनुसूचियों के इन्द्राजो मे वृद्धि अथवा परिवर्तन कर सकती है ।

(ख) जहाँ कोई विद्यमान पद किसी अनुसूची मे सम्मिलित नहीं हो तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे भेजा (Refer) जाकर तय किया जायेगा ।

निलम्बन (Suspension)

१३. निलम्बनः—[१] नियुक्ति अधिकारी अथवा जिस अधिकारी के अधीन, नियुक्त अधिकारी है अथवा इस कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य पदाधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकता हैः—

[क] जहाँ कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासन की कार्यवाही सोची जा रही हो अथवा चालू हो या

[ख] जहाँ कि उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध की जांच की जा रही हो या मुकदमा चल रहा हो । परन्तु शर्त यह है कि जहाँ निलम्बन की आज्ञा किसी अन्य अधिकारी ने दी हो तो ऐसा अधिकारी तुरन्त ही उन परिस्थितियों की सूचना (Report) नियुक्ति अधिकारी को देगा जिनमे कि आज्ञा दी गई थी ।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि ४८ घण्टो से अधिक समय से हिरासत में रखा गया हो (detained in custody) आया किसी फौजदारी चार्ज पर अथवा वैसे ही तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निलम्बित कर दिया गया समझा जावेगा और वह अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा ।

(३) जहाँ कि निलम्बित सरकारी कर्मचारी को दी गई बर्खास्तगी, नौकरी से हटाने या अनिवार्यतः सेवा से निवृत्त करने की सजा इन नियमो के अन्तर्गत की गई अपील, नजरसानी या निगरानी में रद्द कर दी गई हो और मामला आगे (further) जाच या कार्यवाही के लिये या किसी और हिदायत के साथ वापिस लौटा दिया गया हो तो उसके निलम्बन की आज्ञा उसको बर्खास्त, नौकरी से हटाने या अनिवार्यतः सेवाओं से निवृत्त करने की मूल (original) आज्ञा की तारीख को और उस तारीख से प्रभावशील (in force) रहेगी ।

(४) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को दी गई बर्खास्तगी नौकरी से हटाने या अनिवार्यतः सेवा से निवृत्त करने की सजा किसी विधि न्यायालय की आज्ञा से रद्द (set aside) कर दी जाये अथवा निरस्त (void) घोषित कर दी जावे और नियुक्ति प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर गौर करने पर उन आरोपों पर आगे जांच करने का तय करे जिन पर कि पहली बार उसे बर्खास्त करने, नौकरी से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त किया गया था तो सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किये जाने, नौकरी से हटाये जाने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा से किये जाने की पहली (original, असल) आज्ञा की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया समझा जायेगा और अगली आज्ञा तक निलम्बित समझा जायेगा ।

(५) इस विषय के नीचे दी गई या दी हुई समझी गई (deemed) निलम्बन की आज्ञा किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा वापिस ली जा सकती है जिसने कि वह आज्ञा दी थी या जिसके द्वारा वह आज्ञा दी गई समझी गई थी अथवा उस प्राधिकारी द्वारा (भी वापिस ली जा

सकती है) जिसके अधीन कि निलम्बन कर्ता अधिकारी हो ।

अनुशासन

१४. सजायों के रूप (किस्में):—निम्नलिखित सजायें ठीक और पर्याप्त (good and sufficient) कारणों से जो कि बताए (record) जायेंगे, आगे बताए गए तरीके के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को दी जा सकती हैं—

(१) परिनिन्दा (censure)

(२) वेतन वृद्धि को या पदोन्नति को रोकना

(३) उपेक्षा (negligence) या किसी कानून, नियम अथवा आज्ञा के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूरा या अंश रूप में वेतन में से (काटकर) वसूल करना ।

(४) नीचे की सेवा, ग्रेड या पद पर या नीचे की समय श्रेणी (Time Scale) में अथवा उसी समय श्रेणी में नीचे के स्तर पर अवनत (तनज्जुल, reduction) कर देना या पेंशन की धरत में नियमानुसार जितनी पेंशन मिलती हो उसमें कम कर देना; (देखिये राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) ता० १६-१-६१ पृष्ठ ५७२ ।

(५) आनुपातिक (Proportionate) पेंशन पर अनिवार्यतः रिटायर कर देना;

(६) नौकरी से हटाया जाना जो कि साधारणतः फिर नौकरी में लिए जाने के लिए नियोन्यता (disqualification) नहीं होगी ।

(७) नौकरी से बर्खास्त किया जाना जो कि साधारणतः फिर से नौकरी में लिए जाने के लिए नियोन्यता होगी ।

स्पष्टीकरण—(१) इस नियम के अर्थ के लिए निम्नलिखित बातें सजा नहीं मानी (not amount) जायेंगी ।

(१) राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार या उसकी सेवा या पद पर लागू (govern) होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा पास करने में असफलता के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि रोक देना;

(२) किसी राज्य कर्मचारी को समय श्रेणी में दक्षताबरी (efficiency bar) पर उस बरी (bar) की लाघने की अयोग्यता के कारण रोक देना;

(३) किसी राज्य कर्मचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसे उस सेवा, ग्रेड अथवा पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से तरक्की न देना;

(४) किसी ऊँची सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी राज्य कर्मचारी को निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर वापिस इस आधार पर अवनत कर देना कि उसे मौका दिया जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद के अनुपयुक्त समझा गया है अथवा किसी प्रशासनीय आधार पर प्रत्यावर्तित (revert) कर देना जो उसके आचरण (conduct) से असम्बन्धित हो ।

(५) परीक्षण काल (प्रोवेशन), पर किसी दूसरी ऊँची सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी को प्रोवेशन की अवधि समाप्त हो जाने पर उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार या प्रोवे-

शन पर लागू (govern) होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार उसे वापिस उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर फिर भेज देना (reversion)

(६) किसी राज्य कर्मचारी को अधिवापिक हो जाने अथवा रिटायर करने (super annuation or retirement) सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से रिटायर कर देना (शब्द 'for' के स्थान पर 'or' रा० रा० भाग ४ (ग) ता० १०-१२-५६ द्वारा प्रस्थापित)।

(७) सेवा की समाप्ति—

(क) ऐसे राज्य कर्मचारी की जिसे प्रोवेशन पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की शर्तों (terms) के अनुसार या प्रोवेशन पर लागू होने वाले नियमों या आज्ञाओं के अनुसार प्रोवेशन की अवधि में ही या उसके बाद।

(ख) सेवा अनुबंध (contract) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए कर्मचारी के, ऐसे अस्थायी (Temp.) राज्य कर्मचारी की नियुक्ति का समय (Period) समाप्त होने के बाद।

(ग) ऐसे राज्य कर्मचारी की जो किसी ऐसे इकरारनामे के अन्तर्गत नौकर रखा गया है, ऐसे इकरारनामे की शर्तों के अनुसार।

(घ) राजस्थान में सम्मिलित होने वाली इकाइयों (रियासतों) में ^{यहाँ बताने का संकेत} ~~अन्य~~ ^{से} कर्मचारी की एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं में से किसी में भी नियुक्ति के लिए चुने जाने या न मिलाए जाने (Non absorptions) के कारण।

१६. बड़ी सजाए देने का तरीका—

(१) पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट १९५० के प्रावधानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम १४ में (४) से (७) तक बताई गई कोई सजा देने की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यथा सम्भव आगे बताई गई कार्य विधि के अनुसार कार्यवाही नहीं करली गई हो।

(२) अनुशासन अधिकारी (Disciplinary authority) जिन आरोपों के आधार पर जांच करना चाहता है, उनके आधार पर निश्चित चार्ज बनाकर लिखित रूप में मय आरोपों के विवरण (Statement of allegations) के कर्मचारी को देगा और उसे निर्धारित अवधि में लिखित उत्तर देने को कहा जायेगा कि आया वह उन आरोपों को स्वीकार करता है या नहीं और आया कि उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं और क्या वह व्यक्तिगत रूप में सुना जाना चाहता है। यदि कोई आरोप कर्मचारी की सफाई से पैदा हो जाय तो उसके लिए अलग चार्ज बनाना जरूरी होगा।

इन नियमों के उपनियम (२) व (३) के प्रयोजन के लिए वह अनुशासन अधिकारी भी सम्मिलित है जो नियम १४ की सजा (१) से (३) तक दे सकता है।

(३) कर्मचारी को अपनी सफाई तैयार करने के लिए सरकारी रेकार्ड का निरीक्षण करने तथा उसमें से उद्धरण लेने की इजाजत दी जायगी परन्तु यदि अनुशासन अधिकारी की राय में निरीक्षण करने तथा उससे उद्धरण लेने की इजाजत दी जाना आवश्यक न हो तो वह लिखित कारण बताकर अनुमति देने से इन्कार भी कर सकता है।

(४) लिखित उत्तर मिलने पर या दी गई अवधि बीत जाने पर भी उत्तर न मिलने की

सूत्र में अनुशासन अधिकारी चाहे तो स्वयं उन चीजों की जांच करेगा जिनको कि कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया हो या इस काम के लिए कोई जांच बोर्ड या जांच अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(५) जांच बोर्ड या जांच अधिकारी के सामने चीजों की पुष्टि में प्रमाण देने के लिए अनुशासन अधिकारी किसी व्यक्ति को नामजद कर सकता है । कर्मचारी भी अपनी ओर से किसी दूसरे राज्य कर्मचारी की जांच के वक्त सहायता के लिए उपस्थित रख सकता है जिसकी स्वीकृति अनुशासन अधिकारी से लेनी होगी, परन्तु कर्मचारी किसी वकील की सहायता जांच में नहीं ले सकता जब तक कि अनुशासन अधिकारी कर्मचारी को वकील साथ में रखने की अनुमति, मामले की परिस्थितियों पर गौर करके न दे देवे ।

(६) जांच अधिकारी चार्जों के विषय में सम्बन्धित (relevant) मौखिक या लिखित साक्षियों पर जांच के दौरान में गौर करेगा । चार्जों के प्रमाणों में पेश होने वाले गवाहों से कर्मचारी को जिरह करने का अधिकार होगा व वह स्वयं भी साक्षी दे सकेगा । चार्जों की पुष्टि करने वाला व्यक्ति भी कर्मचारी व उसके गवाहों से जिरह कर सकेगा । यदि जांच अधिकारी किसी गवाह का कथन लिखने से इनकार कर दे तो इसका लिखित कारण बताना होगा ।

(७) अनुशासन अनुसार जितनापनि पर जांच अधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक चार्ज के विषय में नतीजा दिया जायगा । यदि जांच से पहिले के चार्जों से भिन्न चार्ज प्रमाणित हो तो वह उन पर नतीजा दे सकेगा व शर्तें कि कर्मचारी ने उन चार्जों की आधारभूत बातों को स्वीकार कर लिया हो या उसको उनके विरुद्ध अपनी वरियत पेश करने का अवसर मिल चुका हो ।

(८) जांच के रिकार्ड में ये चीजें सम्मिलित होंगी:—

(१) कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये चार्ज व आरोपों का विवरण जो उसे उपनियम (२) के नीचे दिए गए ।

(२) सफाई में दिया गया लिखित बयान यदि कोई हो;

(३) जांच के दौरान में दिए गए लिखित बयान;

(४) जांच के दौरान में जिस लिखित साक्षी पर विचार किया गया हो;

(५) अनुशासन अधिकारी या जांच अधिकारी की जांच के दौरान में दी गई आज्ञा, यदि कोई हो;

(६) प्रत्येक चार्ज के वास्तव नतीजा भय कारणों के;

(७) यदि अनुशासन अधिकारी ही जांच अधिकारी नहीं है तो वह जांच के रिकार्ड पर गौर करके प्रत्येक चार्ज पर अपना नतीजा देगा ।

१०. (१) यदि इस तरह गौर करने के पश्चात् अनुशासन अधिकारी यह राय कायम करे कि कर्मचारी को नियम १४ में बताई गई सजा (४) से (७) में से कोई एक सजा दी जानी चाहिये तो वह—

(क) कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट और उस पर अपना नतीजा भय असहमति (नाइसफाकी) के कारणों के, यदि हो तो, देगा ।

(ख) उसे एक नोटिस देगा जिसमें बताया जायगा कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही (सजा)

तजवीज की गई है और यह हिदायत करेगा कि वह भारतीय संविधान की धारा ३११ (२) के नीचे उस तजवीज के विरुद्ध जो प्रतिवेदन करना चाहता हो, नियत अवधि में करे।

(३) जिन मामलों में पब्लिक सर्विस कमिशन की राय लेना जरूरी नहीं हो उनमें अनुशासन अधिकारी कर्मचारी को दिये गये नोटिस व उसके प्रतिवेदन पर गौर करके यह निश्चय करेगा कि उसे क्या सजा देना उचित है और वह इस प्रकार की आज्ञा देगा।

(१२) अनुशासन अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा कर्मचारी को बताई जानी चाहिए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट (जहां कि जांच अधिकारी अनुशासन अधिकारी से भिन्न हो) उसके नतीजे और उससे असहमत होने की अवस्था में असहमति (नाडस्तफाकी) के कारण इस कर्मचारी को दिए जाने चाहिए यदि वे पहले ही उसे नहीं दे दिये गये हों। जिन मामलों में पब्लिक सर्विस कमिशन की राय लेना जरूरी हो उनमें उसकी राय को नकल, और यदि अनुशासन अधिकारी उस राय से असहमत हो तो असहमति के कारण सहित, कर्मचारी को दी जानी चाहिये।

विभागीय जांच

भारतीय संविधान का अनु० ३११ (२) बताता है कि केन्द्र या राज्य के किसी असेनिक कर्मचारी को बिना उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताते का समुचित अवसर (Reasonable opportunity) दिये बिना बर्खास्त, हटाया या पदावनत (तनज्जुल) नहीं किया जायेगा। कहना न होगा कि इससे पूर्व राज्य कर्मचारी को बिना कारण बताए बर्खास्त कर दिया जाने पर भी हाईकोर्ट में कोई सहायता नहीं मिल सकती थी क्योंकि संविधान लागू होने से पहले राजस्थान की रियासतों में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को अनुच्छेद ३११ का संरक्षण प्राप्त नहीं था।

अब इस प्रकार की सजाएं देने से पहले एक निश्चित कार्य विधि का पालन किया जाना जरूरी है और यह कार्यविधि (तरीका) इन्हीं नियमों के नियम १६ में व्योरेवार बताई गई है। इसमें गलती होने पर अभी रह जाने पर अनु० ३११ (२) का संरक्षण मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है—विभागीय जांच में अभियुक्त कर्मचारी को प्रस्तावित सजा के विरुद्ध कारण बताते का समुचित अवसर मिलना चाहिये।

माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, एण्ड अपील) बिल के महत्व पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि इनका पालन अक्षरशः—(in letter and spirit) किया जाना चाहिये क्योंकि ये केवल जांच अधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए ही नहीं हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट तो सम्मति मात्र है और उसको मानना या न मानना अनुशासन अधिकारी का काम है और अभियुक्त कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध अनुशासन अधिकारी को कारण बताये और अपने आपको निर्दोष सिद्ध करें अथवा प्रस्तावित सजा से हलकी सजा का भागी बताये। अनुशासन अधिकारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट गौर से पढ़कर उससे सहमति या असहमति मय कारणों के प्रकट करके सजा तजवीज करना चाहिए। जहां जांच अधिकारी ने तो रिपोर्ट की कि अभियुक्त का दोष प्रमाणित नहीं हो सकता और अनुशासन अधिकारी ने बिना उस पर गौर किए कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, वहां पर बर्खास्तगी की सजा रद्द कर दी गई।

अपीलें

२१. सरकार द्वारा दी गई आज्ञाओं की अपील नहीं:—

इस भाग में कुछ भी दिया होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा नियम १४ में बताई गई किसी सजा की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

टिप्पणी:—सरकार द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध मामले में गुण दोषों पर (Merits of case) पर तो कोई अपील नहीं हो सकती है परन्तु यदि ऐसी आज्ञा देते समय इन नियमों में बताई गई कार्य विधि का पालन नहीं किया गया है तो हाई कोर्ट में याचिका (writ) प्रस्तुत की जा सकती है ।

२२. निलम्बन, मोत्तिल) की आज्ञा के विरुद्ध अपीलें:—

सरकारी कर्मचारी को मोत्तिल करने की आज्ञा जिस अधिकारी ने दी है उससे विरुद्ध अपील उस अधिकारी को की जायेगी जिसके अधीन मोत्तिल करने वाला अधिकारी हो ।

२३. सजा देने की आज्ञा के विरुद्ध अपीलें:—

पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवा का सदस्य (जिसमें आर. ए. सी. भी सम्मिलित है) देखिए रा० रा० भाग ४ (ग) ता० १८-५-६१ पृष्ठ ७८

(१) मिनिस्टीरियल और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नियम १४ में दी गई सजा के विरुद्ध अगले उस अधिकारी को कर सकता है जिसके अधीन कि सजा देने वाला अधिकारी हो जब तक कि सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा में किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त न कर दें ।

(२) अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी नियम १४ में बताई गई सजा के विरुद्ध निम्नलिखित को अपील कर सकता है ।

(क) यदि सजा देने वाला अधिकारी नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीन है तो नियुक्ति अधिकारी को

(ख) यदि नियुक्ति अधिकारी ने ही सजा दी हो तो सरकार को ।

(३) राज्य सेवा का अधिकारी जिसे कि नियम १४ में बताई गई सजा सरकार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई हो सरकार को अपील कर सकता है ।

(४) सिविल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियम १४ में बताई गई सजा (४) से (७) देने की अपील अधिकारियों की आज्ञा के विरुद्ध अपील सरकार के पास होगी और सरकार उन पर आज्ञा देने से पूर्व पब्लिक सर्विस कमिशन की राय लेगी । वगैरें कि सिविल और सेशन अदालतों के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के मामले में अन्तिम अपील हाईकोर्ट में होगी ।

२५. अपीलों के लिए अवधि (मियाद)—इस भाग के अन्तर्गत किसी अपील को विचार के लिये तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील उस तारीख से तीन महीने के भीतर पेश नहीं की गई हो जिस दिन की अपील कर्ता को उस की नकल दी गई हो जिसकी कि अपील की गई हो ।

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (अ) विभाग

निलम्बन-आदेश—१

क्रम संख्या.....

दिनांक

११. श्री

(सरकारी कर्मचारी का नाम व पद)

के विरुद्ध एक अनुशासन कार्यवाही विचाराधीन है/चाही जा रही है ।

अतः राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षर कर्ता श्री.....को इसी

समय से निलम्बित (Suspend) करते हैं ।

सरकार के विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि श्री..... निलम्बित अधिकारी का पद व नाम)

को । निलम्बन की अवधि में मिलने वाले निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) के लिये अतिरिक्त आज्ञा जारी की जावेगी ।

सरकार के विशिष्ट सचिव

अनुशासन प्राधिकारी

निलम्बन-आदेश—२

क्योंकि श्री..... (सरकारी कर्मचारी का नाम व पद) के विरुद्ध दण्ड्य अपराध (Criminal Case), के मामले को जांच हो रही है/का मामला न्यायालय के समक्ष है ।

अतः राज्यपाल/निम्नहस्ताक्षर कर्ता, श्री..... को इसी समय से निलम्बित करते हैं ।

सरकार के विशिष्ट सचिव

अनुशासन प्राधिकारी

प्रतिलिपि श्री..... (निलम्बित अधिकारी का पद व नाम) को । निलम्बन की अवधि में मिलने वाले निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त आज्ञा जारी होगी ।

सरकार के विशिष्ट सचिव

अनुशासन प्राधिकारी

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (अ) विभाग/कार्यालय

आज्ञा

क्रम संख्या.....

दिनांक.....

क्योंकि श्री..... (निलम्बित सरकारी कर्मचारी का नाम) को निलम्बित करने की एक आज्ञा दिनांक.....को दी गई थी ।

अतः अब राज्यपाल/निम्नहस्ताक्षर कर्ता निलम्बन के अपने उस आदेश को इसी समय से वापिस लेते हैं ।

सरकार के विशेष सचिव

अनुशासन प्राधिकारी

प्रतिलिपि श्री (निलम्बित कर्मचारी का नाम) को
 निम्न आदेश की वापसी के निम्न कारण है (संक्षिप्त कारण दिये जाने चाहिए) ।

सरकार के विशेष सचिव

अनुशासन प्राधिकारी

अभियोग पत्र (Charge Sheet)

क्रमसंख्या

..... कार्यालय

श्री को सूचित किया जाता है कि उसके विरुद्ध राजस्थान
 असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण व पुनर्विचार) नियम १९५८ के नियम १६ के अन्तर्गत,
 एक जांच प्रस्तावित है, जिन कारणों से जांच प्रस्तावित है, वे संलग्न आरोप विवरण पत्र में
 उल्लिखित हैं तथा उन आरोपों के आधार पर बने हुये अभियोग संलग्न अभियोग-विवरण पत्र में
 दिये गये हैं ।

(२) श्री को इस पत्र को प्राप्ति तिथि से दिन की
 अवधि में अपने बचाव के लिए एक लिखित वक्तव्य निम्न हस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत करना चाहिये ।
 साथ में—

(अ) यह भी बताए कि क्या वह अपने बचाव के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहता है ।

(ब) अपने बचाव के लिए बुलाए जाने वाले साक्षियों के नाम व पते भी देवे ।

(स) अपने बचाव में प्रेषित किये जाने वाले पत्रादि की एक सूची भी देवे ।

३. श्री को यह भी सूचित किया जाना है कि यदि वह अपन
 बचाव का पक्ष तैयार करने के लिए सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहें अथवा उद्धरण
 लेना चाहे तो उसे ऐसे अभिलेखों की एक सूची निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देनी चाहिए ताकि इस कार्य
 के लिए उचित सुविधायें दी जाने की व्यवस्था की जा सके उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि
 यदि निम्नहस्ताक्षरकर्ता उन अभिलेखों को इस उद्देश्य के लिए असम्बद्ध समझें अथवा ऐसे अभिलेखों
 तक उसकी पहुंच सार्वजनिक हित के विपरीत समझें तो उसे अभिलेखों को देखने की अथवा उसके
 उद्धरण लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

४. श्री को और सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित
 तिथि तक यदि उसका बचाव में लिखित बयान नहीं पहुंचा तो जांच उसकी अनुपस्थिति में कर दी
 जावेगी ।

५. इस पत्र की प्राप्ति की सूचना भिजवाई जावे ।

विशेष सचिव, सरकार

अनुशासन प्राधिकारी

श्री

.....

.....

अभियोग-विवरण पत्र

श्री (सरकारी कर्मचारी का नाम व पद) के विरुद्ध लगाये हुए अभियोगों का विवरण-पत्र ।

अभियोग—१

कि कथित श्री ने अवधि में का कार्य करते हुये

अभियोग—२

कि उपरोक्त अवधि तथा उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते हुए श्री ने

अभियोग—३

कि उपरोक्त अवधि तथा उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते हुए श्री ने

सरकार के विशेष सचिव
अनुशासन प्राधिकारी

आरोप विवरण पत्र

आरोप विवरण पत्र जिनके आधार पर श्री के विरुद्ध अभियोग लगाए गए हैं—

अभियोग १ से सम्बन्धित आरोप

” २ से ” ”

” ३ से ” ”

नोट:—आरोपों में यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी दंडनीय कैसे हैं अर्थात् किसी विशेष मामले में उसका क्या उत्तरदायित्व था तथा वह उसको करने में कैसे असफल रहा ।

सरकार के विशेष सचिव
अनुशासन प्राधिकारी

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम १९६०

भाग १—सामान्य

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—इन नियमों को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, १९६० कहा जायेगा तथा ये शीघ्र प्रभावशील होंगे ।

टिप्पणी:—ये नियम शिक्षा विभाग के अध्यापकों पर लागू होंगे ।

२. वर्तमान नियम एवं आदेशों का अतिक्रमण—इन नियमों के द्वारा शासित सभी मामलों के सम्बन्ध में वर्तमान सभी नियम व आदेश एतद्द्वारा अतिक्रमित किये जाते हैं, किन्तु ऐसे प्रभावशील नियमों व आदेशों द्वारा या इनके प्रधीन यदि कोई कार्यवाही की गई है तो

उसे इन नियमों के अधीन माना जायेगा ।

३. सेवा की स्थिति—राजस्थान शिक्षा सेवा एक राज्य सेवा है ।

४. परिभाषायें—इन नियमों में जब तक कि विशेष संदर्भ में कोई अन्य अर्थ न हो:—

- (क) 'अयोग' का तात्पर्य राजस्थान जन सेवा आयोग से है ।
- (ख) 'संचालक' का तात्पर्य संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से है ।
- (ग) 'सीधी नियुक्ति' का मतलब पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के अलावा अन्य प्रकार से की गई नियुक्ति से है ।
- (घ) सरकार और राज्य का मतलब क्रमशः राजस्थान सरकार एवं राज्य है ।
- (ङ) 'सेवा' का मतलब राजस्थान शिक्षा सेवा से है ।
- (च) 'अनुसूची' का तात्पर्य इन नियमों की अनुसूची है ।
- (छ) 'सेवा का सदस्य' का मतलब उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के प्रावधानों के अधीन या नियम २ द्वारा अतिक्रमित किये गये नियमों के अधीन सेवा में किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये गये हो ।
- (ज) नियुक्त करने वाले अधिकारी का तात्पर्य राजस्थान सरकार एवं संचालक में से जो कोई भी हो, उससे है ।
- (झ) 'प्रधानाध्यापक' में प्रधानाध्यापिका भी शामिल है ।
- (ञ) 'उप-निरीक्षक' में उप-निरीक्षिका भी शामिल है, एवं
- (ट) शिक्षा सहायक संचालक में शिक्षा सहायक संचालिका (महिला) भी शामिल है ।

५. व्याख्या—जब तक संदर्भ आदि द्वारा अन्य रूप से अपेक्षित न हो तो राजस्थान जनरल बलाजेज अधिनियम, १९५५ (१९५५ का अधिनियम संख्या ८) इन नियमों की व्याख्या के लिये लागू होगा क्योंकि प्रत्येक राजस्थान अधिनियम की व्याख्या के लिये वह लागू होता है ।

भाग २—श्रेणी (केडर)

६. सेवा की संख्या—सेवायें तीन श्रेणियों में हैं ।

(१) निर्वाचन पद (२) उच्च पद (३) निम्न पद तथा उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या अनुसूची में वर्णित संख्या के आधार पर होगी; किन्तु शर्त यह है:—

(१) कि अन्य सभी विपरीत नियमों के प्रावधान से प्रभावित हुये बिना महिला पाठशालाओं या उनके निरोद्धण स्टाफ से सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति केवल सेवा में लगी हुई महिलाओं में से ही की जायेगी ।

(२) कि सरकार समय-समय पर जब भी आवश्यक समझे तो किसी पद को चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी रिक्त रख सकती है, अप्रभावशील, या खत्म कर सकती है या नया बना सकती है, तथा बिना सुझावना दिये अनुसूची में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है ।

नोट:—मॉडेशरी पाठशाला को उपरोक्त प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य खण्ड (Proviso) के लिए महिला पाठशालाओं के रूप में समझा जायेगा:—

७. सेवाओं का प्रारम्भिक गठन—यह सेवा प्रारम्भिक रूप से निम्न प्रकारेण गठित की जायेगी:—

(क) सभी व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूची में उक्त निर्वाचन पद, उच्च पद एवं निम्न पदों पर इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व नियुक्त किये गये थे उन्हें इन नियमों के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किया हुआ समझा जायेगा ।

(ख) सभी ऐसे पद, जिन पर व्यक्ति जन सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गये हैं, या जो अस्थायी तथा स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रथम अवसर में मौलिक रूप से ५० प्रतिशत के हिसाब से इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में से जन सेवा आयोग की सलाह लेकर सरकार द्वारा भरे जायेंगे । इस प्रकार चुने हुए व्यक्तियों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया हुआ समझा जायेगा ।

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख) में कहे गये के अनुसार जो व्यक्ति इन पदों पर मौलिक रूप से निर्वाचन के योग्य नहीं है उन्हें निम्न मौलिक पद पर वापिस कर दिया जायेगा यदि वे उससे किसी पद पर अपना लीयन (Lien) रखते हो या यदि उनका कोई लीयन न हो तो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके स्थान पर प्रत्यक्ष नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा कोई अन्य योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाने पर उन्हें सेवा से अलग कर दिया जायेगा ।

भाग ३—नियुक्ति (भर्ती)

८. नियुक्ति के साधन—(क) इन नियमों के आरम्भ हो जाने के पश्चात् सेवा के लिए सीधी नियुक्तियां केवल अनुसूची में वर्णित तृतीय श्रेणी के पद वाली निम्न साधारण कोटि की ५० प्रतिशत जगहों की पूर्ति के लिये ही की जायेगी ।

(ख) बाकी ५० प्रतिशत निम्न पद वाले साधारण कोटि के पदों को उन व्यक्तियों द्वारा वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता (सीनियोरिटी कम मैरिट) के आधार पर चुन कर भरा जायेगा जो एक उच्च विद्यालय में एक मौलिक रूप के अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया हो किन्तु शर्त यह है कि वे नियम १६ में वर्णित अन्य सब प्रकार की योग्यताओं को पूरा करते हो । इस प्रकार प्रत्येक रिक्त होने वाला स्थान सीधी उन्नति एवं पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

(ग) तृतीय निम्न पदो एवं द्वितीय उच्च एवं प्रथम निर्वाचन पदों के अधीन नियुक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर धीरे धीरे पदोन्नति द्वारा की जायेगी ।

किन्तु शर्त यह है कि सरकार संचालक पद पर किसी आई. ए. एस. अधिकारी को नियुक्त कर सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को किन्हीं शर्तों के आधार पर नियुक्त कर सकती है ।

९ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए पद सुरक्षित रखना:—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्त स्थान, नियुक्त के समय प्रभावी शील ऐसे स्थान सुरक्षित रखने सम्बन्धी राज्यों के आदेशानुसार रखे जायेंगे ।

नोट:—सुरक्षित स्थान कुल खाली स्थानों के आधार पर निश्चित किये जायेंगे, वक़ाय़ा हिस्सों का समाधान ५ वर्ष की अवधि पर एक साथ किया जायेगा । पदोन्नतियां जाति विचार को ध्यान में न रखकर ही दी जायेंगी ।

१०. रिक्त स्थान का निश्चित करना:—इन नियमों के प्रावधानों के आधार पर समय समय पर नियुक्ति के विशिष्ट समय में रिक्त स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक तरीके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्वाचन एवं उच्च स्थानों के संबंध में सरकार तथा निम्न स्थानों के सम्बन्ध में संचालक निश्चित करेंगे।

११. इस सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवार को।

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम का निवासी, या

(ग) नेपाल अथवा पुर्तगाल, या फ्रांस के अधिकार में पूर्व भारतीय प्रदेश का निवासी, या

(घ) भारत का मूल निवासी होना चाहिए जो भारत में निश्चित रूप से बसने के लिये पाकिस्तान से आया हो।

किन्तु शर्त यह है कि यदि वह 'घ' श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा उसके पश्चात् उसे भारत का नागरिक बनने पर ही सेवा में रखा जाएगा।

एक उम्मीदवार जिसके लिए योग्यता का प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी है, उसे राजस्थान जन सेवा आयोग या अन्य नियुक्ति कर्ता अधिकारी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए आज्ञा दी जा सकती है, तथा भारत सरकार द्वारा उसे दिए गए आवश्यक प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी नियुक्ति अस्याई रूप से की जा सकती है।

१२. उम्र:—अनुसूची में वर्णित साधारण वेतन दर के निम्न पद पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार को उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें कि उसकी नियुक्ति आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है, कम से कम २१ वर्ष का होना चाहिए तथा ३० वर्ष की आयु नहीं होना चाहिए। किन्तु शर्त यह है कि—

(१) अनुसूचित जाति या जन जाति के लोगो तथा सरकार के शिक्षा विभाग में मौलिक पद धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र में ५ वर्ष की रियायत दी जा सकेगी।

(२) उन जागीरदार व उनके वच्चों की उम्र जो कि उनकी सहायता के लिये और कोई अन्य उप जागीर नहीं रखते हैं, ४० साल तक की हो सकेगी। यह छूट केवल ३१ दिसम्बर १९६१ तक ही प्रभावशील रहेगी।

(३) महिलाओं की उम्र में ५ वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

१३. शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं अनुभव:—(१) सीवे नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यता होनी चाहिए—

(क) बी. ए. की उपाधि मय शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त, और

(ख) उच्च व उच्चतर शालाओं में अध्यापन का अनुभव या प्रशिक्षण शालाओं (एस. टी. सी.) में अध्यापन का ५ वर्ष का अनुभव या माध्यमिक शाला में प्रशासनात्मक चार्ज का ५ वर्ष का अनुभव एवं उच्च शाला, कक्षाओं की २ वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव या माध्यमिक या जे. टी. सी. शालाओं का ५ वर्ष तक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के अनुभव के अलावा ४ वर्ष तक व्यापक कक्षाओं की पढ़ाने का अनुभव।

(२) निम्न पदो (जूनियर पोस्टो) की निर्वाचन वेतन शृंखला में पदोन्नति करने के लिए एक उम्मीदवार को उर्रोक्त याग्यता को प्राप्त करने के अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त करना चाहिये ।

नोट:—उपरोक्त प्रासंगिक डिग्री या डिप्लोमा भारत में कानून द्वारा स्थापित किमी विश्वविद्यालय के होने चाहिये या किसी विदेशी विश्वविद्यालय के होने चाहिये जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हों ।

१४. चरित्र:—सीधी नियुक्त की जाने के लिए उम्मीदवार का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि उसे सेवा में नियुक्त किया जा सके । उसे उस विश्व विद्यालय के शिक्षात्मक अधिकारी या महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें कि वह अन्तिम बार पढ़ा था तथा दो अन्य प्रमाण पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिये जो उसके महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से या स्वयं से कोई सम्बन्ध न रखते हों तथा जो प्रार्थना पत्र देने की तिथि से ६ माह से पूर्व की तिथि के न हों ।

नोट:—कानून द्वारा दोषी सिद्ध होना अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र नहीं देने के लिए कोई आधार नहीं है । अपराधी होने को परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा यदि इसमें उसका कोई नैतिक पतन या हिसात्मक पाप कार्यों में सम्मिलित होना न पाया जाय अथवा ऐसे आन्दोलनों में भाग न लेना पाया जाय जिसका उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकना हो, तो उसके मूल दोष को उसकी अयोग्यता नहीं समझनी चाहिए ।

१५. शारीरिक योग्यता (फिटनेस):—सेवा में सीधी नियुक्त किये जाने के लिए उम्मीदवार का भस्तिष्क एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये । उसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिये जिससे कि सेवा करने में कठिनाई न हो और यदि उसे नियुक्त कर लिया जाता है तो उसी समय उसे इस कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

१६. अभिशंसा:—केवल नियमों के अधीन सिफारिशों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश को विचार में नहीं लाया जायेगा । यदि छात्र द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने चुने जाने के लिए किसी भी प्रकार का सहारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया हो तो वह नियुक्त किए जाने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

भाग ४ सीधी नियुक्ति का तरीका

१७. आवेदन पत्र आमन्त्रित करना:—सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र, आयोग द्वारा राजस्थान राजपत्र तथा अन्य उचित माध्यम में विज्ञापन द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे । किन्तु शर्त यह है कि सीधी नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवारों का निर्वाचन करते समय आयोग (१) यदि निर्वाचन के पहिले आयोग के पास अतिरिक्त नियुक्तियों की सूचना दी गई हो (२) यदि योग्य व्यक्ति प्राप्य हो तो विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या से ज्यादा से ज्यादा ५० प्रतिशत और व्यक्तियों के नाम 'रिजर्व लिस्ट' में रखने के लिये उन्हें चुन सकती है । ऐसे उम्मीदवारों के नामों की साक्षात्कार की तिथि से ६ माह की अवधि के भीतर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा मांग करने पर सिफारिश की जा सकती है ।

१८. आवेदन के फार्म का नमूना:—प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में

भेजा जायेगा तथा आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगा ।

१६. आवेदन शुल्क:—सेवा में किसी पद पर सीधी नियुक्ति के लिये एक उम्मीदवार को आयोग के पास उससे समय समय पर निर्धारित तरीके द्वारा, आवेदन शुल्क २०)६० या १०)६० यदि वह अनुसूचित जाति या अनुमूलित जन जाति का हो तो जमा कराने चाहिए । यह शुल्क केवल उस समय के अलावा जबकि सरकार विज्ञापन वापिस ले लें, किसी भी कारण वापिस नहीं की जायेगी ।

२०. आवेदन पत्रों की जांच:—आयोग उसके द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों की जांच करेगा तथा इन नियमों के अधीन उतने ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने कि वे उचित समझें ।

२१. आयोग की सिफारिशें:—आयोग ऐसे उम्मीदवारों की एक सूची उनकी वरेण्यता के आधार पर तैयार करेगा जिनको कि वे सम्बन्धित पद या पदों के लिए योग्य समझें तथा फिर इसे संचालक के पास प्रेषित करेंगे ।

२२. संचालक द्वारा चयन:—नियम [६] के प्रावधानों के अनुसार संचालक, नियम २१ के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में से वरेण्यता के आधार पर सबसे प्रथम आने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा किन्तु शर्त यह है कि वह उचित व अनावश्यक जांच के बाद इससे सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसे उम्मीदवार, सम्बन्धित पद या पदों पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार में योग्य समझें जाये ।

भाग ५—पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का तरीका

२३. चयन करने का सिद्धान्त:—(१) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए इन नियमों के प्रावधानों के अधीन ऐसी पदोन्नति प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों में से वरेण्यता एवं योग्यता के आधार पर चयन किया जायेगा ।

(२) पदोन्नति प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जायेगा:—

- (अ) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव ।
- (ब) चातुर्य, शक्ति एवं बुद्धिमानी ।
- (स) समन्वयता, एवं
- (द) सेवा सम्बन्धी पूर्व अभिलेख ।

२४. उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये आवश्यक योग्यता:—कोई भी स्थायी उच्च माध्यमिक पाठशाला का प्रधानाध्यापक (मय बहुद्देशीय शाला के) या उपनिरीक्षक शाला/उच्च विद्यालय का प्रधानाध्यापक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए तब तक योग्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसने ऐसे पद पर कम से कम ५ वर्ष तक सेवा न की हो । इन सेवाओं की सीधी नियुक्ति के लिए जो योग्यता एवं अनुभव निर्धारित किये गये हैं उनको भी इनकी पदोन्नति करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

नोट:—राज्य के राजकीय शिक्षा विभाग की सेवा या व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था

की सेवा जो कि बाद में सरकार द्वारा अपने अधीन करली गई हो, को राजकीय सेवा में गिना जायेगा ।

२५. चयन का तरीका:—(१) (क) जैसे ही यह निर्णय लिया जाता है कि अनुसूचित स्थानों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं तो संचालक पदोन्नति देने के योग्य अधिकतम सेवा वाले अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा जो रिक्त स्थानों की संख्या से ५ गुने से अधिक न होगी तथा वह इसे शिक्षा सचिव के पास उनकी व्यक्तिगत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख (Character Rolls) के साथ भेज देगा ।

(ख) निम्न व्यक्तियों की एक समिति, सूची में दिये गये सभी व्यक्तियों के मामलों जिनको वह आवश्यक समझे, उन्हीं व्यक्तियों का साक्षात्कार करके विचार करेगी तथा रिक्त स्थानों की संख्या से दूने व्यक्तियों का चयन करेगी:—

- (१) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया सदस्य ।
- (२) सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, तथा
- (३) संचालक ।

(ग) इस समिति द्वारा तैयार की गई सूची संचालक द्वारा उसमें सम्मिलित उम्मीदवारों की व्यक्तिगत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख के साथ, तथा साथ में यदि कोई हो, तो ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों की, एक सूची जिनकी पदोन्नति के लिए सलाह ली जानी हो, आयोग के पास भेज दी जायेगी । फिर आयोग उस सूची में दिये गये क्रमानुसार व्यक्तियों के बारे में तथा अन्य सूची के अतिरिक्त व्यक्तियों के बारे में विचार करेगा तथा उनकी योग्यता के आधार पर उन्हीं व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगा जिनकी कि जगह खाली है । इन नामों को उनकी वर्यता के आधार पर लिखा जायेगा तथा उसे संचालक के पास भेज दिया जायेगा ।

नोट:—उपनियम १ (अ) के-कार्य के लिए उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के नामों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापकों में से जिनकी नियुक्ति तिथि पहिले की हो, उसी से गिनी जायेगी ।

२—(क) जैसे ही यह निर्णय किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित तृतीय निम्न पदों, द्वितीय उच्च पदों तथा निर्वाचित पदों में से कुछ को निर्वाचित पदों में बदलना है तो संचालक पदोन्नति के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा । इस सूची में लिये गये व्यक्तियों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से ५ गुने से अधिक न होगी तथा ये व्यक्ति सूची में उपरोक्त नियम (१) में निर्दिष्ट तरीके द्वारा सबसे अधिक सेवा वाले व्यक्तियों में से चुने जायेंगे । संचालक इस सूची को उसमें सम्मिलित व्यक्तियों की व्यक्तिगत फाईलें तथा चरित्र अभिलेख के साथ सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास भेजेगा ।

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों का, जिनको यह उचित समझे, साक्षात्कार करके उनके मामलों पर विचार करेगी तथा प्रत्येक श्रेणी में रिक्त स्थानों की संख्या से दूने व्यक्तियों का चयन करेगी तथा सरकार को भेजने के लिए एक सूची तैयार करेगी ।

- (१) सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

(२) संचालक, शिक्षा विभाग

(३) कम से कम उप सचिव के स्तर का नियुक्त विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(ग) सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, समिति द्वारा तैयार की गई सूची को सरकार के पास उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को चरित्र अभिलेख तथा व्यक्तिगत फाइलों के साथ तथा यदि कोई हो तो अतिक्रमित व्यक्तियों की एक सूची के साथ भेजेगा ।

३—नियम २५, १ (ग) के अधीन आयोग से तथा नियम २५, २ (ख) के अधीन समिति द्वारा प्राप्त सूची के सम्बन्ध में अन्तिम चयन क्रमशः संचालक एवं सरकार द्वारा किया जायेगा तथा चयन किये गये व्यक्तियों के नाम वरेण्यता के आधार पर व्यवस्थित किये जायेंगे ।

भाग ६—नियुक्तियां, परीक्षाकाल एवं स्थायीकरण

२६. सेवा में नियुक्ति:—Junior posts (निम्न पदों) पर नियुक्तियां पद रिक्त होने पर संचालक द्वारा नियम २२ एवं २५ (३) में निर्धारित तरीकों से व्यक्तियों का चयन कर, की जायेगी ।

२७. अस्थाई नियुक्तियां:—एक रिक्त जूनियर पोस्ट, संचालक द्वारा अस्थाई रूप से भरी जा सकती है तथा एक रिक्त उच्च निर्वाचित पद सरकार द्वारा किसी एक व्यक्ति को, जो स्थायी रूप से पद पर नियुक्त किये जाने योग्य हो पदोन्नति देकर भरी जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस सेवा में कोई भी नियुक्ति बिना आयोग की इस मामले में सहमति प्राप्त किए ६ माह से अधिक समय की न होगी तथा आयोग द्वारा सहमति न प्रकट करने पर शीघ्र ही उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

२८. वरीयता (सीनियोरिटी):—पदों की प्रत्येक श्रेणी में वरीयता उस श्रेणी में पद पर स्थाई रूप से नियुक्ति की तिथि के आदेश से निश्चित की जायेगी ।

(१) इस नियम के प्रारम्भ होने से पहले नियुक्त किये गए सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जो पहिले ही निश्चित की जा चुकी है या इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सरकार द्वारा नियमों के अनुसार या पहिले से ही प्रभावशील आदेशानुसार या पूर्व आधार पर निश्चित या संशोधित की जायेगी ।

(२) सीधी नियुक्ति द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी में पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता केवल उनके अलावा जो जगह खाली होने पर उनसे कहने पर भी सेवा में आना नहीं चाहते, नियम २१ के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में कम से कम किये गये उनके नामों के अनुसार ही समझी जायेगी ।

(३) यदि दो व्यक्ति पदों की एक ही श्रेणी में एक ही शिक्षण सत्र में नियुक्त किये गये हों तो जो व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है वह सीधी नियुक्ति द्वारा चुने गये व्यक्ति से वरीय (सीनियर) समझा जायेगा ।

२९. परीक्षा काल—सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त किये गए सभी सेवा के सदस्य नियुक्ति की तिथि से २ वर्ष की अवधि तक परीक्षा के आधार पर रहेंगे किन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में जिन्होंने अध्यापकीय उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है तथा जिन्होंने कम से कम ६ माह का उन कक्षाओं का जो उच्च माध्यमिक से कम न हो, पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर लिया

है, उनका परीक्षा काल २ साल से घटाकर एक साल तक का किया जा सकता है ।

३०—परीक्षाकाल में असन्तोषजनक प्रगति—(१) यदि परीक्षाकाल या उसके अन्तरिम काल में किसी भी समय नियुक्ति अधिकारी को यह दिखाई दे कि अमुक सेवा में लीन व्यक्ति सन्तोष प्रदान करने में असफल हो गया है, तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी उसे शीघ्र ही अपने पूर्व मौलिक पद पर बिना परीक्षा काल समाप्त हुए वापिस कर सकता है यदि उसका लीयन (lien) पूर्व पद पर हो, और यदि उसका लीयन किसी भी पद पर न हो तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है ।

किन्तु शर्त यह है कि नियुक्ति कर्ता अधिकारी किसी भी सेवा सदस्य के परीक्षा काल को एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए बढ़ा सकता है ।

(२) परीक्षाकाल में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति यदि उपनियम (१) के अधीन परीक्षा काल में या उसके अन्त में पद से वापिस कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो वह किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति कराने का अधिकार नहीं रखेगा ।

३१. स्थायीकरणः—एक परीक्षाधीन व्यक्ति उसके परीक्षा अवधि के समाप्त होने पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी इसमें सन्तुष्ट हो जाये कि उसकी योग्यता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है तथा अन्य प्रकार से भी वह स्थायी बनने के लिए सर्वथा योग्य है ।

भाग ७—वेतन

३२. वेतनशृंखलाः—इस सेवा में पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की मासिक वेतन की शृंखला वही होगी जो नियम ३५ में वर्णित नियमों के अधीन देय होगी या सरकार द्वारा जो समय समय पर निर्धारित की जा सके ।

३३. परीक्षाकाल में वेतन वृद्धिः—इस परीक्षाधीन (under Probation Period) व्यक्ति परीक्षाकाल में अपनी वेतन शृंखला में जब कभी उसका वेतन वृद्धि का समय आवे, वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा किन्तु शर्त यह है कि यदि सन्तोषजनक प्रगति न करने के कारण उसका परीक्षा काल फल बढ़ा दिया गया हो तो उस समय तक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी जब तक कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी ऐसा करने के लिए आदेश न दे देता ।

३४. दक्षतावरी लांघने का सिद्धान्तः—सेवा के किसी भी सदस्य की उस समय तक दक्षतावरी (E. B.) के द्वारा वेतन वृद्धि नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी की राय में वह सन्तोषजनक कार्य नहीं कर लेगा तथा उसकी ईमानदारी में किसी भी प्रकार का उसको सन्देह नहीं रहता है ।

भाग ८—अन्य प्रावधान

३५. अवकाश भत्ता, निवृत्तिवेतन आदि का नियमः—इन नियमों में रखे गये प्रावधान के अतिरिक्त इस सेवा के सदस्यों का वेतन भत्ता, निवृत्ति वेतन (पेंशन) अवकाश एवं सेवा की अन्य शर्तें निम्न द्वारा नियमित होंगी—

(१) अन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थान यात्रा भत्ता नियम १९४६

(२) अन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थान सिविल सर्विस (ग्रुनोफिकेशन ग्राफ पे स्केल) नियम १९५८

(३) अन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थान सिविल सर्विस (राशनलाइजेशन आफ पे स्केल) नियम १९५६

(४) अन्तिम तिथि तक संगोधित राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) नियम, १९५८

(५) अन्तिम तिथि तक संशोधित राजस्थान सेवा नियम तथा भारतीय संविधान की धारा ३०६ के प्रावधानों के अधीन सक्षम अधिकारियों द्वारा बनाये गए अन्य नियम जो इस समय प्रभाव-शील हों।

अनुसूची

सेवा के अधीन पद संख्या तथा पदों की किस्म

(देखिये नियम ६, ७ एवं २५)

पदों के नाम

पदों की संख्या

१. वरीय (सीनियर) पद

- | | |
|---|---|
| (१) संचालक | १ |
| (२) संयुक्त संचालक | १ |
| (३) उप संचालक शिक्षा | ६ |
| (४) अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर व अजमेर के आचार्य | २ |

२. वरीय (सीनियर) पद

(१) शाला निरीक्षक [मय सहायक शिक्षा संचालक, (प्रशासन) (योजना) एवं (सामाजिक शिक्षा), सहायक शिक्षा संचालिका, (महिला) तथा प्रस्तोता विभागीय परीक्षाओं] २८

- | | |
|---|---|
| (२) आचार्य, सादूल पब्लिक शाला, बीकानेर | १ |
| (३) प्राध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर व अजमेर | २ |

३. निम्न (जूनियर) पद—

(क) निर्वाचित [सलेक्शन] श्रेणी—

- | | |
|---|----|
| (१) बहुउद्देशीय एवं उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकायें | |
| (२) अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर व अजमेर के व्याख्याता | १३ |

(ख) साधारण श्रेणी—

- | | |
|--|-----|
| (१) सामान्य उच्च विद्यालय, वेसिक एस. टी. सी. प्रशिक्षण शाला एवं बाल शालाओं के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिकायें | २१३ |
| (२) उपशाला निरीक्षक/उपशाला निरीक्षिकायें, | |

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें जो कि शिक्षा विभाग से संबन्धित हैं अथवा शिक्षा विभाग के वे आदेश जो कि इस संहिता के बनने के पश्चात समय समय पर जारी होते रहे हैं यहां पर दिये जा रहे हैं।

R. S. R. नियम ७ (८) - कर्तव्य (duty):—(अ) (duty) में निम्न सम्मिलित होते हैं:—

(१) परीक्षणकाल अथवा प्रशिक्षण (apprentice) काल की सेवा अवधि वशतः कि ऐसी सेवा अवधि के अन्त में स्थायीकरण हो जावे ।

(२) कार्य ग्रहण अवधि (Joining time)

(ब) सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकती है कि निम्न परिस्थितियों अथवा उनके समान परिस्थितियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को (duty) पर मान लिया जावे:—

(१) भारतवर्ष में दिये जाने वाले शिक्षण अथवा प्रशिक्षण की अवधि ।

(२) छात्रवृत्ति प्राप्त अथवा अन्यथा, ऐसा छात्र, जो कि भारतवर्ष के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय में प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम पास करने पर सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने का अधिकारी हो उसके अध्ययन को संतोषपूर्वक समाप्त करने तथा अपना कार्यभार सम्हालने के मध्य की अवधि ।

(३) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई हो, नियुक्ति अधिकारी के आदेश के अनुसार सरकार के मुख्यालय अथवा निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं को उपस्थित करने से पूर्व, यदि किसी निर्दिष्ट पद का कार्यभार ग्रहण करने का आदेश प्राप्त नहीं करें तो, अपने को कार्य भारके लिये उपस्थित करने तथा अपने कर्तव्यों का वास्तविक कार्य भार ग्रहण करने के बीच की अवधि ।

नोट:—छुट्टी से लौटने तथा अपने पूर्व पद का कार्य भार सम्हालने के बाद तथा किसी नये स्थान पर उसे पदासिन करने के आदेश प्राप्त करने के बीच की अवधि में कोई सरकारी कर्मचारी बाध्य होकर जो प्रतीक्षा करने में समय लगायेगा, वह भी इसी उपधारा के अन्तर्गत आता है ।

(४) किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, जिसे कि अनिवार्य रूप से किसी विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना हो, अथवा ऐसी परीक्षा में बैठना हो जिसकी कि पास करना उसको सरकारी सेवा में लेने की शर्त हो तथा जो कि उस सरकारी कर्मचारी के विभाग अथवा कार्यालय के सामान्य कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, उस परीक्षा के दिन तथा परीक्षा स्थान तक जाने व आने, यदि ऐसा आवश्यक हो, की यात्रा की उचित अवधि ।

(५) किसी सरकारी कर्मचारी को यदि किसी वैकल्पिक परीक्षा में बैठने की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो तो उस परीक्षा में लगने वाले दिन तथा परीक्षा स्थल तक जाने व आने की यात्रा में लगने वाली अवधि ।

विषय—अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा निर्णित सुविधायें—

१. यदि किसी शिक्षण संस्था अथवा उसकी किसी एक कक्षा में किसी वर्ग विशेष के बालकों की संख्या कम से कम ४० व १० हो तो उस संस्था में उन बालकों को कक्षा १ से ५ तक समस्त पाठ्य विषयों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की व्यवस्था तत्काल करदी जावे ।

२. कक्षा १ से २ तक जिन बालकों को जो मातृभाषा हो उनको हिन्दी के स्थान पर उनकी मातृभाषा ही पढ़ाई जावे । परन्तु कक्षा ३ तथा उसके आगे की कक्षाओं में उन बालकों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ हिन्दी की शिक्षा भी अनिवार्य रूपसे चालू रखनी जावे ।

३. कक्षा ५ से आगे कक्षा ६, ७, ८ व ९ में संस्कृत भाषा अब तक अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती रही है परन्तु अब उस संस्कृत भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में समझा जावे, और परिणामतः अब सभी वर्गों के बालकों के लिए केवल इस विचार से कि उनको अपनी मातृभाषा का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो सके। निम्नलिखित भाषाओं को ऐच्छिक विषय के रूप में रख दिया गया है। परन्तु यह सुविधा उसी दशा में मिल सकेगी जब कि किसी कक्षा में किसी भाषा विशेष को पढ़ाने वाले बालकों की संख्या कम से कम १० अवश्य हो।

वे ऐच्छिक भाषायें ये हैं:—

क. संस्कृत

ख. गुजराती

ग. सिन्धी

घ. उर्दू

ङ. पंजाबी आदि आदि

४. यदि किसी उच्च अथवा उच्चतर शिक्षण संस्था में कक्षा ८ से आगे भी किसी वग विशेष के बालक उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ना चाहें तो उस संस्था अथवा उसकी किसी एक कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या कम से कम ४० व १० होने की दशा में बोर्ड के नियमानुसार इसकी भी व्यवस्था कर दी जावे।

५. अल्प संख्यक वर्गों के बालकों को इनकी मातृभाषा के माध्यम के साथ शिक्षा देने की यह सुविधा कक्षा १ से ५ तक अनिवार्य रूप से दी जावे तथा कक्षा ६ से १० अथवा ११ तक जैसा भी संस्था के स्तरानुसार उचित हो मातृभाषा की शिक्षा ऐच्छिक विषय में के रूप में दी जाने की व्यवस्था कर दी जावे।

६. यदि विभिन्न भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो संलग्न सूची के अनुसार उसमें दिए हुए पते से भंगवा ली जावे।

७. जिन भाषाओं के पढ़ाने वाले अध्यापकों का यदि कहीं अभाव हो तो उसकी मांग तत्काल सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जावे जिससे शीघ्रातिशीघ्र समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त यदि इस सम्बन्ध में और भी कोई समस्या सामने आवे तो उससे भी सम्बन्धित कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जावे।

८. इस परिपत्र के पहुँचते ही तदनुसार कार्य आरम्भ कर दिया जावे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की एक रिपोर्ट तत्काल सम्बन्धित कार्यालय में भिजवाई जावे।

(अतिरिक्त शिक्षा संचालक राजस्थान डॉ. ओ. संख्या ई डी बी/आई सी ए/सी/१४१३६/६८/५६/दिनांक १३-७-५६)

विषय—अध्ययन-अवकाश। असाधारण-अवकाश आदि। सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में उससे वसूल किये जाने योग्य लुभाना की रकम।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन के लिये अध्ययन अवकाश दिया जाता है और जो अध्ययन अवकाश की नमाप्ति या उसकी वापसी के बाद निम्न रूप में अपने कार्य पर लौटने से पूर्व ही या तो त्यागपत्र दे देते हैं

या नेवा निवृत्त हो जाँस है, उनसे वसूल किये जाने वाले अर्थदण्ड की रकम के प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है। सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में लौटाई जाने वाली रकम, अवकाशीय-वेतन (leave salary), अध्ययन-भत्ता (study allowance) शुल्क व यात्रा का खर्चा-तथा अन्य खर्चें, जो कि सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के समय दिये गये हैं अथवा उस पर व्यय किये गये हैं, इन सबकी दुगुनी होगी तथा उस पर व्याज भी लगेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १८ से दिये गये आबंध प्रपत्र (form of bond), जो कि नियम १२१ (घ) के अन्तर्गत दिये जाने वाले अध्ययन अवकाश के लिये हैं, के स्थान पर संलग्न प्रपत्र (अ तथा ब) प्रस्थापित किये जावें।

२. अध्ययन-अवकाश नियमों को शिथिल करके यदि किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया गया हो तो जुमाने की रकम उपरोक्त पैरा १ के ही अनुसार होगी।

३. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जबकि अस्याई सरकारी कर्मचारियों को नियमों को शिथिल करके असाधारण अवकाश, अपनी अन्य नियमित छुट्टी के साथ ही भारत या विदेश में अध्ययन स्वीकृत करदी जाती हो वशतें कि वे अपना अवकाश समाप्त होने के बाद एक निश्चित अवधि तक सरकार की सेवा के लिये लिखित प्रतिज्ञा-पत्र दें। ऐसा निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से प्रपत्र 'स' में एक प्रतिज्ञा-पत्र ले लिया जावे तथा इस प्रतिज्ञा पत्र के बाद ही नियमों को शिथिल करके असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जावे। इन मामलों में, आबंध प्रपत्रों में भरी जाने वाली रकम की उपरोक्त पैरा १ के आधार पर ही गणना की जावे।

[वित्त विभाग-अ (नियम) ओ. एम. संख्या एक, १० (१०) एफ [I/५३ दिांक २८-४-६१]

अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए आबंध-प्रपत्र

कि मैं जो कि जिले के स्थान का निवासी हूँ और इस समय कार्यालय में का कार्य करता हूँ, अपने आपको मेरे उत्तराधिकारियों को, निष्पादकों को (executors) और प्रशासकों को मांगने पर रूपया (रूपया), तथा साथ में उस पर, वापिस मागने की तिथि से सरकारी दरों पर व्याज, जो कि उस समय सरकारी ऋणों पर प्रचलित हो, राजस्थान सरकार (आगे "सरकार" कहलायेगी) को भुगतान करने के लिये अनुबंधित करता हूँ। यदि भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान करना है तो भारत तथा उस देश के मध्य प्रचलित वित्तीय विनियम की सरकारी दरों के अनुसार उस रकम के समान उस देश की वित्तीय इकाई में विनिमित रकम, और साथ में न्यायवादी (attorney) और मुक्किल के मध्य का समस्त व्यय तथा सरकार द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले खर्चों भी लौटाने के लिये अनुबंधित करता हूँ।

सन् एक हजार तीसरी के मास की तारीख लगाई गई। वयोकि कर्तव्याधीन श्री को सरकार ने अध्ययन-अवकाश स्वीकृत हुआ है।

और वयोकि सरकारी हितों की भली प्रकार सुरक्षा के लिये उपरोक्त कर्तव्याधीन कर्मचारी ने यह आबंध अनुवर्ती शर्तों के साथ लिखने की सहमति दी है:—

अब उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह होगी कि यदि उपरोक्त कर्तव्याधीन श्री

..... अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्ति के पश्चात् कार्य पर लौटने से पूर्व अथवा कार्य पर लौटने के बाद तीन वर्ष की अवधि में कभी भी सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा निवृत्त हो जाता है, तो वह तुरन्त ही सरकार को अथवा सरकार द्वारा जैसा निर्देश दिया जावे, उसके द्वारा चाहे जाने पर रुपये (रुपये) चाहे जाने की तिथि से सरकारी ऋणों पर प्रचलित तत्कालीन व्याज की दर के अनुसार उस रकम पर व्याज सहित लौटा देगा ।

और उपरोक्त कर्तव्याधीन श्री..... द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर उपरोक्त लिखित दायित्व रद्द तथा प्रभाव रहित हो जायेगा अन्यथा तब तक वह प्रभावशील रहेगा ।

इस आबंध पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन करना राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया है । श्री की उपस्थिति में उपरोक्त कर्तव्याधीन श्री ने हस्ताक्षर किये एवं हस्तान्तरित किया ।

स्वीकार किया गया

राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते तथा की ओर से

अध्ययन-अवकाश पर जाने वाले अस्थायी कर्मचारी के लिये आबंध-प्रपत्र

कि हम, कार्यालय जो कि स्थान का निवासी हूँ और इस समय कार्यालय में का कार्य करता हूँ (आगे अनुबंध—कर्त्ता कहलायेगा) और स्थान के श्री का पुत्र तथा स्थान के श्री का पुत्र श्री जो कि अनुबंध कर्त्ता के प्रतिभूति हैं, उनकी ओर से सामूहिक रूप से व अलग अलग हम स्वयं को, हमारे उत्तराधिकारियों को, निष्पादकों को और प्रशासकों को अनुबंधित करते हैं कि मांगने पर रुपया ..) (रुपया) तथा साथ में उस पर वापिस मांगने की तिथि से सरकार (आगे "सरकार" कहलायेगी) को भुगतान कर देंगे । यदि भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान करना है तो उस रकम के समान, उस देश की विस्तीय इकाई में विनिमित्त रकम, और साथ में न्यायवादी (attorney) और मुवक्किल के मध्य का समस्त व्यय तथा सरकार द्वारा किया गया अथवा किये जाने वाला खर्च भी लौटाने के लिये अनुबंधित करता हूँ ।

सन् एक हजार नौ सो.....के मास की तारीख लगाई गई ।

क्योंकि उपरोक्त कर्त्तव्याधीन श्री.....को सरकार से अध्ययन अवकाश स्वीकृत हुआ है ।

और क्योंकि सरकारी हित की भली प्रकार सुरक्षा के लिये उपरोक्त कर्त्तव्याधीन कर्मचारी ने यह आबंध अनुवर्ती शर्तों के साथ लिखने की सहमति दी है ।

और क्योंकि कथित श्री तथा श्री ने उपरोक्त कर्त्तव्याधीन श्री की ओर से प्रतिभूति के रूप में इस आबंध को लिख दिया है ।

अब उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह होगी कि यदि उपरोक्त अनुबंधकर्त्ता श्री अध्ययन—अवकाश की अवधि समाप्ति के पश्चात् कार्य पर लौटने से पूर्व अथवा कार्य पर लौटने के बाद तीन वर्ष की अवधि में कभी भी सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा निवृत्त हो जाता है तो यह अनुबंधकर्त्ता एवं प्रतिभूतिगण तुरन्त ही सरकार को अथवा सरकार द्वारा जैसा निर्देश दिया जावे, उसके द्वारा चाहे जाने पर रुपये (रुपये चाहे जाने की तिथि से सरकारी ऋणों पर प्रचलित तत्कालीन व्याज की दर से उस रकम पर व्याज सहित लौटा देंगे ।

और उपरोक्त कर्तव्याधीन अनुबंध कर्ता श्री..... तथा प्रतिभूति गण श्री .. तथा श्री.... द्वारा ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर उपरोक्त लिखित दायित्व रद्द तथा प्रभाव रहित हो जावेगा अन्यथा तब तक वह पूर्ण प्रभावशील रहेगा ।

साथ में शर्त यह है कि यदि सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्त द्वारा कुछ समय को छूट भी देदी जावेगी अथवा सहनशीलता का कोई कार्य किया जावेगा अथवा कोई चूक हो जावेगी (चाहे प्रतिभूतियों की स्वीकृति या जानकारी से ऐसा हो अथवा नहीं हो) तो भी इस आबंध के अन्तर्गत आने वाली प्रतिभूतियों की देनदारी कम या समाप्त नहीं होगी तथा न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि इस आबंध के अन्तर्गत आने वाली किसी रकम के लिए उपरोक्त कर्तव्याधीन प्रतिभूतियों श्रीतथा श्री पर दावा करने से पूर्व वह कथित अनुबंध कर्ता पर दावा करे ।

इस आबंध पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन करना राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री की उपस्थिति में

उपरोक्त नाम वाले प्रतिभूति श्री

द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं हस्तान्तरित किया गया ।

श्रीकी उपस्थिति में

उपरोक्त नाम वाले प्रतिभूति श्री.....

द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं हस्तान्तरित किया गया ।

श्रीकी उपस्थिति में

उपरोक्त नाम वाले प्रतिभूति श्री

द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं हस्तान्तरित किया गया ।

स्वीकार किया गया

राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते तथा की ओर से

भारत या विदेश में अध्ययनार्थ, राजस्थान सेवा नियम के नियम ६६ (ब) में

छूट की जाकर स्वीकृत किए हुये असाधारण अवकाश पर जाने वाले

अस्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए आबंध-प्रपत्र

कि मैं श्री /श्रीमती/कुमारीजो कि श्रीका/की पुत्र/पुत्री/स्त्री हूं और श्री जो कि कार्यालय में के तौर पर वर्तमान में कार्य करता/करती हूं, राजस्थान सरकार (बाद में "सरकार" कहलायेगी), उसके उत्तराधिकारी, या नियुक्त व्यक्ति को, चाहे जाने पर.....रूपये की रकम का भुगतान करने के लिये मैं स्वयं, मेरे उत्तराधिकारियों, प्रशासकों को अनुबंधित करता/करती हूं ।

सन् एक हजार नौ सौ के.....मास की . . . तारीख लगाई गई—

क्यों कि सरकार ने उपरोक्त कर्तव्याधीन श्री/श्रीमती/कुमारीजो कि के रूप में सेवा में है, की प्रार्थना पर उसेस्थान पर अव्ययन करने देने के लिए उसे नियमित छुट्टी

स्वीकार की गई है और क्यों कि साथ में उसे बिना वेतन व भत्ते के वर्षों तथा महिनों की अवधि के लिए असाधारण अवकाश भी दिया गया है ।

और क्यों कि श्री/श्रीमती/कुमारी/.....के असाधारण अवकाश पर जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति की अवधि में का कार्य संपादन हेतु सरकार ने एक स्थानापन्न नियुक्ति की है/करती पड़ेगी ।

और क्योंकि उपरोक्त कर्तव्यधीन श्री/श्रीमती/कुमारी तथा सरकार के मध्य समझौता हो गया है कि सरकार के हित की भली प्रकार सुरक्षा के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....को एक ऐसा आवंध लिख देना चाहिए जैसा कि उपरिलिखित हो तथा ऐसी शर्त युक्त होना चाहिए जैसी कि यहां लिखी हुई है ।

अब उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह होगी कि उपरोक्त कर्तव्यधीन श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा असाधारण अवकाश की अवधि समाप्त होने पर उनके मूल पद पर नहीं लौटने अथवा वापिसी के बाद वर्षों की अवधि तक, जैसा कि सरकार चाहे, सरकार की सेवा नहीं करने, अथवा नियमानुसार जिन वेतन का वह अधिकारी होवे, उस पर किसी अन्य रूप में कार्य करने की सरकार द्वारा कहे जाने पर मना करने की स्थिति में श्री/श्रीमती/कुमारीअथवा उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक, सरकार द्वारा चाहे जाने पर रुपये की धनराशि का सरकार को भुगतान करेंगे ।

और उसके द्वारा ऐसी अदायगी की जाने पर उपरोक्त लिखित दायित्व रद्द तथा प्रभावहीन हो जावेगा अन्यथा तब तक वह पूर्ण प्रभावशील रहेगा ।

यह आवंध उस समय प्रचलित राजस्थान के कानूनों से शासित होगा और इसके अन्तर्गत अधिकार तथा देनदारियाँ, जहाँ आवश्यक होगी, भारत के उपयुक्त न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्णीत होंगी ।

इस आवंध पर स्टाम्प ड्यूटी का वहन तथा भुगतान करने का भार सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है ।

उपरोक्त लिखित आवंध एवं शर्तों की साक्षी में मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आज सन् एक हजार नौ सौ के भास की तिथि को इस पर अपने हस्ताक्षर प्रस्थापित करता हूँ ।

श्री की

उपस्थिति में उपरोक्त कर्तव्यधीन श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदाम किया गया ।

राज्यपाल आज्ञा देते हैं कि राजनैतिक पीड़ित (परिभाषा नीचे दी गई है) यदि उसकी मासिक आय ३०० से अधिक नहीं हो, के बच्चों - तथा पोती को (grand children) निम्न सुविधायें प्रदान की जावे ।

परिभाषा:—राजनैतिक पीड़ित से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कि ६ महिने तक की जेल गया हो, अथवा नजरबन्द रहा हो, या जो नजरबन्दी या कार्यवाही में मर गया हो अथवा मार दिया गया हो या जिते कठोर दण्ड मिला हो या साठी चार्ज अथवा गोलीकांड के कारण से स्थायी तौर पर अंग्र ह्रा गया हो अथवा भारत के अग्र्युत्थान के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण

जिनकी नौकरी चली गई हो या रोजी का साधन समाप्त हो गया हो या अपनी सम्पत्ति का पूरा अथवा अंश भाग चला गया हो ।

सुविधायें:—(१) समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक, बुनियादी व उच्चमाध्यमिक शालाओं में शुल्क मुक्ति, अर्ध शुल्क मुक्ति, प्रवेश के मामलों में विशेष विचार ।

(२) मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से संलग्न छात्रावासों में निःशुल्क स्थान ।

(३) प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक इन छात्रों को सीमित संख्या में पुस्तकें तथा पारिश्रमिक (Stipend) दिये जायें ।

[शिक्षा (स) विभाग आज्ञा संख्या एफ० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ दिनांक १७-६-१९५६]

राज्यपाल आज्ञा देते हैं कि सरकारी अधिसूचना संख्या एफ० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ दिनांक १७-६-१९५६ में दी गई राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों तथा पोतों को सुविधाओं के लिये निम्न कार्य विधि अपनाई जावे:—

(१) इस योजनाके अन्तर्गत आने वाले राजनैतिक पीड़ितों के संरक्षित बालक इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिये संस्थान-प्रधानों को अपने प्रार्थनापत्र देगे । साथ में उस जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाणपत्र भी आना चाहिये जहां उस संरक्षक ने दिनांक १७-६-५६ की अधिसूचना में परिभाषित राजनैतिक पीड़ा पाई हो ।

(२) संस्था प्रधान इन प्रार्थनापत्रों को अपनी टिप्पणी सहित शिक्षा संचालक अथवा उप शिक्षा संचालक, जैसा भी अपेक्षित हो, को भेजेंगे

(३) पारिश्रमिक अथवा छात्रवृत्तियों के प्रसंग में, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लागू दरें वे ही होंगी जो कि योग्यता एवं आवश्यकता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत है ।

[शिक्षा (स) विभाग आज्ञा संख्या एफ० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ दिनांक २४-११-५६]

दिनांक २४-११-१९५६ की अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधन करते हुये, राज्यपाल आज्ञा देते हैं कि दिनांक १७-६-५६ की अधिसूचना में उल्लिखित राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों तथा पोतों को मिलने वाली सुविधाओं के लिये निम्न कार्य प्रणाली अपनाई जावे ।

इन सुविधाओं के अधिकारी राजनैतिक पीड़ित अथवा उनके बच्चे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि इस सुविधा के लिये प्रार्थनापत्र देने वाला छात्र १७ सितम्बर १९५६ की अधिसूचना में परिभाषित राजनैतिक पीड़ित का बच्चा है । इन सुविधाओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थनापत्र आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ छात्र द्वारा उस संस्था प्रधान को दिया जावेगा जहां कि यह पढ रहा हो । संस्था प्रधान उस प्रार्थनापत्र को अपनी इस टिप्पणी के साथ कि प्रार्थी उसकी उस विशिष्ट कक्षा में पढ़ता है, शिक्षा संचालक इन सुविधाओं की स्वीकृति देगा । इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति तथा उनपर दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वह एक त्रैमासिक प्रत्यावर्त सचिवालय को भेजेगा ।

य सुविधायें राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों तथा उनके पहले से मृत पुत्रों के पोतों को मिलेंगी ।

यह भी आगे आदेश दिया जाता है कि इस विभाग की १७-६-५६ की अधिसूचना के पैरा १ में उल्लिखित सुविधायें मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शालाओं तक के लिये हैं और उन

सुविधा को अब निम्नानुसार पढा जाये:—

“समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक, बुनियादी, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुल्क मुक्ति, अर्द्ध शुल्क मुक्ति तथा प्रवेश देने के विषयों में विशेष विचार विमर्श किया जावेगा।”

[शिक्षा (स) विभाग आज्ञा संख्या एक० १५ (५०) शिक्षा/स/५६ दिनांक २०-१-६०]

विषय—सहायता अनुदान

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में Range Accountant द्वारा संस्थाओं के उन भवनों का किराया भी दे दिया गया है जो कि संस्था को संचालन करने वाली जाति या संघ के स्वामित्व में है। यह नियमानुकूल नहीं है। संस्था को चलाने वाले मालिकों अथवा समितियों के भवनों का किराया अथवा उनकी सम्मत का खर्च दिए जाने का सिद्धान्त सरकार के विचाराधीन है।

सभी निरीक्षकों से अनुरोध है कि वे ऐसी सहायता प्राप्त संस्थाओं की सूची, जो कि समाज के भवनों में चल रहे हैं, संबंधित शिक्षा उप संचालकों को भेज दें जो कि उन सबको इस प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को भेज देंगे कि ऐसी संस्था को किराये की कोई रकम नहीं दी गई।

केवल निम्न परिस्थितियों में ही किराये की रकम दी जा सकेगी,

१. जब कि संस्था वास्तव में अतिरिक्त जगह की आवश्यकता में हो,
२. मकान वास्तव में किराये पर लिया गया हो,
३. सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्धारण प्रमाण पत्र साथ भेजा गया हो।

[संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान पत्रांक EDB/Bud/सी. २/१५३८५ (६०) दिनांक १८-११-६०]

विषय—सहायता-अनुदान

निम्न हस्ताक्षरकर्ता जनरल फाइनेन्शियल एंड अकाउन्ट्स हल्स के नियम ३०८ की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो कि अन्य बातों के साथ साथ यह प्रकट करता है कि जब तक सरकार द्वारा अन्य प्रकार का आदेश नहीं दिया गया हो, “अनुदान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उचित समय की अवधि में खर्च की जायेगी यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया हो।”

२. एक प्रश्न यह उठाया गया है कि “उचित समय” शब्द की व्याख्या क्रियान्वयन में कैसे की जावे। राज्यपाल महोदय निर्णय देते हैं कि इन शब्दों का साधारणतया यह अर्थ होगा:—“अनुदान के स्वीकृति-पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष।” इस प्रकार अनुदान, एक वर्ष की आवश्यकता के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, चाहे वह वर्ष वित्तीय वर्ष से आगे तक जाता हो, लेकिन जी. एफ. ए. आर. के नियम ३०६ (२) के प्रावधान के अनुसार अनुदान के केवल उसी अंश का भुगतान उस वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए जो कि उस वर्ष में खर्च किया जा सके। ऐसे मामलों में वर्ष के अन्त में बची हुई धनराशि, जो वित्तीय वर्ष के समाप्त होते पर नहीं लौटानी चाहिए। ऐसे मामलों में स्वीकृति-पत्र की आपा कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे इस विभा-

गीय परिपत्र संख्या डी ३६६७/एफ १ (३२)/एफ/ए. ए./५४/पार्ट-१ दिनांक १६-६-१९५८ के अनुसार वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त नहीं हो जावे । किन्तु स्वीकृति-तथि से एक वर्ष की सम ति होने पर, अनुदान का वह अंश जो खर्च नहीं हो पाया हो, जी. एफ ए. आर. के नियम ३०८ (२) के अनुसार अविलम्ब सरकार को लौटा दिया जाना चाहिए । ऐसी स्वीकृतियों के बावत, जो कि किसी अनुदान को वित्तीय वर्ष में ही खर्च करने की कहती हो, खर्च नहीं की हुई रकम या तो वित्तीय वर्ष के अन्त में सरकार को लौटा दी जावे अथवा यदि अगले वर्ष अनुदान मिलने वाला हो तो उसमें समायाजन (adjust) कर लिया जावे ।

३. उन छोटी संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो कि पूर्णतया/प्रमुखतया सरकार से प्राप्त आवर्त्तक सहायता-अनुदान पर ही निर्भर करती है, यह संभव है कि उपरोक्त सरलीकरण के बावजूद भी, उन्होंने सम्पूर्ण अनुदान का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही खर्च कर डाला हो । उस स्थिति में, ऐसी संस्थायें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अपना खर्च जुटाने के लिए यथेष्ट धनराशि जब तक कि उन्हें नया अनुदान नहीं मिल जावे । इन संस्थाओं की नये सहायता अनुदान की प्राप्ति में होने वाली देरी से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्यपाल निर्देश देते हैं कि यदि आवश्यक होवे तो ऐसे आवर्त्तक सहायता अनुदान को निम्नानुसार तीन किशतों में यदि वित्तीय वर्ष में ऐसी संस्थाओं को भुगतान कर दिया जावे ।

(१) पहली किशत अप्रैल मास में दे दी जावे ।

(२) दूसरी किशत अगस्त मास में दे दी गई ।

(३) अन्तिम किशत वित्तीय वर्ष के अवशिष्ट भाग के खर्च को पूरा करने के लिए दिसम्बर मास अथवा उसके भी बाद स्वीकृत की जावे ।

इस वित्तीय वर्ष में अनुदानों का भुगतान दो किशतों-अगस्त व दिसम्बर मास में कर दिया जावे ।

जी० एफ० ए० आर० के नियम ३०६ (३) के अन्तर्गत चाहे जाने वाले आडिट किये हुये लेखे, यदि तैयार नहीं हो तो, अनुदान की प्रथम दो किशतों की स्वीकृति के लिये, उनको प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया जावे । किन्तु नियम ३०६ (३) के अनुसार, अन्तिम किशत की स्वीकृति देने से पूर्व, विगत वर्ष का लेखा-विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाना चाहिये बशर्ते कि सम्बन्धित संस्था को उनको प्रस्तुत करने से छूट नहीं देदी गई हो ।

(४) इस पत्र के पैरा २ व ३ में दी गई कार्य विधि को स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं ।

किसी विशिष्ट संस्था को प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाने वाली आवर्त्तक सहायता-अनुदान की रकम	सन् १९६०- सन् १९६०-६ में ६१ के लिये स्वीकृत किया हुआ धन	सन् १९६०-६ में सहायता अनुदान को स्वीकृत करने की तिथि	वित्तीय वर्ष १९०-६१ की समाप्ति के समय बची हुई रकम	वह विधि जिसके अनुसार १९६१-६२ में सहायता अनुदान की किशतों का भुगतान किया जाना है ।
(१) १२०००)	१२०००)	१-६-६०	—	अप्रैल की किशत:- अप्रैल, मई, जून व जुलाई के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं ।

(२) १२०००)	१२०००)	१-६-६०	१०००)	<p>अगस्त की किश्त:- अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं। दिसम्बर की किश्त:- अवशिष्ट वित्तीय वर्ष के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं। अप्रैल की किश्त:- जुलाई तक के व्यय के लिये ३०००) दिये जा सकते हैं।</p>
(३) १२०००)	१२०००)	१-६-६०	३०००)	<p>अ-२ की किश्त:- नवम्बर तक के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं। दिसम्बर की किश्त:- अवशिष्ट वित्तीय वर्ष के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं। अप्रैल की किश्त:- जुलाई तक के व्यय के लिये १०००) दिये जा सकते हैं क्योंकि ३०००) का गतवर्ष का अवशेष उपलब्ध है। अगस्त की किश्त:- नवम्बर तक के व्यय के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं। दिसम्बर की किश्त:- वित्तीय वर्ष के लिये ४०००) दिये जा सकते हैं।</p>

(५) उपरोक्त पैरा में बताई गई कार्य विधि केवल उन संस्थाओं पर लागू होगी जो कि सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर ही पूर्णतया/प्रमुखतया निर्भर रहती हैं। जहाँ पर वित्त विभाग की अनुमति से कोई अन्य प्रक्रिया प्रयोग में हो, तथा मंतोपजनक रूप से कार्य कर रही हो, वहाँ पर उपरोक्त कार्य विधि को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

[वित्त अ (नियम) विभाग मिमो नं० एफ० ५ (अ (२८) एफ० डी० ए० (रूल्स)/६१ दिनांक २८-८-६१]

विषय—गैरसरकारी निधियों का संचालन—तत्संबंधित निर्देश

निम्न हस्ताक्षर कर्ता इस विभाग के परिपत्र संख्या डी ३१५३/एफ. १ (६४) एफ /एए/ ५६ दिनांक २८-६-१९६० की ओर मंदर्भ आकर्षित करता है जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि गैरसरकारी रकमों को मार्बजनिक लेखा से बाहर रखने की प्रणाली शीघ्र समाप्त करदी जानी चाहिए और विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्त गैर सरकारी रकम राज्य के सार्वजनिक लेखा में जमा करादी जानी चाहिये। उपरोक्त आदेश जारी करने के बाद, इस प्रकार की रकमों के सम्बन्ध में कई कठिनाईयां उन अधिकारियों को अनुभव हुई हैं जिन्हें कि अपने सरकारी कर्तव्य के रूप में ऐसी गैर सरकारी रकमों का संचालन करना पड़ता है। इस संबंध में, निम्न निर्देश सबके मार्ग दर्शन के लिए जारी किये जाते हैं—

१. (१) गैर सरकारी रकम के संचालन करने वाले अधिकारियों को एक विशेष कोषागार में एक पी डी अकाउन्ट खोलने के लिए अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा सरकार के वित्त (W&M) विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।
 - (२) जब भी गैर सरकारी रकम प्राप्त होवे, उसे शीघ्र ही पी. डी अकाउन्ट में कोष में जमा करा दिया जावे।
 - (३) ऐसी निधियों का लेखा सरकारी निधियों से सर्वथा पृथक् रखा जाना चाहिये। इस कार्य के लिए जी. ए. ५० प्रपत्र में एक पृथक् केश-बुक रखी जानी चाहिये।
 - (४) डाक द्वारा प्राप्त समस्त चैक तथा मनीऑर्डर सबसे पहले प्रपत्र जी. ए. ५१ में एक रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने चाहिए तदनंतर संस्था अथवा कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षरों के अन्तर्गत उसे केश बुक में प्रविष्ट किया जाना चाहिये। चैक का भुगतान कोषागार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जावेगा।
 - (५) कोषागार से रुपया पी. डी. अकाउन्ट का संचालन करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त चैक से निकला जावेगा।
 - (६) निधि में से भुगतान, निधि के संचालनार्थ बने नियमों या आदेशों के अनुसार किया जावेगा।
 - (७) संस्था अथवा कार्यालय का प्रधान निधि में प्राप्त रकमों को छोटे छोटे खर्चों के लिये उपयोग कर सकता है तथा जहाँ किसी अवसर पर रकम की प्राप्ति कम पड़ जावे तो अधिकारी चैक द्वारा Imprest के रूप में कुछ रुपया निकाल सकता है।
२. (१) उपरोक्त निर्देशों का उन सभी अधिकारियों द्वारा पालन किया जावेगा। जो कि अपने सरकारी कर्तव्यों के रूप में सरकारी रकमों का संचालन करते हैं।

- (२) निधि का संचालन करने वाला अधिकारी उसके लेखा के लिये व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा।
- (३) इस प्रकार की निधियों का विस्तृत लेखा, महालेखापाल द्वारा आडिट किया जा सकेगा।

[विस्त विभाग-अ (नियम) सौम्य संख्या एफ. १८ (अ) (५२) एफ. डी. ए. (मल्ल)/६०

(ii) दिनांक ३०-६-६१]

विषय—शिक्षा विभाग में वेतन दरों का पुनर्निर्धारण

शिक्षा विभाग के निम्न वर्ग के अध्यापकों की वेतन-दरों में सुधार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है और अब यह निर्णय ले लिया गया है कि प्राथमिक शालाओं (माध्यमिक या अन्य विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं) के अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन दरों को समायोजित कर दिया जावे। अतः सरकार आज्ञा देती है कि निम्न कई श्रेणियों के दायज केवल एक श्रेणी रहेंगे:—

श्रेणी	वेतन-दर
(१) अप्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक	४०-१-५०
(२) प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक	५०-२-६०-३-७५
(३) अप्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापक	५०-४-७०-५-८०

अब इस श्रेणी का नाम "अप्रशिक्षित मैट्रिक्यूलेट अध्यापक" होगा और वेतन भी ५०-४-७०-५-८० में मिलेगा।

राज्यपाल आगे आज्ञा देते हैं कि यह निर्णय १-४-१९५६ से लागू किया जावे तथा ५०-४-७०-५-८० में वेतन, प्राथमिक शालाओं (अन्य शालाओं की प्राथमिक कक्षाओं भी सम्मिलित होगी) के वर्तमान अध्यापकों को निम्न मापदण्ड के अनुसार मिलेगा:—

- (अ) जितने मैट्रिक पास वर्तमान शृंखला में हैं जो कि प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन सबको ग्रन्टेन्ड मैट्रिक्यूलेट की वेतन दर १-४-१९५६ से दे दी जावे।
- (ब) समस्त प्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापकों को भी १-४-५६ से ग्रन्टेन्ड मैट्रिक्यूलेट की वेतन दर दे दें।
- (स) उपरोक्त (ब) के लिए किसी मिडिल पास अध्यापकों को प्रशिक्षित मान लिया जायेगा यदि उसने १-४-५६ से पूर्व ५ वर्ष का सेवा-काल पूरा कर दिया हो।
- (द) जितने अप्रशिक्षित मिडिल पास अध्यापक हैं जिन्होंने ५ वर्ष की सेवा की अवधि पूरी नहीं की हो, उनको १-४-५६ से वेतन शृंखला के न्यूनतम पर अर्थात् ५० रुपये पर स्थिर किया जावे और उनको वेतन वृद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वे मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास न कर लेवें अथवा स्वयं प्रशिक्षित न हो जावे।

संशोधित वेतन शृंखला में fix करने के लिए समस्त औपचारिकता तथा प्रक्रिया वही होगी जो आर. एस. आर. में दी हुई है।

[वित्त (व्यय-१) विभाग ID/६७/एफ. डी./ई. II/जनरल/६१ दिनांक १८/२० मई १९६१]

विषय—केन्द्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

उपरोक्त योजना भारत सरकार द्वारा मंचालित है तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा की तुलनात्मक संस्थाओं के लिए है ताकि वे अपने अध्यापकों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त कर सकें और इस प्रकार देश में शिक्षण तथा शोध कार्य के स्तर को उन्नत करने में समर्थ हो सकें इस योजना के अन्तर्गत परीक्षा व शिक्षण शुल्क, रेल व समुद्री किराया, पुस्तकों का खर्च, रहन सहन व्यय आदि का ५०% भारत सरकार देती है। इन्हें सहन व अन्य सुविधाओं का पूरा व्यय पहले भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय इस योजना के लिए निर्धारित निधि से वहन करता है। बाद में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उपरोक्त आधार पर व्यय का बटवारा होता है।

२. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियुक्त राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को वेतन व भत्ता दिये जाने का प्रश्न कई दिनों से सरकार के विचाराधीन है और राज्यपाल आज्ञा करते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत विदेश में उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए चुने गये सरकारी कर्मचारियों को निम्न शर्तें मिलेगी:—

- (अ) विशेष अवकाश की अवधि पदोन्नति के लिए सेवाकाल के रूप में मानी जावेगी और यदि सरकारी कर्मचारी पश्चिम योग्य पद पर कार्य करता है, तो पेंशन के लिए भी।
- (ब) विशेष अवकाश सरकारी कर्मचारी के खाते में नहीं दिखाया जावेगा। विशेष अवकाश के दिनों का अवकाशीय वेतन राजस्थान सेवा नियम के नियम ६७ (२) के प्रतिबंधात्मक वाक्यखंड (proviso) के अनुसार नियन्त्रित होगा।
- (ग) उपरोक्त (ब) के अन्तर्गत मिलनेवाली अवकाश के दिनों की तनख्वाह के अतिरिक्त वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. १० (१०) एफ. ११/५३ दिनांक २७ फरवरी १९५६ में दी गई मात्रा के आधार पर सहगाई भत्ता भी दिया जावेगा।

३. राज्य सेवा नियमों के नियम ५१ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार, प्रत्याशियों का चयन तथा बांड्स को निष्पादन (exemption) करने का तरीका ऐसे मामलों में लागू होगा।

[वित्त विभाग-अ (नियम) सी.ओ. संख्या एफ. १० (१०) एफ. ११/५३ दिनांक ३१-५-६१]

विषय—प्रशिक्षण-काल में त्यागपत्र-प्रशिक्षण व्यय की बसूली

सरकार आदेश देती है कि इस विभाग के इसी क्रम संख्या के दिनांक ६-८-१९५६ के आदेश (समय समय पर किये गए संशोधनों सहित) के प्रावधान अनिवार्य रूप से उन सब नियुक्ति पत्रों में सम्मिलित किये जाने चाहिये जो कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को दिये जाने वाले हों जो कि किसी पद का स्वतन्त्र रूप से भार वहन करने से पूर्व कोई प्रशिक्षण पाने वाले हों।

[नियुक्ति विभाग (अ-५) आज्ञा संख्या एफ. २ (४८) अपाइन्ट्स (अ)/५६ दिनांक २०-५-६१]

इस सचिवालय की इसी क्रमांक की दिनांक २५-४-१९६१ की आज्ञा के तिलसिले में उन समितियों, जिनके कि अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त या तो अध्यक्ष थे या सदस्य, के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्न और आज्ञा जारी की जाती है:—

क्रमसंख्या	समिति का नाम	समोनीत अध्यक्ष या सदस्य
१.	वह समिति जो कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा व्यवस्था किये जाने वाले माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च विद्यालयों की विधि पर विचार करेगी।	अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य
२.	राजस्थान विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं पर विचार करने वाली समिति	उप सचिव, योजना विभाग

[केबिनेट सेक्रेट्रियेट आज्ञा संख्या एफ. १२ (६६) कैव/सेकट/६१ दिनांक १६/२५ मई १९६१]

निम्न विभागों के अधिकारियों के दौरे के लिये निम्न आदेश सरकार जारी करती है:—

नं० २ शिक्षा विभाग

	दिन	रात
विभागाध्यक्ष	४०	३०
डिवीजन स्तर के अधिकारी	१२०	८०
जिला स्तर के अधिकारी	१५०	१००

उपरोक्त निर्धारण सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने वाले दौरों के लिये है। सब विभागाध्यक्ष यह देखें कि इन आदेशों का सब सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कठोरतापूर्वक पालन किया जाता है।

सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल व अक्टूबर में अपने विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरो का एक पदमासिक प्रत्यावर्त केबिनेट सेक्रेट्रियेट (प्रो. एंड.एम. सेक्शन) को भेजा जाना चाहिये।

[प्रो० एंड एम० आज्ञा संख्या एफ० ६ (३) प्रो० एंड एम०/६१ दिनांक ६-५-६१]

वरिष्ठ अधिकारियों के जयपुर में हुए आठवें सम्मेलन में राज्य, अधीनस्थ तथा लेखक सेवाओं (State, subordinate & ministerial services) में विभागीय परीक्षाओं को प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा निम्न निर्णय लिये गये:—

(१) कि वे परीक्षार्थे सभी राज्य, अधीनस्थ तथा लेखक सेवाओं में अविलम्ब विना किसी अर्पवाद के प्रारम्भ कर दी जावे ।

(२) कि राज्य स्तर की सेवाओं की विभागीय परीक्षाओं का प्रस्तोता राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा को छोड़कर जैसा कि पहले आदेश दिया जा चुका है, केबिनेट सेक्रेट्रियेट का उपसचिव होगा । राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित विभागीय परीक्षा के प्रस्तोता, अधिकारी प्रजिअण्ड विद्यालय जाधपुर के आचार्य होंगे राजस्थान पुलिस सेवा की विभागीय परीक्षार्थे सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा ली जावेगी । इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम भी सरकार के केबिनेट सेक्रेट्रियेट ओ. एण्ड एम. सेक्शन से स्वीकृत करवा लिया जाना चाहिये ।

(३) कि समस्त अधीनस्थ व लेखक सेवाओं की विभागीय परीक्षाओं के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ही प्रस्तोता होंगे तथा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे । इन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम भी सरकार के केबिनेट सेक्रेट्रियेट (ओ. तथा एम. सेक्शन) से स्वीकृत कराया जाना चाहिये ।

(४) कि इस आदेश के परिशिष्ट १ में उल्लिखित सभी सेवाओं पर राजस्थान असेनिक सेवायें (विभागीय परीक्षार्थे) नियम १९५६ को लागू करते हुये एक अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में अविलम्ब प्रकाशित की जावे ।

(५) कि परिशिष्ट २ में वर्णित सभी सेवाओं के लिये पाठ्यक्रम सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा अविलम्ब तैयार किया जाकर मई १९६१ के अन्त तक उप सचिव, केबिनेट सेक्रेट्रियेट (ओ. तथा एम. सेक्शन) के पास भेज दिया जाना चाहिये ।

समस्त विभागाध्यक्षों तथा सचिवालय के विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन नियमों, जिनको कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है, को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र कदम उठावें ।

[ओ. तथा एम. सेक्शन आज्ञा संख्या एफ. १५ [१३] O & M ६१ दिनांक १०-५-६१]

परिशिष्ट १.

१. शिक्षा विभाग

१. उप निरीक्षक, शिक्षा विभाग

२. सरकारी उच्चविद्यालयों के प्रधानाध्यापक

३. 'अ' वर्गीय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष

४. महाविद्यालयीय पुस्तकालयाध्यक्ष

राज्यपाल आदेश देते हैं कि सरकारी आज्ञा संख्या एफ. १ (१२७) Edp/ब/५६ दिनांक ९-७-१९५६ [अपने अनुवर्ती समस्त संशोधनों सहित], की सुविधायें जो कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान से सम्बन्धित हैं, ऐसे महिला कर्मचारियों के रक्ष्य बालकों [Ward] जिनके कि पति सरकारी सेवा में नहीं हैं और जिनकी कि अपने पति की आमदनी सहित मासिक आय २५०) या उससे कम है, को भी मिला करेगी । आय की धनराशि की गणना नियमानुसार की जायेगी ।

यह वित्त विभाग के यू० ग्री० संख्या ID. २१२८/एफ. डी. [ई. I]/६१ दिनांक ३-५-६१ द्वारा प्रदत्त सहमति से प्रसारित किया गया।

[शिक्षा [व विभाग आज्ञा संख्या एक. ७ [२१] शिक्षा/व/५६ दिनांक २५-५-६१]

विषय—तकनीकी व व्यावसायिक योग्यता-अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग, पश्चिमी बंगाल के मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के डिप्लोमा की मान्यता।

राजस्थान सरकार ने अपने अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में भर्तों के लिये बोर्ड आफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता टेक्नीकल स्कूल द्वारा प्रदत्त मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के डिप्लोमा की मान्यता प्रदान करदी है।

[जी.ए. डी. ए) आज्ञा संख्या एक. ४ (१६) जी. ए/ए./ग्रे/ II/ ६० दिनांक १०-७-६१]

विषय—तकनीकी व व्यावसायिक योग्यताओं की मान्यता

सरकार ने अपने अधीनस्थ ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर आदि की सेवाओं में नियुक्ति के लिये निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है:—

(१) तकनीकी परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश का गवर्नमेन्ट पोलिटेक्निक, नवगांव द्वारा प्रदत्त सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाणपत्र।

(२) राज्य तकनीकी शिक्षा मण्डल, राजस्थान का जोधपुर पोलिटेक्निक द्वारा प्रदत्त ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल का प्रमाणपत्र

[जी. ए. डी. (ए) आज्ञा संख्या एक. २ (३०) जी. ए/ए./ग्रे/II/६१ दिनांक २४-२५ जुलाई १९६१]

सरकार यह आदेश देती है कि विशेष उद्देश्यों, यथा जनगणना व चुनाव आदि, के लिए अध्यापकों का मनोनयन शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानों तथा जिला स्तर तक के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिये ताकि इन कार्यों में लगाये गये अध्यापकों द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के अध्यापन के लिये वे आवश्यक एवजी व्यवस्था कर सकें। इन कार्यों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करते समय, कर्मचारी के पद व स्तर पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये तथा उच्चस्तर वाले कर्मचारियों को निम्न स्तर वाले कर्मचारियों के अधीन कार्य करने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये।

[जी. ए. डी. (ए) आज्ञा संख्या एक. २ (२०) जी. ए/ए. ग्रे. II/६१ दिनांक १५-५-६१]

विषय—कालेज अथवा स्कूल बस का छात्राओं द्वारा प्रयोग के लिये

सरकार आज्ञा देती है कि सरकारी आदेश संख्या डी. ८३८६/एफ. १ (१०७०) शिक्षा/व/५७ दिनांक १६-७-१९६० की धारा ४ में संशोधन कर उसे निम्नानुसार पढ़ा जावे।

४. जो छात्राएँ पूरे सत्र भर बस का प्रयोग करती हैं, उनमें १० माह के लिए बस शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई १ या २ माह के लिए बस का प्रयोग करती है, उससे ३ माह का शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई ३ माह से अधिक व १० माह से कम अवधि के लिए बस का उपयोग करेगी तो उससे जितने माह बस का प्रयोग किया है, उतने ही माह का शुल्क वसूल किया जावेगा। ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश अथवा सर्दी की छुट्टियों के लिए शुल्क

में कोई छूट नहो दी जावेगी । यदि छात्राये छुट्टी पर होगी तब भी शुल्क में कोई कटौती नही की जावेगी ।

इस पर वित्त विभाग (ई०) की उनके पत्रांक संख्या TD/२१३१/एफ डी. (ई०) ग्रे I/६१ दिनांक १०-५-६१ के द्वारा सहमति प्राप्त करली गई है ।

[शिक्षा (व) विभाग राजा संख्या एफ. १ (१०७०), शिक्षा/ब/५७ दिनांक १६-६-६१]

विषय—महाविद्यालयों तथा पोलिटैकनिकों में कार्य करने वाले प्राध्यापकों, व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों के प्रार्थनापत्रों को संस्था प्रधानों द्वारा अग्रसारित करने के सिद्धान्त

महाविद्यालयों तथा पोलिटैकनिकों में कार्य करने वाले प्राध्यापकों, व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों के प्रार्थनापत्रों को संस्था प्रधानों द्वारा अग्रसारित (Forward) करने के लिए सरकार निम्न सिद्धान्त स्वीकार करती है:—

१-अस्थाई सरकारी:—अस्थाई व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों, जिनका कि चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया गया हो, के प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रतिबन्ध के अग्रसारित कर दिये जावें ।

२. राज. लोकसेवा आयोग द्वारा चयन किये गये अस्थायी सरकारी कर्मचारी	} राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गए अस्थाई व्याख्याता एवं अन्य अध्यापकों के प्रार्थनापत्रों को अग्रसारित करने में निम्न सिद्धान्तों का पालन किया जावे—

(अ) सत्र के मध्य में—१ अक्टूबर से ३० अप्रैल तक कोई भी प्रार्थना पत्र अग्रसारित नहीं किये जावेंगे ।

किन्तु यदि प्रार्थी को आगामी अप्रैल से पूर्व कार्य भार से मुक्त नहीं करना है तो इस अवधि में भी प्रार्थनापत्र भेजे जा सकते हैं ।

(ब) जहां तक संभव होवे संघीय तथा राज्य लोक सेवा आयोग को संबंधित प्रार्थनापत्र अग्रसारित किये जाने चाहिये ।

३. स्थायी सरकारी कर्मचारी:—स्थायी अध्यापकों, व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों, के प्रार्थनापत्र एक नियम के रूप में अग्रसारित नहीं किये जा सकते ।

किन्तु किसी व्यक्तिगत मामले को कोई विशेष परिस्थिति न्यायोचित ठहराये और शिक्षण संस्था के कार्य का हर्जाना नहीं होवे तो प्राथमिक एवं माध्यमिक/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षा संचालकों द्वारा संतुष्ट होने पर तथा सरकार के मन्त्रिमंडलीय सचिवालय (Cabinet Secretariat) के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर, उन प्रार्थनापत्रों को अग्रसारित किया जा सकेगा ।

४. पारदेशिक सरकारी पदों के लिये प्रार्थना पत्र—जहां तक संभव होवे सरकारी कर्मचारियों के वे प्रार्थनापत्र, जो कि विदेश में प्रति नियुक्ति (deputation) पर जाना चाहते हो, रोके नहीं जाने चाहिये ।

५. ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने किसी विषय में विशिष्टता प्राप्त करली हो अथवा जिन्होंने वैज्ञानिक प्रगति से सम्बन्धित कोई शोध कार्य किया होवे, तथा जो राज्य ने बाहर अन्वेष

पदों पर जाने को उत्सुक हों, के मामलों पर उनकी श्रेष्ठता से आधार पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि सरकार संतुष्ट हो जावे कि जिन पदों के लिए वे प्रार्थनापत्र दे रहे हैं, उनका राज्य में ही प्रावधान किया जाना कठिन है तथा ऐसा परिवर्तन ऐसे उत्साही युवकों के वास्तविक हितों में है तब उन प्रार्थनापत्रों को राज्य सरकार द्वारा अग्रसारित किया जावेगा। आवेदन प्राप्त किये जाने से पूर्व यह सब जांच समिति द्वारा जावेगा।

[कैबनेट सेक्रेट्रियेट आज्ञा संख्या एक, १२(१३६)/६१ दिनांक ५-६-६१]

विषय—अच्छे परिणामों के लिये प्रोत्साहन देने की योजना

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक परिणाम की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है, अतः राज्यपाल निम्नानुसार आज्ञा देते हैं:—

उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिये

(१) जिन शिक्षा संस्थाओं में १९६०-६१ के सत्र में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का परिणाम लगभग ६०% रहा हो, उन सब के प्रधानों को प्रशंसात्मक पत्र भेजे जावे।

(२) संस्था प्रधानों को १ जुलाई १९६१ से वेतन में एक अग्रिम वृद्धि दी जावेगी। इससे उनको नियमित मिलने वाली वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं होगा वगैरें कि—

(अ) १९६०-६१ के सत्र में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का परिणाम ६०% रहा हो तथा गत वर्ष १९५९-६० में ५०% रहा हो।

(ब) उस संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या दोनों वर्ष २० थी।

(स) संबंधित संस्था प्रधान ने १९६०-६१ के पूरे सत्र में संस्था की सेवा की हो। यदि विगत वर्ष वह प्रधानाध्यापक वहां नहीं था तो जिस संस्था में वह प्रधान था, उसकी परिणामों पर विचार किया जावेगा।

(द) जो प्रधानाध्यापक गत वर्ष प्रधानाध्यापक नहीं थे, उन्हें यह अग्रिम वृद्धि नहीं मिलेगी।

उच्च विद्यालय

१. जिन संस्थाओं का परिणाम १९६०-६१ के सत्र में ७५% से अधिक रहा हो, उन्हें प्रशंसात्मक पत्र भेजा जावेगा।

२. १ जुलाई १९६१ से संस्था प्रधान को एक अग्रिम वेतन वृद्धि मिलेगी। इससे उसकी सामान्य वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं होगा, वगैरें कि—

(अ) शिक्षा सत्र १९६०-६१ में परिणाम ८०% तथा १९५९-६० में ७५% था।

(ब) इन दोनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष में हाईस्कूल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या २५ से कम नहीं रही हो।

(स) सम्बन्धित संस्था प्रधान ने संस्था में पूरे वर्ष कार्य किया हो। यदि विगत वर्ष में वे प्रधानाध्यापक उस विद्यालय में नहीं थे तो उनकी पिछली शाला के परिणाम पर विचार किया जावेगा। किन्तु जो प्रधानाध्यापक गत वर्ष प्रधानाध्यापक नहीं थे, उन्हें यह अग्रिम वृद्धि नहीं मिलेगी।

वे आदेश बालिका विद्यालयों की प्रधानों पर भी लागू होंगे। यह आज्ञा वित्त विभाग की उनके पत्रांक यू. ओ. संख्या एफ. डी./एच/आई/३२६७/६१ दिनांक १२-७-१९६१ में उल्लिखित सहमति से प्रसारित की गई।

[शिक्षा (अ) विभाग आज्ञा संख्या एफ. १० (ई) (८६) शिक्षा/अ/६१ दिनांक २०-७-१९६१]

विषयः—प्रशिक्षण का उद्देश्य

राज्य सरकार प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य निर्धारित करती हैः—

- (१) कार्य-संपादन में स्पष्टता तथा यथार्थ मात्रता की प्राप्ति।
- (२) कर्मचारी के दृष्टिकोण तथा साधनों का समय की नई आवश्यकताओं से निरन्तर समायोजन (adjustment)
- (३) यांत्रिक विश्लेषण तथा अनुपयोगी दक्षता की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण का समावेश।
- (४) केवल वर्तमान कार्य के लिये ही योग्य बनाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं अपितु उच्चस्तर का कार्य तथा, अधिक उत्तरदायित्व के लिये उसकी क्षमता को विकसित करना।
- (५) दैनिक कार्य से उत्पन्न विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिये स्ट्राफ की निष्ठा पर विशेष ध्यान देना।

किसी भी बड़े संगठन में कार्य-निपुणता दो बातों पर आधारित हैः—

(१) दिये हुए विशेष कार्य को करने की किसी व्यक्ति की तकनीकी निपुणता, (२) संगठन की एक सामूहिक इकाई के रूप में एक कम मूर्त दक्षता, जो कि उस संगठन के घटक व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा संगठित भावना से प्राप्त होती हो। प्रशिक्षण में इन दोनों तथ्यों को ही स्थान मिलना चाहिए। केवल यही यथेष्ट नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने स्वयं के धन्य में और अधिक योग्य व निपुण बनाया जावे, अपितु सरकारी कार्य के एक विस्तृत चित्र तथा उसके भाग के रूप में अपने स्वयं के दायित्व को समझने योग्य वह हो सके। कोई भी सरकारी कर्मचारी एकान्त में कब तक काम करता रहेगा और जब तक कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक समझ की भावना का विस्तार नहीं किया जाता, तब तक सरकार की एक इकाई के रूप में कार्य कुशलता को हानि पहुंचेगी।

सरकारी विभागों के समस्त अध्यक्षों और प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानों से अनुरोध किया जाता है कि वे, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त विषयों में इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें।

[कैबिनेट सेक्रेट्रियेट परिपत्र संख्या एफ. २३ (१) कैब/६१ दिनांक ३१-७-१९६१]

विषय—आगे अध्ययन जारी रखने की छूट

सरकारी कर्मचारियों द्वारा आगे अध्ययन जारी रखने पर लगे-हुए वर्तमान प्रतिबंध को आंशिक रूप में ढीला करने का सरकार ने निश्चय किया है सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम १४ (ब) का संशोधन कर दिया है ताकि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को आगे अध्ययन जारी रखने तथा परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकें। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:—

१. आगे अध्ययन करने तथा परीक्षा में बैठने की स्वीकृति के लिये अपने विभाग में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रति वर्ष मार्च मास में प्रार्थनापत्र आमन्त्रित करेगा।

२. यदि कर्मचारी स्नातक स्तर से आगे अध्ययन करने की स्वीकृति चाहता है अथवा उस वर्ष १ मार्च, जबकि प्रार्थनापत्र दिया गया हो, को वह ४५ वर्ष की आयु का हो गया हो तो उसके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

३. ३५ वर्ष से अधिक तथा ४५ वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि फिर भी रिक्त स्थान हो तो ३५ वर्ष से कम आयु वालों में से विगत परीक्षा में प्राप्त द्वितीय के आधार पर चयन किया जाना चाहिये।

४. किसी भी वर्ष में एक विभाग में श्रेणीवार, कुल संख्या के ५% से अधिक कर्मचारियों को अनुमति नहीं मिलेगी।

५. क्योंकि सायंकालीन वक्षाओं की सुविधा केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही होगी, अतः यह देख लिया जाना चाहिये कि अनुमति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को जो कि इन स्थानों पर नहीं हों, पारी पारी से स्थानान्तरण द्वारा इन स्थानों पर लाया जावे। प्रतिवर्ष परीक्षा देने वाले छात्रों में से २ से लेकर ५ पद ऐसे सुरक्षित रखे जाने चाहिए जो कि इन स्थानों के अलावा अन्य स्थानों के हों तथा उन्हें इन स्थानों पर स्थानान्तरण द्वारा इस उद्देश्य के लिये लाता चाहिये।

६. जो व्यक्ति एक से अधिक बार परीक्षा में असफल रहता है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

[नियुक्ति (अ-III) विभाग नमो संख्या एफ. १३ (१७) एपाइन्टस (अ)/५५/क्र. III दिनांक ३१-७-१९६१]

विषय—अजमेर बोर्ड की इन्टरमीजियेट परीक्षा की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल की इन्टरमीजियेट परीक्षा के समकक्ष मान्यता

सरकार आदेश देती है कि राजस्थान सरकार की सेवा के लिए अजमेर शिक्षा मण्डल की इन्टरमीजियेट परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजस्थान की इन्टरमीजियेट परीक्षा के समकक्ष मान लिया जावे।

जी. ए. डी. (ए) आज्ञा संख्या एफ. ४ (३१)/जी. ए./५६ दिनांक १०-६-६०

विषय—शिक्षा संस्थाओं में सेवा निवृत्ति की आयु से आगे स्नातकोत्तर कक्षाओं के विभागाध्यक्षों, रीडर आदि की पुनर्नियुक्ति

प्रसंग—उपरोक्त विषय पर इस विभाग की आज्ञा संख्या एफ. ८ (३३) नियुक्ति—अ/५५ दिनांक ६-६-१९६१

राजस्थान राजपत्र के उपरोक्त तिथि के असाधारण अंक, (भाग ४-ग) में प्रकाशित, उपरोक्त आज्ञा में निम्न संशोधन करने का राज्यपाल आदेश देते हैं:—

संशोधन

निम्नलिखित को नये पैरा संख्या ३-अ तथा ३ ब के रूप में जोड़ो—

३-[अ] ऐसे व्यक्तियों की सेवायें सामान्यतया उनके ५८ वर्ष के होने पर समाप्त कर दी जानी चाहिये किन्तु जिनको दूसरी जांच, जिसके लिए प्रक्रिया इसी आदेश के पैरा (ब) में वर्णित है, के अन्तर्गत भी असाधारण रूप से अच्छा पाया जावे, उनको ६० वर्ष की आयु तक सेवा में रख लिया जावे वशतें कि वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से उपयुक्त पाये जावें।

३-[ब] जिन लोगों को उनकी ६० वर्ष की आयु तक सरकारी सेवा में रखा जाना है, उनके लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे।

(अ) जो व्यक्ति ६० वर्ष तक पुनर्नियुक्ति दिये जाने के लिए असाधारण रूप से अच्छे पाये जायेंगे, उनके मामले संबंधित प्रशासनिक विभाग निम्न सदस्यों की एक समिति के समक्ष रखेगा:—

शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले महाविद्यालयों के लिए समिति

१. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा मनोनीत, आयोग का ही एक सदस्य	अध्यक्ष
२. मुख्य सचिव	सदस्य
३. शिक्षा सचिव	"
४. संचालक, कालेज शिक्षा	"

अन्य महाविद्यालयों के लिए समिति

१. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा मनोनीत, आयोग का ही एक सदस्य	अध्यक्ष
२. मुख्य सचिव	सदस्य
३. सम्बन्धित विभाग का सचिव	"
४. महाविद्यालय अथवा संस्था का आचार्य	"

उपरोक्त पैरा ३ में वर्णित कागजात इस समिति को भी प्रस्तुत किया जावे।

(ब) उपरोक्त जांच समिति की सिफारिशें नियुक्ति विभाग के द्वारा सम्बन्धित मंत्री तथा मुख्य मंत्री को प्रेषित की जावें। प्रत्येक विषय में आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जावेंगे।

[नियुक्ति (अ-ii) विभाग आज्ञा संख्या एफ. ८ (३३) एपाइन्ट्स (अ) ५५-प्रे २ दिनांक

विषय—शिक्षा संचालकों में कार्य का विभाजन

इस विभाग की आज्ञा संख्या एफ० ५(११२) शिक्षा/अ/५८ दिनांक ११-१२-१९५८ के अतिरिक्त शिक्षा संचालक व असिस्टेंट शिक्षा संचालक दोनों के पद क्रमशः संचालक, कालेज शिक्षा तथा संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा बन जाने से इन दोनों अधिकारियों में कार्य का वितरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होगा। ये दोनों अधिकारी अपने अधीन मामलों के बारे में सचिवालय के प्रशासनिक विभाग से सीधे पत्र व्यवहार कर सकेंगे।

[शिक्षा (अ) विभाग आज्ञा संख्या एफ. ८ (४५) शिक्षा/अ/६० दिनांक ६-९-६०]

परिशिष्ट

संचालक, कालेज शिक्षा व संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के मध्य कार्य का विभाजन—

संचालक कालेज शिक्षा

१. कालेज शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा नीति निश्चित करना।
२. विश्वविद्यालयी शिक्षा—स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध समस्त कार्यालय
३. उपरोक्त वर्णित समस्त संस्थाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण
४. उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्तियों, स्थानान्तरण, पदोन्नतियों, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के समस्त मामले तथा उपरोक्त से सम्बन्धित लोक सेवा आयोग से प्राप्त सभी अम्युद्देश (References)
५. उपरोक्त से सम्बन्धित गोपनीय प्रतिवेदन
६. विश्वविद्यालय-शिक्षा का आयोजन व क्रियान्वयन

संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा

१. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा नीति निश्चित करना
२. माध्यमिक, प्राथमिक, बुनियादी, शारीरिक शिक्षा, अध्यापकीय प्रशिक्षण, तथा सभी कार्यालय जो कि स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बद्ध नहीं हो।
३. उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण
४. उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्तियों स्थानान्तरण, पदोन्नतियों, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के समस्त मामले तथा लोक सेवा आयोग से प्राप्त सभी अम्युद्देश
५. उपरोक्त से सम्बन्धित गोपनीय प्रतिवेदन।
६. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का आयोजन तथा उसका क्रियान्वयन और नये विद्यालयों को खोलना व उनकी अभिवृद्धि करना।

७. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें
८. विश्वविद्यालय-समितियों की सदस्यता
९. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल (विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित मामले)
१०. महाविद्यालयों से सम्बन्धित लेखा, बजट, खरीद आदि
११. महाविद्यालयों से सम्बन्धित भवन व यातायात
१२. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को सहायता-अनुदान
१३. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित छात्रवृत्तियां तथा श्रृण
१४. युवक कल्याण, सीनियर एन० सी० सी०, ए० सी० सी०, जो कि स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित हो
१५. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित उत्सव व क्रीड़ा प्रतियोगिताये
१६. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित बैठकें, सम्मेलन, उपनिषद्
१७. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में छुट्टियां व दीर्घकालीन अवकाश
१८. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित तथा उपरोक्त अन्य मामलों पर सचिवालय से प्राप्त अग्र्युद्देश
१९. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित छात्र संघ व समुदाय

७. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें
८. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
९. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामले)
१०. माध्यमिक स्तर तक का बजट, लेखा, खरीद आदि
११. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित भवन व यातायात
१२. स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के अलावा अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान
१३. माध्यमिक स्तर तक की छात्रवृत्तियां व श्रृण
१४. माध्यमिक स्तर तक की जूनियर एन० सी० सी०, ए० सी० सी० तथा स्काउटिंग आदि।
१५. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित उत्सव, प्रदर्शनी, प्रतियोगितायें
१६. माध्यमिक शिक्षा तथा उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित बैठकें, सम्मेलन व उपनिषद
१७. माध्यमिक संस्थाओं में छुट्टियां तथा दीर्घकालीन अवकाश
१८. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित व उपरोक्त अन्य मामलों पर सचिवालय से प्राप्त अग्र्युद्देश
१९. समाज शिक्षा
२०. विशागोय परीक्षाएँ
२१. पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण
२२. व्ययसायिक-मार्ग दर्शन-सेवा
२३. पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की स्वीकृति, वह समितिके अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

शिक्षा संहिता (Education Code) में संचालक को जो अधिकार व शक्तियाँ दी गई हैं, उनका उपयोग स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सम्बन्ध में संचालक, कालेज शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा करेंगे।

विषय—अध्यापकों की सेवा निवृत्ति

राजस्थान सेवा नियम के नियम ५६ (अ) के नीचे के नोट (जिसको कि वित्त विभाग की आज्ञा संख्या डी० १२३६/आर/५७-एफ. १ (५८) आर/५६ दिनांक २२-३-१९५७ तथा ७-६-१९५७ संशोधन चिट संख्या ७६ दिनांक १-६-१९५८ के द्वारा प्रस्थापित किया गया था) के अनुसार शैक्षणिक मंत्र में मितम्बर के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले अध्यापकों की सवान्त (ग्रीष्मावकाश सहित) तक रोका जा सकता है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत पंचायत २-१०-१९५६ से पंचायत समितियों की स्थापना होने के बाद, कुछ प्राथमिक शाला अध्यापक समितियों के नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

राज्यपाल आज्ञा देते हैं कि वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश के अनुसार यदि पंचायत समितियों द्वारा कुछ अध्यापकों को सेवा निवृत्त होने से रोक लिया गया हो, तो वह कार्यवाही सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार ही की हुई मानी जायेगी।

यह आज्ञा २-१०-१९५६ से ही प्रभावशील मानी जायेगी।

[वित्त विभाग-अ (नियम) आज्ञा संख्या एफ. ७ अ (२०) एफ. डी ए. (हस्त)/६० दिनांक १२-८-६०]

विषय—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ द्वारा दी गई उपाधियों की मान्यता

राजस्थान सरकार, गुजरात विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के अनुसार सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर द्वारा प्रदत्त इन्टरमीजियेट (कला, वाणिज्य तथा विज्ञान) बी. ए., एम. ए., बी. एस्. सी. और बी. ई. (मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल) की उपाधियों की राज्य-सेवा के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उनके समकक्ष परीक्षाओं के समान मान्यता प्रदान करती है।

[जी. ए. डी. (अ) आज्ञा संख्या एफ. ४ (१) जी. ए./ए/५७ दिनांक १-७-६०]

विषय—“वर्ष” की परिभाषा

राजस्थान सेवा नियम भाग २ के सेक्शन ३ (आकस्मिक अवकाश) के परिशिष्ट १ में पैरा २ के नीचे निम्न को अपवाद (exception) के रूप में प्रस्थापित करने का राज्यपाल आदेश देते हैं—

अपवाद:—ग्रीष्मावकाश मनाने वाले विभाग यथा राजकीय महाविद्यालय (जिनमें इंजीनियरिंग, वेटरीनरी कृषि तथा मैडिकल आदि भी सम्मिलित हैं) पोलिटेक्नीक स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में “वर्ष” से तात्पर्य १ सितम्बर से प्रारम्भ होकर ३१ अगस्त की समाप्त होने वाले वर्ष से होगा।

यह १ सितम्बर १९६१ से प्रभावशील होगा । १ सितम्बर १९६१ से पूर्व का आकस्मिक अवकाश लेखा १ सितम्बर १९६१ के बाद से समाप्त समझा जावे ।

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अ (हल्स) आदेश संख्या एफ १ (२८) एफ. डी. ए. आर)/ ६१ दिनांक १२-७-१९६१ ।

विषय—राजस्थान यात्रा भत्ता नियम

राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में निम्न संशोधन करने के लिये राज्यपाल ने निर्देश दिया है:—

इन नियमों के परिशिष्ट ३ में मद ८ शिक्षा के उपमद संख्या ४ के नीचे निम्न और जोड़ा जावे:—

५. तकनीकी—शिक्षा—संचालक
६. तकनीकी—शिक्षा—उपसंचालक
७. तकनीकी—शिक्षा—सहायक संचालक
८. इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निकों के आचार्य
९. इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निकों के प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष
१०. इंजीनियरिंग कालेजों के रीडर
११. इंजीनियरिंग कालेजों से सम्बद्ध छात्रावासों के अधीक्षक
१२. तकनीकी शिक्षा मण्डल के प्रस्तोता

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अ (हल्स) आदेश संख्या एफ. ३ (२) एफ. डी. ए. (हल्स) ६१ दिनांक १३-६-६१ ।

विषय:—शिक्षा सेवा नियम में संशोधन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में नियम १४ के नीचे निम्न नोट (२) प्रस्थापित किया जावे तथा वर्तमान नोट की क्रम संख्या १ मानी जावे

नोट—२. राज्य सेवा के लिये ऐसे भूतपूर्व कैदियों, जिन्होंने जेल में अनुशासित जीवन तथा बाद के अच्छे आचरण द्वारा अपने को पूर्णतया सुधारा हुआ सिद्ध कर दिया हो, के साथ उनको मिली विगत सजा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जावेगा । ऐसे व्यक्तियों को, जिनको कि ऐसे अपराधों से सजा हुई है, जिनके लिये उनका नैतिक स्तर उत्तरदायी नहीं हो, सुधारा हुआ मान लिया जावेगा यदि वे अनुवर्ती परिचर्या गृह के अधीक्षक अथवा जहाँ ऐसे गृह नहीं हो, वहाँ जिला-आरक्षी-अधीक्षक से तत्सम्बन्धित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । चरित्र-प्रधान अपराधों के अपराधियों को अनुवर्ती-परिचर्या-गृहों के अधीक्षक से ऐसा प्रमाणपत्र जो कि राज्य के महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, कि ये व्यक्ति राज्य सेवा के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने जेल के अनुशासित जीवन तथा अनुवर्ती-परिचर्या-गृह में सदाचरण से अपने को पूर्णतया सुधारा हुआ सिद्ध कर दिया है, प्रस्तुत करना होगा ।

[नियुक्ति (अ-II) विभाग अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) नियुक्ति/(अ-II)/६० दिनांक २८-६-६१]

विषय—पुस्तकालय प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पुस्तकाध्यक्ष अथवा लेखक वर्ग को सम्पूरक भत्ता Compensatory Allowance)

का अनुदान

राज्यपाल ने आदेश दिया है कि शिक्षा संस्थाओं के लेखक वर्ग अथवा पुस्तकालयाध्यक्षों, जो जब राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये जयपुर में नियुक्त किया जावे, उनके प्रशिक्षण-अवधि में निम्नानुसार सम्पूरक भत्ता उन्हें दिया जावे:—

१. उच्च वर्ग लेखक अथवा योग्यता रहित

पुस्तकालयाध्यक्ष

२५) प्रतिमाह

२. कनिष्ठ लेखक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष

(७०-४-६० ई. बी. ५-१४० मृत्खला के।)

२०) प्रतिमाह

जब तक यह सम्पूरक भत्ता मिलता रहेगा, तब तक कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। जयपुर में निवास के अधिक व्यय को देखते हुये ही यह भत्ता स्वीकृत किया गया है।

[वित्त (व्यय-१) विभाग आदेश संख्या ID/८५/एफ. डी./ई./जनरल/८१ दिनांक ३०-६-६१]

विषय—सरकारी महाविद्यालयों के अस्थाई अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान

सरकारी आदेश संख्या एफ. II (१६५) शिक्षा/५५ दिनांक १०-८-५५ तथा ५-७-१६५६ के अतिरिक्त में राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं कि महाविद्यालयों में अध्यापक-वर्ग को ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान अब निम्न आधार पर नियमित किया जावेगा।

१. राजकीय महाविद्यालयों में उच्चस्तर के व्याख्याता तथा अन्य अध्यापक वर्ग जो कि ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने से पूर्व नहीं हटाये जाते हैं और जो कि ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने के बाद भी सेवा में जारी रहते हैं, की सेवा अवधि को निरन्तर माना जावेगा तथा वे ग्रीष्मावकाश के पूरे वेतन को पाने के अधिकारी होंगे। यह उन पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवार्यें मध्यावधि में किसी कारण से समाप्त कर दी गई हैं तथा अगले मंत्र में जिन्हें नई नियुक्ति दी गई हो।

शिक्षा विभाग के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को नियुक्ति करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहाँ तक सम्भव होवे महाविद्यालयों में दिसम्बर के बाद कोई नियुक्ति नहीं की जावे क्योंकि फाईनल परीक्षाओं के लिए तैयारी करने का अवकाश फरवरी मास से प्रारम्भ हो जाता है तथा तब अध्यापकों की विशेष आवश्यकता भी नहीं रहता।

२. महाविद्यालयों के व्याख्याता तथा अन्य अध्यापक वर्ग, जो कि ऊपर के प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को ग्रीष्मावकाश का वेतन निम्न फार्मुला के आधार पर गणित अवधि के लिये मिलेगा:—

जिन अध्यापकों ने ८ माह से अधिक सेवा की हो तथा जो ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने से पूर्व सत्र के अन्तिम कार्य के दिन उपस्थित हों, उनको निम्न आधार पर ग्रीष्मावकाश का वेतन दिया जावे:—

कार्य करने के दिन
पूरे शैक्षणिक वर्ष के दिन

ग्रीष्मावकाश के दिनों की संख्या—वेतन पाने योग्य
ग्रीष्मावकाश के दिनों की संख्या

यह वित्त विभाग की उनके यू. ओ. नोट नं. ID/१४६६/एफ. डी./इ. आई./६० दिनांक २६-११-६० के अनुसार सहमति से जारी किया गया है।

[राजस्थान सरकार, शिक्षा (अ) विभाग, आदेश संख्या एफ. २ (२०६) शिक्षा/अ/५८ दिनांक ३० दिसम्बर १९६०]

विषय—सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन जारी रखे जाने की स्वीकृति देने के लिये निर्देश

सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में कुछ विभागाध्यक्षों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। उनकी जांच की गई तथा परिणामस्वरूप, उपरोक्त विषय पर इस विभागीय भीमो संख्या एफ १३ (१७) एपाईंटस (अ) ५५/ग्रुप III/दिनांक ३१-७-६१ का निम्न स्पष्टीकरण सबके मार्गदर्शन के लिए दिया जाता है—

१. एल. एल. बी. कक्षाएँ स्नातक स्तर से आगे का अध्ययन माना जाता है, अतः उनके लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।

२. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विदेशी भाषाओं के डिप्लोमा कोर्स में सम्मिलित होने वालों को अनुमति दी जा सकती है।

३. आगे अध्ययन की अनुमति कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार (निम्न लिपिक, उच्च लिपिक) न कि वर्गानुसार (लेखकीय अधीनस्थ सेवाएँ) दी जानी चाहिए।

४. निर्धारित सीमाओं तथा दी गई सूचनाओं के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को प्राईवेट तौर पर बैठने की तब भी अनुमति दी जा सकती है यदि वे रात्रि कक्षाओं जो कि सन् ६२-६३ से प्रारम्भ की जाने वाली हैं, में उपस्थित न भी होना चाहें।

[नियुक्ति (अ-III) विभाग परिपत्र संख्या एफ. १३ (१७) एपाईंटस (अ) ५५/ग्रुप III दिनांक २४-१०-१९६१]

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग राजस्थान

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

प्रधान कार्यालय

बीकानेर (राजस्थान)

आदेश

राजस्थान राज्य की समस्त राजकीय तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सत्र पर्यन्त कार्यक्रमों में एकता लाने हेतु इस विभाग की ओर से सत्र १९६५-६६ के उपयोगार्थ पंचांग (कलेण्डर) प्रस्तुत किया गया है, इस पंचांग में सत्र पर्यन्त के अवकाश विवरण आदि के अलावा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की विधि का भी सविस्तार उल्लेख है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का संचालन तथा आयोजन वांछनीय है। अवसर अथवा कार्यवशात् यदि इसमें

किसी संस्था प्रधान को परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता हो तो इस कार्यालय की पूर्ण आज्ञा प्राप्त कर लेना अपेक्षित है। उपाध्यक्ष मण्डल और निरीक्षक शिक्षणालयों से आज्ञा की जाती है कि वे इस आज्ञा का पूर्णरूपेण पालन करेंगे।

कलेण्डर से सम्बन्धित सूचना सत्र १९६५-६६

१. समस्त शिक्षण संस्थाएं गुरुवार दिनांक १ जुलाई १९६५ को ग्रीष्मावकाश पश्चात् खुलेगी। समय प्रातः काल का रहेगा। समस्त शालाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाएं एवं छात्र/छात्राओं के प्रवेश से सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकायें शालाएं खुलने से तीन दिन पहले अपनी शालाओं में उपस्थित हो जावें।

२. (क) प्रवेश आदि कार्य ७ जुलाई तक समाप्त हो जावे एवं समय विभाग चक्र तैयार कर दिया जावे ताकि ८ जुलाई (गुरुवार) से यथाविधि शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जावे। विशेष परिस्थिति में प्रवेश ३१ जुलाई तक हो सकेंगे।

(ख) वर्ष भर में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को १५ जुलाई तक मासिक पढ़ाई योजना के अनुसार विभक्त किया जाय और न्यूनतम लिखित कार्य की योजना (Schedule of minimum written work) आदि तैयार करली जावे ताकि अक्टूबर १९६५ तथा फरवरी १९६६ में लिखित कार्य का मूल्यांकन सत्र में दो बार इसी आधार पर किया जावे। संस्था प्रधान सत्र के प्रारम्भ में अध्यापकों को इस विषय से अवगत करा दें।

(ग) अभिभावकों (राज कमचारी तथा कोई व्यक्ति) के स्थान परिवर्तन करने पर संस्था प्रधान पूर्व शाला द्वारा दिये हुए स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) के आधार पर छात्र व छात्रा को सत्र के बीच में कभी भी प्रवेश दे सकते हैं।

३. सायंकाल का समय परीक्षाकाल को छोड़कर सत्र पर्यन्त अनिवार्य रूप से खेल अभ्यास में लगाया जावे।

४. शनिवार को पूरी अवधि (Duration) के चार अन्तर (Periods) अथवा कुछ कम अवधि के पूरे आठ अन्तर (Periods) संस्था प्रधान द्वारा सुविधानुसार किये जावें और शेष बचे हुए समय को यदि कोई वाद-विवाद आदि प्रवृत्तियाँ (Co-curricular Activities) न रखी जावे तो अंग्रेजी, गणित आदि की विशेष कक्षाएँ लगा कर काम में लिया जाय।

स्कूलों के लिये स्वीकृत अवकाश

१. वाराणसी	१२ जुलाई १९६५	सोमवार	१
२. रक्षाबन्धन	१२ अगस्त १९६५	गुरुवार	१
३. स्वतन्त्रता दिवस	१५ अगस्त १९६५	रविवार	१
४. जन्माष्टमी	१६ अगस्त १९६५	गुरुवार	१
५. महात्मा गांधी जन्म दिवस	२ अक्टूबर १९६५	शनिवार	१
६. दशहरा	३, ४ व ५ अक्टूबर १९६५	रवि, सोम, मंगल	३
७. दीपावली अवकाश	१७ से २८ अक्टूबर १९६५ तक	रविवार से गुरुवार	१२
८. गुरुनानक दिवस	६ नवम्बर १९६५	मंगलवार	१
९. गीतकालीन अवकाश	२५ से ३१ दिसम्बर १९६५ तक	शनि से शुक्रवार तक	७

१०. गणतन्त्र दिवस	२६ जनवरी १९६६	बुधवार	१
११. महा शिवरात्री	१८ फरवरी १९६६	शुक्रवार	१
१२. होली	६, ७ व ८ मार्च १९६६	रवि, सोम, मंगल	३
१३. ईदुल फीतर	राज पत्रित व चन्द्रोदय के अनुसार	—	१
१४. रामनवमी	३० मार्च १९६६	बुधवार	१
१५. महावीर जयन्ती	३ अप्रैल १९६६	रविवार	१
१६. ईदुल जुहा	राज पत्रित व चन्द्रोदय के अनुसार	—	१
१७. मोहरम	राज पत्रित व चन्द्रोदय के अनुसार	—	१

३८

उत्सव दिवस

६. निम्नलिखित उत्सव दिवस धर्म निरपेक्षता को दृष्टिगत रखते हुए उत्साह पूर्वक मनाये जावें ।

(क) जिस उत्सव के दिन रविवार अथवा स्वीकृत अवकाश पड़ता हो उस उत्सव को एक दिन पहले के बाद अथवा अन्तिम दो अन्तर (पीरियड्स) में मना लिया जावे ताकि ठीक रविवार अथवा स्वीकृत अवकाश के दिन पूर्ण अवकाश मनाया जा सके ।

(ख) जो उत्सव दिवस कार्य दिवस पर पड़ते हैं उन उत्सवों को उत्सव दिवस पर ही अन्तिम दो अन्तर (पीरियड्स) में मनाया जावे ।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) निर्देश १५ अगस्त १९६५, २ अक्टूबर १९६५ और २६ जनवरी १९६६ पर लागू नहीं होंगे इन राष्ट्रीय समारोहों को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उसी दिन निर्धारित समय पर उत्साह पूर्वक मनाना अनिवार्य है तथा शिक्षकों, विद्यार्थियों व विद्यालय के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य है ।

१. बाराबकात	१२ जुलाई १९६५	सोमवार	स्वीकृत अवकाश
२. स्वतन्त्रता दिवस	१५ अगस्त १९६५	रविवार	"
३. जन्माष्टमी	१९ अगस्त १९६५	शुक्रवार	"
४. अध्यापक	५ सितम्बर १९६५	रविवार	अस्वीकृत अवकाश
५. महात्मा गांधी जयन्ती	२ अक्टूबर १९६५	शनिवार	स्वीकृत अवकाश
६. संयुक्त राष्ट्र दिवस	२४ अक्टूबर १९६५	रविवार	अस्वीकृत अवकाश
७. गुरु नानक जयन्ती	९ नवम्बर १९६५	मंगलवार	स्वीकृत अवकाश
८. बाल दिवस	१४ नवम्बर १९६६	रविवार	अस्वीकृत अवकाश
९. ईशुमसीह जन्म दिवस	२५ दिसम्बर १९६५	शनिवार	स्वीकृत अवकाश
१०. गणतन्त्र दिवस	२६ जनवरी १९६६	बुधवार	स्वीकृत अवकाश
११. सांस्कृतिक दिवस (वसंत पंचमी)	जनवरी १९६६	बुधवार	अस्वीकृत अवकाश
१२. दयानन्द सरस्वती दिवस	२ मार्च १९६६	बुधवार	अस्वीकृत अवकाश
१३. रामनवमी	३० मार्च १९६६	बुधवार	स्वीकृत अवकाश

१४. महावीर जयन्ती	३ अप्रैल १९६६	रविवार	स्वीकृत अवकाश
१५. बुद्ध पूर्णिमा	४ मई १९६६	बुधवार	अस्वीकृत अवकाश

१. राजपत्रित तथा अन्य अवकाश	३८	साल के कुल दिवस ३६५
२. रविवार	४०	साल के कुल अवकाश एवं परीक्षा दिवस १४८
३. प्रधानाध्यापक द्वारा घोषित अवकाश	२	साल के कुल कार्य दिवस २१७
४. स्थानीय जिलाधीश द्वारा घोषित अवकाश	२	
५. ग्रीष्मावकाश १५ मई से ३० जून तक	४७	
६. कुल परीक्षा दिवस	१९	

१४८

नोट—१. उपर्युक्त अवकाश रविवारों के अतिरिक्त है।

२. विद्यालयों के कार्यालयों में दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश को छोड़ कर उपर्युक्त अवकाश ही माने जावेंगे। वे कार्यालय इन तीनों अवकाशों में राजपत्रित अवकाश का उपभोग करेंगे।

३. संस्थाप्रधान उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त सत्र पर्यन्त जिलाधीश द्वारा घोषित दो अवकाशों को छोड़कर दो दिवसों का अवकाश निम्नरूपेण घोषित कर सकते हैं:—

(अ) संस्थाप्रधान उच्च/उच्चतर/प्रशिक्षण विद्यालय २ दिवस प्रधानाध्यापक अपने निकटतम उच्चाधिकारी अर्थात् निरीक्षक को तथा प्रधानाध्यापिकाएँ संबंधित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा/निरीक्षिका को इन दोनों अवकाशों के मनाने की पूर्व सूचना तिथि सहित सूचित करें।

(आ) संस्था प्रधान माध्यमिक पाठशाला २ दिवस—प्रधानाध्यापक इन दो अवकाशों को मनाने की तिथि निश्चित कर अपने संबंधित निरीक्षक की पूर्व आज्ञा प्राप्त करके इन अवकाशों को मनावें।

(इ) संस्थाप्रधान प्राथमिक पाठशाला २ दिवस—इन अवकाशों की तिथि निश्चित कर प्रधानाध्यापक अपने संबंधित निरीक्षक तथा प्रधानाध्यापिका अपनी संबंधित उपनिरीक्षिका/निरीक्षिका से पूर्व आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही इन्हें मनावें।

४. अन्य कार्यालयों (विद्यालयों कार्यालयों के अतिरिक्त) में राजपत्रित अवकाश ही माने जावेंगे।

७. स्कूल पार्लियामेंट का चुनाव १५ अगस्त १९६५ तक समाप्त कर दिया जावे।

८. प्रथम टैस्ट अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किया जावे। टैस्ट को कम से कम दिनों में समाप्त कर उसका परीक्षाफल तीन दिनों में तैयार कर दिया जावे।

९. शिक्षण संस्थाओं में समय परिवर्तन (मध्याह्न का) दिनांक १ सितम्बर, बुधवार १९६५ से कर दिया जावे। ऋतु भिन्नता के कारण यदि आवश्यक हो तो वालिका विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाएँ संबंधित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा/उपनिरीक्षिका/निरीक्षिका तथा छात्र विद्यालयों के प्रधानाध्यापक निरीक्षक शिक्षणालय की पूर्व आज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही १५ दिन पहले अथवा पीछे

संस्था के समय परिवर्तन कर सकते हैं। सम्बन्धित उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा उपनिरीक्षिका/निरीक्षिका तथा निरीक्षक शिक्षणालय द्वारा इस परिवर्तन की सूचना शीघ्र अतिरिक्त संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित की जावे।

१०. शिविर काल निम्नरूपेण रहेगा:—

(अ) एन. सी. सी. शिविर:—

एन. सी. सी. जूनियर डिविजन कैम्प दीपावली अवकाश में।

(आ) स्काउट एवं गाइड कार्यक्रम:—

१. कमिश्नरों की कान्फ्रेंस कोटा में २६ अगस्त से २८ अगस्त १९६५ तक।
२. स्टेट, कौन्सिल की बैठक कोटा में २९ अगस्त १९६५ को।
३. डिस्ट्रिक्ट स्काउट्स/गाइड्स ट्रेनिंग कोर्स ३० अगस्त ६५ से ३ सितम्बर १९६५ तक कोटा में।
४. पेट्रोल लीडर्स प्रशिक्षण शिविर अगस्त में।
५. उद्योग पर्व समस्त राजस्थान में तारीख ७ सितम्बर से १४ सितम्बर १९६५ तक।
६. पलांक लीडर्स प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर कोटा में २३ सितम्बर ६५ से २ अक्टूबर १९६५ तक (पूर्वी रेन्ज)।
७. पलांक लीडर्स प्रारम्भिक शिविर उदयपुर में २३ सितम्बर ६५ से २ अक्टूबर १९६५ तक (पश्चिमी रेन्ज)।
८. कंव मास्टर्स के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर डिविजन केन्द्रों पर २४ सितम्बर से ३९ सितम्बर तक।
९. स्काउट मास्टर्स के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर डिविजन केन्द्रों पर १० अक्टूबर से २१ अक्टूबर तक।
१०. गाइड कप्तानों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर अजमेर में ११ अक्टूबर से २० अक्टूबर तक (पूर्वी रेन्ज हेतु)।
११. गाइड कप्तानों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर जोधपुर में ११ अक्टूबर से २० अक्टूबर तक (पश्चिमी रेन्ज हेतु)।
१२. बुलबुल शाखा के लिये एच. डब्लू. बी. कोर्स स्काउट वन सांगानेर में ३० अक्टूबर से ८ नवम्बर तक।
१३. प्रेजिडेंट्स स्काउट्स व गाइड्स रैली देहली में २२ नवम्बर से २६ नवम्बर तक।
१४. फर्स्ट क्लास स्काउट्स/व गाइड्स की रैली स्काउट वन सांगानेर में २६ नवम्बर १९६५ से १ दिसम्बर १९६५ तक।
१५. राजस्थान स्टेट रोवर मीट उदयपुर डिविजन २७ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर १९६५ तक।
१६. राजस्थान स्टेट रेन्जर मीट सवाई माधोपुर में २७ दिसम्बर ६५ से ३१ दिसम्बर १९६५ तक।

१७ हिमालय कबड्डी वुडबैज कोर्स ८ जनवरी ६६ से १६ जनवरी तक ।

१८. कबड्डी वुड वुड वन नाइट कैम्पन लोकल ऐमोनियेशन स्तर पर फरवरी ६६ में ।

१९. बी. पी. डे और माइड पिग्निंग डे २२ फरवरी १९६६ को ।

मई और जून १९६५ में

(ए) फर्स्ट क्लास स्काउट्स ट्रेनिंग कैम्पन माउन्ट ब्रावू में ।

(बी) कबड्डी मास्टर्स एग्जाम्न्स ट्रेनिंग कैम्प माउन्ट ब्रावू में ।

(सी) रोवर स्काउट लीडर प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविर माउन्ट ब्रावू में ।

(डी) गाईडर एडवान्स ट्रेनिंग कैम्प माउन्ट ब्रावू में ।

(ई) रोवर व रेन्ज माउन्टनियरिंग कोर्स माउन्ट ब्रावू में ।

(एफ) स्काउट्स/गाइड्स हार्डक कम कैम्प नेमीनार राज्य में बाहर ।

(जी) रोवर मीट ट्रेनिंग कैम्प माउन्ट ब्रावू में ।

(एन) भारत मेवक समाज तथा अन्य शिविर ३१ अक्टूबर तक समाप्त हो जाने चाहिये ।

११. (क) राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता शिविर अगस्त या सितम्बर १९६५ में ।

(ख) राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता के राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी १९६६ ।

(ग) १० अक्टूबर १९६५-शारीरिक कुशलता परीक्षण के रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि (केवल केन्द्रों पर) ।

नोट—उपरोक्त शिविरों के अतिरिक्त (जैसे लोक महायक सेना आदि) अन्य शिविरों में छात्र एवं अध्यापकों को बिना इस कार्यालय की पूर्व प्राज्ञा प्राप्त किये नहीं भेजा जावे ।

१२. (क) छात्रों की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगितायें १७ अक्टूबर १९६५ में पहले समाप्त करली जावे ।

(ख) नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में छात्राओं की मण्डलीय (Divisional) खेल कूद प्रतियोगितायें समाप्त करली जावें ।

(ग) नवम्बर मास के तृतीय सप्ताह में छात्रों की मण्डलीय (Divisional) खेल कूद प्रतियोगितायें समाप्त करली जावे । इसी अवसर पर दो दिवस के लिये मुख्य अध्यापकों का जोनल सम्मेलन भी आयोजित किया जावे ।

१३ अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में द्वितीय टेस्ट किया जावे और एक सप्ताह में प्रगति पत्र संस्करणों के पास भेज दिये जावें । इस टेस्ट के साथ ही तीसरे टेस्ट के वजाय जुलाई से अक्टूबर तक के लिखित कार्य का मूल्यांकन (एक टेस्ट के आधे अंकों में से) कर लिया जावे ।

१४. दीपावली अवकाश दिनांक १७ अक्टूबर से २८ अक्टूबर १९६५ तक रहेगा ।

१५. शैक्षणिक संस्थाओं को अपने-अपने वार्षिक उत्सव, प्रतियोगितायें आदि दिसम्बर के अन्त तक समाप्त कर देनी चाहिये ।

१६. शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा दूसरी प्रतियोगितायें में केवल स्थानीय छात्र/छात्रा ही दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह

तक भाग ले सकते हैं । अन्य स्थानों पर भाग लेने हेतु स्कूल से कोई टीम नहीं भेजी जावे ।

१७. नवम्बर में शारीरिक कुशलता परीक्षण (केवल निर्धारित केन्द्रों पर ही) किया जावे ।

१८. राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगितायें निम्न दिवसों पर होगी—

(अ) छात्र २ दिसम्बर से ६ दिसम्बर १९६५ अजमेर में ।

(आ) समस्त प्रधानाध्यापिकाओं का सम्मेलन दिनांक ६ दिसम्बर से ८ दिसम्बर १९६५ अजमेर में ।

(इ) राज्य स्तरीय छात्र खेल-कूद प्रतियोगितायें ९ दिसम्बर १९६५ से १३ दिसम्बर १९६५ जयपुर में ।

(ई) वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी सम्मेलन १३ दिसम्बर १९६५ से १५ दिसम्बर १९६५ जयपुर में ।

१९. शीतकालीन अवकाश २५ दिसम्बर १९६५ से ३१ दिसम्बर १९६५ तक ।

२०. अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ जनवरी १९६६ के द्वितीय सप्ताह में आरम्भ की जावे । यह परीक्षा कम से कम अवधि में समाप्त हो जानी चाहिये । इसका परीक्षा फल जनवरी मास के अन्दर तैयार करके प्रगति पत्र संरक्षकों को भेज दिये जावे ।

२१. तृतीय टेस्ट के बजाय ओप ग्रादे अंकों में से लिखित कार्य का मूल्यांकन फरवरी के अन्तिम सप्ताह में किया जावे । प्रमोशन रुल्स में दो बार का लिखित कार्य का मूल्यांकन एक टेस्ट के (तीसरे टेस्ट के) बराबर समझा जाय ।

२२. विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रमः—

(अ) माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएँ १० मार्च से होगी ।

(आ) बी. एड. की परीक्षाएँ सम्भवतः अप्रैल के तृतीय सप्ताह में होगी ।

(इ) शारीरिक शिक्षण परीक्षाएँ सम्भवतः २८-४-१९६६ से होगी ।

(ई) एस. टी. सी. परीक्षाएँ २५-४-१९६६ से होगी ।

(उ) शास्त्री तथा आचार्य व संस्कृत आयुर्वेद की परीक्षाएँ २१-४-१९६६ से होगी ।

(ऊ) संगीत परीक्षाएँ २-५-१९६६ से होगी ।

(ए) कला परीक्षाएँ २५-४-१९६६ से होगी ।

(ऐ) हैडी क्राफ्ट परीक्षाएँ २१-४-१९६६ से होगी ।

२३. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षा केन्द्र संस्थाएँ परीक्षाकाल में अंशतः बन्द रहेगी । कार्य पूर्ण करने के लिए सत्या प्रधान छुट्टियों को कम करके इस काल को पूरा करेगा । छुट्टियों को कम करने का निर्णय कर सत्रारम्भ में प्रधान अपने संबंधित जिला निरीक्षक/उपाध्यक्ष स्त्री शिक्षा/निरीक्षिका के पास सूचना प्रेषित कर दें ।

२४. जनवरी, फरवरी तथा मार्च पूर्णरूपेण शिक्षण कार्य में लगाये जावें । ३० जनवरी को ११ वजे २ मिनट का मौन रखा जावे ।

२५. १ अप्रैल, १९६६ से संस्था का समय प्रातः काल का किया जावे ।

२६. वार्षिक परीक्षा दिनांक २५ अप्रैल से आरम्भ की जावे ।

२७. परीक्षाफल दिनांक १४-५-१९६६ को घोषित किया जावे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर को समस्त शिक्षण संस्थाओं की कक्षा ८ का परिणाम तीन दिन पहले घोषित कर दिया जावे ताकि संचालक शैक्षणिक व व्यवसायिक व्युत्पत्तियों द्वारा उन छात्रों की मनोवैज्ञानिक जांच को जाकर उन्हें ९वीं कक्षा में योग्यतानुसार कौन से विषय लेने चाहिए इस बारे में परामर्श दिया जा सके। १२ मई तक भण्डार, फर्नीचर आदि परीक्षण किया जावे।

२८. रविवार १५ मई, १९६६ से ग्रीष्मावकाश आरम्भ होकर ३० जून, १९६६ तक मनाया जावे तथा व जुलाई १९६६ से नवीन सत्रारम्भ किया जावे।

२९. अक्टूबर १९६५ व फरवरी १९६६ में तृतीय टेस्ट के बजाय लिखित कार्य का मूल्यांकन केवल आठ तक के छात्र/छात्राओं का ही होगा/कक्षा ९ के छात्र/छात्राओं का समस्त विषयों में तथा हायर सैकेंड्री के भाग प्रथम में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का होम एक्जामिनेशन के विषयों में तीसरा टेस्ट फरवरी के अन्तिम सप्ताह में लिया जावेगा।

अनिल वीदिया,
अतिरिक्त संचालक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषय—आकस्मिक अवकाश

राज्यपाल, राजस्थान सेवा नियम खंड २ में निम्न और संशोधन करने का निर्देश देते हैं।

“भाग ३ परिशिष्ट १ के पैरा ३ के अंत में निम्न वाक्य जोड़ दिया जावे—

रविवार, राजपत्रित अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश, जो कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में आते हों, आकस्मिक अवकाश के अंश नहीं माने जावेंगे।”

संख्या एफ. १ (५१) एफ. डी. ए. (नियम)/६१-दिनांक १८ दिसम्बर १९६१

विषय—निःशुल्क शिक्षा

हिज हाईनेस राजप्रमुख राजस्थान में तकनीकी या अन्य अन्य प्रकार की सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं में १९५६-५७ के शिक्षण सत्र से ही राज पत्रांकित एवं अराजपत्रांकित कर्मचारी जिनका वेतन २५०) तक या इससे कम है, के परिवार के सदस्यों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए आज्ञा जारी करते हैं।

[शिक्षा विभाग संख्या एफ. १ (१२७) शिक्षा/बी/५६ दिनांक ९-७-५६]

प्रसंग—इस कार्यालय का आदेश दिनांक ९-७-५६.

उपरोक्त राजकीय आदेश के अधीन राज्य कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में कुछ संदेह उठाये गये हैं। अतः हिजहाईनेस राजप्रमुख निम्नलिखित आदेश देने पर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. राज्य कर्मचारी के परिवार में स्वयं राज्य कर्मचारी, पत्नि, कानूनी एवं गैर कानूनी बच्चे तथा भाई एवं बहने जो पूर्णतया राज्य कर्मचारी पर निर्वाह करते हैं विवाह के समय तक ये

सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

२. इस सुविधा के अन्तर्गत केवल राजस्थान सरकार के कर्मचारी ही शामिल हैं । भारत सरकार के कर्मचारी, जैसे रेलवे, भारतीय डाकखाना तथा अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारी इस आदेश के अधीन शिक्षण शुल्क से मुक्त नहीं किये जा सकते हैं ।

३. जो कर्मचारी अर्द्ध सरकारी कार्यालय जैसे नगरपालिका मंडल, जिला बोर्ड पंचायतें तथा सरकारी सहायता प्राप्त अन्य संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वे शुल्क मुक्ति का कोई अधिकार नहीं कर सकते ।

४. यह "मुक्ति" (exemption) केवल [क] छूटन फीस [ख] प्रवेश शुल्क [ग] साइन्स ड्राईंग व कामसं शुल्क या अन्य किसी शुल्क या अन्य किसी तकनीकी विषय तक ही सीमित है ।

यह (क) पुस्तकालय एवं वाचनालय शुल्क (ख) छात्रावास का कमरा किराया (ग) छात्रावास विद्युत एवं जल व्यय, (घ) परीक्षा शुल्क, (च) कालेज पत्रिका शुल्क, (छ) कालेज दिवस शुल्क, (ज) संलग्न क्लब शुल्क तथा छात्रसंघ शुल्क आदि पर लागू नहीं होगा ।

५. वर्तमान आदेश से उन छात्रवृत्तियों एवं शुल्क मुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये अन्य आदेशों के अधीन जारी की गई हो ।

६. राजस्थान सरकार के पेंशन प्राप्तकर्ता इस आदेश से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे ।

७. यह मुक्ति की सुविधा, जो राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी गई है, उन व्यक्तियों से वापिस ले ली जावेगी, जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । यह सुविधा उस समय तक वापिस नहीं दी जावेगी जब तक कि वह व्यक्ति उसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जावे ।

८. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी हुई जाति के बोनाफाईड छात्र जो विलकुल गरीब परिस्थिति में हों लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों, तो तब तक वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जायेंगे तब तक इस अधिकार से वंचित रहेंगे ।

९. (अ) यह लाभ १९५६-५७ के सत्रारम्भ से सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं में दिया जाना है तथा यदि कोई शुल्क पहिले ही वसूल कर लिया गया है तो उसे नियम के अनुसार लौटा देना चाहिये ।

(ब) एक राजकीय कर्मचारी इसका फायदा उसी समय तक उठा सकता है जब तक कि उसका वेतन जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के नियम २४ में वर्णित है, २५०) तक है । यदि सत्र के बीच में किसी भी समय जब राज्य कर्मचारी का वेतन २५०) से अधिक हो जाता है तो उसे अनुपात के अनुसार सत्र के बाकी बचे समय का शुल्क जमा कराना चाहिए ।

१०. संस्था-प्रधान के समक्ष किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त किये जाने से पूर्व, संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

११. संरक्षता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जबकि ऐसा केवल इस "शुल्क मुक्ति" की सुविधा से लाभ उठाने के लिए ही किया गया हो । ऐसे मामले

टिप्पणी व कार्यों सहित स्वीकृति के लिये सरकार के पास सफाई करके भेजने चाहिये।

शुल्कमुक्ति (exemption) के लिये प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो कि स्कूल में कक्षा का विद्यार्थी है, श्री के परिवार का (स्वयं/पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन) एक सदस्य है। ये मेरे अधीन के रूप में कार्यालय में कार्य कर रहे हैं जिनका कि वेतन प्रति माह की वेतन शृंखला में है। इनकी अग्रिम वार्षिकीवृत्ति दिनांक को होगी।

राजपत्रांकित अधिकारी के हस्ताक्षर

राजपत्रांकित उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं रबड़ की मोहर, साथ में

पद का नाम

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा लड़का/लड़की/भाई बहन है तथा पूर्णरूपेण मुझ पर आश्रित है तथा उपरोक्त मेरी पुत्री/बहन अविवाहित है।

दिनांक

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर
तथा पद

विषय-पाठ्य पुस्तकें

सरकार कक्षा १ से ८ तक की पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की उन्नत नीति को अपनायेगी। यह राष्ट्रीयकरण का कार्य एक मंडल को सौंपा जावेगा जो कि "राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल" कहलायेगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

- | | |
|---|---------|
| १. अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान | अध्यक्ष |
| २. सचिव, शिक्षा विभाग, " | सदस्य |
| ३. श्री एल. एल. जोशी | " |
| ४. संचालक, शिक्षा विभाग | " |
| ५. उप सचिव, वित्त विभाग | " |
| ६. एस. डी. ओ. के स्तर का आर. ए. एस.
अधिकारी या शिक्षा अधिकारी जो
उपसंचालक से कम पद का न हो— | सचिव |
| ७. यह मंडल अपना सचिवालय तथा कार्य का तरीका अलग ही बनायेगा। | |

३. यह पाठ्यपुस्तकों को विभिन्न विषयों में लेखकों को नियुक्त कर लिखा जा सकता है या/तथा उन्हे क्षेत्र के बाहर वाले लेखकों से ग्रामन्वित कर सकता है ।

४. ये पुस्तकें सरकार द्वारा दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जायेंगी ।

५. कुछ ऐसे विषयों में जिसे बोर्ड उचित समझे, वह लेखकों को पाठ्य पुस्तकें लिखने में मार्ग दर्शन के लिए स्वयं आदर्श पुस्तकें भी तैयार करेगा ।

६. यह इन पुस्तकों की जांच कराने का भी प्रबंध करेगा । इन पुस्तकों की अन्तिम जांच एक बहुत उच्च समिति के स्तर पर होगी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक व्यक्ति एवं राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष शामिल होंगे ।

७. अन्तिम निर्वाचन हो जाने के बाद मंडल विभिन्न पुस्तकों के लिये उचित दृश्य बनाने हेतु कलाकारों को नियुक्त करेगा ।

८. मंडल इन पुस्तकों को राजकीय एवं व्यक्तिगत मुद्रणालयों में प्रकाशित कराने का प्रबन्ध करेगा । इन पुस्तकों के कागज, मुख पृष्ठ अक्षर का आकार, जिल्द के किस्म, पुस्तक का आकार, सूची तथा चित्र सूची सम्बन्धित विशेष बातों के विषय में निर्णय अपनी इच्छानुसार लेगा ।

९. यह पुस्तकों के लेखकों, कलाकारों, जांच करने वालों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो इस कार्य में सहायता के लिये बुलाये गये हैं, पारिश्रमिक देने की दर निर्धारित करेगा ।

१०. इन कार्यों को पूर्ण कराने के लिये जो भी वह उचित समझे आवश्यक कदम उठायेगा ।

११. एक बार जो पुस्तकें निर्धारित कर दी गई हैं, वे तीन या चार साल तक चलती रहेंगी, जब तक कि उनकी जल्दी ही परिवर्तन करने के कोई दृढ़ कारण उपस्थित न हो ।

विषय—प्रशासकीय शक्तियों का हस्तान्तरण

राजस्थान असेनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनर्विचार) नियम १९५० के नियम १२ (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हिज हाईनेस राजप्रमुख आदेश देते हैं कि उपरोक्त नियम के साथ संलग्न सूची २ में 'शिक्षा विभाग' मद के अन्तर्गत वर्णित पदों के नीचे निम्नलिखित नोट संख्या १ व २ की तरह शामिल किये जावे—

नोट (१) इन पदों पर कार्यकर्ता, जिनका वेतन १२५ प्रतिमाह से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में भाग ३ में वर्णित शक्तियां उपसंचालक, शिक्षा में उससे सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर तथा नीचे दी गई दूसरे नोट के आधार पर निहित होगी ।

(२) उन अध्यापकों के (उपरोक्त पद) पदों पर काम करने वाले जिनका वेतन ७० से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में भाग ३ में वर्णित शक्तियां उससे सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर, निरीक्षक, उपनिरीक्षक इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट में निहित होगी ।

[नियुक्ति (क) विभाग आज्ञा संख्या—१-१३२५/नियुक्ति (क) ५६-दिनांक १६-१-५६]

विषय—शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सेवा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ एवं वित्तीय शक्तियों की सूची

क्रम संख्या	शक्ति की किस्म	किसको प्रदान की गई	प्रदत्त शक्तियों की सीमा
१.	अध्यय अवकाश एवं असमर्थता अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति	संचालक, शिक्षा विभाग	निरीक्षक की शक्ति तक
		उपसंचालक, शिक्षा विभाग	अप्रशिक्षित ग्रेड में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की शक्ति तक
		सहायक संचालक, शिक्षा (महिला)	निम्न डिवीजन वर्क एवं इन्टर ग्रेड के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की शक्ति तक
		निरीक्षक, उपनिरीक्षक, इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट	इन्टर ग्रेड में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की शक्ति तक
		उप शाला निरीक्षक	मैट्रिक ग्रेड में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की शक्ति तक
		इन्टर कालेजों के प्राचार्य	नियुक्ति करने की शक्ति तक
		उच्च विद्यालय, प्रशिक्षण एवं बहुदेशीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक	नियुक्ति करने की शक्ति तक
२.	उन भवनों की मरम्मत, जिनकी सुरक्षा का भार विभाग पर है।	“अ” श्रेणी की पुस्तकालयों के अध्यक्ष	नियुक्ति करने की शक्ति तक
		संचालक शिक्षा विभाग	पूर्ण शक्तियाँ
		उप संचालक शिक्षा	२०००) तक
		सहायक संचालक (महिला) शिक्षा	५००) तक
		निरीक्षक, उप निरीक्षक, इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट	१००) तक
		उप निरीक्षक, स्कूल	५०) तक

३.	स्टोर की राशीद	<p>संचालक, शिक्षा</p> <p>उप संचालक शिक्षा</p> <p>सहायक संचालक(महिला) शिक्षा</p> <p>निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक, इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट</p> <p>उप निरीक्षक</p> <p>इन्टर कालिजों के प्राचार्य</p> <p>उच्चविद्यालय, प्रशिक्षण एवं बहुउद्देशीय शालाओं के प्रधानाध्यापक</p> <p>“ग्र” श्रेणी के पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष</p>	<p>बीस हजार रुपये तक</p> <p>५०००) तक</p> <p>२०००) तक</p> <p>२०००) तक</p> <p>५००) तक</p> <p>२०००) तक</p> <p>५००) तक</p> <p>१००) तक</p>
४.	सम्पत्ति की हानि होने पर उसे खत्म करना	<p>शिक्षा संचालक</p> <p>उप संचालक, शिक्षा</p> <p>सहायक संचालक शिक्षा (महिला)</p> <p>निरीक्षक एवं उप निरीक्षक, स्कूल इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट</p>	<p>प्रत्येक मामले में ५००) तक किन्तु साल में कुल १०,०००) से अधिक नहीं।</p> <p>प्रत्येक मामले में २००) तक किन्तु साल में कुल २०००) से अधिक नहीं।</p> <p>प्रत्येक मामले में १००) तक किन्तु साल में कुल १०००) से अधिक नहीं।</p> <p>निरीक्षकों के लिये ५०) प्रत्येक मामलों में किन्तु साल में कुल ५००) ६० से अधिक नहीं तथा उप निरीक्षक डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज के लिये प्रत्येक मामले में २५) तक, पर साल में कुल २५०) से अधिक नहीं।</p>

५.

अनुपयोगी वस्तुओं का
नीलाम एवं उनकी
कीमत खत्म करना

उप निरीक्षक

प्रत्येक विषय में २५ तक, पर
मान में कुल २५०) से अधिक
नहीं।

इन्टर कालेजों के शालाया

प्रत्येक मामले में ५०) तक किन्तु
मान में कुल २५०) से अधिक
नहीं।

उच्चविद्यालयों, प्रशिक्षण
शालाओं एवं बहुउद्देशीय
शालाओं के प्रधानाध्यापक

प्रत्येक मामले में २५) तक पर
मान में कुल २५०) से अधिक
नहीं।

"अ" श्रेणी के पुस्तकाल-
यों के अध्यक्ष

प्रत्येक मामले में २५) तक, पर
मान में कुल २५०) से अधिक
नहीं।

संचालक, शिक्षा विभाग

प्रत्येक मामले में ५००) तक पर
कुल वर्ष में १००००) से अधिक
नहीं।

उप संचालक, शिक्षा

प्रत्येक मामले में २००) तक पर
वर्ष में कुल २०००, से ज्यादा
नहीं।

सहायक संचालक शिक्षा
(महिला)

प्रत्येक मामले में १००) तक पर
वर्ष में कुल १०००) से अधिक
नहीं।

निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक
इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट

निरीक्षकों के लिये प्रत्येक मामले
में ५० तक पर वर्ष में कुल ५००)
से अधिक नहीं, उप निरीक्षक
इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट को प्रत्येक विषय
में २५) तक पर कुल वर्ष भर में
२५०) से अधिक नहीं।

इन्टर कालेजों के प्रधाना-
ध्यापक

प्रत्येक मामले में २५) तक पर
वर्ष में कुल ५००) तक

उप शाला, निरीक्षक

उच्च विद्यालय, प्रशि-

क्षण शालाएँ एवं बहु-

उद्देशीय शालाओं के

प्रधानाध्यापक

"अ" श्रेणी के पुस्त-
कालयों के अध्यक्ष

प्रत्येक मामले में २५) तक पर
वर्ष में कुल २५०) से अधिक
नहीं।

नोट—संख्या ४ व ५ के मदों के सम्बन्ध में शक्तियां जनरल फाइनैशियल तथा एकाउन्ट्स नियमों के परिशिष्ट ४ में वित्तीय शक्तियों के प्रदान करने के मद २७-११ के नीचे दी गई शर्तों के आधार पर तथा जनरल फाइनैशियल एवं अकाउन्ट्स नियम के अवीन, उपभोग में लाई जायेगी।

(२) सभी राजकीय सम्पत्ति के स्टोर के नुकसान हो जाने के मामलों में उनको समाप्त करने वाले अधिकारी को उसके नुकसान होजाने की परिस्थितियों की जांच करनी चाहिये तथा यदि यह पाया जावे कि यह नुकसान छल लापरवाही से हुआ है तो उसे—

(क) यदि वह राज्य कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए या यदि वह स्वयं सक्षम अधिकारी है तो उसे उचित कार्यवाही करनी चाहिये। तथा,

(ख) यदि वह कोई अन्य पुरुष है तो ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे कि उसका मूल्य वसूल हो सके, या जैसी भी परिस्थिति हो, अन्य कार्यवाही की जावे।

आवश्यक कार्यवाही करने के बाद सक्षम अधिकारी उसे दी गई शक्तियों की सीमा तक उस नुकसान को समाप्त कर सकता है। महालेखापाल राजस्थान, के पास जनरल फाइनैशियल एवं अकाउन्ट्स नियमों के २० वें नियम के अधीन भेजी जाने वाली उन वस्तुओं को समाप्त करने की स्वीकृति एवं एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिये जिसमें वस्तुओं खोने की परिस्थितियों का एवं उसके नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्णन होना चाहिये।

विषय—छात्रों से शुल्क की वसूली

यह अनुभव किया गया है कि छात्रों की निधि के बारे में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न होती है और यह तब उत्पन्न होती है जब कि एक छात्र सत्र के बीच में एक संस्था से दूसरी संस्था में अपना स्थानान्तरण करवाता है। इस ढंग में नियमितता लाने के लिये छात्र निधि वसूल करने एवं लौटाने के विषय में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं—

१. पुस्तकालय शुल्क, अध्ययन कक्ष शुल्क, पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क, मनोरंजन शुल्क आदि जो वार्षिक रूप में वसूल किये जाने वाले शुल्क हैं, सत्र के प्रारम्भ में ही वसूल किये जाने चाहिये।

२. व्यायाम शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, वाणिज्य, टाइप शुल्क, हस्तकला शुल्क आदि जो मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में वसूल की जाती है, उन्हें मासिक रूप में वसूल किया जाना चाहिये न कि एकत्रित धनराशि के रूप में—

३. परीक्षा शुल्क, परीक्षा होने के पहले के माह में वसूल किया जाना चाहिये। यह शुल्क प्रत्येक छात्र से वसूल किया जाना चाहिए, चाहे वह उस परीक्षा में बैठे या न बैठे।

४. जब कोई छात्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र चाहता है तो उस प्रमाण पत्र के पीछे की ओर जिस तारीख तक छात्र द्वारा शुल्क जमा कराया गया है उसका प्रमाणपत्र देना चाहिये। वह संस्था जिसमें छात्र स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश पाता है, इस प्रमाणपत्र पर अमल करेगी तथा मासिक व त्रैमासिक शुल्क उस तिथि से ही आगे का वसूल करेगी जिस तिथि तक का शुल्क उसने पहले उस संस्था में जमा कराया था जिसको उसने अभी छोड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छात्र को इस कारण में उस समय का शुल्क अपनी नई संस्था में दुबारा न देना पड़े जिसको कि वह अपनी

भूतपूर्व संस्था में पहिले ही दे चुका है।

ये नियम राजकीय संस्थाओं में ही लागू होंगे और जब एक छात्र किसी राजकीय संस्था से सहायता प्राप्त संस्था अथवा सहायता प्राप्त संस्था से किसी राजकीय संस्था में अपना स्थानान्तरण करता है तो उसे नियमों के अनुसार नई संस्था को पूरे वर्ष का शुल्क जमा कराना पड़ेगा तथा उस समय की कोई भी निधि उसे नहीं लौटाई जायेगी जिस समय तक कि वह उस संस्था में अपने स्थानान्तरण के कारण उपस्थित नहीं रहा।

(परिपत्र संख्या ५ एन. ई. डी. बी.-२/१४/८८/७/६० दिनांक १६-५-६०)

विषय—खेलकूद के लिए छात्रवृत्ति

राज्यपाल द्वारा राजस्थान में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के नियमित छात्रों को खेलकूद में निपुणता प्राप्त करने के लिए 'मेरिट स्कालरशिप' संलग्न नियमों के आधार पर देने का अनुमोदन कर दिया गया है:—

यह योजना मन् १९५६-६० से शिक्षण सत्र प्रारम्भ होते ही प्रभावशील होगी तथा क्रिया-न्वित की जावेगी तथा सम्मिलित रूप से राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल, व संचालक शिक्षा विभाग एवं अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा नियन्त्रित की जायेगी।

इस योजना के लिए "राजस्थान खेलकूद परम्पद्" को उचित धनराशि अनुदान रूप में दी जावेगी।

यह व्यय "३७—शिक्षा ई—सामान्य छात्रवृत्ति भारत में अध्ययनार्थ सहायता (योजना व्यय) मद से किया जायेगा।

(आदेश संख्या एफ. १५ (८०) शिक्षा सी/५६/दिनांक १०-५-६०)

खेलकूद में निपुणता प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति के नियम

जबकि राजस्थान में खेलों में रुचि उत्पन्न करना एवं स्कूल एवं कालेज के नियमित छात्रों द्वारा इसमें निपुणता प्राप्त करना अति जरूरी हो गया है, तो सरकार इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति स्वीकार करने के लिए निम्न नियम निर्धारित करती है—

१. इन नियमों को "खेलकूद निपुणता छात्रवृत्ति" नियम कहा जायेगा।
२. ये नियम राजस्थान की सभी मान्यता प्राप्त शालाओं में लागू होंगे।
३. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के उद्देश्य के लिए खेलों के विभिन्न रूपों का वर्णन इसके भाग संलग्न अनुसूची 'क' में दिया हुआ है।
४. निम्न द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं की प्रगति के आधार पर उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

(क) राजस्थान विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रतियोगिताएं।

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगितायें।

५. उपरोक्त प्रतियोगिताओं में वरिष्ठता के क्रम से, जो व्यक्ति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, वह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये योग्य समझा जायेगा।

६. बहुत सी किस्मों के खेलों के लिए छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग छात्रवृत्ति दी जावेगी ।

७. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति कमः (३०), (२५) और (२०) मासिक दर से दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि यदि किसी खेल में दो व्यक्ति बराबर आये तो छात्रवृत्ति की धन राशि उन दोनों में बराबर नहीं बांटी जायेगी बल्कि दोनों ही पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

८. यह छात्रवृत्ति खिलाड़ियों की अतिरिक्त खुराक देने की इच्छा में प्रदान की जानी है जिससे कि वे अपने स्वास्थ्य को बनाये रखें एवं खेल में निपुणता प्राप्त करते रहें । इसका तात्पर्य यह है कि यह धनराशि प्राप्तकर्ता द्वारा अन्य कार्यों में खर्च नहीं की जानी चाहिये । संस्थाओं के अध्यक्ष छात्रवृत्ति के पूर्ण उपयोग के विषय में ध्यान रखेंगे । केवल बीमारी के अतिरिक्त यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य या कार्यक्षमता खराब होती हुई पाई गई तो उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी जा सकेगी ।

९. उपरोक्त नियम ५ के अनुसार योग्य होने पर एक प्रतियोगी को केवल एक ही छात्रवृत्ति मिलेगी । इस बात पर कि एक छात्र एक से अधिक खेलों में अच्छी पांजीशन प्राप्त करता है, तो कोई अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जावेगी ।

१०. इस छात्रवृत्ति की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई माह से १० माह के लिए होगी, जो इस शर्त पर होगी कि यदि सम्बन्धित प्रतियोगी का नाम उतने समय तक उपस्थित रजिस्टर में रहे तथा अपने शिक्षा स्तर को उपयुक्त बनाये रखे और जो किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो या लगातार दो सत्रों तक किसी 'गृह परीक्षा' में बैठने से नहीं रोका गया हो ।

छात्रवृत्ति विद्यालय या महा विद्यालय छोड़ने तथा असफल होने या गृहपरीक्षाओं के परिणाम स्वरूप एक कक्षा में रोके जाने पर देय नहीं होगी । एक संस्था में दूसरी संस्था में स्थानान्तरण हो जाने पर भी छात्रवृत्ति उसे मिलती रहेगी बशर्ते कि वह नियम ८ में दी गई शर्तों को पूरा करता है ।

११. यह छात्रवृत्ति 'राजस्थान खेल कूद परिषद' द्वारा संचालक शिक्षा विभाग या अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग की सलाह करके स्वीकृत की जायेगी एवं दी जायेगी । इन छात्रवृत्तियों को स्वीकार करते समय कांसिल द्वारा प्रोत्साहन एवं सहायता के रूप में दी गई किसी सहायता को भी ध्यान में रखा जायेगा । छात्रवृत्ति प्रदान करने के सिद्धांत को इस दृष्टि से अपनाना चाहिए कि खेलों को प्रगति प्रदान करने के लिए दी जाने वाली सहायता का विस्तार होना चाहिए तथा वह केवल कुछ चुने गये व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए ।

१२. अनुशासन भंग करने पर, दुर्व्यवहार करने पर, अध्ययन से उन्मुख होने पर या प्राप्त की गई धन राशि का दुरुपयोग करने पर किसी छात्र की छात्रवृत्ति से स्वीकार करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा रोकी जा सकती है, निलम्बित की जा सकती है या रद्द की जा सकती है । उसी सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार है कि वह इस तरह में रोकी गई निलम्बित की गई व रद्द की गई छात्रवृत्ति को पूर्ण-रूपेण या आंशिक रूपेण फिर से स्वीकृत कर सकता है यदि भद्र व्यवहार करने, अध्ययन की ओर पूर्ण ध्यान देने या स्वास्थ्य बनाये रखने तथा शारीरिक पुष्टता बनाये रखने का आश्वासन दें ।

विषय—जिला स्तर पर खरीद करने की पद्धति

जिला स्तर पर खरीद करने के सम्बन्ध में राजस्थान वित्त संध के एक दल ने कुछ आपत्तियां प्रकट की थी। उनकी मांगों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद राजस्थान सरकार एतद्द्वारा यह आदेश जारी करती है—

१. यदि अपनी अपनी श्रेणियों के उप संचालकों के पास कुछ वित्तकों को पेशगी पहिले से जमा हो तथा संबंधित फर्म की ओर निर्विवाद रूप से यदि कोई धनराशि वकाया न हो तथा वह वित्तक द्वारा जमा कराई जान वाली नहीं पेशगी के बतौर मानी जा सकती है। यदि टेन्डर खुलने एवं स्वीकृति होने के बाद टेन्डरकर्ता द्वारा समझौता आवंध पत्र भरा जाता है तथा सुरक्षित धनराशि जमा कराई जाती है तो पेशगी के रूप में जमा कराई जाने वाली धनराशि का उद्देश्य पूरा हो जाता है तथा जिला शिक्षाधिकारी के यह बतलाने पर कि उस फर्म की जमानत हो चुकी है, तो उस फर्म को पेशगी रकम वापिस लौटा दी जावेगी यदि किसी फर्म का टेन्डर सभी जिला शिक्षण अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो उसके द्वारा पेशगी के रूप में जमा कराई गई रकम को शीघ्र लौटा देना चाहिए।

२. श्रेणीवार मान्य दरों की सूची सभी टेन्डरदाताओं को पूर्णरूपेण वितरित की जानी चाहिये चाहे उनमें से (श्रेणीवार) कोई दर स्वीकृत की गई है या नहीं।

३. सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों के साथ टेन्डर नोटिस की मिर्क एक प्रतिलिपि तथा उसको पेश करने के समय में वृद्धि की प्रतिलिपि यदि कोई हो तो, प्रत्येक प्रेषक प्रमाणपत्र के साथ भेजनी चाहिए।

४. टेन्डर देने वाले व्यक्तियों को उनके टेन्डर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि टेन्डर खोलने से कम से कम १० दिन पूर्व टेन्डर फार्म एवं वस्तुओं की सूची भेज देनी चाहिये।

५. अनुचित लम्बे समय के बाद वितरित की गई वस्तुओं के रद्द किये जाने; रकम यद्यपि कोषागार से निकाल ली गई हो परन्तु वित्तकों को नहीं दिये जाने, स्वीकृत नमूनों को न लौटाने सम्बन्धी शिकायतों के वित्तकों की ओर से प्राप्त होने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्रय कर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी दिलाई वस्तुओं पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह भी सुनने में आया है कि नमूने बहुत खराब हालत में रखे जाते हैं।

६. यह भी विदित हुआ है कि कुछ निरीक्षकों ने टेन्डर साहित्य एवं चीजों की सूची टेन्डर भरने वाले व्यक्तियों के पास नहीं भेजी है जबकि टेन्डर आमन्त्रित करने की अन्तिम तिथि में केवल २ या ३ दिन ही बाकी रह जाते हैं। ऐसे मामलों में टेन्डर प्राप्त करने की अवधि को १५ रोज तक या इसी प्रकार का समय बढ़ाया जा सकता है, यदि सम्बन्धित निरीक्षकालयों को दूर प्रस्तुत करने के लिए टेन्डर आवेदकों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, दूसरे बन्दों में यदि उसे एक सप्ताह का समय नहीं दिया गया है।

७. यह भी देखा गया है कि जिला शिक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त क्रय कर्ता अधिकारी (purchasing officer) भी वित्तकों से जमानत प्राप्त करते हैं, यद्यपि उनके द्वारा दिये गए आदेश बिल्कुल कम रकम के हैं, जैसे केवल १०० तक ही। ऐसे मामलों में जिला शिक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जमानत को ही पर्याप्त समझना चाहिए तथा इन छोटी छोटी धनराशि वाले

आदेशों के लिए वितरकों से अलग अलग जमानत प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

८. राजस्थान वितरक मंच द्वारा यह भी बताया गया है कि कभी कभी बहुत कम धनराशि की वस्तुओं के आदेश जैसे २) से ५) तक के भी दिए जाते हैं जबकि ऐसी वस्तुयें स्थानीय दुकानदारों से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यह स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं कि आवृत्त अनुदान को जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण वित्तीय वर्ष की दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस से वह दी गई है, काम में लाना चाहिए। ऐसे मामलों से २५) से कम के आदेश स्वीकृत वितरकों को नहीं भेजने चाहिए। ऐसे मामलों में २५) से कम के आदेश स्वीकृत वितरकों को नहीं भेजने चाहिये, यदि वे स्थानीय नहीं हैं तो वे नियमानुसार छोटे कोटेशन प्राप्त कर स्थानीय रूप से खरीद लेने चाहिए।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./एकाउन्ट/बी. १/१८००१/५५/६०-६१ दिनांक ४-५-६०]

विषय—नये विषय खोलने एवं छात्रों का प्रवेश आदि

पाठशाला में नये विषयों को खोलने एवं प्रवेश आदि को नियमित करने के लिये संस्थाओं के प्रधानों एवं नियन्त्रण अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु निम्न लिखित निर्देश दिये जाते हैं—

१. वर्ष के बीच में इस कार्यालय को कुछ ऐसे मामले दृष्टिगोचर हुये हैं जिनमें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा संस्थाओं के प्रधानों को एक ऐसे विषय को खोलने की स्वीकृति दी है जिसे बोर्ड द्वारा बोर्ड मान्यता नहीं दी गई है। कुछ मामलों में अचानक ही इससे इस कार्यालय को जानकारी कराई गई है जब कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने आगे वाले वर्ष की परीक्षा में बैठने के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

नये विषय का खोलना एक नीति का विषय है तथा इस कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई भी नियन्त्रण अधिकारी या संस्था के प्रधान से निम्न स्तर का व्यक्ति नये विषय के खोलने की स्वीकृति देने में समर्थ नहीं है। कुछ ऐसे मामले थे, जिनमें बिना विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के ही नये विषय खोलने का पत्र व्यवहार मण्डल के साथ चल रहा था। एक बार सबको बतलाया गया है कि चाहे उस विषय की मान्यता मण्डल द्वारा दी गई हो तथा नई स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता प्रतीत न हो तब भी एक नये विषय को खोलने के लिये संचालक के कार्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी ही पड़ेगी।

इस सिद्धान्त के आगे भी ऐसे मामलों में उप संचालक की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जहाँ एक विषय कई सालों से पढ़ाया जा रहा है, परन्तु किसी एक या अन्य कारण वश जो एक या एक से अधिक वर्ष तक नहीं पढ़ाया जा सका क्योंकि ऐसे समय व्यवधान के मामलों में कुछ समय बीत जाने के बाद उस विषय को फिर से खोलना, चाहे मण्डल द्वारा उसकी मान्यता वापिस न ली गई हो, उसे उस विषय को नये रूप से खोला हुआ ही समझा जावेगा।

मंजूरी हो जाने की उम्मीद के आधार पर ही नियन्त्रण अधिकारी अथवा संस्था के प्रधान द्वारा कोई नया विषय चालू नहीं किया जावेगा। यदि कर दिया तो यह चालू करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी पर हो होगा।

२. एक स्कूल में एञ्जिल विषयों में नया विषय चलाने के लिए छात्रों की निर्धारित संख्या के बारे में नियम बना दिये गये हैं। ऐसे मामलों में अधिक हैं जिनमें ऐसी रोक का ध्यान न रखा गया हो तथा उस निर्धारित प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए एक नया विषय खोल दिया गया

हो। निर्धारित कम से कम छात्रों के न होने पर कोई ऐच्छिक विषय नहीं खोला जा सकेगा। यह निर्धारित न्यूनतम संख्या केवल ६ वीं कक्षा के लिए ही लागू है न कि १० वीं एवं ११वीं के लिए। एक विषय का चयन करते समय संस्था-प्रधानों को देखना चाहिए कि हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास जैसे ऐच्छिक विषयों को महत्व दिया जावे, जिनको कि आवश्यक विषयों के उच्च अध्यापक पढ़ाने के योग्य हो।

३. कुछ ऐसे मामले भी हैं जबकि प्रधानाध्यापक को यह भालूम होवे कि वह विषय जिसको पढ़ाने के लिए वह योग्य हो, यदि वह स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, पर वह श्रम खोल दिया गया है, या नियन्त्रण अधिकारी से उस विषय को खोलने की निवारण प्राप्त करनी गई है। नीति का विषय होने के फलस्वरूप विभाग किसी भी ऐसे नये विषय को मानने की स्वीकृति नहीं देगा, जहां कि प्रधानाध्यापक के अलावा उम शाला के अध्यापकों की सूची में कोई भी अन्य अध्यापक उस विषय को पढ़ाने के योग्य नहीं हो।

४. गत वर्ष जो स्कूल नये खोले गये थे या उच्च माध्यमिक शाला में परिवर्तित किये गये थे, उनमें कुछ ऐच्छिक विषयों के खोलने के लिये निर्धारित किये गये थे, तथा उन ऐच्छिक विषयों के खोलने की मंडल द्वारा मान्यता भी प्राप्त करनी गई थी। परन्तु कुछ ऐसे कारणों वश जो कि प्रधानाध्यापकों को भली भांति विदित है, उनमें से कुछ विषय ६ वीं कक्षा में खोले नहीं जा सके। उन संस्थाओं के प्रधानों को श्रम लिखा गया है कि इससे आगे वो उन्हीं ऐच्छिक विषयों को चला सकेंगे जो गत वर्ष ६ वीं कक्षा में वास्तव में चलाये गये थे तथा उनके अतिरिक्त अन्य ऐच्छिक विषयों को नया विषय समझना चाहिये तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने पर ही उन्हें चलाया जाना चाहिये, चाहे उन्होंने उन ऐच्छिक विषयों में मंडल की स्वीकृति प्राप्त न की हो।

५. कुछ मामलों में संस्थाओं के प्रधानों ने इस कार्यालय के आदेशों का अर्थ अपने विचारों के अनुकूल लगाया तथा विभाग के लिये समस्याएँ उत्पन्न करदीं, उदाहरणार्थ विज्ञान का पाठ्यक्रम कुछ उच्च माध्यमिक शालाओं में ही खोले जाने थे तथा उनमें भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र एवं गणित के अध्यापक नियुक्त किये गये। परन्तु प्रधानों ने कुछ मामलों में इस बात को बिना जाने वनस्पति विज्ञान (Biology) भी चालू करदी कि वनस्पति विज्ञान को पढ़ाने वाला कोई भी अध्यापक संस्था को प्रदान नहीं किया गया है, एवं इसलिये विभाग की इच्छा केवल इन्जीनरिंग ग्रुप को ही खोलने की है। ऐसे सभी मामलों में जहां चाहे व्याख्या भिन्न हो सकती है परन्तु संस्थाओं के प्रधानों को केवल सीमित क्षेत्र तक ही उसका अर्थ निकालना चाहिये तथा न कि स्वेच्छानुसार तथा इस विषय में अग्रिम स्पष्टीकरण विभाग से मांगना चाहिए। उनके पथ प्रदर्शनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञान पाठ्यक्रम चलाने से तात्पर्य केवल भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित मात्र से ही है तथा इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई अतिरिक्त विषय चालू करना हो तो उसे चालू करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए।

६. ऐसे विषयों में जहां प्रयोगों के लिए यन्त्रादि किसी एक सीमित छात्रों की संख्या तक प्रदान किये गये हैं, वहां छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रखना चाहिए। संस्थाप्रधान को ऐसे मामलों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रखना चाहिए लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि प्रवेश किसी आधार पर किया जाना चाहिये न कि स्वयं के निर्णय के आधार पर जिससे कि शिकायत का मौका न मिले। विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, तकनीकी, संगीत आदि का पाठ्यक्रम इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

७. किसी विशिष्ट वर्ष में नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की हालत में उन्हें इस कार्यालय द्वारा कुछ ऐच्छिक विषय खोलने का अधिकार दिया है। चूंकि यह कार्यालय किसी विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं में परिचित नहीं है, इसलिये यह स्कूल निरीक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने अधीन संस्था-प्रधान में सलाह लेकर तथा नए विषय खोलने के सम्बन्ध में जारी किए गए नियमों के अधीन ऐच्छिक विषय निर्धारित करे। ऐच्छिक विषय खोलते समय वह अपने पड़ोस की संस्थाओं में चल रहे ऐच्छिक विषयों को भी ध्यान में रखेगा। इस प्रकार खोले गये विषयों की सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी तथा केवल वे ही विषय जो पूर्ण रूप से इस संस्था को स्वीकृत किए गए हैं, उनका वर्णन एक प्रार्थनापत्र में शामिल करना चाहिये जिसको कि मंडल के पास मान्यता प्राप्त करने के लिए भेजा जा सके।।

ऐच्छिक विषयों एवं क्राप्ट के विषयों को चोखू करने के नियम इसके साथ संलग्न है।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी. /एका/(क)/३८५१/६५ (५६) दिनांक ८/५/५६]

विषय—नया विषय या पाठ्यक्रम चालू करना

विषय या पाठ्यक्रम चालू करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उन पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू रहेंगे—

सामान्य—(१) उस विषय को कम से कम १० छात्र लेना स्वीकार करते हो।

(२) जबकि उच्च माध्यमिक शालाओं में मानव शास्त्र (Humanities) पाठ्यक्रम में प्रत्येक छात्र को तीन ऐच्छिक विषय लेने पड़ते हैं तो उस स्कूल में यदि २० छात्र हो जो कि एक उच्च माध्यमिक शाला खोलने के लिए आवश्यक है तो केवल वहां पर तीन ही ऐच्छिक विषय खोले जायेंगे। यदि कुल छात्रों की प्रविष्ट संख्या ४० या इससे अधिक हो तो उस स्कूल में ४ ऐच्छिक विषय चल सकते हैं यदि इस पाठ्यक्रम में कुल छात्रों की संख्या ६० एवं १०० से अधिक हो जाती है तो क्रमशः वहां पर ५ व ६ ऐच्छिक विषय खोले जा सकते हैं।

३. संस्कृत विषय कम से कम ८ छात्रों के होने पर चालू किया जा सकता है तथा इंग्लिश ५ छात्रों पर चालू की जा सकती है।

४. विज्ञान, कृषि इत्यादि के लिये अतिरिक्त पाठ्यक्रम चालू किया जा सकता है यदि उस पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या कम से कम २५ हो। ऐसे विशेष समूह के मामले में दी हुई शर्तों के आधार पर चालू हो सकेंगे।

फाईन आर्ट्स:—इस पाठ्यक्रम के लिये शर्त यह है कि उपरोक्त नियम ४ के समान इसमें भी छात्रों की संख्या कम से कम २५ हो। इस पाठ्यक्रम के अधीन ऐच्छिक विषय के लिए कम से कम प्रत्येक ऐसे विषय को लेने वाले छात्रों की संख्या २० होनी चाहिये। लड़कियों के होने की स्थिति में कम से कम १० होने पर भी विषय चालू किया जा सकता है। फाईन आर्ट में अन्य समूह चालू किये जा सकते हैं यदि उसमें छात्रों की संख्या ३० से अधिक पहुँच जाय—तथा कम से कम १५ छात्र उस समूह को लेना स्वीकार करते हों। फिर भी अन्य समूहों के अधीन प्रत्येक अतिरिक्त विषय कम से कम १० छात्रों की संख्या के आधार पर होगा।

वाणिज्य:—उपरोक्त नियम ४ के अनुसार। इस पाठ्यक्रम के अधीन ऐच्छिक विषय चालू करने के लिए किसी एक ऐच्छिक विषय को लेने वाले छात्रों की संख्या कम से कम २० होनी चाहिये।

विज्ञानः—उपरोक्त नियम ४ के अनुसार दृष्टिजन्य ग्राफ के लिये कम से कम २० छात्रों को गणित ऐच्छिक विषय के रूप में लेना चाहिये। जीव विज्ञान (Biology) उच्च स्तर पर खोलना चाहिये जहाँ पर विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या कम से कम ४० हो, जिसमें कि Biology लेने वाले छात्रों की संख्या, २० छात्रों के गणित लेने के साथ, कम से कम २० हो सके।

गृह विज्ञानः—जैसा कि फार्मन ग्राफ़ के सम्बन्ध में है।

आवश्यक विषयों के अधीन अतिरिक्त क्राफ्ट खोलने के नियम

१. ऐसे स्कूल जहाँ २० छात्र हों, जो कि कम से कम होने चाहिये, वहाँ केवल एक ही क्राफ्ट खोलना चाहिये। किन्तु यदि छात्रों की संख्या २० से अधिक है तो, वहाँ प्रत्येक कक्षा के २ समूह होंगे। इससे विद्यालय के क्राफ्ट अध्यापक के काम कार्य बहुत बढ़ जायेगा। वह कार्य समय में अपने खाली अन्तर (Period) रखने के बदले में स्कूल के खुलने से पूर्व या बन्द होने के बाद के समय में ३ समूह चला सकता है।

२. जिस विद्यालय में कक्षा २ गण्डों में चलती हो, तथा प्रत्येक कक्षा गण्ड में कम से कम ३० छात्र हों, वहाँ पर हमें केवल एक क्राफ्ट रखना चाहिए। ऐसे मामलों में केवल एक ही क्राफ्ट-अध्यापक कार्य करेगा। परन्तु यदि प्रत्येक गण्ड में छात्रों की संख्या ३५ या ३५ से अधिक हो तो उसे समूह बनाने पड़ेंगे तथा वहाँ एक ही अध्यापक पर्याप्त होगा, यदि ६ वीं से ११ वीं तक के छात्रों के समूहों की संख्या ८ से अधिक न रहे। यदि यह संख्या ८ है, तो अध्यापक आठो अन्तर (Periods) में पढ़ा सकता है। उस हानत में उसका कोई भी खाली अन्तर नहीं रहेगा।

३. यदि समूहों की संख्या आठ से अधिक होवे, तो हमें वहाँ २ क्राफ्ट अध्यापक नियुक्त करने पड़ेंगे तथा ऐसे सभी मामलों में जहाँ एक से अधिक क्राफ्ट अध्यापक लगाना है, हमें भिन्न भिन्न क्राफ्ट देना चाहिए चूंकि विद्यार्थी उसी अन्तर में प्रत्येक क्राफ्ट के लिये ग्रुप बनायेंगे तथा अपनी क्राफ्ट की कक्षाओं में जायेंगे।

नये ऐच्छिक विषय खोलने के लिये कम से कम १० छात्रों के होने का नियम है। 'स्कूल के लिए इच्छित उत्साह प्रदान करने के लिए केवल ८ छात्रों के होने पर ऐच्छिक विषय खोला जा सकता है।

उपरोक्त नियम १ में से १० छात्रों की संख्या का निर्धारण एवं उपरोक्त नियम ३ के अन्तर्गत दी गई सुविधा को प्रत्येक पाठ्यक्रम के अधीन ऐच्छिक विषय चालू करने पर डाली गई मर्यादाओं के साथ पढ़ना है। उदाहरणार्थ यदि मानवशास्त्र (Humanities) में छात्रों की संख्या ४० हो तो वहाँ मानवशास्त्र के अधीन केवल ३ ऐच्छिक विषय ही होंगे तथा प्रधानाध्यापक चौथा नया ऐच्छिक विषय नये १० लड़के और आजावें तो भी चालू नहीं कर सकता।

ग्रमुक विषय में बोर्ड की स्वीकृति है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपरोक्त नियमों के विपरीत तथा इस कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के लिये बिना, इस विषय को चालू कर दिया जावे।

[परिषद संख्या ई. डी. बी./पी. ई. आर/सी./३१/४१०४/सर./६० दिनांक १०-६-६०]

विषय—परीक्षा में बैठने की अनुमति

परीक्षा नियमों के खण्ड ४ (क) में कोई भी अध्यापक जिसे सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी जा चुकी है, उसे आगे लगातार २ वर्षों तक कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है। यह

खंड उनको भी वंचित रखता है जिन्होंने बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जबकि अध्यापकों को बी. एड. प्रशिक्षण के लिए राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए भेजा जाता है, तो यह निर्णय किया गया है कि इस नियम के लागू करने के लिए बी. एड. परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा नहीं समझा जावेगा।

इसी प्रकार वे जो एक बार सार्वजनिक परीक्षा में अनुनीर्ण हो गये हैं, उनको आगे २ साल तक सार्वजनिक परीक्षा में न बैठने के कारण एक बड़ी अपुविधा एवं कठिनाई में डाल दिया जाता है क्योंकि इसी समय में पुस्तकें व पाठ्यक्रम भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिये यह विज्ञापित किया जाता है कि इन असफल अध्यापकों को दूसरे वर्ष सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जावेगी किन्तु यदि वे दुबारा भी असफल हो गये तो उन्हें आगे २ वर्षों तक परीक्षा में बैठने की कोई स्वीकृति नहीं दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जावे कि अध्यापकों द्वारा हर प्रकार का प्रयत्न किया गया था।

(परिपत्र संख्या ६)

विषय—अनुसंधान कर्त्ता छात्रों (Research Scholars) को आर्थिक सहायता देने के नियम—

१. राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के अनुसंधानकर्त्ता छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

२. यह छात्रवृत्ति केवल राजस्थानी अनुसंधान कर्त्ता छात्रों को ही दी जावेगी और उन्हें को दी जायेगी जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अथवा अकादमी द्वारा विधिवत अधिकृत साहित्यिक शोध कार्य करेंगे।

३. अकादमी इन साहित्यिक शोध कार्यों के विद्वानों को भी विधिवत अधिकृत अनुसंधान छात्रवृत्ति देगी, जो कम से कम १० वर्षों से साहित्यिक शोध कार्य का काम अपने आप अपनी लगन व परिश्रम से करते आ रहे हों और भविष्य में भी जो अपनी शक्ति और श्रम पूर्वक करते रहना चाहते हों।

४. कम से कम तीन लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा विषय व व्यक्ति स्वीकृत किये जाने पर, विश्वविद्यालयों द्वारा वांछित शोध, योग्यता रहित अपितु अन्य प्रकार से प्रतिभावान योग्य लेखकों को निश्चित समय के लिये इस शर्त पर अनुसंधान छात्रवृत्ति दी जा सकेगी कि लिखित सामग्री का प्रकाशन अधिकार अकादमी को होगा।

५. यह छात्रवृत्ति (१००) प्रतिमाह के हिसाब से वर्ष में अधिक से अधिक (१२००) तक की होगी। इस सम्बन्ध में अधिकृत आवेदन पत्र अकादमी द्वारा ही प्रार्थी के पास भेजा जायेगा और प्रार्थी उस आवेदन पत्र को भर कर संचालक साहित्य अकादमी को प्रस्तुत करेगा।

६. (अ) छात्रवृत्ति प्राप्त साहित्यिक सामग्री को अनिवार्यतः अकादमी में प्रकाशनार्थ भेजना होगा और यदि अकादमी प्रकाशित करने से इन्कार करदे तो अन्यत्र प्रकाशित करवाया जा सकेगा।

(ब) छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र को अपना शोध कार्य अनिवार्यतः पूरा करना होगा और यदि ऐसा वह नहीं कर पाये तो प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि को उसे वापिस करना होगा। इस सम्बन्ध

मे अकादमी पहले से ही एक अनुबन्ध पत्र प्रार्थी से भ्रवायेगी ।

७. छात्रवृत्ति किन और कितने छात्रों को दी जावे, इसका निर्णय राजस्थान साहित्य अकादमी की साहित्य वेत्ता (वृत्ति) समिति करेगी किन्तु छात्रवृत्ति के लिए जितनी राशि का प्रावधान होगा उससे अधिक छात्रों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जावेगी ।

८ छात्रवृत्ति की राशि, संचालक, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रति माह छात्रों को भेजी जावेगी ।

९ यदि कोई अनुसंधान कर्त्ता छात्र अपना अनुसंधान कार्य अबूरा छोड़ देगा तो अकादमी को साहित्य वेत्ता (वृत्ति) समिति को यह अधिकार होगा कि वह उसकी अनुसंधान छात्रवृत्ति बन्द करने की और दी गई रकम की पुनः वसूल करने की शिफारिश करे । इस सम्बन्ध में अन्तिम स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जावेगी ।

विषय—निःशुल्क शिक्षा की सुविधा

राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि आदेश संख्या एफ-१ (१२७) शिक्षा/व/५६ दिनांक ६-७-५६ के अनुसरण में राजकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को प्रत्येक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क देने की सुविधाएं राजस्थान सरकार के उन कर्मचारियों के वचनों को, जो कि सेवाकाल में मे ही दैवगति को प्राप्त हो गये हैं, उसी प्रकार उतने समय तक मिलती रहेगी जब तक कि वह मृत कर्मचारी यदि जीवित रहने पर सेवा करता रहता तो पेंशन प्राप्ति के समय तक कार्य करता रहता ।

उपरोक्त सुविधा परिशिष्ट 'क' द्वारा निर्धारित पत्र में छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे दी जावेगी । यह प्रार्थना पत्र राजपत्रांकित व अराजपत्रांकित कर्मचारी होने पर उसे विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा जिनके कि अधीन वह मृत्यु के समय कार्य कर रहा था ।

यह वित्त विभाग पत्र संख्या यू० ओ० क्रमांक आई० डी०/४८०/एफ, डी./ (ई/६० दिनांक १६-३-६० द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर जारी किया जाता है ।

[एफ. १(१२७) शिक्षा/व/५६. Vol. II. दिनांक ४-२७ मई १९६०]

परिशिष्ट "क"

प्रमाण पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी श्री/श्रीमती का पुत्र/पुत्री हैं जो कि दिनांक को राजस्थान सरकार के विभाग/कार्यालय में पद पर सेवा करते हुए दैवगति को प्राप्त हो गया । उसका कुल वेतन मृत्यु के समय था । उसकी (मृत कर्मचारी) सेवा प्रभिलेखों के अनुसार जन्म—तिथि..... थी । यदि वह जीवित रहता तो वह सेवाकाल से दिनांक को निवृत्ति प्राप्त करता । राजकीय आशा संख्या एफ. १(१२७) शिक्षा/व/५६-Vol. II. दिनांक २४-५-६० की शर्तों के अनुसार यह विद्यार्थी राजकीय आदेश संख्या एफ-१(१२७) शिक्षा/व/५६ दिनांक ६-७-५६ के आधार पर सभी प्रकार के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की सुविधायें प्राप्त करने का अधिकारी है ।

विभागाध्यक्ष/कार्यालय

विषयः— निःशुल्क शिक्षा

इस विभाग के आदेश संख्या डी. १७३६२/एफ. २० (२) शिक्षा/व/५४ दिनांक २४-१-५७ को संशोधित करने हुये इसके आंशिक संशोधन में राज्यपाल यह आदेश देने पर महत्त्व हो गये हैं कि इस विभाग-आदेश संख्या एफ. १ (१२७) शिक्षा/व/५६ दिनांक ६-७-५६ द्वारा राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को सर्वा स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाये राज्य विभागों के नियमित स्थापना (Regular Establishment) पर नियुक्त किये गये अथवा ई राज्य कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी ।

यह वित्त विभाग के कार्यालय की संख्या आई./डी/६००/एफ. डी/ई. १/६१ दिनांक १४-२-६१ द्वारा दो गई अनुमति के आधार पर जारी किया जाता है ।

[एफ. १ (१२७) शिक्षा/व/५६/Vol I दिनांक २८-२-६१]

विषयः—उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष से पहिले वर्ष को मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष मानना

राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य में किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शाला में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष से पहले वर्ष में प्रमोशन परीक्षा पास कर लेने वाले को राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए दूसरी मैट्रिक कक्षाओं के बराबर समझा जावेगा जिसके लिये मैट्रिक कम से कम शिक्षात्मक योग्यता रखी गई है ।

[आज्ञा संख्या एफ ४ (३२) जी ए /६० दिनांक १६-१२-६०]

विषयः— नये विषय प्रारम्भ करना

एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या इस कार्यालय का परिपत्र संख्या ई. डी. वी / एफ / (ए) १३८५१/६५/(५६) दिनांक ८-५-१९५६ जो कि उच्चतर माध्यमिक शालाओं में नये विषय प्रारम्भ करने में सम्बन्धित है, उच्च विद्यालयों पर भी लागू होता है । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये नियम उन हाई स्कूलों में भी समान रूप से लागू होंगे जिनमें कि नये विषयों का प्रारम्भ इन नियमों के द्वारा ही किया जावेगा । दूसरा सन्देह यह उठाया गया है कि क्या ये नियम नये विषयों के प्रारम्भ करने के लिये या चल रहे विषयों पर लागू होंगे । इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह वांछनीय है कि कोई एक ऐसा विषय जो विद्यालयों में कई वर्षों से चला आ रहा है, उसे केवल एक वर्ष में आवश्यक कम से कम छात्रों के न होने के कारण ही बन्द नहीं कर देना चाहिए । इन नियमों द्वारा नियमन करने का आशय यह है कि छात्रों की कम संख्या के आधार पर कोई भी ऐसा विषय नहीं चलाना है जिससे कि छात्रों के ऊपर वह खर्चा अधिक पड़े । यह संख्या किसी एक विषय की सार्वजनिक मांग के अनुसार निर्धारित की गई है तथा यदि छात्रों की संख्या कम से कम आवश्यक छात्रों की संख्या से कम हो जाती है तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां उस विषय की मांग नहीं चाही जाती है । फिर भी प्रशासनात्मक तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि यदि कोई विषय निर्धारित छात्रों की संख्या से कम संख्या में ३ साल तक चले तो उसकी सार्वजनिक मांग को कम समझना चाहिए तथा उस हालत में उस विषय को हटा देना चाहिए ।

विषय को चालू रखने हेतु इन तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में उस विषय में छात्रों की

संख्या बढ़ाने के लिए यह लिखा जाता है कि इस प्रकार का प्रोत्साहन उम विषय को बनाए रखने से विद्यालय को कोई लाभप्रद नहीं होगा तथा निबन्धों की भावना को नहीं समझा जावेगा ।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./ए/१४०५५/४०/६०/६१ दिनांक ७-१-६१]

विषय:—खेलों के लिए अनावर्तक अनुदान

किसी संस्था को स्थायी स्वीकृति प्रदान करने के नियम बनाते समय माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने खेलों पर खर्च करने के लिए तथा खेल के मैदान को रखने के लिये (१५००) का प्रावधान रखा है । इस मद पर खर्च की जाने वाली धनराशि का अधिक भाग छात्रों की निधि से आता है परन्तु प्रधानाध्यापक इस मद को उनके वार्षिक विवरण में नहीं दिखाते हैं । वे केवल बजट में स्वीकृत अनुदान को ही विचार में लेते हैं तथा इस बात को भूल जाते हैं कि छात्र निधि से धन छात्रों को सुविधायें देने के लिये खर्च किया गया है । परिणाम यह होता है कि कागज पर यह शर्त अपूर्ण रहती है यद्यपि कार्य के लिये उचित धन राशि खर्च की जा चुकी है तथा बहुत-सा पत्र व्यवहार इस मामले में करना पड़ता है ।

सभी संस्थाओं के प्रधानों से छात्रों की निधि या अन्य प्रकार से खेल के मैदान को बनाए रखने के लिए अनावर्तक मद को उनके विवरण पत्र में शामिल करने के लिये निवेदन किया जाता है ।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./एका/(ए) १४०६१/३६/६० दिनांक २८-१२-६०]

विषय:—छात्रों को रेलवे कन्सेशन

रेलवे मंत्रालय (रेलवे मंडल) ने निर्णय किया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापक जो कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति किये गये हैं, परिशिष्ट के क्रम संख्या १६ से आई. आर. सी. ए. के नियम १८ तक एवं कोचिंग टैरिफ नं० १७ में दिये गये कन्सेशन प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि उनका वेतन या छात्रवृत्ति ३० प्रतिमाह से अधिक है । सभी भारतीय रेलों को प्रेषित रेलवे मंत्रालय के पत्र संख्या टी. सी. II/२०२१/६० दिनांक ४-१-६० की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है:—

“रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापक जो कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किये गये हैं परिशिष्ट के क्रम संख्या १६ से आई. आर. सी. ए. के नियम ११३ तक तथा कोचिंग टैरिफ नं० १७ में दिये गये सब कन्सेशन प्राप्त कर सकते हैं चाहे उनका वेतन या छात्रवृत्ति ३० रु० प्रतिमाह से अधिक हो ।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./जन/(बी) १४५३५/४/६० दिनांक ५-१-६१]

विषय:—विद्यालयों की स्तर वृद्धि के सिद्धान्त

माध्यमिक शाला (छात्रों के लिये) को उच्च माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का सिद्धान्त—

१. माध्यमिक शाला में छात्रों की संख्या कम से कम २०० होनी चाहिये जिसमें माध्यमिक कक्षाओं अर्थात् ६ठी कक्षा से ८वी तक में छात्रों की संख्या कम से कम ७४ होनी चाहिये ।

२. वहाँ २० मील के क्षेत्र के भीतर कम से कम सहारा देने वाले माध्यमिक विद्यालय होने चाहिये ।

३. २० मील के क्षेत्र के भीतर कोई उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिये ।
४. नवीं कक्षा में छात्रों की संख्या २५ होनी चाहिये किन्तु यदि वहाँ कोई ६ मील के क्षेत्र के अन्दर उच्च विद्यालय है तो छात्रों की संख्या कम से कम ४० होनी चाहिए ।
५. आवश्यक भवन प्रदान करने तथा एक साल के आवर्तक एवं अनावर्तक खर्च को सहन करने का उत्तरदायित्व जो करीब १५०००) का होगा का जनता पर होना चाहिये ।
६. तहसील कार्यालयों में जहाँ उच्च विद्यालय नहीं हो, उस स्थान को महत्व दिया जाना चाहिये ।
७. यह आवश्यक है कि सभी चीजें बराबर पाई जाने पर अधिक महत्व नगरो की अपेक्षा ग्रामों को दिया जाना चाहिये ।

छात्रों के प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक

शाला में परिवर्तन करने का सिद्धांत :

जिन प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों की कुल संख्या १०० हो तथा ५वीं कक्षा में कम से कम १५ छात्र हो उसे माध्यमिक शाला में परिवर्तन कर देना चाहिए किन्तु अत यह है कि—

१. १० मील के क्षेत्र के अन्दर कोई भी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिए ।

२. १० मील के क्षेत्र के अन्दर ५ सहायक प्राथमिक शालायें होनी चाहिये ।

३. छठी कक्षा में छात्रों की संख्या कम से कम १५ होनी चाहिये । यदि ६ मील के अन्तर्गत वहाँ कोई अन्य माध्यमिक शाला अथवा उच्च विद्यालय हो तो छात्रों की संख्या २० होनी चाहिये ।

४. जनता उचित मकान देने को तैयार हो ।

५. यदि तहसील कार्यालय पर कोई माध्यमिक विद्यालय न हो तो प्रथम उसे महत्व देना चाहिये ।

(छात्राओं के) प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शाला में उन्नत करने के लिये

१. प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नत करने के लिए कम से कम विद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या ७५ होनी चाहिए तथा ५वीं कक्षा में १० होनी चाहिये । छठी कक्षा की छात्राओं की अनुमानतः संख्या १५ होनी चाहिये ।

२. १० मील के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिये ।

३. विभाग द्वारा निर्धारित उचित भवन प्रदान करने के लिये यदि जनता तैयार हो ।

४. यदि यह तहसील मुख्यालय हो तथा वहाँ कोई अलग माध्यमिक शाला न हो, तो उसे महत्व दिया जाना चाहिये ।

माध्यमिक शालाओं के लिये न्यूनतम आवश्यक स्थान

८ कमरे—२४'×२०'

१ प्रधानाध्यापक कक्ष १२'×१२' या करीब इसी तरह का ।

१ प्याऊ

१ स्टोर कक्ष

विषय:—निःशुल्क शिक्षा

राज्याज्ञा संख्या ८ दिनांक ६-७-५६ के क्रम में, राज्यपाल ने निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जुलाई सन् १९५६ से राजकीय कर्मचारियों के भाई-भतीजों को शुल्क के भुगतान से मुक्त करने की रियायत देने का आदेश दिया है:—

(१) इस प्रकार की सुविधा के लिए आवेदन करने वाले राज्य कर्मचारी को साल में कम से कम एक बार यह हलफनामा करना पड़ेगा कि उसका भाई जिसके लिए यह सुविधा मांगी जा रही है, उस पर आर्थिक सहायता के लिए पूर्णतया निर्भर रहा है, तथा अब भी है।

(२) सभी आगामी वर्षों में वह यह घोषणा करेगा कि उसका अग्रज भ्राता उससे बड़े भ्राता के रूप में बराबर सहायता प्राप्त करता है।

यह परिपत्र इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ० १ (१२७७) शिक्षा/व/५६ दिनांक २४-५-५७ के अतिक्रमण में निकाला गया है।

प्रतिज्ञा पत्र

मैं..... पुत्र पद.....

हृदयकल्प के साथ एवं शपथ लेकर कहता हूँ कि श्री जो संस्था में कक्षा में पढ़ रहा है, वह अविवाहित है तथा मेरा लघु सहोदर है जो आर्थिक सहायता के लिए मुझ पर पूर्णतः निर्भर रहा है तथा रह रहा है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा वेतन रु० मासिक है।

प्रमाणित

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

.....

पद.....

अधिकारी का पद

विभाग.....

घोषणा

मैं पुत्र श्री पद एतद

द्वारा घोषणा करता हूँ कि श्री जो कि शास्त्रा/महा विद्यालय में कक्षा का विद्यार्थी है, मेरा लघु सहोदर है तथा वह आर्थिक सहायता के लिये मुझ पर पूर्णतया निर्भर है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा वेतन रु० प्रति माह है।

.....

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर

पद.....

विभाग.....

विषयः—संस्कृत परीक्षाओं को मान्यता

शिक्षा (तृ) विभाग के आदेश संख्या (१९१६) शिक्षा/व/५६ दिनांक १७-१२-५७ के आंशिक संशोधन में, राजस्थान सरकार सन् १९५४ में पुनः निर्धारित पाठ्यक्रम व अनुसार अंग्रेजी व अन्य विषयों के साथ प्रवेशिका, मध्यमा एवं उपाध्याय, शास्त्री एवं आचार्य परीक्षाओं को क्रमशः उच्च विद्यालय, इंटरमीजियेट, बी. ए. एवं एम. ए. के समकक्ष राजस्थान सरकार के अधीन निगुक्ति करने के उद्देश्य के लिए मान्यता प्रदान करती है।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./एका/व./१४३१७/स्पे./५६ दिनांक २२-९-५६]

विषयः—विशेष अवसरों पर प्राइवेट पार्टियों को स्कूल भवन का देना

इस कार्यालय के आदेश संख्या डी० १२५३/शिक्षा/५३ दिनांक २२-७-१९५३ के अतिरिक्त मण्डल में हिज हाईनेस राज्य प्रमुख यह आदेश देने के लिए सहमत हो गए हैं कि कोई भी विद्यालय किसी भी प्राइवेट पार्टी को उसे उपयोग में लाने के लिए केवल राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना नहीं दिया जावेगा। इस स्वीकृति पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपवाद स्वरूप मामलों में ही विचार किया जा सकेगाः—

- (१) यह स्वीकृति केवल अवकाश के दिनों में ही दी जा सकेगी जो ५ दिन से अधिक की न होगी।
- (२) निम्नलिखित शुल्क पार्टियों से राजकीय सम्पत्ति में नुकसान या नष्ट हुए भाग को ठीक कराने के अतिरिक्त वसूल किया जावेगा।

प्राथमिक शाला—	२० रु० प्रतिदिन
माध्यमिक शाला—	३० " "
उच्च विद्यालय—	५० " "
इन्टर मीजियेट महाविद्यालय—	७५ " "

[परिपत्र क्रमांक पी. एस./जी./५२४ दिनांक १५-९-१९५५]

विषय—सरकारी भवनों का उपयोग

यह देखा गया है कि कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने राजकीय भवनों में कुछ स्थान ले रखे हैं तथा उनका व्यक्तिगत उपयोग करते हैं। यह आदत केवल नियम-विरुद्ध ही नहीं अपितु बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है।

यह भी देखा गया है कि वे जल व बिजली को अनधिकृत तरीके से उपयोग करते हैं। इस लिये उप संचालक, शिक्षा, शाला उप निरीक्षक, निरीक्षकाओं, उपनिरीक्षकाओं इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट एवं इंटर कालेज के आचार्यों से निवेदन है कि वे यह देखें कि यह आदत एक दम रुक जावे। उनसे यह भी निवेदन है कि वे उन कर्मचारियों के बारे में पूर्ण सूचना भेजें जो राजकीय भवन, बिजली व पानी का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रहे हैं।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./जन./ए./जन. २९/५६/१४४ दिनांक १९-१२-५६]

विषय—परिपत्र फाइलों को ठीक तरह रखना

विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के समय यह देखा गया है कि बहुत अधिक मामलों में परिपत्र व तह से नहीं रखी जाती हैं। प्रत्येक कार्यालय परिपत्र फाइलें अपने ढंग से अलग अलग

तैयार करते हैं। कार्यालय के कार्य को आमानों पूर्वक एवं निपुणता से करने के लिए परिपत्र फाईलों को ठीक ढंग से रखने की महत्ता पर अधिक कहना ठीक नहीं। सामान्यतया जो परिपत्र प्राप्त किये जाते हैं उन्हें विभाग एवं सरकार के परिपत्रों तथा परिवर्तनशील प्रकृति के परिपत्रों जो इस प्रकार अलग अलग वर्गीकृत किये जा सकते हैं। (जो कि स्वभावतः अधिक या कम रूप में महत्वपूर्ण हैं।)

फिर परिपत्रों को विषयवार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरणार्थ जैसे अकाउन्ट्स, ऑडिट, क्रय, पुस्तकों का क्रय, राजस्थान सेवा नियम, ट्रेजरी मेन्चुअल, यात्रा भत्ता नियम, अतिरिक्त सेवान खोलना, नये विषय प्रारम्भ करना, स्कूल खोलना आदि। इसलिए यह उचित होगा यदि आदेशों की फाईलें विषयवार तैयार की जावे जो कि कार्यालय के उपयोग के लिए हमेशा प्राप्त हो सकेगी।

स्पष्टतया कहना यह है कि स्थाई आदेशों को (१) स्थापन (२) सामान्य एवं विविध (३) शिक्षात्मक (४) अकाउन्ट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। हैड क्लर्क के निरीक्षण में सामान्य कक्ष के रेकार्ड कीपर द्वारा इन चार श्रेणियों की एक अलग गार्ड फायल तैयार की जानी चाहिए जब कि पत्रों की विषयवार फाईल सम्बन्धित मैकगन इन्चार्ज द्वारा तैयार की जानी चाहिए। ऐसी प्रत्येक पत्रावली में एक सूची होनी चाहिए जिसमें विषयों का वर्णन किया जाना चाहिए तथा पृष्ठों पर सत्या डालना चाहिए। उस परिपत्र पत्रावली में परिपत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पत्र नहीं डालनी चाहिए। यदि किसी परिपत्र की प्राप्ति पर कोई कार्यवाही की जानी है तो उस कार्य के लिए एक अलग पत्रावली खोलना चाहिए तथा जैसे ही वह कार्य पूरा हो जाय, वह पत्रावली रेकार्ड में भेज देनी चाहिए। यह सामान्यतया देखा गया है कि सभी विविध पत्र व्यवहार जो परिपत्रों की प्राप्ति पर जाते हैं परिपत्र के पास सिला दिये जाते हैं तथा वह पत्रावली सामान्यतया साल के अन्त में रेकार्ड में भेज दी जाती है। इसमें कार्यालय के कार्य में बाधा आती है तथा जब कभी उस पूर्व परिपत्र का प्रसंग दिया जाता है तो उन्हें उस परिपत्र की गहरी खोज करनी पड़ती है तथा कभी कभी खूब खोज करने के फलस्वरूप भी वे उस परिपत्र को ढूँढ सकने में सफल नहीं हो पाते।

यह आशा की जाती है कि उपरोक्त विधि से परिपत्र पत्रावली तैयार करने में पूर्ण सारथानी वरती जावेगी जिससे कि कार्यालय का कार्य सुधर सके क्योंकि परिपत्र एवं स्थाई आदेश सभी स्तरों पर कार्य व्यापार में निपुणता लाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं।

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी./पी. ई. आर./सो/२३/३३०/५८ दिनांक २-८-५८]

विषय—राष्ट्रीय वचन प्रमाण पत्र के रूप में काशन मनी

एक जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार के पास यह प्रस्तावित किया गया है कि राजकीय मस्यामों में मध्यमन चालू करने वाले छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय वचन प्रमाण पत्रों के रूप में जमा कराई गई काशन मनी को स्वीकृत करने के लिए आदेश जारी करने की इच्छा पर विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि काशन मनी को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि कोई विद्यार्थी इसे राष्ट्रीय वचन प्रमाण पत्र के रूप में जमा कराना चाहता है।

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी./एका. (ए) १४१८१/४/५६ दिनांक १०-३-५६]

विषय—मुख्यालय (Head quarter) छोड़ने की अनुमति

ऐसा देखा गया है कि राजपशांकित छात्रों में बहुत से संस्था प्रधान विना स्वीकृति प्राप्त किये ही अपना हेड क्वार्टर छोड़ देते हैं। पुनः उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि शिक्षा संहिता के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को अपने तत्कालीन अधिपति से स्वीकृति लेकर ही स्थान छोड़ना होगा। फिर भी आपत्कालीन अवसर पर वह अपना हेडक्वार्टर छोड़ सकते हैं लेकिन उसी समय उन्हें अपने तत्कालीन अधिकारी को इस सम्बन्ध का प्रार्थना पत्र प्रेषित करना चाहिए जिसमें हेड क्वार्टर छोड़ने की स्वीकृति के लिए प्रार्थना की गई हो। कोई भी अधिकारी जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकारी हैं। उप शिक्षा संचालक, सहायक संचालक (महिला), निरीक्षक, उप निरीक्षक (कन्या पाठशालाएँ) से यह देखने की प्रार्थना की जाती है कि ये नियम कठोरता से पालन करें।

अध्यापकों, जो अपना हेड क्वार्टर छोड़ना चाहें, को अपनी मस्था के प्रधान से स्वीकृति लेनी चाहिए।

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी./पर/वी./२८१२/५६ दिनांक ३-१-५६]

विषय—नियन्त्रण अधिकारी

बहुदेशीय एवं उच्चतर माध्यमिक उच्च और प्रशिक्षणशालाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं तथा उप शाला निरीक्षक (कन्या पाठशाला) को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट ४ के मद ३२ के अनुसार उनके अधीन कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा बिलों पर हस्ताक्षर करने हेतु एतद् द्वारा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है।

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी./पर/ए./१३८१/५६ दिनांक १६-२-५६]

विषय—स्थानान्तरण

यह देखने में आया है कि स्थानान्तरण सम्पूर्ण वर्ष भर होते रहते हैं जिनका परिणाम यह होता है कि इन असामयिक स्थानान्तरणों से राजकीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में कांति अव्यवस्था हो जाती है। विषय पर सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार गया है। सरकार चाहती है कि जहां तक संभव हो सभी स्थानान्तरण मई एवं जून में किये जाने चाहिये। सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण दूसरे माह में भी स्थानान्तरण करने पड़े तो स्थानान्तरण के कारण लिखे जाने चाहिये।

चालू वर्ष के अन्त में मई एवं जून के माह के अतिरिक्त अन्य महिनो में किये गये स्थानान्तरणों का एक विवरण पत्र मध्य उनके स्थानान्तरण के कारणों के हर मामले में अभिलिखित किये हुये अपने से दूसरे उच्च अधिकारी के पास कृपया भेज दिया जावे।

[परिपत्र संख्या ई. डी. वी./पर/ए./१३८३/५६ दिनांक ५-५-५६]

विषय—अध्यापकों की तरफ़ी

शिक्षा विभाग में अप्रशिक्षित इन्टर अध्यापकों के स्थानों पर पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा में कार्य करने वाले अध्यापकों की तरफ़ी का नियमन करने के लिये सरकार निम्नांकित हिदायतें जारी करती है:—

(१) इस ग्रेड में रिक्त स्थानों के २५ प्रतिशत तक, विज्ञान, अंग्रेजी, हस्तकला आदि सिखाने के लिये सीधी भरती द्वारा भरे जायेंगे।

(२) इस ग्रेड में बाकी बचे हुये रिक्त स्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा में लगे हुये अध्यापकों में से तरक्की द्वारा भरे जावेंगे।

(३) अध्यापकों की इन दो श्रेणियों में उन्नति का अनुपात जिस वर्ष तरक्की दी जाती है—उस वर्ष की १ जनवरी को प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड में होने वाले अध्यापकों की संख्या के अनुसार होगा।

रिजर्व रूने हुए स्थानों को उन्नति देकर भरे जाने का काम चयन समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जावेगा। चयन समिति के निम्न सदस्य होंगे:—

(१) सम्बन्धित निरीक्षक, शिक्षा विभाग (अध्यक्ष)

(२) जिला परिषद का सचिव

(३) हैड क्वार्टर पर स्थित उच्च विद्यालय या उच्च माध्यमिक शाला का सबसे वरिष्ठ प्रधानाध्यापक।

तरक्की के लिये वे ही अध्यापक योग्य होंगे जिन्होंने लगातार कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की हो।

[परिपत्र संख्या एफ ४/मी/शिक्षा/ए./६० दिनांक २६-८-६१]

विषय—प्रवेश फार्म में भाषा लिखी जावे

विद्यालयों के प्रधानों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे प्रवेश प्रपत्र में १ खाना और बढ़ावें जिसमें कि वह भाषा लिखी जा सके जिसमें कि संरक्षक/पिता अपने पुत्र/रक्षित की शिक्षा उस माध्यम द्वारा दिलाना चाहता है। अतः समस्त प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रवेश प्रपत्र में यह एक नया खाना और जोड़ लेना चाहिये।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी. ए. सी. ए/बी-२/१४१५६/३१/(६१) दिनांक ५-१०-१९६१]

विषय—प्रगति पुस्तिका का मूल्य

यह देखा गया है कि कुछ संस्थाओं में प्रधानाध्यापक, छात्रों से प्रगति पुस्तिका का मूल्य ४ आना प्रति पुस्तिका से ले लेते हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है।

अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि ये प्रगति पुस्तिकायें परीक्षा निधि से छपवा ली जावे और भविष्य में छात्रों से प्रगति पुस्तिका की कोई कीमत नहीं ली जावे।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी. ए. सी. ए/बी. २/१४१५५/६/६१ दिनांक २-१२-६१]

विषय—देहाती क्षेत्र में अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर

जैसा आप को भली प्रकार विदित ही है कि दूनरो पंच वर्षीय योजना में अध्यापिकाओं के लिए देहाती में क्वार्टर बनाने का प्रावधान रखा गया था। वही योजना तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी चालू रखी गई है।

इस विषय में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अध्यापिकाओं, के क्वार्टर ऐसी अनुविधापूर्ण जगह पर बनाए गए हैं जबकि कभी कभी तो घरों से इतनी दूरी पर बनाए गये हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थान न होने के कारण कोई लेने को तैयार नहीं है। सभी क्षेत्रों से इस विषय में बार बार काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं इस वास्ते यह आवश्यक हो गया है कि इस समस्या पर काफी ध्यान दिया जावे जिससे इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके।

तदनुसार, सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि देहातों में अध्यापिकाओं के क्वार्टर बनाते समय निम्न बातों, ध्यान में रखी जावे।

(१) सुरक्षा—क्वार्टरों को गांवों के अन्दर बनाकर।

(२) पाठशाला के नजदीक—पाठशाला से जोड़ कर या पाठशाला के त्रिकुल नजदीक बनाकर।

(३) अन्य महिला कार्यकर्ताओं के त्रिकुल समीप क्वार्टर बनाकर जिससे उन्हें संगति व सुरक्षा मिल सके।

(४) निर्माण में कम खर्च।

यह भी सुझाया गया है कि एक ही गांव में जहां एक से अधिक महिला कार्यकर्ता जैसे अध्यापिका, ग्राम सेविका या दाई या महिलाओं के लिए हस्तकला की अध्यापिका हो, वहां सब के क्वार्टर पास पास बनाये जावें। जिससे कि एक दूसरे की सहायता भी कर सकें।

यदि कही ऊपर बताई गई समस्या न हो तथा अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर का स्थान भी संतोषजनक चुना गया हो, फिर भी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के शिक्षा अधिकारी को इस प्रकार के क्वार्टर के लिए जगह चुनने अथवा उनकी स्वीकृति के लिये अधिकृत किया जाता है।

अतः इस बात का संतोष प्राप्त करने के लिये कि क्वार्टर निर्माण करने से पूर्व सभी सावधानियां बरती गई हैं, जिला शिक्षा अधिकारियों को खण्ड पंचायत समितियों की मीटिंग में जाने पर इस प्रकार का कार्य कर लेना चाहिए। यदि वे चाहें, तो यह काम उप निरीक्षकों को भी सौंप सकते हैं किन्तु उप निरीक्षकों द्वारा यह काम अपने में निम्न श्रेणी के अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है।

अतः विकास अधिकारियों से निवेदन है कि अध्यापिकाओं के क्वार्टरों के लिये चुने हुए स्थान की स्वीकृति अपने जिले के शिक्षा अधिकारी से ले लेनी चाहिये।

[परिपत्र संख्या ई. डी. बी./पी. एल/(१) २१२६४/१३०/६० दिनांक २८-२-६२]

विषय—एक स्थान पर २ वर्ष से कम समय तक रहने वालों का स्थानान्तरण

आपका ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग (क) आदेश संख्या एफ. १ (२२) जी ए/ए/५८ दिनांक ३१-७-५८ की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को इससे आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता यदि वह अपने पूर्व स्थान पर कम से कम २ वर्ष तक न रहा हो। इस सिद्धान्त का केवल दिनांक ३१-७-५८ के आदेश में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किया जावेगा। बाद में आदेश की स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह स्थानान्तरण व्यक्ति की प्रार्थना पर उस समय तक

नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि राजकीय आदेश दिनांक ३१-७-५८ में दी गई शर्तों को पूरी नहीं करता है।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण करने के संबंध की स्थिति को इन दो आदेशों के संदर्भ में जांचा गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय तक नहीं किये जायेंगे जब तक कि उसने अपने पूर्व स्थान पर कम से कम तीन वर्ष पूरे नहीं कर लिये हैं। अन्य शर्तें एवं पद्धति वैसी ही रहेगी जैसी कि उपरोक्त वर्णित सामान्य प्रशासन विभाग आदेश में दी गई है। फिर भी विभाग की उन महिला कर्मचारियों के मामले में कुछ अपवाद स्वरूप स्थानान्तरण किये जा सकते हैं जो अपना आवेदन पत्र उस स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिये देती है जहां उनके पतिदेव रहते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों की प्रार्थना पर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

[परिपत्र ई. डी. बी. / पी. ई. आई. ए./११/१३०८/जन./स्पेशल/६० दिनांक २७-२-६०]

विषय—विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं का समितियों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति अवकाश स्वीकृति करने की पद्धति।

राज्यादेश संख्या एफ. १३ (१२) शिक्षा/१/५२ दिनांक २२-६-५४ एवं क्रमांक एफ १३ (१२) शिक्षा/११२ दिनांक १८-१०-५४ के अतिक्रमण में राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एवं राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के मुख्य कार्यालयों से अनुपस्थिति रहते के सभी मामले निम्न नियमों द्वारा शासित होंगे।

१. राजस्थान के भीतर यात्रा:—(क) राजस्थान विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, तकनीकी शिक्षा मंडल, निरीक्षण करने वाली, युवक समारोह में उपस्थित होने विवृत व्याख्यान देने के लिये प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित होने एवं शिक्षण सम्मेलन आयोजित करने आदि के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किसी भी मंडल के आधार पर अप्रस्तुत कार्य को संभालने के लिए मुख्यालयों से बाहर रहना सभी मामलों में ह्यूटी पर समझा जावेगा जो साल में अधिकतम १५ दिन तक के लिये लागू होगा तथा यदि वह राजस्थान विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट का सदस्य है तो २१ रोज तक के लिये लागू होगा।

किन्तु आगे फिर शर्त यह है कि टी. ए., व डी. ए. इस सम्बन्ध में सरकार से प्राप्त नहीं किया हो। अध्यापकों को, कालेज टीम के साथ तथा टूर्नामेंट्स अथवा क्रमशः युवक समारोहों में जाने पर, यदि विश्वविद्यालय नहीं दे, तो कालेज खर्चा देगा। जबकि वे छात्रों के साथ जावें तो जिस श्रेणी में विद्यार्थी यात्रा करें उसी श्रेणी में यात्रा का खर्चा पाने के वे अधिकारी हैं यद्यपि अन्य खर्च व दैनिक भत्ता उनको उसी हिसाब से दिया जावेगा जिसके कि वे पाने के अधिकारी हैं।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले किसी भी मंडल की ओर से पारिश्रमिक मिलने वाले शिक्षात्मक काम में जाने हेतु हेडक्वार्टर से सभी मामलों में अनुपस्थिति, आकस्मिक अवकाश या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जो संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार स्वीकृत है मानी जावेगी।

शर्त यह है कि इस सम्बन्ध में यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता सरकार से प्राप्त नहीं किया गया हो।

२. राजस्थान के बाहर की यात्रा:—(क) राजस्थान विश्व विद्यालय या उक्त बोर्ड शिक्षण संस्थाओं के बाहर बिना पारिश्रमिक वाले शिक्षण कार्यों पर जाने हेतु हेडक्वार्टर से अनुपस्थिति के सब मामले, राजस्थान के अन्दर जाने पर दिए जाने वाले १५ दिनों के अलावा एक सत्र में अधिक से अधिक ६ दिन बतौर ड्यूटी के सम्भले जायेंगे ।

शर्त यह है कि सरकार से इस संबंध में कोई यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता वसूल न किया गया हो ।

(ख) विश्व विद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थाओं के बाहर पारिश्रमिक मिलने वाले शिक्षात्मक कार्य के लिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के सभी मामलों में आकस्मिक अवकाश या नियमानुकूल उसे स्वीकृत किसी भी प्रकार का अवकाश लिया हुआ समझा जावेगा ।

किन्तु शर्त यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार से कोई यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता वसूल नहीं किया गया हो ।

नोट:—युवक समारोह, खेलकूद सभा, प्रतियोगिताओं एवं शिक्षात्मक यात्राओं के मामलों में छात्रों के साथ जाने वाले स्टाफ के सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए तथा सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना प्रतिभू (Sponsoring) अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स आचरण नियम

(ये आचरण नियम शिक्षा संहिता के अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, इसीलिए इनको भी यहां पर दिया जा रहा है)

१—तात्पर्य—(अ) राज्य कर्मचारी से अभिप्राय प्रत्येक उस व्यक्ति से है, जो कि संयुक्त राजस्थान सरकार की असैनिक सेवा में नियोजित है. चाहे वह कुछ समय के लिए विदेशी सेवा में ही क्यों न हो । इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि राज्य सेवा से कहीं अन्यत्र सेवा निवृत्ति हुआ हो और जो कि राजस्थान सेवा में पुनः नियोजित किया गया हो अथवा जो कि किसी अनुबंध के कारण सेवा में हो । किन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो कि भारत सरकार अथवा किसी अन्य प्रान्त या राज्य की सेवा में हों तथा राजस्थान राज्य में प्रति नियुक्ति (deputation) पर हो, ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित नियमों से प्रशासित होते रहेंगे ।

(ब) “पेंशनर” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि संयुक्त राजस्थान राज्य अथवा भूतपूर्व देशी रियासतों की सेवा में रहा हो और राजस्थान सरकार से जिसे विश्राम वृत्ति मिल रही हो ।

१ अ— प्रत्येक राज्य कर्मचारी प्रत्येक समय अपने पद के महत्व एवं अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी तथा पूर्ण ईमानदारी बनाये रखेगा ।

२—उपहार—(१) इस नियम में ही आगे दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, तथा संयुक्त राजस्थान राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी राज्य कर्मचारी—

(अ) अपने स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर, अथवा

(ब) अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्वीकृति नहीं देगा कि वह, कोई उपहार,

अनुतोष अथवा इनाम या ऐसे उपहार, अनुतोष या इनाम के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करे।

(२) सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत, कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्ति से पुष्पों, फलों अथवा इसी प्रकार के नगण्य मूल्य की मामूली वस्तुओं की कोई शुभकामनापूर्ण भेंट स्वीकार कर सकेगा किन्तु समस्त राज्य कर्मचारी ऐसे उपहारों को देने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे।

(३) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्तिगत अथवा धार्मिक उत्सव यथा विवाह, वर्षगांठ अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर अथवा सम्बन्ध में अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से एक ऐसे मूल्य की भेंट, जो कि सभी परिस्थितियों में उचित हो, स्वीकार कर सकता है अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।

२अ. दौरे के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण करना—
प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने दौरे के समय, अपने रुकने के स्थानों पर निवास एवं भोजन का प्रबन्ध स्वयं करना चाहिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने उच्चाधिकारियों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करना चाहिए।

३. (१) इस नियम में दिये गए प्रावधानों के अलावा कोई भी राज्य कर्मचारी, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना—

(अ) स्वयं अपने सम्मान में आयोजित कोई सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन, अथवा प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा और न ही कोई सार्वजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित ही होगा।

(ब) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवा से निवृत्ति अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये जाने वाले किसी सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन अथवा प्रशस्ति-पत्र में सम्मिलित नहीं होगा न ही तत्सम्बन्धित किसी सार्वजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित ही होगा।

(स) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या किसी अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवाओं के सम्मान में स्थापित किसी छात्रवृत्ति अथवा आयोजित किसी अन्य सार्वजनिक या दातव्य उद्देश्य, या किसी चित्र, प्रतिमा आदि जो कि ऐसे अन्य राज्य कर्मचारी या व्यक्ति को भेंट दिये जाने वाले हों, पर खर्च की जाने वाली किसी निधि को एकत्र करने में भाग नहीं लेगा।

(२) उप नियम (१) में कही हुई किसी भी बात से प्रभावित हुये बिना—

(अ) ५०) या उससे कम वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी से अपने कार्य के वास्तु कोई प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर सकता है।

(ब) कोई राज्य-कर्मचारी किसी सार्वजनिक सभा के अनुरोध पर किसी चित्र, मूर्ति आदि की तैयारी के लिये बैठ सकता है वशत कि वह चित्र आदि उसे भेंट करने के उद्देश्य से नहीं बनाये जा रहे हों।

(स) सरकार के किसी विशेष अथवा साधारण आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी राज्य-कर्मचारी अत्यन्त व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक ढंग के किसी विदाई समारोह में भाग ले सकता है जो कि उसके स्वयं के अथवा किसी अन्य कर्मचारी के अथवा हाल ही में जिसने सेवा छोड़ दी हो, ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, सेवा निवृत्ति अथवा एक स्थान से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करने के अवसर आयोजित किया गया हो।

(द) 'ध्वज दिवस' के मनाने की अवधि में भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये स्वयं की लगन से धन जमा करने में कोई भी राज्य कर्मचारी भाग ले सकता है।

४. समारोह में करनी (Trowel) इत्यादि का भेंट करना:—कोई भी राजकीय कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समारोह यथा कोई जिलान्यास अथवा सार्वजनिक भवन का उद्घाटन, के अवसर पर उसको भेंट की गई कोई करनी, अथवा इसी प्रकार कोई अन्य वस्तु, प्राप्त नहीं करेगा।

५ नियम (२) और (३) का चिकित्सा तथा शिक्षा अधिकारियों पर लागू होना:—इस प्रश्न पर बने हुए विभागीय नियमों के अधीन, कोई चिकित्सा अथवा शिक्षा अधिकारी उसकी व्यावसायिक अथवा शैक्षणिक सेवाओं के सम्मान में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह द्वारा सद्भावना से दिया गया कोई उपहार, अनुतोप अथवा इनाम, स्वीकार कर सकता है।

६. चन्दा इकट्ठा करना:—सरकार की पूर्व स्वीकृति होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र किये जाने वाले किसी चन्दे अथवा अन्य आर्थिक सहायता के लिए न तो किसी से कहेगा, न इसे स्वीकार ही करेगा और न उस धनराशि के संग्रह में किसी भी प्रकार भाग ही लेगा।

७. त्याग-पत्र की खरीद—सरकार के अधीन किसी पद के त्याग पत्र के सम्बन्ध में किसी अन्य को लाभ पहुँचाने की दृष्टि में कोई भी राज्य कर्मचारी किसी आर्थिक व्यवस्था में भाग नहीं लेगा। यदि इस नियम की अवहेलना की गई तो ऐसे त्यागपत्र देने के बाद किया गया कोई मनोनयन या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और इस व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे लोगो जो कि यदि तब भी सेवा में होंगे, को सरकार की आज्ञा मिलने तक अथवा जैसा कि मामला हो, निलम्बित कर दिया जायेगा।

८. रुपया उधार देना और लेना:—(१) कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसका कि वेतन २००) २० प्रतिमाह अथवा अधिक हो, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्दर रहने वाले अचल सम्पत्ति के स्वामी किसी व्यक्ति को रुपया उधार नहीं दे सकेगा और न ही वह, किसी ज्वैलरी स्टॉक, बैंक अथवा किसी प्रसिद्ध फर्म के साथ किए जाने वाले साधारण व्यावसायिक कार्य को छोड़ कर, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में रहने वाले, अचल सम्पत्ति रखने वाले अथवा अपना व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले सकेगा और न ही किसी अन्य प्रकार के आर्थिक दायित्व में अपने आपको बांध सकेगा।

(२) जब कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) मासिक अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला अधिकारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है अथवा स्थानान्तरित किया जाता है, जहाँ

पर कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको कि उसने रुपया उधार दे रखा हो अथवा जिनके साथ उसने स्वयं ने किसी आर्थिक दायित्व में अपने को बाध रखा हो, होगा और जो कि उसकी सरकारी अधिकार सीमा के अन्तर्गत होगा, अथवा रहता होगा, अथवा सम्पत्ति रखता होगा अथवा उस अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में कार्य करता होगा, तो उसे उचित मार्ग द्वारा उन परिस्थितियों को सरकार को सूचित कर देना चाहिए।

(३) इस पैरा के आदेश, २००) प्रतिमाह में कम वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी लागू होते हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में उनके कार्यालयाध्यक्ष की मर्जी से विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को उपरोक्त उप पैरा (२) में वर्णित प्रतिवेदन अपने कार्यालयाध्यक्ष को दे देने चाहिये।

६. मकान एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय—

(१) किसी नियमित विक्रेता के साथ अर्द्धेय में किये गए किसी सौदे के मामले को छोड़ कर २००) प्रतिमाह अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी, जो कि एक हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार में निस्तार करना चाहता है, अपनी ऐसी इच्छा निर्धारित अधिकारी को घोषित करेगा। ऐसी घोषणा, परिस्थितियों, एवं प्रस्तावित मूल्य का पूरा विवरण देगी और विक्रय के अलावा निस्तार को कोई अन्य विधि अपनाते की स्थिति में, निस्तार (disposal) की विधि भी उसमें उल्लिखित होगी। इसके पश्चात् वह राज्य कर्मचारी ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए हों। किन्तु गर्त यह है कि यदि सम्पत्ति का मूल्य १००) अथवा उससे ऊपर है, तो सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी और आयुक्त, विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति किया गया अन्य कोई अधिकारी ऐसे आदेश देने से पूर्व सरकार को वह मामला भेज देगा।

(२) उप नियम (१) में दी गई किसी भी बात को ध्यान में न लाते हुए कोई राजपणित अधिकारी अथवा २००) या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाला कोई अधिकारी, जो कि अपने नियुक्ति के स्थान, जिला अथवा अन्य स्थानीय सीमा को छोड़ने वाला हो बिना किसी अधिकारी को सूचित, किये अपनी चल सम्पत्ति को, समाज में साधारणतया उसकी एक सूची घुमाकर अथवा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा विक्रय कर के, निवटारा कर सकता है।

१० राज्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण—

(१) इन नियमों के प्रभावशाली होने के तीन माह के भीतर भीतर राज्य सेवा में संलग्न प्रत्येक कर्मचारी, उचित मार्ग द्वारा, उसके स्वयं के, उसकी पत्नि, या उसके साथ रहने वाले अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में रहने वाली अचल सम्पत्ति की एक घोषणा करेगा। ऐसी सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिले, प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है उसका भी उस घोषणा में उल्लेख होगा और उसमें ऐसी अन्य सूचना भी दी हुई होगी जैसी कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा चाहे।

(२) उप पैरा १० (१) में वर्जित प्रथम घोषणा के बाद यदि राज्य कर्मचारी उसकी पत्नि, उसके साथ रहने वाला अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त करता है अथवा उत्तराधिकार में पाता है, तो वह उचित मार्ग द्वारा ऐसी सम्पत्ति

का एक घोषणा पत्र सरकार को प्रेषित करेगा ।

(३) निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी नियमित विक्रेता के द्वारा किसी अचल सम्पत्ति को क्रय, विक्रय अथवा उपहार के रूप में कोई भी राज्य कर्मचारी न तो प्राप्त कर सकेगा अथवा उसका निस्तार कर सकेगा ।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई भी सोदा, जो कि एक नियमित व प्रसिद्ध विक्रेता के मार्फत नहीं हुमा हो, निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वीकृत से ही हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—संदर्भित राज्य कर्मचारी का नियुक्ति अधिकारी ही इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा ।

११. अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य बातों में विनियोग—कोई भी राज्य कर्मचारी न तो स्वयं ऐसा विनियोग (Investment) करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा जिससे कि उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसको प्रभावित होना पड़े अथवा जो कि उसकी स्थिति को उलभन में डाल देवे ।

नोट—इस नियम के लिए, परिवार में प्रत्येक वह सम्बन्धी भी सम्मिलित होगा जो कि उस राज्य कर्मचारी के साथ रह रहा हो अथवा जो चाहे उसके साथ नहीं रहता हो किन्तु उस पर आश्रित हो ।

किन्तु यह शर्त है कि वह, किसी ऐसी कम्पनी जिसमें कि खदान अथवा कृषि की कम्पनी भी सम्मिलित है और जिसका कि उद्देश्य देश के सीतो वा विकास करना है, के हिस्से प्राप्त कर सकता है अथवा उसके हिस्से रख सकता है किन्तु उसे ऐसे जिले में नियोजित नहीं किया जावेगा, जहाँ पर कि उम कम्पनी का कार्य होता हो ।

उसी शर्त के साथ, सन् १९१२ के द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी प्रादेशिक अथवा केन्द्रीय बैंक में, वह धन जमा करवा सकता है और उसी नियम के अन्तर्गत पंजीकृत गैर कृषि प्रधान समितियों तथा जो कि केवल राज्य कर्मचारियों के लिए ही हो, में विनियोग कर सकता है चाहे फिर वह बैंक अथवा समिति उनी क्षेत्र में ही कार्य क्यों नहीं करते हो जहाँ कि वह नियोजित किया गया हो ।

उपरोक्त के अलावा अन्य पंजीकृत सहकारी समितियों में भी वह विनियोग कर सकता है अथवा धन जमा करवा सकता है ।

१२. सट्टा—कोई भी सरकारी कर्मचारी विनियोग (investment) में सट्टा नहीं कर सकेगा ।

इस सामान्य नियम को लागू करने में, किसी मूल्यवान् खनिज सामग्री युक्त भू-भाग की इस दृष्टि से खरीद, कि उसे कम्पनियों को बेच दिया जावेगा अथवा उत्तार चढ़ाव वाले विनियोगों के । अभ्यस्त क्रय विक्रय, भी-विनियोग में सट्टा माना जावेगा ।

१३. कम्पनियों की स्थापना एवं प्रबन्ध—कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसका वेतन ₹००) ४० मासिक या इससे अधिक हो, चाहे वह छुट्टी पर हो या सक्रिय सेवा में, सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना किसी बैंक अथवा अन्य कम्पनी की स्थापना, पंजीकरण अथवा व्यवस्था में भाग नहीं ले सकेगा ।

यह नियम किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो कि सरकार की स्वीकृति से, सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई किसी रेलवे कम्पनी की सेवा में प्रवेश करता है, अथवा जो कि पारस्परिक सहयोग और लाभ प्राप्त नहीं करने के उद्देश्य से मदमावना में संचालित अथवा स्थापित किसी मंगल की व्यवस्था करता हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसी व्यवस्था को देखना उसके सार्वजनिक कर्तव्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे अथवा इसी शर्त के साथ यह नियम उन राज्य कर्मचारी पर भी लागू नहीं होगा जो सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष स्वीकृति के अन्तर्गत, किसी सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेता है।

१४. व्यक्तिगत व्यापार अथवा नियोजन—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य व्यापार में अपने आप को नहीं लगा सकेगा और न कोई अन्य नियोजन ही स्वीकार करेगा।

कोई राज्य कर्मचारी किसी नाट्यिक अथवा कलात्मक प्रकृति का सामूहिक कार्य कर सकता है बशर्ते कि उसके सार्वजनिक कर्तव्यों को उससे हानि न हो, किन्तु सरकार, अपनी मर्जी से, किसी भी समय उसको ऐसा करने में रोक सकती है अथवा उसको ऐसा कोई भी नियोजन छोड़ने का आदेश दे सकती है जो कि उसकी राय में अवान्छनीय हो।

नोट—किसी क्लब का मन्त्री पद संभालना इस नियम के अन्तर्गत नियोजन में नहीं आता बशर्ते कि उसमें उस अधिकारी का इतना समय नहीं लगे कि जिससे उसके सार्वजनिक कर्तव्यों में बाधा पड़े और वह एक अवैतनिक पद होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि उसको उस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का नकद भुगतान अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य सुविधा, जिसमें कि सुप्त निवास एवं भोजनालय शुल्क से मुक्ति की परम्परागत सुविधायें शामिल नहीं मानी जायेगी, के रूप में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए। जो अधिकारी किसी क्लब का अवैतनिक मन्त्री बनना चाहे, तो उसे उसकी मूचना उसके निकटतम विभागीय उच्चधिकार को देनी चाहिए, जो कि इस नियम के संदर्भ में निर्णय करेगा और यह देखेगा कि क्या इस विषय को सरकार की आज्ञा के लिए भेजा जाना चाहिए।

१५. अराजकीय संरक्षण प्राप्त फर्म में निकटस्थ संबंधी का नियोजन:—राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पुत्र पुत्री अथवा आश्रित को ऐसी व्यक्तिगत फर्म जिसके कि साथ सरकारी तौर पर उसका संबंध है अथवा ऐसी अन्य फर्म जो कि सरकार से लेन देन का व्यवहार रखती हो, में किसी नियोजन को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। किन्तु शर्त यह है कि जब ऐसा नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की जा सके अथवा जो अन्य प्रकार में आवश्यक समझा गया हो, तो यह मामला सरकार की भेजा जायेगा और ऐसा नियोजन सरकार की स्वीकृति के अधीन अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

१४ ब. शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने पर प्रतिबन्ध:—कोई भी राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा में रहते हुए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी मान्यता प्राप्त मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करने की दृष्टि में न तो किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेगा अथवा उपस्थित होगा और न उन परीक्षा में बैठेगा।

किन्तु शर्त यह है कि:—

(१) इस नियम में उल्लिखित कोई बात ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो कि विद्यालय अथवा महा विद्यालय के उस सत्र जिसमें कि वह ऐसी तैयारी करना चाहता है, की पूरी अवधि के लिए राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत मिलने वाले अवकाश के लिए प्रार्थनापत्र देता है और जिसे ऐसा अवकाश स्वीकार किया जाता है।

(२) किसी भी राज्य कर्मचारी को, जिसने सत्र ५५ में अथवा उसके पूर्व के वर्षों में किसी परीक्षा का पूर्व खण्ड उत्तीर्ण कर लिया हो को नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी ऐसी पूर्ण खंड परीक्षा से घागे वाली अन्तिम परीक्षा में बैठने अथवा अपने आप की तैयारी करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा के समय के बाहर के समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थिति होने की स्वीकृति दी जा सकती है।

(३) प्रत्येक राज्य कर्मचारी को किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिये तैयारी करने अथवा उनमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए, उसके नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

(४) प्रत्येक अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत को किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्व विद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हों, के लिए तैयारी करने अथवा उनमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए, उसकी नियुक्ति कर्त्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है, और

(५) किन्हीं विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी अधिकारी को भी, उच्च तकनीकी अध्ययन करने अथवा किसी तकनीकी परीक्षा में बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में, किसी तकनीकी संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण:—

(अ) पूर्व खण्ड परीक्षा से अभिप्राय अन्तिम इन्टरमीडिएट अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा से तुरन्त पूर्ववाली वार्षिक परीक्षा से है, और

(ब) तकनीकी अधिकारी से अभिप्राय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, वन, सार्वजनिक निर्माण और खान एवं भूगर्भ विभागों अथवा राज्य द्वारा संचालित फैक्ट्रियों अथवा राज्य के उद्योग विभाग के अधीन उत्पन्न केन्द्रों में किसी तकनीकी कार्य वाले किसी पद पर आसीन अधिकारियों से है।

१५. दिवालियापन एवं अभ्यस्त कर्जदारी:—(१) प्रत्येक राज्य कर्मचारी स्वभार से कर्जदार बनने की स्थिति को रोकेगा।

(२) जब किसी राज्य कर्मचारी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा न्यायालय ऐसा फैसला दे देती है और जब ऐसे राज्य कर्मचारी के वेतन का एक यथेष्ट भाग लगातार दो व

से अधिक की अवधि तक कुर्क रहता है अथवा जब उसका वेतन ए०- ऐसे रकम के लिये कुर्क किया जाता है जो कि सामान्य परिस्थितियों में २ वर्ष की अवधि में नहीं चुकाया जा सके, तो उसको बर्खास्त करने के योग्य माना जायेगा ।

(३) जब ऐसा राज्य कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से अथवा उसके द्वारा ही बर्खास्त किये जाने योग्य है और अन्य प्रकार से नहीं है, और यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो वह मामला सरकार को भेजा जाना चाहिए और यदि केवल उसके वेतन का भाग ही कुर्क किया गया है तो उस मामले पर सरकार को प्रतिवेदन दिया जा सकता है ।

(४) किसी अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में ऐसा मामला उसके कार्यालय अथवा विभाग जिसमें कि वह नियोजित है, के प्रधान को भेजा जाना चाहिए ।

(५) जब किसी अधिकारी के वेतन का कुछ भाग कुर्क कर लिया गया है, तो प्रतिवेदन में यह वर्णित होना चाहिए कि कर्ज का वेतन से क्या अनुपात है, उससे राज्य कर्मचारी की कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कर्जदार की स्थिति असाध्य है और क्या उस मामले की परिस्थितियों में उसे उसके स्वयं के अथवा किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय है जब कि यह मामला प्रकाश में आ गया है ।

(६) इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में यह बात सिद्ध करने का भार कि दिवालियापन अथवा कर्जदारी ऐसी परिस्थितियों का परिणाम है जो कि सामान्य चतुरता दिखाने के बाद भी, कर्जदार पहले से नहीं इन्हें आंक सका अथवा जिन पर कि उसका कोई नियन्त्रण नहीं रहा और यह कर्जदारी उसकी फिजूल खर्चों अथवा अन्य आदतों के कारण नहीं हुई है, कर्जदार पर होगा ।

१५अ. कोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी कि एक पति जीवित है, सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, चाहे ऐसा दूसरा विवाह करने की उस पर लागू उसके व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उसे स्वीकृति मिल सकती हो ।

१५ब.—कोई भी महिला कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगी जिसके कि पहले वाली पति जीवित हो ।

१५स.—कोई भी राजकीय कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों में नशा किये हुए नहीं जायेगा ।

१६. सरकारी कागजात अथवा सूचना दूसरे को देना—कोई भी राजकीय कर्मचारी, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जब तक सामान्य अथवा विशेषतया अधिकार नहीं दिया गया हो, किसी भी अन्य विभाग से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा समाचार पत्रों को अत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कागज अथवा ऐसी सूचना जो कि उसके अधिकार में उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान आई हो अथवा जो कि उसके द्वारा ऐसे कर्तव्यों के दौरान संग्रहित अथवा तैयार की गई हो चाहे सरकारी सूत्रों के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से, सूचना नहीं देगा । इसमें ऐसे अधिकारी प्रतिबन्धित नहीं होंगे जिनका कि कर्तव्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अनुसार समाचार पत्रों को सरकारी कार्य की प्रचार सामग्री देना है ।

१७. समाचार पत्रों से सम्बन्ध—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना, किसी समाचार पत्र अथवा अन्य सामयिक प्रकाशन की व्यवस्था अथवा सम्पादन में न तो भाग ले सकेगा और न उसका संचालन कर सकेगा और न ही वह उसका सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से देना सकेगा ।

ऐसी स्वीकृति केवल उसी समाचार पत्र अथवा प्रकाशन में ली जावेगी जो कि केवल विभागीय अथवा राजनीति रहित विषयों के लिए कार्य करता हो और ऐसी स्वीकृति सरकार की इच्छा के अनुसार कभी भी वापिस ली जा सकती है।

१८. नियम (१६) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी राज्यकर्मचारी समाचार पत्रों में अपना नाम व्यक्त किये बिना रचना भेज सकता है लेकिन उसे स्वस्थ एवं उचित वाद-विवाद तक ही अपने को सीमित कर रखना चाहिए और यदि उसका समाचार पत्र में सम्पर्क सार्वजनिक हित के विपरीत है तो सरकार उसकी रचनाएं भेजने की स्वतंत्रता को वापिस ले सकती है जब कोई गंका हो जाये कि किसी राज्य कर्मचारी का समाचार पत्रों के साथ सम्बन्ध सार्वजनिक हित के विपरीत है या नहीं तो वह मामला सरकार को आज्ञा के लिए भेज दिया जायेगा।

१९. सरकार की आलोचना तथा विदेशों सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर सूचना एवं राय प्रकट करना:—

(१) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से प्रकाशित किसी पत्र में अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी सार्वजनिक वक्तव्य में कोई ऐसा तथ्य एवं मत प्रकट नहीं करेगा जिसमें कि निम्न बातों में अन्तर आ सके—

(अ) राजस्थान राज्य के लोगों अथवा उनके किसीवर्ग एवं सरकार के बीच सम्बन्धों में, अथवा

(ब) भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के आपसी सम्बन्धों अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा रियासती सभों की सरकार के बीच।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि अपने स्वयं के नाम से कोई कागजात प्रकाशित करना चाहता है अथवा कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देना चाहता है। जिसके कि वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी गंका उठ खड़ी हो कि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध उस पर लागू होते हैं कि नहीं तो वह ऐसे प्रस्तावित प्रकाशन अथवा वक्तव्य की एक प्रति सरकार को प्रेषित करेगा और उस प्रकाशन तथा वक्तव्य को, सरकार की स्वीकृति को छोड़कर तथा सरकार द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों के बिना तब तक प्रकाशित नहीं करेगा अथवा वक्तव्य नहीं देगा।

नोट:— किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन करने के दौरान में लिखित अथवा मौखिक रूप से की गई विचारों की अभिव्यक्ति उसे इस नियम के अन्तर्गत नहीं ला सकेगी। किन्तु ऐसी अभिव्यक्ति चाहे लिखित में या अन्य प्रकार से और चाहे उसका प्रसार अथवा ओतागण सीमित ही हों, यदि वह उसके सरकारी कर्तव्यों से सम्बन्धित न हो तो उसको एक प्रकाशन अथवा सार्वजनिक वक्तव्य मान लिया जावेगा।

(३) (१) कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न उद्देश्य से संसद अथवा राज्य विधान सभा के किसी सदस्य से सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा—

(अ) उसकी सेवा की शर्तों अथवा उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई प्रश्न पुछवाना अथवा प्रस्ताव रखवाना, अथवा

(ब) कोई ऐसा बात बतला देना जो कि सरकार की स्थिति को संकट में डाल दे।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने किसी उच्चाधिकारी पर न तो कोई बाहर का प्रभाव लायेगा और न ऐसा करे

का प्रयत्न ही करेगा ।

२०. समितियों के समक्ष साक्षियाँ:—कोई राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक समिति के समक्ष कोई साक्षी नहीं दे सकेगा ।

यह नियम ऐसी साक्षियों पर लागू नहीं होगा जो निम्नलिखित न्यायिक आयोग जो कि लोगों की अनिवार्य रूप से उपस्थित कराने एवं उत्तर प्राप्त करने का अधिकार रखते हों अथवा जो कि न्यायिक जांच या सरकार द्वारा या उसकी अनुमति से नियुक्त समितियों के समक्ष दी गई हो ।

२१. राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना—(१) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी राजनैतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का न तो सदस्य होगा और न किसी अन्य प्रकार से उससे सम्बन्ध होगा । वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में न तो कोई भाग लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा अथवा न उसकी किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा ।

(२) प्रत्येक राज्य कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पर आश्रित अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन अथवा गतिविधि, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कानून से स्थापित सरकार को उलटने के लिए की जा रही हो, में भाग लेने अथवा उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता करने से वह उसको रोके और जहाँ पर कोई राज्य कर्मचारी ऐसी गतिविधि अथवा आंदोलन में उसके परिवार के किसी सदस्य को भाग लेते, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने अथवा किसी अन्य विधि से मदद करने से, रोकने में असमर्थ रहता है तो वह उसकी सूचना सरकार को देगा ।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक आंदोलन अथवा कोई गतिविधि इस नियम के अन्तर्गत आती है या नहीं, तो उस पर दिया गया सरकार का निर्णय ही अन्तिम होगा ।

(४) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी विधान सभाएं अथवा स्थानीय चुनाव में न तो प्रचार कर सकेगा और न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उसके सम्बन्ध में अपने सुभाव का उपयोग कर सकेगा और न उसमें भाग ही लेगा, किन्तु शर्त यह है कि—

(१) ऐसे चुनाव में मत देने की योग्यता रखने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपने मत देने के अधिकार का उपयोग कर सकता है किन्तु जहाँ वह ऐसा करेगा, वहाँ वह ऐसा कोई संकेत न देगा कि वह कैसे मत देना चाहता है अथवा उसने कैसे मतदान किया है ।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी केवल इसीलिए इस नियम का उल्लंघन किया हुआ नहीं माना जायेगा कि उस पर उस समय में प्रचलित किसी कानून के द्वारा अथवा अधीन किसी कानून के ऐसे कर्तव्य पालन का भार है जिससे उसे किसी चुनाव के संचालन में सहायता करनी पड़ती है ।

मैं किसी राज्य कर्मचारी द्वारा दिया गया सहयोग इस नियम की धाराओं के अन्तर्गत प्रतिबन्ध में नहीं आता है ।

स्पष्टीकरण:—राज्य कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपने वाहन (Vehicle) अथवा घर पर किसी चुनाव चिन्ह अथवा कोई अन्य चिन्ह या किसी राजनैतिक संस्था से विशेष प्रकार से सम्बन्धित किसी उपादान का प्रदर्शन, जब तक कि अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं कर दिया जावे, इस नियम के अन्तर्गत, किसी चुनाव में अपने प्रभाव को प्रयोग किया हुआ माना जावेगा ।

२२. सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी, अपने खिलाफ किये गये आरोपों के अनुसार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों अथवा आचरण को स्पष्ट करने के लिये समान-चार पत्रों तथा किसी न्यायालय की सहायता नहीं लेगा । न्यायालय कार्यवाही के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व, सरकार, प्रत्येक मामले में यह निर्णय करेगी कि क्या राज्य कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा अपने खर्च से चलायेगा और यदि ऐसा है तो क्या न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिये जाने की स्थिति में, सरकार उस मुकदमे के खर्च का पूरा अथवा अंशभाग उस कर्मचारी को दे देगी ।

इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि राज्य कर्मचारों के अपने प्राईवेट कार्य अथवा आचरण को स्पष्ट करने के अधिकार को प्रभावित कर सके ।

२३. अ-प्रदर्शन तथा हड़ताल—अपनी सेवा को शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई भी राज्य कर्मचारी न तो किसी प्रदर्शन में भाग ले सकेगा और न किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेगा ।

२३. सेवा संघों की सदस्यता:—कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसे संघ, जो कि राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा करने के उद्देश्य वाले हों, का सदस्य, प्रतिनिधि तथा अधिकारी तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि उस संघ को सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्रदान कर दी गई है ।

२३. अ—राज्य कर्मचारियों द्वारा संघों में प्रवेश:—कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न प्रकार के राज्य कर्मचारियों के संघों का सदस्य नहीं बन सकेगा और न उनका गठन कर सकेगा:—

(अ) ऐसा संघ, जिसने अपने गठन के ६ मास की अवधि के भीतर सरकार से तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं कर ली हो ।

(ब) ऐसा संघ, जिसको कि नियमों के अन्तर्गत मान्यता देने से मना कर दिया गया हो अथवा सरकार द्वारा जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो ।

२४. अवकाश प्राप्त कर्मचारी (Pensioners):—(१) विश्राम वृत्ति की प्रत्येक स्वीकृति के लिए भविष्य का अच्छा आचरण एक गभित (implied) शर्त है । यदि पेंशनर किसी भयंकर अपराध में सजा प्राप्त करे अथवा गम्भीर दुराचरण का अपराधी पाया जावे, तो राज्य सरकार, किसी पेंशन अथवा उसके किसी अंश को वापिस लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है ।

स्पष्टीकरण:—राज्य की नींव को उखाड़ने वाली राजनैतिक प्रवृत्तियों में भाग लेने अथवा अवैधानिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने को इस नियम के लिए गम्भीर दुराचरण माना जा सकता है ।

(२) राज्य कर्मचारियों के आचरण के अन्य नियम अवकाश प्राप्त कर्मचारियों (Pensioners) पर लागू नहीं होते हैं ।

२५. बचाव:—राज्य कर्मचारियों के आचरण से सम्बन्धित, वर्तमान समय में प्रचलित, किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश अथवा कानून के लागू होने में इन नियमों की कोई भी बात प्रभावित नहीं करेगी ।

२६. Repeal:—राजस्थान के किसी भी भाग में प्रचलित कर्मचारियों के आचरण

नियम, उन सब कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन पर ये नियम लागू होने हैं एतद्वारा अतिक्रमित माने जाते हैं।

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों) को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी नियम, १९६२

समाज कल्याण विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी १७, १९६२

संख्या एक० १ (२०६) एस-डब्ल्यू०/६०:—राजस्थान सरकार एतद्वारा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर अध्ययन जारी रखने के हेतु छात्रवृत्तियाँ देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर अध्ययन जारी रखने के हेतु छात्रवृत्तियाँ देने सम्बन्धी नियम।

१. ये नियम, राजस्थान सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों) को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी नियम, १९६२, कहलायेंगे।

२. ये तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

३. इन नियमों में, जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) “संचालक” से तात्पर्य संचालक, समाज कल्याण राजस्थान, में है।

(ख) “सरकार” से तात्पर्य राजस्थान सरकार, में है।

(ग) “उच्चतर अध्ययन” से तात्पर्य राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्व-विद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा स्तर तक अध्ययन या ऐसे विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान, सामाजिक कार्य, या समाज कल्याण या सुधार विषयक प्रशासन (Correctional administration) स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के स्तर तक अध्ययन, में है तथा इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा स्तर तक प्रावैधिक कोर्सेज का अध्ययन शामिल है।

(घ) “मूल निवास स्थान” से तात्पर्य उस नगर से है जिसका कि छात्र वास्तव में निवासी है।

(ङ) “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिये भारत के संविधान के खण्ड २४ तथा २५ में दिये गये हैं।

(च) “छात्र (Scholar)” से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऐसे सरकारी कर्मचारी से है जो उच्चतर अध्ययन कर रहा हो, और

(छ) “अनुसूची” से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है।

४. (१) इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी उम्मीदवार छात्रवृत्ति दिये जाने योग्य नहीं होगा जब तक कि:—

[१] वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का सदस्य नहीं हो, और

राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) पृष्ठ संख्या ७०१ पर दिनांक २० दिसम्बर १९६२ में छपा।

[२] वह सरकार का स्थायी कर्मचारी नहीं हो या उसने सरकार के अधीन लगातार तीन वर्षों तक सेवा नहीं करली हो; और

[३] उसने राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में और प्रावैधिक डिग्री कोर्स के मामले में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया हो, और

[४] वह, उस वर्ष, जिसमें स्वीकृति जारी की जाती है, के जनवरी के प्रथम दिन ४५ वर्ष से अधिक का नहीं हो।

(ऐसे उम्मीदवार भी जो भी किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाय छात्रवृत्ति पाने के अयोग्य हैं)

(२) अन्य बातें समान होने पर, तरजीह उन उम्मीदवारों को दी जायगी जो किसी प्रावैधिक कोर्स के लिये आगे अध्ययन करना चाहते हैं।

५. (१) छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र, छात्र द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में अपने विभाग, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा नियुक्त है, के अध्ययन के जरिये, संचालक को, सम्बोधित किये जायेंगे तथा उनके साथ विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र, आवेदक की जाति तथा परिवार, जिसका आवेदक सदस्य है, की वार्षिक आय बताते हुए, संलग्न किया जायगा।

(२) संचालक, ऐसे आवेदन पत्रों का, यह देखने के लिए कि आवेदक ऐसी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, परिनिरीक्षण करेगा।

स्पष्टीकरण:—छात्रवृत्तियां प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बात, जिसका ध्यान रखा जायगा, यह होगी कि उम्मीदवार को अन्तिम परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए थे। यदि उम्मीदवारों की संख्या इस प्रयोजन के लिए प्रावहित उपलब्ध रकम से अधिक है तो उच्चतर आय वाले छात्र को तरजीह दी जायगी।

६. (१) इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि, छात्र द्वारा अपने अध्ययन के सम्बन्ध में निम्नांकित मदों पर किये गए खर्च को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट की जायगी तथा रकम के उपलब्ध होने के अधीन होगी।

(क) एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, यूनिफ़ॉर्म, वाचनालय मेगजीन, स्वास्थ्य-परीक्षा-शुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क जो छात्र द्वारा संस्था या विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्यतः देय हैं किन्तु किसी भी दशा में राशि, इन समस्त मदों पर एक सौ रुपये (१००) रु० से अधिक नहीं होगी;

(ख) छात्र का वेतन तथा वेतन दर तथा अध्ययन अवकाश के दौरान में स्वीकार्य अर्द्ध-औसत-वेतन दिये जाने के कारण परिलाभों (emoluments) में हुई वास्तविक हानि;

(ग) परिवार, जिसका कि छात्र सदस्य है, की वित्तीय स्थिति।

(२) छात्र, उपरोक्त उप-नियम (१) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति की राशि में से, आवश्यक पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री इत्यादि, क्रय करेगा। यदि संबंधित संस्था के अध्यक्ष द्वारा यह सूचना दी जायगी कि किसी छात्र ने पाठ्य पुस्तकें इत्यादि क्रय नहीं की है तो छात्रवृत्ति की राशि संचालक के विवेकानुसार कम की जा सकेगी।

७. (१) उपरोक्त नियम ६ (१) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति केवल १० मास के लिये ही देय होगी ।

(२) इन नियमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला कोई भी छात्र किसी भी गैर-सरकारी, या स्थानीय नियमों या सरकारी विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक कोई नौकरी नहीं करेगा और इसमें चूक करने की दशा में छात्रवृत्ति रोक दी जायगी और उसे, उस विद्या-वर्ष (academic year) की अवधि में उमको दी गई कोई भी राशि प्रत्यापित (refund) करनी होगी । इसके अतिरिक्त इन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सरकार उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी ।

८. (१) छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जायगी जो किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं या विश्वविद्यालय या बोर्ड या उस संस्था जिसमें वह अध्ययन कर रहा है से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं । योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र की दशा में छात्रवृत्ति की राशि किसी भी अन्य साधन में प्राप्त राशि की मात्रा तक कम कर दी जायगी ।

(२) इन नियमों के अन्तर्गत दी गई छात्रवृत्ति संचालक द्वारा बन्द कर दी जायगी:—

[१] यदि ऐसा पाया जाय कि छात्र ने अपने को किसी अवैध कार्यवाही से सम्बद्ध कर लिया है; या

[२] यदि छात्र घोर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है; या

[३] यदि छात्र अपने अध्ययन में सन्तोषजनक प्रगति करने में विफल रहता है; या

[४] यदि छात्र (scholar) किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जब तक कि विद्यार्थी (student) संचालक को सन्तुष्ट न करदे कि उसकी असफलता का कारण बीमारी या उसके नियन्त्रण से परे अन्य ऐसा कोई ही कारण था;

[५] यदि ऐसा पाया जाय कि छात्र ने आवेदन-पत्र में गलत विवरण या अपूर्ण सूचना दी है;

[६] सरकार की या उस विभाग, जहां वह सेवामुक्त है, के अध्यक्ष की आज्ञा द्वारा;

[७] सरकार स्वविवेक से किसी भी छात्रवृत्ति को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये, बन्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है ।

(३) किसी छात्र द्वारा अध्ययन करने में घोर असाधवानी बरतने की स्थिति में संचालक स्वविवेक से, आगे अध्ययन की बन्द करने के अतिरिक्त सम्पूर्ण छात्रवृत्ति या उसका कोई भी भाग वसूल कर सकेगा ।

९. किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी:—

(१) यदि शिक्षा के एक स्तर में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् वह किसी भिन्न विषय में उसी स्तर में अपना अध्ययन चालू रखता है (जैसे बी० ए० में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् किसी की बी० काम० इत्यादि में अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जायगी) ।

(२) यदि वह संचालक की लिखित में पूर्ण स्वीकृति के बिना अध्ययन के पाठ्यक्रम (Course) को, जिसके नियम उसे छात्रवृत्ति मूलतः दी गई थी, के विषय (Subject) में

परिवर्तन करता है या अध्ययन करने की संस्था को बदल लेता है तो संस्था का अध्यक्ष ऐसे मामला की रिपोर्ट, स्वीकृति देने वाली सत्ता को देगा तथा छात्रवृत्ति का भुगतान रोक देगा। ऐसे मामलों में पहले भुगतान की गई राशि भी संचालक के स्वविवेक से वसूल की जा सकेगी।

(३) यदि कोई छात्र उस वर्ष के दौरान में, जिसके कि लिये छात्रवृत्ति दी गई है, उसके द्वारा आरंभ किये गए अध्ययन को बन्द कर देता है तो वह संचालक के स्वविवेक से छात्रवृत्ति की राशि का प्रत्यर्पण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

१०. छात्रवृत्ति को राशि उस संस्था, जिसमें छात्र भर्ती किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा उठाई तथा छात्र को वितरित की जायेगी। विप्रेक्षण व्यय यदि कोई हों, छात्र द्वारा वहन किये जायेंगे।

११. छात्र द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत उसके द्वारा उठाई गई राशि का, उस संस्था, जहां वह अपना अध्ययन करता है, के अध्यक्ष द्वारा यथाविधि सत्यापित लेखा, विद्या-वर्ष (Academic year) की समाप्ति के दो महीनों के अन्दर तथा किसी भी दशा में आगामी वर्ष के लिये सहायता उठाने के पूर्व, प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

संख्या एक. १ (२०६) एस. डब्ल्यू ६० दिनांक २०-१-६२ में संलग्न कीजिये।

अनुसूची

(आवेदन का पत्र)

नियम ३ (छ) तथा ६ [१] के अधीन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सरकारी कर्मचारियों को छात्रवृत्तियां दी जाने के लिये आवेदन का पत्र १९६१-६२।

नोट १ स्तम्भ:—आवेदक द्वारा सही रूप में भरे जाने चाहियें तथा पत्र पर उसके हस्ताक्षर होने चाहियें। किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी गलत विवरण उसे छात्रवृत्ति पाने के निमित्त अयोग्य बना देगा।

२. छात्रवृत्तियां केवल उच्चतर अध्ययन के लिये ही हैं।

३. संचालक, समाज कल्याण विभाग को आवेदन-पत्र देने की अंतिम तारीख..... है। इस तारीख के पश्चात् कोई भी आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं किया जायगा।

कोई भी स्तम्भ बिना भरे नहीं छोड़ना चाहिये अन्यथा आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जायगा।

सेवामें,

संचालक,

समाज कल्याण विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिये

उत्तर अध्ययन के निमित्त रखी गई छात्रवृत्ति के लिये अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ ।

मैं..... जाति का हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर ।

१. आवेदक का पूरा नाम महिला उम्मीदवार, यह बतलावे कि वह श्रीमती (विवाहित) है या कुंवारी है.....
२. धर्म..... जाति .. तप-जाति ..
३. पिता का नाम पूरे स्याई पते सहित ..
४. जन्म की तारीख..... जन्म स्थान..... गांव.....
डाकघर..... तहसील..... जिला.....
५. [१] उम्मीदवार के गृह का वर्तमान पता.....
[२] स्याई गृह का पता.....
६. विभाग, जिसमें वह इस समय कार्य कर रहा है, के अध्यक्ष का नाम.....
७. दफ्तर (पूरे पते सहित) जिसमें वह आजकल कार्य कर रहा है, का नाम ..
८. आवेदक द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा के विवरण.....
- [१] परीक्षा का नाम.....
- [२] वर्ष, जिसमें परीक्षा दी गई.....
- [३] उस संस्था का नाम, जिसमें वह आखिरी बार पढ़ा ..
- [४] आया वह विश्वविद्यालय । बोर्ड या किसी क्लास की परीक्षा थी.....
- [५] उम्मीदवार उसमें उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण.....
- [६] क्या वह उसमें एक बार बैठने पर उत्तीर्ण हो गया.....
- [७] यदि उम्मीदवार एक बार बैठने पर उत्तीर्ण नहीं हुआ तो क्या वह कम्पार्टमेन्टल या सप्लीमेन्टरी परीक्षा में रखा गया था । कम्पार्टमेन्टल या सप्लीमेन्टरी परीक्षा का परिणाम बताइये ।
- [८] विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा में उम्मीदवार का रोल । रजिस्टर नम्बर ..
- [९] परीक्षा में प्राप्त अंशी (Class) या डिविजन, प्राप्त अंकों प्रतिशत सहित
- [१०] प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक—

क्रम संख्या	विषय	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक न्यूनतम अंक	प्राप्त अंक	कुल प्राप्त अंको का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					
८					
९					
१०					
योग					

नोट:—अंक पत्र (Mark sheet) को अभिप्रमाणित (attested) प्रतिलिपि भी संलग्न की जानी चाहिये।

६. (क) उस संस्था का नाम, जिसमें प्रवेश पाया हो

(ख) तारीख, जिसको प्रवेश मिला

(ग) पाठ-चर्चा (Course of study) का नाम तथा विषय जिसका वह अध्ययन करेगा

(घ) पाठ-चर्चा का चरण या क्लास जिसमें प्रविष्ट हुआ है

[१] पाठ-चर्चा की सम्पूर्ण अवधि

[२] अवधि, जो अब तक पूरी की जा चुकी है

(ङ) उपाधि (Degree) (डिप्लोमा) प्रमाण-पत्र तथा विषयों के नाम जो लिए गये हैं

(च) प्राधिकारी (मन्त्र) जिसके द्वारा उपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायगा

(छ) क्लास, जिसमें प्रवेश लिया हो

१०. क्या उम्मीदवार को किसी अन्य राज्य सरकार से या किसी अन्य संस्था या समाज-संस्था (Society) से उली अकादमिक वर्ष (academic year) के लिए जिस के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कोई छानवृत्ति मिलती है

यदि मिलती है, तो निम्नलिखित व्योरे दीजिये:—

कहाँ से मिलती है

मासिक दर

मिलने की अवधि

तारीख, जिससे दी जाती है

कुल राशि

(यदि इस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् फीस में कोई रिमायट या छात्रवृत्ति मिलनी है तो आवेदक को चाहिये कि वह संस्था के अध्यक्ष की मारफत उक्त तथ्य की सूचना तुरन्त संचालकालय को दे।

उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति

११. आया उम्मीदवार मंयुक्त परिवार में रहता है ?

- (क) यदि रहता है तो परिवार के सदस्यों की पूरे विवरण सहित संख्या बताइये
- (ख) सरकारी तथा प्राईवेट सेवा में नियोजित परिवार के सदस्यों की संख्या.....
- (ग) समस्त सदस्यों की मासिक आय
- (घ) कोई भी अन्य व्ययरे

नोट:—विवाहित महिला उम्मीदवार को अपने पति का नाम तथा उसकी आय भी बतानी चाहिये।

१२. उम्मीदवार का वर्तमान पद नाम

१३. (१) मासिक वेतन) रु०
- (२) मासिक मकान किराया भत्ता) रु०
- (३) अन्य भत्ते) रु०
- (४) संपूर्ण मासिक आय) रु०

१४. सरकारी सेवा में प्रवेश करने की तारीख

१५. सेवा के विवरण (History)

.....

.....

.....

१६. मेट्रिक अथवा तत्समान परीक्षा से आरम्भ करते हुए विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त परीक्षाओं के, जो पाम की हो और उपाधियों के, जो प्राप्त की हों, विवरण दीजिये। प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमा अथवा उपाधियों की अभिप्रमाणित (attested) प्रतिलिपियां संलग्न करनी चाहिये।

स्कूल/कालेज/ विश्वविद्यालय/ बोर्ड, जिससे परीक्षा दी हो, का नाम	परीक्षा जो पास की हो, का नाम	वर्ष जिसमें परीक्षा पास की थी	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी या डिविजन	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	परीक्षा किन विषयों में दी गई थी
--	------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------

१

२

३

४

१७. क्या उम्मीदवार को पहले कोई छात्रवृत्ति मिली थी, यदि मिली थी तो निम्नलिखित व्योरे दीजिये:—

(१) छात्रवृत्ति का नाम

(२) उस संस्था का नाम जहां से छात्रवृत्ति दी गई थी

(३) वर्ष जिसमें छात्रवृत्ति दी गई थी, उसकी राशि सहित ।

वर्ष राशि

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है । यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाय तो मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी छात्रवृत्ति, यदि मन्जूर करदी गई, रद्द करदी जाने के योग्य होगी और छात्रवृत्ति के रूप में मेरे द्वारा प्राप्त कोई भी राशि मेरे द्वारा लौटाई जायगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

१८. जाति प्रमाण-पत्र ।

इस प्रमाण-पत्र पर विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल आफिसर, तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे ।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी से यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/कुमारी/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पति श्री निवासी भारत का/की नागरिक है और वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति का/की है ।

(२) उसका जन्म है तथा उप-जाति है ।

(३) उसका पिता/संरक्षक/पति गांव/कस्बा तहसील जिला राज्य का स्थायी निवासी है ।

(४) उसके माता पिता/संरक्षक/पति तथा उसकी स्वयं की समस्त छोटों से कुल मासिक आय रु० है ।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी विश्वास के अनुसार उपरोक्त सही है ।
साक्षी

पदनाम

१९. विभाग के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेक्षण प्रमाण-पत्र ।

इस प्रमाण-पत्र पर उस विभाग के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी जिसके कि अधीन उम्मीदवार आजकल सेवा कर रहा है, के हस्ताक्षर होने चाहिये ।

(क) उम्मीदवार का मौलिक (Substantive) वेतन

(ख) उम्मीदवार का स्थानापन्न (Officiating) वेतन

(ग) महंगाई-भत्ता

- (ग) गहनान विद्याया भगा
 (घ) अन्य भत्ता, यदि कोई हो
 (ग) कुल आर्थिक धाय
 (ङ) सरकारी नौकरों में प्रवेश करने की तारीख
 (ज) विद्यार्थी आर्थिक चेतन वृद्धि की तारीख
 (झ) प्राणामी आर्थिक चेतन वृद्धि की तारीख

२०. श्री के विना के तब सम्बन्धन अवकाश (study leave) के दिने माउन्टन किया है और उम्मेद निम्नलिखित सम्बन्धन अवकाश माउन्टन किया गया है;

२१. उनके सम्बन्धन अवकाश देने के कारण परिस्थिति की हानि
 २२. विभाग के अध्यक्ष या प्रभारी अधिकारी की मित्तरिध

१. प्रभारी अधिकारी के पूरे घर में रहना।

२. विभागाध्यक्ष के रहना।

२३. सम्बन्धन प्रमाण-पत्र।

यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। यह उन संस्थाओं, जिनमें उम्मेदवार प्रविष्ट हुआ है के, अध्यक्ष द्वारा भरा जाना चाहिए।

१. छात्र शिक्षण-शुल्क (Tuition Fee) देने में मुक्त है/मुक्त नहीं है।

२. छात्र से निम्नांकित शुल्क देने की अपेक्षा की जाती है, जिसका प्रतिशोधन (reimbursement) नहीं होता:—

२० न. व

- (क) प्रवेश या पंजीगन शुल्क
 (ख) शिक्षण (tuition) शुल्क
 (ग) विज्ञान या प्रयोग शाला शुल्क, यदि कोई हो।
 (घ) खेल कूद शुल्क
 (ङ) मूनीयन शुल्क
 (च) पुस्तकालय शुल्क
 (छ) मेगजीन शुल्क
 (ज) परीक्षा शुल्क

ऐसे शुल्कों का जो सम्पूर्ण विद्यार्थी-वर्ष के लिये वास्तव में देय हों, उल्लेख किया जाना चाहिये। यहां बताया गये शुल्कों के सिवाय कोई भी अन्य शुल्क शामिल नहीं करने चाहिये।

[१] संस्था द्वारा वसूल किया जाने वाला

[२] विश्वविद्यालय या ऐसी अन्य संस्था, जिसमें परीक्षा का संचालन किया हो, द्वारा वसूल किया जाने वाला

योग देय शुल्क

२४. (क) क्या विद्यार्थी (student)..... संस्था के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्वीकृत (approved) छात्रावास में रहता है.....

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त छात्रावास का नाम तथा पता

(ग) छात्रावास में प्रवेश की तारीख

(घ) क्या विद्यार्थी से, छात्रावास को दाय भोजन-व्यय (boarding charges) का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है

(ङ) यदि वह व्यय देकर छात्रावास में रहता है तो मासिक व्यय जो देय है

(च) भोजन व्यय.....

(छ) निवास व्यय

२५. (क) आवेदित शिक्षण-वर्ष के लिए संस्था के शिक्षण-सत्र (session) के प्रारम्भ की तारीख

(ख) तारीख, जिसको आवेदक ने संस्था में प्रवेश किया.....

(ग) उसकी वार्षिक परीक्षा का महीना और तारीख.....

२६. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटस्थ शाखा या सरकारी कोषागार (ट्रेजरी) जिसके जरिये छात्रवृत्ति का भुगतान चाहा जाता है

२७. संस्था के अध्यक्ष जिसको आवेदक के लिये छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा सके, का पत्र तथा पूरा पता.....

२८. यह संस्थाविश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बन्ध (Affiliated to) है और भारत सरकार..... राज्य सरकार द्वारा मान्यता है।

२९. आवेदक अपेक्षित न्यूनतम योग्यता रखता है और उसे इस संस्था में..... पाठ्यक्रिया में प्रविष्ट किया गया है।

३०. संस्था के अध्यक्ष की सिफारिश

संख्या.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

प्रिन्सिपल/उप-कुलपति।

दिनांक.....

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम सन् १९६३

शिक्षा विभाग (कोष्ठ ६)

विज्ञप्ति

जयपुर, १६ जनवरी, १९६३

संख्या एक. २ (२४) शिक्षा कोष्ठ ६/६२—गैर सरकारी (Non-government) शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सहायक अनुदान सम्बन्धी अनुशासित आदेशों एवं नियमों को निष्प्रभावित करते हुए, राज्यपाल ने राजस्थान की जनता के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं शारीरिक संवर्धन के लिये कार्य करती हुई गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान को व्यवस्थित रूप से वितरण के लिये संलग्न संशोधित नियम लागू किये हैं।

ये नियम १९६३-६४ के अनुदान वितरण के लिए लागू होंगे। १९६३-६४ में आवर्त्तों (Recurring) अनुदान वितरण १९६२-६३ के खर्चों पर होगा।

विष्णुदत्त शर्मा

शासन सचिव के आदेश से

१९६३ में राजस्थान में गैर-सरकारी शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान वितरण करने के नियमः—

१. संक्षिप्त नामः—इन नियमों को शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम सन् १९६३ के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है।

परिभाषाः—इन नियमों में जब तक कि प्रसंग का अन्य अर्थ अपेक्षित न हो,

(अ) स्नातक (Degree) एवं स्नातकोत्तर (Post-graduate) महाविद्यालयों के सम्बन्ध में शिक्षा संचालक से अभिप्राय, राजस्थान महा-विद्यालय (College) शिक्षा संचालक, से है।

(ब) विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के अलावा) के सम्बन्ध में शिक्षा संचालक से अभिप्राय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संचालक से है।

(स) संस्कृत शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से अभिप्राय, संस्कृत शिक्षा संचालक, से है।

(ह) शिल्प (Technical) शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षा संचालक से अभिप्राय, शिल्प शिक्षा संचालक, से है।

(य) सरकार से अभिप्राय, राजस्थान राज्य सरकार ।

(फ) राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय एवं राजस्थान में नियमानुसार स्थापित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होंगे ।

३. योग्यता:—राजस्थान में जनता की शिक्षा एवं संस्कृति के विकासार्थ एवं शारीरिक संवर्धन के लिये कर्तव्यरत, सम्पूर्ण संस्थाएँ, मंजूर प्राधिकारी (Sanctioning authority) की स्वेच्छा (discretion) पर निम्नप्रकार के अनुदान लेने योग्य हैं:—

(i) आवर्ती या बनाये रखने वाला अनुदान ।

(ii) उपकरणों/भवनो इत्यादि के लिए अनावर्ती अनुदान ।

(iii) ऐसे अन्य अनुदान जो कि सरकार से समय समय पर स्वीकृत किये जा सकें ।

टिप्पणी

१. असामान्य (Exceptional) अवस्था में सरकार राजस्थान से बाहर किसी भी ऐसी संस्था को, ऐसी शर्तों पर जो कि वह लागू करने योग्य मानती हो,

यदि ऐसी संस्था सम्पूर्ण भारत की हैसियत रखती हो और इसकी परियोजना एवं का केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

२. स्वामित्वपूर्ण संस्थाएँ जैसे कि, संस्थाएँ जो कि सन् १८६० ई० के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (Societies Registration act) या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट या किसी अन्य एक्ट आदि जो कि सरकार द्वारा उल्लिखित हो, के अन्तर्गत पंजीकृत (Registered) न हो, सार्वजनिक कोष (Public fund) से किसी भी प्रकार के अनुदान के लिये ग्राह्य (Eligible) न होगी ।

३. राज्य में शैक्षणिक कार्य के लिए सार्वजनिक कोष से वार्षिक अनुदानित राशियाँ, इन नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार शिक्षण संचालक के नियन्त्रण में प्रवृत्त हैं ।

४. संस्थाओं के अनुदान का वितरण करने में शर्त यह होगी कि आवश्यक अनुदान वजट राज्य विधान सभा मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जावे । किसी भी वर्ष में संभावित कमी की सूचना अनुदान वजट की स्वीकृति के बाद शिक्षातिशोध्य दी जायेगी और ऐसी कमी तब तक चालू रहेगी, जब तक कि सूचना संशोधित अथवा विलोपित न हो जाये ।

२. संस्थाओं का वर्गीकरण:—संस्थाएँ निम्न दो श्रेणियों में विभक्त होंगी:—

(अ) शिक्षण संस्थाएँ:—इस श्रेणी में समस्त शालाएँ, महाविद्यालय, औद्योगिक संस्थाएँ, या दूसरी संस्थाएँ जो प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा देती हो और जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग या भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय या उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान या राजस्थान में स्थापित या स्थापना किये जाने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हों, सम्मिलित होंगी ।

(ब) अन्य संस्थाएँ:—इस श्रेणी में शिक्षा के अन्य पहलुओं का सम्पादन करने वाली संस्थाएँ जैसे कि नर्सरी (Pre-primary) प्रशिक्षण संस्थाएँ; नर्सरी, माट्टेसरी एवं किडर गार्टन शालाएँ, शानोपति के लिए शोध एवं सांस्कृतिक समितियों अथवा प्राचीन साहित्य संग्रह, सुरक्षण, सम्पादन एवं प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त (Recognised)

शाला अथवा महाविद्यालय से संलग्न न हो, वशतें कि वे साम्प्रदायिक अथवा विध्वंसकारी कार्यों में भाग न लेते हों; संगीत और/या नृत्य और/या नाटक (Drama) शिक्षण अथवा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कर्तव्यरत (Engage) समितियाँ अथवा वरिष्ठ शालायें (संस्कृत पाठशालायें एवं महाविद्यालय); सांस्कृतिक संवर्धन संगठन और क्रीड़ा (Sports) संघ अथवा खेल-कूद या सांस्कृतिक कार्यों के लिये प्रतियोगितायें और स्पर्धायें संचालन करने वाली दूसरी सभायें; शारीरिक व्याधिग्रस्त बच्चों के लिए विशिष्ट शालायें; कला विज्ञान अथवा वाणिज्य महाविद्यालय; अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय अथवा शालायें; यन्त्र शास्त्र महाविद्यालय, व्यवसायिक और शिल्प (Technical) शालायें; अथवा कला या हस्तकला शालायें, ग्रामीण संस्थायें, बालचर (Scouts) पथ प्रदर्शन समितियाँ, शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित व्यावसायिक मार्गदर्शक क्लिनिकस (Clinics) प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षण संस्थायें, सार्वजनिक पुस्तकालय, शिक्षण शिविर आदि संस्थायें सम्मिलित होंगी।

३. अनुदान के लिये शर्तें:—किसी संस्थाको जब तक अनुदान ग्राह्य नहीं होगा, जब तक कि वह एतत्पश्चात् (Hereinafter) रखी गई शर्तों की पूर्ति के लिए सहमत न हो, जो कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान (Board of Secondary Education Rajasthan) और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त हो, और सहायता अनुदान के लिए आवेदन देने वाली हर एक संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति के लिए इसके आभार स्वीकृत की हुई समझी जायेगी:—

(१) संस्था किसी भी उम्मीदवार को, बिना शिक्षा संचालक की अनुमति के दूसरे राज्यो द्वारा रखी गई परीक्षा के लिये न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी, जब कि उसी प्रकार की परीक्षायें राजस्थान में शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय संचालित करता हो।

(२) संस्था के अभिलेख (Records) तथा विवरणों (Accounts) का निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा (Audit) सरकार अथवा शिक्षा विभाग अथवा महा लेखापाल (Accountant General) द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा।

(३) संस्था द्वारा प्रदत्त (Provided) प्रवेश की तथा निःशुल्क विद्याध्ययन, अर्द्धशुल्क विद्याध्ययन सहित समस्त सुविधायें, बिना किसी जातिगत अथवा पंथ के भेदभाव के हर एक वर्ग के लिये ग्राह्य होंगी।

(४) संस्था किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाई जायेगी, और उसकी संचालन निकाय (Governingbody) समिति या व्यवस्था पर इस बात के लिए विश्वास किया जा सके कि संस्था को पूंजी केवल उस संस्था के उद्देश्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई जाती है।

(५) संस्था, संचालक अथवा व्यवस्थापक समिति के सन्बन्ध में परिशिष्ट १ (Appendix) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

दूसरी बात कि उक्त समिति का विधान अपनी असाम्प्रदायिक विशेष निर्धारण द्वारा पंजी करेगा कि इसके सदस्यों का दो तिहाई भाग किसी जाति, वर्ग या पंथ विशेष से सम्बन्धित नहीं होगा। व्यवस्थापिका अथवा प्रबन्धिका समिति के किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन की सूचना शिष्टाचार विभाग को दी जावेगी।

(६) संस्था शिक्षा विभाग को अपनी सारी सम्पत्ति की सूची, जिसकी आय खर्च के उपयोग में लाई जाती हो, देगी।

(७) सरकार के संतुष्ट हो जाने की दशा में, कि संस्था की प्रबन्धक समिति या व्यवस्थापक में कोई गंभीर भगड़ा है, वो कि संस्था के सुचारु रूप से चलने में बाधक है और या प्रबन्धक समिति के सदस्यों को चुनाव जान-बूझकर ६ माह से अधिक विलम्बित किये गये हैं, सरकार उन्हें कारण बतलाने का सूचना पत्र देने के पश्चात् व्यवस्थापक सभा। समिति अथवा प्रबन्धक समिति को स्थगित (Suspend) कर सकती है और तब तक के लिये सम्पत्ति नियन्त्रण तथा संस्था को चलाने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त कर सकती है जब तक कि या तो एक नई व्यवस्थापक सभा। समिति अथवा प्रबन्धक समिति न बन जाय या भगड़ा न सुलभ जाय।

(८) विभाग को बिना एक पूरे साल की सूचना के कोई भी संस्था बन्द नहीं होगी अथवा down graded नहीं होगी। ऐसे सूचना पत्र में निम्न बातें होंगी:—

(i) बन्द करने का अभिप्राय या down guarding का कारण।

(ii) समस्त रखी हुई सम्पत्ति की सूची।

(९) संस्था तब तक अपने धर्मस्व को, त्रुसट स्टॉक (Trust stock) में विनियोजन (Invest) करेगी अथवा स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) में अथवा केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त किसी बैंक में धरोहर के रूप में रखेगी, जब तक कि वह सरकार से विशेष रूप से मुक्त न हो संस्था के लिए विद्याधियों से शुल्क के रूप में अथवा चन्दा (Contribution), धर्मस्व और दान के रूप में वसूल की गई समस्त राशि, इसके संचित को, भवन मरम्मत अथवा दूसरे मूल कार्यों के लिये सुरक्षित राशि, तथा सहायक अनुदान आदि के रूप में समस्त राशि संस्था कोष (Institutional fund) में होगी, जो कि स्टेट बैंक आफ इंडिया; पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अथवा किसी अन्य अनुसूचित बैंक अथवा केन्द्र से मान्यता प्राप्त बैंक में रखी जायेगी। कोई भी राशि संस्था कोष से बाहर नहीं रखी जायेगी। संस्था कोष से राशि केवल वही व्यक्ति निकाल सकेगा जो कि कोष को कार्यान्वित करने का और वह भी केवल प्रबन्ध के चालू खर्चों के लिये (Incurring expenditure for the maintenance) अथवा संस्था के विकास के लिये व्यवस्थापिका सभा अथवा प्रबन्ध समिति से अधिकार प्राप्त किया हुआ हो।

(१०) संस्था देखेगी कि नामावली (On roll) में विद्याधियों की संख्या और उनकी औसतन उपस्थिति अथवा इससे लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे लिखे स्तर अथवा संख्या से कम तो नहीं है:—

वर्ग	कक्षा	नामावली में औसतन विद्याधियों	औसतन उपस्थिति
निम्न श्रेणी की—			
प्राथमिक शालाएं	प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी	३५	७५ प्रतिशत
प्राथमिक वर्ग	प्रथम श्रेणी से पंचम श्रेणी	७५	७५ ”
मिडिल वर्ग	छठवीं श्रेणी से आठवीं श्रेणी	४५	७५ ”

माध्यमिक शाल	नवमी श्रेणी से दसवीं श्रेणी	४०	७५	”
उच्च माध्यमिकशाला	नवमी श्रेणी से ग्यारहवीं श्रेणी	४५	७५	”
छात्रावास		२५	७५	”
संस्कृत संस्थाएं
प्रवेशिका संस्थाएं		१२	७५	”
मध्यमा		६	७५	”
शास्त्री तथा आचार्या		२	७५	”

टिप्पणी:—

किन्तु साथ ही लड़कियों की संस्थाओं में औसतन कम से कम नामांकन (Enrolment), लड़कों की संस्था के उपरोक्त वर्णित नामांकन के ७५ प्रतिशत होगा । लड़कियों की संस्था में औसतन उपस्थिति ६० प्रतिशत से कम न होगी ।

(११) संस्था, संस्था को उचित रूप से चलाने के लिये विभाग द्वारा निकाली गई समस्त हिदायतों (Instructions) का अविलम्ब (Promptly) पालन करेगी ।

(१२) विद्यार्थियों से लिये गये शिक्षण एवं अन्य शुल्क की श्रेणी, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित श्रेणी (Scale) से कम न होगी और बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ये परिवर्तित नहीं की जायेगी ।

(१३) कोई संस्था तब तक के लिये नये पाठ्यक्रम की कक्षा, वर्ग अथवा विषय अथवा परियोजना चालू करने के लिये अनुदान के लिये ग्राह्य नहीं होगी, जब तक कि विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त न हो । यदि संस्था की प्रवन्धिका किसी पाठ्यक्रम, कक्षा, वर्ग अथवा विषय को बन्द करना चाहती है तो विभाग को उसकी सूचना बन्द करने के कम से कम तीन माह पूर्व दी जानी होगी ।

(१४) अप्रशिक्षित (Untrained) अध्यापक, बिना संचालक की अनुमति के तब तक के लिये किसी शाला अथवा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्रशिक्षण योग्यताओं के लिये मुक्त (Exempted) न हो ।

टिप्पणी:—

यह नियम उच्च माध्यमिक शालाओं के लिये, शिक्षण सत्र १९६५-६६ तक लागू नहीं होगा ।

(१५) बिना शिक्षा संचालक की अनुमति के, कोई भी संस्था कर्मचारी (Staff) की दो वर्ष से अधिक समय के लिये अस्थायी नियुक्ति नहीं करेगी ।

(१६) साधारण तथा अध्यापक की अतिवयस्कता वय (Superannuation age) ५८ वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगी तथा सेवा में पदोन्नति/पुनः नियुक्ति (Re-employment) ६० वर्ष की आयु के पश्चात स्वीकृत नहीं की जायेगी । विशेष परिस्थिति में सरकार, विशेषतः स्नातकोत्तर अथवा अनुसंधान कार्य करने वाले अध्यापकों के लिये, इस शर्त को ५ साल तक के लिये त्याग सकती है ।

(१७) सहायता अनुदान उन संस्थाओं के लिये स्वीकृत नहीं किया जायेगा जो कि भूत (Past) काल में शर्तों की पूर्ति में असफल हो गई हो।

(१८) सहायता अनुदान जिस कार्य के लिये स्वीकृत हुआ है, उसी कार्य के उपयोग में लिया जायेगा।

(१९) बिना प्रयोग में लाया गया शेष धन शिक्षण सत्र की समाप्ति के पूर्व विभाग सरकार को समर्पित किया जायेगा।

नियम ४:—कर्मचारी गण (Staff) की सेवा की शर्तें:—

(अ) शिक्षक एवं प्रशासी वर्ग के हर एक सदस्य की सेवा शर्तें, उसके द्वारा, तथा व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका समिति के द्वारा, परिशिष्ट ३ में दिये गये रूप में, लिखित करार से शासित होगी। लघु व्यौरों में परिवर्तन शिक्षा संचालक की अनुमति से हो सकते हैं। व्यक्ति की परीक्षा (Probation) पर नियुक्ति के एक माह के अन्दर करार लिख जाना चाहिये।

(ब) संस्था के कर्मचारीगण के वेतन व भत्ते की श्रेणी, सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में उसी श्रेणी के कर्मचारीगण के लिये निर्धारित श्रेणी से कम न होगा। उच्च वेतन श्रेणी के सम्बन्ध में साधारणतया, सहायता अनुदान केवल सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुसार ग्राह्य होगा। विशिष्ट अवस्था में सरकार उच्च वेतन श्रेणी अनुदान स्वीकार कर सकती है।

(स) संस्था के कर्मचारी स्तर के सदस्यों के लिये, निजी शिक्षा (Private tutions) तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के नियम, उसी तरह की तथा उसी श्रेणी की सरकारी संस्थाओं में निर्धारित नियमों से अधिक (Liberal) नहीं होंगे।

(द) कर्मचारी गण को वेतन, पूरा तथा नियमित रूप से हर माह चुकाया जायेगा तथा उसमें कोई अनधिकृत (Un-authorised) कटौति नहीं की जायेगी। शिक्षा संचालक यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी संस्था की व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका की चेक (cheque) द्वारा वेतन वितरण के लिये निर्देशित कर सकता है।

(य) संस्था के कर्मचारी स्तर का कोई भी व्यक्ति तब तक के लिये पदच्युत (dismissed) अथवा निष्कासित पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बनाने के लिये, उसे उचित अवसर न दिया गया हो, वरन् कि निम्न-लिखित खण्ड लागू न होगा:—

(१) जहां कि एक व्यक्ति आचरण के आधार पर पदच्युत अथवा निष्कासित अथवा पदावनत किया गया है, जिससे कि अपराधिक आरोप के आधार पर उसका दोष सिद्ध हो जाय, अथवा

(२) जहां कि उस व्यक्ति को कारण बतलाने का अवसर देना व्यवहारिक न हो तथा कार्यवाही करने में पूर्व विभाग की नम्रमति प्राप्त कर ली गई हो।

(फ) उपरि-निर्दिष्ट खण्ड (उ) की तरह के दण्ड में आरोपित आदेश' उनमें कारण रखेंगे, और उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को शिक्षाप्रतिनिधि दी जायेगी। तथा एक प्रति विभाग की सूचनाएं एक माह के अन्दर भेजी जायेगी।

(ज) उपरि-निर्दिष्ट खण्ड (य) में दण्ड देने वाली व्यवस्थापिका सभा। समिति अथवा प्रबन्धिका समिति की हर एक आज्ञा में, परिशिष्ट ५ में वर्णित आदेशानुसार पुनर्विचार होगा।

(च) ऊपर खण्ड (ज) में वर्णित पुनर्विचार प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रवन्धिका उसकी प्रति की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर, कार्यान्वित करेगी, जब तक कि ऐसे उपकरण किसी न्यायालय अथवा किसी उच्च प्राधिकार द्वारा स्थगित (Stayed) नहीं कर दिये गये हों।

(स) पुनर्विचार प्राधिकारी के आदेशों में उल्लिखित, यदि कोई भी राशि जिसको प्रवन्धिका बिना पर्याप्त कारणों के चुकाने में अवहेलना करती हो, की अवस्था में संचालक आगामी सहायता अनुदान में से उस राशि की कटौती कर सकता है, तथा, यदि आवश्यक हो तो आगामी (Subsequent) सहायता अनुदान विधेयक में से भी काट सकता है तथा प्रवन्धिका के निमित्त सम्बन्धित व्यक्ति को चुका सकता है। यह राशि संस्था की प्रवन्धिका को वितरण (Payment) समझा जायगा।

(ग) विभाग/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय/स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये P. F. नियम संस्था द्वारा अनुसरणीय हैं।

नियम ५.—वार्षिक पुनरावृत्त अनुदान का निर्धारण.—(अ) वार्षिक पुनरावृत्त अनुदान गत वर्ष के मान्य आवर्ती-खर्च के आधार पर, तथा शिक्षक, प्रशासी एवं क्लास IV वर्ग के लिये स्वी-कारार्थ वार्षिक वृद्धि के आधार पर दिया जायेगा।

(ब) स्वीकार किया गया खर्च नियमों तथा ऐसे दूसरे अनुदेशों, जो कि इसके पश्चात् शिक्षा संचालक द्वारा समय-समय पर निकाले जा सकें, के अनुसार पहुँचेगा।

(स) सहायता अनुदान समिति की सलाह के अनुसार, संस्थाएं श्रेणियों में विभक्त की जायेंगी तथा निम्न प्रकार से सहायता अनुदान प्राप्त करेंगी:—

श्रेणी

A	८० प्रतिशत	गत वर्ष के मान्य खर्च का तथा
B	७५ "	कर्मचारी वर्ग के वृद्धि का
C	६० "	
D	५० "	

विशिष्ट श्रेणी—(शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार प्रयोगात्मक शिक्षण कार्य को चलाने वाली संस्थाएं—६० प्रतिशत।

टिप्पणी ४.—सहायता अनुदान में वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति द्वारा साधारणतया निरीक्षण प्रसूचना (Reports) तथा दूसरी श्रेणी के सिद्धान्तों में सामान्य उन्नति के आधार पर, तीन साल पश्चात् पुनर्विलोकित की जा सकती है।

सहायता अनुदान समिति, परिशिष्ट १० में सूचीबद्ध कसौटी में संस्थाओं की परिस्थितियों का निरीक्षण करने के पश्चात् ही उनको विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित करेगी।

(द) राजस्थान सरकार से किसी साल में कुल आवर्ती अनुदान, लेखा किये हुए कुल स्वीकृत खर्च तथा उसी साल में शुल्क तथा दूसरे आवर्ती साधनों से (जिसमें कि दूसरे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार, सभाओं, समितियों तथा स्थानीय सभाओं द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं) हुई आय के अन्तर से अधिक नहीं होगा।

इस नियम के प्रयोजन के लिए;

- (i) आरक्षित कोष (Reserve Fund) अथवा संपत्ति के किराये से आय,
 (ii) वास्तविक अधिक वसूली की परिधि तक, सरकारी दर से ऊँची दर पर वसूल किये गये शुल्कों से शुल्क आय,
 दूसरे आबतों साधनों से हुई आय की तरह नहीं समझी जायेगी।

उदाहरण.—

(१)	१९६०-६१ में संस्था का खर्च	६२००/—
	अस्वीकृत राशि	२००/—
	स्वीकृत खर्च	६०००/—
	कर्मचारी वर्ग पर संभाव्य वृद्धि इत्यादि	२०-००/—
	गणना की हुई सहायता (Assistance to be calculated on)	१०,०००/—
	शुल्क एवं शुल्क साधनों से संस्था की आय	१,०००/—
	संस्था की श्रेणी B है।	
	सन् ६१-६२ के वजट में अनुदान वितरण करना	६,०००/—
(२)	उपरोक्त उदाहरण में यदि संस्था ने १९६०-६१ में केन्द्रित अनुदान प्राप्त किया हो	१,५००/—
	सन् १९६१-६२ में राज्य सरकार द्वारा वितरित अनुदान	६,०००/—
(३)	यदि संस्था ने १९६१-६२ में केन्द्रीय अनुदान प्राप्त किया हो	३,०००/—
	तो राज्य सरकार से अनुदान, स्वीकृत खर्च और शुल्क तथा दूसरे साधनों से हुई आय के अन्तर के बराबर ही सीमित रहगा	५,०००/—

टिप्पणी १—जब कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कक्षा प्रारम्भ की गई हो, अथवा एक नया प्रयोग या परियोजना हाथ में ली हो, अथवा संस्था को गम्भीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, की विशिष्ट परिस्थितियों में चालू साल के अनुमानित वजट के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि अनुदान को समस्त राशि उसी साल में खर्च नहीं हुई तो बची हुई राशि संस्था से वापिस ले ली जायेगी अथवा आगामी वर्ष के अनुदान में से काट ली जायेगी।

टिप्पणी २—उपनियम (द) से निर्दिष्ट शुल्क तथा धर्ष दण्ड (Fines) से हुई आय में निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा दूसरे माय्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार लेखा परीक्षा विवरण में अलग से वर्णित होंगे:—

- (१) शिक्षण-शुल्क
- (२) ट्यूटोरियल शुल्क
- (३) प्रवेश तथा पुनः प्रवेश शुल्क

(४) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क

(५) कोई दूसरा शुल्क जो कि उपरोक्त शुल्कों में न आता हो, अथवा इसके कि

(अ) विषय शुल्क जैसे कि वाणिज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क आदि

(ब) खेल-शुल्क तथा हस्तकला और कृषि दुग्ध शाला, गृह विज्ञान आदि दूसरे कार्यों के लिए शुल्क, जो कि नियम ६ के उपखण्ड K. M. N. में निर्दिष्ट है।

(६) अर्थ दण्ड

उपरोक्त (अ) तथा (ब) में निर्दिष्ट दूसरे शुल्कों के सम्बन्ध में, कि जैसे विषय-शुल्क, खेल तथा हस्तकला शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य जिसके लिये वे लिये गये हैं, में ही होगा और उनके पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग न होने की दशा में, वह राशि आगामी वर्ष में उपयोग किये जाने वाले छात्र कोष में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका किसी दशा में छात्र कोष का कोई भाग संस्था के चलाने में अथवा कर्मचारीगण को वेतन वितरण में अथवा भवन किराये आदि उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं करेगी।

३—सहायता अनुदान सूची में प्रविष्ट हर एक संस्था को हर साल गत वर्ष के निर्दिष्ट सालाना अनुदान का $\frac{1}{2}$ भाग के बराबर मासिक राशि के रूप में अथवा $\frac{1}{2}$ भाग के बराबर, तिमाही राशि के रूप में अस्थायी रूप से चुकाया जायेगा, जब तक कि चालू साल का अनुदान, अन्तिम समाधान (Adjustment) का ध्यान रखते हुए स्वीकृत न हो जाय।

संस्थाओं की श्रेणी विभक्ति का आधार निम्नलिखित होगा:—

(१) शिक्षण कार्य की श्रेणी का निर्णय संस्था में सबसे ऊँची कक्षा के गत तीन वर्षों की सर्व साधारण परीक्षाओं के औसत परिणामों से, किया जाये।

(२) संशोधन कार्य (Correction Work)

(३) वैयक्तिक ध्यान (Individual Attention)

(४) शिक्षण दक्षता (Teaching efficiency)

(५) संस्था का अनुशासन एवं प्रवृत्ति (अनुशासन के नियम, परिशिष्ट II)

(६) अन्य सह-शिक्षण वृत्तियाँ (activities) यथा सांस्कृतिक जीवन, खेल इत्यादि।

(७) सामुदायिक जीवन को अंशदान (क्षेत्र में विशिष्ट सेवा)

(८) सारे साल की कक्षा वार उपस्थिति।

(९) खेल-कूद, पी. टी. तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तथा साफल्य (Achievement) की सुविधायें।

(१०) भवन तथा सामान के लिए व्यवस्था।

(११) दुराचरण तथा अनियमितता की अनुपस्थिति।

(१२) विद्यार्थियों में निष्प्रवाहित अनुपस्थिति।

(१३) व्यवस्थित विषय एवं विभागों की संस्था।

टिप्पणी—संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया सूचना विधि-वेतन और भविष्य निधि के हिस्से की प्रबन्धक द्वारा दी गई राशि, जो कि प्रबन्धक द्वारा वर्ष के मध्य में अधिभ्रूषित

की गई है, को लेखा-विवरण में आग्र व्यक्त करना पड़ेगा और संस्था के वास्तविक स्वीकृत व्यय के आंकड़े पर पहुँचने के लिए आग्र बताया जायेगी ।

६. स्वीकृत खर्चः—उपरोक्त नियम ५ में निर्दिष्ट स्वीकृत खर्च केवल निम्नलिखित विषय क्रमो से सम्बन्धित होगा :—

(a) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि अंशदान शैक्षणिक कर्मचारियों का $६\frac{३}{४}$ प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूर्ववर्ती जोधपुर राज्य के पूर्व सिविलियन सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों, और C. B. शालाओं, जो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और बूंदी जिलों में म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा चलाई जाती है, के मामलों में $८\frac{३}{४}$ प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(b) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि अंशदान प्रशासी तथा गैर प्रशासी कर्मचारियों का $६\frac{३}{४}$ प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूर्ववर्ती जोधपुर राज्य में पूर्व सिविलियन सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों और C. B. शालाओं, जो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और बूंदी जिलों में म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा चलाई जाती है, के मामलों में $८\frac{३}{४}$ प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(c) लेखन सामग्री तथा मुद्रण खर्च

(d) महंगाई भत्ता लागू सरकारी दर से ज्यादा न हो

(e) कार्यालय संबंधी पत्र-व्यवहार के लिये डाक व्यय टिकट, किराया, महाविद्यालय, तथा निवासाय तथा आंशिक निवासाय उच्च या उच्च माध्यमिक शालाओं के लिए टेलीफोन के खर्च । डाक-व्यय के लिये कुल सीमा निर्धारित की जायेगी ।

(f) जल एवं विद्युत खर्च ।

(g) पंजीयन (Registration) लेखा-जोखा शुल्क एवं संलग्न शुल्क ।

(h) उपकरण तथा विज्ञान सम्बन्धी सामान के पुनरावृत्त खर्च ।

(i) भवन की साधारण मरम्मत (यदि संस्था तथा फर्नीचर आदि के संबंध में हो) मरम्मत पक्के भवनों के एक प्रतिशत तथा कच्चे भवनों के लिए २ प्रतिशत के हिसाब से दी जा सकती है ।

(j) भवन किराया (यदि भवन किराया का है)—तब अवस्थाओं में विभाग संतुष्ट होना चाहिए कि भवन, उसी समाज से बनी हुई समिति का अथवा संस्था को चलाने वाले व्यक्तियों के समूह का तो नहीं है । भवन का उसी समाज अथवा व्यक्तियों के समूह का होने की दशा में किराया स्वीकृत न होगा ।

(नीचे सूचना ५ व ६ देखो ।)

(k) पुस्तको, पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों के लिये पुनरावृत्त खर्च ।

(l) निवासाय संस्थाएं अथवा शिक्षण समितियाँ, जो कि एक से अधिक संस्था चला रही हैं, की दशा में प्रवृत्तिका के ऐसे खर्च जो कि संस्था और समिति की स्थापना एवं बनाने में आवश्यक या अनुपंगिक (Incidental) हो ।

(m) खेल शारीरिक शिक्षा, तथा अन्य सह शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ, जैसे शिविर, वार्षिक महोत्सव (पारितोषिक आदि खर्च) नाटक, सिलण, पर्यटन, भ्रमण सामाजिक मेवायें आदि, के लिए पुनरावृत्त खर्च ।

(n) कृषि दुग्धालय गृह विज्ञान आदि हस्तकलाओं के लिए उनसे अर्जित आय के कटाने के पश्चात् पुनरावृत्त खर्चें ।

(o) शिक्षा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में सरकार अथवा विभाग द्वारा संचालित सभाओं में उपस्थित होने के लिए अध्यापकों को यात्रा खर्च ।

(p) मशीनरी अथवा विज्ञान विषयों, गृह विज्ञान, अंग्रेजी शरीर शास्त्र आदि के लिए अध्यापक एवं व्याख्याताओं (Lecturers) को पदों के विज्ञापन के लिए खर्चें जो कि वर्ष में दो विज्ञापन से अधिक के लिए नहीं ।

(q) भाड़, डस्टर तथा पानी के लिये मिट्टी के घड़े तथा रस्सी आदि के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार छोटे मोटे खर्चें ।

(r) केवल अनुसंधान संस्थाओं के लिए अनुसंधान विवरणिका ।

(s) पुस्तकों की जिल्दें [Book-Binding] केवल सर्वसाधारण पुस्तकालयों के लिए ।

(t) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए खर्च (सरकारी कर्मचारी के सेवा नियम के अनुसार)

(u) शाला भवन में सीमित मात्रा तक करो का खर्च यदि वास्तव में व्यवस्थापक द्वारा चुकाया गया हो ।

(v) शिक्षा संचालक की पूर्व अनुमति को ध्यान में रखते हुए, शाला के बच्चों के साथ यात्रा में जाने वाले अध्यापकों को यात्रा व्यय ।

(w) किराये के प्रमाण के लिए P.W. D. से प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए खर्च ।

(x) एक नई संस्था, जो कि इन नियमों के लागू होने के पश्चात् अस्तित्व में आ रही है, सहायता अनुदान पाने की अधिकारिणी तब तक नहीं होगी जब तक कि विभागीय मान्यता की तारीख से एक, शैक्षणिक सत्र तक सफलता पूर्वक चालू न रही हों तथापि अधिक विशिष्ट परिस्थिति में सरकार द्वारा इस शर्त को छोड़ना पड़ सकता है । ऐसी अवस्था में, प्रथम वर्ष के स्वीकृत बजट के विपरीत अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है । ऐसे अनुदान वर्ष भर के अन्दर उठाये जाने वाले शिक्षक वर्ग के संभावित वेतन के आधे से अधिक नहीं बढ़ेंगे तथा प्रबन्धिका की इच्छानुसार मासिक, तिमाही तथा अर्द्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जायेगा

५. छात्रावास पर खर्चें—छात्रावास के लिए स्वीकृत खर्चें निम्न विषय क्रमों से सम्बन्धित होंगे:—

(i) प्रतिपालक (Warden) अथवा निरीक्षक (Superintendent) अथवा अधीक्षिका (matron) का वेतन अथवा भत्ता ।

(ii) विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृत किया हुआ प्रशासी एवं चतुर्थ श्रेणी (Class IV) का स्थापन ।

(iii) साधारण कार्यालय सम्भाव्यतायें (Contingencies)

(iv) संस्थाओं के एक से अधिक छात्रावास चलाने की अवस्था में, प्रबन्ध के ऐसे खर्चें जो कि संस्था के स्थापन एवं बनाये रखने के लिये आनुवंशिक (Incidental) तथा आवश्यक हो, जैसे कि उपर्युक्त नियमों में उपबंधित (Provided) है ।

टिप्पणी

१-(१) में वर्णित केन्द्रीय कार्यालय के खर्चे तब ही अनुदान के लिए स्वीकृत होंगे, जब कि कुल समिति स्वीकृत खर्चा १ लाख २० सालाना से अधिक हो तथा समिति के द्वारा कम से कम तीन संस्थाएं चलाई जा रही हों। संस्थाओं से अभिप्रायः केवल वे जो कि विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए संस्थाएं हों/संस्था विभाग अथवा शाखा अथवा उसी संस्था की गतिविधि की प्रकृति की हो, से है।

२. निवृत्ति वेतन कोष अथवा निवृत्ति पारितोषिक योजना को संस्था द्वारा दिये गये अंशदान के कारण से व्यय अथवा पुराने अध्यापकों को चुकाया हुआ निवृत्ति वेतन या निवृत्ति पारितोषिक के कारण साधारणतया तब तक सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए स्वीकृत नहीं किये जायेंगे तब तक कि अधिनियम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, दशतें कि राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवाओं से प्राप्त किये गये कर्मचारियों के मामले में उनका निवृत्ति वेतन और अवकाश वेतन अंशदान स्वीकृत व्यय में स्वीकृत किया जायेगा।

३. मृत अध्यापकों की विधवा पत्नियों की निवृत्ति वेतन के कारण से व्यय साधारण तथा सहायक अनुदान के लिए तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि निवृत्ति वेतन अनुदान के लिए नियम सरकार द्वारा अल्प रूप से स्वीकृत न हो।

४. संस्था को किराया खर्चा विशेष काल के लिये, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शोभा केवल तभी ग्राह्य होगा जब कि भवन वास्तव में किराये पर लिया गया हो तथा किराये नामे में किराये की अवधि तथा शर्तें लिखित एवं पंजीकृत हो, जहां उद्भव निकाय ने ट्रस्ट (Trust) को भवन, शिक्षण संस्था को चलाने के धर्मार्थ उद्देश्य के लिये दान में दिया हो किराया ग्राह्य न होगा।

जहां गैर सरकारी संघ द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्थाओं के लिये प्रतियोगित भवन की मरम्मत, बड़ाव तथा परिवर्तन के लिये पहले ही सहायता अनुदान दिया जा चुका हो, कोई किराया-ग्राह्य नहीं होगा।

ऐसे मामलों में जहां कि शाला को चलाने का कार्य संस्थाओं अथवा समिति जो कि उद्भव संस्था से अलग हो को सौंपा गया हो तथा वे उसी भवन का उपयोग करते हो जिसको कि उद्भव संस्था ने शाला के लिये बनवाया था तथा तब नयी प्रबन्ध समिति को एक बन्ध नाम (Bond) अथवा करार (Agreement) लिखना आवश्यक है और इसी आशय से उसे पंजीकृत करवाना है कि शाला को चलाने के लिए भवन के उपयोग का किराया नई संवित प्रबन्धिका द्वारा उद्भव संस्था को चुकाना पड़ेगा, समिति के द्वारा किराया सहायक-अनुदान के लिये ग्राह्य होगा।

५. भवन की मरम्मत का जो किराये पर हो, खर्चा, सहायता अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा क्योंकि ऐसी मरम्मत भवन स्वामी द्वारा की जानी चाहिये, जब तक कि इसके लिए विशेष प्रावधान हो।

६. न्याय व्यय (Legal expenses) सहायता अनुदान के लिए ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वे अनावर्तक (Non recurring) व्यय हैं, तो भी असाधारण परिस्थितियों में संचालक की खर्च की ग्राह्यता के सम्बन्ध में आजाओं के लिये संगत निवरण अभिविष्ट (Revised) करना चाहिये।

७. ऋण वापसी:—ऋण वापसी अथवा राजस्व कोष की राशि का स्थानान्तरण, सहायता अनुदान के उद्देश्य से ग्राह्य खर्च पर नहीं है।

८. खर्च का अवशिष्ट भाग:—ऐसा खर्चा जो कि किसी पहले के समय के देयधन की पूर्ति के लिए उठाया गया हो, परन्तु जो कि उस वार्षिक खर्च में सम्मिलित हो, जिस पर कि अनुदान आधारित है, सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए ग्राह्य नहीं होगा।

९. अधिकृत (Authorised) खर्च की अधिकतम सीमा परिशिष्ट ६ में वर्णित है।

१०. उपरोक्त किसी भी विषयक्रम पर कोई नये अथवा अलग खर्चों जो कि स्वीकृत बजट में उपबन्धित नहीं हैं, के लिये विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

७. अनावर्त्तक (Nonrecurring) अनुदान:—(अ) अनावर्त्तक अनुदान, कुल स्वीकृत एवं वास्तविक खर्च के ६० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ब) अनावर्त्तक अनुदान निर्माण, मरम्मत, एवं भवन विस्तार (छात्रालय सहित) के लिए उपकरण (Furniture) एवं सामान की खरीद के लिए तथा पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद के लिए, दिये जा सकते हैं।

(ग) बस की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियन्त्रित मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा। साधारणतया प्रतिस्थापन १० साल के समय के प्रश्नात स्वीकृत किया जायगा। साधारणतया ऐसे अनुदान केवल बालिका संस्थाओं मान्टेसरी शालाओं के लिए ही विचारित किये जायेंगे तथा शहरों में स्थित अथवा निवामार्थ स्थानों से दूर संस्थाओं को ही पूर्वाधिकार दिया जायगा।

टिप्पणी

बालिका संस्थाओं के मामले में अध्यापिकाओं के मामले में अध्यापिकाओं के निवासस्थान के लिये बास गृह (Quarters) निर्माण के लिए उठाये गये खर्च सहायता अनुदान के लिए ग्राह्य होंगे।

(द) सहायता अनुदान केवल उन्ही विषय में दिया जायेगा जहां कि खर्च की योजना एवं अंजन (Estimate) योग्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं जैसे कि परिशिष्ट ५ में उल्लेखित शक्तियां।

(य) भवन निर्माण के लिये २५००० रुपये तक की योजनायें एवं आगवन (Estimates) जिले से सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांचे एवं प्रति हस्ताक्षरित (Countersigned) किये जा सकते हैं, यदि (योजनायें एवं आगवन) किसी योग्यताप्राप्त अभियन्ता (Engineer) अधिकर्मकर (Over seer) के द्वारा तैयार की गई हो।

२५००० रुपये से अधिक की योजनायें एवं आगवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निमित्त एवं प्रमाणित होने चाहिए तथा उचित मार्ग से शिक्षा संचालक की प्रस्तुत करना चाहिये।

(फ) सहायता अनुदान सुयोग्य अधिकारी द्वारा संस्था के लिए स्वीकृत एवं छोड़ा (Released) जायेगा, जैसा कि परिशिष्ट ५ (मद Item) में उल्लेखित, शक्तियां। अनुदान की स्वीकृति से पूर्व सुयोग्य अधिकारी संतुष्ट हो जायेगा कि:—

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (Chartered accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया

हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) निर्माण की लागत के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों का प्रमाण पत्र की व्यय स्वीकृत योजना अथवा परियोजना के अनुसार है।

(ज) साधारणतः सहायता अनुदान स्वीकृत निर्माण परियोजना के पूर्ण होने पर ही छोड़ा जाता है। विशिष्ट अवस्थाओं में जहाँ कि अनुदान की मध्यवर्ती किश्तें स्वीकृति के लिये निश्चित की गई है, सुयोग्य अधिकारी संतुष्ट हो जायेगा, कि

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया हुआ व्यय-विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) संचालक, निरीक्षक अथवा विद्यालय निरीक्षक का किये कार्य एवं उपयोग में लाये गये सामान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

स्वीकृत किश्तें, स्वीकृत एवं वास्तविक व्यय के ५० प्रतिशत से अधिक की नहीं होंगी। अन्तिम भुगतान के लिये, प्रमाण-पत्र जैसा कि ऊपर (फ) में है, आवश्यक होगा।

(घ) सभी अवस्थाओं में स्वीकृत राशि के भुगतान के समय या इसके पूर्व अनुदान ग्राही (Grantee) एवम् अनुदान-कर्ता राज्यधिकारी इन अभिप्राय की एक लिखित सविदा हस्ताक्षरित करेंगे कि, अनुदान इस शर्त पर दिया जा रहा है व स्वीकार किया जा रहा है कि, इन नियमों में वर्णित समस्त शर्तें मान्य होंगी व अनुदान-ग्राही (Grantee) वेदान के लिये आश्वासन देगा व पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करायेगा। ऐसी अवस्था में जब कि, अनुदान राज्य सरकार द्वारा किसी भवन के निर्माण, सरोवर, सुधार अथवा मरम्मत के लिये दिया गया हो, वह भवन न तो हस्तान्तरित ही किया जावेगा तथा न ही विभाग की लिखित आज्ञा के बिना किसी भी समय अन्य उद्देश्य के लिये काम में लाया जायेगा। साधारणतया ऐसे भवन पर दी गई अनुदान की राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार का प्रथम गृहणाधिकार होगा जब कि, या तो भवन को हस्तान्तरित किया जा रहा हो या उसे किसी ऐसे उद्देश्य के लिये काम में लेने का प्रस्ताव हो जो उस उद्देश्य से भिन्न हो कि जिसके लिये भवन का निर्माण किया गया था। ऐसे भवन बाजार-भाव निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। उपरोक्त शर्तें ऊपर वर्णित सविदा में अवश्य सम्मिलित की जायगी।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये जाने वाले सविदा का प्रारूप परिशिष्ट ८ के अनुसार, ऐसे सुधारों के साथ जो शिक्षा संचालक द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हो, होगा।

(६) (i) वही निर्माण परियोजनाओं के उपक्रम करने वाली मजबूत बुनियाद पर स्थापित संस्थाओं की अवस्था में, सरकार, अपनी इच्छा से सहायता अनुदान की प्रथम किश्त व्यय के पेशगी में दे सकती है।

८. कार्य दिवस:—यदि किसी संस्था ने ११ मार्च को समाप्त होने वाले १२ महिनों में २०० दिन से कम कार्य किया हो, तो नियमानुसार मालाना अनुदान की चुकौति (Payable) में अनुपातिक कमी की जा सकती है।

६. सहायता अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र:—किसी भी वित्तीय वर्ष के सहायता अनु-

दान अथवा विशिष्ट अनुदान के लिये प्रार्थनापत्र हर साल के अगस्त माह में निर्दिष्ट प्रपत्रों (forms) में होना चाहिये। ऐसे प्रार्थना पत्र निम्नलिखित बातों सहित होगा:—

(१) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) से लेखा परीक्षण किया हुआ, पिछले साल की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण।

टिप्पणी

संस्थाएँ, जिनके वार्षिक खर्चें २०००/रुपये अथवा इससे कम प्रति वर्ष हैं, वे चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अपने लेखा के परीक्षण करवाने से मुक्त हैं।

(२) संस्था जिनके लिये अनुदान मांगा जा रहा है, की प्रबन्धिका से अधिकृत व्यक्ति से एक घोषणा कि, वार्षिक व्यय की राशि से तिथुनी के करीब राशि इस की परिसम्पत् है तथा ऐसी परिसम्पत् (सूची नली करनी चाहिये) सारे ऋणों से मुक्त है, और प्राप्त किये हुए सहायता अनुदान से उत्पन्न आशा बड़ी हुई परिसम्पत् इसमें सम्मिलित नहीं है और न ही सहायता अनुदान के से न्यूनता पूर्व की हुई ऐसी परिसम्पत् से आय, संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए, तथा संस्था कर्मचारी वर्ग के वेतन की चुकौती करने के लिये जैसा कि सरकार अथवा सुयोग्य अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट है, प्रबन्धिका को योग्य बनाने में पर्याप्त होगी।

टिप्पणी

बशर्ते कि शर्त को, संस्था के प्रथम तीन वर्षों में जोर नहीं दिया जायेगा।

नियम

१०. अनुदान में कमी, वापसी, रोकना आदि:— सहायता अनुदान स्वीकृति देने वाले अधिकारी की इच्छा में रोके जाने, कमी करने अथवा वापसी करने के लिये उत्तरदायी होगी, यदि इसकी [स्वीकृति देने वाले अधिकारी] सलाह में, संस्था इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को संतुष्ट करने में असमर्थ हो गई है, लेकिन इस नियम के अन्तर्गत कोई ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व प्रबन्धिका को सूचित किया जायेगा तथा लगाये गये अभियोगों के विरुद्ध कारण बताने के लिये तथा इसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया जायेगा। अनुदान को रोकने, कम करने अथवा वापसी के लिये अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सरकार से अपील के लिये प्रबन्धिका को स्वतंत्रता होगी, तथा यह अपील कथित आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो माह के अन्दर होगी।

११. प्रार्थना पत्र को जांचने लिये समिति:—

- [i] नयी संस्थाओं के लिये पुनरावृत्त [Recurring] अनुदान
- [ii] सहायक सूची में रही हुई संस्थाओं के पुनरावृत्त अनुदान को प्रतिशत के वृद्धि तथा
- [iii] अपुनरावृत्त अनुदानों के लिये सभी प्रार्थना पत्र निम्नलिखित सदस्यों से बनी हुई समिति द्वारा विचार किये जायेंगे तथा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को सिफारिश किये जायेंगे। समिति इन नियमों, सरकारी आदेशों तथा इसके लिये समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों तथा बजट में व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा:—

[१] [प्राथमिक एवं माध्यमिक] शिक्षा संचालक..... संयोजक

[२] महा विद्यालय शिक्षा संचालक, [जब कि महाविद्यालयों के प्रकरण (cases) विचरित हों]

(३) माध्यमिक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष ।

(४) शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि ।

(५) वित्तीय विभाग का प्रतिनिधि ।

(६) संस्कृत शिक्षा संचालक, जब कि संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण पर विचार हो ।

(७) हर श्रेणी का उपशिक्षा संचालक, जबकि उसही श्रेणी से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार हो ।

(८) तीन मुख्य गैर सरकारी शिक्षण विशेषज्ञ ।

(९) शिल्प शिक्षण संचालक, शिल्प शिक्षा के प्रस्तावों के लिये ।

शिक्षा संचालक, उपरोक्त समिति को वित्तीय वर्ष में उपरोक्त अनुदानों के लिए ग्राह्य हो सकने वाली राशि की सूचना देगा, जब कि उपरोक्त समिति सहायता अनुदान के प्रार्थनापत्रों के विचारार्थ मिलती है ।

१२.—स्वीकृति देने वाला अधिकारी:—

(i) नई संस्थाओं को ५०००० रुपये से ऊपर (व्यय की गणना) के पुनरावृत्त अनुदान सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे ।

(ii) शिक्षा संचालक व्यय तथा मंजूरी को स्वीकृत करने का अधिकारी होगा:—

(अ) सहायता अनुदान सूची में स्थित संस्थाओं को पुनरावृत्त अनुदान इन नियमों के अनुसार होगा ।

(ब) ५०००० रुपये तक के अपुनरावृत्त अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की स्वीकृति से ।

(स) २५००० रुपये तक के अपुनरावृत्त अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की सहमति के ।

१३. सम्पत्ति का हस्तान्तरण:—संस्थाएं अथवा सभा, जिसने कि इन नियमों के अनुसार सहायता अनुदान प्राप्त किया है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को बिना विभाग/सरकार की सहमति के सम्पत्ति का स्थानान्तरण, सिवाय अनुपयोग वस्तुओं के निवटारे के, नहीं करेगी ।

१४. रजिस्टर इत्यादि का परिचक्षण:—समस्त वस्तुएं जो कि संस्था निधि से समय २ पर खरीद की जाती है, को सामग्री पंजिका में प्रविष्ट किया जायेगा, जिनको प्रत्येक संस्था अनुदान सूची के अनुसार परिचक्षित करेगी । संस्था प्रमुख इसके ठीक मंरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा । तमाम बीजकों (Bills) पर, जो कि चुकारे के लिये प्राप्त किये गये हैं निम्न प्रमाण-पत्र होगा ।

“प्राप्त की गई वस्तु के लक्षण अच्छे हैं, तादाद सही है और विशिष्ट गुणों के अनुसार है, दरें बाजार में प्रचलित दरों से अधिक नहीं हैं, तथा सामग्री पंजिका के पृष्ठ संख्या में प्रविष्ट कर ली गई है ।”

१५. निविदा (Tender) के द्वारा क्रय—समस्त प्रकार का क्रय, जो २५० रुपये के मूल्य से अधिक हो, उत्पादक वितरक और ठेकेदारों में निविदा प्राप्त करके खरीद किया जायेगा ।

जहां तक सम्भव हो, सबसे निम्ननिविदा को स्वीकार किया जायेगा, जब तक कि किसी विशेष कारण से प्रबन्ध कारिणी इसके अतिरिक्त तय न करे, जो कि अभिलिखित होना चाहिये ।

इन नियमों के प्रावधानों में छूट देने का सरकार का अधिकार—सरकार विशेष मामलों में संस्था को इन नियमों में उल्लिखित एक या अधिक परिस्थितियों में छूट स्वीकार कर सकती है ।

१६. अधकमण (Super-session):—राजस्थान शिक्षा अधिनियम, १९५७ के अध्याय १७ के उल्लिखित वर्तमान अनुदान नियमों (जैसा कि इसके द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है) का इसके द्वारा अधिकमण करती है ।

सहायृतों (Enclosures) की सूची

परिशिष्ट	१	नियम संख्या ३ के उपनियम (V)— प्रबन्ध कारिणी का गठन
"	२	अनुदासन
"	३	नियम संख्या ४ का उपनियम (अ)— प्रबन्ध कारिणी समिति तथा अध्यापक
"	४	प्रबन्ध कारिणी समिति तथा संस्था का प्रधान
"	५	नियम संख्या ४ के उपनियम (जी), नियम संख्या ११, का उपनियम (बी)— शक्तियां
"	६	नियम संख्या ६ की टिप्पणी संख्या ६—खर्च की अधिकतम सीमा
"	७	चतुर्थ श्रेणी की शृंखला
"	८	नियम संख्या ७ का उपनियम (डी) करण पत्र (Deed)

परिशिष्ट १.

प्रबन्ध मण्डलों का निर्माण

(१) प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल में १५ सदस्य से अधिक नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त समाज द्वारा चलाई जाने वाली संस्था का प्रधान या संस्थाओं के प्रधान शामिल होंगे ।

(२) प्रबन्ध में किसी एक समुदाय, सम्प्रदाय या जाति का हिस्सा २/३ से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(३) कुल सदस्यों के १/३ भाग से वान देने वाले या चंदा देने वाले कम नहीं होने चाहियें ।

(४) प्रबन्धकों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था या संस्थाओं के अध्यापक वर्ग में से कम से कम एक सदस्य अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये ।

(५) शिक्षा विभाग प्रबन्ध समिति में एक सदस्य भेजेगा जो कि शिक्षा विभाग का उच्च अधिकारी या प्रमुख अर्थशास्त्री होगा।

नोटः—प्रबन्ध समिति या मण्डल जो कि तीन संस्था से अधिक न चलाती हो, या कम से कम हाईस्कूल स्तर पर चलाती हो, जिसका वार्षिक व्यय तीन से अधिक न हो तो मनोनयन संचालक द्वारा किया जायगा। प्रबन्ध मण्डल अगर तीन संस्था से अधिक चलाती हो जो कि कम से कम हाईस्कूल स्तर पर हो, जिसका खर्चा तीन लाख से अधिक हो तो इस स्थिति में शिक्षा संचालक की सलाह से सरकार मनोनयन करेगी।

(६) प्रबन्धको द्वारा चलाई जाने वाली संस्था या संस्थाओं में विद्यार्थियों के संरक्षकों की ओर से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित किया जावेगा।

(७) उप वाक्य ४, ६, ७ के अन्तर्गत प्रबन्धको द्वारा चलाई जाने वाली संस्था में से प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल के दूसरे सदस्यों द्वारा एक पुराना विद्यार्थी चुना जावेगा।

नोटः—(१) दान देने वालेः—वे जिन्होंने कम से कम २५० रु० एक ही साथ दिया हो, या ३ रु० प्रतिमास के हिसाब से कम से कम एक साल तक दिया हो, दान देने वाले कहे जायेंगे। संस्थायें अपनी अपनी आवश्यकतानुसार दान या चन्दे की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है।

(२) दान देने वाले व निर्माण करने वाले एवं अवैतनिक सदस्य (अगर कोई हो) प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल उप वाक्य ३ के अनुसार सदस्यों का चुनाव कराने के लिए (जो भी उनके द्वारा निर्धारित की जावे) एक महा विद्यालय का चयन करेगी।

(३) नाम निर्देशन करते समय विभाग यह देखेगा कि प्रधान, जो कि संस्था के प्रधान के पद पर मनोनीत किया जायेगा, निम्न श्रेणी का नहीं है।

परिशिष्ट २.

शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन के नियम

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों को अनुशासन से सम्बन्धित निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए।

(१) कक्षा में हुई नियम व अनुमित आज्ञा-पालन यथार्थ में होना चाहिये।

(२) संस्था के विरोध में कोई भी मतव्य प्रकट करे, या वृत्तान्त दे, तो दंड देना चाहिये।

(३) संरक्षकों को यह समझा देना चाहिए कि वे प्रबन्धको को आज्ञा नहीं दे सकते बल्कि प्रबन्धकों को यह अधिकार हैं कि वे शिष्य को अपनी संस्था में भर्ती करें अथवा न करें।

(४) विनय, भाषण व व्यवहार में नम्रता उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार व्यक्ति और कपड़े की सफाई।

(५) कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था ऐसे छात्रों को, जो कि संक्रामक या घूत की बीमारी का रोगी हैं, उपस्थित होने की अनुमति नहीं देगी।

(६) पढ़ते समय व्यक्ति जो कि १६ साल से ऊपर है, समस्त सार्वजनिक सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतन्त्र है। पढ़ते समय १६ से कम उम्र के व्यक्ति को कालेज या स्कूल का प्रधान, संर-

क्षक को सहमति से किसी भी प्रकार की सभा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्ध लगा सकता है, अगर कालेज या स्कूल के प्रधान को इसमें आपत्ति हो ।

(७) पढाई के समय १८ वर्ष से अधिक आयु होने पर संगठन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता है, परन्तु जिनकी नीति या कार्यक्रम हिंसा के विचारों को फैलाना व उनमें सम्मिलित करना है अथवा जो हिंसा को प्रयोग में लेते हैं, को छोड़कर ।

(८) व्यक्ति पढ़ते समय समस्त शिक्षण सम्बन्धी, सामाजिक व धार्मिक संघों की गतिविधि में भाग ले सकता है ।

(९) इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी राजनैतिक व धार्मिक संगठनों को प्रबन्ध समिति के सदस्य नहीं बन सकते, जो सम्प्रदाय विरोधी हो, या उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय भाग लेते हो ।

परिशिष्ट ३.

एकरारनामों का प्रपत्र

यह एकरारनामादिनको (जो कि बाद में अध्यापक पुकारा जाएगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समितिके बीच किया जाता है, समिति अध्यापक को सेवायुक्त करने की सहमति देती है, और अध्यापक पद पर इन शर्तों के साथ नौकरी करने की सहमति देता है:—

(१) अध्यापक का सेवाकाल दिनांक.....१९ से प्रारम्भ हो जायेगा, वह प्रथम बार एक वर्ष तक परीक्षण के तौर पर नियुक्त किया जायेगा, किसी भी स्थिति में परीक्षण का काल दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा, दो वर्ष समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक सुयोग्य या उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसकी नियुक्ति समाप्त हो जावेगी ।

(२) परीक्षण काल के समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक को स्थायी किया जाता है तो मासिक वेतनवेतन क्रम के अनुसार होगी ।

(३) उपरोक्त मासिक वेतन जिस माह में देय हो, उसी माह में नियमित रूप से दी जायेगी ।

(४) अध्यापक का कर्तव्य न तो स्कूल भवन के स्थान तक और न कक्षा को पढ़ाने के लिए स्कूल खुलता है, उस समय तक ही स्थिर है । अध्यापक को अपना कर्तव्य पालन के लिए उन समस्त समय कार्यों को करना पड़ेगा जिसकी प्रधानाध्यापक को आवश्यकता हो । अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे प्रत्येक समय समस्त स्थानों पर, समस्त आज्ञाओं का, जो कि संस्था के प्रधान द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, माननी होगी । जो कार्य स्कूल से सम्बन्धित न हो, उसके द्वारा नहीं करवाया जायेगा, स्कूल/कालेज/संस्था के लिए दान व चन्दा इकट्ठा करना उसके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है । परन्तु वे स्वेच्छा से इस प्रकार का कार्य करे तो रोक नहीं है ।

(५) घंटों के बीच की अवधि के अलावा जब स्कूल कम से कम क्रमागत चार दिनों के लिए बन्द होता है, तो अध्यापक, जब तक प्रधानाध्यापक से लिखित अनुमति प्राप्त न करले, स्टेशन जहां स्कूल स्थित है नहीं छोड़ सकेगा ।

(६) अध्यापक को राजस्थान सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जायगा ।

(७) (i) इस वाक्य के उपवाक्य (३) के अनुसार समिति बिना सूचना के कितनी भी समय नियमित सभा में प्रस्ताव पास करके अध्यापक को निम्न में से एक या अधिक अपराध करने पर कार्यच्युत कर सकती

(१) संस्था के प्रधान या प्रबन्धक की आज्ञा भंग करना या आज्ञाओं की अवज्ञा करना

(२) जानबूझ कर कार्य की अवज्ञा

(३)

अध्यापक प्रस्ताव पास करने के ३० दिन के अन्दर समिति के निर्णय पर द्वितीय सभा में पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है । गर्भित इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभा बुलायेगी, दूसरी सभा में अध्यापक अपने मामले से सम्बन्धित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है । वह स्वयं उपस्थित होने की इच्छा करता है तो हो सकता है, व सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे सकता है । यदि अध्यापक समिति की प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थनापत्र नहीं देता है, और समिति दूसरी सभा में प्रस्ताव को स्वीकृत कर देती है, तो अध्यापक को कार्यच्युत करने की दूसरी बार सूचना नहीं दी जावेगी, परन्तु उसे प्रस्ताव की एक लिखित प्रति जिसमें कार्यच्युत करने के कारणों का विवरण हो, भेजी जावेगी । उसे जब से कार्यच्युत किया या उन दिनों के साथ उसे उसका वेतन चुकाना होगा, परन्तु उसे स्कूल का रुपया या स्कूल सम्पत्ति अथवा उसकी कोमत जिसका उसने दुरुपयोग किया है, या उसने गलती से अधिकार में रोक रखा है, उसका भुगतान करना होगा ।

(ii) उपरोक्त कारणों से अध्यापकों को कार्यच्युत करने के स्थान पर समिति प्रस्ताव पास करके अल्प दण्ड दे सकती है, जैसे निश्चित समय तक वेतन कम करके अथवा स्याई व अंस्याई रूप से उसके वेतन में वृद्धोत्तरी रोक करके, या कार्य च्युत करने के समय का वेतन हरण करके, अगर कोई हो साधारण दण्ड दे सकती है । उपवाक्य (१) के अन्तर्गत अध्यापक समिति को पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र देता है, यह समिति की इच्छा पर निर्भर है कि उसकी अपील स्वीकार करे अथवा नाम-जूर करे, या उपरोक्त लघु दण्ड के स्थान पर कार्यच्युत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस प्रकार के मामले में अध्यापक का कार्यच्युत का प्रस्ताव आखिरी होगा और कार्यच्युत के प्रस्ताव की दूसरी बार सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

(iii) अध्यापक के दण्ड देने या कार्यच्युत करने के लिए सभा बुलाने से पहले समिति या प्रबन्धक अध्यापक के विरुद्ध लगाये दोषों का या खास दोषों का समय और स्थान के साथ एक विवरण अध्यापक को देना होगा । और कम से कम दस दिन का समय उसे लिखित उत्तर देने के लिए देना होगा । समिति की विचाराधीन सभा उपरोक्त दोष या दोषों पर विचार कर सकती है, समिति या प्रबन्धक सदस्य को कार्यच्युत कर सकता है । अगर अध्यापक की इच्छा अपने मामले को समझाने के लिए समिति के सामने स्वयं उपस्थित होने की है, तो हो सकता है । और सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे सकता है ।

नोट:—प्रबन्धक का यह कर्तव्य है कि अध्यापक के, जिसको कार्यच्युत किया गया है, दोषों

का उत्तर पाने के एक मास के अन्दर सभा बुलायें । जब तक उसे, कार्यच्युत होने के समय से लेकर मामला तय नहीं हो जाय तब तक आजीविका के लिए उसके वेतन का एक चौथाई भत्ता चुकाना चाहिए ।

(iv) अगर अध्यापक अपने को दोषों के विरुद्ध निर्दोष सिद्ध कर देता है, तो उसे अपने पद पर पूर्व अवस्था के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और कार्यच्युत होने के समय का उसका वेतन चुकाया जायेगा ।

(v) वाक्य १ के अनुसार जब अध्यापक परीक्षणकाल में हो तो प्रबन्ध समिति किसी भी समय इस एकरारनामे को एक माह का लिखित नोटिस देकर या अग्रिम माह का वेतन देकर निकाल सकती है । अध्यापक भी एक माह का संस्था के प्रधान के जरिये समिति को लिखित नोटिस देकर या समिति को एक माह का वेतन जमा करा कर एकरारनामा तोड़ सकता है ।

(६) परीक्षणकाल के समाप्त होने के तीन माह बाद एकरारनामा समाप्त करने की सूचना प्राप्त न हो, या परीक्षणकाल बढ़ाया जाने की सूचना अध्यापक को न मिले तो उसकी नियुक्ति स्थायी समझी जायेगी ।

(१०) जब अध्यापक को स्थायी कर दिया गया हो तो वाक्य ७ के अनुसार न तो अध्यापक न समिति ही एकरारनामे को तोड़ सकेगी । सिवाय-या तो ३ माह की लिखित सूचना देकर या अध्यापक उस समय जो प्राप्त कर रहा है, एक दूसरे को जमा कर एकरारनामा तोड़ा जा सकेगा ।

समिति किसी भी स्थिति में एकरारनामे को नहीं तोड़ सकेगी जब तक कि समिति की सभा में इस पर पड़ने वाला प्रभाव के लिए प्रस्ताव पास न कर लिया हो, खासतौर से प्रस्ताव में उद्देश्य व प्रमुख कारण दिये जाने चाहिए । ये कारणः—(१) अदक्षता, (२) आर्थिक कमी के कारण सामान्य छूटनी करना, (३) विषय के समाप्त होने पर (४) कक्षा या वर्ग के समाप्त होने पर ।

(११) अध्यापक को परीक्षा व निजी ट्यूशन के लिए संस्था में लागू नियमों का पालन करना पड़ेगा ।

(१२) अगर अध्यापक की इच्छा किसी दूसरे स्थान पर कार्य के लिये प्रार्थना पत्र देने की है तो प्रार्थना पत्र संस्था के प्रधान द्वारा भेजा जायेगा ।

(१३) अगर अध्यापक वाक्य ७ या ९ का उल्लंघन करता है तो उसका वकाया वेतन जब्त किया जावेगा और समिति उसको सेवा से मुक्त कर सकती है या निकाल सकती है, जैसी भी स्थित हो ।

(१४) शिक्षा संचालक की पूर्व (लिखित) स्वीकृति के बिना समिति वाक्य ८ में आये अधिकारों को एक जनवरी से ३१ मार्च के बीच काम में नहीं लेगी । वाक्य ८ में तीन माह की सूचना में छुट्टियाँ शामिल नहीं की जावेगी ।

(१५) इसी तरह किसी भी अध्यापक को शिक्षा संचालक की पूर्व लिखित स्वीकृति बिना सत्र के अन्त में सेवा मुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

(१६) इस एकरारनामे के उप-वाक्य ७ के अन्तर्गत समिति कोई दण्ड देना तय करती है, तो समिति अपना निर्णय तत्काल काम में लेगी, और अध्यापक उसका तत्काल पालन करेगा ।

सहायक अनुदान नियम की परिशिष्ट ३ के अन्तर्गत उसे अपोल अधिकारी के पास प्रसोल करने का अधिकार है ।

(१७) अपोल के समस्त मुकद्दमों के निर् विभाग का या सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । निर्णय किये मामलों के बारे में किसी भी दीवानी अदालत में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकेगा । एकरारनामे को तोड़ने के लिए दूसरी पार्टी ने तो मुकद्दमा ही चला सकती है और न पंचायत को ही माँप सकती है जब तक कि इस भगड़े के प्रश्न को संचालक शिक्षा के पाम न भेज दे । भगड़े को मुलमाने के लिए उचित समय देना चाहिये, परन्तु दो माह से अधिक नहीं ।

नोट:—प्रगेर प्रबन्ध ३ माह तक अपोल सुनने वाले अधिकारी का ध्याय पालन करने में असफल रहता है तो ७ वीं रकम अव्यापक को दी जाने वाली है, वह रकम शिक्षा संचालक संस्था के सहायक अनुदान बिल में से काट कर, प्रबन्ध को सूचना देकर, सम्बन्धित अव्यापक को चुका देगा ।

(१८) एकरारनामे सम्बन्धित दी जाने वाली सूचना के समय अगर अव्यापक स्टेशन पर नहीं है, तो इस प्रकार की सूचना उसको, उसके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी चाहिए, अगर जानते हो । सूचना जो कि भेजी जानी चाहिए । भेजी जाय अवयग नहीं, उमका अमर उमी दिन से प्रारम्भ होगा जिस तरह सामारण डाक उसको प्राप्त होती । अगर अव्यापक बिना पत्रा दिये स्टेशन छोड़ता है, उसे सूचना दिये जाने के १४ दिन के अन्दर कोई प्रस्ताव या निर्णय समिति पास करती है, और वह स्टेशन पर मौजूद है, तो उमका प्रभाव उस पर पड़ेगा, चाहे सूचना मिले अथवा न मिले ।

उपरोक्त लिखित साल और दिन में पक्षों के माक्षी ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किये ।

समिति की ओर से प्रस्ताव पास करने वाले अधिकारी.....
 ने निम्न की उपस्थिति में प्रस्ताव पास किया:—

साक्षी (१)

पता

साक्षी (२)

पता

साक्षी (१)

पता

साक्षी (२)

पता

परिशिष्ट ४

यह एकरारनामा दिनांक ... १९ (जो कि बाद में प्रधानाध्यापक पुराया जायगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समिति स्कूल के बीच तय किया जाता है । (जो कि बाद में प्रबन्धक कहा जायेगा) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक

को सेवायुक्त करने की स्वीकृति देता है और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के पद पर निम्न शर्तों के साथ सेवा करने की स्वीकृति देता है:—

(१) प्रधानाध्यापक का सेवा काल....

... दिनांक

१६

से प्रारम्भ हो जायगा। वह प्रथम बार १२ मास तक परीक्षण के तौर पर नियुक्त किया जायगा। इस वाक्य में मासिक वेतन रु. होगा।

(२) परीक्षण काल के समाप्त होने पर अगर स्थायी हो जाता है तो उसका मासिक वेतन रु. बढ़ीतरी के अनुसार होगा।

(३) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक को उसके द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह के दस दिन के अन्दर भुगतान करदे, और प्रधानाध्यापक दूसरी रसीद के लिए क्रम के अनुसार हस्ताक्षर करदे।

(४) प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक से सम्बन्धित समस्त कार्य करने चाहिए। इन समस्त कर्तव्यों के लिए प्रधानाध्यापक प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी है, प्रधानाध्यापक आन्तरिक प्रबन्ध व अनुशासन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, जैसे पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, समय सारणी की व्यवस्था, स्कूल अधिकारी वर्ग के सदस्यों के कार्य वितरण, प्रबन्धकों द्वारा बनाये गये अवकाश नियमों के अनुसार अधिकारी वर्ग का आकस्मिक इदकाश स्वीकृत करना, सेवक की नियुक्ति, दोषति, नियन्त्रण व कार्यच्युत करना, प्रबन्धकों की स्वीकृति के अनुसार आधी शुल्क व शुल्क मुक्त छात्रों को भर्ती करना, अधीक्षक द्वारा छात्रावास पर नियन्त्रण, छात्रों की भर्ती व उनकी उन्नति, खेल की व्यवस्था, खेल कोष और उसके समान अन्य कोषों जैसे वाचनालय या परीक्षा कोष पर अधिकार, आर्थिक व अन्य मामलों में जिसमें प्रधानाध्यापक पूर्णतया जिम्मेदार नहीं है, उसे प्रबन्धक के निर्देश मानने चाहिये। प्रबन्धकों द्वारा दिये गये, अधिकारों के सदस्यों के लिए निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा दिये जाने चाहिए।

प्रधानाध्यापक का लेखक पर नियन्त्रित शासन होना चाहिए, और प्रबन्धकों को सलाह देनी चाहिए कि कितने छात्र शुल्क भुगत व कितनी आधी शुल्क के होंगे। प्रबन्धकों को लेखक को नियुक्त करने, पदोन्नति करने, और उसको कार्यच्युत करने का अधिकार है, परन्तु प्रधानाध्यापक को उस पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है।

(५) प्रधानाध्यापक को सब समय स्कूल की सेवा के लिए देना होगा। वह कोई भी वैसा कार्य जो स्कूल से सम्बन्धित नहीं है, जब तक प्रबन्धक पूर्व लिखित आज्ञा प्राप्त न करले, न करेगा, प्रधानाध्यापक जहाँ स्कूल स्थित है, उस स्थान को छुट्टियों में या अवकाशों में दिना प्रबन्धक की आज्ञा के न छोड़ेगा।

(६) प्रधानाध्यापक को संस्था में लागू समस्त स्वीकृति नियमों व प्रवकाश नियमों की पृष्टी करनी चाहिए। एवं उसे समस्त वादनी आज्ञाओं व निर्देशों का, जो कि समय समय पर प्रबन्धकों से प्राप्त होते हैं, पालन करना चाहिये।

(७) (अ) प्रबन्धक, प्रधानाध्यापक को निम्न में से किसी एक या अधिक अपराध करने पर कार्यच्युत कर सकता है:—

(१) आज्ञाभंग

(२) जान बूझ कर कर्तव्य की अवज्ञा

-(३) गम्भीर दुराचार, या ऐसा कार्य जो कि कौजदारी अपराध हो।

उचित जांच करने के बाद एक दोपारोपण पत्र दिया जाता है व सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर देने की सुविधा दी जाती है।

(व) इस प्रकार की निकासी विशेष प्रस्ताव द्वारा होनी चाहिये, जिसमें तीन चौथाई सदस्य उपस्थित हो, व उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई मत बहुमत में प्राप्त हो ।

(स) संचालक की अनुमति से ही किसी अध्यापक को निकाला जायगा या कार्यच्युत किया जायगा । अगर कोई अध्यापक बिना सूचना के या सूचना के कार्यच्युत किया जाता है, तो वह कार्यच्युत या हटाये जाने की आज्ञा प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर संचालक के पास अपील कर सकता है ।

(ञ) वाक्य १ के अन्तर्गत जब प्रधानाध्यापक परीक्षण काल में हो, तो प्रबन्धक दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का अग्रिम वेतन, जो कि वह प्राप्त कर रहा था, देकर निकाल सकता है । इसी तरह प्रधानाध्यापक प्रबन्धक को दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का वेतन जमा कर इस एकरारनामे को तोड़ सकता है ।

(ट) परीक्षण काल समाप्त होने के बाद, वाक्य ८ के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक न तो एकरारनामा तोड़ने की सूचना ही पाता है, और न देता ही है, तो उसकी नियुक्ति वास्तविक में स्थाई हो जायगी ।

(१०) वाक्य ७ के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक के स्थाई होने के बाद न तो प्रधानाध्यापक और न प्रबन्धक ही तीन माह की लिखित सूचना देने पर या तीन माह का वेतन जमा करा कर, जो कि प्रधानाध्यापक प्राप्त कर रहा है, के बाद में एकरारनामे को तोड़ सकेंगे ।

(११) अगर प्रधानाध्यापक वाक्य ८ या १० के विरुद्ध किसी भी समय एकरारनामे का खण्डन करता है, तो उसकी वकाया रकम जप्त करली जावेगी और प्रबन्धक उसे कार्यच्युत कर सकता है ।

(१२) इस एकरारनामे के पक्षों की, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के व्यवहार के नियमों के लिए लागू शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा ।

उपरोक्त लिखित साल व दिन में पक्षों ने साक्षी के सम्मुख लिखित हस्ताक्षर किये ।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध समिति की ओर से प्रस्ताव पास करने वाले अधिकारी न
निम्न की उपस्थिति में प्रस्ताव पास किया :—

साक्षी (१)

पता

साक्षी (२)

पता

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

इनकी उपस्थिति में :—

साक्षी (१)

पता

साक्षी (२)

पता

नोट:—(१) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए जहाँ कहीं भी शब्द “स्कूल” आया है वहाँ “कालेज” व “प्रधानाध्यापक” के स्थान पर “आचार्य” समझा जाय ।

(२) छात्राग्राहों के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी शब्द “प्रधानाध्यापक” आया है, वहाँ “प्रधानाध्यापिका” समझा जाय ।

परिशिष्ट ५

मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विभागीय अधिकारियों के अधिकारी की सूची

क्रम सं.	व्यय का नाम	सरकार	विद्या संचालक	श्रेणी का उपविद्या संचालक	निरीक्षक शिक्षणालय	विशेष कथन
१	२	३	४	५	६	७
१	नियुक्ति के लिए अनुमोदन	समस्त सचिवार	१. शिक्षा संचालक (कालेड्या) प्राध्यापक तक (२८५-२५-५१०- दक्षतावरी-२५-५६०- ३०-८००)	वैसिक एस. टी. सी. में शिक्षक (१७०-१०- ३१०-१२१-३३५)	प्रशिक्षित इन्टर तक (७५-४-६५-५-१०५ दक्षता वरी-५-१३० दक्षता वरी-५-१६०)	
			२. शिक्षा संचालक (प्रा. व. मा-) (i) प्रधानाध्यापक हार्डस्कुल (२८५-२०-३८५- २५-५१०-५४०) (ii) प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक शाला (२७५-२०- ३७५-२५-५६०- ३०-६५०)	प्रशिक्षित स्नातक या स्नातक (११५-५-१५५- १०-१६५-दक्षता वरी- १०-२३५-२५०)	कनिष्ठ लेखक (६०-४-१०२ दक्षता वरी-४-१०- ५-१५०)	

[illegible]

一、政治
 二、經濟
 三、文化
 四、教育
 五、社會
 六、宗教
 七、藝術
 八、科學
 九、法律
 十、道德
 十一、哲學
 十二、歷史
 十三、地理
 十四、生物
 十五、醫學
 十六、農業
 十七、工業
 十八、商業
 十九、交通
 二十、通訊
 二十一、能源
 二十二、環境
 二十三、人口
 二十四、民族
 二十五、語言
 二十六、文字
 二十七、音樂
 二十八、舞蹈
 二十九、戲劇
 三十、電影
 三十一、電視
 三十二、廣播
 三十三、報紙
 三十四、雜誌
 三十五、圖書
 三十六、文具
 三十七、紙張
 三十八、印刷
 三十九、設計
 四十、建築
 四十一、園林
 四十二、城市
 四十三、鄉村
 四十四、郊區
 四十五、山區
 四十六、平原
 四十七、丘陵
 四十八、沙漠
 四十九、海洋
 五十、天空
 五十一、大地
 五十二、森林
 五十三、草原
 五十四、河流
 五十五、湖泊
 五十六、冰川
 五十七、火山
 五十八、地震
 五十九、洪水
 六十、乾旱
 六十一、瘟疫
 六十二、戰爭
 六十三、和平
 六十四、革命
 六十五、改革
 六十六、開放
 六十七、合作
 六十八、競爭
 六十九、發展
 七十、進步
 七十一、繁榮
 七十二、昌盛
 七十三、富強
 七十四、民主
 七十五、自由
 七十六、平等
 七十七、正義
 七十八、誠實
 七十九、勇敢
 八十、勤勞
 八十一、節約
 八十二、愛國
 八十三、敬人
 八十四、守法
 八十五、守紀
 八十六、守信
 八十七、守禮
 八十八、守德
 八十九、守節
 九十、守貞
 九十一、守孝
 九十二、守義
 九十三、守仁
 九十四、守忠
 九十五、守信
 九十六、守諾
 九十七、守約
 九十八、守時
 九十九、守序
 一百、守規

१	२	३	४	५	६	७
				व्यापिका/हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शाला तक ।		अपील सरकार के पास होगी ।
				३. संचालक, शिल्पशिक्षा, प्राध्यापक तक—(३६०- २५-५६०-३०-५००- दक्षता गरी-३०-६०- ६००)		
				४. संचालक संस्कृत शिक्षा- प्राध्यापक, संस्कृत कालेज समस्त अधिकार	मिडिल स्तर तक (अनुमोदित प्रणाली के अन्तर्गत)	प्राथमिक स्तर तक (अनुमोदित प्रणाली के अन्तर्गत)
				उपरोक्तानुसार सहायता अनुदान समिति की राय से ५०,००० तक	उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रणाली के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर तक	उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर तक
				सहायता अनुदान समिति की राय से ५०,००० के ऊपर के समस्त अधिकार समस्त अधिकार (कालेज)	समस्त अधिकार (स्कूल स्तर)	प्राथमिक शाला
५	स्तर का उठाते के लिये अनुमोदित					
५	नया वर्ग खोलने के लिए अनुमोदित					
६	अन्तर्गत व्यय का अनुमोदित					
७	संस्थान के लिए अनुमोदित					

१	२	३	४	५	६	७
८	अनावर्तक अनुदान की स्वकृति बजट के अनुसार	समस्त अधिकार	१५००० तक	×	×	
९	नई संस्थाओं को सहायता अनुदान की स्वीकृति	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	×	×	×	
१०	राजस्थान से बाहर की संस्थाओं को सहायता अनुदान	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	×	×	×	
११	संस्था को सहायता अनुदान की स्वीकृति को पहले से ही बजट से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है		समस्त अधिकार	×	×	
१२	संस्था को अंशों का परिवर्तन		महायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	×	×	
१३	उच्चतर व व्यास बढोतरी का प्रमुख बढोतरी के लिए अनुमोदन	समस्त अधिकारी	नियुक्ति के अधिकार तक समस्त अधिकार	×	×	

पश्चिमि ३

निजी संस्थाओं में सहायता अनुदान के लिये अनुमानित खर्चों की अधिकतम सीमा का संशोधित मूल्य निरूपण

क्रम	सहायता अनुदान में	टेकनीकल स्नाकोत्तर	उपाधि महा-	प्रशिक्षण	उच्चतर माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	हाईस्कूल	मिडिल स्कूल	प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्तर	मान्यकारीस्कूल
सं०	निर्दिष्ट शीर्षक	इंजीनियर-उच्च	विद्यालय ११	महा-विद्यालय ९	से	शाला ६	से १२	या	एस्.टी.सी.	१ से ३ तक	१२
१	१२	रिंग कालेज विद्यालय	से १४ तक	विद्यालय १२ तक	तक	५	६	१०	११	१२	

व्युत्पत्तिः—

(अ) अध्ययनक वर्ग

राजस्थान वेतन क्रम या विश्वविद्यालय द्वार निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार (जो अधिक हो) परन्तु कर्मचारी वर्ग के बढ़ने पर या वेतन मान अथवा मंहंगाई भत्ते के बदलने से होने वाले परिवर्तन से बढे हुये नृणों के लिए विभाग से पहले स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये ।

(ब) लेखक वर्गी

कर्मचारी वर्ग

(स) चतुर्थः श्रेणी

कर्मचारी वर्ग

प्रोविडेन्ट फण्ड

६३% से अधिक नहीं। जोधपुर राज्य में पहले और अनिवार्य शिक्षा स्कूल के पूर्व विलयी कर्मचारी के लिए ८३% तक। उपर्युक्त महा विद्यालय और स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ८% प्रत्येक द्वारा स्वीकार की गई क्रम (Scale) से अधिक नहीं।

	२००	७००	६००	५००	४००	३५०	२००	७५	१५०
महंगाई भत्ता									
लेखन सामग्री एवं									
मुद्रण	२००	७००	६००	५००	६००	५००	४००	७५	१५०
पानी और रोशनी									
खर्च	६००	६००	५००	६००	६००	३००	१२५	५०	२५०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
सामान पर श्रावर्तक											
खर्च	विश्वविद्यालय की शर्त के अनुसार			बोर्ड की शर्त के अनुसार और एस० टी० सी० स्कूल के लिए विवरण "च" में दी गई सीमा होगी।							
साधारण मरम्मत											
(१) भवन											
यहके भवन के लिये लागत का १% प्रतिवर्ष, और कच्चे भवन के लिए २% प्रतिशत २५००० तक. और इसकी जांच निरीक्षक, शिक्षा विभाग करेगा और पी० डब्लु० डी० द्वारा स्वीकृत किया जायगा।											
(२) फर्नीचर और											
उसका स्थानान्तरण	७००	६००	६००	६००	५००	५००	२००	१५०	१००	२००	
पुस्तकालय की पुस्तकें											
व. वाचनालय पर											
किन्हे जाने वाला	७००				७००	५००	३००	१००	५०	१५०	
खर्च	विश्वविद्यालय की शर्त के अनुसार										
खेल, शारीरिक शिक्षा											
व अन्य सांस्कृतिक कार्यों											
पर किये जाने वाला											
शुद्ध खर्च	५००	५००	७००	७००	७००	५००	३००	२००	५००	२५०	
क्रापट पर खेती, डेरी											
शुद्ध विज्ञान इत्यादि											
पर किया जाने वाला											
शुद्ध खर्च	—	—	३००	—	—	३००	३००	५०	१००	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

अध्यापकों द्वारा सम्बन्ध

में भाग लेने हेतु,

यात्रा व्यय

अनेक संस्थाओं का प्रबंध

करने वाले केन्द्रीय

कार्यालय का खर्च—

सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के अनुसार

(१) विभाग द्वारा अनुमोदित १ लाख का खर्च, और जो तीन अलग (२) दो लाख का खर्च अनुमोदित और आगे विभाग द्वारा, संस्थाओं रखती हों:—

[१] प्रबन्ध मन्त्री	१५०-३००	[१] प्रबन्ध मन्त्री	२५०-५००
[२] निम्न श्रेणी लेखक	६०-१३०	[२] लेखापाल	१५०-३००
[३] चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक	२५-४०	[२] उच्च श्रेणी लेखक-कमिस्टेन्तो	८०-२००
[४] कार्यालय का प्रशासनिक व्यय	५००	[४] दो निम्न श्रेणी कर्मचारी	६०-१३०
		[५] दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२५-१-४०
		[६] कार्यालय का प्रशासनिक व्यय	१०००-

टिप्पणियाँ

(१) पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय:—अगर मिडिल स्कूल में छात्रों की संख्या ३०० से अधिक है, तो १५० रु० और प्राथमिक शाला में छात्रों की संख्या २०० से अधिक हो तो ७५ रु० स्वीकार किया जायगा।

(२) पुस्तकालय के निम्ने ।

(३) मद नं० ६ में सामान पर खर्च और मद नं० ६ में पुस्तकालय की पुस्तकों पर खर्च, साधारण सीमा उपरोक्त अनुसार विषय के अनुसार क्रिये जाने वाला खर्च परिगिष्ट (अ) में देखें।

(४) मद (अ) और ३ मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विषय में—यव कि वह अजमेर राज में १-१-५५ के बाद नियुक्त किया गया हो उस पर राजस्थान के नन भुखला लागू होगी।

(५) सामान्य पुस्तकालय के लिए मद्य नं० ६ में दिखाये गये विषय के अनुसार खर्च के लिए परिशिष्ट (अ) देखें ।

छात्रावास

सड़कों की संख्या २५ होने पर और नड़कियों की संख्या १५ होने पर कक्षा भत्ता ३० रु० प्रति मास के हिसाब से दिया जा सकता है, और संरक्षक/प्रधोक्त/मेटर्न का वेतन प्रतिमास २०० रु० से कम नहीं होना चाहिये ।

सारणी—ब (परिशिष्ट—६ से संलग्न)

एत. दी सी. स्कूलों के लिए शीर्षक सामान तथा यन्त्रों के अत्यवश्यक आवश्यक प्रनुदान की सीमा निर्धारण का निरण पत्र		
[१] ऐतिहासिक मानचित्र और चार्ट्स	—	५०.०० रु.
[२] भूगोल	—	५०.०० रु.
[३] वाणिज्य	—	१००.०० रु.
[४] चित्रकला और रंगसाजी	—	१००.०० रु.
[५] संगीत	—	१००.०० रु.
[६] यन्त्र और रसायन (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र)	—	३००.०० रु.
[७] सामान्य विज्ञान	—	२००.०० रु.
[८] ग्रह विज्ञान	—	२००.०० रु.
[९] भारतीय शासन तथा नागरिक शास्त्र	—	२५.०० रु.
[१०] जीव विज्ञान	—	१००.०० रु.
[११] बेसी	—	५००.०० रु.

संस्था में चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणी का विवरण पत्र

क्रम सं०	शोर्षक	टेक्नीकल इन्जीनियरिंग कार्तेज	स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय	उपाधिमहा विद्यालय	प्रशिक्षण महा-विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक शाला	हाईस्कूल या एम.टी.सी.	माध्यमिक शाला	प्राथमिक शाला	मान्यकारी स्कूल	अना-वास	विशेष कयन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

चपरासी	४	४	४	४	४	३	३	३	—	—	२	तन्हा जहाँ एक ही
चौकीदार	१	१	१	१	१	१	१	१	—	—	१	भवन में दो शिफ्ट
जलधारी	१	१	१	१	१	१	१	१	—	—	—	चलती है वहाँ एक प्रतिरिक्त चौकीदार
प्रयोगशाला												
का नोकर (लेव वियरर)	जहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला काम में लाई जाती है, वहाँ प्रत्येक वर्ग विषय के लिए एक लेव वियरर											
गैस यंत्र के लिए मिस्त्री	१	१	१	१	१	१	१	१	—	—	—	हाईस्कूल और नीचे
हलिन (भंजी)	१	१	१	१	१	१	१	१	१	—	१	जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ५०० से अधिक हो वहाँ एक प्रतिरिक्त फराश रखा जा सकता है।
फराश	२	२	२	२	२	२	२	२	—	—	—	
गेम्स वॉय	१	१	१	१	१	१	१	१	—	—	—	
वागवान	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
खेतीदार कर्मचारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
पुस्तकालय परिचायक	१	—	—	—	—	१	—	—	—	—	—	

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

उच्चतर माध्यमिक शाला में

शिक्ष्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों

के लिए

सेती

ललित कला (फाइन आर्ट्स)

गृह विज्ञान

वाणिज्य

लेखक वर्गीय कर्मचारी

पुस्तकालयाध्यक्ष

उच्च श्रेणी वर्ग लेख

निम्न श्रेणी वर्ग लेखक

ये संस्था द्वारा
निर्धारित विषय
पर निर्भर है२
२
१
१

१

१
१
१
२१
१
१

१ अंशकाल

नोट:—[१] गेस बॉय:—समस्त उच्चतर माध्यमिक शालाओं और उतर माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ३०० से अधिक हो, न मगस्त विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सेल की सुविधा हो।

[२] बागवान:—हाईस्कूल तथा उच्चतर संस्थाओं में जहाँ संस्था बाग का भरणपोषण करती हो, और पूरे समय के लिए आदमी का कार्य हो, तो बागवान रख सकेगी।

[३] पुस्तकालय:—परिचायक:—समस्त हाईस्कूलों व ऊपर की संस्थाओं में, जहाँ अलग से पुस्तकालयाध्यक्ष है, एवं पुस्तकें ठीक प्रकार से दी जाती हैं, वहाँ पुस्तकालय परिचायक की आवश्यकता है। जहाँ खुली अलमारी काम में लाई जाती है, वहाँ एक प्रतिरिक्त पुस्तकालय परिचायक रखा जा सकता है।

[४] मान्टेसरी स्कूल:—अगर मिडिल वर्ग तक हो और छात्रों की संख्या २०० से अधिक हो तो एक प्रतिरिक्त अलमारी और एक प्रतिरिक्त जलपारी रखा जा सकेगा।

संचालक

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विधि (क) विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, १ नवम्बर २५, १९६४

सं० एफ ७ (२६) एल/६३:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, १९५६ [राजस्थान अधिनियम ४७ सन् १९५६] की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान प्राईमरी एजुकेशन एक्ट, १९६४ (एक्ट ३१ आर्क १९६४) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनाय प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १९६४

(अधिनियम ३१ सन् १९६४)

राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ नवम्बर, १९६४ को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य में बालकों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में व्यवस्था करने हेतु अधिनियम।

रास्थान राज्य विधानमंडल द्वारा भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है:-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ:- (१) यह अधिनियम राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(३) यह ऐसी तारीख को प्रभावशील होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति के जरिये नियुक्त करे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

२. परिभाषाएँ:- इस अधिनियम में जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,- [क] "शिक्षा वर्ष (Academic year)" से तात्पर्य वह वर्ष है जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ हो जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति के जरिये, किसी निदिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में या मान्य (approved) शालाओं के लिए सामान्यतया या विशेषरूप से किसी मान्य शाला या मान्य शालाओं के किसी वर्ग के लिए विशिष्टतया नियत करे;

(ख) "मान्य शालाओं" से तात्पर्य किसी भी निदिष्ट क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा देने वाले ऐसे किसी शाला से है जो-

(१) राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के प्रबन्धनाधीन हो या

(२) किसी अन्य प्रबन्धन के अधीन होते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्य किया गया हो;

(ग) "उपस्थिति अधिकारी (Attendance Authority)" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे धारा ७ के अधीन उपस्थिति अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(घ) "किसी मान्य शाला में उपस्थित होने" का तात्पर्य किसी मान्य शाला में शिक्षा पाने के लिए वर्ष में उतने दिन और उक्त दिनों में से ऐसे समय या नियमों पर जो निर्धारित अधि-

कारी द्वारा नियत किये जायें उपस्थित होने से है;

(ङ) “बालक से तात्पर्य किसी बालक या बालिका से है जो ऐसे आयु वर्ग का हो जिसमें छः वर्ष से कम या ११ वर्ष से अधिक के बालक न हो, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक मामले में, सामान्य रूप से या किसी निदिष्ट क्षेत्र से सम्बन्ध में निदिष्ट करे;

(च) “शिक्षा प्राधिकारी से तात्पर्य है,—

[१] जहां किसी क्षेत्र में ऐसी कोई स्थानीय सत्ता विद्यमान है जिसे प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य सौंपा गया हो, उक्त स्थानीय सत्ता, और

(२) वैसी स्थानीय सत्ता के अभाव में संचालक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान;

(छ) “स्थानीय सत्ता” से तात्पर्य ऐसी नगरपालिका या पंचायत समिति से है जिसे प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन सुपुर्द किया गया हो;

(ज) “माता पिता (Parent)” से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिस पर विधि या प्राकृतिक अधिकार अथवा मान्य-प्रथा के अनुसार किसी बालक के संरक्षण (Care), भरण-पोषण या अभिरक्षण का भार आया हो या जिसने ऐसे किसी बालक के संरक्षण, भरण-पोषण या अभिरक्षण करने का कार्य स्वीकार या ग्रहण (assume) कर लिया हो या जिसको वध प्राधिकारी द्वारा किसी बालक के संरक्षण का कार्य सुपुर्द किया गया है;

(झ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ञ) “प्राथमिक शिक्षा” से तात्पर्य ऐसी कक्षाओं या श्रेणियों (Standards) जो ५वीं कक्षा या श्रेणी में ऊपर न हों, जैसी निर्धारित की जाय, में या तक की शिक्षा से है,

(ट) “विशिष्ट शाला” से तात्पर्य ऐसी किसी संस्था से है जिसमें ऐसी प्राथमिक शिक्षा दी जाती हो जो राज्य सरकार की राय में किसी शारीरिक या मानसिक दोष से पीड़ित बालकों के लिए उपयुक्त हो; और

(ठ) “निदिष्ट क्षेत्र” से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसमें धारा ४ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने की घोषणा की जाय ।

प्राथमिक शिक्षा के लिए योजनाएं;—(१) शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सामान्यतः रहने वाले बालकों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे, और इस प्रयोजन के निमित्त वह समय समय पर, राज्य सरकार की योजना के रूप में ऐसे प्रस्ताव, जो वह उचित समझे, प्रस्तुत करेगा जिममें क्षेत्राधिकार के भीतर संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में ऐसे आयु के बालकों के लिए तथा ऐसी कक्षा या श्रेणी तक जैसा वह निर्णय करे, उक्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

(२) उपधारा (१) में किसी भी बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार, उसको किसी भी समय, किसी स्थानीय सत्ता से ऐसे समय के भीतर जो निदिष्ट किया जाय, उक्त स्थानीय सत्ता के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ऐसे क्षेत्र में, उसमें सामान्यतः रहने वाले और ऐसे आयु के बालकों के लिए तथा ऐसी कक्षा या श्रेणी तक, जैसा राज्य सरकार निर्देश करे, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के

संबंध में एक योजना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी ।

(३) उपधारा [१] या उप धारा [२] के अन्तर्गत प्रस्तुत योजना एंसे प्रपत्र में होगी जो राज्य सरकार निदिष्ट करे और उसमें निम्न लिखित व्यौरे दिये जायेंगे:—

- (क) ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी,
- (ख) ऐसे बालकों की अनुमानित संख्या—आयु और मातृभाषा के अर्थात् वह भाषा जो बालक द्वारा घर पर बोली जानी है, के अनुसार वर्गीकरण करते हुए जिन-पर उक्त योजना लागू होगी;
- (ग) वर्तमान मान्य शालाओं की तथा ऐसे शालाओं, यदि कोई हों जिन्हें तत्प्रयोजनार्थ खोला जाना प्रस्तावित है की सूची जिनका वर्गीकरण भाषाओं जिनमें शिक्षण दिया जाता है या दिया जाना प्रस्तावित है, के आधार पर किया जाये;
- (घ) पहिले से ही नियोजित अध्यापकों एवं भर्ती किये जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कर्मचारी की संख्या
- (ङ) योजना की आवर्तक एवं अनावर्तक लागत; और
- (च) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जायें ।

(४) उप-धारा (१) के अधीन शिक्षा प्राधिकारी द्वारा और उप-धारा [२] के अधीन स्थानीय सत्ता द्वारा प्रस्तुत योजना का राज्य सरकार, ऐसी जांच किये जाने के पश्चात् जो कि वह उचित समझे, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के स्वीकर कर सकेगी ।

[५] किसी भी योजना के लिए उपधारा [४] के अन्तर्गत उस समय तक स्वीकृति नहीं दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि उन 'समस्त बालकों को जिन पर यह योजना लागू होगी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं' जुटाने हेतु के सब कदम उठा लिये गये हैं जो निर्धारित किये जायें ।

४-निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य होना:—[१] धारा [३] की उप-धारा [४] के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर शिक्षा प्राधिकारी इस प्रकार स्वीकृत योजना 'को ऐसी घोषणा के द्वारा कार्यान्वित करेगा कि आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रथम दिन से प्राथमिक शिक्षा घोषणा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, साधारणतः उस क्षेत्र के निवासी बालकों के लिए ऐसे आयु वर्ग' के अन्तर्गत और ऐसी कक्षा या श्रेणी तक जो घोषणा में निर्दिष्ट हों, अनिवार्य होगी, ।

[२] उप-धारा [१] के अन्तर्गत की गई प्रत्येक घोषणा—

- [क] सरकारी गजट में और एंसे अन्य तरीको से, जिसका निश्चय घोषणा करने वाला शिक्षा प्राधिकारी करे, प्रकाशित की जायेगी;
- (ख) इस प्रकार की जायेगी कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि घोषणा प्रकाशित की जाने की तारीख तथा आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रथम दिन के बीच की अवधि एक सौ बीस दिन से कम नहीं है ।

५-सहाय्यार्थ अनुदान—धारा ३ की उप-धारा [४] के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा धारा १७ की उप-धारा [१] के अन्तर्गत तैयार की गई प्रत्येक योजना से सम्बन्धित आवर्तक एवं

अनावर्तक लागत का ऐसा भाग जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाय, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(६) बालकों की सूची तैयार करने का शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य:—शिक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ४ के अन्तर्गत घोषणा प्रकाशित होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जाय, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के बालकों की एक सूची तैयार करवायें, तथा शिक्षा प्राधिकारी उक्त सूची को ऐसे समयान्तरों पर, जो कि निर्धारित किये जायें, संशोधित करवायेगा।

(७) उपस्थिति प्राधिकारी:—(१) शिक्षा प्राधिकारी जितने व्यक्तियों को वह उचित समझे उतने ही व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा, तथा उपस्थिति प्राधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता देने के लिए भी जितने व्यक्तियों को वह आवश्यक समझे उतने ही व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।

(२) इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपस्थिति प्राधिकारी या उपस्थिति प्राधिकारी को सहायता देने के हेतु नियुक्त कोई भी व्यक्ति माता पिता में से किसी से उसके बालक के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्न कर सकेगा अथवा माता पिता में से किसी से ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे तथा प्रत्येक उक्त माता पिता अपने सम्पूर्ण ज्ञान या विश्वास के साथ उक्त प्रश्नों का उत्तर अथवा उक्त सूचना यथा-स्थिति देने के लिए बाध्य होगा।

८. उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा माता पिता को बालक के प्रति उनके उत्तरदायित्व से सूचित किया जाना:—उपस्थिति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक बालक, जिस पर धारा ४ के अन्तर्गत की गई घोषणा लागू होती है, के माता पिता को सूचित करे कि आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से बालक की किसी मान्य स्कूल में उपस्थिति की व्यवस्था करने का दायित्व उन पर है।

९. अपने बालक की शाला में उपस्थिति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में माता पिता का उत्तरदायित्व:—प्रत्येक बालक के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बालक को शाला में उपस्थिति की व्यवस्था तब तक करे जब तक कि उसकी अनुपस्थिति के लिए धारा १० के अर्पान्तर्गत कोई युक्ति युक्त आधार विद्यमान न हो।

१०. अनुपस्थिति के लिए युक्ति युक्त आधार:—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित में से कोई भी परिस्थिति किसी मान्य शाला में बालक की अनुपस्थिति के लिए युक्ति युक्त आधार समझी जायेगी—

(क) कि उसके निवास-स्थान से निर्धारित दूरी के अन्दर प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कोई मान्य शाला नहीं है;

(ख) कि बालक किसी अन्य रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संतोषप्रद घोषित कर दी गई है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है;

(ग) कि बालक ने धारा ४ के अधीन की गई घोषणा में निर्दिष्ट श्रेणी तक प्राथमिक शिक्षा पहिले ही पूर्ण करली है;

[घ] कि बालक किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकार से पीड़ित है जो उसे उपस्थित होने से रोकता है,

[ङ] कि कोई अन्य विवश करने वाली ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जो बालक को शाला में उपस्थित होने से रोकती है, वशत कि वह इस रूप में उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दी जाय; या

[च] ऐसी अन्य परिस्थितियां जो निर्धारित की जायं ।

११. शारीरिक या मानसिक रूप से हीन [deficient] बालकों के लिए विशेष शाला:—यदि किसी ऐसे बालक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दोष से ग्रस्त है, के निवास के स्थान से निर्धारित दूरी में कोई विशेष शाला विद्यमान है तो उपस्थिति प्राधिकारी, यदि वह सन्तुष्ट हो गया है कि बालक किसी अन्य रीति से, जिसे वह संतोषप्रद समझ सके, शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वह आदेश द्वारा, बालक से विशेष शाला में भर्ती होने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे बालक के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि बालक को विशेष शाला में, जब तक कि धारा १० के खंड [ङ] के अर्थ में बालक की अनुपस्थिति के लिये उचित कारण न हो, भर्ती करावें ।

१२. कतिपय मामलों में अंशकालिक शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान:—[१] यदि उपस्थिति प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो गया है कि बालक जिस परिवार का सदस्य है उस परिवार की आर्थिक या अन्य परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रपेक्षित रीति से किसी मान्य शाला में भर्ती होने में असमर्थ है तो वह आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हे वह लगाना उचित समझे, के अधीन, बालक को अंशकालिक-संस्था के रूप में स्थापित किसी भी मान्य शाला या जिसमें अंशकालिक आधार पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, में भर्ती होने की अनुमति दे सकेगा ।

(२) किसी भी माता पिता को, जो बालक को, जिसके कि सम्बन्ध से उप-धारा [१] के अन्तर्गत कोई आदेश दे दिया गया है, आदेश में निर्दिष्ट रीति से किसी मान्य शाला में भेजता है, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया हुआ समझा जायेगा ।

१३. उपस्थिति आदेश:—[१] जब कभी भी उपस्थिति प्राधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि बालक के माता पिता बालक को मान्य शाला में भेजने में विफल रहे हैं तथा धारा १० के अर्थ में बालक की अनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण नहीं है तो वह निर्धारित रीति में जांच करेगा ।

(२) यदि जांच के परिणाम स्वरूप उपस्थिति अधिकारी संतुष्ट हो जाय कि बालक इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्य शाला में उपस्थित होन योग्य है और धारा १० के अर्थ में उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण नहीं है तो वह निर्धारित रूप में उपस्थिति आदेश पारित करेगा जिसमें माता पिता को निर्देश दिया जायेगा कि आदेश में निर्दिष्ट तारीख से बालक को मान्य शाला में उपस्थित करें ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत माता पिता के विरुद्ध उनके बालक के सम्बन्ध में पारित उपस्थिति आदेश उप-धारा ७ प्रावधानों के अधीन रहते हुए उस समय तक, प्रभाव में रहेगा जब तक कि यह अधिनियम बालक पर लागू रहता है ।

(४) यदि माता-पिता जिनके विरुद्ध, उप-धारा (२) के अन्तर्गत उनके बालक के सम्बन्ध में उपस्थिति आदेश पारित किया गया है, ऐसी अवधि में, जिनमें उपस्थिति आदेश प्रभाव में है, बालक से सभारक्षण का भार इस प्रकार हस्तान्तरित किया गया है, उपस्थिति प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे हस्तान्तरण की लिखित में सूचना देने के लिए बाध्य होंगे।

(५) जहाँ इस धारा में अन्तर्गत माता पिता के विरुद्ध उनके बालक के सम्बन्ध में उपस्थिति आदेश पारित कर दिया गया हो तो ऐसा आदेश, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसको ऐसी अवधि के दौरान, जिसमें उपस्थिति आदेश प्रभाव में है, बालक के सभारक्षण का भार हस्तान्तरित कर दिया जाय, के सम्बन्ध में उसी रूप में लागू होगा जिस रूप में वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू होता है जिसके कि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।

(६) माता पिता किसी भी समय उपस्थिति प्राधिकारी को निम्नांकित कारणों से उपस्थिति आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेंगे:—

[१] कि वह अब बालक के माता पिता नहीं रहे हैं; या

[२] कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जो उसकी अनुपस्थिति के लिये उचित कारण हैं; और तदुपरान्त उपस्थिति प्राधिकारी निर्धारित रीति से जांच करने के पश्चात् उपस्थिति आदेश को रद्द या रूपान्तरित कर सकेगा।

१४. बालकों को इस प्रकार सेवा युक्त नहीं किया जायेगा, जिससे उनके शाला जाने में रुकावट हो:—कोई भी व्यक्ति किसी बालक को ऐसी रीति से सेवा युक्त नहीं करेगा जिससे बालक के किसी मान्य शाला में जाने में रुकावट हो।

१५. प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क होना:—(१) किसी मान्य शाला, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के प्रबन्ध के अन्तर्गत है, में जाने वाले किसी भी बालक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(२) जब किसी बालक के सम्बन्ध में, जिस पर धारा ४ के अधीन की हुई घोषणा लागू होती हो और एक मात्र शाला जिसमें वह जा सकता है वह शाला धारा २ के खण्ड (ख) के उप-खण्ड [२] के अन्तर्गत आने वाला, निजी प्रबन्ध के अधीन मान्य शाला दोनों शिक्षा अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा जो बालक को प्राप्त करनी है, निःशुल्क है, ऐसे कदम उठायेगा जो वह उचित समझे।

१६. बालक की आयु की गणना किस प्रकार हो:—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बालक की आयु गणना शिक्षा वर्ष के प्रथम दिन को या उससे पूर्व बालक द्वारा पूर्ण किये गये वर्षों के रूप में की जायेगी।

परन्तु शर्त यह है कि जब बालक का जन्म-दिन किसी ऐसे दिन आता हो जो शिक्षा वर्ष के प्रथम दिन से ६० दिन से बाद का न हो तो जन्म-दिन, बालक की आयु की गणना करने के लिए शिक्षा वर्ष के प्रथम दिन को ही समझा जायेगा।

१७. स्थानीय सत्ता का योजना तैयार करने अथवा पूरा करने में विफल होना:—

[१] यदि कोई स्थानीय सत्ता जब उसे धारा ३ की उपधारा [२] के अधिन योजना प्रस्तुत करने को कहा जाए, ऐसा करने में विफल रहे या धारा ३ की उपधारा [४] के अधीन योजना स्वीकृत हो पश्चात्, इस प्रकार स्वीकृत योजना को, चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः क्रियान्वित करने

मे असफल रहे तो राज्य सरकार ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और स्थानीय सत्ता को इस मामले में सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् योजना तैयार करने या उसको क्रियान्वित करने जैसी भी स्थिति हो, के लिये, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और यह निर्देश दे सकेगी की व्ययों का ऐसा अंश, जो राज्य सरकार निश्चित करे, स्थानीय सत्ता की निधि में से दिया जायेगा ।

(२) जब ऐसा कोई निर्देश जैसा कि उप-धारा (१) में उल्लिखित है, जारी किया जाए तो कोई भी व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में स्थानीय सत्ता की ओर से तत्समय या तो बैंकर के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में, कोई रूपया है, तत्समय प्रभावशाली किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसे निर्देश का पालन करने के लिये बाध्य होगा ।

१८. धारा १३ के उल्लंघन के लिए शास्ति:—(१) यदि धारा १३ के अधीन पारित किसी उपस्थिति आदेश का पालन करने में माता-पिता विफल रहते हैं तो वे ऐसे अर्थ-दण्ड से जो दो रुपये से अधिक नहीं होगा, और उल्लंघन के जारी रहने की स्थिति में ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषी सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड से जो प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस नये पैसे से अधिक नहीं होंगे; दण्डनीय होंगे;

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी बालक के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा देय अर्थ दण्ड की राशि किसी एक वर्ष में पच्चीस रुपयों से अधिक नहीं होगी ।

(२) यदि कोई व्यक्ति, धारा १३ की उप-धारा (४) द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना देते में विफल रहता है तो ऐसे दण्ड-से, जो पांच सौ रुपयों तक हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

१९. धारा १४ के उल्लंघन के लिए शास्ति:—यदि कोई व्यक्ति धारा १४ के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह इसे अर्थ-दण्ड से, जो पचास रुपयों तक हो सकेगा, और उल्लंघन के जारी रहने की स्थिति में इसे प्रथम उल्लंघन के लिये दोषी सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है १ रु. से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

२०. अपराधों पर वैधिक विचार करने के लिये सक्षम न्यायालय:—इस अधिनियम के विपरीत अपराधों पर वैधिक विचार:—

(क) न्याय सर्जन में राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ (राजस्थान अधिनियम संख्या २१, सन् १९५३) के अधीन किसी क्लिमिनल अपराध पर वैधिक विचार करने का क्षेत्राधिकार रखने वाली न्याय पंचायत जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध करने वाला व्यक्ति रहता है, द्वारा किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब कि उक्त व्यक्ति ऐसे कस्बे या गांव में रहता हो मजिस्ट्रेट का प्रधानास्पद स्थित हो;

(ख) अन्यत्र अथवा उस दशा में जब कि अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसे कस्बे या गांव में रहता है जहां मजिस्ट्रेट प्रधानास्पद स्थित हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा ।

२१. न्यायालयों की प्रक्रिया:—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर वैधिक विचार करते समय मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता १८६८ (सैन्ट्रल एक्ट ५, सन् १९५८) की धारा २६३ में प्रावहित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर वैधिक विचार करते समय न्याय पंचायत

राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ (राजस्थान अधिनियम २१, १९५३) के अधीन न्याय पंचायत द्वारा क्रिमिनल अपराधों पर वैधिक विचार करने के लिये प्रावहित प्रक्रिया का पालन करेगी।

२२. अपराधी संज्ञानः—कोई भी न्यायालय उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा अथवा शिक्षा प्राधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत करने के अतिरिक्त, अन्यथा इन अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

२३. कतिपय व्यक्ति लोक सेवक होंगेः—भारतीय दण्ड संहिता (सेन्ट्रल एक्ट ४५, सन् १८६०) की धारा २१ के अर्थ में, उपस्थिति-प्राधिकारी, धारा ७ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत उपस्थिति-प्राधिकारी की सहायता करने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति तथा धारा २१ के अन्तर्गत शिकायत करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक समझे जायेंगे।

२४. सद्भावना से किये गये कर्म का संरक्षणः—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी कार्य के सम्बन्ध में सरकार या किसी भी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद अभियोध या कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

२५. मुक्ति देने की शक्तिः—यदि राज्य सरकार इस बात में संतुष्ट हो जाय कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है या कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को या किसी भी समुदाय को इन अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रावधानों के प्रभाव से मुक्त कर सकेगी।

२६. शक्तियों का प्रत्याखेपनः—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी शर्तों यदि कोई हों, जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें के अधीन रहते हुये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी समस्त या कोई शक्तियों का जो इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदान की गई हों, धारा १ की उप-धारा (३) धारा २५, २७ और २८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़ कर प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी।

(२) कोई शिक्षा प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी सभी या कोई शक्तियों का जो इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत किसी शिक्षा प्राधिकारी को प्रदान की गई हो, प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

२७. नियम बनाने की शक्तिः—[१] राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

[२] विशेष तौर पर, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नांकित समस्त विषयों या उनमें से किन्हीं के लिये प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) शिक्षा की कक्षा (Class) या श्रेणी (Standard) जिस तक कि प्राथमिक शिक्षा समझी जायेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी योजना में समाविष्ट किये जाने वाले व्योरे जिनमें वे व्योरे सम्मिलित हैं जो किसी क्षेत्र में विशेष शालाओं की या अंशकालीन

प्राथमिक शिक्षा देने वाले शालाओं की, स्थापना के लिए अपने अथवा बालकों की, शाला में उनके अध्ययनकाल में भोजन या अल्पाहार पुस्तकें, लेखन-सामग्री, यूनीफार्मस या अन्य आवश्यक सुविधायें, देने के लिए, किये गये या किये जाने वाले प्रावधान से सम्बन्धित हों;

(ग) रीति जिससे धारा ६ के अधीन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में बालकों की सूचियां तैयार की जा सकेंगी, समयावधियां [intervals] जिनकी समाप्ति पर सूचियां संशोधित रूप में रखी जायेंगी और व्यक्ति जिनकी सहायता से ऐसी सूचियां तैयार की जायेंगी;

(घ) उपस्थिति प्राधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कृत्य और रीति जिससे ऐसे कृत्य, और रीति जिससे ऐसे कृत्य किये जा सकेंगे;

[ङ] दूरी जिसके अग्रे किसी बालक को किसी मान्य शाला में पढ़ने जाने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकेगा;

[च] परिस्थितियां जो किसी बालक की अनुपस्थिति के लिए धारा १० के अर्थ में युक्ति युक्त आधार मानी जा सकेंगी।

[छ] रीति जिसमें कोई जांच इस अधिनियम के अधीन की जा सकेंगी;

[ज] प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई उपस्थिति-प्रदेश पारित किया जा सकेगा।

[झ] मान्य शालाओं द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रखे या प्रस्तुत किये जाने वाले रजिस्टर, विवरण और अन्य सूचना;

[ञ] कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है अथवा जो निर्धारित किया जा सके।

(३) प्रत्येक नियम जो इस धारा के अधीन बनाया जाय, बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधान मंडल, जबकि सत्र चालू हो, के समक्ष चौदह दिन की कुल अवधि जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में पूर्ण हो, के लिए रखा जायेगा, और यदि उस सभा की, जिसमें कि वह रखा जाय, या तदनुवर्ती सत्र की, समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान मंडल का सदन उक्त नियम में कोई रूपांतर करने के लिए सहमत हो जाय अथवा इससे सहमत हो जाये कि उक्त नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उक्त नियम तत्पश्चात् उक्त रूपेण रूपान्तरित स्वरूप में ही प्रभावयुक्त अथवा प्रभावशून्य यथा स्थिति, होगा तथापि इस भांति उक्त नियम के अन्तर्गत पूर्णतः की गई किसी बात की वैधता पर वैसा कोई रूपान्तरण अथवा अभिशून्यन, प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा;

परन्तु शर्त यह है कि दण्ड विषय की प्रावधानों [Penal provisions] के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन बनाये गये नियम राज्यविधान मंडल के सदन द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही प्रभाव में आयेंगे।

२८. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति:—[१] यदि उस अधिनियम के प्रावधानों की कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाय तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा ऐसा प्रावधान जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो किन्तु इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो बना सकेगी।

[२] उप-धारा [१] के अधीन किसी विज्ञप्ति द्वारा किये गये प्रावधानों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों वे इस अधि नियम में अधि नियमित हों और उक्त कोई विज्ञप्ति ऐसी किसी तारीख नियत दिन से पहले की न हो—से अतीत प्रभावी [Vetrospective] बनाई जा सकेगी;

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति, किसी विज्ञप्ति के ऐसे अंश के कारण जो उक्त विज्ञप्ति के बनाये जाने की तारीख की पूर्ववर्ती किसी तारीख से अतीत प्रभावी बताता हो, किसी अपराध का अपराधी नहीं माना जायेगा ।

स्पष्टीकरण:—‘नियत दिन’ से किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस तारीख से तात्पर्य है जो धारा १ की उप धारा [३] के अधीन उक्त क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति की जाय ।

२६. निरसन:—बीकानेर कम्पलसरी प्राईमरी एजुकेशन एक्ट १९२९ तथा अजमेर प्राईमरी एजुकेशन एक्ट १९२९ [अजमेर एक्ट २ आफ १९५२] और राज्य के किसी भाग में प्रवर्तनशील कोई अन्य तदनुरूप विधि, एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं, किन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त एक्टों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिये गये कोई आदेश, जारी की गई कोई विज्ञप्ति, किया गया कोई कार्य, की गई कार्यवाही या चलाया गया कोई मामला इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिया गया, जारी की गई, किया गया, की गई या चलाई गई समझी जायेगी ।

कार्यालय निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर

पत्रांक नि० शि० जी० डी०

दिनांक ८-७-६६

समस्त प्रधानाध्यापक,

उ० मा० शाला, उच्च माध्यमिक शाला, माध्यमिक शालाएं, प्राथमिक शालाएं,
(राजकीय एवम् मान्यता प्राप्त) जिला जयपुर,

(विषय:— शिक्षा विभाग राजस्थान सत्र ६६-६७ का कलेण्डर,

उक्त विषय में शिक्षा विभाग राजस्थान सत्र ६६-६७ को लिए उपयोगार्थ पंचांग (कलेण्डर, प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पंचांग में सत्र पर्यन्त के अवकाश विवरण आदि के अलावा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजन दिवश भी दिए जा रहे हैं ।

निरीक्षक, शिक्षणालय, जयपुर

आदेश

राजस्थान राज्य की समस्त राजकीय तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवम् प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सत्र पर्यन्त कार्यक्रमों में एकता लाने हेतु इस विभाग की ओर से सत्र १९६६-६७ के उपयोगार्थ पंचांग (कलेण्डर) प्रस्तुत किया गया है, इस पंचांग में सत्र पर्यन्त के अवकाश विवरण आदि के अलावा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की विधि का भी सविस्तार उल्लेख है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का संचालन तथा आयोजन वांछनीय है, अवसर अथवा कार्यवशात् यदि इसमें किसी संस्था प्रधान को परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हो तो इस कार्यालय की पूर्व आज्ञा प्राप्त कर लेना अपेक्षित है ।

कलेण्डर सम्बन्धी सूचना सत्र १९६६-६७

१. समस्त शिक्षण संस्थायें शुक्रवार दिनांक १ जुलाई ६६ को शीघ्रमावकाश के पश्चात् खुलेगी । समय प्रातः काल का रहेगा । समस्त शालाओं के प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिकाएं एवं छात्र-छात्राओं में प्रवेश से सम्बन्धित अध्यापक, अध्यापिकायें २३ जून ६६ तक अपनी शालाओं में उपस्थित हो जाएं ।

२. (क) प्रवेश कार्य ३० जून तक समाप्त हो जाए एवं समय विभाग चक्र तैयार कर लिया जावे और एक जुलाई से नियमित शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जावे । सामान्य तथा ५ जुलाई के बाद भर्ती न की जावे ।

(ख) अभिभावकों (राज कर्मचारी तथा अन्य कोई व्यक्ति) के स्थान परिवर्तन करने पर पूर्व संस्था प्रधान द्वारा दिये हुए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर छात्र व छात्रा को सत्र के बीच में प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ग) वर्ष भर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को १५ जुलाई तक मासिक पढ़ाई योजना के अनुसार विभक्त किया जाय और न्यूनतम लिखित कार्य की योजना तैयार करली जावे और अक्टूबर ६६ व फरवरी ६७ में लिखित कार्य का मूल्यांकन सत्र में दो बार इसी आधार पर किया जावे ।

३. सायंकाल का समय परीक्षा-काल को छोड़कर सत्र पर्यान्त अनिवार्य रूप से खेल अभ्यास में लगाया जावे ।

४. शनिवार को हर अन्तु (पीरीय) में से पांच मिनट और खेल के ५० मिनट कुल १० मिनट के समय की पाठ्यतर कार्यक्रम में लगाया जाय ।

५. (अ) (प्रथम स्वीकृत अवकाश

B. Rule

१. स्वतंत्रता दिवस	१५-८-६६	१
२. रक्षा बन्धन	३०-८-६६	१
३. दशहरा अवकाश	१३-१०-६६ २४-१०-६६	१२ दिन
४. दीपावली	१२-११-६६ से १३-११-६६	२ दिन
५. गुरुनानक दिवस	२८-११-६६	१
६. शीतकालीन अवकाश	२५-१२-६६ से १-१-६७	८
७. उदुलफित्तर	१३-१-६७	१
८. गणतन्त्र दिवस	२६-१-६७	१
९. इदुलजुहा	२३-३-६७	१
१०. होली	२६-३-६७ से २७-३-६७	२ दिन
११. महावीर जयन्ती	२२-४-६७	१

(अ) निम्नलिखित दिनों में से स्थानीय आवश्यकतानुसार तीन अवकाश संस्था प्रधान घोषित कर सकता है । सत्र आरम्भ होने पर इन में से तीन अवकाशों की सूचना संस्था प्रधान सम्बन्धित निरीक्षक को भेज दें ।

१. वाराणसी	३ जुलाई ६६)
२. जन्माष्टमी	७ सितम्बर ६६)
३. महाशिवरात्रि	७ फरवरी ६७) ३ दिन
४. रामनवमी	१९ अप्रैल ६७)
५. मोहर्न	२१ अप्रैल ६७)

(चन्द्रोदय के अनुसार)

(२) उत्सव दिवस

६. निम्नलिखित उत्सव दिवस धर्म निरपेक्षता की दृष्टिगत रखते हुए उत्साह पूर्वक बनाये जावें ।

(क) जिस उत्सव के दिन रविवार हो स्वीकृति अवकाश हो उस उत्सव को एक दिन पहले या बाद में मनाया जाए ।

(ख) उत्सव दिवस के दिन शनिवार की तरह ही पूरे आठों कालांश हों । प्रत्येक कालांश में से पांच मिनट का समय बचाया जाय, आवश्यक हो तो इस बचे समय में खेल का समय जोड़ कर उस अवधि में उत्सव मनाया जावे :—

१. तिलक शताब्दी	१ अगस्त ६६
२. स्वतन्त्रता दिवस	१५ अगस्त
३. अध्यापक दिवस	५ सितम्बर

४. जन्माष्टमी	७ सितम्बर
५. हिन्दी दिवस	१४ सितम्बर
६. महात्मा गान्धी जन्म दिवस	२ अक्टूबर
७. कालिदास जयन्ती	२३ अक्टूबर
८. संयुक्त राष्ट्र दिवस	२ अक्टूबर
९. बालदिवस	१४ नवम्बर
१०. गुरुनानक दिवस	२८ नवम्बर
११. क्रिसमस दिवस	२५ दिसम्बर
१२. विवेकानन्द दिवस	१३ जनवरी ६७
१३. गणतन्त्र दिवस	२६ जनवरी
१४. वसन्तपंचमी	१४ फरवरी
१५. दयानन्द सरस्वती दिवस	९ मार्च
१६. रामनवमी	१९ अप्रैल
१७. महावीर जयन्ती	२२ अप्रैल
१८. रवीन्द्र दिवस	७ मई

७. दीपावली, शीतकालीन अवकाश व ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के कार्यालय राजपत्रित अवकाश का उपयोग करेंगे।

८. (अ) संस्था प्रधान उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त सत्र पर्यन्त दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं। उच्च एवम् उच्चतर माध्यमिक और शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधान अध्यापक, अध्यापिकाएँ अपने निकटतम उच्च अधिकारी को पूर्व सूचना दें और प्राथमिक व मिडिल शालाओं के प्रधानाध्यापक सम्बन्धित निरीक्षक, उपनिरीक्षक से पूर्व स्वीकृति ले, और

(आ) जिलाधीश द्वारा घोषित अवकाश विद्यालयों में नहीं होंगे। यदि किसी दिन करना आवश्यक समझा जाए तो प्रधान अध्यापक द्वारा घोषित किए जाने वाले दो अवकाशों में से ही किया जाए।

९. अन्य कार्यालयों (विद्यालय के अतिरिक्त) में राजपत्रित अवकाश ही माने जायेंगे।

१०. विद्यालय संरचना का चुनाव २५ अगस्त ६६ तक समाप्त कर दिया जाए।

११. टैस्ट व परीक्षाएँ।

(तृतीय) टैस्ट व परीक्षाएँ

प्रथम टैस्ट	२२ अगस्त	—	२७ अगस्त
द्वितीय टैस्ट	२६ अक्टूबर	—	२९ अक्टूबर
अर्द्धवार्षिक परीक्षा	१९ दिसम्बर	—	२४ दिसम्बर
तृतीय टैस्ट	२० फरवरी	—	२५ फरवरी
वार्षिक परीक्षा	२४ अप्रैल	से	आरम्भ

१ टैस्ट उपरोक्त दिनों में कमी भी कालांशों में ही लिए जाए। प्रत्येक विषय का टैस्ट एक या दो कालांशों में समाप्त हो जाना चाहिए। यदि पूरे दिन टैस्ट न हो तो उस में नियमित पाठन कार्य होने

२ बोर्ड की परीक्षा के केन्द्र विद्यालय परीक्षा काल में अंशतः बन्द रहेंगे । कार्य पूर्ण करने के लिए संस्था प्रधान छुट्टियों को कम करके इस काल को पूरा करेंगे । छुट्टियों को कम करने का निर्णय कर सत्रारम्भ में प्रधान अपने सम्बन्धित जिला निरीक्षक, उपाध्यक्ष, निरीक्षिका के पास सूचना प्रेषित करेंगे ।

१२. खेलकूद प्रतियोगिताएं (उच्च व उच्चतर माध्यमिक शालाएं)

जिलास्तरीय छात्र प्रतियोगिताएं २ अक्टूबर — ८ अक्टूबर के मध्य

छात्र मंडलीय प्रतियोगिताएं १० अक्टूबर — १३ अक्टूबर

छात्र मंडलीय प्रतियोगिताएं

वीकानेर विभाग	१३ नवम्बर — १६ नवम्बर
जयपुर विभाग	१३ नवम्बर — १६ नवम्बर
कोटा विभाग	१५ नवम्बर — १८ नवम्बर
अजमेर विभाग	१७ नवम्बर — २० नवम्बर
जोधपुर विभाग	१७ नवम्बर — २० नवम्बर
उदयपुर	२० नवम्बर — २३ नवम्बर
छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं	२५ नवम्बर — २९ नवम्बर
छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं	७ दिसम्बर — ११ दिसम्बर

राष्ट्रीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिताएं २८ दिसम्बर — १ जनवरी

५. १३. शिक्षण संस्थाओं में समय परिवर्तन (मध्याह्न का) १ सितम्बर ६६ और प्रातःकाल का १ अप्रैल ६७ से होगा । ऋतु भिन्नता के कारण यदि आवश्यक हो तो इसमें १५ दिन का फेर बदल निरीक्षक निरीक्षिका की आज्ञा से किया जा सकता है, निरीक्षक निरीक्षिका इसकी सूचना अतिरिक्त शिक्षा संचालक को देंगे ।

१४. शालाओं की अपने वार्षिक उत्सव, प्रतियोगिताएं आदि दिसम्बर के अन्त तक समाप्त कर देनी चाहिए ।

१५. स्काउट एवं गाइड कार्यालयः—

१० जुलाई प्रेसिडेंट एकाउन्ट के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि ।

२६ जुलाई से ३० जुलाई — कमिशनर (स्काउट) प्रशिक्षण शिविर, सांगानेर ।

२८ जुलाई से ३० जुलाई मन्त्री (एकाउन्ट) प्रशिक्षण शिविर सांगानेर ।

३१ जुलाई स्टेट काउन्सिल की बैठक, जयपुर ।

७ सितम्बर से १४ सितम्बर पेट्रोल लीडर शिविर

७ सितम्बर से १४ सितम्बर उद्योग पर्व

४ अक्टूबर १५ अक्टूबर स्काउटमास्टर प्रशिक्षण शिविर

६ अक्टूबर से १५ अक्टूबर — गाइड कैप्टीन प्रशिक्षण शिविर

२५ अक्टूबर प्रथम श्रेणी के बालबच्चों के प्रार्थना-पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ।

१ नवम्बर कव स्वर्ण जयन्ती उत्सव

५ नवम्बर — कव मास्टर प्रशिक्षण शिविर की समाप्ति

७ नवम्बर स्काउट गाइड दिवस

१७ नवम्बर से २३ नवम्बर—प्रेसिडेंट एकाउंट/गाइड की दिल्ली में रेली ।

५ दिसम्बर—प्रथम श्रेणी वालचर, गाइड रेली समाप्त ।

७ दिसम्बर से १८ दिसम्बर—हिमालय बुड वैंज (गाइड) द्वितीय कोर्स समाप्त ।

२६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर—९वीं स्टेड रोवर सूट, माउन्ट आवू

२६ फरवरी ६७—बैंडन पावंल दिवस

१६. एन. सी. सी. शिविर

एन. सी. सी. जूनियर डिविजन कैम्प दशहरा अवकाश में ।

१७. विभिन्न परीक्षाएं—

१. माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा—१४ मार्च से प्रारम्भ ।

२. शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षाएं—२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

३. कला परीक्षाएं—२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

४. संस्कृत परीक्षाएं—२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

५. आयुर्वेदिक परीक्षाएं—२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

६. उद्योग परीक्षाएं—२४ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

७. शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा—२७ अप्रैल ६७ से प्रारम्भ ।

८. संगित परीक्षाएं—२ मई ६७ से प्रारम्भ ।

१८. अवकाशः—

दीपावली अवकाश १३ अक्टूबर से २४ अक्टूबर ६६

शीतकालीन अवकाश २५ दिसम्बर से १ जनवरी ६७

ग्रीष्म अवकाश १७ मई ६७ से ३० जून ६७

१९-२३ जून ६७ प्रधान अध्यपिक, प्रधान अध्यापिकाएं व भर्ती से सम्बन्धित अध्यापक । अध्यापिकाएं अपनी शाला में उपस्थित हो जायें । तथा सत्र आरम्भ होने से पहले भर्ती कार्य सम्पूर्ण हो जाय और समय विभाग चक्र बना दिया जाय । ह० अनिल बोधिया ।

—अ० शि० संचालक, बीकानेर

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय—अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

सरक्यूलर

विषय—सहायताार्थ अनुदान नियमावली १९६३ के नियम ३ (१६) के अन्तर्गत सेवाकाल में वृद्धि ।

चूँकि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि समस्त सहायता प्राप्त संस्थाओं में नियम ३ (१६) का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिये अतः पूर्ववर्ती समस्त आदेशों, सरक्यूलरों, स्थायी आदेशों आदि जो इस विषय में जारी हुए हैं, का अधिकरण करते हुए निम्नलिखित सविस्तार अनुदेश जारी किये जाते हैंः—

(१) समस्त कर्मचारी, सिवाय उन अध्यापकों के जो भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, गृह-विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जिनकी आयु, तारीख ३०-६-६७ को अथवा

उसके पूर्व ५८ वर्ष की हो गई है, तारीख १-७-१९६७ में सेवा-निवृत्त हो जायेंगे यदि उनकी सेवाएं राज्य सरकार अथवा इस निर्देशकालय के किसी निदिष्ट आदेश के जरिये उस तारीख से आगे बढ़ाई न दी गई हों ।

(२) समस्त कर्मचारी जिनके मामले सेवा-काल को ६० वर्ष की आयु से अधिक समय तक बढ़ाने के विषय में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे किन्तु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, की तारीख १-७-१९६७ से सेवा-निवृत्त हो जायेंगे क्योंकि वे प्रवन्ध समितियों की स्वयं की जिम्मेदारी पर सेवा में रहे हैं ।

ऐसे समस्त मामलों में इस कार्यालय की सिफारिशें तारीख ३०-६-६७ के उपरान्त प्रत्याहृत की हुई समझी जायेंगी ।

(३) वे कर्मचारी जिनका सेवा-काल इस कार्यालय के किसी निदिष्ट आदेश के जरिये ६० वर्ष की आयु तक बढ़ाया गया था, नीचे लिखे अनुसार सेवा-निवृत्त हो जायेंगे:—

(क) तारीख ३१-७-६७ को यदि स्वीकृति की अवधि तारीख ३१-१२-६७ तक समाप्त होती है ।

(ख) तारीख ३०-९-६७ को यदि स्वीकृति की अवधि तारीख ३०-१२-६७ के पश्चात समाप्त होती है ।

इन मामलों में यदि स्वीकृतियों इन तारीखों से उपरान्त तक के लिये हो तो वे रद्द की हुई समझी जायेंगी ।

(४) राज्य सरकार से भी प्रार्थना की जा रही है कि वह अपनी उन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में जिनके जरिये सेवा-काल ६० वर्ष की आयु के उपरान्त तक बढ़ाया गया है, उपरोक्त (३) के अनुसार आदेश जारी करें ।

(५) तारीख ३०-६-६७ के पश्चात सेवा-काल में वृद्धि के मामलों पर सहायतायें अनुदान नियमावलि १९६३ के नियम ३ (१६) के प्रावधानों का कठोरता से अनुसरण करते हुए, विचार किया जायेगा सिवाय उन अध्यापकों के मामलों के जो वस्तुतः भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, गृह-विज्ञान, तथा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ।

(६) ऐसे मुख्य अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को जो किसी शिक्षण-वृत्त में तारीख ३० सितम्बर के पश्चात अधिवर्षिकी आयु प्राप्त करते हों, प्रवन्ध-समिति के निदिष्ट संकल्प के जरिये उस सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे स्वीकृत व्यय तब माना जायेगा जबकि सम्बन्धित संकल्प की सही प्रति प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(अनिल बोडिया)

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय—अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

अनुदान प्रार्थना-पत्रों को इस कार्यालय द्वारा जांच से पता चलता है कि काफी अनुदान प्राप्त संस्थाएं पाठन तथा अन्य शुल्क "राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम वसूल करती हैं और वसूल की गई राशि का पूर्णरूप से हिसाब में नहीं दर्शाती है।" जो इस विषय पर अनुदान नियम ३ (१२) एवं कार्यालय के निम्न परिपत्रों की अवहेलना है :

पत्रांक इडीबी : बीयूडी : डी : १५३८२ : १०७ : ५८ दिनांक ७-१०-५८)

पत्रांक इडीबी : बीयूडी : डी : १५३८२ : ११० : ५८ दिनांक १०-१०-५८) (प्रतिष्ठा सलमन है

पत्रांक इडीबी : एसीए : सी : १४१८६ : (४) ५९ दिनांक १७-१-५९)

२. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की शुल्क इस कार्यालय के पत्रांक इडीबी : एक : बी-२ : १४१८८ : ५७ : ६२ दिनांक १६-१०-६२ में दी गई दरों व वाद में समय समय पर जारी किये गए शुद्धिपत्रों से कम वसूल न की जाय तथा वसूली का छात्रानुसार मांग व वसूली रजिस्टर (Demand and Realisation Register.) रखा जाय। यदि कोई संस्था इन आदेशों में वर्णित फीस या उसकी सीमा से अधिक बिना इस कार्यालय की स्वीकृति से वसूल करती है तो वह राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-२ (४१) शिक्षा: प्रकोष्ठ १६६ : दिनांक २५-३-१९६६ के अन्तर्गत आय मानी जायेगी।

३. फीस सम्बन्धी अन्य स्पष्टिकरण इस प्रकार है :—

(क) कन्या पाठशालाओं के पाठन शुल्क को छोड़कर अन्य फीस वालकों के विद्यालयों के अनुसार वसूल होनी चाहिये।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा मान्ट-सरी स्कूलों के लिए भी शुल्कों का निर्धारण हो चुका है। अतः वे भी उन दरों के कम दरों पर शुल्क वसूल न करें।

(ग) जिन संस्थाओं का अन्य संस्था 'के रूप में अनुदान प्राप्त होता है वे जिस स्तर के लिए छात्र तैयार करते हैं या अनुदान के लिए स्टाफ व "अन्य व्यय" हेतु मार्ग पेश करते हैं, ऐसे ही स्तर की संस्था के लिए निर्धारित दरों से कम दर पर फीस वसूल नहीं करें।

(घ) जिन संस्थाओं का स्तर निर्धारित नहीं हुआ है या जिनके स्तर की समस्या के लिए राज्य सरकार ने फीस निर्धारित नहीं की है वे संस्थाएँ फीस वसूली के अपने, प्रस्ताव शीघ्र भेजकर निर्णय प्राप्त कर लें।

(ङ) सत्र ६४-६५ में वसूली की गई शुल्क की दरों में इस कार्यालय की पूर्व स्वी. ति के बिना कमी नहीं हो सकेगा।

(च) वसूल करने योग्य फीस यदि वसूल नहीं की जायेगी तो उन्हें अनुमानित आय माना जायेगा।

४. संस्थाएं चन्दे तथा दान से प्राप्त होने वाली राशि का भी हिसाब रखें। दानदाता के नाम मध्य वल्लिदयतः व पूरे पत्र के रसीद जारी करें और इस का नियमित हिसाब जांच के समय पेश करना होगा।

५. संस्था का वार्षिक हिसाब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जांच कराया जा कर रिपोर्ट में आय का विवरण अनुदान नियम ५ के नोट २ में दर्शाई गई मदों के अनुसार बनाया जायेगा। पैरा (a) और (b) यानि पाठन शुल्क, छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क, प्रवेश व पुनः प्रवेश शुल्क, तथा दण्ड को छोड़कर शेष सभी प्रकार की शुल्कों का पिछले वर्षों का पोते बाकी भी दिखाया जाकर प्रमाण स्वरूप निम्न सथापन नोट के रूप में किया जायः—

“संस्था की आय का हिसाब अनुदान नियम ५ के नोट २ के अन्तर्गत ठीक है फीस/आप नियमानुसार पूर्ण वसूल हो चुकी है..... रुपये छात्रों से निर्म्न पदों में वसूल करने शेष हैं।” पाठन शुल्क के आकड़े निश्चित प्रतिशत पर “पूर्ण शुल्क व अर्द्ध माफी” का ध्यान में रखते हुए दर्शाये गये हैं।

इस पत्र की प्राप्ति रसीद भेजी जाय।

अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

सं० E D.B./Bud/D/15-383/107/58

दिनांक ७ अक्टूबर १९५८

सरक्यूलर

राजस्थान में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है चाहिये कि वे सब प्रकार की फीस भाविष्य में (अर्थात् १९५८-५९ के सत्र से) उन्हीं दरों के अनुसार वसूल करें जो दरें सरकार द्वारा उन स्थानों में स्थित सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के लिये मंजूर की गई है और इन्हीं समयावधियों के लिये जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।

यदि इसका अनुसरण नहीं किया जायगा तो सहायता प्राप्त संस्थाएं, 'सहायतायर्थ अनुदान' से उस सीमा तक वंचित रहेगी जिस सीमा तक वे इसका पालन नहीं करेंगी।

हस्ताक्षर—
निदेशक, शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

सं० E D.B./Bud/D-15382/110/58

बीकानेर १० अक्टूबर १९५८

सरक्यूलर

इस कार्यालय के सरक्यूलर सं० E D.B./Bud/D-15382/107/58 दिनांक ७ अक्टूबर १९५८ के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किन्हीं संस्थाओं में निर्धारित फीस वर्तमान समय में, उन दरों की अपेक्षा उच्चतर दरों पर वसूले की जा रही हो जो दरें सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं तो वे इस कार्यालय में पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किये बिना घटाई न जायें।

हस्ताक्षर—
निदेशक, शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

सरक्यूलर

सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस के सम्बन्ध में इस निदेशकालय के सरक्यूलर सं० EDB/Bud/D/15382/110/58 दिनांक ७ अक्टूबर १९५८ तथा सं० EBD/Bud/D-15382/110/58 दिनांक १० अक्टूबर १९५८ के क्रम में एक बार पुनः समस्त उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, निरीक्षक शिक्षा विभाग, उप-निरीक्षक शिक्षा विभाग, इन्चार्ज जिला तथा सहायक निदेशक, शिक्षा विभाग (महिला) को यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त संस्था कम से कम नवी तथा उससे ऊँची कक्षाओं से, शिक्षा विभाग की अनुसूची के अनुसार न्यूनतम फीस वसूल करे और कोई भी संस्था इस फीस को जो वह वर्तमान समय में कक्षा १ से कक्षा ८ तक किसी भी कक्षा में वसूल कर रही है बिना इस विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न घटावे।

यह भी लिखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा १ से कक्षा ८ तक में कोई ट्यूशन फीन नहीं ली जाती परन्तु ट्यूशन फीस के अलावा समस्त अन्य फीस ऐजुकेशन कार्ड में दिये हुए शिड्यूल के अनुसार वसूल की जाती है। समस्त सहायता-प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी संस्थाओं के विद्यार्थियों से इन दरों से नीची दरों पर फीस वसूल न करें और इससे होने वाली सम्पूर्ण आय का अपनी लेखा-पुस्तकों में ठीक ठीक हिसाब रखें।

हस्ताक्षर

निदेशक-शिक्षा विभाग

राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय

सहायक क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वचत,

भगवानदास रोड, जयपुर

सं० २४४७/७(६)/७७

दिनांक दिसम्बर ५, १९६६

सरक्यूलर

विषय—स्कूलों में अल्प वचत।

विद्यार्थियों में वचत करने की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर/दिसम्बर १९६६ में जयपुर जिले में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें ३०,००० रुपया फ्री कण्ड के रूप में दिया जायगा जो कि स्कूलों के तीन वर्गों (१) सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी, एस टी. सी., (२) मिडिल और (३) नगरीय प्राइमरी स्कूल (चाहे सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल लड़कों या लड़कियों के हों) में से प्रत्येक वर्ग को १०,००० रुपया बालकटर द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को सम्बन्धित शैक्षणिक अधिकारियों के माफ़त वितरित किया जायगा। यह इनाम प्रत्येक प्रवर्तित सर्वश्रेष्ठ स्कूल को १००० रुपये से ५००० रुपये तक की होगी जो कि मुख्य कार्यों पर खर्च की जायगी।

सर्वश्रेष्ठ प्रथम, द्वितीय आदि स्कूल का प्रवर्णन, नवम्बर/दिसम्बर १९६६ में उनके द्वारा किये गये अल्प वचत कार्य के आधार पर, अङ्क प्रदान करते हुए प्रतिशत के अनुसार किया जायगा, अर्थात्

१०० अङ्क पो. ओ. सेविंग बैंक एकाउण्ट—विद्यार्थियों अथवा अध्यापकों के नाम से खोले गये—के लिये ।

१०० अङ्क सी. टी. डी. एकाउण्ट—जो पेरॉल पद्धति के अनुसार स्टाफ के सदस्यों द्वारा खोले जायें उनके लिये प्राथमिकता होगी । (पुराने एकाउण्ट गिनती में लिये जायेंगे)

बराबर अङ्क प्राप्त करने के दशा में प्रवरण नवम्बर/दिसम्बर १९६६ में प्रति व्यक्ति द्वारा बचाये गये राशि के आधार पर किया जायगा ।

इस सम्बन्ध में सूचना, शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा अपने पत्र सं० NS-SHT-J-G.D. AFR/२६/६६ दिनांक १-११-६६ तथा २९-११-६६ के जरिये सभी सम्बन्धित सस्थाओं को भेजी जा चुकी है ।

एक रिपोर्ट नीचे दिये गए प्रपत्र में दिनांक १०-१-६७ तक निश्चित रूप से हिन्दी इन्स्पेक्टर्स, गर्ल्स स्कूल जयपुर को भेजी जानी है और उसकी एक प्रति सहायक क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, भगवानदास रोड़, जयपुर को भी भेजी जायगी ।

१—स्टाफ के सदस्यों की कुल संख्या ।

२—विद्यार्थियों की कुल संख्या ।

३—पो. ओ. से. बैंक एकाउण्ट्स जो चालू हैं, उनकी कुल संख्या ।

४—सी. टी. डी. एकाउण्ट्स जो चालू हैं उनकी कुल संख्या ।

क्रियात्मक उपाय—

१—समस्त विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की मार्फत तारीख ३१-१२-१९६६ तक सीधे पो. ओ. से. बैंक में प्रथम बार २) जमा कराकर एकाउण्ट खोलने या नेशनल सेविंग स्टांप खरीद कर या किसी वक्ता से इकट्ठा करके २) बचाने के लिये आग्रह करना । (नियमों के अनुसार पो. ओ. ऑफिस में अवयस्क व्यक्ति भी अपने हिसाब में स्वाधीनता से लेन देन कर सकते हैं । अवश्यकी की ओर से उसका पिता भी लेन देन कर सकता है)

२—समस्त अध्यापकों, क्लर्कों, चपरासियों आदि को पो. ओ. से. बैंक एकाउण्ट तथा सी. टी. डी. एकाउण्ट खोलने के लिये आग्रह किया जाय । सी. टी. डी. एकाउण्ट पे. रॉल पद्धति के अनुसार खोले जायें तो उत्तम है ।

जयपुर में अग्रवाल, महेश्वरी, पोदार तथा मॉडल स्कूलों ने और चाकसू, अन्टेला; बांदी-कुई, आदि स्थानों पर भी स्कूलों ने इन इनामों को जीतने का उत्साहपूर्ण प्रयत्न आरम्भ कर दिया है ।

ऐसे स्कूलों की जो इस दिशा में अच्छा कार्य करें किन्तु इनाम न जीत सकें समूचे १९६६-६७ वर्ष के लिये सर्वश्रेष्ठ स्कूल का चुनाव करने के निमित्त शामिल किया जायगा और उसके लिये रनिंग शील्ड आदि दी जायेंगी ।

अन्य विशेष सूचना के लिये डिस्ट्रिक्ट बागेनाइजर, राष्ट्रीय बचत, भगवानदास रोड़, जयपुर (टेलीफोन नं० ७४४८२) से सम्पर्क स्थापित करें ।

विषय—सहायता-प्राप्त संस्थाओं में सेक्रेटरी/मैनेजर/प्रिंसीपल के बदल जाने की स्थिति ।

यह देखने में आया है कि कुछ एक प्रबन्ध समितियाँ, सहायता-प्राप्त संस्थाओं में, सही तथा अद्यावधि पूरा हिसाब नहीं रखती हैं जिसके परिणामस्वरूप बाद में जबकि प्रबन्ध-समिति में कुछ हेरफेर हो जाता है, कितनी ही अनावश्यक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । इन अनियमितताओं के कारण, सरकारी रुपये तथा बाँझ फण्ड के रुपये का गवन होता है एवं दुरुपयोग भी होता है और अन्य प्रकार की घोर अनियमितताएँ होती हैं और प्रबन्ध-समितियों के सदस्य अपने उत्तरदायित्व से बचते हैं यद्यपि नियमानुसार उनमें से सभी व्यक्तिगतरूप से एवं संयुक्तरूप से तथा अलग अलग उत्तरदायी हैं । अतः यह निर्णय किया है कि समस्त वर्तमान कर्मचारिवर्ग जिन्हें सहायतार्थ-अनुदान की राशि निकालने के लिये प्राधिकृत किया गया है, संलग्न प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें और उसकी दो प्रतियाँ प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को भेजे जिनमें से एक प्रति वह अपने कार्यालय में और दूसरी प्रति इस कार्यालय में, रेकार्ड पर रखी जायगी ।

भविष्य में, सेक्रेटरी अथवा मैनेजर बदल जाने की दशामें, ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र पर पहिले हस्ताक्षर करा लिये जायें और तत्पश्चात् सहायतार्थ अनुदान के बिलों पर प्रति हस्ताक्षर किये जायें ।

प्रतिलिपि पत्र संख्या २ (१४४) Edu/Cell VI/६६ दिनांक २१-१-१९६७ जयपुर जो महायक सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्राइमरी सैक्ण्डरी शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजा गया ।

विषय—सहायता प्राप्त संस्थाओं की, मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने के कारण, उनकी वही हड़ देयता की पूर्ति के लिये अग्रिम भुगतान ।

प्रसंग—आपका पत्र नं० EDB/Aid/16760/14/65 दिनांक १९-१२-१९६६

निदेशानुसार राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की सूचना दी जाती है कि ऐसी विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को जो कि शिक्षा विभाग से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची में है अग्रिम सहायतार्थ अनुदान एतदर्थ आधार पर, दिया जायगा जिससे उन संस्थाओं की प्रबन्ध समितियाँ, सन् १९/६६-६७ में उनके कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण, अपने पर आई हुई अतिरिक्त देयता की पूर्ति कर सकें । यह एतदर्थ अनुदान मंहगाई-भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण भुगतान की अतिरिक्त अनुमानित राशि तक सीमित होगा । ये अग्रिम अनुदान, जब कि सन् १९६७-६८ में नियमित अनुदान दिये जायें, समायोजित न किये जायें । अगर १९६७-६८ में मंहगाई-भत्ता की दरों में स्थिरता आवेगी तो इन अग्रिम सहायतार्थ अनुदानों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा । ये सहायतार्थ अनुदान इस शर्त पर दिये जायेंगे कि संस्थाओं ने मंहगाई भत्ता की उन दरों से मान लिया है और वे अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता उन दरों से नीची दरों पर भुगतान नहीं कर रही है जिन पर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है ।

यह वित्त विभाग (व्यय-१) की सहमति से जो कि उनके पत्र आई डी नं० १५३६ दिनांक १८-३-६७ प्राप्त हुई, जारी किया जाता है ।

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय—अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र संख्या इडीवी : एड : इ : १७९२५ : स्पेशल ६५-६६ दिनांक ३-१-६७ के अनुक्रम में उक्त विषय पर राज्य सरकार से प्राप्त पत्र संख्या एफ-२ (१९४) शिक्षा प्रकोष्ठ ६:६६ दिनांक ३१-३-६७ की प्रति भेजी जाती है तथा तत्सम्बन्ध में निम्न आदेश दिये जाते हैं जिनका अविलम्ब अनुपालन किया जाकर इस कार्यालय को सूचित किया जाय ताकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यथेष्ट अधिमत्त भेजा जा सके—

(१) संस्था के व्यवस्थापक जो सत्र ६६-६७ में उक्त विज्ञप्ति के अनुसार मंहगाई भत्ते पर अनुदान ले चुके हैं/लेने हेतु मांग पेश की है तथा जो भविष्य में मांग पेश करने से पहले “व्यवस्थापक समिति” द्वारा निम्न प्रारूप में पारित किये गए प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की जाय—

श्री.....
(संस्था का नाम) की व्यवस्था समिति अपनी आज दिनांक..... की बैठक में प्रस्ताव संख्या..... के अनुसार स्वीकार करती है कि संस्था के कर्मचारियों को दिनांक..... से राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उनकी ही श्रेणी के कर्मचारियों को समय समय पर दी जाने वाली दर से कम मंहगाई भत्ता नहीं होगा।

हस्ताक्षर अधिकृत पदाधिकारी मय पद।

(२) मंहगाई भत्ते के लिए बनाये जाने वाले स्टेटमेंट पर निम्न आदेश के प्रमाण-पत्र दर्ज कराये जाय—

(क) केवल उन्ही पदों पर मंहगाई भत्ते की मांग की गई है जो कि विभाग द्वारा अनुदान हेतु स्वीकृत हैं।

(ख) इस मांग को मैं इस दस्ते सहित स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में हिसाब की जांच के दौरान और अधिक उद या अमान्य दर के फलस्वरूप अधिक भुगतान होना पाया गया तो विभाग द्वारा चाहे गए रूप में वह राशि अविलम्ब लौटा दी जायगी।

(ग) उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव व्यवस्था समिति द्वारा उसकी बैठक दिनांक..... के प्रस्ताव संख्या..... से पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

ऐसे मांग पत्रों पर संस्था की ओर से केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करें जिसके हस्ताक्षरों से अनुदान राशि उठाई जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी सत्र ६६-६७ में जारी की गई स्वीकृतियों को उपरोक्त निदेश के अनुसार पुनः जांच करके अपना अभिवेदन मय व्यवस्था समिति के प्रस्ताव व प्रमाण-पत्रों के इस कार्यालय को अविलम्ब पेश करेंगे।

सत्र ६६-६७ में दिये गए महगाई भत्ते की राशि के बारे में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने की दशा में उक्त राशि को सत्र ६७-६८ में दी जाने वाली अन्तरिम किस्तों में भी शुमार किया जा सकता है।

अपर निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय—प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

तारीख १८ फरवरी, १९६७

स्थायी आदेश नं० ७, सन् १९६७

विषय:— सहायता-प्राप्त संस्थाओं में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से ली जाने वाली फीस की प्रति पूर्ति।

केन्द्रीय सरकार कुछेक मामलों में अपने कर्मचारियों को उन स्वीकृत ट्यूशन फीस तथा अन्य फीस की प्रति पूर्ति के निमित्त आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है जो कि उनके आश्रित विद्यार्थियों (Wards) से सहायता-प्राप्त एवं मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में ली जाती है। ऐसी रिपोर्ट की गई है कि इस प्रकार की प्रति पूर्ति को आडिट में रोका जा रहा है कारण कि यह प्रमाण-पत्र नहीं है कि आ। वे फीस राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है।

यद्यपि राज्य सरकार ने अभी तक सहायता-प्राप्त एवं मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में ली जाने वाली ट्यूशन तथा अन्य फीस की एक-समान दर निर्धारित नहीं की है जिस कि सहायता-अनुदान नियमावलि १९६३ के नियम ३ (१२) द्वारा अपेक्षित है, किन्तु ऐसी फीस राज्य सरकार द्वारा इस विषय में निश्चित पमाने से नाची नहीं हो सकती और यही राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वसूल की जा सकती हैं।

परिणामतः एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि तारीख १-४-१९६३ के पहिले किसी भी संस्था में जिन दरों पर ट्यूशन तथा अन्य फीस वसूल की जा रही थी अथवा जिनकी स्वीकृति तत्पश्चात् उस संस्था ने इस कार्यालय से प्राप्त कर ली है वे सरकार द्वारा यथाविधि स्वीकृत दरें समझी जायेंगी और इस तथ्य का एक प्रमाण-पत्र, सत्यानं प्रधान अधिकारी द्वारा मलग्न प्रपत्र में, उन संरक्षकों को जारी किया जायगा जो कि तदर्थ निवेदन करें। प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी प्रमाण-पत्र का सत्यापन करेंगे और सबूत के रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

हस्ताक्षर आनेल बोडिया

अतिरिक्त निदेशक

प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र

प्रमाण-पत्र फीस की प्रतिपूर्ति के विषय में ।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित द्यूशन तथा अन्य फीस जो कि श्री..... पुत्र श्री..... विद्यार्थी कक्षा..... संस्था..... से वसूल की गई है यथाविधि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है :—

क्रम संख्या	फीस का व्योरा	दर	अवधि	राशि
१—	द्यूशन फीस			
२—	वाणिज्य फीस			
३				
४				
५				
६				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्योरा रेकाडें से सत्यापित कर लिया गया है और सही है ।

तारीख.....
 पूर्तिहस्ताक्षरित
 मुहर कार्यालय

हस्ताक्षर (मुहर सहित)
 मुख्य अधिकारी, संस्था

राजस्थान सरकार
 वित्त विभाग व्यय नियम

आदेश

क्रमांक एफ १, १६, वि० वि० व्यय नियम ६६—१
 विषय—मंहगाई भत्ता,

दिनांक, जयपुर १ अक्टूबर १९६६

राजस्थान के राज्यपाल ने प्रसन्नतापूर्वक आदेश दिया है कि १ अक्टूबर १९६६ से उन राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम १९६१ के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन शृंखलाओं में वेतन प्राप्त करते हैं उनको मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर मिलेगा—

वेतन प्रतिमाह

रुपये

७० से कम

७० और इससे अधिक लेकिन ११० से कम

मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह

रुपये

३५ पैंतीस रुपये

४१ इकतालिस रुपये

११० और इससे अधिक लेकिन १५० से कम	५० पचास रुपये
१५० और इससे अधिक लेकिन २१० से कम	६९ गुनहतर रुपये
२१० और इससे अधिक लेकिन ३८० से कम	७६ छिहतर रुपये
३८० और इससे अधिक लेकिन ४०० से कम	वह रकम जो वेतन के ४५६ तक पहुँचने से कम पड़ती है।
४०० और इसमें अधिक लेकिन २१९४ तक	यह रकम जो वेतन के २२५० रु० तक पहुँचने में कम पड़ती है।
२१९४ से अधिक	

२. राज्यपाल ने प्रसन्नतापूर्वक यह भी आदेश दिया है कि इसी तारीख अर्थात् १ अक्टूबर १९६६ से उन राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन श्रृंखलाओं से पहले के वेतन मान से वेतन लेते हैं उनको निम्नलिखित अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा—

परिलाभः एमाल्यूमेन्टसः प्रतिमाह महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि की दर प्रि. माह

रुपये	रुपये
१०३ से कम	२
१०३ और इससे अधिक लेकिन १४६ से कम	५
१४६ और इससे अधिक लेकिन १९३ से कम	७
१९३ और इससे अधिक लेकिन २७० से कम	९
२७० और इससे अधिक लेकिन ४४५ से कम	११
४४५ और इससे अधिक लेकिन २२३९ तक	११
२२३९ से अधिक	वह रकम जो परिलाभ एमाल्यूमेन्टस में मिलाने पर कुल जोड़ २२५० हो जावे।

३. अनुच्छेद २ में उल्लेखित परिलाभः—एमाल्यूमेन्टस शब्द का तात्पर्य उस राशि से हो जो राजस्थान सेवा नियम ७ : २४ : के अन्तर्गत वेतन की परिमापा में है तथा महंगाई वेतन महंगाई भत्ता जो वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१६-वि० वि० व्यव नियम ६६.१ दिनांक १८-६-६६ के अन्तर्गत मिलता है का कुल योग है।

राज्यपाल के आदेश से

मा० मुकर्जी

ह० के० डी० भार्गव

वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग (व्यय-नियम)

अधिमूचना

नं० एफ २ (बी) (३४) एफ डी० (एनसेप-हलस)/६६-१ दिनांक जयपुर, १६ जून १९६६

विषय राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) हलस १९६१—उनमें संगोवन ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य-पाल महोदय, राजस्थान एतद् द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) हलस १९६१ में और संगोवन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

१—ये नियम राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) संगोवन नियम १९६६ कहलायेंगे ।

२—ये अप्रैल १९६६ के अन्तिम दिन में लागू हुए समझे जायेंगे सिवाय उस स्थिति के जबकि अन्यथा निर्दिष्ट किया जा चुका हो ।

३—राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) हलस १९६१ में नियम ५ के उप नियम (५) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायगा—

“(६) प्रवरण हेतु विनिष्ट रोक” तथा संकेताक्षर “S. B.” से अभिप्राय वेतन-श्रृंखला में उस स्थिति से है जिसका नियमन करते समय, नियुक्ति करने वाला अधिकारी अथवा उससे नीचा कोई अन्य अधिकारी जिसे इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकेगा कि अमूर्त व्यक्ति को, निश्चित रूप से विपरीत रेकार्ड को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थिति से ऊपर नहीं जाने दिया जायगा ।

४—अनुमूची-१ में—भाग-क संशोधित वेतन-दरें (पुस्तिका का पृष्ठ ६) :—

(१) क्रम सरया १ से १९ तक के समझ लिखे हुए शब्द तथा अङ्क निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किये जायेंगे : —

वेतन-दर सं०

वेतन-दर

१	२
१—	४५-१-५५-१७-१-६२-S. B. ६४-१-७०-२-७६-E. B. २-८०
२—	५०-१-६०-६२-१-६७-S. B.-७०-२-८६-E. B.-२-९०
३—	६५-१-७०-२-८०-८ -२-९०-४-९८-S. B.-१०६-११०
४—	६५-२-७५-३-९०-E. B.-९७-४-१०५-५-१२०-S. B.-१३०-५-१४०
५—	७५-३-१०५-१११-३-१२०-५-१३०-S. B.-१४०-५-१५०
६—	७५-३-९०-४-११०-१२०-५-१४५-S. B. & E. B-५-१७५
७—	कोई वेतन-दर नहीं
८—	७५-४-९५-५-१०५-E. B.-५-१२०-१३०-E. B.-५-१५५-S. B.-१६५-५-२००
९—	९०-४-१०२-E. B.-४-११०-५-१३५-१४५-५-१७०-S. B.-१८०-५-२००

१०—	९०-४-११०-E.B.-५-१३५-१४५-५-१५५-७-१७७-S. B-१९५-१०-२२५
११—	१८५-५-१५५-१६६-८-१९०-२००-S. B-२२०-१०-२४०
१२—	१२०-५-१५०-८-१८७-२००-१०-२५०-S. B-२७०-१०-३००
१३—	११५-५-१५५-१६५-E. B.-१७५-१९५-१०-२४५-S. B-२६५-१०-२८५-३००
१४—	१३०-५-१५५-१०-२०५-२२५-१०-२७५-S. B-२३५-१२ $\frac{१}{२}$ -३२०
१५—	१४०-५-१५०-७ $\frac{१}{२}$ -१८०-१०-२२०-२४०-१०-२९०-S B-३१५-३३०
१६—	१२०-५-१५५-१०-१८५-२०५-१०-२५५-S. B. & E. B.-२७५-१०-२९५-१२ $\frac{१}{२}$ -३७०-३८५
१७—	१७०-२७०-२९०-१०-३१०-१२ $\frac{१}{२}$ -३४७-S. B.-३७२-३८५
१८—	१७०-२७०-२९०-१०-३१०-१२ $\frac{१}{२}$ -३४७-S. B-३७२-३७५-१२ $\frac{१}{२}$ -४००
१९—	२००-१०-३००-३२२ $\frac{१}{२}$ -१२ $\frac{१}{२}$ -३८५-S B.-४१०-१२ $\frac{१}{२}$ -४३५-४५०

[११] वर्तमान वेतन-दर '३२ क' के स्थान पर निम्नलिखित निविष्ट की जायेगी—
"३२-क" "१३.००-६०-१६००"

[II] वर्तमान वेतन-दर ३६ के स्थान पर निम्नलिखित निविष्ट की जायेगी—
"३७" २०००-१००-२५००"

टिप्पण—राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स १९६१ के भाग ग तथा घ में दिये हुए संशोधित वेतन-दरों के निर्देश उपरोक्त भाग-क में अनुसूची-१ में यथा संशोधित वेतन-दरों के प्रसंगवद्ध निर्देश समझे जायेंगे।

४. शीर्षक "राजस्थान शिक्षा सेवा (सामान्य ब्रांच) में (क) निम्नलिखित नई प्रविष्टियां विनिष्ट की जायेंगी—

१	२	३	४
निदेशक शिक्षा विभाग	कुछ नहीं	१६५०-७५-१८००-१००-	(३५)
यदि कोई हो)		२०००	
संयुक्त निदेशक, प्राइमरी एव कुछ नहीं		९००-१०-१५०० न्यूनतम	(३२)
सेकण्डरी शिक्षा, (यदि कोई हो)		वेतन १०५०	
निदेशक विज्ञान शिक्षा संस्था	६५०-५०-	९००-५०-१५०० न्यूनतम	(३२)
	१२५० (३०)	वेतन १,५०	

निदेशक स्टेटइंस्टीट्यूट ऑफ
एजुकेशन

(ख) वरिष्ठ वेतन-श्रृंखला में रखे गये पद—

१ उप निदेशक शिक्षा विभाग	शब्द एवं अंक "५५०-३०-८२०-EB-३०-
२. निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा	८५०-५०-९५०" तथा "१३८"
३. प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज	पाश्चात्तिक पदों के सामने जो स्तर ३ व ४ में
४. निदेशक संस्कृत शिक्षा	लिखे हुए हैं, के स्थान पर शब्द तथा अंक

५ प्रिंसिपल, कालेज शारीरिक शिक्षा "६५०-५०-१२५० न्यूनतम वेतन ७५०" तथा "(३०)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

६. प्रिंसिपल, साइल पब्लिक स्कूल

(ग) निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि उपरोक्त (ख) की क्रम सं० ६ के नीचे निविष्ट की जायगी।

१	२	३	४
७ उप निदेशक (वरिष्ठ) स्टेट इन्स्टीट्यूट शिक्षा	६५०-५०-१२५० न्यूनतम वेतन		(३०)
८. सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स।	७५०		
९ निदेशक मूल्यांकन			
(घ) उप शीर्षक "सामान्य वेतन श्रंखला १" के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियां मय पदों के विलोपित की जायेंगी।			
(ङ) शीर्षक "सामान्य वेतन श्रंखला १ के अन्तर्गत पद" के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि की जायेंगी।			

१	२	३	३
१. निरीक्षक/निरीक्षिका, शिक्षा विभाग	३००-२५-५०-३८-७००		
२. सहायक निदेशक	"	५०-३०-८२०-ED-	
३. ३१ निदेशक (जूनियर) एस टी सी	"	३०-८५०-५०-१/००	
४. रजिस्ट्रार डिप्टी परीक्षा	"		
५. मूल्यांकन अधिकारी, स्टेट एजुकेशन ३ बैलुएशन यूनिट	"		
६. रजिस्ट्रार, बोर्ड टेकनिकल शिक्षा	"		
७. वाइस प्रिंसिपल, कालेज शारीरिक शिक्षा	"		
(घ) उप शीर्षक "सामान्य वेतन श्रंखला ' २, ३, ४ तथा ५' के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियां, मय प्रविष्टियां जो वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ १ (५१) FD (A) रूल्स/६१/४ दिनांक २१-८-६२ के अधीन निविष्ट की गई है, मय उप-शीर्षकों के विलोपित की जायेंगी।			
(ङ) शीर्षक "सामान्य वेतन श्रंखला २" के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां निविष्ट की जायेंगी --			

१	२	३	४
१. मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका हाई स्कूल/जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल	२५०-१५-४००-२००-५००		

१	२	३	४	५
२. मुख्य अध्यापक बी० एस० टी० सी०		„		
३. सहायक निदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन		„		
४. मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका शिशु स्कूल		„		
५. मुख्य अध्यापक, २५८-१५-४००-२०-५०० नेत्रहीन विद्यालय				ऐसे व्यक्ति से जो १-४-६६ से पूर्व हायर सेकण्डरी या
६. ऑडियो विजुअल एजुकेशन अफसर	„			मल्टी परपज हायर सेक० स्कूल के मुख्य अध्यापक/
७. उप-निरीक्षक शिक्षा विभाग	„			मुख्य अध्यापिका के पद पर नियुक्त किया गया है, भिन्न
८. पी० ए०, अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (पी. एण्ड एस.)	२८५-२५-५६०-EB-३०-८००		(२६)	व्यक्ति मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका हायर सेकण्डरी
९. मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका, हायर सेक. तथा मल्टी परपज हायर सेकण्डरी स्कूल	३००-२५-६००			मल्टी परपज हायर सेक० स्कूल के पद पर नियुक्त किया जाने पर अपना वेतन अपनी वेतन श्रृंखला में दो
१०. प्राध्यापक अध्यापक, ट्रेनिंग कालेज।	२५०-२५-५५०-३०-७००-२५-७५०			सीडी (स्टेजेज) ऊपर नियत करा सकेगा किन्तु शर्त यह
११. रिसर्च अधिकारी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	„			है कि उन्नति डिपार्टमेंटल कमेटी की राय पर की
१२. टेक्नीकल लेक्चरर सांईस शिक्षा यूनिट	„			जायगी जो कि उन्नति सम्बन्धी नियमों के अनुसार ए में होगी। कोई व्यक्ति जो
८ शीर्षक “राजस्थान एजुकेशन सर्विस (कॉल्लिजिएट ब्रांच (पृष्ठ १५) उप-शीर्षक “प्रवर वेतन-श्रृंखला में रखे गये पद” के अन्तर्गत।				इसी प्रकार उन्नति के योग्य समझा जाय वह भी अपना वेतन अपनी वेतन श्रृंखला में दो सीडी (स्टेजेज) ऊपर
(क) निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि निविष्ट की जायेगी।				नियत करा सकेगा यदि वह मुख्य अध्यापक बी. एस. टी. सी स्कूल के मुख्य अध्यापक के पद पर ता० १-४-६६ से काम कर रहा हो या १-४-६६ के पश्चात उन्नत किया गया हो।

१	२	३	४
निदेशक शिक्षा विभाग	१६५०-७५-१८००-१००-२००० (३५)		
(ख)	शब्द तथा अंक "६५०-५०-१२५० न्यूनतम वेतन ७५० प्रतिमाह" और "(३०)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "९५०-५०-१५०० न्यूनतम वेतन १०५०" और "(३२)" सम्बन्धित स्तम्भों में प्रिंसिपल, पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज के पद से समक्ष प्रतिस्थापित किये जायेंगे।		
(ग)	निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जायेगी।		

१	२	३	४
संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा (यदि कोई हो)	कुछ नहीं	९५०-५०-१५००- न्यूनतम वेतन १०५०	(३२)
(घ) वरिष्ठ वेतन-श्रृंखला में पद—शब्द तथा अंक "५५०-३०-८२० EB प्रिसिपल डिग्री कालेज, हेड ऑफ डिपार्टमेण्ट्स, उन विषयों के जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढाई होती हो।			
		३०-८५०-५०-९५०" और "(२८)" जो पारवांक्ति पदों के सामने स्तम्भ ३ व ४ में अङ्कित हैं, के स्थान पर शब्द तथा अंक "६५०-५०-१२५०" और "(३०)" सम्बन्धित स्तम्भों में प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	

अनुसूची 'ग'

(ग) अनुसूची १ के भाग ग में पद जो विभिन्न विभागों में हैं, (पृ० ४१)

१. पदों "अन्य कार्यालयों में सुपरिण्टेण्डेंट्स" के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियाँ निविष्ट की जायेंगी।

१	२	३	४
असिस्टेंट अधीनस्थ कार्यालयों में—	कुछ नहीं	१२०-५-१५५-१०-१८५ २०५-१०-२५५-SB & EB २७५-१०-२९५-१२५- ३७०-३८५ न्यूनतम वेतन १५५	(१६) डम श्रृंखला में वेतन अधीनस्थ कार्यालयों के उन उच्च लिपिकों को दिया जा सकेगा जो खास तौर पर, स्वीकृत पदों पर स्थायी अथवा स्थानापन्न स्थिति में नियुक्त किये जायें।

२. सचिवालय, राज लोकसेवा आयोग, विधान सभा, गवर्नर सचिवालय में असि. का पद एवं सचिवालय में राज-लोक सेवा आयोग, विधान सभा, गवर्नर सचिवालय में उच्च लिपिक का पद मध्य स्तम्भ २, ३ तथा ४ में की हुई प्रविष्टियाँ, विलोपित की जायेंगी।

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ निविष्ट की जायेंगी—

१	२	३	४	५
सचिवालय, राज-लोक सेवा आयोग, विधान सभा तथा गवर्नर सचिवालय में असिस्टेंट सचिवालय राज. लोक सेवा आयोग, विधान सभा, गवर्नर सचिवालय में उच्च लिपिक ।	१२०-५-१५५-१०-१८५ २०५-१०-२५५-SB & EB २७५-१०-२९५-१२५-३७०-३८५ न्यूनतम वेतन १४०	(१६)	उन्नति सम्बन्धी नियमों के अनुसार पदोन्नत होने पर उच्च लिपिक को असिस्टेंट के रूप में, वेतन दो सीढ़ी ऊपर के स्तर पर या १७५ रु. जो भी उसे लाभ प्रद हो, दिया जायगा ।	

३. पृष्ठ ३९ पर दी हुई निम्नलिखित प्रविष्टियां विलोपित की जायेंगी ।

१	२	३	४
प्रवर वेतन श्रृंखला मोटरों के ड्राइवर	८०-४-१००-५-१२५ तथा विशेष वेतन, यदि कोई हो ।	१०५-४-१२५-५-१५०	(७)
प्रवर वेतन श्रृंखला ट्रेक्टरों के ड्राइवर	"	"	(७)

(८) स्तम्भ १ में लिखित "मोटरों के ड्राइवर" तथा "ट्रेक्टरों के ड्राइवर" पदों के सामने स्तम्भ २ में शब्द तथा अङ्क '८०-४-१००-५-१२५ तथा विशेष वेतन यदि कोई हो' निविष्ट किये जायेंगे । शब्द "सामान्य वेतन-श्रृंखला" जो स्तम्भ १ में मोटरों के ड्राइवरों तथा ट्रेक्टरों के ड्राइवरों के लिये लिखे हुए हैं, विलोपित किये जायेंगे ।

(छ) १-वेतन-श्रृंखला नं० १-(पृष्ठ १२१)-वेतन-श्रृंखला नं० १ के नीचे वर्तमान अनुदेश '१]' के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और अनुदेश नं० '[२]' के रूप में निम्नलिखित नया अनुदेश जोड़ा जायगा ।
 " [२] ७६ पर लगा हुआ E. B. (दक्षता अवरोध) तक पार नहीं किया जायगा जब तक कि व्यक्ति मिडिल स्कूल परीक्षा पास न कर ले । S. B. (विशिष्ट अवरोध) उन व्यक्तियों के लिये लागू नहीं होगा जिनका विशेष वेतन सचिवालय, राज-लोक सेवा आयोग, विधान सभा, तथा गवर्नर सचिवालय में, दिनांक १-९-१९६१ से अनुसूची २ भाग १ के अनुसार उनके वेतन में मिला दिया गया था ।"

२-वेतन-श्रंखलानं० २-अङ्क "७६" जो अनुदेश नं० १ की लाइन १ में दिया हुआ है उसके स्थान पर अङ्क "८६" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

३-वेतन-श्रंखलानं० ६-अङ्क "१३०" जो अनुदेश नं० ६ की लाइन १ में दिया हुआ है उसके स्थान पर अङ्क "१४५" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

४-वेतन-श्रंखलानं० १६-वर्तमान अनुदेश (४) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा—

“४-नये भर्ती किये हुए व्यक्तियों को तथा उन व्यक्तियों को जिन्हें कम वेतन मिल रहा है नीचे लिखे अनुसार दिया जायेगा:—

(क) [१] पोलिटेकनिक डिप्लोमा पास व्यक्ति जो ओवरसियर, या ड्राफ्ट्समैन, ग्रेड १, या सर्वेयर ग्रेड १, या कम्प्यूटर, या ऐस्टीमेटर अथवा उन पदों पर जो परिशिष्ट में दिये हुए हैं । १७)

[२] संगीत या कला में यूनीवर्सिटी डिग्री पास या मान्यता प्राप्त सस्याओं से तत्समान डिप्लोमा पास व्यक्ति जो संगीत या कला के अध्यापक के रूप में या दस्तकारों अथवा डिजाइनरों (यह उन लोगों को नहीं मिलेगा केवल सामान्य ग्रेजुएट हैं जिनका एक विषय संगीत था) के रूप में भर्ती किये जाये । १४०)

[३] ग्रेजुएट्स जो मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, शारीरिक प्रशिक्षण में प्राप्त किये हुए हों, फिजीकल इंसट्रक्टर के रूप में भर्ती किये जाये । १४०)

[४] ग्रेजुएट्स साइन्स में जिन्हें अनुभव प्राप्त हो, जो पोलिटेकनिक या इंजीनियरिंग कालेजों में केमिस्ट या नान-टेकनिकल इंसट्रक्टर के रूप में भर्ती किये जाये । १४०)

(ख) [१] सचिवालय, राज.-लोक सेवा आयोग, विधान सभा तथा गवर्नर सचिवालय में उच्च लिपिक । १४०)

[२] अधीनस्थ कार्यालयों में असिस्टेंट । १५५)

[३] सचिवालय, राज.-लोक सेवा आयोग, विधान सभा, तथा गवर्नर सचिवालय में असिस्टेंट । १७५)

(ग) इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो ओवरसियर या तत्समान पदों पर भर्ती किये जायें और जिनका पद नाम जूनियर इंजीनियर रखा जाय । २५५)

५-वेतन श्रंखला नं० २५-अनुदेश नं० (१), (२) तथा (४) विलोपित किये जायेंगे ।

६-वेतन श्रंखला नं० २६-वर्तमान अनुदेश (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और निम्नलिखित अनुदेश (२) के रूप में निविष्ट किया जायगा —

(२) सी. ए. एस. श्रेणी १ तथा सी. ए. एस. श्रेणी २ के विषय में —

(क) सी. ए. एस. श्रेणी १ तथा सी. ए. एस. श्रेणी २ के रूप में पद नाम समाप्त कर दिये गये हैं और उन पदों को २३-८-१९६१ के पश्चात् सी. ए. एस. पद नाम दिया गया है।

(ख) स्पेशल पे/कम्पेनसेटरी एलौस की दरें जो १-९-१९६१ के पूर्व सी. ए. एस. श्रेणी १ के पद के साथ स्वीकृत थीं समस्त सिविल असिस्टेंट सर्जनों को दिनांक १-९-१९६१ से, तत्पश्चात् किये गये रूपान्तरों तथा सशोधनों के अधीन रहते हुए, होंगी।

(ग) किसी अधिकारी को दक्षता अवरोध (E B) पार करने की अनुमति देने के बारे में निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं :—

[१]-मेडिकल ग्रेजुएट्स ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष सविन्य कर चुके हों।

[२] लाइसेंसियेट (अथवा बी-डीएस) १५ वर्ष की सविन्य कर चुके हों जिसमें से दो वर्ष का अनुभव ग्रामीण डिस्पेंसरी में, या कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक या लैबर एसाइलम, या ग्रामीण एवं शिशु कल्याण केंद्रों में या एन. एम. ई. पी. या डी. सी. जी. या पी. एच. सी. या टूट्रिशन एव पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी में सविन्य का होना आवश्यक है।

[३] सेवा जो की गई हो वे अन्यथा सतोष-प्रद होनी चाहिये।

(घ) नान-प्रेक्टिसिंग एलौस और सचारी एलौस की दरें जो मेडिकल अधिकारी (सिविल असिस्टेंट सर्जन श्रेणी १) को ई. ए. एस. १ स्कीम में स्वीकृत हैं पदों की वेतन-ऋंखलाओं के संशोधित होने पर दिनांक १-९-१९६१ से अपरिवर्तित रहेंगी किन्तु तत्पश्चात् किये गये रूपान्तरों तथा सशोधनों के अधीन रहते हुए होंगी।

संशोधित पुनरीक्षित वेतन ऋंखलाओं में वेतन नियत करने के बारे में निम्नलिखित अनु-देश जारी किये जाते हैं :—

१—राजस्थान सविन्य रूप के नियम २८ के प्रावधानों के होते हुए भी, जिन्हें राज्य कर्मचारी जिन्हें वर्तमान पुनरीक्षित वेतन ऋंखलाओं में वेतन मिल रहा है, उनका वेतन संशोधित पुनरीक्षित वेतन-दरों में १-४-१९६६ को निम्न किया जायेगा।

२—जिन राज्य कर्मचारियों ने राजस्थान सिविल सविसेज (रिवाइज्ड पे) रूलस १९६१ के नियम ८ के अनुसार अपना विकल्प, रिवाइज्ड पे स्केल को चुनने के लिये नहीं दिया था वे अब नये रिवाइज्ड पे स्केल को चुनने के लिये अपना विकल्प दे सकते हैं। विकल्प लिखित में ३० सितम्बर १९६६ तक दिया जा सकेगा और उसकी सूचना राजस्थान सिविल सविसेज (रिवाइज्ड पे) रूलस १९६१ के नियम ८ के उपनियम (२) में वर्णित प्राधिकारी को दी जायेगी।

३—संशोधित पुनरीक्षित वेतन ऋंखला में आगामी वेतन-वृद्धि की तारीख, राजस्थान सिविल सविसेज (रिवाइज्ड पे) रूलस १९६१ के नियम ११ के अनुसार होगी।

४—जहाँ संशोधित पुनरीक्षित वेतन ऋंखला में अनुमत वेतन वर्तमान पुनरीक्षित वेतन ऋंखला में किसी सीढ़ी (Stage) के अनुरूप न हो उस दशा में वेतन एक सीढ़ी नीचे स्तर पर

नियत की जायेंगी और पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में वर्तमान वेतन तथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में आगणित वेतन, की अन्तर-राशी, पसलल वेतन माना जायेगा जो कि भावी वेतन-वृद्धियों में विलीन किया जायेगा।

५—ऐसे राज्य कर्मचारियों का वेतन, जो ऊँचे पदों पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं और ऊँची वेतन-श्रृंखला में वेतन पा रहे हैं, संशोधित पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में, राजस्थान सिविल सर्विसेज (निवाइज्ड पे) रूलस १९६१ के नियम १० में निर्धारित प्रणाली से निश्चित किया जायेगा परन्तु ऐसे वर्तमान सिविल जजों का, सिविल एण्ड एडीशनल मेशन जजों के पद में स्थानापन्न वेतन, जिनका वेतन संशोधित पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में दो अग्रिम वृद्धियाँ मजूर करने के बाद नियत किया जाय और जो १-४-१९६६ के पूर्व सिविल एण्ड एडीशनल सेसन जज के पद पर स्थानापन्न रूप में काम कर रहे थे, नीचे लिखे अनुसार पुनर्नियत किया जायेगा—

(क) जो व्यक्ति १-४-१९६६ पहिले स्थानापन्न रूप में काम करना आरम्भ कर चुके थे उनका स्थानापन्न वेतन, उनके सिविल जज के रूप में मूल-वेतन से एक सीढ़ी ऊँचे स्तर पर नियत किया जायेगा।

(ख) जिन व्यक्तियों ने १-४-१९६६ को अथवा तत्पश्चात् स्थानापन्न रूप में काम करना आरम्भ किया हो उनका स्थानापन्न वेतन, संशोधित पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में, राजस्थान सिविल रूलस के नियम २६-क के अनुसार नियत किया जायेगा।

६- जो राज्य कर्मचारी १-४-१९६६ को एक वर्ष अथवा अधिक समय से वर्तमान पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में अधिकतम वेतन पा रहे हैं, उन्हें, संशोधित पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में उनका वेतन निश्चित हो जाने के पश्चात्, एक वृद्धि दी जायेगी परन्तु जहाँ विशेष वेतन, वेतन में विलीन कर दिया गया है और वर्तमान पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में अधिकतम वेतन १-४-१९६४ को एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्त किया जा चुका था, उस दशा में वेतन संशोधित वेतन-श्रृंखला में, वर्तमान पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला की अधिकतम राशि तथा विशेष वेतन की राशि के योग के बराबर राशि से ऊपर की सीढ़ी के स्तर पर नियत किया जायेगा।

हस्ताक्षर—एम. मुकजी
फाइनल कमिश्नर एवं
सचिव, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि पत्र संख्या ईडी बी. एली. जी० सी. १९०२/स्पेशल/६६/दिनांक १५-९-६६ से श्री अतिरिक्त संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर समस्त सम्बन्धित को।

इस कार्यालय के पत्र संख्या ईडी बी. एका. बी-२: १४२२७: २४१: ५९ दिनांक २-९-५९ के संदर्भ में यह आज्ञा प्रसारित की जाती है कि अंग्रेजी माया अब साधारण प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जानी चाहिये अब यह निम्न खास प्रकार के प्राथमिक मॉन्टेसरी विद्यालयों में जिन्हे इस कार्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, पढ़ाई जा सकती है यह साबब नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी शिष्यों के पढ़ाने की

शिक्षण पद्धति (Structural approach) के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जा सके। अतः यदि बालक गलत तरीके से प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वे गलत आदतें जो उन्होंने प्राप्त कर ली हैं उनका सुधारना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

निरीक्षक शिक्षणालय

जयपुर

श्री अतिरिक्त शिक्षा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश संख्या स० शि० सा घा। डी जी। १। अन्वेषण ६५-६६ दिनांक ३१-५-६६ की प्रतिलिपि जो इस कार्यालय व अन्य को भेजी गयी।

स्थायी-आदेश संख्या १६६६/११ दिनांक ३१-५-१९६६

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की स्वीकृति हेतु नियुक्त राज्य-स्तरीय पुस्तक एवं पत्र-पत्रिका चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर विभाग के समस्त अधिकारियों के पालनार्थ निम्न निदेश दिये जाते हैं:—

१. विद्यालय के पुस्तकालय में रचि लेने एवं उनके लिये उपयुक्त पुस्तकों के चयन हेतु प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

२. विद्यालय के पुस्तकालय के लिये अच्छी उपयोगी पुस्तकों का चयन एवं क्रय होना चाहिये।

३. राजस्थान के लेखकों को उनकी अच्छी कृतियों के लिये उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

४. छात्र-कोष का उपयोग प्रधानाध्यापक अपने विवेक से करेंगे। छात्र-कोष में से पुस्तकों के चयन के लिए जहां तक सम्भव हो सके अधिक अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाय। छात्र-कोष का उपयोग स्वीकृत पुस्तक सूची तक ही सीमित रहेगा। फिर भी, प्रधानाध्यापक स्वीकृत पुस्तक सूची से बाहर की पुस्तकों क्रय कर सकते हैं, परन्तु ऐसी पुस्तकों की सूची अलग से बनाकर तैयार रखनी चाहिये जिसका निरीक्षण-गण निरीक्षण के समय अवलोकन करेंगे।

५. पत्र-पत्रिकाओं का क्रय-स्वीकृत सूची तक ही सीमित रहना चाहिये। स्वीकृत सूची के बाहर से पत्रिका, दैनिक/पत्र के क्रय करने से पहले प्रधानाध्यापक के लिये विभागीय अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

६. निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण के समय विद्यालय के पुस्तकालय की दशा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। पुस्तकालय के लिये चयन एवं क्रय की गई पुस्तकों के विषय में देखा जावे कि प्रधानाध्यापक ने पुस्तकों के क्रय में उचित विवेक से काम लिया है या नहीं।

७. प्राथमिक शालाओं के लिये किसी प्रकार की समाचार-पत्रिका का चन्दा नहीं दिया जायेगा।

८. क्रय अधिकारी किसी भी प्रकार से पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिये स्वीकृत अनुदान व्ययगत (लेप्स) नहीं होने देंगे। वे इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे कि पुस्तकों एवं पत्र-

पत्रिकाओं हेतु स्वीकृत अनुदान का पूर्ण उपयोग प्रतिवर्ष ३० नवम्बर तक हो जाये। इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय आदेश प्रपत्र क्रमांक स० शि० । साधा । डी. । १। त्रिशेष । ६५-६६ दिनांक १६-५-६६ द्वारा पूर्व भेजे जा चुके हैं।

विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सूचनार्थ विभाग द्वारा पुस्तकों की स्वीकृत सूची निकाली जायगी। समय समय पर अनुपूरक सूचियाँ निकलती रहेंगी। इन पुस्तक सूचियों के लिये विभागीय गजट (शिविरा पत्रिका) में प्रायः नियमित परिशिष्ट रहेगा।

पत्रांक नि० शि० । जय । सामान्य । जीए । परिपत्र/१६५/१३४/६६ दिनांक ११-८-६६

निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

(शिक्षा विभाग)

स्थायी आदेश १६६६

अल्प भाषा भाषी जाति के बालकों को पांचवी कक्षा तक उनकी मातृ-भाषा के माध्यम से पढ़ाने की सुविधायें दी हुई हैं।

इस विषय में इस कार्यालय को यह जानकारी करवाई गई है कि उर्दू पढ़ने वाले बालकों की परीक्षा में दिये जाने वाले पर्चे उर्दू भाषा में न देकर हिन्दी भाषा में दिये जाते हैं, चूँकि छात्र उर्दू भाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हिन्दी भाषा में दिये जाने वाले पर्चे को समझने में कठिनाई होती है।

इसलिये उन सभी शालाओं को जिनमें उर्दू, पंजाबी, सिन्धी या गुजराती भाषा द्वारा पांचवी कक्षा तक पढ़ाने का प्रवन्ध है उनको लिख दिया जाय कि उर्दू भाषा-भाषी जाति के छात्रों की परीक्षा में जो पर्चे दिये जाय वे उस भाषा में ही हों जिस भाषा के माध्यम से वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

हस्ताक्षरित

अतिरिक्त संचालक, प्राथमिक और
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि परिपत्र संख्या १ (३) हि० वि० । ६६ । १४९४२ दिनांक १-२-६६ और से, शासन उप सचिव भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर क्रमांक ईडीबी। नियुक्ति।वी।२ ए।२७।६६ दिनांक १८-३-६६ श्री अतिरिक्त संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के समस्त अवीनस्य कार्यालयों की।

विषय:—हिन्दी तार व्यवस्था का राज्य कार्य में प्रयोग।

राजस्थान शासन की आज्ञा एफ २ (सी) ६ जी ए बी। ६३ दिनांक अक्टूबर ११, १९६३ द्वारा आदेश प्रदान किये गये कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को राज्य के समस्त विभागों में प्रयोग करने की नीति के अनुक्रम में सभी विभाग तार हिन्दी में ही भेजेंगे, जहां तक सम्भव हो। इस सम्बन्ध सभी सामान्य प्रशासन (ख) विभाग में प्रपत्र संख्या ७ (क-१५) सा० प्र० (ख) । ६२ दिनांक

१ जनवरी, १९६५ द्वारा सभी विभागों का ध्यान पुनः आकर्षित किया गया था। इस सम्बन्ध में भुझे पुनः आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश है कि भविष्य में विभागों द्वारा दिये जाने वाले तार हिन्दी में ही भेजे जायें। अपने अधीनस्थ विभागों को भी यह निर्देश पहुँचा दिये जावे।

सन्दर्भ—सुविधा के लिए राजस्थान के जिन डाक व तार घरों में हिन्दी में तार लेने की सुविधा है, उनकी सूची संलग्न है। इन सब तार घरों के क्षेत्र सभी प्रकार के तार, जब तक कोई अनिवार्य कारण द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं, हिन्दी में ही भेजे जायें।

निरीक्षक शिक्षणालय,
जयपुर।

डाक घरों की सूची।

१. बाडमेर	३० आदर्श नगर अजमेर	५९ एस. एम. एस. होस्पिटल जयपुर
२. डोडवाना	३१ चीड गढ अजमेर	६० स्टेशन रोड, जयपुर
३. डिगाना	३२ दर्गा, अजमेर	६१ सीकर ८९ सुजानगढ़
४. जंसलमेर	३३ केशरगंज अजमेर	६२ चिरावा ९० रानी बाजार बीका.
५. जालौर	३४ कचहरी अजमेर	६३ झुन्झुन ९१ तारा नगर
६. जोधपुर पोस्ट	३५ गेव अजमेर	६४ खन्डेला ९२ संगरिया
७. जोधपुर सिटी	३६ रामगंज अजमेर	६५ पडाला ९३ हनुमानगढ़
८. जोधपुर-बलोथ मार्केट	३७ बान्दीकुई	६६ नालगढ़ ९४ नोखा (बीकानेर)
९. जोधपुर गिरदीकोट	३८ व्यावर	६७ पिलानी ९५ चूरू
१०. जोधपुर कचेरी	३९ भीलवाड़ा	६८ खेतरी ९६ रतनगढ़
११. जोधपुर एरोड्रम	४० भूपालगंज	६९ कोटपुनली
१२. कुचामन	४१ विजैनगर	७० नीम का थाना टाउन
१३. नागौर राज	४२ गुलाबपुरा	७१ फुलेरा
१४. मेरता	४३ केकड़ी	७२ भवानी मंडी १ अजमेर डीटीओ
१५. उदयपुर हैडपोस्ट आफिस	४४ किशनगढ़	७३ देवली (अजमेर) २ जयपुर
१६. नाथद्वारा	४५ भदनगंज	७४ झालावाड़ ३ जोधपुर सिटी
१७. कांकरोली	४६ नसीराबाद राज	७५ मानलरा, पाटन
१८. झुंगरपुर	४७ पाली मारवाड़	७६ कोटा जकशन ४ अलवर
१९. चित्तौड़गढ़ एल एस जी	४८ पुष्कर	७७ कोटा कचहरी ५ बीकानेर
२०. प्रतापगढ़ राज	४९ सिरौही	७८ हाथीरी ६ उदयपुर
२१. वासवाडा	५० सोजत	७९ निवाई ७ कोटा
२२. नीम्बाहेडा	५१ सुमेरपुर	८० आकेलाईक ८ श्री गंगानगर
२३. भरतपुर सी. ओ.	५२ शाहपुरा राज	८१ रामगंज मंडी
२४. धोलपुर	५३ रेजीमेंट बाजार अजमेर	८२ सवाई माधोपुर
२५. गंगपुर	५४ चान्दपोल बाजार अजमेर	८३ सवाई माधोपुर टाउन
२६. राजगढ़	५५ जयपुर सिटी	८४ टोंक राज
२७. खेरली	५६ जोहरी बाजार जयपुर	८५ श्रीहंगरपुर
२८. आवू	५७ राजस्थान सफ्टरीयट जयपुर	८६ राजलदेसा
२९. आवू रोड	५८ सांगानेरी बाजार जयपुर	८७ सरदार शहर

कार्यालय, सचिव. राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एन० बी० एल ६६-६७/३१४४ दिनांक २१-७-६६

राजस्थान के समस्त उच्चतर माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थाएँ (राजकीय व मान्यता प्राप्त)।

ऐसा विदित हुआ है कि कक्षा ६ से ८ तक की राष्ट्रीकृत पुस्तकें वच्चों को बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अतिकृत पुस्तक विक्रेताओं को सभी पुस्तकें विद्यार्थियों की अनुमानित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दे दी गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दुकानदार किताबों को अपने पास रोक रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके विद्यालय में जिन जिन छात्रों को जिस जिस कक्षा व विषय की पुस्तकों की आवश्यकता हो उसकी एक सूची बनाकर हमें एक सप्ताह के अन्दर अन्दर भ्रमजवादे और उन छात्रों को निर्देश दे दे कि वे उन पुस्तकों को बाजार से न खरीदें। आपके छात्रों की आवश्यकतानुसार सभी पुस्तक आपके विद्यालय को सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कर दी जायेगी।

(सौमित्र चन्द्र)

सचिव

राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशकालय—प्राइमरी तथा मेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान बीकानेर-७ जून १९६६

स्थायी आदेश नं० १६६६/१३

विषय—सहायता—प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा-काल में अधिवापिकी-आयु के ऊपर वृद्धि सम्बन्धी मामलों का निबटारा।

पुनर्गठित सहायता-अनुदान नियमावली के नियम ३ (१५) में अंकित है कि सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का सेवा-काल अधिवापिकी-आयु से ऊपर ६० वर्ष तक इस कार्यालय की स्वीकृति से और ६५ वर्ष की आयु तक सरकार की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। सेवा-काल के विस्तार में एकसूत्रता लाने के लिये निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाते हैं:—

१—जिन अध्यापकों की आयु ३० सितम्बर के पश्चात् ५८ वर्ष की होगी उनका सेवा-काल तदनुवर्ती वर्ष की ३० जून तक स्वतः ही बढ़ा दिया जायगा। ऐसी वृद्धि के लिये कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

२—अध्यापक-वर्ग को ६० वर्ष तक सेवा-काल में वृद्धि केवल तब ही दी जा सकती है जब कि सेवा का रिकार्ड अच्छा हो और वृद्धि के लिये प्रदग्ध-समिति सिफारिश करे। साधारणतया अप्रशिक्षित अध्यापकों को वृद्धि नहीं दी जायगी परन्तु अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, सेवा-काल में वृद्धि करने के लिए शक्ति प्राधिकारी, अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी वृद्धि दे सकता है।

नॉन-मैट्रिकुलेट अध्यापकों के सेवा-काल में वृद्धि निम्न हस्ताक्षर-कर्त्ता की पूर्व-स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी। प्रशिक्षण की शर्त पर, हालांकि, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों के मामलों में, जोर नहीं दिया जायगा।

३—सेवा-काल ६० वर्ष की आयु तक बढ़ाने की स्वीकृति देने की शक्ति का प्रयोग नीचे लिखे अनुसार किया जायगा :—

अध्यापक श्रेणी ३—निरीक्षक स्कूल, निरीक्षिका गर्लस स्कूल, उप-निरीक्षिका गर्लस स्कूल, यथास्थिति।

अध्यापक श्रेणी-२

उप-निदेशक, शिक्षा विभाग

शिक्षक एस. टी. सी.

वरिष्ठ अध्यापक तथा

अतिरिक्त निदेशक (P & S)

उनसे ऊपर

४—जिन मामलों में ६० वर्ष की आयु तक सेवा-काल बढ़ाया जाना अपेक्षित है वे निरीक्षक स्कूल के मार्फत चलाये जायेंगे। वरिष्ठ अध्यापकों के सेवा-काल की वृद्धि के मामले निरीक्षक स्कूल द्वारा सीधे हैड ऑफिस भेजे जायेंगे। वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन-श्रृंखला से उच्चतर वेतन-श्रृंखला में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा-काल की वृद्धि सम्बन्धी मामले निरीक्षक स्कूल द्वारा उप-निदेशक शिक्षा विभाग के मार्फत चलाये जायेंगे।

५—सेवा-काल में वृद्धि के मामले प्रबन्ध-समिति ६ महीने पहले प्रस्तावित करेगी। ऐसी वृद्धि के प्रत्येक मामले के साथ प्रबन्ध-समिति का एक प्रमाण-पत्र इस तथ्य का शामिल होगा कि कर्मचारी शारीरिक स्थास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त है और उसकी सेवा का रेकार्ड अच्छा रहा है। वृद्धि के लिये आवेदन-पत्र संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

६—६० वर्ष की आयु से ऊपर सेवा-काल में वृद्धि सम्बन्धी मामलों को सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामले सरकार को इस कार्यालय की मार्फत प्रेषित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों के मामलों को मुख्य अध्यापकों की वेतन-श्रृंखला से नीची वेतन-श्रृंखला में हैं, निरीक्षक स्कूल द्वारा सीधे हैड ऑफिस को भेजे जायेंगे। मुख्य अध्यापकों तथा उच्चतर वेतन-श्रृंखला वाले कर्मचारियों के मामले सम्बन्धित उप-निदेशक की मार्फत भेजे जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि ६० वर्ष की आयु से ऊपर सेवा-काल में वृद्धि की सिफारिश बहुत ही परिमित मामलों में करनी है और उस विषय विवेक में अध्यापकों के अत्यन्त अभाव के आधार पर अथवा सेवा का रेकार्ड विशिष्ट तथा उत्तम होने के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

७—जिन अध्यापकों के सेवा-काल में वृद्धि अपेक्षित है उनके वेतन पर सहायतार्थ-अनुदान प्रति हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बन्द कर दिया जायगा जब तक कि सेवा काल में वृद्धि की स्वीकृति संक्षेप प्राधिकारी द्वारा प्रदान न कर दी गई हो।

हस्ताक्षर—अनिल बोडिया

अतिरिक्त निदेशक

प्रपत्र—सेवा-काल में, सहायतार्थ-अनुदान नियमावलि १९६३ के नियम ३ (१६) के अन्तर्गत, वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र ।

- १—नाम कर्मचारी.....
- २—नाम संस्था.....
- ३—जिला.....
- ४—तारीख नियुक्ति.....
- ५—अर्हताएँ—(क) शैक्षणिक.....
(ख) व्यावसायिक (प्रोफेशनल).....
- ६—वेतन तथा वेतन-श्रृंखला जो अन्त में प्राप्त की हो.....
- ७—तारीख जन्म.....
- ८—सेवा-निवृत्ति की यथाविधि तारीख.....
- ९—सेवा-काल में वृद्धि के कारण.....

१—प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखा हुआ विवरण मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर—आवेदक

२—(क) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखा हुआ विवरण कर्मचारी की सर्विस बुक तथा अन्य रेकाडों जो संस्था में रखा जाता है, के आधार पर सही है ।

(ख) अतः कर्मचारी के सेवा-काल में.....से.....तक वृद्धि किये जाने की सिफारिश, प्रबन्ध-समिति के संकल्प संख्या..... तारीख..... (प्रतिलिपि साम्मिलित है) के अनुसार की जाती है ।

(ग) प्रमाणित किया जाता कि अध्यापक संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार उपयुक्त है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर

प्रबन्ध-समिति की ओर से

३—सहायतार्थ अनुदान बिल पर प्रति हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की अभ्युक्ति (रिमार्क्स)

४—उप-निदेशक, शिक्षा विभाग की अभ्युक्ति (जहां आवश्यक हो)

५—निदेशक शिक्षा विभाग का आदेश—

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

परिपत्र

विषय सहायता प्राप्त संस्थाओं में अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रवर वेतन श्रृंखला स्वीकृत किया जाना ।

राजस्थान में गैर-सरकारी जेथरिणिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्राप्त अनुदान नियमावली १९६३ के नियम ४ (ख) के अनुसार सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारीवर्ग को वेतन श्रृंखला और भत्ते, सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में तत्समान कर्मचारीवर्ग को निर्धारित वेतन श्रृंखला और भत्तों से कम नहीं होंगे ।

राजस्थान सरकार ने अपने वित्त विभाग के द्वारा अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनका अधिकतम वेतन, मंहगाई भत्ता के साथ मिलकर ३३५१ से अधिक नहीं है, प्रवर वेतन श्रृंखला मंजूर की है, यह लाभ सहायता-प्राप्त संस्थाओं में भी कर्मचारियों को उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसरण में दिया जाना चाहिए । यह आवश्यक है कि ऐसे प्रत्येक मामले की, जिसमें प्रवर वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रस्ताव रखा जाय, जांचे तथा स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी से पहिले प्राप्त करली जाय ।

यह लाभ किसी भी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ से गतकालापेक्षी प्रभाव (Octrospective effect) न रखते हुए, दिया जा सकता है ।

ऐसी वेतन श्रृंखला मंजूर किये जाने के बारे में अनुदेश वित्त विभाग के आदेश नं० एफ १ (५१) एफ. डी. ए/रूस्स/६१-१ दिनांक ६-१२-१९६१ में विस्तारपूर्वक दिये गये हैं ।



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग (रुल्स)
आदेश

विषय—अल्प वेतन शोभी कर्मचारियों को प्रवर वेतन श्रृंखला दिया जाना ।

राज्य सरकार ने ऐसे पद-वर्गों को जिनका अधिकतम वेतन महगाई भत्ते के साथ मिलकर ३३५) से अधिक नहीं है प्रवर वेतन श्रृंखला निर्धारित करने का निर्णय किया है । उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये नियम यथा समय में जारी किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता निदेशानुसार सरकार के निम्नांकित निर्णय की सूचना देता है—

(क) एक ही वर्ग के जिन पदों पर नियुक्तियाँ एक ही प्राधिकारी द्वारा की जाती हैं जैसा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (प्लासीफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील) रुल्स १९५८ में उल्लिखित है, उन पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों में से दस प्रतिशत को प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे । किसी नियुक्ति अधिकारी के अधीन एक ही वर्ग के पाँच या कम पद होने की दशा में किसी को प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन नहीं दिया जायेगा । तथापि ऐसी दशा में, मित्र मित्र नियुक्ति अधिकारियों के अधीन पदों को एक ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के अधीन समेकित किया जा सकेगा ताकि समेकित पदों में से दस प्रतिशत को प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन दिये जाने का निश्चय किया जा सके । ६ या इससे अधिक किन्तु दस से कम पदों में से केवल एक व्यक्ति प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन पाने का पात्र होगा ।

(ख) प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन पाने के लिये पात्र व्यक्तियों की संख्या का निश्चयन, स्वीकृत पदों की उस संख्या के आधार पर किया जायेगा जो कि तारीख १-९-१९६१ को थी । प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन पाने के लिये पात्र व्यक्तियों की संख्या का निश्चयन करने के लिये स्थायी और अस्थायी पदों को अलग अलग माना जायेगा ।

(ग) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति अधिकारी, किसी राज्य कर्मचारी को प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन स्वीकार करने के लिये सक्षम होगा ।

(२) प्रवर वेतन श्रृंखलाओं में वेतन स्वीकार किये जाने के बारे में, निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाये जाने के लिये राज्यपाल महोदय के आदेश की भी सूचना निदेशानुसार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दी जाती है—

(क) कोई राज्य कर्मचारी प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन पाने का पात्र होगा यदि वह—

[१] सरकार के अधीन कुल मिलाकर १५ वर्ष सविन्य कर चुका है जिनमें अस्थायी सेवा और मित्र मित्र रूप की सेवायें शामिल हैं परन्तु सेवाओं में वास्तविक विच्छेद (ब्रेक) की अवधियाँ शामिल नहीं हैं ।

[२] उन पदों पर जिनके लिये प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन दिया जाने को है, पांच वर्ष निरन्तर सेवा कर चुका है।

टिप्पण—इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ सेवा में ऐसी सेवा भी शामिल है जो सरकार के अधीन नहीं की गई हो परन्तु जो, वर्तमान आदेशों के अनुसार, पेंशन के लिये अर्हकारी (qualifying) है। इसमें ऐसे पद पर की गई सेवा शामिल नहीं है जिसका वेतन कण्ट्रिजेंसी से दिया जाता है अथवा जो वर्क-चांज वर्ग की है।

(ख) प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन की मंजूरी, वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ (२०) एफ.डी./आर/६१ दिनांक ७-८-१९६१ के अर्थ में पदोन्नति समझी जायगी।

(ग) प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन की मंजूरी नितान्त वरिष्ठता के आधार पर होगी, परन्तु किसी राज्य कर्मचारी को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार नहीं की जायगी जिसमें उसे राजस्थान क्लासीफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील रुल्स के अन्तर्गत अथवा उस पर लागू होने वाले किन्हीं अन्य अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत दुर्व्यवहार के कारण दण्डित किया गया हो।

(घ) कोई व्यक्ति जो उपरोक्त उप-पैरा (क) में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, वह प्रवर वेतन श्रृंखला में रिक्त स्थान पर नियुक्त नहीं किया जायगा।

प्रवर वेतन श्रृंखला में रिक्त स्थान, इस कारण कि उस पर नियुक्त किये जाने हेतु कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, साधारण पद में परिवर्तित हुआ समझा जायेगा। ऐसा स्थान पुनः प्रवर वेतन श्रृंखला में उठाया हुआ समझा जायगा जब कि कोई व्यक्ति उसे धारण करने के लिए पात्र हो जायगा।

(एफ डी० आदेश नं० एफ २ (बी) एफ डी० (एफ०आर०)/६४ तारीख ७-५-६४)

५—निदेशानुसार, निम्न हस्ताक्षर-कर्ता यह भी कहता है कि आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ वह व्यक्ति जो कि प्रवर वेतन-श्रृंखला में वेतन पा रहा है, ऐसे व्यक्ति की तुलना में वरिष्ठ नहीं माना जायगा जो कि सामान्य वेतन-श्रृंखला में वेतन पा रहा हो, अर्थात् प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन भोगी व्यक्ति की वरिष्ठता सामान्य वेतन-श्रृंखला में वेतन पाने वाले व्यक्ति की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी।

राज्यपाल के आदेश से
हस्ताक्षर-एम. मुकर्जी
शासन सचिव

विषय—अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रवर वेतन-श्रृंखला की मंजूरी।

इस विभाग के आदेश सं० एफ १ (५१) एफ डी. (ए) (रुल्स)/७१-१ दिनांक ६ दिसम्बर १९६१ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लिखित है कि एक ही वर्ग के जिन पदों पर एक ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियों की जाती हैं उन पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों में से १० प्रतिशत व्यक्ति प्रवर वेतन श्रृंखला में वेतन पाने के पात्र होंगे जैसा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील) रुल्स १९५८ में वर्णित किया गया है।

एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि आया समान पद-पर की गई सेवा प्रवर वेतन श्रृंखला मंजूर किये जाने के प्रयोजनार्थ मानी जानी चाहिए। इस मामले की जांच-पड़ताल करली गई है और राज्यपाल महोदय का आदेश हुआ है कि अस्थायी अथवा स्थायी सेवा, यथास्थिति, जो उन पदों पर की गई हो जिनसे वे सरप्लस घोषित किये गये थे तथा जिन पर उन्हें एवजांप्शन कमेटी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से नियत किया गया था अथवा किसी अन्य विभाग में समान पद पर की गई हो, भी, ऐसे व्यक्तियों के मामलों में मानी जानी चाहिए। इस पृष्ठा-द्वारा में प्रयुक्त पद "समान पद" से अभिप्राय ऐसे किसी पद से होगा जिसकी वेतन श्रृंखला उस पद की वेतन श्रृंखला की तुलना में या तो एक रूप हो या नीची हो जिस पर उन्हें नियत किया गया हो।

[एफ डी (एकम पे-कूलस) आर्डर नं० एफ २ (बी) (७) एफ डी/एकम पे/६४]

दिनांक १७-४-१९६५)

सहायकसचिव—राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग (प्रकोष्ठ ६) द्वारा अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजे गये पत्र सं० एफ २ (४१) सैल ६/६६ जयपुर तारीख मार्च-१९६६ की प्रतिलिपि।

विषय—गैर सरकारी संस्थाओं का वर्गीकरण।

प्रसंग—सं० २ ई डी बी/एड/ए/१६००२/स्पेशल/६५-६६ तारीख १९ जून १९६६ जो अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा भेजा गया।

मैं, निदेशानुसार सूचित करता हूँ कि सहायतार्थ अनुदान समिति ने अपनी बैठक जो कि तारीख १३ जनवरी १९६६ को उदयपुर में हुई थी, में जो सिफारिशें गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में की थी उनके अनुसार उक्त संस्थाओं के वर्गीकरण की राज्यपाल महोदय भेद १ से ४ तक में सशर्तियों के अधीन रहते हुए, स्वीकृति प्रदान करते हैं और आज्ञा देते हैं कि—

१—१९६५-६६ का सहायतार्थ अनुदान, सहायतार्थ अनुदान समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक १३ जनवरी १९६६ की सक्षिप्त कार्यवाही-विवरण (मिनट्स) के अनुसार स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसरण में दिया जाय।

२—सहायतार्थ अनुदान जो कि सत्पूर्ववर्ती वर्षों में इन संस्थाओं को एड हॉक रूप में दिया गया था तथा जो वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय के होने तक विचाराधीन रह रहा था अब सब मामलों में पूर्णतया निश्चित (फाइनल) समझ लिया जाय।

३—वर्तमान अनुदान और वर्गीकरण के प्रस्ताव जो दिये हैं, दोनों के अन्तर की रकम, १९६५-६६ से १९६७-६८ तक तीन वर्षों की भूतपूर्व अजमेर राज्य की संस्थाओं को दे दी जाय, यदि वर्गीकरण के अनुसार स्वीकार्य अनुदान राशि, वर्गीकरण के पूर्व प्राप्त वार्षिक अनुदान राशि से कम हो। १९६८-६९ से आगे, अनुदान अब स्वीकार किये गये वर्गीकरण के अनुसार दिया जायगा।

भूतपूर्व अजमेर राज्य की संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं के मामले में यदि नवीन नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य अनुदान-राशि पुराने नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य अनुदान-राशि से कम हो तो, उन्हें भी तीन वर्ष अर्थात् १९६५-६६ से १९६७-६८ तक की अन्तर-राशि, भूतपूर्व अजमेर राज्य की संस्थाओं के उदाहरण पर, अतिरिक्त अनुदान के रूप में दे दी जाय जैसा कि ऊपर मदे (३) में वर्णित है।

-मद ३ में वर्णित तीन वर्ष की अवधि संस्थाओं को पर्याप्त समय देने के अभिप्राय से मजूर की जाती है ताकि संस्थाएं अपने स्वयं के साधनों को बँटालें जिससे वे अपने खर्चों को स्वयं उठा सकें जब कि १९६८-६९ से आगे अनुदान-राशि कम हो जायगी।

इस प्रकार होने वाला व्यय सम्बन्धित निदेशकालयों के चालू वर्ष के अपने अपने बजट में सहायतार्थ अनुदान सम्बन्धी शीर्षकों में दिया जायगा।

यह वित्त विभाग की सहमति उनके आई-डी० न० (कुछ नहीं) दिनांक २३ मार्च १९६६ के द्वारा प्राप्त, से जारी किया जाता है।



सहायक सचिव, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग (प्रोप्ट-६) द्वारा अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एव सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, को भेजे गये पत्र सं० एफ २ (४१) एजू०सल ६/६६ दिनांक २५ मार्च १९६६ की प्रतिलिपि।

इस विभाग के पत्र सं० एफ २ (४१) एजू०/६/६६ दिनांक २५ मार्च १९६६ के क्रम में, निदेशानुसार, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से सूचित करता हूँ कि संस्थाओं को सरकार से दिया गया आवर्ती (रेकरिंग) सहायता-अनुदान, फीस तथा अन्य आवर्ती साधनों से हुई आय के साथ मिलकर किसी भी दशा में, स्वीकृत सम्पूर्ण व्यय के १०० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

राजस्थान सरकार

(शिक्षा विभाग)

आदेश

विषय:- सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड तथा अनुदान नियमों के अनुसार सुविधायें देना।

ऐसी सूचनायें प्राप्त होती रहती हैं कि सहायता प्राप्त संस्थायें अनुदान नियम १९६३ के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ता तथा प्रोविडेंट फंड की सुविधायें नहीं देती वेतन तथा भत्ता के विषय में इस कार्यालय के क्रमांक ईडीबी/एड/ए/१६००/१५/६५ दिनांक २२-८-६५ के द्वारा उचित आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

प्रोविडेंट फंड के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कर्मचारी के नाम से अलग अलग पोस्ट आफिस ग

बैंक में ग्वाता खोले। केवल प्रोविडेंट फंड की धनराशी बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करवा देना पर्याप्त नहीं है। ऐसा न करने से किसी भी स्थिति में प्रोविडेंट फंड के लिये अनुदान नहीं प्राप्त हो सकेगा।

विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इसका ध्यान रखें कि सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अलग अलग खाता खोला जाता है तथा ऐसा न करने पर प्रोविडेंट फंड के लिये किसी प्रकार का अनुदान न दिया जाय।

हस्ताक्षरित
(अनिल बोर्दिया)
अतिरिक्त सचालक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक—अतिरिक्त निदेशक

प्राइमरी एवं नेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रेषिणी—सहायता-प्राप्त संस्थाओं की समस्त प्रबन्ध-समितियां, माफत प्रति हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी।

सं० ई.डी.बी. /एच/ए/१६६३०/३/६६

दिनांक ११ अप्रैल १९६६

विषय—सहायता-प्राप्त संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में विभिन्नता।

समस्त प्रबन्ध-समितियों का ध्यान विशेष रूप से सहायतार्थ अनुदान नियमावली के नियम ३ (१२) को ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत सहायता-प्राप्त संस्थाओं में वसूल की जाने द्यूशन तथा अन्य फीस की दरों में कोई विभिन्नता, सरकार की स्वीकृति-प्राप्त किये बिना, नहीं हो सकती।

१९६४-६५ के दौरान वसूली की गई दरों की तुलना में कोई विभिन्नता, आय का हिसाब लगाने के लिये, तब तक नहीं मानी जायगी जब तक कि उसकी अनुमति निम्न हस्ताक्षर-कर्ता द्वारा न दे दी गई हो जो कि आवेदन-पत्र जिसमें निम्नलिखित व्योरा दिया गया हो, पर होगी :—

(क) द्यूशन तथा समस्त अन्य फीस का विवरण-पत्र (जिसमें एडमिशन फीस, वाइज फण्ड व्यय, बस का खर्चा इमारत का खर्चा तथा अन्य समस्त फीस व्यय (वार्जेज) लेवी आदि जो विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य हैं, सम्मिलित हैं।)

(ख) द्यूशन अथवा अन्य फीस में कमी या वृद्धि करने के समय का, इसी प्रकार का, विवरण-पत्र।

(ग) प्रबन्ध-समिति के संकल्प (रिजोल्यूशन) का प्रतिलिपि भय तारीख निर्णय।

हस्ताक्षर—अनिल बोर्दिया
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:—आदेश संख्या ई. डी. बी./ए स ई. सी./ई/एस. सी. एच./२२४६१/६५-६६ दिनांक ८-७-६५ जो अतिरिक्त निदेशक प्राईमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजा गया ।

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा जे. सी. ओ./एन. सी. ओ./ओ. आर जो सेना में हैं तथा अन्य सेवाओं में समकक्ष पदों पर हैं तथा चीन के विरुद्ध युद्ध में जो व्यक्ति (युद्ध न करने वाले) मारे गये थे अथवा स्थायी रूप से अमर्त्य हो गये थे और जो राजस्थान के निवासी हैं, उनके वचनों की छात्र-वृत्तियाँ दिया जाना स्वीकार किया गया है ।

(१) नवीं तथा दसवीं कक्षा में

बोर्डस—	३० ६० मासिक
डे स्कालर्स—	२५ ६० मासिक

(२) छठी से आठवी कक्षा में

बोर्डस तथा डे स्कालर्स (दोनों)	१२ रु. मासिक
--------------------------------	--------------

(३) सेवा-रत व्यक्तियों, जो

२० रु. मासिक

जे. सी.ओ. रैंक तथा उससे
नीचे रैंक के हैं, की पत्नियों
को जो कक्षा ६ से ८ तक में
अध्ययन कर रही हैं ।

पात्र विद्यार्थियों से आवेदन-पत्र शिक्षा-सन् १९६५-६६ के लिये, उक्त योजना के अन्तर्गत प्रामाणित किये जाते हैं । छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष १० महीने के लिये होगी अर्थात् जुलाई से अप्रैल तक के लिये । नमूने के तौर पर आवेदन-पत्र का प्रारम्भ मंगलन है जिसके अनुसार टाईप की हुई या हाथ से लिखी हुई प्रतियाँ काम के लिये तैयार कर ली जाय ।

हाई स्कूलों तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों (लड़के तथा लड़कियों) के मुख्य अधिकारी आवेदन-पत्रों को नव प्रकार से पूरा करवा कर, तारीख १५ अगस्त १९६५ तक निरीक्षक स्कूल को प्रेषित करेंगे ।

मिडिल स्कूलों (लड़के तथा लड़कियों) के मुख्य अधिकारी भी आवेदन-पत्रों को प्रामाणित सब प्रकार से पूरा करवा कर जिला निरीक्षक को तारीख १५ अगस्त १९६५ तक भेज देंगे । निरीक्षक स्कूल उन आवेदन-पत्रों को प्रति हस्ताक्षर करेगा और तारीख ३१ अगस्त १९६५ तक उप-निदेशक, प्राईमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेंगे । निरीक्षक स्कूल, इस सूचना को समस्त मिडिल स्कूलों (लड़के तथा लड़कियों) में भिजवायेगा । अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । जिन विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं, वे उनके नवकरण के लिये अपने अपने आवेदन-पत्र फार्म 'ग' में इस कार्यालय को संस्था के मुख्य अधिकारी की मार्फत, भेज सकते हैं ।

कार्यालय निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर

पत्रांक नि० शि० जय० एफ ८ / १६/ए०/६५-६६ जयपुर दिनांक ६-८-६५

परिपत्र

कार्यालय अतिरिक्त शिक्षा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के अधिसूचना क्रमांक ई डी बी/सेकि०/ई०/२२४१६ विशेष ६५-६६ दिनांक २८ जून १९६५ एवं संशोधन क्रमांक ईडीबी. सेकि० ई० /२२४१६/६५ दिनांक २७-७-६५ के क्रम में जयपुर जिले की समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक (लड़कों एवं लड़कियों) के विद्यालयों में विद्याध्यायन करने वाले अनुसूचित जन-जाति, अनुसूचित जाति, घुमवकड़ जाति एवं विमुक्त जाति के छात्र, छात्राओं से जिन्हें समाज कल्याण विभाग, द्वारा इस विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है उनसे सन् १९६५-६६ के लिए नई छात्रवृत्ति हेतु तथा छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

नई छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ सितम्बर, सन् १९६५ रखी गई है तथा छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ३१ अगस्त १९६५ रखी गई है इस तिथि के बाद में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

छात्र वृत्ति के कुछ आवेदन पत्र फार्म आपको इसके साथ भेजे जा रहे हैं, आवश्यकतानुसार ऐसे ही आवेदन पत्र फार्म टाइप कर लिये जावे या हाथ से लिखे जावें। टाइप किए हुए तथा हाथ से लिखे आवेदन पत्र भी यदि छात्रों द्वारा भरे जावेंगे तो मान्य समझे जायेंगे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को चाहिये कि वे अपने विद्यालय के समस्त अनुसूचित जन-जाति, अनुसूचित जाति, घुमवकड़ जाति एवं विमुक्त जाति के छात्र, छात्राओं को आवेदन पत्र भरने हेतु दें, यदि छपे हुए आवेदन पत्र कम पड़ते हैं तो टाइप कराले अथवा हाथ से लिखे हुए फार्म ही भरावें, कोई भी छात्र फार्म भरने से वंचित नहीं रहने पावें, इस सम्बन्ध में उपरोक्त जाति के प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की एक सूची तैयार करा लें तथा फिर कक्षाध्यापक द्वारा उनको आवेदन-पत्र वितरित कर दें, कक्षा अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को आवेदन पत्र भरने में भली प्रकार सहयोग दें तथा फिर कक्षा के समस्त आवेदन पत्र इकट्ठे करके प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को दें।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अपने विद्यालय के समस्त आवेदनपत्र इकट्ठे करके उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करके इस कार्यालय में निश्चित तिथि से पूर्व प्रस्तुत करें।

निम्नलिखित उच्च, उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके नाम के सामने अंकित माध्यमिक विद्यालयों के उपरोक्त जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति-सन् १९६५-६६ के लिए नवीनीकरण करने के अधिकार दिये जाते हैं—

- (१) पोद्दार बहु० उद्देशीय उच्चतर मा०
शाला गांधीनगर, जयपुर ।
- (२) दरबार बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक
शाला, तोपखाना, जयपुर ।
- (३) महाराजा बहुद्देशीय उच्चतर माध्य-
मिकशाला, मानक चौक जयपुर ।
- (४) राजकीय उच्चतर विद्यालय,
मोती कटला, जयपुर ।
- (५) राजकीय उच्चतर विद्यालय, आदर्शनगर
जयपुर ।
- (६) राजकीय उच्च विद्यालय, चौमू ।
- (१) रा० माध्यमिक शाला गरुपति नगर,
जयपुर ।
- (२) रा माध्यमिक शाला रेजीडेन्सी, जयपुर ।
- (१) रा० वेसिक माडल मिडिल स्कूल,
तोपखाना जयपुर ।
- (२) राजकीय मिडिल स्कूल लेवर कालोनी
जयपुर ।
- (१) रा० माध्यमिकशाला, मोदीखाना जयपुर,
(२) राजकीय माध्यमिकशाला नाहरगढ रोड,
जयपुर ।
- (३) दरवार मिडिल स्कूल, जयपुर ।
- (१) रा० माध्यमिक विद्यालय, रामगंज,
जयपुर ।
- (२) राजकीय माध्यमिकशाला आमेर ।
- (३) महाराजा वेसिक मॉडल मिडिल स्कूल,
जयपुर ।
- (१) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, घाटगेट,
जयपुर ।
- (६) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चौमू ।

उपरोक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि वे समस्त उपरोक्त जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन-पत्र उपरोक्त सम्बन्धित उच्च, उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पास नियत तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु गत वर्ष की भांति प्रस्तुत करें ।

समस्त उच्च, उच्चतर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चाहिये कि वे अपने विद्यालय के छात्रों से एवं उनके अधिनस्थ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से आवेदन पत्र छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु प्राप्त करके इस कार्यालय की धनराशि के लिए १० सितम्बर ६५ तक मांग प्रस्तुत कर दें इसके बाद से धनराशि के लिए मांग प्रस्तुत की जायगी तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायगा तथा इससे जिन छात्रों को नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मांग देर से प्रस्तुत करने वाले प्रधानाध्यापक की समझी जायगी ।

उपरोक्त माध्यमिक शालाओं के अतिरिक्त माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शालाओं के छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन-पत्र इस कार्यालय में निश्चित तिथि से पूर्व प्रस्तुत करें ।

(नारायणलाल वर्मा)

अतिरिक्त निरीक्षक शिक्षणालय,
जयपुर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार

(निदेशकालय शिक्षा)

सं० ई डी वी/एड/१६००७/स्पेशल/६५ दिनांक २७-१२-१९६५

प्रेषितो—

समान उप-निदेशक शिक्षा

(पुरुष एवं महिला)

समस्त निरीक्षक, स्कूल/निरीक्षिका

गर्ल्स स्कूल/उप-निरीक्षिका गर्ल्स स्कूल ।

विषय—अपीलों के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली

राजस्थान राज पत्र दिनांक २४ जनवरी १९६३ में प्रकाशित सहायतार्थ-अनुदान नियमावली के नियम ४ (ड) में प्रावधान है कि किसी संस्था के स्टाफ का कोई सदस्य जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, या हटा दिया गया है अथवा पदावनत कर दिया गया है, शिक्षा विभाग को परिशिष्ट ५ को मद सं० २ पृष्ठ ८५४ के अनुसरण में अपील कर सकता है। इसके अनुसार शिक्षा विभाग के वे अधिकारी जिन्हें मद ७ (१) के अनुसरण में नियुक्तियों की स्वीकृति देने की शक्ति है प्रथम अपील को सुनवाई करने की शक्ति रखते हैं। इसमें उल्लिखित है कि—

(१) निरीक्षक स्कूल उन समस्त कर्मचारियों की अपीलों की सुनवाई करेंगे जो कि श्रेणी ३ में निम्नलिपक वर्ग की वेतन श्रृंखला में अथवा किसी अन्य निम्नतर वेतन श्रृंखला में काम कर रहे हैं।

(२) उप-निदेशक शिक्षा विभाग, नम्बन्धित क्षेत्र, श्रेणी-२ में काम करने वाले अव्यक्तों को तथा एस.टी.सी.इन्सट्रक्टरों की अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं।

(३) अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, मुख्य अध्यापकों, सीनियर अध्यापकों, और एस.टी.सी. स्कूलों के इन्सट्रक्टरों के ग्रेड में ऊँचे ग्रेड में काप करने वाले कर्मचारियों के तथा ऐसी संस्थाओं के समस्त कर्मचारियों को जो कि दोन प्रथम चार संस्थाएँ चला रही हैं एवं जिनका समग्र स्वीकृत व्यय एक लाख रुपये से अधिक है, अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियमों में यह प्रावधान भी है कि द्वितीय अपील उस अधिकारी को होगी जो कि प्रथम अपील के अधिकारी से ठीक उच्चतर (सुपरियर) अधिकारी हो। नियमों में और किसी अपील का प्रावधान नहीं है।

अपीलों के लिये प्रणाली

कोई अध्यापक जो प्रबंध-मिति के आदेश से परिवेदित हो, ऊपर वर्णित अधिकारी को उस आदेश की तारीख से एक महीने के अन्दर जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदन (Representation) करना है, अपील पेश कर सकता है। वह अपील के कारण स्पष्टतया व्यक्त करेगा। उसे यह भली प्रकार ध्यान रखना चाहिये कि केवल बरखास्तगी, हटाये, जाने तथा पदावनति के ही विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा अपील ग्रहण की जा सकती है। ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसमें कोई अन्य दण्ड दिया गया हो कोई अपील विभाग द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकेगी।

प्रबंध-समिति के आदेश के विरुद्ध अपील करने वाला अध्यापक अपील की दो प्रतियां पेश करेगा और उसे अपील प्राधिकारी को रजिस्टर्ड ए-डी. पोस्ट से भेजे जाने की सलाह दी जाती है। उसे अपील के आधारों का स्पष्टतया उल्लेख करना चाहिये तथा समस्त सुवर्गगत दस्तावेजों की प्रतियां शामिल करनी चाहिये।

अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने पर अपील की एक प्रति रजिस्टर्ड ए-डी. पोस्ट से प्रबंध-समिति को भेजेगा और उससे अपील की प्रति प्राप्त होने की तारीख १५ दिन के अन्दर आलोचनात्मक-टिप्पण (comments) आमंत्रित करेगा। यदि प्रबंध-समिति अथवा टिप्पण भेजने में असफल रहे तो, अपील प्राधिकारी अपील का एकतरफा निर्णय दे सकेगा।

जहां प्रबंध-समिति अपना टिप्पण भेजे तथा अपीलकर्ता अध्यापक के विवादास्पद-कथन (Contentions) का विरोध करे तो, अपील प्राधिकारी मामले की जांच गुण-दोषों (Merits) के आधार पर अपील के विषय में अपना निश्चित विचार बना सके तो वह दोनों पक्षों की सूचना देकर ऐसा करेगा।

जहां अपील-प्राधिकारी किसी विवादास्पद-वात विशेष के बारे में जांच करना आवश्यक समझे तो वह या तो स्वयं कर सकेगा अथवा उसे किसी ऐसे अधिकारी विशेष को सौंप सकेगा जो कि उप-निरीक्षक स्कूल से नीच पद का न हो। जिस अधिकारी को जांच फार्म सौंपा जाय उसे उन्हीं निदिष्ट बातों के विषय में जांच करने को कहा जाना चाहिये और एक निदिष्ट अवधि दी जानी चाहिये जिसके अन्दर उस कार्य को पूरा किया जाय। जांच अधिकारी, साधारणतया जांच दोनों पक्षों की मौजूगी में करेगा परन्तु विशिष्ट मामलों में, गोपनीय तरीके से भी कर सकेगा। जिस पत्र के जरिये अपील प्राधिकारी किसी अधिकारी को किन्हीं निदिष्ट बातों की जांच करने का निदेश दे उसकी एक एक प्रति प्रबंध-समिति तथा अपीलकर्ता अध्यापक को भेजी जायेगी, वे दोनों जांच अधिकारी के साथ, जांच कार्य में, सहयोग करेंगे।

अपील प्राधिकारी, जांच अधिकारी का प्रति-वेदन प्राप्त होने पर, अपील के गुण-दोष (merits) निश्चित करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय की सूचना निर्णय होने के बाद तुरन्त ही देगा।

जैसा ऊपर वर्णित है, परिवेदित पक्ष द्वारा द्वितीय अपील, प्रथम अपील-प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर प्रस्तुत की जा सकेगी। द्वितीय अपील का निर्णय सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उसी प्रणाली का अनुकरण करते हुए किया जायेगा जो कि प्रथम अपील के लिये है।

इसकी प्रतियां पर्याप्त संख्या में मंगलम हैं जिन्हें सहायता प्राप्त संस्थाओं को भेजना है और वे इसे सूचना पट्ट पर चिपका कर समस्त अध्यापकों का ध्यान इसकी ओर आकषित करेंगी।

हस्ताक्षर-अनिल बोडिया

प्रतिरिक्त निदेशक

प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय—अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

विषय—सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों का वेतन, पुनरीक्षित वेतन श्रृंखलाओं में नियत किया जाना।

प्रसंग—इस कार्यालय का परिपत्र नं० ई. डी. बी/एड/ए/१६००५/१६/६५ तारीख २२-८-१९६५।

उपरोक्त प्रसंग में खेद है कि अनुदेश -१ में उल्लेखित परिशिष्ट ऊपर उल्लेखित परिपत्र के साथ संलग्न नहीं की जा सकी। उसे अब भेजा जा रहा है।

हस्ताक्षर-अनिल बोडिया

अतिरिक्त निदेशक

परिशिष्ट—१

मंहगाई भत्ता की दरों सम्बंधी अनुसूचा

तारीख १-६-१९६१ को विद्यमान मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरों का विवरण

वेतन	मंहगाई भत्ता
१५० रु० से कम	१०)
१५० रु० तथा उससे अधिक किन्तु	
३०० रु० से कम....	२०)
३०० रु० तथा उससे ऊपर	वह रकम जिसमें वेतन ३२० रु० से कम रहे।

जैसी कि १-३-१९६४ को थी

१५० रु० से कम	१५)
१५० रु० तथा उससे अधिक किन्तु	
३०० रु० से कम	२५)
३०० रु० तथा उससे ऊपर	वह रकम जिसमें वेतन ३२५ रु० से कम रहे।

जैसी कि १-८-१९६४ को थी

१५० रु० से कम	२०)
१५० रु० तथा उससे अधिक किन्तु ३०० रु० से कम	३०)
३०० रु० से ऊपर और ३२० रु० तक	वह रकम जिससे ३३० रु० से कम रहे।
३२० रु० से ऊपर तथा ३६० रु० तक	४० १०)
३६० रु० से ऊपर	वह रकम जिसमें वेतन ४०० रु० से कम रहे।

जैसी कि १-३-१९६५ की थी

१५० रु० से कम

२५ रु०

१५० रु० तथा उससे ऊपर किन्तु ५४० रु० तक

३५ रु०

५४० रु० से ऊपर

वह रुकम जिससे वेतन ५७५ रु० से कम रहे।

कार्यालय

अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा।

परिपत्र

विषय—सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन शृंखला १९६१ में नियत किया जाना।

इस कार्यालय में परिचय सं. ई. डी. बी. /वज/सी.-१/१६५१७/४/६३ दिनांक २२-५-६३ तथा ई. डी. बी. /वज/सी.-१/१६५१७/१४/६३ दिनांक ११-६-१९६३ में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, पुनरीक्षित वेतन, शृंखला १९६१ सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये भी लागू कर दिये गये हैं। इस पर जो व्यय होगा वह सहायताार्थ अनुदान के प्रयोजनार्थ स्वीकृत व्यय माना जायगा तथापि यह ध्यान में लाया गया है कि बहुत संख्या में सहायता-प्राप्त संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन शृंखलाओं में वेतन मंजूर नहीं किया है। अतः समस्त सहायता-प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन-शृंखलाओं के अनुसार वेतन तथा राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाना मंजूर करें।

पुनरीक्षित वेतन दरों में वेतन नियत करने के बारे में अनुदेश

(१) कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता पुरानी वेतन-शृंखला के साथ दिया जा रहा है उसे वेतन में विलीन कर दिया जाय और इस प्रकार समग्र परिणाम (Total emoluments) मालूम हो जायेंगे। इस समग्र परिणाम की राशि में से पुनरीक्षित दरों (जैसा कि परिशिष्ट-१ में बताया गया है) के अनुसार मंहगाई भत्ते की राशि घटा दी जाय और इस प्रकार निकाली हुई राशि, यदि, पुनरीक्षित वेतन-शृंखला में किसी स्तर के समक्ष हो तो वेतन इसी स्तर पर नियत किया जायगा, जहां ऐसी कोई स्तर न हो, तो वेतन आगे ऊंची स्तर पर नियत किया जायगा। एक सारिणी वेतन का नियतन बताते हुए, संलग्न की जाती है जिससे तुरन्त हिसाब लगाया जा सकता है।

(२) जहां वेतन नियतन के परिणामस्वरूप होने वाला लाभ एक वेतन वृद्धि का या उससे कम हो तो वृद्धि की वही तारीख रहेगी। जहां लाभ एक वेतन-वृद्धि से अधिक हो उस दशा में, आगामी वृद्धि उस वृद्धि की अवधि पूरी होने के बाद प्रोदभूत होगी।

(३) दक्षता अवरोध पार करने के बारे में, वित्त विभाग के परिपत्र ने एक १(५१) एक डी-ए (स्लैट) ६१ दिनांक ३१-१-६२ तथा एक २(बी) (१३) एक डी एक्सपे-स्लैट) ६४ दिनांक २७-४-६४ (सत्काल अवलोकनार्थ प्रति सेलन) को ध्यान में रखा जाय।

(४) वेतन नियतन सम्बन्धी विवरण-पत्र निर्धारित प्रयत्नों में तैयार किया जाय और उसे पहिले निरीक्षक स्कूल/निरीक्षिका, गर्ल्स स्कूल/उप-निदेशक शिक्षा विभाग (महिला), यथा स्थिति, के कार्यालय से स्वीकृत कप लिया जाय तत्पश्चात् कर्मचारियों को पुनरोक्षित वेतन शृंखलाओं के अनुसार वेतन दिया जाय ।

(५) इस बात पर जोर दिया जाता है कि पुनरोक्षित वेतन-श्रृंखलाएं अवश्य ही अर्दताओं (Qualifications) से सम्बद्ध हैं और उन्हें देते समय यह सुनिश्चित कर लेना है कि इस सम्बन्ध में निर्धारित अर्दताओं की पूर्ति हो गई है ।

(६) पुनरोक्षित वेतन-श्रृंखलाओं में वेतन-नियत करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी वर्ग की संख्या जो कि तारीख १-६-१९६१ को है परिवर्तित नहीं की जायेगी परन्तु नीचे लिखे अनुसार समकक्षीय ठहराई जायेगी (जहां वेतन-नियतन विवरण-पत्र नहीं दिया गया है वहां राज. पेंशन क्लस १९६१ के अनुसार कार्य किया जाय) :—

वेतन-	पुनरोक्षित	पुरानी वेतन-	गतें
श्रृंखला संख्या	वेतन-श्रृंखला	श्रृंखलालाएं जो समेकित की गई	
८. ७५-४-६५-५-१०५ द. अव. (६B)-५-१३०- द. अव ५-१६०-प्रेणी-३ अध्यापक		४०-१-५० ५०-२-६०-३-७५ ५०-४-७०-५-८० ६०-३-६० ४०-४-८०-५- १३०-७०-४- ६०-५-१००- ७०-४-६०-५- १४०-८०-५- १२०-८-१६० १०-२००	साधारण अध्यापक जो न तो मैट्रिक पास है और न प्रशिक्षित है तथा नहीं प्रवेशिका पास है उसे ७५) स्थिर वेतन मिलेगा। ६१) उच्चतर प्रारंभिक वेतन नये अध्यापक को मिलेगा। जो कि मैट्रिक पास तथा प्रशिक्षित हो। १०५) पर दक्षता अवरोध नान-मैट्रिकुलेट किन्तु प्रशिक्षित साधारण अध्यापक द्वारा, जब तक कि वह मैट्रिक की परीक्षा पास न करले, और मैट्रिक पास किन्तु अप्रशिक्षित साधारण अध्यापक द्वारा, जब तक कि वह प्रशिक्षण प्राप्त न करले, पार नहीं किया जायेगा। १३०) पर दक्षता अवरोध, आर्ट्स (कला), क्राफ्ट्स (शिल्प) तथा संगीत के साधारण अध्यापक अथवा फिजीकल इन्सट्रक्टर (शारीरिक व्यायाम शिक्षक) द्वारा, जब तक कि वह मैट्रिक पास न करले, एवं प्रशिक्षण प्राप्ति का एक प्रमाण-पत्र जो कि विभाग द्वारा मान्य हो प्राप्त न करले, पार नहीं किया जायेगा।
१३. ११५-५-१५५-१०- १६५-द. अव १०-		६०-५-१४० ११०-५-१३५-	१४०) प्रारम्भिक वेतन ऐसे व्यक्ति को जो ग्रेजुएट हो और शिक्षा में उपाधि लिए

२३५-२५०

श्रेणी-२ अध्यापक

१०-२२५

७०-४-६००

५-१००

हुए हो, नवीन साधारण अध्यापक के रूप में भर्ती किये जाने पर दिया जायगा। माॅण्टेसरी प्रशिक्षित ग्रेजुएट जोकि किसी बच्चों के स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर नवीन भर्ती की जाय।

१६५) पर दक्षता अवरोध किसी ग्रेजुएट अध्यापक जो किसी हाईस्कूल या हायर-सेकण्डरी स्कूल में काम करता है द्वारा, जब तक कि वह शिक्षा में उपाधि प्राप्त न करले, पार नहीं किया जायगा। एक ग्रेजुएट सहायक अध्यापिका, जो किसी बच्चों के स्कूल में है, द्वारा, जब तक कि वह माॅण्टेसरी प्रशिक्षण प्राप्त न कर ले।

११.२२५-१०-२७५-द. प्रव.

१५०-१०-२५०-१२३-३५०

२७५) परदक्षता अवरोध

१८-२८५-१५-४३५-२५

२००-१०-२५०-१२३-३५०

वर्तमान व्यक्तियों तथा भविष्य में

४८५ श्रेणी १ अध्यापक

२००-१०-२५०-१५-४००

भर्ती होने वाले व्यक्तियों, जो कि

२००-१०-२५०-१५-४००-

हायर सेकण्डरी स्कूलों में अपने विषय

२५-४५०।

के इन्चार्ज हो, द्वारा, जब तक कि

२००-१०-२८०-१५-४००-

वह B. Ed. ग्रहण विभाग द्वारा

२५०-२०-४५०

मान्य तत्सदृश ट्रेनिंग पास करलें,

१५०-१०-२५०-१२३-३००

पार नहीं किया जायगा।

१. ४५-१-७०

२५-१-४०

श्रेणी-४ कर्मचारियों के लिये

३०-१-४०

३०-१-४५

३०-१-४५-२-५५

(७) सहायता प्राप्त संस्थाएँ पुनरोक्षित वेतन श्रृंखलाएं तारीख १-६-१९६१ से अथवा तदनुवर्ती किसी तारीख से मंजूर कर सकती है परन्तु धर्त यह है कि यदि वे १-६-१९६१ के बाद मंजूर करें तो किसी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ से होना चाहिये।

(८) ऐसे मामलों में जिनके सम्बन्ध में इसमें कोई प्रावधान निर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है, निर्णय उन नियमों के अनुसार किया जायगा जो कि राज्य कर्मचारियों के लिये लागू होते हैं। इस विषय में अपील सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक लेखाधिकारी का परामर्श लेने के बाद, निर्णय करेगा।

(९) संस्थाएँ वेतन नियतन के कारण बकाया निकली हुई राशि को मांग करते समय, स्वीकृत विवरण-पत्र की एक प्रति तथा उसके साथ एक और विवरण-पत्र जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को दी जाने वाली बकाया-राशि दिखाई गई हो, प्रेषित करेंगी ताकि जाच की जाये इसी स्थिति में की जा सके और सरकारी श्रेष्ठ का रूपया दिया जा सके।

हुस्ताक्षर अनिल बोडिया

अतिरिक्त उप-निदेशक

प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर।

शासन सचिव वित्त विभाग-ए (रूल्स) राजस्थान जयपुर

द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजे गये परिपत्र

सं. एफ १ (५१) एफ डी (रूल्स)/६१ दिनांक ३१ जनवरी १९६२ की प्रतिलिपि

विषय—पुनरीक्षित वेतन श्रृंखलाओं में दक्षता अवरोध (Efficiency Bar) का प्रयोग
जब पुनरीक्षित वेतन श्रृंखलाओं में राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पे) रूल्स १९६१ के
अन्तर्गत दक्षता अवरोध के स्तर से नीचे अथवा ऊपर वेतन निश्चित किये जाने की दशा में दक्षता
अवरोध के प्रयोग के बारे में विचार किया गया और मैं, निदेशानुसार, स्थिति का नीचे लिखे
अनुसार स्पष्टीकरण करता हूँ:—

(१) ऐसी दशा में जब कि वेतन-नियतन के परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारी का वेतन
पुनरीक्षित वेतन-श्रृंखला में दक्षता अवरोध के स्तर से ऊपर चला जाय तो दक्षता अवरोध के प्रयोग
का प्रश्न नहीं उठता यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी ने वर्तमान वेतन श्रृंखला में दक्षता अवरोध को पार
नहीं किया होता ।

(२) यदि वेतन पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में दक्षता अवरोध के स्तर से नीचे नियत किया
जाय तो, अधिकरण को दक्षता अवरोध सामान्य तरीके से पार करना होगा ।

(३) यदि कोई व्यक्ति वर्तमान वेतन श्रृंखला में दक्षता अवरोध पर रोक दिया गया है
तो, उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में, राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड-पे) रूल्स
१९६१ के नियम १० के अनुसार नियत किया जा सकता है परन्तु ऐसे कर्मचारी को उस स्तर पर
रोक दिया जाना चाहिये जिस पर उसका प्रारम्भिक वेतन पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में नियत किया
जाय जब तक कि उसे दक्षता अवरोध पार करने के लिये उपयुक्त न मान लिया जाय ।

परिपत्र संख्या एफ २ (वी) (१३) एफ डी (एक्सपे.-नियम)/६४ दिनांक २७-४-१९६४

विषय—पुनरीक्षित वेतन श्रृंखलाओं में दक्षता अवरोध का प्रयोग—

सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें राज्य कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन
श्रृंखला में, राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पे) रूल्स १९६१ के अनुसार, दक्षता अवरोध के
स्तर से ऊपर नियत किया गया था, यद्यपि ऐसे दक्षता अवरोध किन्हीं निर्धारित ग्रहताओं की प्राप्ति
में सम्मिलित थे । यह तरीका अनियमित है ।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता, निदेशानुसार, स्पष्टीकरण करता है कि जहां पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला
में दक्षता अवरोध का प्रयोग होता है और उसका सम्बन्ध ग्रहताओं से होता हो, तो, ऐसे राज्य
कर्मचारी का वेतन जो निर्धारित ग्रहताएं नहीं रखता हो, पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला दक्षता अवरोध
के स्तर ऊपर नियत नहीं किया जाना चाहिये ।

(३) वित्त विभाग का परिपत्र संख्या एफ १ (५१) एफ डी-ए (रूल्स)/६१ दिनांक
३१-१-१९६२, जो कि दक्षता अवरोध के बारे में है, उपयुक्त पैरा २ में वर्णित मामलों पर लागू
नहीं होता ।

जिन मामलों में वेतन नियत किया जा चुका है उनका पुनरावलोकन (Revised) किया जाय
और तदनुसार वेतन का पुनरीक्षण किया जाय ।

अध्यापकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय फाउण्डेशन

[नेशनल फाउण्डेशन फोर टीचर्स वेलफेयर्स]

भारत सरकार द्वारा जून, १९६२ से अध्यापकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय (नेशनल) फाउण्डेशन प्रारम्भ किया गया। यह फाउण्डेशन राजकीय संस्थाओं तथा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के निमित्त है। भारत सरकार द्वारा इस फण्ड में ५ लाख रुपये का प्रारम्भिक प्रशदान दिया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा भी इस फण्ड में २५,०००) प्रतिवर्ष का योगदान देने का निर्णय किया गया है।

राष्ट्रीय (नेशनल) फाउण्डेशन के नियमों के अनुसार किसी अध्यापक की असामयिक मृत्यु के कारण अथवा लम्बी बीमारी के कारण अध्यापक अथवा उनके आश्रितों को यह सहायता दी जा सकती है।

प्रपत्नी संस्था व समाज में अध्यापक के रूप में ३० साल तक अत्यधिक प्रशंसनीय सेवा करने वाले कुछ अध्यापकों को उनके रिटायरमेंट के समय सहायता (ex-gratia grant or award) भी दी जा सकती है। इस अनुदान के लिए संस्था के अध्यक्ष (हैड आफ दी इन्स्टीट्यूशन) की राय पर (न कि पृथक्-पृथक् प्रार्थना-पत्रों पर) विचार किया जायगा।

अध्यापक अथवा उनके आश्रित जो कि निम्न शर्तों में से एक अथवा अधिक शर्त को पूरी करते हैं, सहायता के पात्र हैं:—

- (१) यदि प्रार्थना-पत्र अध्यापक के आश्रितों द्वारा दिया जाता है तब यह प्रार्थना-पत्र अध्यापक की मृत्यु के बाद के १ साल के अन्दर दिया जाना चाहिये।
- (२) अध्यापक यदि जीवित है तो सहायता तभी देय है जब कि वह स्थाई रूप से अथवा अनिवार्य रूप से सविनय अथवा अन्य कार्य के लिए अयोग्य (incapacitated) हो गया है।
- (३) अध्यापक के कुटुम्ब की वार्षिक आय तभी स्त्रोत से १,५००) से अधिक न हो।
- (४) कुटुम्ब में अन्य कोई वयस्क पुरुष कुटुम्ब की सहायता करने के योग्य न हो।

प्रार्थना-पत्र निर्धारित छपे फार्म पर अनुसूची (अ) अथवा (ब) पर, जो भी प्रावश्यक होना चाहिए। शिक्षा विभाग के समस्त उप-संचालिकाओं, निरीक्षकों, निरीक्षिकाओं, उप-निरीक्षिकाओं उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं तथा पंचायत समितियों के कार्यालयों से फार्म उपलब्ध हो सकेंगे।

ग्राह्य है कि अध्यापकगण व उनके आश्रित इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावेंगे।

अनिल बोडिया
आई. ए. एस.

अतिरिक्त संचालक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान सरकार

(शिक्षा-विभाग)

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

वर्तमान में सहायता प्राप्त संस्थाएँ प्रोविडेंट फण्ड (भविष्य निधि) की रकम को पोस्ट ऑफिस में अथवा शिड्यूल्ड बैंकों में रखती हैं । राज्य की क्षमता को, हमारी सीमाओं पर पैदा कर दी गई । स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए अधिक बलवती बनाने के दृष्टिकोण से को ध्यान में रखते हुए समस्त सहायता प्राप्त संस्थाओं की प्रबल समितियों से निवेदन है कि वे जमाकर्ता के यथोचित परामर्श से, अधिकाधिक २० दीर्घकालीन डिफेंस अथवा सेविंग के रूप में लगावें ।

हस्ताक्षर—अनिल बोडिया

अतिरिक्त निदेशक

प्राइमरी एवं सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर ।

प्रतिलिपि—सरकार के आदेश सं० एफ १७/(३४) कैव/६५ दिनांक १५ मई १९६५ जो कि उप-सचिव, गवर्नमेंट केबिनेट सेक्रेटेरियर राज० जयपुर द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजा गया और जो अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की पृष्ठांकना से ईडीबी./एस्ट/ए/ए/११३१६/स्पेशल/१५ दिनांक १६-६-१९६५ के जरिये उक्त निदेशकालय के अधीन समस्त अधीनस्थ विभागों को भेजा गया ।

विषय—मितव्ययता के उपाय जो कि वर्तमान सखुट कालीन अवधि में किये गये ।

सरकारी विभागों में मितव्ययता तथा कठोरता के बारे में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों को पुनर्विलोकित करने के पश्चात्, सरकार नीचे लिखे अनुसार आदेश जारी करती है कि—

१—आदेश से एफ. १२(४१) कैव/६२ दिनांक अक्टूबर १९६२

‘तत्काल’/‘आवश्यक’ टेलीफोन करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया जाय ।

२—परिपत्र नं० एफ १२(४७) कैव/६२ दिनांक अक्टूबर १९६२

(क) सरकारी विभागों द्वारा सेमीनार तथा कांफ्रेंस आयोजित करने में माय कमी होना चाहिये ।

(ख) ऐसी वस्तुओं के खरीदने पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटा लिया जाय जो कि तत्काल आवश्यक नहीं हैं ।

(ग) किसी नवीन गतिविधि अथवा किसी नवीन संगठन के लिए सहायताएं अनुदान दिये जाने के प्रस्तावों पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया जाय ।

३—परिपत्र नं० एफ १२ (४७) कैब/६२ दिनांक ६ नवम्बर:१९६२

जारी किये गये यह अनुदेश कि ऐसी मदों पर जिनके लिए वेंजट में प्रावधान नहीं है) व्यय सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं भेजा जाये; जब तक कि विभागाध्यक्ष तथा शासन सचिव यह प्रमाणित न करे कि व्यय अपरिहार्य है, कठोरता से पालन किये जाने चाहिये।

४—आदेश संख्या एफ. १२ (४७) कैब/६२ दिनांक १५-११-६२

शीर्ष "अन्य प्रभार" तथा वैसी ही अन्य मदों पर जो कि विभागों के वेंजट में दिये हैं, खर्च उसी दशा में किया जाना चाहिए जब कि वे अपरिहार्य हों।

५—आदेश नं. एफ १२ (५) कैब/दिनांक २०-११-६२

नीचे लिखे अनुदेश कठोरता के साथ पालन किये जायें:—

(क) कोई कीमती कागज, बिना सरकार, कैबि. सचिवालय की विशिष्ट स्वीकृति के, काम में नहीं लिया जाय।

(ख) अनुपयोगी फार्मों को काम में लिया जाय।

(ग) कागज की दोनों तरफ प्रयोग में लाई जाय।

(घ) टाईप में लिखा जाने वाला सब कार्य मिगिल स्पेस में किया जाय।

(ङ) प्रकाशनों को छपाने का प्रस्ताव, छपने के लिये भेजे जाने के पहिले, सावधानी पूर्वक जांच कर लिये जाने चाहिये—

(च) केवल वे नियम कालिक पत्र-पत्रिकाएं ही छपाई जायें जिनसे कोई आवश्यक प्रयोजन सिद्ध होता हो।

(छ) साधारण चिट्ठियों के स्थान पर 'कम्पलीमेण्टरी चिट' ही प्रयोग में लाई जायें।

(ज) कलण्डरो तथा डायरियों को कीमती कागज पर न छापा जाय।

(झ) पुराने लिफाफों पर 'मितव्ययता स्लिप' लगाकर उन्हीं लिफाफों का बराबर प्रयोग में किया जाय।

(ग) आवश्यकतानुसार छोटे लिफाफे काम में लिये जायें, और एक ही प्रिंटी को भेजे जाने वाले कई पत्र एक ही लिफाफे में रखे जायें।

(ङ) अनुपयोगी फार्म तथा रद्दी कागज, लिफाफे आदि बनाने के काम में लिये जायें।

(ठ) ड्रुपलीकेट कागज दोनों तरफ से काम में लिया जाय।

(ड) विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनो का कलेवर दस पृष्ठों से अधिक न हो और उनकी प्रतियों की संख्या नितान्त न्यूनतम रखी जाय।

(ढ) सर्व साधारण के हित साधक भिन्न भिन्न परिपत्रों के लिये स्थायी मेलिंग लिस्ट रखी जाय ताकि लम्बी शीटों का प्रयोग कम हो सके।

(ण) समितियों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचनाएं तथा सरकारी निर्णयों सम्बन्धी अधिसूचनाएं केवल उन्हीं अधिकारियों को भेजी जाय जिन्हें कोई खास कार्यवाही करनी हो।

(स) दोरे के प्रोग्राम केवल थोड़े से अत्यावश्यक व्यक्तियों को भेजे जायें एवं आमतौर पर नहीं।

नीचे लिखे प्रविबंध हटा लिये जायें:—

- (क) सरकारी समारोहों (Functions) के अवसर पर छपे हुए ग्रामंत्रण पत्रों की प्रापेक्षा साइक्लोस्टायल किये हुये फार्म काम लिये जाये।
- (ख) मीटिंगों की संक्षिप्त कार्यवाही (minutes) अतिसूक्ष्म हो। उनमें उपस्थित अधिकांश कारियों के नाम लिखने की सदैव आवश्यकता नहीं है।

६-आदेश संख्या एफ. १२ (४७) कैब/६२ दिनांक १५-१२-६२

- (क) दोहरे इन्स्पेक्शन में तथा दोनों सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये जायें।
- (ख) रेल, वायुयान, तथा टेलीफोन, पर आदि सभी साधनों के न्यूनतम उपयोग पर लगाये हुए प्रतिबंध हटा लिये जाये। प्राइवेट तथा सरकारी समारोहों में संयम तथा भोजन प्रबंध फिजूल-खर्च, सम्बन्धी प्रतिबन्ध कायम रखा जाय।

आफिशियल पार्टियों तथा समारोह उन अवसरों पर ही किए जायें जबकि अत्यावश्यक हों।

७-आदेश संख्या एफ १२ (८६) कैब/६२/दिनांक २-२-६३

विभागों द्वारा फर्नीचर की खरीद सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया जाय। किन्तु फिर भी खर्च, बजट प्रावधान के अनुसार ही होना चाहिये और उसकी जांच कठोरता से की जाय।

८-सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश संख्या एफ. (११०) जी. ए. ए./ग्रुप-२/६२ दिनांक १५ दिसम्बर १९६२

निम्नलिखित प्रतिबन्ध हटा लिये जायें।

- (क) सरकारी इमारतों की मरम्मत तथा सुरक्षा के लिये रखे गये प्रावधान में १५ प्रतिशत कमी की जाय।
- (ख) विभागों की गाड़ियों तथा व्यक्तियों के लिये किये गये पेट्रोल के प्रावधान में १५ प्रतिशत कमी की जाय।
- (ग) जब तक नई इमारत बनाने के लिए फण्ड न हो तब तक कोई इमारत अस्थायी तौर पर दो या तीन वर्ष के लिए किराये पर न ली जाय।

९-सा. प्र. विभाग का आदेश सं. एफ. १ ८) सा. प्र./ए/ग्रुप-२/६३ दिनांक २७-५-६३

- (क) राजपत्रित अधिकारियों का अवकाश, स्थानान्तरण, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचना का प्रकाशन न किये जाने विषयक प्रतिबन्ध कठोरता के साथ पालन किया जाय।
- (ख) नियतकालिक विवरण-पत्रों, तथा नक्शों की संख्या कम की जाय।

१०-आदेश सं. एफ. १२ (१०६) कैब/सचिवा./६१ दिनांक ६ मई १९६१

निम्नलिखित अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाय।

- (क) सरकारी हिमाव में कोई कीमती फर्नीचर, सिवाय स्टेट होस्टल को सजाने के लिये, नहीं खरीदा जाय।
- (ख) किसी सरकारी कार्यालय अथवा संस्था के लिये, सिवाय स्टेट होस्टल को छोड़ कर, दरियां न खरीदी जायें।

- (ग) पदों का कपड़ा ४ रुपये प्रति गज, जिसकी चौड़ाई ४५ इंच हो, से अधिक कीमती नहीं खरीदा जाय।
- (घ) राज्य कर्मचारी एक ही पद पर दो वर्ष पूरे होने से पहिले स्थानान्तरित न किये जायें।
- (ङ) जिला स्तरीय तथा डिवीजन स्तरीय अधिकारियों के स्टेट हैडक्वार्टर या दौरों को सीमित किया जाय।

निम्नलिखित प्रतिबंध हटा लिये जाये :—

- (च) सरकारी कार्यालयों में एग्जर कण्डीशनर अथवा रूम क्लर लगाने पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे।
- (छ) औपचारिक ढंग के समारोहों उदाहरणार्थ, नींव लगाये जाने, उद्घाटन अथवा समापन समारोहों आदि में यथासम्भव, स्थानीय, जिला स्तरीय अधिकारी वर्ग ही उपस्थित हो और सचिवालय के अधिकारी तथा विभागीय अध्यक्ष साधारणतया ऐसे समारोहों में उपस्थित होने के ही लिमिटेड दौरे न करें, ऐसे अनुदेश जो पहिले जारी किये गये थे।

प्रतिलिपि—आदेश नं. एफ. १ (२२) एजू. (मैल-६) ६४ दिनांक १७-६-६५ सहायक सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग-द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी किया गया।

आदेश

राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किया है कि जिन व्यक्तियों ने सेना में कमीशन अधिकारी जे.प्रो.सी./एन.सी.प्रो./प्रो. प्रार. के रूप में तथा नौ सेना तथा वायु सेना में समकक्ष रैंकों में प्रतिरक्षा सेवाएँ प्रारम्भ की, जबकि लोग अध्ययन कर रहे थे, उन व्यक्तियों को सरकारी संस्थाओं में, अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में अथवा रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, प्रतिरक्षा सेवाओं से मुक्त होने पर, अपना अध्ययन पूरा करने में सुविधाएँ सरकारी के खर्चे पर, दी जायें। उन्होंने यह भी आदेश प्रदान किया है कि:—

- १—जिन विद्यार्थियों ने स्कूल में पढते हुए अपना अध्ययन छोड़ दिया था उन्हें स्कूल शिक्षा अर्थात् हायर सैकण्डरी क्लास तक की शिक्षा पूरी करने की सुविधाएँ दी जायेंगी।
- २—जिन अधिकारियों ने, कालेज पढते हुए अपना अध्ययन छोड़ दिया था उन्हें कालेज शिक्षा अर्थात् प्रथमभूत डिग्री तक अध्ययन पूरा करने की सुविधा दी जायेगी।
- ३—उपरोक्त १ व २ में उल्लिखित शिक्षा पूरी करने की सुविधाएँ इस शर्त के अधीन होंगी कि वे प्रति वर्ष उत्तीर्ण हो जायें यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा अनुत्तीर्ण रहे तो उसे तदनुवर्ती वर्ष परीक्षाओं के लिये सुविधाएँ नहीं दी जायेंगी।
- ४—ऊपर १ व २ में लिखित व्यक्तियों को ट्यूशन फीस के भुगतान से मुक्त किया जायगा और अन्य तत्सम्बन्धी खर्चों के लिये उपयुक्त छात्रवृत्तियाँ भी दी जायेंगी।
- ५—ये सुविधाएँ उन लोगों को उपलब्ध होंगी जो प्रतिरक्षा सेवाओं में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सम्मान पूर्वक मुक्त किये जायें किन्तु मुक्त होने की तारीख से वे एक वर्ष के अन्दर स्कूल अथवा कालेज में भर्तों हो जायें।

उपरोक्त सुविधाएँ उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो राजस्थान के सद्भावी (बोनोंफाइड) निवासी हैं और जिन्होंने राजस्थानस्य स्कूलों अथवा कालेजों को छोड़ा था और ये सुविधाएँ उन लोगों को नहीं दी जायेंगी जो राजस्थान के बाहर या सहायता प्राप्त संस्थाओं में अथवा पब्लिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति जो उनके नं० १९७४ दिनांक ३ जून, १९६५ के जरिये प्राप्त हुई, जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि

अधिसूचना संख्या ५८२०६-३०८ ई. दिनांक २२-७-६५ जो रजिस्ट्रार राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को जारी किया गया।

अधिसूचना

सर्व साधारण की सूचनायें अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने बी. ए. तथा बी. कॉम (फाइनल) परीक्षाएँ (रूढिगत योजना) सन् १९६६ में भी लेने का निर्णय लिया यह इसलिये सन् १९६५ में अथवा उसके पूर्व हुई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पुनः परीक्षा दे सके। जो विद्यार्थी १९६६ में अनुत्तीर्ण रहेंगे पुनः १९६७ में परीक्षा में बैठना होगा और तत्पश्चात् तत्सम्बन्धित फाइनल परीक्षा में, अवर्षाय डिग्री योजना के अनुसार बैठ सकेंगे। उपरोक्त परीक्षाएँ १९६४ की परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम तथा योजना के अनुसार ली जायेगी।

नवीन विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं होगी वे टी. डी. सी. परीक्षाओं की योजना के अनुसार परीक्षा दे सकेंगे वरन् वे अन्यथा उन परीक्षाओं में शामिल होने के नियमानुसार पात्र हों।

प्रतिलिपि पत्र सं. ई. डी. बी./एस्टे/ए/बी./२२१६६/३/६५ दिनांक ३१-जुलाई १९६५-जो कि अतिरिक्त निदेशक, प्राइमरी एवं मेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा निरीक्षक, स्कूलों को भेजा गया।

एन. एफ. सी. प्रोग्राम की समस्त हाई स्कूलों, हायर मेकण्डरी स्कूलों तथा उन मिडिल स्कूलों को भी जहाँ पी. ई. टी. काम कर रहे हैं, क्रियाविन्त करने के उद्देश्य से, यह निश्चित किया गया है कि ऐसे स्कूलों के बच्चे हुए समस्त पी. ई. टी. जिन्होंने एन. डी. एस. न्यू दिल्ली, के डायरेक्ट द्वारा १९५३ से संगठित कोर्सों में से किसी को टेनिंग नहीं पाई है, उन्हें तुरन्त ही किसी कांश प्रोग्राम में ई. सप्ताह के स्पेशल कोर्स के द्वारा पुनर्नवीकृत कर दिया जाय।

मई १९६५ से ऐसे तीन कोर्स पुरुष प्राइमरी एजुकेशन टीचरों के लिये सरिस्का तथा चौकी में संगठित किये गये हैं और एक कोसी महिला, प्राइमरी एजुकेशन टीचरों के लिये अजमेर में आयोजित किया गया था। यद्यपि संस्थाओं को तथा अजमेर में आयोजित किया गया था। यद्यपि संस्थाओं को तथा इंसपेक्टरेट्स में सूचना समय पर ही भेज दी गई थी तो भी मंथना में प्राइमरी एजुकेशन टीचरों ने अभी कुछ न कुछ कारण बताते हुए पुनर्नवीकरण (re-orientation) का कोर्स पूरा नहीं किया है।

इस उद्देश्य में अवशिष्ट समस्त प्राइमरी एजुकेशन टीचर पुरुष तथा महिला, पुनर्नवीकरण टेनिंग डायरेक्टोरेट नेशनल डिस्पॉजिबल स्कीम, नई दिल्ली, नीचे लिखे कोर्स को संगठन कर रहे हैं।

१-समस्त अविशिष्ट पी. ई. टी. (पुरुष) वर्ग के लिये-सरिस्का में तारीख २३-८-६५ से १-१०-६५ तक (अनवर)

२-समस्त अविशिष्ट महिला पी. ई. टी. वर्ग के लिये-सरिस्का में ता. २८-१०-६५ से ६-१२-६५ तक (अनवर)

अतः आप से निवेदन है कि इसके तिये पूरा पूरा प्रयास किया जाय कि प्रत्येक पी. ई. टी. वर जिम्मे अभी तक पुनर्नवीकरण (re-orientation) ट्रेनिंग सरिस्का अनवर में प्रतिनियुक्त कर दिया जाय कोई भी बच न जाय, जो कि वहां पर इस ट्रेनिंग में आखरी अवसर पर, शामिल हों जाय। यह सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं पर लागू होता है। यदि कोई पी. ई. टी. कोई 'जूनियर' एन. सी. सी. अधिकारी हो तो भी उसे प्रतिनियुक्त करना है।

ऐसे अत्यापकों के नाम जो अप्रशिक्षित (un-oriented) है तथा इस कोर्स में शामिल न हों, उस निदेशकालय को भेजे जाय ताकि उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जाय जो उपयुक्त समझी जाय।

कार्यालय-इन्सपेक्टर ऑफ-स्कूलस् जयपुर (राजस्थान) जयपुर

अधिसूचना

सरकारी आदेश सं. एक ४ (१७) एज्./सैन-६/६२/भाग-२ दिनांक १०-१०-६३ तथा प्रतिरिक्त निदेशक, ग. इ. रो एवं मेमण्डरी शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के परिपत्र नं. ई.डी.बी./एच.ई. सी./ई/एस सी.एच./२०४२१/३/६५-६५ दिनांक १ जुलाई १९६५ के अनुसरण में, पात्र उम्मेदवारों में, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, अर्थात् उन विद्यार्थियों से जिन्हें १९६४-६५ में छात्र-वृत्ति मिली है एवं जो सरकारी मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों में तथा जयपुर जिले के नागरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार के माध्यता प्राप्त संस्थाओं में, अध्ययन कर रहे हैं, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में, उनकी छात्रवृत्तियों को १९६५-६६ के लिये नवीनीकृत करने के लिये, अत्यन्त निर्धनता योजना के अनुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित करती है जिनमें स्वयंवासी राज्य कर्मचारियों के परिवार तथा शारीरिक निरायता से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन-पत्र इस कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र 'ग' में उन संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों की भावकत भेजे जने चाहिये जिनमें कि आवेदक अध्ययन कर रहे हों। प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज शामिल होने चाहिये—

१- उस संस्था के मुख्य अधिकारी का भर्ती होने का एक प्रमाण पत्र 'ब' में जिसमें आवेदक छात्र-वृत्ति की अवधि में अध्ययन करना चाहता है।

२- पिछली परीक्षा की प्रप्ताङ्क सूची अर्थात् १९६६ की एक प्रतिलिपि जो यथा विधि प्रेषित करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणिकृत हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिये।

संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों के लिये अनुदेश

१- संस्था के मुख्य अधिकारी को समस्त आवेदन-पत्रों को प्रपत्र 'ब' में दर्ज करना चाहिये, और यह देख लें कि आवेदन-पत्र का कोई स्वम्भ खाली न रहे। आवेदन-पत्र के समय 'छ' में पिछले वर्ष (१९६४-६५) की स्वीकृति की सं० तथा तारीख तथा क्रम संख्या स्पष्टतया लिखी जानी चाहिये अथवा छात्र-वृत्ति का नवीकरण नहीं किया जायगा।

- २—समस्त आवेदन-पत्र प्रपत्र 'च' में एक ही बार में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए ।
नवीकरण केवल १० महीने के लिये होगा जिसकी अवधि जुलाई १९६५ से अप्रैल १९६६ तक (शिक्षा सन् १९६५-६६) होगी ।
- ३—जो विद्यार्थी १९६५ की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे उनके आवेदन-पत्र न भेजे जायें ।
- ४—छात्र-वृत्ति हेतु आवेदन-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों पर स्वयं मुख्य-अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जायें न कि उसकी ओर से संस्था के किसी अन्य सदस्य द्वारा ।
- ५—किसी विद्यार्थी की सरकारी फण्ड में एक से अधिक छात्र-वृत्ति नहीं दी जानी चाहिये ।
- ६—आवेदन पत्र में कोई प्रविष्टि अपूर्ण या गलत होने की दशा में आवेदन-पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकेगा ।
- ७—उपयुक्त छात्र-वृत्तियाँ मंजूर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित टाइम-टेबुल का अनुसरण करना होगा—

[१] आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ग' में संस्था के मुख्य अधिकारी के पास पहुँचने की अन्तिम तारीख १५ अगस्त १९६५ होगी—

[२] आवेदन-पत्रों के एकीकृत प्रपत्र 'च' यदाविधि मुख्य अध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होकर, इस कार्यालय में पहुँचने की अन्तिम तारीख २० अगस्त १९६५ होगी ।

उपरोक्त तारीखों का ठीक-ठीक पालन किया जाना चाहिये । जो आवेदन-पत्र देर से प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों को ये अनुदेश ठीक-ठीक पालन करने चाहिए ।

सरकारी हाई स्कूलों / हायर सेकण्डरी स्कूलों / मल्टी परपज हाई तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के मुख्य अध्यापक भी उनके स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से आवेदन-पत्र लेने के सम्बन्ध में इसी प्रकार कार्य कर सकते हैं और १९६५-६६ में छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के कारण आवश्यक रुपये का हिसाब १५ अगस्त तक लगा लें । ये छात्रवृत्तियाँ अत्यन्त निर्धारित योजना के अन्तर्गत होंगी, और उनमें स्वर्गवासी राज्य कर्मचारियों के विद्यार्थियों तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों के मामले शामिल होंगे । इन्हें, फण्ड नियत किए जाने के लिए इस कार्यालय में निश्चित रूप से तारीख २० अगस्त १९६५ की अवधि तक पहले भेज दिया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर-एन.एल.वर्मा

प्रतिष्ठित निरीक्षक स्कूल

जयपुर

आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ग'

अत्यन्त निर्धारित योजना स्वर्गवासी राज्य कर्मचारियों के विद्यार्थी तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों के मामलों, में छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण हेतु ।

सेवा में

निरीक्षक महोदय,

स्कूल, जयपुर

१—विद्यार्थी का नाम (मोटे अक्षरों में)

२—पिता का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)

३—कक्षा जिसमें अब भर्ती हुआ है।

४—कक्षा जो पिछली बार पास की है।

५—(क) संस्था का नाम जिसमें इस समय अध्ययन कर रहा है।

(ख) संस्था का नाम जिसमें गत वर्ष अध्ययन किया था।

६—स्वीकृति अधिकार पत्र सं० तथा सारीख जिसके अनुमरण में गत वर्ष छात्रवृत्ति मंजूर हुई थी और स्वीकृत सूचि में बताई हुई क्रम संख्या जिस पर उक्त मंजूरी अंकित है।

७—पिछली परीक्षा की प्राप्ति सूचि (प्रमाणिकृत प्रति लगाई जाय)

८—माता पिता/संरक्षक की सब साधनों से होने वाली सम्पूर्ण आय/(इस तथ्य का एक प्रमाण-पत्र मजिस्ट्रेट/संस्था के मुख्य अधिकारी यदि वह अपना निकालने वाला अधिकारी हो अन्यथा निरीक्षक स्कूल / निरीक्षक गवर्न्स) स्कूल, उप-निरीक्षक गवर्न्स स्कूल से प्राप्त किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर-विद्यार्थी

हस्ताक्षर संरक्षक

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक द्वारा वर्णित उपर्युक्त विवरण सही है। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किए जाने के लिए मैं सिफारिश करता हूँ।

हस्ताक्षर—

मुख्य अधिकारी संस्था

(मुहर)

प्रपत्र 'घ'

भर्ती होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(विद्यार्थी का नाम)पुत्र/पुत्री/पति

श्री संस्था का नाम में.....कक्षा में..... दिनांकको भर्ती किया गया था और निरन्तर अध्ययन कर रहा है।

हस्ताक्षर (मय मुहर)

मुख्य अधिकारी संस्था

प्रपत्र "च"

छात्र वृत्ति दिये जाने सम्बन्धी विवरण-पत्र

क्र.	नाम	कक्षा	पिछली कक्षा	पिछली	पिछली	माता-पिता/	अन्य साधनों
संस्था	विद्यार्थी	जिसमें	में विद्यार्थियों	कक्षा में	कक्षा में	संरक्षक की	से प्राप्त
		पढ़ रहा है	की कुल	प्राप्त किया	प्राप्त	व्यक्ति	सहायता
			संख्या	द्वितीय	अंकों का	आय	
				प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८

सेवा में,

श्रीमान प्रतिरिक्त निदेशक महोदय,

प्राइमरी सेकण्डरी शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर ।

(आवेदन-पत्र—जे. सी. ओ./एन. सी. ओ./सी. ओ. तथा नान-कॉन्वेंटेंट्स के बच्चों को और जे. सी. ओ. रैंक के तथा उससे नीचे रैंक के सैनिकों की पत्नियों को जो राजस्थान में कक्षा ६ से कक्षा ८ तक में अध्ययन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु)

नोट—ये छात्रवृत्ति केवल—

- (१) उन्हीं सैनिकों के बच्चों को मिलेगी जो कि चीन के साथ युद्ध में मारे गये थे अथवा स्थायी तौर पर असमर्थ हो गये थे ।
- (२) जे. सी. ओ. रैंक के अथवा उससे नीचे रैंक के सैनिकों की पत्नियों को मिलेगी ।
- (१) विद्यार्थी का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)
- (२) पिता का (पत्नी की दशा में पति का) पूरा नाम
- (३) पालन करने वाले संरक्षक का नाम
(यदि गिता या पति जीवित न हो और विद्यार्थी से उसका रिश्ता)
- (४) जे. सी. ओ./एन. सी. ओ. तथा अन्य अधिकारियों का विवरण—
 - (१) नाम
 - (२) रैंक
 - (३) विद्यार्थी से रिश्ता
 - (४) जीवित या मृत
- (५) स्कूल जिसमें अध्ययन कर रहा है.....स्थान.....जिला.....
- (६) कक्षा जिसमें पढ़ रहा है
- (७) डे—स्कालर या होस्टलर
- (८) पिछली परीक्षा का परिणाम मय अंशों
- (९) किसी अन्य छात्रवृत्ति का विवरण—
(जो अन्य सरकारी/विभागों से मिल रही हों)

तारीख आवेदन-पत्र

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

संस्था के मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित

(१) उपरोक्त विवरण सही है—

(२) कि श्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... रैंक उस स्कूल की कक्षा में विद्यार्थी है । वह पिछली परीक्षा में कक्षा में उत्तीर्ण/मनुस्तीर्ण रहा/रही ।

[ख] श्रीमती..... पत्नी श्री.....
रैंक..... इस स्कूल की कक्षा में विद्यार्थी है । वह पिछली परीक्षा में
कक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण रहा/ रही ।

हस्ताक्षर

मुख्य अध्यापक/अध्यापिका

प्रपत्र "ख"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... जो इस स्कूल की कक्षा में विद्यार्थी है, के पिता
श्री चीन के साथ हुए युद्ध में मारे गये थे या
अस्थायी रूप से असमर्थ हो गये थे ।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

मुख्य अधिकारी संस्था/एस. डी. ओ./प्रथम
श्रेणी मजिस्ट्रेट ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
गांव.....

तहसील जिला..... राजस्थान का सद्भावी (बोनाफाइड) निवासी है ।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

एस. डी. ओ./प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

नोट—मुख्य अध्यापक उपरोक्त सं० १ का प्रमाण-पत्र केवल तभी दे सकता है जब कि
प्रावेदक उसे एस. डी. ओ. अथवा मजिस्ट्रेट से प्राप्त न कर सकता हो और मुख्य अध्यापक अपनी
निजी जानकारी के आधार पर उक्त तथ्य का सत्यापन कर सकता है ।

